

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

हिन्दुस्थानका कानून दिवालिया

अर्थात्
प्रान्तिक कानून दिवालिया

एक्ट नं० ५ सन १९२० ई०
प्रेसीडेन्सी टाउन्स कानून दिवालिया

एक्ट नं० ३ सन १९०६ ई०
Provincial Insolvency Act 5 of 1920.

AND
Presidency Towns Insolvency Act 3 of 1909.

सर्वाङ्गपूर्ण व्याख्या और सन १९३० ई० तकके समग्र
संशोधनों व नज़ीरों आदि सहित

लेखक. —
बाबू रूपकिशोर टण्डन

एम० ए०, एलएल० बी०, एम० आर० ए० एल० एडवोकेट

प्रकाशक : —
पं० चन्द्रशेखर शुक्ल
सन १९३० ई०

मुद्रित
कानून प्रेस, कानपुर

सर्वाधिकार सुरक्षित

मूल्य
२५ रुपया प्रति

भारत

कानून दिवालीया

प्रान्तिक कानून दिवालीया (एक्ट ५ सन १९५० ई०)

प्रेसीडेन्सी गवर्नर्स कानून दिवालीया (एक्ट ३ सन १९५६ ई०)

इस समय भारतवर्षमें प्रत्येक प्रचलित कानूनका हिन्दी भाषामें होना आवश्यक है क्योंकि इस भाषाको जानने व समझने वालोंकी संख्या बहुत है तथा वह दिन बदिन बढ़तीही जाती है। प्रचलित कानूनोंका ज्ञान भी जनसाधारणके लिये किसी हद तक परमावश्यक है क्योंकि उनकी पाश्चीसे वह लोग बच नहीं सकते हैं। समझदार व्यक्तियोंका यह कर्तव्य है कि यह ऐसी बातोंको अवश्य जानते रहें जिससे किसी समय भी अनायास हानि पहुँचनेकी सम्भावना हो अथवा जिनके आधार पर वह अपने स्वार्थोंकी रक्षा कर सकते हों। मनुष्यकी अवस्था सदैव एकसी नहीं रहती है कभी उसे लाभ होता है तथा कभी हानि, परन्तु वही मनुष्य अपनी स्थिति को समयानुकूल सँभाल सकता है जिसे प्रचलित नियमोंका यथा सम्भव ज्ञान होवे। ऐसे नियमों का जानने वाला व्यक्ति केवल अपना ही भला नहीं कर सकता है किन्तु वह अपनी सलाहसे दूसरोंको भी लाभ पहुँचा सकता है।

देशमें व्यापार फैलाने तथा लेनदेनका काम विस्तृत रूपसे हो जानेके कारण इन कामोंसे सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियोंका अनायास ही हानि पहुँचनेके अवसर आजाते हैं। चालाक व्यक्ति प्रचलित कानूनोंका अनुचित लाभ उठा कर दूसरे लोगोंको जो उन कानूनोंसे अनभिज्ञ होते हैं तब तरहकी हानियाँ पहुँचा दिया करते हैं। कानून दिवालीयाका प्रयोग अब बहुतयावतसे किया जाने लगा है इस कारण उक्त कानूनका ज्ञान लेना हर व्यक्तिके लिये आवश्यक माना जाता है जिससे कि वह अपने स्वार्थोंकी रक्षा कर सके तथा जहाँ तक होसके हानियोंसे भी बच सके। इसी प्रकारकी आवश्यकताको प्रतीत कर कानून दिवालीया हिन्दीमें प्रकाशित किया गया है।

यह पुस्तक सरल हिन्दी भाषामें लिखी गई है। प्रत्येक दफाका अनुवाद समझने योग्य भाषामें दिया जानेके अतिरिक्त उसकी व्याख्या भी पूर्ण रूपसे की गई है। व्याख्यामें दफाओंका अर्थ भली भाँति समझानेका प्रयत्न किया गया है तथा उन सब उल्लेखनीय मुकदमोंका भी

हवाला दिया गया है जो भिन्न भिन्न हार्दिकोंटों तथा चीफकोर्ट द्वारा अवतक तय किये गये हैं। यह पुस्तक दो भागोंमें विभक्त है एकमें प्रान्तिक कानून दिवालिया (एक्ट ५ सन १६२० ई०) का पूरा वर्णन है तथा दूसरेमें प्रेसीडेन्सी टाउनस कानून दिवालिया (एक्ट ३ सन १६०६ ई०) का उसी प्रकार विवरण दिया हुआ है।

ब्रिटिश भारतमें कानून दिवालियाका चलन इंग्लैण्डके चैम्बर्ली एक्टको देख कर हुआ है तथा उसी एक्टके नियमोंका अधिकतर प्रयोग पहिले होता रहा है अब भी कानून दिवालियाके सम्बन्धकी बहुतसी बातोंका अर्थ लगाते समय चैम्बर्ली एक्टका सहारा लिया जाता है तथा अङ्गरेजी अदालतों द्वारा तय किये हुए फैसलोंका उल्लेख हार्दिकोंटके जज अपनी सजवीजोंमें किया करते हैं। प्रान्तिक कानून दिवालिया (एक्ट ५ सन १९२० ई०) के लागू होनेसे पहिले प्रान्तिक कानून दिवालिया सन १९०७ ई० (एक्ट ३ सन १८०७ ई०) प्रचलित था। इससे पेशतर इस एक्टके स्थानमें जो नियम लागू थे उनका उल्लेख संग्रह जायता दीवानी (Code of Civil Procedure) में मिलता है अर्थात् संग्रह जायता दीवानीमें दिवालेके सम्बन्धमें दिये हुए नियम मुकदिसलमें लागू थे। इस प्रकारके नियमोंका हवाला सबसे पहिले सन १८५६ ई० के संग्रह जायता दीवानीमें मिलता है इसके पश्चात् सन १८७३ ई० व १८७६ ई० के संग्रह जायता दीवानीमें भी ऐसे नियमोंका उल्लेख है। संग्रह जायता दीवानीमें जिन नियमोंका हवाला मिलता है उनका सम्बन्ध केवल उन कर्जब्याहोंसे है जो स्वयंकी वसुलीके सम्बन्धमें डिमी हासिल कर चुके हैं तथा उन मर्दिमूनोंका है जो गिरफ्तार हुए हों या जिनकी जायदाद कुर्के की गई हो। इस प्रकार उन नियमोंसे सब प्रकारके कर्जब्याहों के फजोंकी रक्षा नहीं हो सकती थी और न उनसे कर्जदारोंका ही पूर्ण बचाव था। उन नियमों को अपर्याप्त समझ कर तथा उनको संग्रहीत करनेके लिये एक्ट ३ सन १८०७ ई० (प्रान्तिक कानून दिवालिया १८०७ ई०) बनाया गया था जो पहिली जनवरी सन १८०८ ई० से लागू हुआ था। यह एक्ट सन १९१४ ई० में कुछ संशोधित किया गया था और लगभग १० साल तक इसका प्रयोग जारी रहा। इस दर्मियानमें बहुतसी न्यूनताएँ इस एक्टमें दिखलाई दीं जिनके दूर करनेके लिये भिन्न भिन्न अवसरों पर जजों वकीलों व व्यापारियों आदिने अपनी रायें प्रकट कीं। उन्हीं न्यूनताओंको दूर करनेके लिये प्रान्तिक कानून दिवालिया सन १८२० ई० (एक्ट ५ सन १६२० ई०) बनाया गया इसके अनुसार धोड़ा देन वाले कर्जदारको उचित दण्ड दिया जासकता है। अदालत दिवालिया धोखा देने वाले दिवालिपाके बहाल होनेमें रुकावट डाल सकती है तथा उसें रोक भी सकती है। इस कानूनमें अज्ञात दिवालिपाके अधिकार जो उसे वाक्याती या कानूनी मसलोंको तय करनेके सम्बन्धमें हैं भली प्रकार दिखला दिये गये हैं। सरसरीमें सुने जाने वाले मामलोंको नियमबद्ध कर दिया गया है इसी प्रकारकी और भी बहुतसी बातें बढ़ा दी गई हैं तथा संशोधित कर दी गई हैं जो एक्ट ३ सन १८०७ ई० में नहीं थीं। इस एक्टमें भी सन १८२० ई० के बाद कुछ संशोधन हुए हैं जिनका हवाला संलेपमें दे दिया गया है। सन १८२६ ई० के संशोधनके अनुसार अर्थात् एक्ट ६ सन १८२६ के अनुसार प्रान्तिक कानून दिवालियाका प्रयोग कराची टाउन पर नहीं रहा है इससे पहिले यहीं एक्ट उस टाउनके लिये प्रयोग किया जाता था। अब प्रेसीडेन्सी टाउनस इन्सलवेन्सी एक्ट उस टाउन (Town) के लिये लागू है। इसी प्रकार संशोधनके अनुसार अदालत दिवालिया फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेटके पास इस एक्टके अनुसार किये हुए जुर्माना इस्त-

भासा भेज सकती है पहिले वह स्वयं उन जुर्मोंकी सुनती थी और इधर भी बहुतसे संशोधन हुए हैं जिनका हवाला इस पुस्तकमें यथा स्थान दिया गया है ।

प्रेसीडेन्सी टाउन्स इन्साल्वेन्सी एक्ट (एक्ट ३ सन १६०६ ई०) केवल प्रेसीडेन्सी टाउन्स (कलकत्ता, बम्बई व मदरास), रंगून व कराचीके लिये लागू है इस एक्टसे पहिले इसके स्थान पर दि इण्डियन इन्साल्वेन्ट एक्ट सन १८४८ [Indian Insolvent Act 1848, (11 & 12 Vic. C. 21)] लागू था परन्तु वह एक्ट केवल प्रेसीडेन्सी टाउन्स व रंगूनके लिये लागू था । यह एक्ट अर्थात् एक्ट ३ सन १६०६ ई० भी केवल इन्हीं शहरोंके लिये लागू था । परन्तु सन १६२६ ई० के संशोधनके अनुसार इस एक्टका प्रयोग कराची शहरके लिये भी किया जाने लगा है । प्रान्तिक कानून दिवालियाके अनुसार प्रेसीडेन्सी टाउन्स कानून दिवालियामें भी संशोधन हुए हैं जिनका हवाला इस पुस्तकमें यथा स्थान दे दिया गया है ।

जहां तक हो सका है इस पुस्तकमें कानून दिवालिया सम्बन्धी सभी बातों पर प्रकाश डालनेका प्रयत्न किया गया है । प्रान्तिक कानून दिवालिया (एक्ट ४ सन १६२० ई०) अर्थात् पहिले भागके अन्तमें कुछ नमूने भी दे दिये हैं जिनके अनुसार दिवालियेकी कार्यवाईके सम्बन्धमें दूरवार्ते दी जा सकती हैं । नमूनोंके अतिरिक्त कानून दिवालियाके सम्बन्धमें बनाये हुए भिन्न भिन्न हाईकोर्टोंके नियम भी लिख दिये गये हैं । इस पुस्तकको पढ़ कर कर्जदार अधिक कर्ज हो जाने पर अपनी रक्षाका विधान कर सकता है तथा इसी प्रकार कर्जप्राप्त भी दिवालिया कर्जदार से अपना कर्ज वसूल करनेके तरीकोंका प्रयोग कर सकता है, धोखादेहीसे किये हुए सौदोंको रद्द करा सकता है, किसी कर्जदारको दिवालिया करार दिला सकता है तथा भोखेबाज़ दिवालियों को अदालत द्वारा सज़ा दिया सकता है और उनको हमेशाके लिये दिवालियेके गहमें डकेल सकता है ।

आशा है कि पाठकगण इस पुस्तकको अपश्य अपनायेंगे जिससे लेखक व प्रकाशक अन्य कानूनी अर्थोंको भी इसी प्रकार उनके सम्मुख रखनेका प्रयत्न कर सकें । जो त्रुटियां पुस्तकमें रह गई हों पाठकगण उन्हें भी बतलाने की कृपा करें जिससे वह आनन्द सुधारी जा सकें ।

निवेदक:—

रूपकिशोर टण्डन

विषय	पेज
—गैजमे काम दिवालियाके काम नहीं है—१ ...	१३
—कौशदासे जब अपने महाजन या उनके एजेन्टों से सूचना दी हो कि मैं दिवालिया हूँ	१३
—जब मालभन्ने माल खरीद जावे और उसे बेच कर दूसरा बर्तन खरीदा गया हो	१३
—जब कौशदासे मजूर किया है कि कुछ देना कर्ज देना है मगर उन वक्त अंगुष्ठान नहीं दे सकता है ...	१३
—गैजमे काम दिवालियाके काम है—१ ...	१४
—जब कौशदासे सब जायदाद दूसरे किसी को दे दी हो नि वह उसका सब कर्ज चुका देता है ...	१४
—जब कौशदासे दिवालिया बननेकी अर्जी दी हो और वह बड़े अर्जी खासि न हो गई हो	१४
—कौशदाके दरखवास्त देनेके तीन महीनेके अन्दर कौशदासे यह प्रकट किया हो कि वह कर्ज नहीं चुका सकता	१४
—दुष्टियोंके सुपुर्दे जायदादना किया जाना ...	१४
—कौशदाके अपनी जायदाद इस इशारे से दे दी कि उसमें कौशदाके लाभ न उठा सके	१४
—एक कौशदाको दूसरे कौशदाके मुराबिमें फायदा पहुँचाया हो	१५
—दिवालिया पर उस अदालतमें दरखास्त दिवालिया बनने की दी जायगी अगर वह इशारा हो या धनका कस्ता हो	१५
—कौशदा अपनी जायदाद चला जावे, छिन्न जावे, भग जावे या निर्यात भास्ते चला जावे	१५
—इशारा, भागना, छिन्न आदि हम मशयसे हैं कि कौशदाका कर्ज मारा जावे या देह बसूरतमें हो ...	१५
—कौशदासे बहीखाता, दिवालियाके इशारा दिया हो और कोई बड़ा रकम दे दी हो	१५
—जब कौशदा नाम लाने और एक बड़े मुराबि कर जावे कि महाजन उस वक़्तसे कर्ज ले	१५
—पाहली अर्जी दिवालिया बनानेकी अगर खासि हो जाय तो दूसरी अर्जी दूसरी कोई रकम नहीं देना	१५
—किसी कर्जका डिफेंस कौशदाकी जायदाद विन्याय तो माय जायगा कि वह दिवालियाका काम है	१५
—जब शागवत नाराज हो और एक आदमीकी जायदाद डिफेंसमें बिने तो दूसरे डिफेंसदा दिवालिया न माने जायगे	१५
—जब कौशदासे दिवालिया बननेका अर्जी दी और वह नामाज हो गया तो वह उरुन फिर दी तो यह काम दिवालिया का काम समझा जासकता है	१५
—कौशदा अपने किसी कर्जखाताकी जब नोटिससे उसने कर्ज देना बन्द कर दिया है	१५
—एक शागवतसे ऐसा नोटिस देने पर कि वह कर्ज नहीं चुका सकता तो दूसरे शागवतों पर असर नहीं पड़ेगा	१५
—कौशदाके मुताबिक या एजेन्ट का किया हुआ काम कौशदाकी हिफाजत हुआ काम समझा जायगा	१५
—सुधीय या एजेन्टका काम उसी वक्त कर्ज का पान्डा करेगा जब उसने अपने अधिकारके अन्दर काम किया हो	१५
७ दरखास्त और दिवालिया करार दिया जाना ...	१५
—कौशदा और कौशदाके दावा की आवज पर कि दिवालिया करार दिये जाने की अर्जी दे सके	१५
—दिवालियाकी अर्जी देनेसे पहिले कोई नया काम दिवालिया पर कर होना चाहिये	१५
—अब कौशदाकी रकम १० और १० में उन जतोंस निक दे गिनता ध्यान अर्जी देते समय रखना चाहिये	१५
—जौरवाद सिर्फ अर्ज कौशदा पर अर्जी दे सकता है कौशदाके वासि पर नहीं दे सकता	१५
—जब कौशदा की दिवालिया बनानेकी अर्जी दी गई हो और वह मर गया हो तो अर्जी खासि न होगी	१५
८ रुमा आदिक दिवालिया की फाईदाईसे बरी होना	१५
—रुमाके जुदा समा या कर्जानेके सिर्फ दिवालिया बनने की अर्जी नहीं दी जासकती	१५
—एगोविशुन, कर्जानेके आद कर्जाने या फाक	१५

क्षम	विषय	पृष्ठ
—	—बिबी फर्मके खिलाफ दिवालिया अर्जी श्री जासखा इ १९	१९
—	—नावालिग, निवालिग करार मही दिशा जासखा १९	१९
—	—शामिल शासक हिंदू कुटुम्बक जेव वालिग इहरमदार निवालिग बनाने गये हैं तो नावालिगकी जायदाद रिहीवर अपन कजम नहीं गेया १९	१९
६	कर्जद्वाराके दरखास्त देने की शर्तें १९	१९
—	—ऊपर दस्ता ६ में बताप हुए कामम स कर्जदारने कोई एक काम छ कामक अदर किया हा ... २०	२०
—	—कर्जदारने याना अजा देने वात हा कर्जी ५००) रुपयम कम न हो ... २०	२०
—	—कर्जदारन १० कर्जद्वाराक कजत २ कर १००० हा तो अदागत स दामदका तय कर द ॥ ... २०	२०
—	—पाइल जगलन गढ़ जाव करी कि कर्जदारहा कज ५००) ६० या जायक है या नहीं ... २०	२०
—	—इज अमला हाना चाहिये और उसरी जिम्मादार कर्जदार पर हाना चाहिये २०	२०
—	—नव कज किमा सामिल कामक हिंदू गामवा पर ने ता अदरकालय कोई व्यापक इवाक्या बनाना जासकताह २०	२०
—	—कर्जद्वाराक लिय जल्दी नहा इ कि नहा इवाक्याया हुकम हान तर कजगव न बना रहे २०, २१	२०, २१
—	—अगर कर्ज वसूल बनन लिय दावा किया जातुग हो तो भी उस कजक आधार पर दिवालियेका अजा दा जासखा २०	२०
—	—एक या बहु एक मिलकर कर्जद्वारा, कजदारकी दिवालिया बनानकी दरखास्त द सनते हैं .. २०	२०
—	—नव कजक पानके कई एक इकदार हैं ता उभेस एव दिवालिया बनाने की अर्जी नहीं द सनता २०	२०
—	—न कोरी तादाद खास आर नय का हुई तादाद हाना चाहिये ... २१	२१
—	—इजेका रजमका कर्जी १०० मानकर दिवालियेका अर्जी नहीं दा जासकता .. २१	२१
—	—कर्जद्वारा, दिवालियेक जस कामके आधार पर अर्जी दे वह काम अर्जी देनेकी तागिलस ३ मासके अदर हाना चाहिये .. २१	२१
—	—अगर अर्जी गजत अदालतमें दा गई हा तो सही अदालतमें अजा दनक लिय वह मियार नहीं मिलेगा २१	२१
—	—सर्वेक्षण या कम्पनी कर्जदारका दिवालिया बनानक लिय अर्जी द सकता इ ... २१	२१
—	—अर्जी दिवालियेके काम या कामा बा पूरा निक होना चाहिये चलताऊ न हाना चाहिये ... २२	२२
—	—चाह दूसरे बहुतस काम दिवालियेक इलाय गय हैं मगर इस कजूनके एक भा न हो ता अर्जी नहीं चलगा २२	२२
—	—मइकून कर्जद्वारा भा दिवालिया बनानकी अजा द सकता है मगर च द शर्तोंक साथ २२	२२
१०	वद शर्तें जय कि कर्जदार दिवालिय की दरखास्त दे सकता है ... २२	२२
—	—प्रमाण सा सजमे चाह वह इवाक्या कया इदा गया हा तो भायद नया उगम लागू हाया २३	२३
—	—कर्जदार इवालिया बननक अजा उस दशम दे सकता है जब वह कज अदा न कर सकता हा .. २३	२३
—	—१० कजदारके कज ५००) स कम न हा और उकी वद अजा न कर पाता हा .. २३	२३
—	—नव कजदार किमा डिफामें गिणवार हो गया हो आर इकरा का रुपया अजा न कर सकता हो .. २३, २४	२३, २४
—	—नव डिफामें कजदारका जयदाद चुक हा गई हा आर वह अजा न कर सकता हा .. २३	२३
—	—कजदारकी एहा अजा नेक गायतम और मचा हना चाहिये नामापन फायगा उठानक ठिय न हा .. २३	२३
—	—कर्जदारका पावना, कर्जेस बादा हा ता अदालत दिवालिया नहा बनानकी .. २३	२३

दफा	विषय	पन्ना
—	जजदार जब गिफतार किया गया हा और छेड़ दिया गया हा ता वह दिवाणिया बननी अता नहीं दे सकता	२३
—	शाहिलदारीक पावनाम भाप आर दा लडकोंके हान पर दिवाणिया बननका प्रश्न	२४
११	वह अदालत अहा दिवाणिया की दरखास्तें दी जावें	२५
—	अनी दिवाणिया की वहा दी जायगी अहा पर जजदार उपादा तर रहता हो उस जगहका अदालतमें	२५
—	दिवाणिलयनी अजा वहा भी दा जायगा जहा कजदार व्यापार करता हो	२५
—	जहा पर कजदार गारफ्तार हुआ हो वहा का अदालत भा दिवाणियाका अनी दा जायगी	२५
—	नन कि गलत अगलतमें आग पेश की गई हा ता उअ बहुत अरद करना जरूरी है	२५
१२	दरखास्तकी तस्दीक	२७
—	ज वहा दाव नीकी ताह दिवाणियाका अनी का भा तरदाक का जायगा	२७
१३	दरखास्तमें दिखताई आने वाली बातें	२७
—	उन कर्जदार कजारा जुगता न दे सकता हा तब वह दिवाणियाका अजा दे सकता है	२८
—	सय कजदक रखना बताया जो कजदारक निम्न न का हा वह कजा समझा जायगा	२९
—	अनीम कजरावाहा ने नाम व उनका पना व कर्जा आद साफ साफ बताना चाहिये	२९
—	कर्जदारको अपनी सब जायदाद व लइना व प्राबाड ड फण आदि बताना चाहिये	२९
—	अनी देनक बाद दिवाणियाकी सब जायदाद रसमवरक सिधुर हा ताब ता	२९
—	मुदलखड लण्ड एलनशा एकर व प्राविड ड फड एक्की जायदाद कूक व नालम न हो ही	२९
—	दिवाणिलयका दरखास्तके अनी तान बात निहायन अरी है, स्थान, काम, आर कर्ज	३०
१४	दरखास्तका वापिस लिया जाना	३०
—	अनी देनक बाद, फिर वाई बिना अदालतका आह्राके अनी वापिस नहीं ल सकता	३०
—	जब सब मामल तर हा गये हो तो भा अदालतकी अधिकार है कि अनी वापिस न देके	३०
१५	कई दरखास्तों देने में अदालतका अधिकार	३०
—	वह कर्जदारान दिवाणिया करार दनी दरखास्तें दा हो तो वे सब साथही सुनी जावगी	३१
—	शामिल स। क। इ. दू आनदानके खिलफ उरी समय दिवाणिलयकी दरखानत दा जायगा जब शागिल	३१
—	श। क। उस प्रकारके काम हो	३१
१६	कार्रवाईका तर्न बदलनका अधिकार	३१
—	अगलतका अधिकार दूसरका व तस्वाह मान लेनका जब बसका तर्न (पृ. ५०) नो स कम न हो	३१
—	कजरावाह दरनारत देने न बाद अगर इवा लिखे भिन्न जाव तो अदालतके अधिकार	३१
—	जब कर्जदारान अता देने के बाद परकी करना छड दिया हा	३१
१७	कर्जदारके मर जाने पर कार्रवाईका खाल रहना	३२
—	दिवाणिलयकी कार्रवाई खतम हुनस पहिल अगर कर्जदार मर जाव तो उसके लम्के अपना हक नहीं प्राप्त सकते	३२
—	कजदारक मर जान पर भा उस अदालत दिवाणिया करार द सुनता ह	३२

पृष्ठ	विषय	पेज
१८१	१८ दरखास्तोंके तनेका तरीका	३२
	—दावाना अदालतमें जिस तरह अर्जी दाव लिये जाने है उसी तरह दिवालिया की अर्जी भी ली जायगी	३२
१८२	१९ दरखास्तें ली जानेके बाद की कार्यवाई	३२
	—अर्जी छन के बाद अदालत उसके सुन जानके लिये कोई तारीख नियत करेगी	३३
	—नियत की हुई तारीख का सूचना कर्जदारानको दी जाना चाहिये	३३
	—टाक द्वारा खिराईमें भी एसी सूचना अदालत भन सकती है, जहाँ तार पर तारीख होना जरूरी नहीं है	३३
	—कर्जदारको इस सूचनाकी तारीख उसी प्रकार होना चाहिये जसे दीवानाके समनकी होती है	३३
	—कर्जदारका बिना नामित पहुँच जो कार्यवाई की जाय सब बेकारवा होगी व मसूल हो जायगी	३३
२०	२० दरमियानी रिस्वीयरको नियुक्ति	३४
	—दिवालियाकी जयदाद पर पान चम्पा हर लेखक अधिवार अदालतकी प्राप्त है	३४
	—अगर कर्जदार द्वारा अर्जी दा गई है तो दायमिया रिस्वीवर जम्बू नियुक्त किया जाना चाहिये	३४
	—दरमियानी रिस्वीवर अधिवार नहीं होगा जा जाला रावाना द्वारा नियत किया हुए रिस्वीवरके हात है	३४
२१	२१ कर्जदारके खिलाफ दरमियानी कार्यवाई	३५
	—जमानत दिवालियेसे ली जायगी अगर अदालत उसे उचित समझे	३५
	—दिवालिया बराबर दिये जावेते पहले जमाना दावानाके अनुसार समधी जायदाद हुई हो सकती है	३५
	—जा जाले दूसर कानूनस हुई व बीलाम नहीं हो सकती व इस कानूनसे भी न होगी	३५
	—प्राइमेट फंड हुई व मोडम नो किया जासकता	३५
	—कर्जदारका गिरफ्तार कर लेन व छेड देने व जमानत पर रिहा कर देनका अधिवार अदालतकी है	३५
२२	२२ कर्जदारके कर्तव्य	३६
	—वहा जमाना सब, दिवालिया की अर्जिन सापटी अदालतमें दायित कर देना जरूरी है	३६
	—पेइसिड व उदनाम चिहा व कर्जी अर्जिड सब दाखिल करना चाहिये	३६
	—बही छाता व मिसाव दाखिल करनेके बाद भी दिवालियाकी रिस्वीवर या अदालतके हुक्म पर हाजिर होना चाहिये	३६
	—दिवालिया अदालत निर्माण २०० सालसे ब्यादा भी जायदाद आदक जल्दके लिये तल्प कर सकता है	३६
	—दिवालियाको चाहिये कि रिस्वीवरको, मरदद, सब समझाव, वार नह जा जाइ उस मरद करे	३६
	—अगर कर्जदार, दिवालिया, रिस्वीवर अदालतके हुक्मका न मान ता गवा होगी	३६
२३	२३ कर्जदारकी रिहाई (लुटफर)	३७
	—विभी लिखमें मि फार कर्जदारको अदालत छोड सकता है या दूसरा हुक्म दे सकता है	३८
	—अगला डिगरे गिरफ्तार कर्जके जल, दिवालियाका भेज सकता है	३८
२४	२४ दरखास्तके सुन जानका तरीका	३८
	—अदालत पहले यह देखगी कि सायलज अर्जे देनेका हक है का न ?	३९
	—अर्जा फेर होनेके समय अगर कर्जदार दिवालिया मासुद हो तो अदालत उसका कमान जबर लेवे	४०
	—कर्जदारका बरान छनका उदरा यह है कि बहुत जल्द दिवालियाका जायदाद अदालतको मादम हो जाय	४०

दफा	विषय	पेज
—	अगर कर्मदारका लहना कर्जे क्यादा हो तो भी कर्जा चुकानेकी अवसर्यता कही जासकेगी ...	४०
—	अदालत सरसरी जाय करेगी, पूरी तोरसे नामक जाय करने की जरूरत नहीं है ...	४०
—	अदालत, दिवालिया हो जायदुर्की कीमत कायदा पर ध्यान रखेगी और देनेकी कि उससे कर्जे चुकाये जायकेमे? ...	४०
—	कर्जे सही माने जायगे जब तक वे कर्जों न साबित हो जावें ...	४१
२५	दरखास्तका होना ...	४१
—	नायत दिवालियेकी उस समय देखी जायगी जब उसके पहाल होनेका हुक्म होने वाला हो ...	४१
—	दिवालिया अगर दते समय, दिवालियेकी नीयत क्या थी यह देखना जरूरी नहीं है ...	४१
—	जब अर्जों खारिज की जाय तो अदालत सब कारण हुक्ममें लिख देगी ...	४२
—	दिवालियाकी अर्जों सिन सिन कारणोंमे खारिज हो जायगी ई उनका खोरा ...	४२
—	दिवालियेकी अर्जों देनेके बाद जब कर्तदारने किसीको कथा सुनाया हो तो हर्जा नहीं पड़ सकता ...	४३
२६	हजेका मिलना ...	४३
—	कर्जदारका दावा दी हुई अर्जों खारिज हो जाने पर (१०००) रु० तक हरना कर्जदारको मिल सकता है ...	४४
—	हार्ड रोड में इस दफ्तारी अंगीकृत करेगी ...	४४
२७	दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म ...	४४
—	अगर दरखास्त दिवालिया खारिज न हो तो अदालत जरूर दिवालिया करार देगी ...	४४
—	मोहूरतर्फी अर्जों दी जासकती है कि तारीख आगे बढ़ा दी जाय ...	४५
—	अदालतका कर्तव्य है कि दिवालिया करार देने पर पहाल होनेकी तारीख जरूर बना देने ...	४५
२८	दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मका असर ...	४५
—	दिवालिया करार दिये जाने पर उज्जदार सब कर्जोंसे मुक्त हो जाता है अगर जेलमे नहीं होता ...	४५
—	सब जायदाद कर्जदारकी रिसीवरके जिम्मे पूरी तोरसे हो जायगी और उसमें कर्जा भरा जायगा ...	४६
—	कोई छद्मदार कुछ भी कर्जावाँ न कर सकेगा ...	४६
—	हिस्ती कर्मेके दिवालिया करार देने पर उस कर्मेके सब साक्षीदार दिवालिया माने जायगे ...	४६
—	दिवालियाका हुक्म होने पर टिकीदार कर्जदारको अदालतकी इनायतसे गिरफ्तार न वेद रखा सकता है ...	४७
—	सामिलदगीक दि दू कुटुम्बके वालिय मेम्बरोंके दिवालिया होने पर उनके हक रिसीवरको प्राप्त हो जाने हैं ...	४७
—	दिवालिया बन जाने पर कर्जदार किसी महानको कथा नहीं दे सकता रिसीवर दे सकता है ...	४७
—	जन किसी कर्मेके कुछ हिस्सेदार दिवालिया हों तो रिसीवरको यह हक नहीं है कि उस कर्मे का जायदाद पर अनेके सबकी तरफसे कब्जा करे ...	४७
—	मिताधारार्थ के दि दू परिवारके पितके दिवालिया होने पर उसके लडकों की जायदाद भी पाबन्द होती है और रिसीवरके कब्जेमे दी जा सकती है ...	४८
—	शामिलदगीक कुटुम्बके मेम्बरोंके दिवालिया होनेकी सूखनेमें रिसीवरके हक व अधिकार ...	४८
—	मालखानाके दिवालिया होने पर उसकी सारी जमीन रिसीवरके कब्जेमे जावेगी अगर मौसली कायद नहीं जावेगी ...	४८
—	हरामी या रेलवे प्रायोजक कब्जकी रकम पर दिवालिया ना कोई असर नहीं पड़ता ...	४८/४९

दण	विषय	पंज
—	आपस देनेकी एवढे अवकाश दयावा ताका हो सका है	१८
—	चर दिवा लेने आने कहींको बिभी हमेंको दे दिया हो तो हम पर सिरेवरता हक नहीं रहता	४१
—	आगर अगर दिवाले घने किमी हक दे दिवें हो आर कसना न किया हा तो दे दिवालेके नमस्त जदिये	४१
—	दिवाले को देनेके बाद वज्रदारकी अमदनी या नमस्तहके किमा रिम्वेको रिम्वे मे सवना है	४२
—	जा जायदाद कानूनमे कुर्क नहीं हो सवनी वद दिवालेके भी न होगी	४२
—	मुद्राखण्डमे जगजग देका कानो की अमदनी कुर्क नहीं हो सवनी तो हम कानूनमे भी न होगी	४२
—	वृत्त वज्रदार पर हम देकावा अदर नहीं पटना वद अपना ररवा दल्ल वर सवना है	४२
—	असा रिप जाम की हारमिय दिवालेका माना जाइगा	४३

२६ बाबू कारवाइयो का मेका जाना ... ४२

—	जिनकी अदायगीमे कोई मामला दिवालेका पर या दिवालेकी तरफमे दल्ला होगा सब वद हो जदिये	४०
—	वज्रदार अगर चाह तो अपना माना पाट आर रख सकना है	४०
—	वृत्त वज्रदारमे लक्ष्मीर या अद्विष्टमे रिम्वेकर फाँक मुकदमा बनाया जाना चाहिये	४०
—	देकावादी आपदारके खीरको सब हक सगे दी हुई वाददामे न पेश होना	४०
—	दुसरा दिवालेका कर्तार है उमरान न वद होनी उवादवालेमान अजी दी होमगर कतर न दिया गया हो	४१

२७ दिवालिया करार देने वालें हुक्मकी मुदतदारी ... ४१

—	दिवालेका करार दिवें जलें पर तरफकी चमकेमे नाम, पना, देश, मवाशि रिवा जाइगा	४१
---	--	----

दिवालिया करार दिये जानेके बादको कारवाइ

२८ दिवालियेकी रदाका हुक्म ... ४१

—	पाइके कानूनमे दिवालेका करार देने हो वज्रदार जेल्लजमे बने हो जवा या पर अर नहीं होना	४२
—	वज्रदारको जेल्ले बचनेके लिये दुपग अजी विपारके अदर देना चाहनी है	४२
—	जब तक वज्रदार दिवालेका करार न दिया जाय तब तक जेल्ले हुक्मकी अजी नहीं दे सकना	४२
—	अदालत मजदूर को है कि वज्रदारको जेल्लेजमे बचनेका हुक्म जेल्ले दी दे	४२
—	वेददामे को पूरा हक है कि वज्रदारको जेल्ले हुक्मकी अजी को अजी पर उमर करे, सुदूर है	४२
—	मरकासी वज्रके लिये जेल्ले हुक्मकी वज्रदपका हजिज नहीं होगी	४२

२९ दिवालिया करार दिये जानेके बाद गिरफ्तारीके अधिकार ... ४२

—	दिवालेका करार देनेके बाद अर जेल्ले रदाका हुक्म देनेमे चले जेल्ले वज्रदारी गिरफ्तार कर सकनी है	४२
—	अदालतको अधिकार है कि वज्रदारको ३ मय जेल्ले रसे	४२

३० कर्तारजाहकी सूची ... ४२

—	जेल्लेदामे असा कजी हम बल नी सवित वर सूची जव दिवालेका हुक्म हो जल	४२
—	वज्रदारकी सूची तय्य करना अदालतका कर्तार है	४४
—	सूची वज्रदारको को कप तय्यार होगी जलमे क्या रिखा जायगा, वद बनेकी, वद वददेशा है	४४

दफा	विषय	पृष्ठ
—	अगर किसी का कोई कर्ज साबित करनेसे छूट गया हो तो वह भी सचिवन किया जा सकता है ...	५४
—	सब कर्जों कर्जदारके बहाल (जल्द से छूटने) होने तक सूचीमें दर्ज हो जाना चाहती है ...	५४
—	अगर कोई जमानदार दूसरे लहेनदारका कर्ज भन्त भगाय तो अज्ञान्त इस मामलेको तय कर देगी ...	५४
—	अगर कोई कर्जम्बदाह मर जाये तो उसके वारिसों को नोटिस दिया जाना चाहिये ...	५५
३४	यह कर्ज जो इस एक्टके अनुसार साबित किये जासकते हैं ...	५५
—	वे कर्ज नहीं दिलाये जायग जिनकी कीमत वा अदामा अदालत नहीं लगा सकती ...	५६
—	लहेनदारोंके कर्जें नहीं माने जायगे जो जलसे छुटता पानेसे पहिले साबित कर दिये गये हों ...	५६

दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी मंजूरी

३५	दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी मंजूरीके अधिकृतपाठ ...	५६
—	जब अदालतकी सभमें दिवालिया करार न दिया जाना चाहिये ...	५७
—	जब सब कर्जें पूरे पूरे बहालन लेहनदारों को चुका दिये जायें ...	५७
—	दिवालिया करार देनेके हुक्मकी ममूखी की दस्तावेज कर्जदार खुद भी दे सकता है ...	५७
—	अगर कर्जदारने लेहनदारोंको बांधाई अदि कर्जों चुकाना मजूर किया हो तो हुक्म मसूख दहोगा ...	५७
—	कर्जदारके कर्जें दूसरा आदर्श भी अदा कर सकता है, यह जरूरी नहीं है कि कर्जदार ही अदा करे ...	५८
३६	एक साथ दिये हुए दो दिवालियोंके हुक्मकी मंजूरी करनेका अधिकार ...	५८
—	जब दूसरी अदालतमें दिवालियोंकी कार्रवाई चलती हो तो एक अदालत बन्द कर देगी ...	५८
—	कर्जदारके कर्जोंके बटनमें जहासे सद्बिचय हो वहा पर कार्रवाई होना चाहिये ...	५८
३७	मंजूरीके याचकी कार्रवाई ...	५९
—	कर्जदारको समझी जायदार कय वापिस मिल जायेगी ...	५९
—	बहालकी दस्तावेज न देने पर दिवालियोंके हुक्मकी ममूखी होना ...	५९
—	ममूखीके हुक्म कार्रवाई गमरमें प्रकाशित किया जायगा ...	६०

तस्फीया तथा तय करनेका तरीका

३८	तस्फीया तथा तय करनेका तरीका ...	६०
—	कर्जदार अपने लेहनदारोंसे तस्फीया कर सकता है कि वे कम कया लेकर पूरे कर्जोंकी भुगतान कर दें ...	६१
—	कर्जदारों की मांदिगी जायगी और जो तीन चौपाईसे कम न हों या उनके प्रतिनिधि हों ...	६१
—	जिस कर्जदारकी सूचना न मिली हो वह मांदिगीकी कार्रवाईका पाबन्द न होगा ...	६१
—	कर्जदारोंकी मांदिगीमें वही शर्त होगी कि जिनक कर्जें सूचीमें दर्ज हो चुके हैं ...	६१
—	कर्जदारने जब रिहाइसे छिटाकर किसी लेहनदारको रुपया दिया हो तो क्या फल होगा ...	६२
३९	मंजूर करने पर हुक्म ...	६२
—	तमकालमें कार्रवाई कर्जें कर्जदारों पर जाएंगे होगी जिनका कर्ज सूचीमें दर्ज हो चुका है ...	६२

वक्र	विषय	पेज
४०	कर्जदारको फिर दिवालिया करार देनेका अधिकार	६२
	—समझतेके मुताबिक किसी अदायगी ठीक तौर पर न हो या घोस दिया गया हो	६३
बहाल होना (जेलखानेसे छुटकारा पाना)		
४१	बहाल होना	६३
	—किसी मियाद तक अदालत बहाल होनेका हुक्म मुकदमी कर सकती है	६४
	—जेलखानेसे रखाका हुक्म अदालत बहुत सोच समझ कर देगी	६४
	—अदालत बहाल होनेमें शर्तें लगा सकती है जिससे कर्जदारका आमदनी, आगे भी लड़नेदारोंका धंदा जाय	६४
४२	पूर्ण रूपसे बहाल होनेका हुक्म अदालत द्वारा न दिये जानेके कारण	६४
	—जब लड़नेमें आधा बर्जों भी न सुनाया जासकता हो	६५
	—हिसाब किताब कर्जदार ने न रखा हो या ठीक न रखा हो	६५
	—रिहानते कर्जदारके व्यवहार, खाल चलन आदिक बारेमें खराब रिपोर्ट दी हो	६५
४३	बहालकी दरखास्त दिये जाने पर दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी संसूची	६६
	—कर्जदारका इजाजत लेकर इस हुक्मकी अपील कर सकता है	६७
४४	बहाल होनेके हुक्मका असर	६७
	—बहाल होनेसे कर्जदार उन सब बर्जोंसे छूट जावेगा जो सूचीमें दर्ज हो चुके होंगे	६८

तीसरा प्रकरण

कर्जोंके साधित करनेका तरीका (जायदादका प्रबन्ध)

४५	आश्चर्या अदा होने वाले कर्ज	६९
	—जब कोई बर्ज आयन्दा वागिजगल् अदा हो तो वह पहिले ही हाविन हो जायगा	६९
४६	आपसका ब्योहार से मुजरार	६९
	—अगर दिवालिया और महाजन दोनोंम एकदूमेसे लेना देना हो तो मुजरार होकर रकम निश्चित न होगी	६९
	—हिसाब होनेके बाद रकमकी मुजरार होगी, पहिले नहीं	७०
	—दोनोंके हिसाब प्रग्या देने पर जिसके किये बाकी निचले वह उस रकमका देनदार होगा	७०
४७	महफूज कर्जखाना	७०
	—जब किसी चीज की जमानत पर बंधा दिया गया हो तो वह बंधा पूरा मिलेगा	७१
	—जब कि कुछ बंधा जमानत पर हो कुछ न हो तो बंधा हालत होगी	७१
	—जमानतसे ज्यादा बंधा जब लड़ना निश्चय हो तो साधित करना होगा	७१
	—महफूज कर्जदार जमानत ठीक तौर पर दे, उसकी हानि पर निर्भर है	७१

क्रमा	विषय	पेज
४८ सूद (ब्याज)	...	७१
—जब सूद की दर ठहरी न हो तो	६) रुपया सेवक सालाना की दरसे सूद लगाया जायगा	७२
—सूद, दिवालिया करार दिये जानेके हुक्मना तारीख तक दिलाया जायगा	...	७२
—पहिले सूद तय न हुआ हो पीछे नोटिस दी गई हो तो नोटिस लिखी हुई होना चाहिये	...	७२
—परफूट करीबना ही सूद, कर्जा वसूल होनेकी तारीख तक मिल सकेगा	...	७२
४९ साक्षित करनेका तरीका	...	७२
—करी किस प्रकार साक्षित करना चाहिये उसका तरीका	...	७३
—जैसे दूसरे कहे साक्षित किये जाते हैं वैसे यह भी होंगे	...	७३
—इच्छानामोंके द्वारा कर्जों का तफ्तील आदि दाखिल करके कर्जा साबित हो सकता है	...	७३
—वह कागजात या बहोखाता पेश होंगे जिनसे कर्जा साबित होता हो	...	७३
५० सूचीके इन्तख़ाबको नामंजूर करना या घटाना	...	७३
—अदालतका अधिकार है कि सूचीके कर्जों को हटा सके, बदल सके आदि	...	७३

पहिले किये हुए सौदों या कार्रवाईयों पर दिवालिया असर

५१ इजरायमें कर्तव्याधानके हकमें रुकावट	...	७४
—दिवालियेकी अर्जों देनेके बाद उसकी जायदाद एक आदमी दीनार न करा सकेगा	...	७४
—दीनार चाहे हो गया हो मगर रुपया चाहेमें वसूल होगा तो वह रसीदवरना होगा	...	७५
—जसदातल १ रुपया दे दिया पीछे दिवालियाकी अर्ज दी गई तो सब रुपया रसीदवरके बचतेमें गया	...	७५
—रुपया कर्तव्याहरी मिलनेसे पहिले यदि दिवालियेकी अर्ज दी गई हो तो वह रुपया रसीदवरना है	...	७५
—जब खर्चदारको यह न मालूम हो कि वह दिवालियाकी जायदाद है और बेकसीयतीसे ले ली हो	...	७५
५२ जायदादके खिलाफ डिक्री इजराय करमें अदालतके कर्तव्य	...	७५
—दिवालियाकी जायदादसे सब कर्तव्याहरी लाम पहुंचानेका बदेश	...	७७
—अदालतको नोटिस मिलना तब तक जायदादको, जब दीनार किया जाय	...	७७
५३ अपने आप किये हुए सौदोंकी मंजूरी	...	७८
—दिवालियेके पहिलेके इन्तकायात्र जब किस दशामें मसूम हो सकेंगे	...	७८
—अदालतके अधिकारसे बाहरनी जायदादका इन्तकाल भी मसूम हो सकता है	...	७९
—गैर, जैसे, किस तरहके व रिम इन्तकाल मसूम होंगे	...	७९
—दो सालके अंदर किये हुए इन्तकाठ ही रहें हो सकेंगे	...	८०
—दो सालके मियाद अर्जों देनेकी तारीखसे न ली जायगी बल्कि हुक्ममें ली जायगी	...	८०
—कोई भी इन्तकाल उसी समय मसूम होगा जब दिवालियाकी कार्रवाई चलती हो	...	८१
—रसीदवर किसी इन्तकालके प्रश्नको तय नहीं कर सकता	...	८१
—इन्तकाल मसूम की कार्रवाई उससे तोरसे नहीं की जायगी	...	८१

पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
५४	कुछ मामलों की की हुई तरजीह की मंजूरी	८२
	—दिवालिया करार दिये जान बाल हुसमना असर पिछर सौदों पर क्या पड़ता है	८२
	—तीन महानेके सौदों पर असर पड़ता है इससे पहिलेके सौदों पर नहीं पड़ता	८२
	—वह कौनसे सौदे हैं जिन पर दिवालियाका असर पड़ता है	८२
	—कौन सातोंके पदा हानि पर छोड़े रद्द हो जायेंगे	८२
	—सौदोंके सम्बन्धमें दिवालिये की इजाजी जान करना जरूरी है	८३
	—सौदोंका मसूदा की अर्जी दिवालियाकी कार्रवाई खतम होनेसे पाहल द्य जायगी	८३
	—कौन सौदे फव नहीं मसूदा समझ जायेंगे	८४
	—जब दबाव या धारी या आगते कोई सौदा किया गया हो उसका असर	८४
	—जब कोई वाम पदा दिया गया हो जिसमें पूर ज़ादमीने लाभ होना हो दूसरको नहीं	८५
	—कर्मदारने जब न लिखत बचने और दशा छि नेके छिये जायदाद देहन कर दी हो	८५
	—गिठल कर्जें और कुछ रुपये दूसर दानाके बदल जब जायदाद देहन कराई गई हो	८६
	—नालपस जायदाद बचानका मतलब जब जायदाद देहन कर दी गई हो	८६
	—कर्मदारने मित्री कथा याद बिना सारमें दिया हो तो वह उसे बचपस वासकेगा	८६
	—कलेक्टरके कपरा खर्चके लिये जिस इजाजत पहिल जमा कर लिया जायगी	८६
	—साधोंके बारमें सत्यता परावर्त नहीं होगी बका जल्य की जायगी	८७
५४ (५)	मंजूरीकी दरखास्त कौन लोग दे सकते हैं	८७
	—सौदों की मसूदा कार्रवाई अर्जी कौन ९ लोग दिये तथा परिणाम	८७
५५	नकलीपतीले किये हुए सौदों की रक्षा	८८
	—कौन सौदे इस कानूनके अनुसार रद्द नहीं किय जायेंगे	८९
	—कैसे जोर कर वे सौदे रद्द न होंगे	८९

जायदादका बसूल करना

५६	रिसीदकी नियुक्ति	९०
	—दिवालिया की कार्रवाईके तैयारीमें अदालत रिसीदके नियम उसकी सब जायदाद दे दर्ती है	९०
	—रसायनक बचमें जायदादका हाना, अदालतक बचमें होना माना जायगा	९१
	—अदालतको अधिकार है कि किसी आदमी की भी रिसीद नियुक्त कर दे	९१
	—किसी कर्मध्याइका, दिवालियाकी जायदाद पर रिसीद नियुक्त न करना चाहिये	९१
	—जहा तक हो सम्मता बातोंके जानन बाला ही आदमी रिसीद नियुक्त किया जाय	९१
	—रसायनको अदालत न मानना चाहिये, वह अदालतका अधिकार मात्र है	९१
	—दुबानीके मामलोंमें नियुक्त किये हुए रिसीद और दिवालियाक रिसीदका अधिकारमें फरक है	९१
	—रिसादर द्वारा बची हुई जायदादने यरीदारको, वन हानि होगी और लाभ नहीं	९२
	—रिसादरमें अदालत जमानन से सहायी है जिसमें दाखिल क्या सहायी है	९२

दफा	विषय	पेज
	—रिसेवरकी फीस, कमीशन, तनखाह अदायत तय कर सकनी है ...	१२
	—दिवालियारा अर्जी खातिज ओ हो जावे तो भी रिसेवरकी वह फीस मिलेगी जो अदालतने तय की हो	१२
	—बन्धनमें ५) सैकड़ासे ज्यादा रिसेवरकी नहीं मिलता ...	१३
	—रिसेवरके अधिकार, वर्तव्य, जायदाद पर कब्जा आदिमा होना ...	१३
	—खराद काम करने पर रिसेवरको अदालत सजा दे सकती है ...	१३
५७	सरकारी रिसेवरको नियुक्त करनेके अधिकार ...	१४
	—आफिशियल रिसेवर बन, कैसे किस दशामें नियत किया जावेगा ...	१५
	—अधिकार, वर्तव्य, जायदाद पर कब्जा लेना, उसकी फीस आदि ...	१५
५८	अदालतके अधिकार जय कि रिसेवर नियुक्त न किया गया हो ...	१५
५९	रिसेवरके कर्तव्य व अधिकार ...	१६
	—रिसेवर मुकदम करेगा सबन, अधिकार, वर्तव्य, ओहदेस वर्धन ...	१७
	—जायदाद बेचना, समझौता करना, इन्तजाम करना, कर्जो वसूल करना, और नाकियों करना ...	१८
	—रिसेवर मुकदमामें, रिसे कर्जदार पर दावा कर सकता है ...	१९
६१ (ए)	दिवालिये की जायदादके सम्बन्धमें हाल दर्यास्त करनेके अधिकार ...	१००
	—गैर आदिमियोंक बन्धे की जायदाद, दस्तावेजात, बागजान आदिमा तलब करना ...	१०१
	—जब कोई शरय, तलब किया गया हो, न आवे या वह चीज शामिल न कर तो वाण्ट जारी होगा ...	१०१
	—जिस इस मतलबके लिये तलब किया जायगा उर्जो दिया जायगा ...	१०१
६०	गैर मनकूला जायदादके लिये खास नियम ...	१०१
	—मरकारि टैक्स देने वाली जायदाद या जमीन वास्तवी रिसेवर नहीं बेंच सकता है ...	१०२
	—अदालत तीन महीना पहिले निर्णय करेगी ...	१०२
	—कलक्टरके द्वारा चीज जायदाद किस कयदसे बेची जायगी ...	१०३
	—जब कि डिकरी किसी मुआहिदेके अनुसार नहीं दी गई है ...	१०३
	—डिकरीदारको नोटिस दिया जाना और उनको जो जायदादमा दावा करते हैं ...	१०३
	—डिकरीका पना खाना निश्चित करना और जायदाद गैरमनकूला मुहैया करना ...	१०३
	—जब जिले वा अदालतने नोटिस जारी कर दिया हो ...	१०४
	—अदालतमा फैसला करकेनके बीच एक प्रकयकी डिकरी समझा जायगा ...	१०४
	—कयया वसूला तरीका और बिचार जायदादको सुरक्षित रखत हुए ...	१०४
	—कलक्टरकी हिसाब देनेकी जिम्मेदारी अदालतकी ...	१०५
	—जायदाद बेचनेका तरीका और सल्लिखन तथा लाभ का ख्याल ...	१०६

तकसीम जायदाद

६१	कर्जोंका पेयतर चुकाया जाना	१०७
----	----------------------------	-----	-----	-----	-----

धारा	विषय	पेज
—	—दिवालयिके रीतों व जै पहिले चुकाने जायगे उसका वर्णन ...	१०७
—	—समाप्त न जाँ और उसके बाद २०) से कम कर्मचारियोंका व तें वास्ते चुकाना जायगा ...	१०७
—	—कौन कर्ज पूरे चुकाने जायगे और कौन कर्जोंमें हिस्सा रखना दिया जायगा . .	१०८
—	—यहाँ जा वसूल्दारोंमें पड़े हों कष्ट जिये जायगे तब सूद या बुझाया जायगा ...	१०८
६२	डिवीडेण्ड, हिस्सा रखदीका लगाया जाना ...	१०८
—	—कौन कर्जोंमें हिस्सा रखदी कय्या बाण जायगा, तर्फीका, कर्तव्य और अधिकार ...	१०९
६३	डिवीडेण्ड आहिर किये जानेसे पहिले जिस कर्जख्याहने कर्ज साधित नहीं किया है उसके हक ...	१०९
—	—जब लहनदारने, कय्या तबसीय करनेके बाद अपना कर्ज साधित किया हो तो उसे कुछ न मिलेगा ...	१०९
—	—जब लहनदारने, पहिले कय्या तबसीय होनेके बाद कर्ज साधित किया हो तो दूसरे बार उसे कय्या मिलेगा ...	१०९
—	—अगर लहनदारने देखे अपना कर्ज साधित किया तो उसका हक पाया नहीं जायगा ...	११०
६४	आखिरी डिवीडेण्ड ...	११०
—	—रिसीवरका कर्ज नोटिस देनेका उन लोगोंके विनय कर्ज साधित नहीं हुआ ...	११०
—	—आखिरी कय्या उन सबोंमें बाँटा जायगा जो बहनेके समय कर्जखानेकी सूचीमें दर्ज हो चुके हैं ...	११०
६५	डिवीडेण्डके लिये कोई शर्त नहीं हो सकती ...	१११
—	—अगर रिसीवर कय्या न दे और उसका नाम सूचीमें हो तो उसे अर्ज देने पर शर्त मिल जायगा ...	१११
६६	दिवालयिके द्वारा इन्तज़ाम और उसका मत्ता ...	१११
—	—कमेदार दिवालयिके भा उसकी जायदादका शब्द सुपुर्दे किया जायकना है ...	११२
—	—जो काम बार चलत हो उसे इदालिया कायम रख सकता है और प्रबंध कर सकता है ...	११२
—	—दिवालयिके प्रबंधते जो कय्या जमा होया या लाभ होया सब कर्जखानेमें बाँटा जायगा ...	११२
—	—दिवालयिके तनखा, या कमीशन अगलत दिशा छली है ...	११२
६७	यचे हुए दिवालयिके अधिकार ...	११२
—	—पूरा कर्ज, सूद, सबे सुधारे जाँके बाद जो कुछ बचे वह दिवालयिके भिन्न जायगा ...	११२
६७ (प)	जाँचकी कमेटी ...	११३
—	—रिसीवरके कामों को जाँचके लिये अगलत एक कमेटी नियत कर सकती है, व अधिकार ...	११३

रिसीवरके खिलाफ अदालतमें अपील

६८	रिसीवरके खिलाफ अदालतमें अपील ...	११४
—	—रिसीवरके बिना नाम या हुक्मसे किसीको हाजि पदवी हो वह उसकी अगलत अदालतमें कर सकता है ...	११४
—	—अरीदार नीलाम दिन सूचीमें अपील कर सकता है ...	११४

दफा	विषय	पेज
—	अपीलकी मियाद २१ दिनों की है इसके बाद रिस्तिनरके किसी काम या हुक्मकी अपील न होगी	११४
—	अदालतके हुक्मकी भी अपील दूसरी अदालतमें की जासकती है	११५
—	अगर किसीने २१ दिनोंके अन्दर अपील न की हो तो वह दीवानोंमें दावा दापर कर सकता है	११५
—	रिस्तिनर यदि किसीका बर्जो मजबू न करे तो वह अदालतमें अपील कर सकता है	११५
—	रिस्तिनर अगर दूसरे आदमी को जायदाद, दिवालिखारी जायदाद समझ कर ले ले	११६
—	दूसरे आदमी को जायदाद पर अगर रिस्तिनर कृपा कर लेवे	११६
—	इस दफाके अनुसार अपील करने पर उसे अलग दावा, दीवानोंमें दापर करनेका हक नहीं रहेगा	११६

चौथा प्रकरण

दण्ड (सजा)

६९	दिवालिएके जुर्म	११८
—	क्रायेदेके अनुसार काम न करने पर जो बर्जो है वे इस दफामें बताने गये हैं	११९
—	दिवालिएजान मूझ पर जायदाद पर कब्जा रिस्तिनरको न दिया हो या काम न किया हो	११९
—	जब कि बर्जोद्वारे धोखाधेने की नियतसे काम किये हों	११९
७०	दफा ६६ का जुर्म लगाने पर कार्रवाई	१२०
—	जब दफा ६९ के जुर्म दिवालिएने किये हों तो मजिस्ट्रेटके पास मुकदमा भेजा जायगा	१२१
७१	बहाल होने या तस्फीया हो जानेके बाद फौजदारी मामलोंकी ज़िम्मेदारी	१२२
—	दिवालिएकी अर्जी मजबू होने पर और बहाल होने पर भी वह सजा पायेगा अगर जुर्म दफा ६९ के हों	१२२
७२	बिला बहाल किया हुआ दिवालिया अगर कर्ज लेवे	१२३
—	दिवालिएदे ५० के अन्दा बर्जो किया हो बाद कि वह बहाल नहीं हुआ तो जुर्म है	१२३
—	ऐसा दशमें दिवालिया फौजदारी सिपुर्द निया जायगा और सजा होगी	१२४
७३	दिवालियेकी असुविधायें (रुकावटें)	१२४
—	कौन्सिलका मेम्बर नहीं हो सकता जब तक कि बहाल न हो गया हो-	१२५
—	नावालिखरी जायदादका बर्जो नहीं हो सकता, हो तो हथपा जायगा	१२५

पाँचवां प्रकरण

सरसरी कार्रवाई

७४	सरसरी कार्रवाई	१२६
—	छोटे २ मामले जल्द फैसल कर दिने जायेंगे ताकि दिवत न बढने पावे	१२६
—	५०० से कम कीमतमें जायदादके सम्बन्धमें ही सरसरी कार्रवाई की जासकेगी	१२७

दफा

विषय

पेज

छठवां प्रकरण

अपील

७५ अपीलें	१२८
—दिवाणिया अदालतके हुक्मकी अपीलें जिनकी अदालतमें सब हो सकती है	१२८
—जलदकी अदालतकी नियमनी हार्डकोर्टमें होगी जो शिड्यूल १ में बताई गई है	१२८
—जायदादीदानी की दफा १०० के अनुसार हार्डकोर्टमें अपीलें, व मापलोंकी निर्णयें	१२९, १३०, १३१

सातवां प्रकरण

विविध सुतफारिक

७६ खर्चा	१३४
—दिवाणियेकी जेज्जानिमें रखनका खर्चा दिहना अदालत पर निर्भर है	१३४
—दीवानी अदालतमें जिकीरकी खर्चा देना पड़ता है मगर दिवाणियामें नहीं देना पड़ेगा	१३४
७७ अदालतमें एक दूसरेको मदद देवंगी	१३४
—एक अदालत, दूसरी अदालतकी दिवाणियेके काम करनेका लिख सकती है	१३५
७८ मियाद	१३५
—अपील करनेकी मियादमें कानून मियादकी दफा ५११२ लागू होगी	१३५
७९ नियम बनानेके अधिकार	१३७
—भारत सरकारकी आज्ञासे कलकत्ता हार्डकोर्ट और स्वामी सरकारकी आज्ञासे अन्य हार्डकोर्ट नियम बना सकते हैं	१३७
८० सरकारी रिखीवरको अधिकारोंका दिया जाना	१३९
८१ प्रान्तिक सरकार द्वारा कुछ नियमोंका प्रयोग कुछ अदालतके लिये रोका जाना	१४०
८२ बचत (Savings)	१४०
८३ मंजूरी	१४१

सूची (शिड्यूल) और हार्डकोर्टोंके बनाये रूल्स

सूची नं० १ वह फैसले व हुक्म जिनकी अपील दफा ७५ (२) के अनुसार हार्डकोर्ट में हो सकती है	१४२
सूची नं० २ ऐक्टके वह नियम जिनका प्रयोग प्रान्तिक सरकार द्वारा रोका जासकता है	१४३
सूची नं० ३ यह सूची रिपीलिंग ऐक्ट सन् १६२७ ई के द्वारा हटा दी गई है	१४३

दफा

विषय

पेज

कलकत्ता हाईकोर्ट रूलर्स

कलकत्ता हाईकोर्टके बनाये हुए नियम कानून दिवालियाके सम्बन्धमें	१४४
—बायदे दिवालियाकी अर्जीस लेकर अन्त तककी कार्यवाईके सम्बन्ध तक	१४४
—रिहीवरकी नियुक्ति, अधिवार, कर्तव्य और अन्य सब बातोंका वर्णन	१४५
—कजोके साबित किये जानेके सम्बन्धमें पूरी कार्यवाईका किया जाना	१४६
—दिवालियेकी योगमनकूला जायदादका बेचा जाना	१४७
—हिस्सा रसदोश दिया जाना और अन्य बातें	१४७
—सरसरी कार्यवाई किन किन मामलोंमें कैसी की जावेगी	१४८
—नमूना, कर्जदार दिवालियाकी दरखास्त का (अर्जी)	१४८
—दिवालियाकी दरखास्त सुने जानेका नोटिस जो कर्जत्वाहोंको दिया जायगा	१४९
—दिवालिया कुरार दिये जानेका हुक्म	१५०
—नमूना उस कर्जत्वाहकी दरखास्तका, नोटिस जिसका नाम सूचीमें दर्ज नहीं है	१५०
—दिवालिया कुरार दिये जाने वाले हुक्ममें मसूखोंका हुक्म	१५१
—तस्दीया या हुप करनेकी रसीम पर चौर करनेके लिये जो तारीख हो उसकी सूचना देना	१५१
—उन कर्जत्वाहों की फहरिस्त जो तरकीया या तय करते समय रसीममें शामिल हों	१५२
—रसदवाहोंकी बहाल होनेकी दरखास्तकी सुचना	१५२
—आददा होने वाली आमदनी या मिशने वाली जायदादमें चौर पर बहाल होनेका हुक्म	१५३
—कजो साबित किये जानेका आम तरीका	१५३
—रिहीवरकी नियुक्ति का हुक्म	१५४
—अन्तिम हिस्सा रसदी बाटनेका नोटिस जो कर्जत्वाहोंको दिया जायगा	१५४
—कर्जत्वाहोंकी सरसरी कार्यवाईका नोटिस	१५५

इलाहाबाद हाईकोर्ट रूलर्स

इलाहाबाद हाईकोर्टके बनाये हुए नियम कानून दिवालियाके सम्बन्धमें	१५६
—बायदे दिवालियाकी अर्जीस लेकर अन्तिम कार्यवाईके सम्बन्ध तक	१५६
—रिहीवरकी नियुक्ति, अधिवार, कर्तव्य, और अन्य सब बातोंका वर्णन	१५७
—कजोके साबित किये जानेके सम्बन्धमें पूरी कार्यवाईका किया जाना	१५८
—दरखास्त व नोटिस	१५७
—दिवालियेकी योगमनकूला जायदादका बेचा जाना	१५७
—सरसरी कार्यवाई किन किन मामलोंमें कैसी की जायगी	१५८
—नमूना—नतरल टाइटल का लिखा जाना	१५८
—कर्जदारकी दरखास्तका जिसका	१५८
—कर्जत्वाहोंकी दिवालियेकी दरखास्त सुने जानेका नोटिस	१५९

दस्ता	विषय	पेज
—दिवाल्या करार दिये जानेका हुक्म	...	१६३
—रिमांवरकी नियुक्तिका हुक्म	...	१६३
—क्रैमिक मामिल किया जाना आम तरीका	...	१६४
—मजदूरोंका कर्म साधित किया जाना	...	१६४
—तस्वीया या तय होनेकी रसीम पर कर्जखानोंके नाम नोटिस जारी किया जाना	...	१६५
—उन कर्जखानोंकी फहरिस्त जो तस्वीया या तय होने वाली रसीमके समय बचाई जावे	...	१६५
—दफा ६४ के अनुसार दिया जाने वाला नोटिस	...	१६६
—दिवाल्या करार दिये जाने वाले हुक्मकी मसूदा या हुक्म	...	१६६
—कर्जखानोंकी बहालकी दरखास्तका नोटिस	...	१६६
—आमदनी व चार्जमें आने वाली जायदादके सम्बन्धमें लगाई हुई फाँकों साथ बहालकी हुक्म	...	१६७
—कर्जखानोंके नाम नोटिस सरकारी कार्रवाईमें	...	१६७
—वेहे कर्जखानोंकी दरखास्तका नोटिस जिसका नाम सुर्खमें दैन नहीं है	...	१६८

घम्वई हाईकोर्ट रूलस

घम्वई हाईकोर्टके धनाये हुए नियम कानून दिवाल्याके सम्बन्धमें	...	१६८
—बाबू दिवाल्याकी अर्जमें लकर आतम कार्रवाई तक	...	१६८
—कसौम साधित किया जाना पूरी कार्रवाई	...	१६९
—रिमांवरकी नियुक्ति, अधिकार, कर्तव्य और अन्य बातोंका वर्णन	...	१७०
—दिस्मा रसदी और बहाल होना	...	१७१
—हर एक दफाके अनुसार किस तरह नोटिस जारी किया जायगा	...	१७२
—मरसला कार्रवाई दिन दिन मामलोंमें कैसे की जायगी	...	१७४
—मुआदना और बरीअर्थी कीम आदिका वर्णन	...	१७६
—नमूना आम उनबला	...	१७६
—कसौदर द्वारा दी जाने वाली दिवाल्याकी दरखास्त	...	१७७
—कर्जखाने द्वारा दी जाने वाली दिवाल्याकी दरखास्त	...	१७८
—कर्जखानाने दिवाल्याकी दरखास्त सुने जानेकी तारीखका नोटिस	...	१७९
—दिवाल्या करार दिये जानेका हुक्म	...	१७९
—रिमांवरकी नियुक्ति का हुक्म	...	१८०
—छाँवा सुवत (आम तरीका दफा ४९) के अनुसार	...	१८०
—मजदूरोंके कर्मे का सुवत	...	१८१
—तस्वीया या तय होनेकी रसीमका नोटिस जो कर्जखानोंके दिया जाना चाहिये	...	१८१
—कर्जखानोंकी फहरिस्त जो तस्वीया या रसीम पर विचार करते समय बचाई जाय	...	१८२
—अन्तिम दिस्मा रसदी बोधनेसे पहिले कर्जखानोंको दिहा जाने वाला नोटिस	...	१८२
—दिवाल्या करार दिये जाने वाले हुक्मकी मसूदा का हुक्म	...	१८३

दफा	विषय	पेज
—बहाल होनेकी दरखास्त नोटिस जी कर्जदारोंको दिया जाना चाहिये	...	१८३
—सरसरी धारबादगी नोटिस दफा ७४ के अनुसार	...	१८३

मान्ति कानून दिवालियाके अनुसार नमूने

नमूने का फार्म नं० १	कर्जदार द्वारा दिवालिया करार दिये जानेकी दरखास्त	...	१८४
११ ॥ नं० २	कर्जस्वाह द्वारा दिवालिया करार दिये जाने की दरखास्त	...	१८५
११ ११ नं० ३	दरखास्त वाले नापेस छने मुकदमा	...	१८६
११ ११ नं० ४	कर्जस्वाहन द्वारा दरखाल दमियानी रितावरके मुकदमे करनेके लिये	...	१८७
११ ११ नं० ५	नोटिस वाले दरखास्त दिवालियाके छुने जानेकी	...	१८८
११ ११ नं० ६	कर्जदारके मुक्त रिये जानेके लिये दरखास्त दफा २३ के अनुसार	...	१८८
११ ११ नं० ७	प्रोटेक्शन ऑर्डर मिन्चकी दरखास्त	...	१८९
११ ११ नं० ८	क्षमानतनामा	...	१९०
११ ११ नं० ९	अर्जी मिन्जानिब कर्जदार बाबत दिमाये जाने हनी दफा २६ के अनुसार	...	१९१
११ ११ नं० १०	दरखास्त वाले शिफारस किये जाने दिवालियाके दफा ३२ के अनुसार	...	१९१
११ ११ नं० ११	कर्जा साबित करनेकी दरखास्त	...	१९२
११ ११ नं० १२	दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्म की समुचीके लिये कर्जदारकी दरखास्त	...	१९३
११ ११ नं० १३	दरखास्त कर्जबाह वाले समुची हुक्म दिवालिया	...	१९३
११ ११ नं० १४	तरकीया या रजामे पेस करनेका दरखास्त	...	१९४
११ ११ नं० १५	दरखास्त वाले बहाल रिय जानेके	...	१९५
११ ११ नं० १६	दूसरा मनुष्य दरखास्त वाले बहाल रिय जानेके	...	१९६
११ ११ नं० १७	बहालका दरखास्तके विषयके दी जाने वाली दरखास्त	...	१९६
११ ११ नं० १८	दरखास्त बाबत समुची इन्फाल जामदाद	...	१९८
११ ११ नं० १९	धोखादेहीसे तरकीह देने बाबत इन्फाल की समुची दरखास्त	...	१९८
११ ११ नं० २०	दरखास्त कर्जस्वाह वाले समुची इन्फाल जामदाद	...	१९९
११ ११ नं० २१	दरखास्त बाबत तरकीह देने दिवालिया	...	२००

शब्दार्थ सूची

अ

अदालत-कचेहरी, न्यायालय
अभिप्राय-मतलब, आशय
अहाता-प्रदेश, सूबा
अनुसार-मुताबिक
अलहदा-भिन्न, अलग
अर्थ-मतलब, मानी
अधिकतर-बहुतायतसे, अक्सर
अधिकार-अक़्क़ार
अदालत एकीकृत-रमात काजकोर्ट
अवध-ज़रूर
अभिरिक्त-अलावा
अर्जों-दरख़ास्त
अन्न-घात
अन्नतजवीजशुदा-जिन यातका फैसला हो
गया हो
अदमपैरधी-पैरहाजिरीमें
अपील-हुकमके विरुद्ध अर्जों
अइयागी-देना
असर-प्रभाव
अइत्याए-अधिकार
असुविधा-अइवन
आकिशल पसायनी-सरकारी रिखीवर
आवश्यकता-ज़रूरत
आगरा टेनेन्सी पकट-क़ानून लगान आगरा
॥ अवध
आधिपत्य-प्रधानता

इ

इन्तकाल-हस्तान्तरित
इस्तकारिया-किसी वस्तुके भान लिये जाने
के लिये

इनकारी-न मानना
इन्सालघेन्सी-विवालिया
इजराय-डिकरी-डिकरीका जारी करना
इजराय-जारी करना
इतलाय-संदिस
इस्तनार् हुन्म-हमेशाके लिये हुक्म जारी होना
इतज़ाम-प्रबन्ध

उ

अदाइरण-मिसाल
उल्लेख-जिक़र
उपस्था-इफाके अन्दरका अंक
उचित रूपसे-जायज़ तरीक़ेसे
उपस्थित-मौजूद

ए

एडीशनल-संस्करण, जुदा हुआ
एकतर्फा-एकहीपक्ष
एतराज-आपत्ति
एक्ट-क़ानून

क

कमिश्नरी-सूबेकी बड़ी अदालत
कर्ज़ेवाह-लेहनदार जिन लोगोंका रुपया
कर्जदार पर बाकी हो
कर्जदार-रु० जिस पर बाकी है, (विवालिया)
कर्ज-करजा, अरण
क़रार देना-मान लेना, तप कर देना
कम्पनी-जमात
कर्तव्य-कर्ज
कमटी-समाज, सम
क़ाज-अन्दर या ऊपरकी दफ़ा या अफ़ के
कानून इन्काल जायदाद-ट्रान्सफर आफ़
प्रापटी

कारवाई-काम करना, कारगुजारी

कारण-सबब

कास अपील-अपील करने पर दूसरा पक्ष भी जो अपील कर दे

ख

ख्याल करना-मान लेना

खफीफा की अदालत-स्माल क्लाज कोर्ट

खबर-सूचना

खास-विशेष

खानदान मुश्तका-शामिल शरीक परिवार

खारिज-रद्द कर देना

खुलासा-सारांश

ग

गिरफ्तारी-कैदके लिये पकड़ना

गिरफ्तार-कैदके लिये पकड़ लेना

गैरहाजिर-न उपस्थित होना

गैरमनकूला-अचल जायदाद, स्थावर

घ

घटना-वाकिया

घोषणा-सूचना, खबर

घोषित-प्रकाशित

ज

जमानतदार-जिसने जमानत की हो

जमाअमानत-मांगतेही मिलने वाली वस्तुका रखना

जराअत काइतकारी

जागीरें-सरकारसे इनाममें पाई हुई जायदाद

जागीरदार-इनामदार, मालगुजार

जायदाद-सम्पत्ति

जायदादीवानी-सिविल प्रोसीजर कोड

जायदाद फौजदारी-क्रिमिनल प्रोसीजर कोड

जाती-निजी

जिक-उल्लेख, बयान

जुर्म-अपराध

ट

टापू-जिस ज़मीनके चारो तरफ जल हो

टाउम्स-कलकत्ता, यम्बई, मद्रास, कापंची

ड

डिक्रीदार-जिसके हकमें फैसला हुआ हो

डिक्री-अदालतका फैसला मुद्देके पक्षमें

डिवीडेन्ड-निश्चित समयमें बांटने वाली रकम

त

तय-फैसला, ठीक

तस्दीक-ज्ञानूनके अनुसार मंजूरी

तजवीजगुदा-जिसका फैसला हो गया

तहरीर-लिखित

तहरीरी-लिखी हुई

तस्फीया-आमलका मय हो जाना

तस्फीयानामा-फैसलानामा

तर्ज-प्रकार, क्रिस्म

तर्जुआमा-बर्नाथ की क्रिस्म

तरीका-तरह, रीति

तरजीब-भेद्यता

तकलीम-बंद जाना

तजवीजखानी-हुक्मके विचारके लिये अर्जों

तात्पर्य-मतलब

द

दरमियान-अध्यम, बीचमें

दरअसल-वास्तवमें

दस्तूर-कायदा

दस्तन्दाजी-आपत्ति करना

दफा-धारा

दरखवास्त-अर्जों, प्रार्थना पत्र

दरमियाबी-बीचमें

दस्तावेज-लिखतें जो स्टाम्प पर हों

दण्ड-सजा

दाखिल होना-पेश होना

दाया-नालिश

दिवालिया-कर्जदार
दिवालियेके काम-जिन कामोंसे दिवालिया
बनाया जा सके
दीवानी अदालत-दीवानीकी फोर्ट
दफ्तर-सम्हाल, निगरानी

ध

धन-रुपया
धनराशि-रुपयोंकी शकलमें
ध्यान रखना-ब्याल रखना

न

नगरस्थानी-कैबलके लिये दुवारा विचार
कराने की अर्जी
नावालिग-अज्ञान
नावाकिफ-न जानने वाला, अज्ञान
निम्न-जैस, नीच
निर्धारित-मुकरर
निश्चित-कसई तय कर देना
नियम-क़ायदे
नियत-मुकरर
निजीतौर पर-घरेलू
नियुक्ति-मुकररी
नियुक्त-मुकरर
नीयत-ईमान
नैकनीयती-शुदावरण ईमानदारीसे
नोद्विष-सूचना

प

परिमाप-खास अर्थ का मान लेना
परिशिष्ट-तितम्भा
प्र-न्तु-लेकिन
परवाह-मानना, ऊँकरत
प्रधान-मुख्य
प्रसङ्ग-सम्बन्ध
प्रयोग-इस्तेमाल
प्रकरण-बेप्तर

प्रकाशित-जाहिर
प्रश्न-सवाल
प्रचलित-रायज है
प्रतिनिधि-एवजोमें, स्थानापन्न
प्रांत-ज़िला
प्रांशिक-सुवेका
प्राप्त-मिल गया
प्राचिडेन्ड फंड-काट काट कर जो रुपया जमा
किया जाता है
पूर्णतया-पूरी तरहसे
पंशा-धंधा
पेश्वर-पहले
प्रेसीडेन्सी-सुबा
प्रेसीडेन्सी टाउन्स-कलकत्ता, बम्बई, मद्रास,
करांची रंगून
पेंशन-नौकरी के बाद की तनखाह
पोलिटिकल पेंशन-राजनैतिक पेंशन

फ

फर्म-दुकान, कोठी
फार्म-तरीका, छपा हुआ कागज़
फीसदी-सैकड़े पर
फैसला-तय हो जाना, निश्चित हो जाना
फैसल- तय होना
फैलाय-विस्तार

ब

बयान लहरीरी-जवायदावा
बहुमत-कसरतराय
बहाल होना-ज़ेलसे रखा पाजाना
बरी करना-छोड़ देना
बहेंसियत-इज्जतके मुताबिक
बयनामा-बैचा नामा
बयबात-बेहनमें यह शर्त होती है
बखत-बकाया
बार सुबूत-सुबूतकी ज़िम्मेदारी
बिडिश-अङ्गरेज़ी

ब्रिटिश भारत-अङ्गरेजीराज वाला भारत
बुन्देलखण्ड लैन्ड एलीमेशन ऐक्ट-बुंदेलखंड

का ज़मीन लेने सम्बन्धी कानून
घेनामीदार-फर्जी नाम वाला व्यक्ति
वेजा लाभ-अनुचित लाभ
वेजा-नाजायज़

भ

भसा-खर्चा

भोंति-तरह, प्रकार

म

मध्यमदेश-सो० पी० प्रंत

मदियून-जिस पर डिकरी हो

महफूज-रेहन रखने वाला

महफूज कर्जब्याह-ज़मानत पर जिसने रुपया
बिधा हैमनकूला जायदाद-जंगम जायदाद, जो
जायदाद खल सकती है

मतालिवा-कीमत

मामला-मुकद्दमा

मातहत-वशीभूत

माक़बल-पहलें

मालकियत-हकीयत

भिताकरा-धर्म शास्त्रका मान है

मुतकरिफ़-फुटकल

मुनाफा-लाभ

मुन्तकिज़-इस्तान्तरित करना

मुन्तकिलअलेह-जिसके पास हत्यादी जाय

मुआहिदा-इकरार

मुश्तहरी-घोषित की हुई

मुकरर-नियत

मुहय्या-होसिल की गई

मुर्तदन-जिसने रेहन रखा हो

मौदसी-पैतृक

मंसूखी-रद्द

र

रक्षा-महफूज

रह-मंसूख

रसदी-हिस्सेके मुताबिक

राय-मत

रिखीवर-अदालतका एक अफसर

रिहई-छुटकारा पाना

रिपीजिंग ऐक्ट-जिसके द्वारा अन्य कानून
रद्द हों

रुकावट-अड्डम

रुस-कायदे

रस्पान्डेन्ट-जिसके खिलाफ अपील हो

ल

लागू-सम्बन्ध

लाभ-फायदा

व

व्यवस्थापक-कायम करने वाला

व्यवस्थापिका सभा-जहां पर कानून बना
जाते हैं

व्यक्ति-शख्स

व्यवहार-तर्ज़अमल

वाक्य-अल्फाज़

वाकियाती-जो कानून सम्बन्धी न हो

वारिस-उत्तराधिकारी

वांट-गिरफ्तारीका हुक्म

व्याख्या-तशरीह

बिस्तार-तशरीह

बिपरीत-खिलाफ़

विविध-मुस्तलिफ

व्यौरा-तफसील

श

शब्द-लेफ़्ज़

शर्त-पाबंदी

शुद्ध-व्यक्ति
शरीरदार-हिस्सेदार
शामिल शरीक खानदान-मुश्तरका परिवार

स

सरसरी-साधारण
सीमा-दद
साधारण-सरसरी
सूची-फेहरिस्त
सूचना-इस्लाह
सूद-न्याज

संशोधित-तरीमी किया हुआ
संदिग्ध-मुश्तर
संगीन-मुश्किल, कठिन

ह

हकीकतमें-दरअसलमें
हक-स्वत्व
हस्तक्षेप-मुद्दिल होना
हक-शिका-दक दूसरेसे पहले अपना
हस्य-अनुसार
हिस्सा रसदी-हिस्सेके अनुसार

अङ्ग्रेजी नज़ारोंकी सङ्केताक्षर सूची

A या All.	इन्डियन लॉ रिपोर्ट्स इलाहाबाद सीरीज
A. I. R. (All.)	आल इन्डिया रिपोर्ट्स नागपुर (इलाहाबाद सीरीज)
A. I. R. (Cal.)	आल इन्डिया रिपोर्ट्स नागपुर (कलकत्ता सीरीज)
A I R (Mad)	आल इन्डिया रिपोर्ट्स नागपुर (मद्रास सीरीज)
A. I. R. (Bom)	आल इन्डिया रिपोर्ट्स नागपुर (बम्बई सीरीज)
A. I. R. (Pat)	आल इन्डिया रिपोर्ट्स नागपुर (पटना सीरीज)
A. I. R. (Rang.)	आल इन्डिया रिपोर्ट्स नागपुर (रंगून सीरीज)
A I. R. (Pr.)	आल इन्डिया रिपोर्ट्स नागपुर (प्रिंसी कॉन्सिल सीरीज)
A I. R. (Nag)	आल इन्डिया रिपोर्ट्स नागपुर (नागपुर सीरीज)
A. I. R. (Sindh)	आल इन्डिया रिपोर्ट्स नागपुर (सिंध सीरीज)
A I R. (Lah.)	आल इन्डिया रिपोर्ट्स नागपुर (लाहौर सीरीज)
A. L. J.	इलाहाबाद लॉ जर्नल
A W. N.	इन्डियन वीकली नोट्स
B. या Bom.	इन्डियन लॉ रिपोर्ट्स बम्बई सीरीज
B H. C.	बंगाल हाईकोर्ट रिपोर्ट्स
B. L R	बम्बई लॉ रिपोर्ट्स
Bur L. R.	बरमा लॉ रिपोर्ट्स
C. या Cal.	इन्डियन लॉ रिपोर्ट्स कलकत्ता सीरीज
C. L J.	कलकत्ता लॉ जर्नल
C. W. N.	कलकत्ता वीकली नोट्स
F. B.	फुलबैच
I. C.	इन्डियन केसेज लाहौर
L. B. R.	लोअर बरमा रिपोर्ट्स
M. या Mad.	इन्डियन लॉ रिपोर्ट्स मद्रास सीरीज
P. L. J.	पटना लॉ जर्नल

प्रेसीडेन्सी टाउन्स कानून दिवालिया

एक्ट नं० ३ सन् १९०६ ई०

[कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, रंगून और कराची शहरोंके लिये]

सर्वाङ्ग पूर्ण व्याख्या और हाल तककी नज़ीरों सहित दफावार सविवरण सूची

पृष्ठा	विषय	पृष्ठा
१	नाम व प्रारम्भ	१
—	ता० १ जनवरी सन् १९१० ई० से यह कानून लागू होगा	१
—	प्रेसीडेन्सी टाउन्स (कलकत्ता, बम्बई, मद्रास) के अलावा भी यह कानून ऐक्ट नं० ९ सन् १९२६ ई० के अनुसार रंगून और कराचीमें भी लागू किया गया है	१
—	प्राथमिक कानून दिवालिया और इस कानूनका भेद	२
—	इस ऐक्टका पहलेके कानूनों पर प्रभाव क्या पड़ता है	२
२	परिभाषाये	२
(ए)	'कर्जस्त्राह' (Creditor) शब्दके अन्तर कौन लोग शामिल किये जायेंगे	३
(बी)	'कर्ता' (Debt) और कर्जदार (Debtor) शब्दोंका अर्थ	३
(सी)	'आफिशियल एससिने' (Official Assignee) शब्दका मतलब	३
(डी)	'निर्धारित किये हुए' (Prescribed) शब्दका अभिप्राय	३
(ई)	'जायदार्' (Property) का अभिप्राय और मतलब	३
(एफ)	'नियमों' (Ruls) का अर्थ और अभिप्राय	३
(जी)	'सिक्यूरज कर्जस्त्राह' (Secured Creditor) का मतलब व अर्थ	३
(एच)	'अदालत' (The Court) शब्दका मतलब	३
(आई)	'इन्गकाल जायदार्' (Transfer of Property) शब्दका अर्थ व अभिप्राय	३
—	किसी बेनामीदारको कर्जस्त्राह नहीं समझना चाहिये	३
—	अगर कोई साया दस्तावेज व हर हालतमें अदा करनेका है तो वह कर्ज है	३
—	उधार देने वाले और उधार लेने वालोंपर परस्पर सम्बन्ध क्या है	३
—	जब किसीने रुपया दूसरेको दिया कि वह तीसरे आदमीको देदे तो सम्बन्ध कैसा होगा	३
—	इस कानूनके पारिभाषिक शब्दोंकी व्याख्या वहीं होगी जो अन्य कानूनोंमें दी गई है	४
—	इस कानूनके सम्बन्धमें इंगलिश फ्रैम्मे से सब तात्पर्य हो सकते हैं	४

वक्र

विषय

पृष्ठ

पहिला प्रकरण

अदालतों की व्यवस्था व उनके अधिकार

अधिकार सीमा

३ यह अदालतें जिनको दिवालयिके अधिकार प्राप्त हैं	४
—बलवत्ता, प्रदत्त, जर्ज और नवीं हाईकोर्ट तथा सिन्ध के हाईकोर्ट ट्रिबुनल	४
४ अकेला एकही जज इस पदके अधिकारोंको चरत सकता है	५
—हाईकोर्ट या चीफ कोर्टके चीफ जस्टिसको अधिकार है कि किसी एक जनको दिवालयिके कामके लिये नियत करे	५
५ कमरेमें जजोंका काम करना	५
—जनको अधिकार है कि वह चाहे खुली अदालतमें मामला सुने या कक्षमें	५
६ अदालतके अफसरोंको अधिकार प्रदान करना	५
—चीफ जनको अधिकार है कि वह दिवालयिके मामलोंके सुननेका अधिकार किसी अफसरको देवे	६
—जिस अफसरको दिवालयिके मामला सुननेके अधिकार मिले हों वह ही होगा	६
—अधिकार प्राप्त अफसरको तारीफ अदालतके मामलोंसे संबन्ध न होना	६
७ दिवालयिके सम्पूर्णमें पैदा हुए सब प्रश्नोंको तय करनेके अधिकार	६
—आदिशत प्रमाणों आदिके बीचके सम्पर्कोंके तय करनेका अधिकार	७
—दिवालिया अदालतके हुक्मकी रद करनेके लिये कोई मुकदमा दोबानोंमें दाखल न किया जाएगा	७
—अधिकार सीमाके बाहर किसी जायदादके बारेमें अदालत हुक्म दे सकती है	७
—कानूनकी पाबंदी करनेके लिये अदालत भी दिवालयिके मामलोंमें बाध्य है	७
—क्योंकि पैसा अदायगीके बारेमें जो प्रश्न होंगे तब दिवालयिका अदालत तय करेगी	७
—२०० मीलस ज्यादा दूरीके आदमीको भी सब अदालत चलन करेगी	७
—नव दूर, गवाह पछ हो तो उसे सब सुविधाओं मिलेंगी जो दूतोंको मिलती है	७
—वाह्य शक्ति मनाही देनेसे इन्कार नहीं कर सकता	८

अपील

८ दिवालयिके मामलों की अपील	८
—अदालत दोबारा अपने हुक्मों पर दुबारा विचार कर सकता है	८
—नवास्तानी (Keyrow) उसी दायित्वके सामने होगी जिसने हुक्म दिया हो	८
—अगर बदल गया हो या दूरा हासिल आगया हो तो उसका सामने भी नज़रआनी होगी	८
—जिस हुक्मकी अपील जिस साहब कहा पर की जाएगी और कहा पर नहीं	९
—दोबानोंकी अपीलका तब तक बान सामनेमें अपील का बाधक होगा	९

दूसरा प्रकरण

दिवालियेके कामसे लेकर बहाल होने तककी कार्यवाही

दिवालियेके काम

१ दिवालियेके काम	५
— दिवालियेके काम कौन कौनसे होते हैं और कौन नहीं	५
— जिस पर डिफ्टी होगई हो दिवालियाका काम है	५
— “ कर्जदार ” शब्दके अन्तर कौन लोग होते हैं, साधारण अर्थ माना जाता है	५
— किसीके देनेको जो कपया लिया जाय तो लेने वाला कर्जदार नहीं माना जायगा	५
— परमपूजा रहने वाला आदमी भी दिवालिया करार दिया जासकता है	५
— जो व्यक्ति सही मुआहिदा कर सकते हैं वह दिवालिया करार दिये जासकते हैं	१०
— दिवालियेको अपनी सब जायदाद दे देना चाहिये चाहे जहा पर वह हो	११
— अगर कर्जदारमें कपया मगानेके लिये सब या कुछ जायदाद दया दी हो	११
— जब कर्जदारने किसी खास लड़नदारको कपया चुकया हो दूसरोंका नहीं तो ऐसे मामलोंका विचार	११
— जब कर्जदार अङ्गरेजों मारते बाहर चला जावे या मृत हो जावे, भाग जाय	१२
— किसी फर्मका एक डायरेक्टर जब बाहर चला जाय तो फर्म दिवालिया न होगी	१२
— कर्जदारके अधिकतर रहनेवाली जगह कौन समझी जायगी	१२
— कैसला आरसी और अदालतकी डिक्लीरेशन फार्म	१३
— जब कर्जदारने लड़नदारको यह नोटिस दिया हो कि कपया नहीं चुकाया जावेगा	१३
— किसी डिक्लीरमें कर्जदार जब कैद कर लिया गया हो तो वह काम दिवालिया है	१३

दिवालिया करार दिये जानेका हुकम

१० दिवालिया करार देनेके अधिकार	१३
— जहाँ देने पर भी दिवालिया करार देना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है	१३
— इन्क्विजिटो दिवालिया बन जाने पर भी हिदुस्थानमें दिवालिया बनना आवश्यकता है	१४
११ अधिकारोंमें रुकावट	१४
— फ्रिज ट्विन दशाश्रममें अदालतकी दिवालिया करार देना अधिकार नहीं है	१५
— कर्जदारका दीनानी की जेलमें होना और एक साल तक अदालतकी माँगमें रहना	१५
— जब किसी फर्मके दिवालिया बननेकी अर्थात् दी जाय तो उस फर्मको एक साल बढ़ा होना चाहिये	१५
— दिवालिया बननेके लिये किसी एकही शर्तका पूरा करना काफी होता है सबका नहीं	१५
— कमीशन लेकर काम करने वाला, एजेंट नहीं कहा जाता है	१५
— जैसे मुनीम, गुप्तार, मुख्तार आदि जो उसी मालिकता ही वहा काम करते हैं एजेंट हैं	१५

वर्ग	विषय	पृष्ठ
—	निवास स्थान कर्जदारका एक साल तक जिस अदालतकी सीमामें हो—मतवेद ...	१५
—	होटलमें रहना भा अदालतके अधिकार सीमाके अन्दर माना जायगा ...	१५
—	पुनर्हित ४ मास तक बन्दहमें शिष्टोंके पास रहा तो उसका बन्दहमें रहना नहीं माना जावेगा ...	१६
—	धूमने जाना, सैरके जाना, निवास स्थान नहीं माना जावेगा ...	१६
—	दिन्दू परिवारका कर्ता जहा काम करता हो तो वह न माना जायगा कि दूसरे लोग भी वहां रहते हैं ..	१६
१२	यह शर्तें जिनके अनुसार कर्जद्वारा दिवालिया क्रमर दिलायेकी दुरवस्थास्त दे सकता है	१७
—	कर्जद्वारा कम, जिस दशामें, कर्जदारके निरुद्ध दिवालिया की अर्जी दे सकता है ...	१७
—	(१००) २० वा कर्जा होना एक लड़कनद्वारा या कई लड़कनद्वारा होना जरूरी है ...	१७
—	तीन महीनेके अन्दरके वे फाय होना चाहिये जिन काममें दिवालिया बनया जाता हो ...	१७
—	सुरतहिन (जिसके पास जायदाद रहन हो) रहनका एक छेद कर अर्जी दे सकता है ...	१७
—	सुरतहिन जब अपनी रहनकी जायदादका अर्धांश देगा दे तो दूसरा पौर्ष उसे खतना दे सकता है ...	१७
१३	कर्जद्वाराकी दुरवस्थास्त पर कार्यवाई तथा उस पर हुकम ...	१७
—	कर्जद्वारा द्वारा अर्जी देने का कौन कर्जवाई आवश्यक होगी ...	१८
—	कर्जद्वारा जब दिवालिया बननेकी अर्जी दे तो उसे हलफनामा दाखिल करना होगा ...	१८
—	वे बातें सब साबित करना पड़ेगी जो अर्जमें लिखी गई हैं ...	१९
—	अदालतकी अधिकार है कि कार्यवाई करनेके लिये वारीज बदा दे ...	१९
—	सुप्रीम सुननेके बाद अदालत यदि समझे तो अर्जा खारिज कर सकती है ...	१९
—	कर्जदार, पंजरी अदा कर सकता है, या उसने वे बाने न कां हो तो अर्जा खारिज होगी ...	१९
—	समन मिलने पर अगर कर्जदार न आवे तो अदालत उसे दिवालिया बना सकती है ...	१९
—	कर्जद्वारी तादातमें समझा हो तो अदालतकी जमानत मागनेका अधिकार ...	२०
—	कर्जद्वारा अपनी अर्जी बिना अदालतकी मजूरीके वापिस नहीं ले सकता ...	२०
१४	यह शर्तें जिनके अनुसार कर्जदार दुरवस्थास्त दे सकता है ...	२०
—	(५००) २० कर्जा हो या गिरफ्तार किया गया हो या जायदाद कुके की गई हो ..	२०
—	बिक्रीके द्वारा धुनी रुपयेकी अदवतकी लिये होना चाहिये ...	२०
१५	कर्जदारकी दुरवस्थास्त पर कार्यवाई च उस पर हुकम ...	२१
—	अदालत पहले यह देखेगी कि उसके समातके योग्य वह अर्जी है या नहीं ..	२१
—	अर्जी उभी समय तक वापिस हो सकती है जब तक दिवालियाका हुकम न हो गया हो ...	२१
१६	दरमियांनी रिसीवरकी नियुक्तिके लिये अदालतकी स्थतन्त्र अधिकार ...	२१
—	अदालत बीचमें जायदाद पर रिसीवर नियत कर सकती है यह बात उसकी शर्त पर है ...	२२
—	अर्जी देनेके बाद और दिवालियाका हुकम होनेसे पहले रिसीवर नियत किया जासकता है ...	२२
—	रिसीवर आगिशल एसायरी नियत किया जायगा ...	२२
—	दरमियांनी अफिशल एसायरीकी जयता दीनार्नाके गारंटी ४० के हक होगे ...	२२

दफा	विषय	पेज
—	जायता दावाना ऐक्ट न० ५ सन १९८ ई० वा आर्दर ४० ...	२२
—	अदालत आ फ़ैसल एसायना वा फ़ैसल निदान कर सकता है ..	२२
—	रिडीवरसे जमानत ली जासकता है, और हुक्मोंका मानना उकवा बतलवा होगा ..	२३
—	अगर रिडीवर हिंसा न दारिज कर या रुपया अदा न करे या चलती करे .	२३
—	अदालत कम्पट साइवका वा रिडीवर नियत कर सकता है जब मालगुजारी की जायदाद हो ...	२३
१७	दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी प्रभाव .	२३
—	दिवालियाकी अर्ज देने पर कोई कर्जदार अर्जद्वारा बालिग नहीं कर सकता ..	२४
—	जब जाना क्षाया दाखिल किये गये हों तो अदालतसे आज्ञा लकर दावा हा सकता है ...	२४
—	रेहन रखने वाला साधन बद नहीं सकता जासकता बस स्वतंत्रता रहेगी ..	२४
—	शामिल शराफ परिवारके बापका आयदादमें लड़कों, पत्नीका एक शामिल रहेगा ...	२४
—	जब कोई मुकदमा दायर हो पांच फ़ासक दिवालिया हा जाय ता जब तक उसका फ़ैसला न हो मुकदमा न चलेगा . . .	२४
१८	कार्रवाईका रोक जाना , ...	२४
—	दिवालिया अदालत दूसरा अदालतका कार्रवाईका रोक सकता है .	२५
—	ग़रनका हुक्म लकड़ ज़रियस भगा जासकता है या नक़ल भगी जासकती है ...	२५
—	कोई मामला चाह दिवालिया करार दनक बाद भी चलता हा ता वा रोक जासकता है ...	२५
—	कलकता हाईकोर्टका राय है कि जलज भगनी कार्रवाई दिवालिया, टाउसु कार्यसे राही नहीं जासकती	२५
—	टाउसु हा सल्लव सा अदालत, निजामी दिवालिया अदालतकी कार्रवाई नहीं राक सरनी ..	२५
१९	विशेष मेनेजरकी नियुक्तिके अधिकार ..	२५
—	विशेष मेनेजर तब नियत किया जावे जब कर्जदारका आयदाद विशेष प्रकाशकी हो ..	२५
—	आकिदात एसायना और विशेष मेनेजरका कार्य ..	२५
—	विशेष मेनेजरसे जमानत ली जापगी उसे सब हुक्मोंकी तामाक करना होगी .	२५
२०	दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी घोषणा ..	२६
—	दिवालिया करार दिये जानकी घोषणा सरकारी गज़टमें की जापगी ..	२६
दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी मंजूरी		
२१	कुल मामलोंमें दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी मंजूरीके अधिकार ...	२७
—	या ता उसे दिवालिया करार दिया हा न जाना चाहिये या या कर्जान पुकारा जाना	२७
—	नहनदारा कुल कर्जे चुका दिये गये हों तथा दिवालियाका व्यवहार आद ..	२७
—	दिन सूतोंमें कर्जोंकी अदापगी मान ला जावगी—अदालतका रयाक ..	२८
२२	अगरकी अदालतमें साथ साथ कार्रवाईका होना ...	२८
—	जब १६ अदालतमें कार्रवाई चालू हो ता उस अदालतमें होगी जिसमें सहूलियत हो ...	२८

धारा	विवरण	पन्ना
२३	मंजूरी पर होने वाली कार्यवाई	२८
	—मंजूरी के दृष्टिकोण परलेके वाम सब सहा मान जावेगे जो अदालतने किये लें	२९
	—मंजूरी के बाद कर्जदार जेम्स भजा जासकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है	२९
	—मंजूरी के दृष्टिकोण कायमा सराफा गजटमें अवश्य की जायगा	२९

दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मके होने पर कार्यवाई

२४	दिवालिये द्वारा दी जाने वाली सूची	३१
	—जर्जदार को सूची अपने इसकामके साथ दाखिल करना जरूरी होगा	३०
	—सूची कैसे बनाई जायगी, कब दाखिल होगी और उसका असर क्या होगा	३०
	—किसी भी दस्तावेज पर अदालत कर्जदारके कसूर पर सजा दे सकती है	३१
	—कर्जदारने अगर सूची न बनाई व न दाखिल की तो आर्थिक एसायनी बनावेगा	३१

२५	रक्षा का हुक्म	३१
	—जर्जदार अपनी गिरफ्तारी और जेल जानेसे बच सकता है	३१
	—रक्षा जेल जानेसे कहीं कहीं दीर्घ हो सकती जो सूचीमें बताया गया है	३१
	—कर्जदार अदालतमें दिवालियेकी रक्षा करनेके हुक्ममें उद्युक्त कर सकता है	३१
	—कर्जदारके लिये जेलसे रक्षा का हुक्म देनेमें अदालत धूस विचार करेगी	३१

२६	कर्जद्वाराओंकी मीटिंग	३२
	—अर्ज देने पर अदालत सब लहनगोंकी मीटिंग करने व मामलात द्रव करनेका हुक्म देगी	३२

२७	दिवालियाका खुली अदालतमें बयान	३२
	—जर्जदारका बयान उसके बर्तान, व्यवहार व जायदादके सम्बन्धमें अदालतमें होगा	३२
	—सूची कर्जदारी दाखिल करनेके बाद जेम्स वगैरह दिवालियेका हाना चाहिये	३२
	—आर्थिक एसायनी बयानके समय भाग लेगा तथा बोर्ड प्रश्न पूछ सकती है	३२
	—जर्जदारका बयान, लिखा जायगा, हर कैडनदार उसे देख सकेगा, बयान हल्काम होगा	३३
	—जब जर्जदार पागल हो या बेगुनाह हो या नाबालिग हो या अशक्त हो	३३
	—किन हालातोंमें व किनसे अदालत बयान लेनेसे नकार सकती है	३३

तस्फीया तथा तय किये जानेकी स्कीम

२८	प्रस्तावोंका पेश किया जाना तथा उनका कर्जद्वाराओं द्वारा स्वीकार किया जाना	३४
	—कर्जदारका आधार, स्वीकार पेश करनेका, व दाय करनेका, प्रस्ताव पेश करनेका	३४
	—एमे प्रस्तावकी दरुआवा कर्जदारका पास भजा जाना और वसूली करना	३४
	—प्रस्तावका मंजूरान, और कर्जद्वाराओंका अधिकार मंजूर करनेका	३४
	—कर्जदारका द्वारा प्रस्तावकी मंजूर कब मानी जायगी	३४

दफा	विषय	पंज
६४	—कस्तूरवाह अपनी राय लिखे ३१ दिन पहले आधिकारिक एसायनीके पास भेज सकते हैं ...	३५
६६	अदालत द्वारा प्रस्तावकी स्वीकृति ...	३६
	—कस्तूरवाहोंके मजूर करने पर अदालतमें दगवास्त दी जायगी ...	३५
	—होन बर्जवाह विरोध कर सकता है, ३५ ३२ सनता है और कैसे रहेगा ...	३५
	—प्रस्तावकी मजूरीके पहले आधिकारिक एसायनीकी रिपोर्टका अदालतमें प्रमाण जाना ...	३६
	—किन बानोंके होने पर अदालत प्रस्तावकी मजूरीको रद्द कर दगी और फोन उग्र करेगी ...	३५
	—मरसौरी की कार्यवाहीमें अदालतकी आज्ञा के ३१ मामला तय किया जा सकता है ...	३५
	—अदालत प्रस्तावका मामला तब तक मजूर न करेगी जब तक कम्पे कम करेगा और आज्ञा अदालत न हो ...	३६
७०	प्रस्ताव स्वीकार किये जाने पर हुक्म ...	३७
	—आपसी समझौता कर्जदार और कर्जदारके बीचका तस्वीरा नहीं समझा जायगा ...	३६
७१	दिवालियेका दुबारा दिवालिया करार देनेका अधिकार ...	३८
	—अगर कर्जदार तस्वीरेमें किन्तु ठीक वक्त पर अदा न करे तो दुबारा दिवालिया बनाया जासकेगा ...	३८
	—अदालतके अधिकार जब कर्जदार अपने पूरी न करे ...	३८
	—दुबारा दिवालिया करार देनेकी अर्जा देने पर सब कर्जें सन्निहित किये जायेंगे ...	३८
७२	तस्वीर या स्वीकृतिका प्रभाव ...	३८
	—फोन कर्जें तस्वीरा हो जाने पर भी जैसेके तैसे बने रहेंगे उन पर दस्तक अलग न पड़ेगी ...	३८

दिवालियेकी ज्ञात व जायदादके सम्बन्धमें अधिकार

७३	जायदादके चतकाने या उसको बसूल करानेके सम्बन्धमें दिवालियेके कर्तव्य ...	३९
	—कर्जदारको, कर्जदारकी मॉर्गमें शामिल होना जरूरी होगा ...	३९
	—कर्जदार अपनी जायदादकी कर्जदार देवे बयान देवे, शक्ति हो, दस्तावेज मिलें आदि ...	३९
	—कर्जदार, कथन वसूलीमें मदददे, या हुक्मकी तात्काल न करेगा तो सजा दी जायगी ...	३९
७४	दिवालियेकी गिरफ्तारी ...	४१
	—३५, किन्तु दशम, कैसे, दिवालिया गिरफ्तार किया जायगा और जेल भेजा जायगा ...	४१
	—नद दिवालिया भ्रम जाय, या भागने काय हो, या भागनेमें उत्पन्न टाकता चाहे ...	४१
	—यदि यह मादूम हा कि कर्जदार अपनी जायदाद हटाना चाहे है या हटा दी है ...	४१
	—यदि विना आज्ञा आधिकारिक एसायनीके ५०) से ज्यादा कर्जें जायदाद हटा दी हो ...	४१
	—यदि कर्जदारने अपनी दस्तावेजों, नहीं खाता अदिनो छिपा लिया हा ...	४२
७५	खुर्साका दूसरी जगहोंके लिये भेजा जाना ...	४२
	—कर्जदारके नामके भनीआउर, बरसल, खद, बंया आदि ७७ आधिकारिक एसायनीकी दिवे जायेंगे ...	४२
७६	दिवालियेकी जायदादका पता लगाना ...	४२

दफा	विषय	पेज
—अदालत ऐसे व्यक्तियोंको तब तक कर सकती है जबके कन्जेम दिवालयिकी जायदाद हो	...	४३
—नद श्रमस वाण्टसे गिरफ्तार होगा या अदालतने हुकम पर न आवे या दस्तावेज न दे-	...	४३
—दिवालयिकी कब्जा किसी पर साबित होने पर उचित दण्डसे वसूल किया जावेगा	...	४३
—दिवालयिकी अदालतके हुकमोंकी तासील जानना दोनानीकी डिफेंसी तरफ तासील होगी	..	४४
—जायदाद दोनानी ऐक्ट न० ५ सन १९०८ का आर्डर २१ कूल ३०३३१३५१३६	...	४४
४७ कमीशन जारी करनेके अधिकार	...	४६
—महालके बंधन लेनेके लिये कमीशन भी जारी किया जायकता है	...	४६
—जायदाद कमीशन जायदाद दोनानीके जायदोंके मुताबिक जारी होगा	...	४६
—जायदाद दोनानी ऐक्ट न० ५ सन १९०८ का आर्डर २६ कूल १ से ८ और १५ से १८	...	४६
दिवालयिकी बहाल किया जाना		
४८ दिवालयिकी बहाल किया जाना	...	४८
—दिवालयिकी बंधन देनेके बाद जेल्से छुटकारा पानेकी दरखास्त दे सकना है	...	४८
—जेलसे रक्षक हुकम देनेसे पहले अदालत जाकिराल एसापमसे रिपोर्ट मांगगी	...	४८
—अदालतके अधिकार दिवालयिकी जेलम रखा करनेके सम्बन्धमें	...	४८
४९ यह मामलें जिनमें पूर्ण रूपसे बहाल किये जाने वाले हुकम देनेसे इनकार कर देना चाहिये	...	४९
—जिन दस्तावेजोंमें दिवालयिकी जेल मानसे रखा अदालत नहीं देगी	...	४९
—जब दिवालयिकी तासीलतहिमी दण्ड ४२१ से ४२४ के ऊर्ध्व गिये हों	...	४९
—दिवालयिकी अपराधोंका बर्णन जिनके सबसे जेल जानेमें रखा नहीं मिल सकता	...	४९
—अदालत तीन तीन बातें पहले दैगी जब जेलसे कर्जदारकी रखा हुकम देगी	...	४९
५० बहालकी दरखास्तका मुला जाना	...	५१
—बहाल होने अर्थात् जेल जानगी श्राफा हुकम होनेकी घोषणा ठीक रीतिसे की जावेगी	...	५१
५१ बहाल होनेकी दरखास्त न देने पर दिवालयिकी क्रार देने वाले हुकमकी मंजूरी	...	५३
—यदि दिवालयिकी बहालकी अर्जी न दी, या शक्ति न हुआ तो पहले अर्जी खारिज हो जायगी	...	५४
—पहली अर्जी खारिज होने पर बन्दार बन्द भेजा जायकता है	...	५४
५२ बहाल होनेकी दरखास्तका हुबारा दिया जाना	...	५४
—दुसरा दरखास्त बहाल होनेकी मियादके बाद नहीं दी जायगी तथा न सुनी जायगी	...	५४
५३ बहाल किये हुए दिवालयिकी जायदाद वसूल करानेके सम्बन्धमें कर्तव्य	...	५५
—जब दिवालयिकी जेलसे रखा पानेके बाद भी कर्जा वसूलमें मदद न दे तो सजा दी जायगी	...	५५
५४ धोखेदेहीसे किये हुए सौदे	...	५५
—दिवालयिकी जायदाद जब अपनी ओर या लड़कों के नाम लिख कर द्या दी हो	...	५५
—तो ऐसा मुआहिदा जिसमें जायदाद दिवालयिकी कानूनों के आगे बान्ध होवे	...	५५

दफा	विषय	पेज
४५	वहातके हुक्मका प्रभाव ...	५६
	—नेमये रवा पातनेका हुक्म किन बातों पर जहर नहीं करता उनका वर्णन ...	५६
	—हरकत बर्बा, धोखेके मामले, जाना चौकदारोंको दफा ४८८ के मामलों पर प्रभाव न पड़ेगा ...	५६

तीसरा प्रकरण

कज़ोंका साबित किया जाना

४६	दिवालयिके सम्बन्धमें साबित किये जाने योग्य कज़ें ...	५७
	—दिवालयिके वार्डरोंमें सैन कज़ें साबित होंगे किन नहीं उनका वर्णन ...	५८
	—मुआदिदे, दस्तावेज, भागे, कमानों, जिनकी कीमत निश्चित न हो, जिम्मेदारियों आदि का वर्णन ...	५९
४७	अपस्तमें व्यवहार व उसकी सुझाव ...	५९
	—जब एक दूतरेका पावना एक दूसरे पर हो तो दोनोंमें मुजरार्द हो जायगी ...	६०
	—केवलद्वाराके पावनाको वज्रदार मजूर न बतला हो तो आक्राइल पतायनी उसका कर्ता न मानेगा ...	६०
४८	कज़ों साबित करनेके नियम ...	६०
	—ऐसे कज़े साबित हिये जावें जेव्हा दूतरी सूची १० ३ से ६ ...	६०
४९	कज़ोंका एक दूसरेमें पहिले अदा किया जाना ...	६१
	—दिवालयिके वार्डमेंसे सैन कज़ें पहले बुकाये जावेंगे और सैन उसके बाद ...	६१
	—हरकती कज़ें मोक़रों की तनख़ाह, मसूफ़ा दाम, मरानका बिराया आदि पहले बुकाये जायेंगे ...	६१
	—साबित कर्तोंके बुकाये जानेका तरीक़ा, व बचतके रूपसे देवका तरीक़ा ...	६१
	—जितने कज़ें साबित हो चुके हैं उन पर हिस्सा रसदी मिलनेका तरीक़ा ...	६२
५०	दिवालयिका क्रमसे दिये जानेसे पहिलेका किराया ...	६२
	—पहलेका किराया कज़ों मानकर हिस्सा रसदी बुकाया जायगा ...	६३

वह आयदाद जिससे कि कज़ें चुकाये जासकते हैं

५१	दिवालयिकी कारयर्दका सम्बन्ध ...	६३
	—दिवालयिके समयका प्रारम्भ दिवालयिके काम होनेमें अदालतमें आना जायगा ...	६३
	—तीन सालके अन्दर जो काम सबसे पहले हुआ हो उसके दिवालयिके समय माना जाना ...	६३
५२	जो आयदाद कज़ेखाहोंमें बाँटी जासकती है उसका विवरण ...	६४
	—अमानतरी चायदाद, निजारी अमानत, पहलनेके कपड़े भरतन नहीं दाते जावेंगे ...	६४
	—जिस सब छोड़ने वाले सामानकी कीमत २०० रु० से ज्यादा न हो तो वह बाय जायगा ...	६४
	—सैन आयदाद कज़ेखाहोंकी बाँटी जायगी उसका वर्णन ...	६५
	—प्रामेसरी नोट जो उस दिवालयिकाके पास अमानतमें हों ...	६५

दण	विषय	पेज
—	नो सोना जेवर बनानेको दिया गया हो और इसके पहले वह दिवालिखा हो गया हो ...	६५
—	दिवालिखे के पास जो जायदाद बतौर अमानतके हो या ट्रेडरके वह उसकी न होगी ...	६५
—	गवर्नेमेण्ट श्रमिकों को अमानत पाने पर मरदास बस ...	६५
—	इसमें से पाठिस दिवालिखे के कारिगों को दियाई गई ...	६५
—	डिपॉजिट के होने पर लेइनदार डिपॉजिटर का पूरा हक माना जावेगा ? ...	६५
—	तनखाह भी पैदा की हुई जायदादमें शामिल की जासकती है ...	६६
—	जबकि गादामें गाल भरा हो और चार्ज कर्जदारके पास कुछ समय रहती हो ...	६६
—	जो माल दिवालिखे के नौकर या सिपुर्देदारके कब्जे हो तो वह उसका समझा जायगा ...	६६

पिछले सौदों पर दिवालिखा होनेका प्रभाव

५३ इजराके सम्बन्धमें बिक्रीदारोंके अधिकारोंमें रुकावट ...

- जब लेइनदारों दिवालिखी बात में मालूम हो और डिपॉजिट रूपया नमूल करले ...
- रेगनी जायदाद पर जब रुकावट प्रभाव कुछ भा नहीं पड़ सकता है ...
- नीलाममें पहले दिवालिखा बन गया हो तो खरीदार जायदादका उसमें हक नहीं होगा ...
- यदि मोदीयून हाजिर न हो और रूपया जमा किया गया हो डिपॉजिटरको मिलेगा ...
- अगर किसी ने नैनीयतीये यह बात बिना जाने कि वह दिया लिया हो है खरीदी हो ...

५४ इजराय करने वाली अदालतोंके दिवालिखेकी जायदाद सम्बन्धी कर्तव्य ...

- अगर अदालतको दिवालिखेकी खबर मिल जाय तो इजरायी करिवारें रोक देवेगी ...

५५ स्वयं किये हुए इन्तकाल जायदादकी भेखड़ी ...

- कहाँ नैतकाल जायदादके दो वर्षों के अन्दरके मसूल हो जासकते हैं ...

५६ कुछ मामलोंमें तरजीहका रद्द किया जाना ...

- बरोक्षारने जब किसी एक लेइनदारको सब रूपया चुकाया हो दूसरोंको न दिया हो ...
- नैनीयतीये जब कोई कर्ज चुकाया गया हो, बर्खानीय इरादा न हो ...
- बर्खानीयके सोदे भिये हुए उस समय रद्द होगे जब वह अपने रूपयासे अन्य कर्जों न चुका सके ...
- वेसे सोदे और मामले बर्खानीयके भिये हुए रद्द होगे और काम कम न होंगे ...

५७ नैकनीयतीसे किये हुए सौदोंकी वचत ...

- जैसा दशम वक्तदारके किये हुए सोदे सही माने जावेंगे और रद्द न होंगे ...

जायदादका वसूल किया जाना

५८ आफिशल एनायनी द्वारा जायदाद पर कब्जा लिया जाना ...

- नियती ४ की दोसरे आफिशल एनायनी दिवालिखेकी जायदाद पर कब्जा करेगा ...
- आफिशल एनायनीके अधिकार और हक तथा कर्तव्योंका वर्णन ...

दफा	विषय	पृष्ठ
५९	दिवालियेकी जायदाद पर कब्जा लेना	७१
	—दिवालियेके वमरे, मजानम छुप कर तलाशी लेने आदिका हुक व अधिकार	७२
	—दिवालियेके लगे कौन कान सामान छाड़ दिया जासक्ता है	७२
	—दिवालियेकी जायदाद जब किन्ना दूसरक धम हो या कसमें हो तो वारण्ट जारी होगा	७२
६०	दिवालियेकी तनख्वाहका कर्जखानोंके लिये लिया जाना	७३
	—सरकारी नावरीकी तनख्वाह दिवालियेकी लेहनासामें भायी जावेगा	७३
	—दिवालियेकी आपदना आद बेस, बानमी, कब लइनासोंका बाप जायगा	७३
६१	जायदादका एकके पासले दूसरेके पास जाना या एक व दूसरेको मिलना	७३
	—एक अफिशल एसायनीके हाथत दूसरे अफिशल एसायनीके हाथमें जायदाद जासक्ता	७३
६२	बिला लाभको व भारी बार वाली जायदादका छोड़ दिया जाना	७४
	—जिस जायदाद पर ज्यादा कला लदा है या बहुत झगडना है वह छाड़ा जासक्ती है	७४
	—जिस मामक अन्दर भारी बार वाली या उलझनकी जायदाद छड़ा जासक्ती है	७४
	—अफिशल एसायनीके छड़ देने पर उस जायदादमें दिवालियाका हुक न होगा	७४
६३	ठेकेंका छोड़ा जाना	७५
	—दिवालियेके ठेका अदालतवा मज्गसे अफिशल एसायनी छड़ सकता है	७५
	—छानामें नद ई हुई चानों आदक लगे छड़ जानमें प्रावब	७५
६४	अफिशल एसायनी द्वारा जायदादका छुड़ाया जाना	७५
	—भगर २० दिनक अन्दर जायदाद छाड़नकी बाबत तय न हो ता फिर नहीं छाड़ा जासक्ती	७५
	—अदालत २० दिनका मियादमा अपने हुक्मत नदा सकती है	७६
६५	अदालत द्वारा मुआहिदोंके छोड़े जानेका अधिकार	७६
	—मुआहिदा पूरा न करनेक कारण अदालत हरना लाल्या सकता है	७६
	—जिस मुआहिदेमें लाभ हाता हो उसका अर्धों पर अदालत उस मुआहिदे पर बिषार करती	७६
६६	छोड़ी हुई जायदादके सम्बन्धमें सिपुर्देगीका हुक्म देना	७६
	—छाड़ा हुई जायदादके मिलनके लिय जब किसान चर्को अदालतमें दा हो	७७
	—एसा अजामें अपना आवका, हुक आद जाहिर करना जरूरत है	७७
	—अदालतका अधिकार शो लगानेका, सिपुर्दे करत तथा दनका	७७
६७	छोड़ी हुई जायदादसे जिस हानि पहुचती हो वह साबित कर सकता है	७८
	—छोड़ा हुई जायदादत जो शानि हो वह बतौर बर्जेके दिवालियामें बसूल का जावेगी	७८
६८	जायदादकी वसूलीमें अफिशल एसायनीके कर्तव्य व अधिकार	७८
	—गितनी मज्ग हो सके दिवालियेका कया वसूल करता वतव्य होगा	७८

दफ़ा	विवरण	पेस
—	जायदाद या हिस्सा बेचना, कपया वसूल करना, व्यापार चलाना, धुकहमा लड़ना, रेंटन करना आदि ...	७९
—	चंदा फ़ैमला करना, वसूली कपयों पर रसीद देना, अदालती कामों का करना आदि ...	७९
—	अभिप्राय प्राप्त करने के अधिकार, हक और कर्तव्यों का वर्णन ...	७९

जायदादका बांटा जाना

६१	हिस्सा रसदीका पलान व उसका बांटा जाना	८०
—	परिष्ठा हिस्सा रसदी एक सालके अन्दर पलान करके बाटा जाना चाहिये	८०
—	दूसरा हिस्सा रसदी जहा तक हो ६ मासके अन्दर बाटा जाना चाहिये	८०
—	हिस्सा रसदी बाटे जानेके पहले सूचना सब लेह्मदारोंको मेमो जवगो जिनके नाम दर्ज हैं	८०
७०	संयुक्त तथा अलगकी जायदाद	८१
—	बुदागाना कसे बुदागाना जायदादसे पहिले बुकाये जावेगे पोंडे अन्य कसे	८१
७१	हिस्सा रसदीका अन्दाजा लगाया जाना	८१
—	बुद्ध कपया रोके कर बांटी कपया हिस्सा रसदीमें आकिशक प्राप्तनी कष्ट देया	८१
—	जायदादका इन्तजाम करनेके लिये जो खर्च पड़े बसके लिये कपया रोका जासकता है	८१
७२	उस कर्ज-प्याहका हक जिसमें हिस्सा रसदीके पलानसे पहले, अपना कर्ज साधित न किया हो	८१
—	उन वसूलदारोंको हिस्सा मिल सकेगा जो रसदीके बाद अपना कर्ज साधित करे	८१
—	साधित होनेके बाद जो कपया दुबारा बटेगा उसमें उनकी हिस्सा रसदी मिलेगा	८१
७३	अन्तिम हिस्सा रसदी	८२
—	आखिरी कपया बांटेनेके पहिले उन लेह्मदारोंको सूचना देना जिन्होंने कर्ज साधित नहीं किया	८२
—	नोटिसकी प्रत्येक कलवा लेह्मदारोंको मोहजत भी मिल सकेगी	८२
७४	हिस्सा रसदीके लिये कोई दावा नहीं हो सकता	८३
—	जिसे हिस्सा रसदी न मिले वह अदालतमें अर्जी दे सकता है अगर दावा नहीं कर सकता	८३
—	अदालत, रोके हुए समयका ध्यान और अर्जाओं खर्चा भी दिना सकता है	८३
७५	दिवालिये द्वारा जायदादका इन्तजाम कराया जाना तथा उसे उसके पयज़में श्रम-फल मिलना	८४
—	दिवालियेसे जायदादका प्रबन्ध, व्यापारिक इन्तजाम आदि करना जासकता है	८४
—	अदालत दिवालियेसे काम लेनेके बदलेमें उसे उतार दे सकती है खर्चके लिये	८४
७६	वसे हुए हिस्सेको पानेका हकदार दिवालिया है	८४
—	उन सब लेह्मदारोंका कपया अदा हो जाय तो नार्क सब जायदाद दिवालियेको मिलेगी	८४

दफा	विषय	पृष्ठ
	चौथा प्रकरण	
	आदिफल एसायनी	
७७	दिवालियोंकी जायदादके लिये आफिशल एसायनीकी नियुक्ति तथा हटाया जाना ...	८५
	—बलकता, बर्ग, मकान, बरामें आफिशल एसायनीकी नियुक्ति कैसे होगी ...	८५
	—आफिशल एसायनीके कर्तव्य, अधिकार और हक्कोंका वर्णन ...	८६
७८	हस्तक देनेके अधिकार ...	८६
७९	दिवालियोंके व्यवहारके सम्बन्धमें कर्तव्य ...	८६
	—दिवालियोंके कामों व व्यवहार पर भी पूरा विचार दिया जायगा ...	८६
	—जेलसे छुटकारा पानेके समय दिवालियोंके व्यवहारोंकी रिपोर्ट मांगी जायगी ...	८७
	—जब कर्जदारने धोखेके काम जालसाजी, बेईमानी आदि की हो तो अदालत विचार करेगी ...	८७
८०	कर्जप्राप्तियोंकी फेहरिस्त दाखिल करनेका कर्तव्य ...	८७
	—लेहनदारोंकी अधिशर दिवालियोंके लेहनदारोंकी फेहरिस्त देनेका ...	८७
८१	धमकल-मेहनतकी फीस ...	८७
	—आफिशल एसायनीकी फीस अदालत निर्दिष्ट करेगी देहो नियम ११२ (५) ...	८७
८२	आफिशल एसायनीकी बैठनवानी ...	८७
	—अदालत, आफिशल एसायनीकी बरनी आदेशे पैदा हुई इमिती की पूर्ति करा सक्ती है ...	८८
	—अदालतका कर्तव्य है कि वह आफिशल एसायनीमें घल्लाके बोमें जवाब तलब करे ...	८८
८३	किस नामसे दावा दायर किया जाना चाहिये या दावा उस पर होना चाहिये ...	८८
	—सब बार्बार् ^१ दिवालियोंकी जायदादका आफिशल एसायनी ^२ इस नामसे की जायगी ...	८८
८४	दिवालिया होने पर आफिशल एसायनी अपनी जगहसे हट जायेगा ...	८८
	—अगर छुट्टी आफिशल एसायनी दिवालिया हो जाय तो वह अपने पदसे कौत हटा दिया जायगा ...	८८
८५	मीटिंग आदि करनेके कर्तव्य तथा उसकी पाबन्दी ...	८९
	—लेहनदारोंका मशआरानेके लिये मीटिंग करना उचित माना गया है ...	८९
	—मीटिंगमें पास हुए प्रस्ताव पर अमल करना जरूरी होगा ...	८९
	—आफिशल एसायनीको जायदादके प्रबन्धमें पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त रहेगी ...	८९
८६	अदालतमें अपील ...	८९
	—आफिशल एसायनीके प्रत्येक काम और हुक्मकी अपील अदालतमें हो सकेगी ...	९०
	—इस कानूनकी दफा १०१ के अनुसार २० दिनोंके अन्दर अपील करना चाहिये ...	९०
८७	अदालतका दवाव ...	९०

वर्ग	विषय	पंज
—	आरिश्तल एसायनों के खिलाफ़ कार्रवाई की जायगी तथा उसने कोई तिलक काम किया हो	९०
—	एसायनों के हिसाबका जाल या जासकती है, जवान पूरा आसकता है	९०

पाँचवां प्रकरण

जांच कमेटी

८८	जांच कमेटी	९१
—	छेदनदारोंकी एक जांच कमेटी, एसायनोंके कामोंकी जांचके लिये बनाई जासकती है	९१
—	चीन लोग मेमबर होंगे, कमेटी क्या करेगी, कैसे बनाई तथा इक क्या होंगे	९१
८९	जांच कमेटीके, अधिकार, आरिश्तल एसायनोंकी जांचके सम्बन्धमें	९१
—	कमेटीको जो अधिकार दिये गये हों उनमें ब्यादा प्रयोगमें नहीं लाये जासकते	९१

छठवां प्रकरण

कार्यक्रम

९०	अदालतके अधिकार	९२
—	दिवालयके मुकदमोंमें सब कार्रवाई, जमाना बीमानीरी तरह की जावेगी	९२
—	अदालतके अभियोगका वर्णन, महाद्वान आदिके सम्बन्धमें कार्रवाई	९२
९१	पिटोशनोंका एक साथ शामिल किया जाना	९२
—	एकही कर्जदारके अनेक छेदनदारोंकी अनेक अभिया एकात्मि शामिल होगी	९२
९२	एकके स्थानमें दूसरे कर्जस्वाह द्वारा कार्रवाईका किया जाना	९४
—	जिसन दिवाल्या बचनेकी अर्जा दी हो और ठीक पक्की न करेता बदल दिया जायगा	९४
९३	कर्जदारके मर जाने पर भी कार्रवाईका चालू रहना	९४
९४	कार्रवाईको रोकनेके अधिकार	९४
९५	किसी शरीकदारके विरुद्ध दिवालयको दुरस्वाम्तका दिया जाना	९४
—	नाराजियोंमें कर्ज लिया हुआ व्यक्ति नाश्रि होने पर दिवाल्या नहीं बनाया जासकता	९५
९६	कुछ टेम्पान्डेन्ट्सके विरुद्ध दुरस्वाम्तका सारिज किया जाना	९५
—	अनेक दिवालयामें जब कुछको अदालत परी करदे ता नारीक बग न मान जायेंगे	९५
९७	शरीकदारोंके विरुद्ध जुदागाना पिटोशनोंका दिया जाना	९५
—	एक मापलसे सम्बन्ध रखने वाले जब अनेक मापल हों तो पक्की अदालत सुनेगा	९५

क्रमांक	विवरण	पेज
१६	ऑफिशियल एसायनी तथा दिवालियेके अधिकदार द्वारा चलाये जाने वाले मुकदमे ...	१६
	—एक सार्जीदार दिवालिया बननेमें दूसरे सार्जीदार उन्नत कर सकते हैं ...	१६
१६	सामके नामसे मामलेका चलाया जाना ...	१६
	—जिस नामसे दफ्तार चलती हो उस नामसे दिवालियेकी कोर्वाई चल सकती है ...	१७
	—किसी फर्मका नाराजिब सार्जीदार दिवालिया करार नहीं दिया जा सकता ...	१७
१७०	अदालत दिवालियाके धारण ...	१७
	—कायदा कौनसीके बाण्डोंके नियम इस दिवालियेकी कोर्वाईमें लागू होंगे ...	१७
	—कायदा कोनसाही दफ्तार ७७ (२), ७९, ८२, ८३, ८४, तथा १०२ का वर्णन ...	१८

सातवां प्रकरण

मिथाद

१०१	अदालतके लिये मिथाद ...	१९
	—एसायनीके काम या हुक्मकी अग्रील २० दिनोंके अन्दर हो सकती है ...	१९
	—जबके लिये जमानत हा मागती है अगर अदालत मुनासिब समझ ...	१९

आठवां प्रकरण

दण्ड

१०२	यिला बहाल किया हुआ दिवालिया यदि कर्तुं लेवे ...	१९
	—बहाल होनेमें पहिल ५०) ६० से ज्यादा वर्षे जिया हो तो १ मासकी जेलकी सजा जरूर होगी ...	१००
	—वैसी दशमें सजा न होगी और वैसा हान्तमें अपराध न माना जाएगा ...	१००
१०३	कुछ जुर्मानेके लिये दिवालियाका सजा दिया जाना ...	१००
	—जब दिवालियेने बड़ी घाता न पैदा किया हो, धोखा दिया हो या छिपाया हो या जाल बनाया हो ...	१००
	—पूछा जाना खर्च किया हो, खिस्टाही न हो, या बदल दिया हो या ऐसेही अन्य काम किये हों ...	१००
	—अपना लहना छिपाया हो, जायदाद नचाई हो, या फोन किया हो, धोखा दिया हो ...	१००
	—किसी एक लेहनदारकी सजा दे दिया हो दूसरोंको कम या कुछ न दिया हो ...	१०१
	—ऊपरके जुर्मानेके साबित होने पर २ साल जेलखानकी सजा दिवालियेको दी जा सकती है ...	१०१
	—प्राविन्सल फुडरस अपना उठा लेना शुरू नहीं माना गया बल्कि सजा दिवालियाका ही है ...	१०१
	—सजा देनेके लिये मुद्देकी, दिवालियेकी जयत साबित करना चाहिये ...	१०१
	—दिवालियेकी कोर्वाई जारी रहते समय फोर्जदरी मामला चलाया जा सकता है ...	१०१
	—इस दफ्तारके अनुसार दिवालिये पर जमाना नहीं लगा बल्कि जेलकी सजा होगी ...	१०१

दफा	विवरण	पेज
१०४	दफा १०३ के जुमॉर्के लिये कार्यक्रम ...	१०१
	—अकिष्ण एसायनीमे रिपोर्ट करना चाहिये कि दिवालियेने अप्रकृ अपगन किया है ...	१०२
१०५	यहाल होनेके बाद या नत्कीया होनेक बाद भी जिम्मेदारी ...	१०३

नवां प्रकरण

दिवालियेकी छोटी कार्रवाईयां

१०६	छोटे मामलोंमें सरसरीकी कार्रवाईयां ...	१०३
	—जब दिवालियेकी जायदाद (१०००) ५० से ज्यादा न हो तो सरसरी कार्रवाई की जावेगी ...	१०४
	—मामूकी कार्रवाईमें असील तब होती जब परिके अर्पाक करनेका हुक्म मिल जाय ...	१०४
	—सरसरी कार्रवाईमें १३६३ कानून बंद दिया जावेगा, प्रिन्सिपल्स अर्थात् नहीं है ...	१०४

दसवां प्रकरण

विशेष नियम

१०७	कारपोरेशन आदिका दिवालियेकी कार्रवाईसे बरी होना ...	१०५
	—रिजिस्ट्रार फर्म या कम्पनी दिवालिया नहीं बनाये जासकेंगे ...	१०५
	—एग्जिक्यूटिव, कारपोरेशन, रिजिस्टर्ड कम्पनी लिमिटेडमें जाती है ...	१०५
१०८	दिवालियेकी हालतमें मरने वाले कर्जदारकी जायदादका दिवालियेकी कार्रवाईके सम्बन्धमें प्रबन्ध ...	१०५
	—कर्जदारके या जाने पर भी उसकी जायदाद दिवालिया अदालतके अधिकारमें जासकती है ...	१०५
	—किन शर्तों पर हुए कर्जदारके खिलाफ दिवालियेकी अर्थात् दी जासकती है ...	१०६
१०९	जायदादका मिलना तथा उसके प्रबन्धका तरीका ...	१०६
	—जब हो हुए कर्जदारके दिवालिया बनानेकी अर्थात् हो तो उसकी कार्रवाईका तरीका ...	१०६
११०	कानूनी वारिस द्वारा रुपयेकी अदायगी या जायदादका अलहदा किया जाना ...	१०७
१११	एडमिनिस्ट्रेटर जनरलके अधिकारोंकी रक्षा ...	१०८

ग्यारहवां प्रकरण

नियम (रूलस)

११२	रूलस (कायदे बनानेके अधिकार अदालतोंको) ...	१०९
	—इस कानूनके कानूनों के लिये लानेके लिये समय समय पर अदालतें नियम बना सकती हैं ...	११०
	—किन किन कानूनोंके सम्बन्ध में रूलस बनाना चाहिये उनका वर्णन ...	११०

दफा	विषय	पेज
११३	हलसके लिये स्वीकृति मिलना ...	११०
	विवाय कलकत्ता हार्नेमेर्टके अन्य अदानमें रुस्तकी मजूरी प्रान्तिक सरकारसे लेगी ...	१११
११४	हलसका प्रकाशित किया जाना ...	११०
	—जो रुस्त बनाये जावेगे वे सब सरकारी गजटमें छापे जावेगे ...	१११

चारहवां प्रकरण

११५	हल एक्टके अनुसार किये हुए इन्तकाल आदिका स्टाम्प या करसे बरी होना ...	१११
	—दिवानिया अदालतके बैराया, देननाया, मोबसी, आदिके कापडोंमें स्टाम्प बरौदा नहीं छेगेगा ...	१११
	—आफिजल एसायनीका अर्वा आदिमें भी कोई स्टाम्प नहीं छेगेगा ...	१११
	—एसायनीका तरफसे काप करने नाखोंकी भी कोई स्टाम्प आदि नहीं छेगेगा ...	१११
११६	गजट शहादत होना ...	११२
	—सरकारी गजटमें जो प्रकाशित होगा वह शहादतमें काप या सफता है ...	११२
११७	हलफनामोंकी तस्दीक ...	११२
	—हलफनामों, वहां पर किस अफसर द्वारा कैसे तस्दीक किये जायें उसका वर्णन ...	११२
११८	व्यवहारिक पलतीके कारण कार्रवाइयां रद्द नहीं होनी चाहिये ...	११३
	—छिन्ने आदिनी पलती होने पर वह कार्रवाई रद्द नहीं हो जावेगी ...	११३
	—व्यवहारिक पलती, नेतरतीकी सबसे बड़ काम रद्द नहीं हो जावेगा ...	११३
११९	ट्रस्टीके दिवालिया होने पर दूसरे ऐक्टका लागू होना ...	११३
	—अगर दूरी सुद दिवालिया हो जाय तो बरद दिया जावेगा ...	११४
१२०	सरकारको पाबंद करने वाले कुछ नियम ...	११४
	—गजोंका एक हुमेसे पढ़के अदा किया जाना, तरकीया, आदिनी पाबंदी सरकार पर भी है ...	११४
१२१	मुलाकात के अधिकारों की वधत ...	११४
१२२	उन हिस्सा रसदीका सरकारको मिलना जिनका कोई दावेदार न हो ...	११४
१२३	दफा १२२ के अनुसार सरकारमें दिये हुए रुपये पर दावे ...	११५
	—लेनदारके रुपया न लेने पर अब सरकारमें जमा हो जाने तो कैसे वापिस मिलेगा ...	११५
१२४	दिवालियेकी किताबोंका मुयाजना व कब्ज़ा ...	११५
	—दिवालियेके नदी खानों पर समते पढ़के कम्प्रा एसायनीका होगा ...	११५
१२५	फीस ध.....की सैकड़ा ...	११५
१२६	अदालतें एक दूसरेकी सहायक होगी ...	११६
१२७	कानूनोंकी मसूखी ...	११६
	—तीसरी सूचीमें जो कानून बनाये गये हैं वे सब मसूख कर दिये गये हैं ...	११६

पहिली सूची (First Schedule)

क्रजकुवाहों (लेहनदारों) की भीटिंग

१ कजकुवाहों की भीटिंग	...	११७	१३ कजकुवाहों का मानन जोड़ देने के लिये कहने का अधिकार	...	१२०
२ भीटिंग का युगाया जाना	...	११७	१४ शरीरकदरता सुवृत्त	...	१२०
३ भीटिंग के नोटिस	...	११७	१५ एसायनों के अधिकार कर्ता साविन मानन के कारण	...	१२०
४ दिनालियिका इनदार	...	११८	१६ मौकसी	...	१२१
५ नोटिस में पहुँचने पर भीटिंग की कार्यवाही का रद्द होना	...	११८	१७ प्रार्थना की दस्तावेज	...	१२१
६ नोटिस के जारी होने का सुवृत्त	...	११८	१८ प्रार्थना का आम अधिकार	...	१२१
७ भीटिंग का कार्य	...	१२८	१९ भीटिंग की तारीख से १ दिन पहले प्रार्थना का दाखिल किया जाना	...	१२१
८ बेयरमिन	...	११९	२० आफिसल एसायनों का स्वयं प्रोक्त होना	...	१२१
९ बोट देने के अधिकार	...	११९	२१ भीटिंग का बन्दा दिया जाना	...	१२१
१० कुछ कजों के हस्त-पदों बोट नहीं दिये जायेंगे	...	११९	२२ कार्यवाही विवरण	...	१२१
११ महसूला कजकुवाहों	...	१२२			
१२ उन दस्तावेजों का सुवृत्त जो काबिल तलाशिले के हैं	...	१२२			

दूसरी सूची (Second Schedule).

कजों के सुवृत्त

१ सुवृत्त दाखिल करने का समय ...	१२२	१५ जबकि कामानत बादमें बसूल हो तब सशोधन	१२५
२ सुवृत्त दाखिल करने का तरीका ...	१२२	१६ हिस्सा रसरीके बचि रदना ...	१२६
३ हलफनामा दाखिल करने का अधिकार ...	१२२	१७ पाने की हद ...	१२६
४ हलफनामोंमें कपड़ मान दिखलाई जाना चाहिये	१२२	(रेहन की जायदाद का हिस्सा व घेचना)	
५ हलफनामोंमें कामानत का जिक्र होना ...	१२३	१८ रेहन नामे आदि की तहकाशत ...	१२६
६ कजों का बचि करने का अधिकार ...	१२३	१९ दस्तावेज इन्तबाल ...	१२७
७ सुवृत्त देने के व जस का मुआयना करने का हक	१२३	२० निकाका कपया ...	१२७
८ सुवृत्तों के दफा घयाया जाना ...	१२३	२१ तहकाशत पर कार्यवाही ...	१२८
(महसूल कजकुवाहों का सुवृत्त)		२२ समय समय पर कपये की आमदनी ...	१२८
९ जबकि कामानत बसूलरी या उखी हा ...	१२३	२३ सुद ...	१२८
१० जबकि कामानत जोड़ दी गई हो ...	१२४	(चह कजों जो भविष्यमें अदा होना चाहिये)	
११ दूसरे मामलोंमें सुवृत्त ...	१२४	२४ भविष्यमें घुपये जाने वाले कज ...	१२९
१२ कामानत की कीमत का लगाया जाना ...	१२४	२५ सुवृत्त का मान लिया जाना व सारिन होना ...	१२९
१३ कीमत में सशोधन ...	१२५	२६ बेकायदा सुवृत्त का सारिन होना ...	१३०
१४ अगदा बसूल हो जाने पर लीया दिया जाना	१२६	२७ सुवृत्त के बारेमें अदालतके अधिकार ...	१३०

तीसरी सूची (Third Schedule).

प्रान्तिक कानून दिवालिया एक्ट नं० ५ सन १९२० ई०

**Provincial Insolvency Act,
No. 5 of 1920.**

भारतके समस्त प्रांतोंमें प्रचलित
सर्वाङ्गपूर्ण व्याख्या और हाल तककी समग्र
नज़रों एवं उदाहरणों तथा अन्य
कानूनोंके पूरे हवालों सहित

लेखक :-

वाचू रूपकिशोर टाण्डन

एम० ए०; एलएल० बी०; एम० आर० ए० एत० एडवोकेट

प्रकाशक :-

पं० चन्द्रशेखर शुक्ल

मुद्रित :-

कानून प्रेस, कानपुर

The Provincial Insolvency Act.

Act No. 5 of 1920.

प्रान्तिक कानून दिवालिया

एक्ट नं० ५ सन् १९२० ई०

भारत व्यवस्थापिका सभा (The Indian Legislative Council) द्वारा

पास किया हुआ और

ता० २५ फरवरी सन १९२० ई० को गवर्नर जनरल महोदय

द्वारा स्वीकृत किया हुआ

यह एक्ट प्रेसीडेंसी टाउन्स (Presidency Towns) तथा रगूत को छोड़कर शेष ब्रिटिश भारत (British India) की भदालतों में प्रयोग किये जानेवाले कानून दिवाला को सम्प्रदात तथा संशोधित करने के लिये बनाया गया है।

सूची यह आवश्यक प्रतीत होता है कि दिवालिया सम्बन्धी कानून जिनका प्रयोग प्रेसीडेंसी टाउन्स तथा रगूत को छोड़कर ब्रिटिश भारत की शेष सब भदालतों में होता है सम्प्रदात तथा संशोधित किया जावे अतः नीचे लिखा हुआ कानून बनाया जाता है।

दफा १ संक्षिप्त नाम और विस्तार

(१) यह एक्ट सन् १९२० ई० का प्रान्तिक कानून दिवालिया (The Provincial Insolvency Act 1920) कहलायेगा।

(२) सूची में दिये हुए जिलों (The Scheduled Districts) को छोड़कर यह एक्ट समस्त ब्रिटिश भारत में लागू होगा।

व्याख्या—

यह कानून कहां पर लागू नही होगा और विस्तार—यह प्दान रहे कि यह कानून प्रेसीडेंसी टाउन्स (बलुक्ता, बम्बई, मद्रास के शहरों) और विशाखी, रगूत तथा नीचे सूची में दिये हुए स्थानों में लागू नहीं होगा बल्कि अंग्रेजी भारत के सब हिस्सों में लागू होगा।

सूची में दिये हुए जिलों में यह कानून लागू न होगा—सूची में दिये हुए जिलों का अभिप्राय उन जगहों से है जो सन् १८७४ ई० के शिन्धून डिस्ट्रिक्ट एक्ट न० १४ (The Schedule District Act XIV of 1874) की पहली सूची (The First Schedule) में दी हुई हैं वर मगर यह है उन जगहों में यह कानून लागू न होगा—

बङ्गाला प्रेसिडेंसी (Bengal Presidency)—मकसदगिरी और दामिनिश्चरी बमिस्ती, चरगज्जे पदाई विभाग (The Hill Tracts) सभास परगना, चार्ग नामपुर यह बिहागें हैं (The Chota Nagpur) को बमिस्ती तथा अंगुन का सद्वृत्त ।

बम्बई प्रेसिडेंसी (Bombay Presidency)—मिथ, जून, मरवावा सद्वृत्त के कुछ गांव ।

मध्य प्रदेश (The Central Provinces)—बोस बज्जतार तेलियादामिया तथा उदियागारा नामगिरी ।

मद्रास प्रेसिडेंसी (Madras Presidency)—गन्नामके मन्तिरा, नेतुरी सिर्गिरी तथा और मन्तिरा व मुत्ता आर विजयपुरम् इत्यादि गांवकुण्डा इत्यादि गांव तथा मिन्नमगन्नासुम् ताम्बुल तथा लंगा विभाग, हिन्दू पराम्भगा क लकाईल दारु मिन्म मन्तिरा दारु भी दामिन्त है ।

संयुक्त प्रदेश (United Provinces)—इम्फू, गुरुवान, वाजपुर, बारांशुर, जन्पुर, बद्रपुर, गिरपुर, गानगमठ व बिन्हा नामी तगाई परगने, दामदूत सिन्धे पुत्र लण्ड, मिन्तपुर जिन्हे कुछ टपा ।

नीमीन प्रदेश (N W F Provinces)—इलाहा, पेशावर, बोहार, चतु, छेय इत्यादि गाँ ।

पञ्ज घक—बेरागाला, लाङ्ग व स्यंगल बिन् ।

मुनफरिन्तै—हुग गन्ती, आगमान व नामेवार दारु अगवेर प्रात ।

आमानम प्रान्तके—जामान व पगाडा सिन्धे, मानपुर ए गरा ।

प्रजासली टाउन (Presidency towns)—इन्ही बमिस्ती जनरल क्लॉजेन ऐक्ट (General clauses Act) की दफा ३ में बज्ज ४१ में दी हुई हैं ।

कानूनी (Karnachi)—यह वर ऐक्ट अन्तर्गामी कानून दिवाण क्लॉजेन ऐक्ट या पानु अत्र नहीं है । मानिक जस्टिस कमिटी (Civil justice committee) का फिक्काज व कर्गनी टाउन पर यह ऐक्ट लागू गवना धरित नहीं समना तथा और प्रजासली टाउन पर प्रजासली ऐक्ट (Presidency towns Insolvency Act) लागू पर लागू किया गया दसिधे गने १९२६ ई० वर ऐक्ट ९ ।

प्रयोग—यह ऐक्ट म बज्ज कर्गनी पर भी नम दिया हुआ है कि यह ऐक्ट कबने लागू होगा पानु इत्यादि छात्र होव २५ फी व। सने १०२० ई० से मक्दना क डिधे गवना मक्दना जनल मक्दना इदने जगनी खाही । यह ऐक्ट अ द्दि सन १०२० के ऐक्ट १०५ वर मन्ति प्रदामना भी बमिस्ती ८०७१ के जनरल क्लॉजेन ऐक्ट वर १० (The General Clauses Act X of 1897) की दफा ५६ अन्तर्ग अगव तथा जद क्लॉजेन जनरल द्वाय बज्जो हुण कानूनने लिये यह म दिया गया है कि बज्ज कबने प्रयोग किया जावया तो यह मक्दना बमिस्ती कि बज्ज कानून उम साधारण लागू समना नित साधारण मक्दना जनरलने इनके डिधे जगना रमिक्ती है ।

ब्रिटिश भारत (British India)—ब्रिटिश मक्दना अमिस्ती उम नामिसेही भी मक्दना जनरल हिन्दू या उमने मानिक सिन्धे मक्दना या दूधे दमिस्ती प्रव गने हो । ब्रिटिश मक्दना पराम्भगा जव व क्लॉजेन ऐक्ट सने १८५७ ई० के ऐक्ट १० (The General Clauses Act X of 1897) की दफा ३ में दी हुई है ।

दफा २ परिभाषा

(१)—जब ऐक्टमें जव तक कोई बात विषय या प्रजासली विपरीत न पदुती हो तबतक मन्तिरा दिवित मक्दनाका अर्थ रस मक्दना समझना चाहिये—

करते हैं परन्तु इस ऐक्टमें इस सम्बन्ध अर्थात् केवल उन्हीं कर्जों (Debts) से सम्बन्धन चाहिये जो इस ऐक्ट की दफा ३८ के अनुसार स्थापित किये जा सकते हैं।

महकाज़ा (बी) इस क़ानूनमें अदालत ज़िला (District Court) की परिभाषा दी गई है। पुराने ऐक्टमें कोई शब्दसी परिभाषा दी गई थी परन्तु इस ऐक्टके अनुसार कार्य करनेका अधिकार अदालत ज़िला (District court) को प्राप्त है और इसी शब्द (District court) का प्रयोगभी ऐक्टमें किया गया है इस कारण इसी परिभाषा दे दी गई है।

महकाज़ा (सी) इस क़ानूनमें प्रयोग किये हुये बिलियर्ड्स एपेंडिक्स दफा ७९ व ८० तथा एपेंडिक्स (Appendix) में दिये जा।

महकाज़ा (डी) (Property) 'जायदाद' शब्द की पूरी परिभाषा इस ऐक्टमें नहीं दी गई है। इस शब्द का प्रयोग जायदाद मनकूला, (Moveable), और मनकूला (Immoveable) तथा उन दावों के लिये (Actionable claims) किया गया है जो क़ानून बालिग है।

मेसेस कापी मर्से इम्प्रायल जो एपेंडिक्स 11 Ind Case 14 में यह निश्चित हुआ था कि अगर कोई माल किसी अदालतके सुप्रीममें बेचनेके लिये दिया गया हो और अदालतके उस मालके अन्वेषण करतवा अधिकार हो तो क़ानून दिवारा (Insolvency Act) के अनुसार वह माल अदालतकी जायदाद (Property) समझी जावेगी और वसूली भी उसमें सिवाय अपने क़र्जों में से सकता है।

ऐसा ही बात रिमथ बनाम इलाहाबाद बैंक 23 All. 131 में निश्चित की गई है।

अमनादास बनाम बिनायक 10 Ind. Cas 698 में यह निश्चित हुआ था कि लाठी कर्माई भी जायदाद समझना चाहिये। रामचन्द्र बनाम झापाबास 19 C L J. 83 में यह तय हुआ था कि समझनाइसी जायदाद है। अधिकारानन्दन विस्वास 3 Cal 434 के मामलेमें यह तय हुआ था कि क़ानून दिवाराके अन्वेषणमें उपरान्त जायदाद समझना चाहिये। अनन्तमिश्र बनाम बालवासीह 48 Ind Cas. 526 में यह तय हुआ था कि अविनयक मिताश्रम दिव्दू घरानेमें दिवाराके का बिलग मया हुआ हिस्सा जायदाद न समझी जावा चाहिये।

इसलिये सुन्नाल बनाम राधागोहन 54 Ind. Cas. 93 में यही निश्चित हुआ था कि यदि किसी मिताश्रम दिव्दू घरानेमें वित्त दिवाराके क़ार दिया जावे और जिन कर्जोंके लिये वह दिवाराकिया करार दिया गया हो नर्जित कर्जोंके लिये न लिए गए हों तो उस दिवाराकिया जायदाद तथा उसके अन्वेषण कर्जोंका हिस्सा सब रिक्वायर (Requirer) की सुप्रीममें आ जावेगा। वरदलालाबायी 2 M.L. 15 के मामलेमें यह तय हुआ था कि टूटकी जायदाद दिवाराके जायदाद नहीं मानी जावेगी क्योंकि उस जायदादकी अपने कर्जोंके लिये अख़्तदा कर्मेका अधिकार टूटकी दिवाराकियाकी नहीं है।

महकाज़ा (ई) इस क़ानूनमें महकाज़ा व बिलग महकाज़ा कर्ज स्वीक़ानका शिक है। महकाज़ा (Secured) कर्जस्वाइसे तात्पर्य इस अर्थस्वाइका है जिसने अपने कर्जोंके लिये कोई जमानत ले ली हो अर्थात् वह अपने कर्जोंको कर्जदारकी जायदादके वसूल कर सकता हो चाहे जायदाद कर्जोंके हावम हो या उसने किसी दूसरेको दे दी हो और ऐसे कर्जस्वाइका इतक और बिलग महकाज़ा (Unsecured) कर्जस्वाइसे इक़तें पड़ले होगा अर्थात् बिलग महकाज़ा कर्जस्वाइका या तो कर्जदारकी जायते जगहा कर्जों वसूल कर सकते हैं या उस जायदाद से वसूलकर सकते हैं जो महकाज़ा कर्जस्वाइसे के बग़ैर उन पर नये।

कर्जस्वाइका कर्ज जिस जायदादके लिये सुस्थित किया जाता है उसे जमानत (Security) कहते हैं।

महकाज़ा (एफ) इतकाल जायदाद (Transfer of property) का अर्थ केवल जायदादकी इतकाल कर देने, लिख देने या दे देनेमें नहीं है बल्कि जायदादके हक व अधिकारों को इतकाल कर देने, लिख देने व दे देने से है।

उपदफा (२) बहुतेके ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग शा एक्टमें दिया गया है परन्तु उनकी कोई परिभाषा इस ऐक्टमें नहीं दी गई है। गो उनकी परिभाषा जानता दीवानोंमें दी गई है उन शब्दोंका अर्थ वही समझना चाहिए जो जानता दानाओंमें दिया हुआ है उदाहरणस्वरूप हुक्म (Order), गनकूला जायदाद (Moveable property) दिक्री (Decree) आदि शब्दोंकी परिभाषा जानता दीवानोंमें दी हुई है परन्तु इनकी परिभाषा शा एक्टमें नहीं है इत्यादि।

पहला प्रकरण

अदालतका सङ्गठन तथा उनके अधिकार

(Constitution & Powers of Court)

दफा ३ दिवालेकी कार्रवाईके लिये अधिकार की सीमा

(१) अदालत ज़िला (District Court) को इस ऐक्टके अनुसार कार्य करनेका अधिकार प्राप्त होगा:—

परन्तु प्रान्तिक सरकारको अधिकार है कि वह सरकारी गज़ट द्वारा घोषणा प्रकाशित करके अदालत जिलाकी मातहत किसी दूसरी अदालतको, किसी खास किस्मके मामलात करनेका अधिकार दे सके और इस प्रकार जिस मातहत अदालतको अधिकार दिया जावेगा उसको अपने अधिकारकी सीमामें वही अधिकार प्राप्त होंगे जोकि अदालत जिलाके इस ऐक्टके अनुसार प्राप्त है।

(२) इस ऐक्टके लिये अदालत खकीफाभी अदालत जिलाकी मातहत समझी जावेगी।

व्याख्या—

क्लाज (१) अधिकारकी सीमा (Jurisdiction)—अदालत जिला प्रधान दीवानी अदालत है जिनको मूल अधिकार प्रेसीडेंसी डाउन्स व ग्यूनकी ओड़कर अन्य जगहोंमें प्राप्त है और अदालत जिलाके हाकिम को जिला जज (District Judge) कहते हैं। इसलिए जिला जजनी अदालतकी दिवालेकी दायित्वों तनने का अधिकार है।

अदालत जिला उसी समय दूसरी अदालतोंकी करीवाई इन्साल्ट डिस्ट्रिमें इस्तखेफ कर सकती है जबकि वह इस ऐक्टके अनुसार काम करती हो आर दूसरी सूतमें उसे ऐसे इन्साल्ट करनेका अधिकार नहीं है अर्थात् जब मद्रून दिक्री दिवालिया करा दे दिया गया है या उसकी जायदादके लिए रिसीवर चुर्कर कर दिया गया है उस समय सैरियत अदालत दिवालियाके अदालत जिलाको दूसरी अदालतोंकी इन्साल्ट डिस्ट्रिगे कार्रवाईमें इस्तखेफ करनेका अधिकार प्राप्त है देखो—अबूकूमर बनाम केशोदात 39 All. 547.

सहकारी जिला जज (Additional District Judge)—सहकारी जिला जजके उन कामोंको करेंगे जिन्हें जिला जज उनके सिपुर्दे करे और उन कामोंके करनेमें उनको वही अधिकार प्राप्त होंगे जो जिला जजके प्राप्त है।

सहकारी जिला जज—जिला जजका मातहत नहीं है, देखो—मास्टरनल बनाम भीराल 34 All. 382; 9 A. L. J. 371. ऊपर दिए हुए मामलेमें अपीले समय यह भी प्रश्न उठा था कि जूनि (एवैक्लनल)

सदस्य जिनका जन्मोद्देशिक समझे सुनना अधिकार प्राथमिक सरकार द्वारा नहीं दिया गया है न उसका प्राधान्य कीर्ति है न उसका उपयोग। इसाभियोग मामला सुनिश्चित अधिकांशी नहीं था परन्तु उक्त मामले में यह तय हुआ कि अदालत जिनका दिव्यक मान्य सुननेका अधिकार है और सदस्यी जिनका जिन निमित्त का सुनने का अधिकार है न उनका उपयोग उन कालों को करना था अदालत जिनका उनके सुनने से तथा उन सुनने के तर्कों को नहीं उठे नहीं और फिर प्राप्त हो तो प्रत्यक्ष जिनका है। किन्तु इस मामले में जिनका जन्मोद्देशिक यह कि यह सदस्यी जिनका जन्मोद्देशिक सुनना था अदालत सदस्यी जिनका जन्मोद्देशिक सुनने का अधिकार प्राप्त था और उसको नईमित्त जिनका जन्मोद्देशिक उस मामले में नईमित्त एक था था उस सदस्यी जिनका जन्मोद्देशिक अधिकार प्राप्त था और उसने अपने अधिकार प्रथम के अधिकांशी मामलों में दिया है। परन्तु यह दृष्टान्त जन्म प्राथमिक सरकार द्वारा घोषित नियम द्वारा सुननेका आधार पर काम करता है। या उस समय उस दफा ७-(२) के अनुसार मातृ अदालत ही समझना उचित प्रतीत होता है।

अर्थ (Proviso)—प्राथमिक सरकारों यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपना जिनका मान्य अदालतकी जौति अदालत जिनकी मातृद्वारा दिव्यनिर्णय का काम करनेका अधिकार द सुनने के परन्तु इस प्राधान्य अधिकार देनेकी अथवा प्राथमिक सरकार की जन्मोद्देशिक प्रकाशितता आना चाहिए और जन्मोद्देशिक प्रकाशित कीर्ति इस प्रकार का प्रथम में यह भी प्रकट किया गया चाहिए कि किस प्रकार के मामले सुननेका अधिकार उन मतदान अदालतों दिया गया है।

वृत्ति (Proviso में) Class of cases (जिस जिसके प्रकार) का उल्लेख है इसमें यह प्रकट होता है कि प्राथमिक सरकार मान्य अदालतोंकी दिव्यनिर्णय मामले सुननेका अधिकार देते समय यह बता सकती है कि अदालत मान्य जिन किन्तु प्रकट करनेकी परन्तु वह उसके अधिकार मामलों परितर्जन नहीं कर सकती है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो इसका भी उल्लेख Proviso (में) में अवश्य किया जाता—तर्जनी यह है कि अदालत मान्य इस प्रकार के लिए प्राथमिक सरकार द्वारा प्राप्त अधिकारोंका केवल अपा अधिकार सीमा में ही प्रयोग कर सकता है उसके बाहर नहीं।

रिती मान्य अदालत (Any Subordinate Court) से अभिप्राय यह है कि इसकी भी दिव्यनिर्णय के मामले सुननेका अधिकार दिया जा सकता है।

यदि, रिती अदालतका नियमन दायित्व करने समय हमने सुननेका अधिकार प्राप्त न हो, परन्तु उसे विनिश्चित केमन्ने पाई अधिकार प्राप्त हो जन्म तो ऐसा अदालत फसल उचित कैसदा प्रकाश दिया, देली दृष्टान्त बनाम स्ट्यूडेंट 6 A L J 483, 2 L C 223

दफा ४ दिवालेके सब प्रदनोंको तय करनेके लिये अदालतके अधिकार

(१) यदि अदालत के सामने कोई दिवालेका मामला हो तो उसमें जो प्रदत अदालतके सामने आवे या जिन प्रदतोंको निश्चित करना अदालत पूर्ण न्यायके लिये प्रथम जायदादको पूर्ण रूपसे बाँटने के लिये उचित या आवश्यक समझे तो उन सब प्रदतों को तय करनेका पूर्ण अधिकार अदालतको होता यदि वह प्रदत कानून हो या बाकिपाती या बाँटने वह दृष्टिकोण का हा या दुरु माकूल (Priority) के हा या और किसी किस्मके हा परन्तु साथ साथ इस प्रेडक नियमोंका ध्यान रखना आवश्यक है।

(२) इस ऐक्ट के नियमोंका ध्यान रखते हुए तथा किसी दूसरे प्रचलित कानूनकी परवाह न करते हुए जो निर्णय अदालत करेगा वह अन्तिम निर्णय होगा तथा यह निर्णय उन सब बातों के लिये माननीय होगा जो कर्जकुबाह या बचपनी जायदाद और इनका या उसके हकदारों या हकदारों के हकदारों पर निर्णय पैदा हो।

(३) जब कि अदालत किसी ऐसे प्रश्नका जिसका उत्तरेय पहिली उपदफा में है तब फर्माव दियित्त था कि उत्तरक न खोजे पान्तु उसे विव्वास हो कि कर्जुसवाहका देखनेका हक किसी जागदासमें पहुँचता है तो ऐसी धारामें अदालतमें अधिकार है कि वह बिना अधिक जाँच परताव दिये हुए जित प्रकार के जिन शर्तों के साथ चाहे कर्मचार के ऐसे हक को देख सकती है।

क्याहया—

इस दफाके अनुसार अदालत दिवाणियाको बंदी विस्तार अधिकार प्राप्त है। अदालत दिवाणिया, एक या हम प्रश्नको कि वामता एक पहिले पहुँचना है तब कर सकती है। इसके अतिरिक्त उसे यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी विरमक मामलों चाहे वह कानूनी हो या चाहे वह कारुणिक हो तब कर सकती है जो कि किसी दिवाणके मामलों उत्तरे तबमें आवे या जिसे वह उस मामल के ठीक तोर से समझ करतमें तब करना उचित समझ।

यह प्रश्न नीचे दिये हुए मामलोंमें तब भिये आ चुके हैं—

हीचन्द बनाम मौनता 48 All. 411, 24 A. L. J. 4951 मरहमा कुवर बनाम ईबिड 46 All. 16, 21 A. L. J. 737, अफिजल रिनीवर बनाम सीतपुन 97 I. C. 321, राम स्वामी बेदियर बनाम राम स्वामी अयगर 43 M. L. J. 165

यदि अदालत दिवाणियामें उचित रूपमें हम दफाके अनुसार दखवात दी गई हो, तो उसे अधिकार है कि वह इन सनकाह को कि आया जायदारी दिवाणिया की है या नहीं है तब कर सकती है, देखो—बितामल बनाम पोन्दू स्वामी 60 M. L. J. 180, 92 I. C. 573.

इसी प्रकार अदालत दिवाणियाको अधिकार प्राप्त है कि वह इन दोनों प्रश्नों को एक साथही तब कर सकती है यह कि दिवाणिया बाधित नियमों के बाले व्यापकी क्या देना है तथा उसकी मालाकरण क्या तक है, देखो—बकरी सिंह बनाम जननीदास A. I. R. 1926 Lah. 679.

जब कि अदालत दिवाणियाके सामने दफा ५३ कानून द्वारा तब व्यापकी के अनुसार वह प्रश्न उपरिपर बेचि कि कोई अन्यथा आधुनिक कानून मसूमा दे तो उसे बाधित कि वह ऐसे प्रश्नका समाप्त करके तब रिनीवर दी की रायको पूर्ण रूपमें नहीं न मात्र के बलके प्रो पेशक, तब कानूनक अनुसार हीनकर तब करे, देखो—सिनीपसद बनाम अमीन अली 44 All. 71, 19 A. L. J. 862.

दफा ५३ कानून दफाका जायदारी के अनुसार पैग हुए प्रश्नको सरतरीमें तब नहीं करना चाहिये किन्तु उसे हम दफाके अनुसार हुए नियमों के अनुसार तब करना चाहिये, देखो—सुतना बनाम गेरेट A. I. R. 1925 Oudh. 109.

इस दफाक अनुसार अदालत तीसरी शर्तक हकका अवलियन तब करेगा। पूर्ण अधिकार प्राप्त है, देखो—गजधर बनाम मौनर 61 I. C. 589

इस। जमिनाय यह है कि जब रिनीवर किसी जायदारीको दिवाणियाकी जायदारी के तब देखने के लिये तब तीसरे शर्तको अतिरिक्त है कि वह हम दफाके अनुसार अदालत तबमें अवधि एक उस जायदारीके लिये पैग कर सकता है, देखो—बेचिया बलिया बनाम समनाजन बेचिया 17 Madras 446, A. I. R. 1924 Mad 529, राध्या बनाम माममल 2 Lah. 147, 61 I. C. 532.

परंतु हम ताजे सा है कि यह भी अधिकार है कि वह अपनी एक उस जायदारीके लिये मालिक के लिये भित्तरेके लिखाक दूसरी दीवानी अदालत में दवा दवा कर सकता है, देखो देवराव बनाम बिड्डू A. I. R. (1925) 3 N. 369, हरनाथ बनाम नाना A. I. R. 1923 Lah. 224

जबकि किसी हिंदू मीतके दिवाणिया करार दिए जाने पर सिविलर उसकी कुछ खानदानी जायदाद पर कब्जा कर लेवे और उसके कब्जे इस बिना पर मि पिताने कर्जें गर बावनी थे, व बंदकबनीके लिए, लिए गए थे पुराज करें तो अदालत दिवाणियाको अधिकार है कि वह ऐसे प्रश्नको तय कर सकती है, देखो सन्तप्रसाद बनाम शिवदत्तसिंह 2 Pat. 724.

हकके प्रदन किस समय तक नहीं लिये जाना चाहिये—जो कि इस दफाके अनुसार। अदालत दिवाणिया को हर प्रकारके हक आदिके मामले तय करनेका पूर्ण अधिकार प्राप्त है किन्तु जहां हम प्रकारके महान प्रश्न या अस्वाभाविक उत्पन्न आ जावे वहां अदालतको चाहिए कि वह फर्जनेसे ऐसे मामलेकी जायदाद दावा दायर करे तय कर लेकी वह देखे, देखो—राधाविहारी बनाम आशिशाल एमथनी 25 O. W. N. 852, फूलडुमारी बनाम खिरोड 31 C. W. N. 502, 44 Mad. 524, 66 I. C. 863 (All).

अदालत दिवाणियाको चाहिए कि वह उस समय हकके प्रश्नोंसे तय करनेकी कोशिश न करे जबकि उसके माहूम हो जावे कि ऐसे प्रश्नको तय कर देने पर भी वह जायदाद पर कब्जा रखने वाले सम्बन्ध कब्जा न दिया संजोगी क्योंकि दिवाणियाको खुद भी उस जायदादमें मोखदा हक ऐसा नहीं है कि जिसमें वह कब्जा रखने वाला व्यक्ति इयाया आ सके, देखो—आशिशाल सिविलर बनाम परबल सिंह A. I. R. 1924 Mad. 87.

मामलोंको तय करनेका तरीका—हक आदिके प्रश्न तय करनेमें अदालत दिवाणियाको चाहिये कि वह मामूली अज्ञात दीवानोंके नियमोंका प्रयोग करे। अर्थात् अदालतके सामने दफ्तरातमें वह सब बातें दिवाणिया जाना चाहिये जोकि अजीदावामें दिखलाई जानी हैं और तब दूसरे फीकको उसकी जवाबदेही करना चाहिये। इसके बाद तनहीं कीमाया चाहिये और तब जायदादीवानों व कानून सारादाके अनुसार उन प्रश्नोंका फैसला होना चाहिये देखो—विहामल बनाम चोन्न्नामी 49 Mad. 762, शिर्कप्रसाद बनाम अजीजखली 44 All. 71-19 A. L. J. 862.

अप्र तजवीज हुदा (Resjudicata)

खपदका (२) का अतिप्रथम है कि अदालत दिवाणियाके फैसले अप्र तजवीज हुदा (Resjudicata) समझना चाहिए देखिये मिथीलाल बनाम रमैयालाल A. I. R. 1922 All. 128. दफा ११ जायदादीवानोंमें अप्र तजवीज हुदा (Resjudicata) का उल्लेख है। यह कहा जासकता है कि उस दफाके अनुसार नहीं अप्र तजवीज हुदा समझ जावेंगे जिनके हुन जानेका अधिकार पहिली अदालतकी रहा हो और पहली बात अदालत दिवाणियाके लिए भा कहा जासकती है कि उसे अदालत दीवानोंके मामलेको सुननका अधिकार प्राप्त नहीं है इसलिए उसका फैसला अप्र तजवीज हुदा (Resjudicata) नहीं समझना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं है। इस दफाके अनुसार किया हुआ अदालत दिवाणियाका फैसला आखिरी फैसला है और हर एक फीकनेके लिए माननीय है और वह फैसला द्वारा किसी अदालत दीवानोंमें नहीं उठाया जासकता है देखो—बहा बेराम बनाम देवनाथल A. I. R. 1923 All. 293

परन्तु वह बात, जिसका फैसला नहीं किया गया अप्र तजवीज हुदा (Resjudicata) नहीं समझा जावेगा देखिए नीरा बनाम नवाब सुल्तान 64 I. C. 523 (All) अगर किसी फीकनेकादे यह प्रश्न अदालत दिवाणियाके सामने उठाया हो कि दिवाणियाके कोई इतकाज जायदाद, पोखानेदीनी था और वह प्रश्न उसके विरुद्ध तय किया हो तो उसको अधिकार नहीं है कि वह दूसरा इस प्रश्नको उठा सके कि वह इतकाल जायदाद, फीज व पोखानेदीनी था पहिला फमला अप्र तजवीज हुदा (Resjudicata) ऐसे मामलेके लिए समझा जावेगा देखो—मथेशन बनाम हादत्ताम 16 N. L. R. 201.

इस दफाके आधार पर अदालत दिवाणियाका एक्तरा फैसलाभी उस सूत्रमें अप्र तजवीज हुदा (Resjudicata) समझा जावेगा जबकि किसीबरेन दफा ५३ के अनुसार दिवाणियाके किसी इतकाज जायदादको फीजों के तार देनेकी दखलातदी हो और उसकी इतरा पुतकितअवेह (Transfere) को हो जावे ऐसी सूत्रमें वह सुतकितअवेह

(Transferee) द्वारा इस्तक़ागिया मुवदमा इस अन्तर् लिखे दायर नया कर सकता है कि वह इतकाल मायदाद सही या और उस न्यायदाना वह मायदाद ह दफा—कनीज़्का विमा बनाम गायनसिंह 24 A. L. J 897.

अदालत दिवालियाके हुक्मोंकी इजराय—अदालत दिवालियाके हुक्मोंकी इजराय दफा ५ में लिखे हुए नियमोंके अनुसार होनी अर्थात् अदालत दिवालियाके इजरायके सम्बन्धमें नई अधिकार प्राप्त होने जो उसे मूल दीवानोंके अधिकारोंको वहाँ में प्राप्त है, एको—गयखानी चेष्टियर बनाम अफिखर रिनीजर मद्रुस 4231 L J 185, 651 C 334.

अपील—इस दफाके अनुसार लिखे हुए कैमरेकी पहिली अतीत हार्डिमेंटें दफा ७५ (२) तथा सूची न० १ (Schedule 1) के आशय पर हो सकती है। यदि इस दफाके अनुसार किसी माददा अदालतने कैम ग किया हो तो उसकी दूसरी अतीत (कानूनी मसल पर) हार्डिमेंटें दफा ७५ (१) के आधार पर भी जासबती है। दूसरी अतीत आता दीवानोंकी दफा १०० में लिखे हुए नियमोंके अनुसारही की जासबती अर्थात् (१) उस समय जबकि कोई कानूनी मसला तय होनेमें होवे (२) उस समय जबकि कोई नक़्क़ी तनरीद तय होनेमें रह गई हो (३) जबकि कोई विशेष पन्ती या बन्धनवाली मामलके सुननेमें कोई हो। मियाद अपील दफा ७५ (४) में दी हुई है, दफा—सेठ रिब्याज बनाम गिरधारीदास A. I. R. 1924 Nag. 361, 19 A. L. J 862.

जबकि अदालत दिवालियाके उपदफा (३) के अनुसार बर्तिकाईकी हो तो अदालतकी आज्ञा देने पर अपीलकी जासबती है देखो—दफा ७५ (२)

चुकि अदालत दिवालियाके कैमलकी अपीलकी जासबती है, इस कारण यदि अदालत कैसा दफनेसे इनकर कर तो उस इनकरकी भी अपीलजा जासबती है, जैसाकि नयनगर बनाम शम्सुद्दाय 52 Cal. 662. में तय हुआ है। यह सब फरकना हार्डिमेंटें ही दूसरे किसी हार्डिमेंटें राय इस नियममें खगोलक कुछनी नहीं है और न दफासे पड़नेहीसे यह तय पाया हुआ है।

जब कि बेसा मुद्देयाके देवरक सिलाफ किसी मुकद्दमें कोई नयदाद कर्त की गई हो और मुद्देयाका आँडा २१ रु० ५८ जाबती दीवानोंके अनुसार एतगजरी दरगाना देने और समक बाददा उसका बंड देन दिवालिया कर दिया जावे तथा रिहोव उम देवरकी जगह करीक मुद्रगा बन जावे और मुद्देयाके दुबारा एतगजरी दरगाना दो पर वह दरखास्त नामज़र होगई हो और इसके बाद मुद्देयाने वालिख, अपना हक समित करनेके लिये दायरकी हा ता यह सब पाया कि जदा त दिवालियाका कैमरा जितम कि उनने मुद्देयाके एतराजको तय किया हो दफा ४ के अनुसार नई कमरा सगझना चाहिये और दुबारा उसके लिय कोई नया मुकद्दमा नहीं दायर किया जासकता है। यह भी तय हुआ कि आँडर २१ रु० ५८ के अनुसार दिया हुआ हुक्म कभी हुक्म नहीं है और उसके लिय नया मुकद्दमा दायर जासकता तय हुआ है देखो—गयखानी बका मिहान बनाम जवाहिरलाक मदनलाक A. I. R. 1228 All 158

कानून दिवालियाकी दफा ४ (१) का प्रत्येक नियमित मुकद्दमें अनुसार तय किया जाना चाहिये अर्थात् सब फरकने की सूचना दी जाना चाहिये तथा उनके बयान तदरीफ आदि खखिल होना चाहिये उनके कागधान खखिल करन माना चाहिये तथा उनकी शहदत सुनी जाना चाहिये देखो—गनीमुद्दनाद बनाम दीनानाथ पुरी 108 I. C. 602, A. I. R. 1928 Lah. 556

इलावावद हार्डिमेंटें सामने दो प्रश्न हट करनेके लिये रखते पाये थे उनमेंसे पहिले प्रश्नको उत्तर दिया गया था पन्तु दूसरे उत्तरकी आवश्यकता नहीं मगझी गई थी पहिले यह कि यदि कोई इतरा नयदाद दिवालिया केगार दिए जानने दो साठ पड़िये हुआ हो और उस इतराके लिये इकता प्रश्न उपस्थित हो तो क्या अदालत दिवालिया की कानून दिवालिया की दफा ५३ के तामागोहा ध्यान रखते हुए ऐसे प्रश्नको तय करेगा बरिफार प्राप्त है। हार्डिमेंटें न जमाने इदुनने यह तय किया था कि अदालत दिवालियाका एमे प्रश्न तय करेगा बरिफार प्राप्त है।

इस प्रश्नको तय करते हुए नटुपन वाले नवोंने इस बात पर भी प्रकाश डाला था कि यदि कोई मामला किसी अमनवीके खिलाफ भी अदालत दिवालिया से तय कर दिया जावे तो अदालत दीवानी उस फैसलेके विरुद्ध नहीं आसनेगी अर्थात् दफा ११ कायदा दीवानों लागू समझी जावेगी जैसा कि A. I. R. 1926 All. 470; A. I. R. 1927 All. 66 आदि में तय किया जाएगा है।

दफा ४ में अधिकारका वर्णन है और उसके बाद दूसरी दफाओंमें जो अधिकारोंका उल्लेख है उनका ध्यान रखते हुए ही दफा ४ में वक्त किये हुए अधिकारको समझना चाहिये। दफा ५३ व ५४ में अदालत दिवालियाके अधिकार सीमाका वर्णन नहीं है उनमें केवल वही रतलाया गया है कि अदालतमें उपस्थित होने वाले सात २ प्रत्येकी तय करते समय किम निर्णयोंका ध्यान रखना उचित है इस प्रकार उन दफाओंका कोई प्रभाव दफा ४ पर नहीं पड़ता है जो दफा ५६ का प्रभाव अवश्य पड़ता है अदालत दिवालियाको अधिभार है कि वह ऐसे प्रश्नों तय कर सके कि दिवालियाका हक किसी जायदाद पर पहुँचना है या नहीं परन्तु ऐसे प्रश्नों तय करते समय दूसरा फीकटो भी यथोचित अवसर उस दफा बालके सम्बन्धमें जवाब देदी करनेके लिये देना चाहिये। देखो—A. I. R. 1929 All 105.

दफा ५ अदालतके साधारण अधिकार

(१) इस एक्टके नियमोंका ध्यान रखते हुए अदालतको इस एक्टकी कार्रवाई वसी प्रकार करना चाहिये जिस प्रकार वह दीवानोंके मूल अधिकारों को करने में करती है।

(२) ऊपर लिखे अनुसार हाईकोर्ट व मद्रास जिलाको अपनी मातहत अदालतके फायों के लिये वही अधिकार होंगे और वसी प्रकार बने जावेंगे जो अधिकार उनकी दीवानी मामलोंमें प्राप्त है व जिस प्रकार उनमें यह बतें जाते हैं।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार अदालत दिवालियाको उन नियमोंके अनुसार भी कार्य करनेका अधिकार प्राप्त है जिन नियमोंका प्रयोग अदालत दीवानी किया बम्की है अर्थात् जाबाना दीवानोंमें दिये हुए नियमोंके अनुसार अदालत दिवालिया भी काम कर सकती है केवल विरोधता यह है कि अदालत दिवालियाको चाहिये कि इस एक्टमें दिये हुए नियमोंका उद्भव न करे अर्थात् यदि इस एक्टमें बताया हुआ कोई नियम जाबाना दीवानोंमें नतलपड़े हुए किसी नियमके विरुद्ध पड़ता हो तो अदालत दिवालिया ऐसी सूत्रमें इस एक्टमें बताया हुए नियमोंके अनुसार कार्यवाही करेगी। जाबाना दीवानीके नियमों उक्त समय कोई पर्वी न करेगी परन्तु जहाँ वा इस एक्टमें किसी कार्यके करनेके लिये कोई विशेष नियम न दिया हुआ हो वहाँ पर जायदाद दीवानातमें दिये हुए नियमोंके अनुसार ही कार्य किया जावेगा इस प्रकार अदालत दिवालियाको इस एक्टमें दिये हुए नियमोंके अनिर्दिष्ट उन सब अधिकारोंके बर्तनेका अधिकार प्राप्त है जो अदालत दीवानी अपने मूल अधिकारोंके बर्तनेमें प्रयोग कर सकती है।

इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि ऊपर कहे हुए अधिभार केवल उनही कार्रवायोंके लिये प्राप्त होंगे जो इस एक्टके अनुसार की जानेनी है अर्थात् इस एक्टमें जिन कार्रवायियोंको करनेका अधिकार अदालत दिवालियाको दिया गया है उन्हीं कार्रवायियोंको करनेमें वह उक्त नियमावली प्रयोग कर सकती है। देखो—चालीन बनाम अब्दुल 15. C. W. N. 253, नीलमनी बनाम दुर्गाचरण 22. C. W. N. 704, 16. L. C. 377.

इस दफाके इस एक्टके अनुसार कार्यवाहीसे अनिवार्य उस कार्यवाही है जो किसी अदालतमें कीजाने अर्थात् यदि इस एक्टके अनुसार कोई कार्यवाही स्थानीयके सामने हो रही हो तो उसमें जाबाना दीवानोंके नियमोंके प्रयोग लिये जानिका अधिकार नहीं दिया गया है। देखो—अदालत बनाम लक्ष्मणप्रसाद 39 All 267, 37 I. C. 830, मिट्ठलीपट्टी बनाम मट्ठलीपट्टी 47 I. C. 33, 24 M. L. T. 106

इसी प्रकार यह भी तथ्य हुआ है कि रिजीवर द्वारा दिवालियाई जायदाद बेच जान पर जायदादीवानाके नियम लागू नहीं हैं। देखो—हमने नाम प्रहमद का.प्र. 26 O C 319=74 I. C 802, रिजीवर द्वारा रिहा जायदादका बेचा जाना दफा ५ (१) के अनुसार की कार्यवाई नहीं है और इसी कारण ऐसे बेच जानेमें जायदादीवानाके आर्डर २१ रु. ८२ के नियम लागू नहीं हैं। देखो—A. I. R. 1928 Ran 60, 5 Rang 768.

इस दफाके अनुसार अ अन्त दिवालिया तथा उसकी अर्पित सुनवाग अदालत उस अधिकारका प्रयोग कर सकती है जो जायदादीवानाकी दफा १५१ म दिशा हुआ है। इस प्रकार वह अपने का किसी सन्तानी सुधार करने में देता—रामचन्द्र बनाम मजहर हुसैन ७1 I C 55 (All) भा यापने लिये रिहा आवश्यक आज्ञा दी सकती है देखो—अभ्युक्त बनाम मशीनहीन 14 C. W. N. 586.

इसी प्रकार जब मित्र कार्यवाई का गई हो या नरनीयतामें दिवालिया बननेके लिये दम्पत्यन नहीं दी गई हो तो अदालत ऐसी दरखास्त को इसी बात पर खारिज कर सकती है। देखो—गिरनगरी बनाम मजबबम 32 All 645

प्राप्त उपर से हुई बातोंसे यह न समझ लेना चाहिये कि अदालत इच्छानुसार जब चाहे जिस हुक्मरी समूह पर सन्तानी है अर्थात् किसी हुक्मरी उसी समय वह खारिज करगी जबकि कानूनन उसको उक्त खारिज करनेका अधिकार प्राप्त होगा। देखो—हमने आर सिध 82 I C 575.

दफा ५ के अनुसार अदालत दिवालियाई नहीं अधिकार प्राप्त है जो जायदादीवानाके अनुसार मामूली दीवानी अदालतोंको प्राप्त है और इसी कारण यदि दो कर्जदारोंमें किना जायदादे लिये सगुना बन्त रहा हो तो जबतक वह सगुना तय न हो जाये तब तकके लिये अदालत दिवालिया एक कर्जदारको भी उस जायदादके नीलाम करनेमें रोक सकती है। देखो—A I R 1928 Rang 241

इस दफाके अनुसार जायदादीवानाके आर्डर ९ में दिये हुए नियमोंका प्रयोग भी दिवालिया की कार्यवाईमें किया जानसकता है इसलिये अगर कर्जदार दिवालिया की दरखास्त सुने जानेके समय खारिज न होवे तो वह दरखास्त खारिज कर दी जायेगी। दिवालिया की अधिकार दे कि वह या तो कि उरी दरखास्तके सुने जानेके लिये दम्पत्यन दे या वह नहीं दरखास्त दिवालिया बननेके लिये दे सकता है। कठिन जब यह दरखास्त दिवालिया बननेके लिये दी जाये तो उसमें यह दिखलाना चाहिये कि दरखास्त किस कारण खारिज हुई थी और अन्ततः दफा १० (२) के अनुसार दुबारा दरखास्त देने की आज्ञा प्राप्त करना चाहिये। अगर अदालतमें खारिज की हुई दरखास्तके बत व नम्बर कायम होने की दरखान्त मजबूत न की जाये तो इससे यह न समझना चाहिये कि नहीं दरखास्त भी नहीं दी जासकता इ अर्थात् यदि कानूनन नहीं दरखास्त देने का हक प्राप्त है तो ऐसी दरखास्त नाममात्र होने पर भी दुबारा नहीं दम्पत्यन दिवालिया बननेके लिये दी जानसकती है। देखो—अभ्युक्त अजीन बनाम हवीद मिर्जा 49 I. C 228.

इस एक्टके अनुसार कुकारी कार्यवाई करनेमें अदालत दिवालियाको वही नियम बर्नना चाहिये जो जायदादीवानाके अनुसार दीवानीके मूल अप्रिलोंका बननेमें लिये जाते हैं। देखो—इसमत नीकी बनाम मजबबम 36 All 65

अगर कानून लेनेका वाद रिजीवर या उसके किसी खरीदारके हकम प्राप्त जाय तो उसके प्रयोग करनेमें वही तरीका इस्तेमाल किया जायेगा जो दीवानीके मूल अधिकारों की बननेमें किया जाता है। देखो—समस्यामी वेष्टिंग बनाम आकिशय रिजीवर मदम 45 Mad 434

इस दफाके अनुसार अदालत दिवालिया (Insolvency Court) अपने हुक्म की नजरतानी (Reveu) भी कर सकती है जैसा कि आर्डर ५७ जायदादीवानाके दिया हुआ है। देखो—51 M L J 60, 46 Mad 405, 44 All 605

उपबन्ध (१)—इस उपबन्धमें यह प्रकट है कि जबवा दावानाके अनुसार हाईकोर्ट व जराय्व निका मानवत सदाउन या अपऑको ठीक उसी प्रकार सुन करनी ह जमाने दावानी की अफले सुने जानेस नियम ह अर्थात् आर्टर ४१ जावन दावानामे दिने हुए नियमके अनुसार अर्थात् वा जातनी ह व सुनी जातनी है ।

इस उपबन्धके आशर पर जबवा दावानाके आर्टर ४१ क्ल ५ के अनुसार हाईकोर्टको अधिकार है कि वह किसी मामले की सुनवाई का बद करनका ठुकर दे । देखो—नागिनदास बनाम घेरासाई 56 I C 449

दियागियाके मामले की अर्थात् सुने समय जिन जगहों वहा खबिबर प्राप्त हैं जो उसे मामली दावानाके सम्पत्ति अर्थात् सुननेमें प्राप्त है । देखा मन्मथल बनाम कुनविहारी 44 All 605=A I. R 1922 All 206

इसमें (Insolvency) की अर्थात् होने या गियाण्ट की नाम अर्थात् (Cross objection) आर्टर ४१ क्ल २२ जावना दावानाके अनुसार कमेंके अधिकार प्राप्त है । देखो—41 Mad 904.

निम्नलिखित मामलों की अर्थात् प्रिया राजीसठ (Pray Council) में भी की जासकती है क्योंकि एकदो बोई ऐसी बात नहीं है किसे ऐमा अपालन न हो सकना पाया जान । देखा—छपाव बनाम लक्ष्मि 40 Cal. 680 14 Cal 535

दूसरा प्रकरण

दिवालेके कामोंसे लेकर बहाल (Discharge) होने तककी कार्यवाहियाँ

धका ६ दिवालेके काम

(१) नीचे लिखे हुए कामोंके करनेसे यह मानलिया जावेगा कि बर्जदारने दिवाले का काम किया है—

(ए) जबकि ब्रिटिश भारतमें या दूसरी जगह बर्जदारने अपनी कुल जायदाद या करीब २ सज्जायशद किसी तीसरे शखके सुपुर्द करदी हों जिससे कि उसके सब बर्जदारोंको लाभ न होसके ।

(बी) जबकि ब्रिटिश भारतमें या दूसरी जगह बर्जदारने अपनी जायदाद या उसका कोई हिस्सा इस इरादेसे अलहदा कर दिया हो कि जिससे उसके बर्जदारोंका कर्जा बसल न होसके या उसके बसल होनेमें देर हो ।

(सी) जबकि ब्रिटिश भारतमें या किसी दूसरी जगह बर्जदारने अपनी जायदाद या उसका कोई हिस्सा इस प्रकार अलहदा कर दिया हो जो इस एकद या किसी अन्य प्रचलित एकदके अनुसार उसके दिवालिया होने पर घासका सौदा (Fraudulent preference) मान कर नाजायज़ (Void) क़ारर दिया जावे ।

(डी) यदि बर्जदार अपने बर्जदारोंका रुपया मारने या उनका कर्जा बसल होनेमें देर कामकी बजहसे —

(१) वह ब्रिटिश भारतसे चला जावे या बाहर रहे

(११) वह अपने सन्तूनती मकान या रोजगारकी जगहमें चला जावे या और किसी प्रकार घरहाजिर हो जाव, अथवा

(१११) वह छिप जाव जिसमें कर्जदारोंको उसकी खबर न मिल सके ।

(ई) जबकि कर्जदार की कोई जायदाद उनके कर्जमें इजराय डिक्री द्वारा अधिक गद्द हो

(यफ) जबकि वह इस एक्टके अनुसार दिवालिया बनाय जानिकी दरखास्त देव ।

(जी) जबकि कर्जदार अपने किसी कर्जदारवाहका यह नाटिस द्य कि वह अपना कर्ज अदा नहीं करेगा या उसकी अदायगी न करने पर इजराय डिक्री में गिरफ्तार हुआ हो ।

(घच) जबकि कर्जदार किसी अदालत द्वारा रुपयेकी अदायगी न करने पर इजराय डिक्री में गिरफ्तार हुआ हो ।

मुसाला (Explanation)—इस एक्टके अनुसार कार्याई करनेके लिये कारपरदाज (Agent) का काम मालिकका काम माना जासकता है ।

व्याख्या—

दिवालेके क़ाग (Acts of Insolvency)—इस दफ़ाम दिवालेके काम की कोई विशेष परिभाषा नहीं दी हुई है कि तु इसमें ऐसे ग़ागना उल्लेख है जिनक वन वा हानेसे यह माना गया कि कर्जदारने दिवालिया काम किया है । अगर इन धर्माँ बतलये हुए दिवालेके कार्योंमें से कोई भी शय दिया जाव ता कर्जदारको खप या उसके किसी भी कर्जदारका दफा १ व २० क नियमाग आन रखते हुए दिवाली दरख्तान देवका इक हो आवेगा जैसा कि दफा ७ म बतलाया गया है अ तथा कोई न दिया क़ार दिये जानते लिय दरखास्त नहा दा नामकता है ।

जिन कर्जदारका प्रयोग २३ दफ़ाम दिन छठ काम बतल नमें किया गया है उनका शब्दिक अर्थ जैसा तैताहा टीक तारने समझना चाहिये क्योंकि एसा काम करावत अत्यन्त लिय बहुतसी अशुविधाएँ उपस्थित हा जाती हैं । देखा—४७ Mad 250 परतु जब दिवालिया रखता दरख्तान देवे आरवतमें यह प्रकृ कर कि वह अपने क़ागना अदा नहीं कर सक्ता है या वाक्य तत यह प्रकृ हा कि क़ागदार रखती दिवालिया बनना चाहता है तो एसा दशाम यह आवश्यक नहीं है कि दिवाली क काम की बहा छनवान की जावे देखो—A. L. R 1925 Mad 483

फ़ौनसे काम दिवालिवाके काम नहीं है—कर्जदार काग किसी कर्जदार ह या उनके एजेंटों केवल यह सूचना देता कि वह दिवालिया है दिवालिदेश पम नहा समझना चाहिये । देखो—मरकटायल बैंक बनाम आडिहियन एसोस ३७ Mad 230.

आर किसी एक कर्जदारको सोग खरीदा जाव व वह मीदा फ़ुक्तरमें दूसरोंसे बेचा जाव और बिकने दामसे दूरे कर्जदारका कर्ज चुकाया जावे ता ऐसे कामको दिवालेका शय नहा समझना चाहिये दखा—दुर्गाराय बनाम हरकिशन 23 A. L. J 536=A. I. R 1925 All 564

बिभी आदमको दिवालिया क़ार देवका काम एक बना समान काम है इस कारण अदालतका चाहिय कि दिवालिया क़ार दमेने पहिल मला भाते अनवीन सर लेव और यह देख लेवे कि कानून पूरतया लागू है " याद कोई कर्जदार म बनाता न म काम कर लेवे कि उसे बिना कर्ज वा हा क़ागना देता है और वह उस कर्जको अदा नहीं कर सक्ता है तथा इसक पशान्त उस कर्ज की शृण देता वा केवल इतनाही शायन यह है कि मान लिया जावेगा कि उस कर्जदारन दिवालिया नाम

मिया है और न एसा काम दफा ६ के गिल २ वजोंमें बताये हुए कामोंमें आता है। देखो—A. I R 1928 Mad 393 यदि कोई कर्जदार अपने कर्जखानोंकी पाग होने पर यह प्रश्न करे कि वहने अपनी सब दायित्वोंमें किसी तीसरे शब्दिक कन्वैन्समें देदा है जिसमें कि वह शब्द उसकी सब जायदाद पर बंध तक और उसके वजोंका निपटा सक ता उसका यह काम दिखाने का काम समझा जावेगा। देखो—A. I R 1928 Mad. 903.

यदि कोई कर्जदार दिवालिया बननेके लिये दरखास्त देने को चाहे उसका पेटीशन खारिज भी हो जावे तब भी यह समझना चाहिये कि उसने इस दफा ६ क्लॉज (ए) के अनुसार दिवालिया काम किया है। देखो—A. I R. 1929 Lah. 72 (1)

जबकि कर्जखाना देनेके दरखास्त देनेके तीन माहके अन्दर कर्जदारने यह प्रकट किया हो कि वह अपने कर्जोंका नहीं चुका सकता है तथा साथ २ यह भी अपने कर्जखाना देनेके यह दिया हो कि वह सबका रज एक साथही चुकावेगा अलहदा २ नहीं चुकावेगा तो इस प्रमाण कहना इत दृढ़के ऋज (जी) के अनुसार साफ तारीफे मोटिल देनेके बराबर है। देखो—A. I. R. 1929 Lah 136

क्लॉज (ए) कर्जखानोंके कामके लिये दस्तियोंके सुपुर् आयदादका किया जाना इस क्लॉजके अनुसार दिवालिया काम है। देखो—हरामल बनाम गोटम 19 I C 443

ब्रिटिश भारत (British India) का परिभाषा बमाल क्लॉज एक्ट (General Clauses Act X. 1897) की दफा ३ (७) में दी हुई है अर्थात् इसका अभिप्राय सब सब देशोंके है जो गवर्नर जनरल हिन्दू या उसके मातहतों द्वारा शासित किया जाता है।

दिवालिया काम चाहे ब्रिटिश भारतमें किया जावे चाहे उसके बाहर किया जावे दिवालिया दरखास्त कर्जदारके विरुद्ध दी जा सकती है परन्तु दिवालियाकी दरखास्त उसी अदालतमें दी जाना चाहिये जिसमें अधिकतर सीमामें कर्जदार अधिकतर रहता हो या अपना धंधा करना हो, यदि कोई कर्जदार सबरा तास्फया करनेके लिये दस्तावेज (Composition deed) लिखे तो यह दिवालिया काम समझना चाहिये। देखो—लालचंद खुशालदास बनाम हुसेनिया A. I. R. 1927 Sindh 78.

क्लॉज (बी) इस उपदशके अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि कर्जदार अपनी कुल जायदाद या लगभग सब जायदाद हटा देवे इसके लिये यदि वह अपनी जायदादका मोटासा भी हिसा हटा देवे तो यह उद्देश्य लागू हो सकेगी परन्तु यह बात अवश्य साधित होना चाहिये कि कर्जदारने अपनी जायदाद इस कारण हटाई है कि जिसमें उसके कर्जखाने उस जायदादमें न पावें या बनना कर्ज नसूल होनेके बजाय पड़े न दे देवे। क्लॉज (ए) के अनुसार जायदाद किसी तीसरे व्यक्ति का नाम की जाना चाहिये परन्तु इस क्लॉजके अनुसार जायदाद किसी कर्जखानेके नामकी न हो जा सकती है इसलिये यदि कोई कर्जदार अपने किसी एक कर्जखानेके हकमें अपना जायदाद या उसका कोई हिस्सा इस मशरते लिख देवे कि उसके दूमे कर्जखानेका वह जायदाद न मिल सके या उनका बजें नसूल करने में देर हो ॥ भा यह काम दिवालिया काम समझा जावेगा।

क्लॉज (सी) इस क्लॉजके लिये यह आवश्यक नहीं है कि कर्जदार अपना कुल जायदाद को अलहदा करे जैसा कि क्लॉज (ए) के लिये आवश्यक है और न यह आवश्यक है कि इतकाल जायदाद कर्जखानेके वजों हस्त करने या उनके वसूल होने में देर लाजनेकी वनहस किया गया हो, यह भी आवश्यक नहीं है कि इतकाल निम्न तीसरे क्लॉजके हकमें किया जावे अर्थात् इस क्लॉजके लिये चाहे कुल जायदाद या उसका कोई भी भाग हटाया गया हो या किसी भी शब्दिक हकमें हटाया गया हो आर किसी भी मशरते हटाया गया हो तब

यदि वह इतकाल जायदाद कानूनन दिवालििया होने पर इमतिना पर नाजायज कार दिया जासके कि वह धोरेसे कारदा देनेके लिये (*Fraudulent preference*) किया गया हो तो ऐसे इतकाल जायदाद के होने पर दिवालििया काम मासलिया जावेगा । ' *Fraudulent preference* ' धोरेसे कारदा पहुँचानेका अर्थ यह निकरता है कि " निम्नी एक कर्जस्वाहको दूसर कर्जस्वाहको मुकाबिलेमें कारदा पहुँचाना " इस प्रकार इतरान जायदाद उसी कर्जस्वाहको इकमे हाना चाहिये परन्तु वह इतकाल उस कर्जस्वाहको कारदा पहुँचानेके लिये स्वयं उसके हकमें किया जासकता है तथा और भी तीसरे शक्तक हकमें किया जासकता है निम्ने उस कर्जस्वाहको कारदा पहुँच सरे निम्ने वह फलदा पहुँचाना चाहता है ।

ऐसे इतकाल जायदाद होनेमें यह आवश्यक नहीं है कि वह निम्नी द्रव्यसे बरपाया गया हो क्योंकि तर्जिह (*Pierference*) शब्दही इस बातका सातक है कि इतकाल जायदाद करने वालेने अपनी इच्छा माननूस कर एक कर्जस्वाहको दूसर कर्जस्वाहको मुकाबिलेमें कारदा पहुँचानेका इच्छा उस कामको किया है । देखो—देवी ब्रथाप बनम आधुनो २१ C. L. J. 167; मोलावरदा बनम तेजमल 11 A. L. J 545

परन्तु यदि ऐसा इतकाल जायदाद दबावही बजहसे किया गया हो तो उसमें यह शक होगा कि कर्जदार की मशाल गिर्ज यह नहीं थी कि वह एक कर्जस्वाहको दूसरके मुकाबिले जफिक लाभ पहुँचानेको इच्छा रखता हो और फिर यह बात साफ नहीं रह जावेगा अब दबावका अम ब होनाही इस बातकी मशाले लिये माना गया है ।

कलाञ्ज (डी) इस बातको कार्यरूपमें परिणत करनेके लिये यह बात साबित होना आवश्यक है कि कर्जदारने इस मशाले कि उसके कर्जस्वाहानका कर्जो वस्तु न किया जासके या उसके वस्तु होनेमें दर लग इस बातकी तीनों उपश्रुतोंमें इनमेंसे दुई कारवाही हो आवनी यदि ऊपर बगई दुई मशाले मिश्रित मशाले बाहर रहता हो या चला जावे अथवा अपने रहने या व्यापार का जगहसे हट जावे अथवा अपन कर्जस्वाहानमे छिप जावे तो यह मान लिया जावेगा कि उसने दिवालििया काम किया है ।

इस बातके आधार पर निम्नी कर्जदारको दिवालििया कार देनेमें पहिले यह निश्चित करलेना चाहिये कि आया कर्जदार दरअसल इस नीयतसे कि उसके कर्जस्वाहानका मशाल मारा जावे या उसके वस्तु होनेमें देर हो, हट गया है । देखो—अबूहाजी बनम हाजीमान ■ Bom L R 684.

चूकि हटना, कर्जस्वाहानका रुपया माने या उसके वस्तु होनेमें देर करनेकी मशाले होना चाहिये इस कारण यदि कोई व्यापक व्यापारके सम्बन्धमें चला जावे तो उसका जाना दिवालििया काम इस बातके अनुसार नहीं समझा जावेगा । देखो 1816 Holt (N P) 175

जबकि किसी कर्जदारने अपना हिसाब किताब कर्जस्वाहानको दिवालिनेमें इनकार कर दिया हो और एक लम्बी रकम इस मशाले लेन भपने व्यापारकी जगहसे हट गया हो कि जिसमें वह कर्ज न मरई जासके तो अतन्तका यह मशाले कि वह कर्जदार अपने कर्जस्वाहानका रुपया हक करन या उसके वस्तु होनेमें देर करनेकी मशाले हट गया है उचित होना । देखा 21 Bom. 297.

यदि कोई मशाले अपने व्यापार की जगहको छोड़ जावे व नहा एक योगित दस्तखत अपने वकीलका लगा जावे कि कर्जस्वाहान उस मशाले अपने कर्जके निम्न लितापटी करें तो यह समझ लेना चाहिये कि ऐसे कर्जदारने दिवालििया काम किया है । देखो—दीवालि दिवनराधन 97 I C. 446

जायसे केवल कुछ समयके लिये योगदाजिर होना इस बातके अनुसार योगदाजिर होना नहीं समझना चाहिये । देखो — 23 A. L. J. 586—A I R 1925 All 564

जबकि वर्ज्यदर्शी दस्तावेज दिवाल्या बानके छिे स्मारित हो गई हो और एउ वर्ज्यताहरी दस्तावेज भा इन्ही तौर पर स्मारित हो गई हो और इसके बाद कोई दूसरा बन्तल्लाह दिवाल्या बरार देनेके लिये दस्तावेज दल तो। यह तथ हुआ है कि पहिली दस्तावेज स्मारित होना अत्र तमनीज मुदा दफा ११ जाबना दीयावीके अनुसार नहीं समझा जावेगा यदि वह दूसरा वर्ज्यल्लाह भी पहिली दस्तावेजमें फरीक रहा हो अर्थात् दूसरे वर्ज्यल्लाह की दस्तावेज वाले फगर देने दिवालयिक सुनी न ना चाहिये। देखो—चौथमल वनाम लेपननदात A I R 1228 Pat 116

वलाज (ई) यदि वर्ज्यदर्शी जायदादवा कोई हिस्सा इन्गयडिमें नो म्पोंके छिये हो बिनाजावे तो इस दफाके अनुसार यह मानलिया जावेगा कि उसने दिवाल्या बाम लिया है। जायदाद दस्तावेज बिक जाना चाहिये देखल उसका नोत्पान पर चढना फाफी नहीं है। देखो—दोन्नदाम का मामला 56 I C 158

अगर कोई हिस्सादोनों के उपर राजगार शतकनामे शम्भ धमें कोई डिस्टी होये और किसी एक हिस्सेदारा अन्दाज हिस्सा नीयम होनाये तो यह नहीं म ना जावगा कि अगर हिस्सेदोनों भी दिवाल्या बाम लिया है। देखो—A I R. 1926 Mnd 976

फलाज (एफ) जबकि वर्ज्यदार स्वयं दिवाल्या बरार दिये जागे लिये दस्तावेज देने तो उसका यह काम दिवाल्या बाम समझा जावेगा और जबकि कि कोई बन्तल्लाह उसके स्मारित किये जावेगा न दस्तावेज जमि ना अमरी वह दस्तावेज मन्जूर होकर वह दिवाल्या बरार दिया जाना चाहिये। देखो—A. I. R. 1926 Mnd 494

जबकि लिया गया फगर दोनो हुपम म्पूज ११ दिया गया हो और दिवाल्या कि दस्तावेज दिवाल्या निशानेनी देवे ता उसको इस दस्तावेज की मन्जरीक लिय एक नया दिवाल्या बाम इस क्रमसे अनुसार दिखाना चाहिये। देखो—फमा दीन वनाम बिलम्बरदयाल 109 I C 578 (2)

फलाज (जी) यदि वर्ज्यदार अपने किसी वर्ज्यरव इसो यह नोटिस देवे कि उसने अपना वर्ज्य देना बद कर दिया है या वह अपना कामगार बद करेगा है तो यह समझना चाहिये कि उसने अपना कामगार दिवाल्या बाम लिया है। देखो—वनासीदास वनाम न दवदास A I R. 1926 Oudh 222

यदि नोटिस किसी वर्ज्यरके माफन भी दिया गया हो तो वह ग्रांत है। देखो—A I R. 1926 Sind 18 पर नु मरि साफ श देखें ब ठौर होना चाहिये और उससे यह बात साफ स्पष्ट होना चाहिये कि वह वर्ज्य बद करना चाहता है या उसने अदायगी बद करदी है। उस नोटिससे उसकी यह बात मन्जूर होना चाहिये कि वह वर्ज्य देना बद करने वाला है या वर्ज्य देना बद कर दिया है नोटिस केवल इस बातसा कि वर्ज्यदार दिवाल्या बाम हाजिर है काफी नहीं है—अगर ऐसे नोटिसके देखने यह नहीं जाना जावेगा कि वर्ज्यदारने दिवाल्या बाम लिया है। देखो—39 Mnd 250, नगमनदात वनाम बिम्पनल 25 A. L. J. 219

इस दफाके अनुसार जो नोटिस देना बालाया गया है उसमें मन्जूर उस नोटिससा है जो वर्ज्यदार अपनी उ नुसार देने और वर्ज्यदारका यह इच्छा मामलके वाक्यान्तमें समझी जावता है। यह बात कि आधा कोई नोटिस इस दफाके अनुसार फाफी है या नहीं हर मामलके आर सब बातोंको भी देखकर समझा जावना है अगर किसी कर्जदारने यह प्रगना की जाय कि जबकि आजारकी दशा सुधार न जावे वह अपना वर्ज्य वसूल करने के लिये बरि दवाज न डाल ना समझे ता प्रसार का प्रस्ताव लिया जावे कि वह अपने वर्ज्यका कुछ हिस्सा पूरे वर्ज्यी अदायगीमें लेव ता इस प्रकारवा नोटिस इस दफाके लिय काफी नोटिस समझा जावेगा। देखो—A I R. 1926 Sind 246,

अगर कोई एक शर्तदार (Partners) इस प्रकारका नोटिस देवे कि वह वर्ज्यी अदायगी नहीं करेगा तो

ऐसा नोटिस दूसरे शरीकदारों (Partners) के लिये दिवाने का काम नहीं समझा जावेगा । देखो—देवेन्द्र बनन पत्रोत्तर 55 I C. 186

इस कानून के लिये फ्रेन्च कपेको अदायगीही बंद कर देनेसे विनाय मुखामत पैदा नहीं होती है किन्तु इस बंद कानून का नोटिस देनेसे विनाय मुखामत पैदा होती है और उम्मी समये मिथाद खोजाना चादिष्ट । देखो—मोरामल बनन पत्र उपाखा A I R 1928 Sind 177.

बुलावा (Explanation)—एजेन्ट का दिया हुआ काम मालिक का काम समझा जावेगा । इस प्रकार यदि कोई व्यापारी बलवत्ता हाईकोर्ट के अधिकार सीमा से बाहर रहना हो परन्तु उसका एजेन्ट (मुमाला) उसकोमें नाम लगा हो और वह बुलावा कर्जों की अदायगी बंद कर दूँ तब अपना दुश्मान छोड़ देवे या कोई ऐसा काम करे जिसे यदि व्यापारी स्वयं करता तो वह दिवालिया करार दिया दिया जासकता तो एजेन्ट के ऐसे काम करने पर उसका मालिक दिवालिया करार दिया जासकता । देखो—हर्षचन्द्र 5 Cal 805. लेकिन वह साथ इसके बाद वाले छुट्टियों में इस प्रकार नहीं रहती गई थी यानी यह तब पाया था कि यदि मालिक की रायसे कोई काम किया जावे तो उसकोही पावनी उस पर हो सकेगी । देखो—धूपतसिंह 20 Cal 771.

एजेन्ट का काम उनी वक्त मालिक को बंध सकेगा जबकि वह अपने अधिकार के बाहर (नतीर एजेन्ट के) काम करेगा । देखो—20 Cal. 771, 23 Cal 26 (I C)

दफा ७ दरखास्त और दिवालिया करार दिया जाना

जगर कोई कर्जदार दिवालिये का कोई काम करे तो उसका कोई कर्जदार या कर्जदार स्वयंही दिवाली के दरखास्त इस एकट में दिय हुए शायतने साथ दे सकता है और अदालत ऐसी दरखास्त पर कर्जदार का दिवालिया करार देने का हुक्म देसकती है इसी आर्डर का दिवालिया करार देने का आर्डर (Adjudication order) कहते हैं उदाहरण (Explanation)—कर्जदार का स्वयं दरखास्त देना इस दफा के अनुसार एक दिवालिये का काम है और अदालत ऐसी दरखास्त पर दिवालिया करार देने का हुक्म दे सकती है ।

व्याख्या—

दफा ७ में कर्जदार के उन कामों का उल्लेख है जिनके करने या होनेसे यह मान लिया जावेगा कि उस कर्जदार ने दिवालिये का काम किया है इस दफा में यह बतलाया गया है कि दिवालिये का नाम होने पर उसका धारण क्या है तबता है अर्थात् इस दफा में यह बतलाया गया है कि जब कोई दिवाली का काम किया गया हो तो कर्जदार तथा कर्जदार के दोनों अधिकार हैं कि वह अदालत दिवालिया में जग कर्जदार को दिवालिया करार दिये जाने का दरखास्त पेश कर सकें और एसी दरखास्त के आकार पर वह कर्जदार दिवालिया करार दिया जायके ।

इस दफा के साथ जो व्याख्या (Explanation) दी हुई है उसको चकरत इस बातसे पड़ो कि जिनमें काम के या जग दूर हो सके क्योंकि दिवालिया करार दिये जाने की दरखास्त दी जानेसे पहिले कोई न कोई दिवालिये का काम अवश्य होना चादिगे । दफा ७ क्लॉज (एक) के अनुसार यदि कोई दिवालिया कर्जदार दरखास्त दी जावे ता यह मान लिया जायगा कि दिवालिये का काम हुआ है इस कारण कर्जदार द्वारा कोई दरखास्त दिये जानेसे पहले एक बेवगी दरखास्त दी जा चुकना चादिगे इस प्रपत्ति दूर करने के लिये तथा किशोर की पावनी से बचने के लिये यह व्याख्या माफदा गई है जिनके अनुसार कर्जदार का स्वयं दरखास्त देना दिवालिया काम मान्य गया है तथा अदालत को ऐसी दरखास्त पर दिवालिया करार देने का अधिकार प्राप्त है ।

दरखास्त नहीं दी जा सकती है। ऐसी दशाप इस दफा का ध्यान रखन हुए तथा दफा ७९ (२) की पर दृष्टि डालने हुए यदि यह मान लिया जाय कि फर्म (Firm) के विरुद्ध दिवाल्याकी दरखास्त दी जा सकती है तो अनुचित न होगा। बर्तमान दिवाल्या फर्म (Firm) के नाम से ही जामज्नी हे गो अदान्तका दिवालिखा करार देनेका हुक्म उस फर्मके सब शराकदारों (Partners) के लिये समझना चाहिये।

नावालिग—इस एक्टमें कहीं पर यह नहीं बतलाया गया है कि नावालिग दिवालिखा करार दिया जा सकता है या नहीं परन्तु अधिस्त वहा व्यक्ति जो कानून प्रवर्द्ध कर सता है दिवाल्या करार दिया जा सकता है बूकि नावालिग (Minor) मुआहिदा नहीं कर सता है। इस कारण वह दिवाल्या भी नहीं करार दिया जा सकता है। पर प्रकार यह तय हुआ है कि किसी फर्म (Firm) का नावालिग (Minor) शरीकदार (Partner) निजीतौर पर (Individually) दिवाल्या नहीं कर दिया जा सकता है। देखो—सम्पादीकरण बनाम असतोश पौष 42 Cnl. 225, जानकाप्रसाद बनाम गिरधारीलाल 16 O O. 68.

कानून प्रवर्द्ध (Contract Act) की दफा २४७ का ध्यान रखने हुए किसी नावालिग शरीकदार (Partner) का दिवाल्या घोषित करना अनुचित है। देखो—जममोइन बनाम गिरीश बानू 42 All 515

अनकि किसी स्युक्त हिंदू परिवारके बाल्य (Adult) मेंबरमें दिवाल्या करार दिये गए हों तो उस परिवारके नावालिग (Minor) मेम्बरका हिस्सा रीसिवरकी सूरक्षामें नहीं जावेगा और रीसिवरको उस पर हस्तक्षेप करनेका अधिकार नहीं है। देखो—A I R 1924 Mad. 791

दफा ९ कर्जखाहके दरखास्त देनेकी शर्तें

(१) कोई कर्जखाह किसी कर्जदारके खिलाफ दरखास्त उस वक्त तक न देसकेगा जब तक कि:—

(ए) कर्जदारका कर्जा जो उसे दरखास्त देने वाले कर्जखाहको देना है या उन सब कर्जोंका जांच जो उमे उन सब कर्जखाहोंको देना है भिन्होंने एक साथ दरखास्त दी हो पांच सौ रुपये न हो। और

(बी) वह कर्ज निश्चित धन राशिके रूपमें या तो फौरन अदा होना चाहिये या भविष्य में किसी समय अदा किया जाना चाहिये। और

(सी) दरखास्त में दिवाल्या करार दिये जानेके लिये जो दिवालयिका काम दिखलाया गया हो वह दरखास्त दिये जानेके तीन महीनेके अन्दर हुआ हो।

(२) अगर दरखास्त देने वाला कर्जखाह एक महफूज कर्जखाह है तो उसे अपनी दरखास्तमें दिखलाना पड़ेगा कि अगर कर्जदार दिवाल्या करार दिया जावेगा तो वह अपनी जमानत दूसरे कर्जखाहोंके फायदेके लिये छोड़ देगा या वह अपनी दरखास्तमें जमानतकी क्रीमतका अन्दाजा देगा। जबकि वह दरखास्तमें अपनी जमानतकी क्रीमतका अन्दाजा देगा तो वह उतने रुपयेके लिये दरखास्त देने वाला कर्जखाह समझा जावेगा जितने रुपये उसके कर्जेमेंसे जमानतकी अन्दाजा लगाई हुई क्रीमत घटा देनेसे बचेगे और उस बचाया रुपयेके लिये वह बिला महफूज कर्जखाह समझा जावेगा।

ज्याहना—

हा अपराध नर-पुत्र दण्डार्ह नहीं है जितने दोषित कर्म-साधक। अपने व्यवसायिक जिलाध्यक्ष दिवालयीय दण्डात्मक दण्डा-प्रतिपाद प्राप्त है। उपद्रव (१) के हात (ए, (२) व (३) में गिन बानोका उल्लेख है वह नव बाने उपागत दोषा-प्रतिपाद तभी व्यवस्थाहीन दण्डात्मक मन्त्रोपाय कानून के अन्तर्गत व व्यवस्था द्वारा किया हुआ दिवालयक धर्म (Act of Inoffensiveness) की भावित होना चाहिये अर्थात् कर्म-साधक दण्डात्मक पा-प्रतिपाद कर्म-उत्पाद अपराध दिवसिता का दिया फलमेव जन्मि यह सिद्ध होना कि जितने दण्डा-प्रतिपाद व बन्त-प्रतिपाद किन्ति दिवालयिके कानून के अन्तर्गत नये जन्मि होना चाहिये अन्तर दिया हो तथा एम पर दण्डात्मक देने वालों का वरत ५००) इत्यादि वरतमेव ही जन्मि वरतमेव एम समय या आगुदा किन्ति समय लम्बित धन-प्रतिपाद कानून अन्तर्गत नये अन्तर्गत हो।

परन्तु इस प्रकार दिवालीया करार दिये जाने की दृष्टिकोण से दिये जाने पर अदात्मिका पक्ष के हित न हों इस बात की जांच करे कि आया दम्पत्य के देने वाले परचबन्दा (Creditor) का पत्र ५००/३० या इससे ब्याप्त है या नहीं और उसे अधिकतर दण्ड ५० में घटायें हुए नियमाका पालन करना चाहिये। देव्य—बापू नवान् घुमान् दातव्यौ
A. I R. 1926 Lah 638 (2).

जगति धर्मोऽत्र दृग्भावात् तेन बाधे कर्मस्वात्मे अर्थमे ह्यग्रा कं तो अदात्त दिवाहिय इत आदेशं लिख्य
सर्वतो हे । देतो - दुष्माणाद वनाम आनन्द 7. Lah. L. J. 201.

जयति । इति । अथ दिवाग्या भाग है नो अद्वान्तमे चाह्ये कि पहिले बह इस नामा यवन काले कि
अथ द्वाताय देने वाला ब्रह्मदेव अथमक कहते इत्येव ब्रह्मदेव है या नहीं तैसाकि उसने द्वातात्मने दिवाग्या ह
जितने कि उसे द्वातात्मने देना एक घेरा है न हो अपौरुषेय ब्रह्मदेव द्वातात्मने देना इकदार है या नहीं है । देखो—
ताथेव इत्यम उल्लिखितम् ॥ ७६ ॥ ७१३

कर्ज (Debt) - कर्ज उसमें होता बाह्य तया उसकी अदायगी के लिये कर्जदार को स्वयं ज़िम्मेदार होना चाहिये जैसे दाई, पुराना कर्ज या बर्ताना आने पर अधिक दामनाने लक्षण के लिये कर्ज के लिये दिव्यानिश कर तर्जों से नाम करने है ।

आदि निम्न वर्गकाहवा फलें मिथी मयुक्त हिन्दू पवित्रा प्र हविता पुने वर्गेने मिथी उम पवित्रका वारं भी व्यक्ति जो दिवाभिया फल दिना जामना है दिवाभिया क्यार दिना जामवेगा तेनेकि वरु फलें समुदा होने । देखो—
 इयुवम वना सिमना 49 Mad. 217—A. I. R. 1926 Mad 182

[illegible]

११. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अन्तर्गत, जहाँ का दिया गया है कि भी उस सर्वोच्च न्यायालय पर निर्णयित करार देता है। उदाहरण के लिये देखो—A. I R. 1926 Cal. 234.

[illegible]

अप्रतिनिधी वतीने पालके लिखे पुरस्कार खरेदी करावी. इच्छा हो पालतु वनपेठे एकही मान्य उर मंदुक्त वलेके
अप्रतिनिधी वतीने पालके लिखे पुरस्कार खरेदी करावी. इच्छा हो पालतु वनपेठे एकही मान्य उर मंदुक्त वलेके
देखा- A. I. R 1926 Cal 234.

निश्चिन धन राशि (Liquidated Sum)—जबकी तादाद एक खास व ठपकी हुई तादाद होना चाहिये जिसे कि अन्ततः उसी तादाद न निश्चिन करना पड़े। टॉर्ट (Tort) या मुआझदा शिकोके आधार पर होने आदि। दोषा एक अनिश्चिन (Unliquidated) जबकी इसलिये ऐसे दावके आधार पर दिवालिया की दाखलात नहीं दी जा सकती है जो यह जबकी दूसरे कसोती भाति दफा ३४ (१) के अनुसार साबित किया जासकता है।

तीन महीनेके अन्दर—कर्मखवाह जिस दिवानेके मामले के आधार पर अपनी दाखलात देने वह दिवालीया काग हावके बाद ठाँव ताँ माहके अन्दर दिवालीया करार दिये जानेकी दाखलात देना चाहिये वरना इसके बाद देनेमें वह दाखलात बाद मियाद समझी जावेगी और उस दिवालीयेके मामले के आधार पर वह दाखलात कबिल चलनके नहीं समझी जावेगी। देखो—A. I. R. 1925 Oudh 222.

यह तीन महीनेका समय अंग्रेजी महीनोंके हिसाबसे गिनना चाहिये जैसाकि जनरल क्लॉजेस एक्ट (General Clauses Act) की दफा ३ में बखलाया गया है यदि आखिरी दिन छुट्टियोंमें पड़ जाय तो छुट्टियोंके समाप्त होने ही जिस दिन कचहरी खुले उस दिन दखलात दाखिल की जासकती है जैसाकि जनरल क्लॉजेस एक्टकी दफा १० में बखल था गया है क्योंकि कानून मियाद (Limitation Act) की दफा ५ ब २२ की ओवरर आ किमीके लागू होनेका निक दफा ७८ (१) में या कानून दिवालीया (Insolvency Act) का किसी अन्य दफा में नहीं है देखो—42 Mad 18.

यदि दाखलात निर्मा गणत अदालतमें देदी गई हो तो वह समय जेके गणत अदालतमें लग गया हो दुबारा दाखलात देने समय घुलने नहीं मिलना देखो—39 Mad 74. यदि दाखलात ठीक समयके अन्दर दी गई हो परन्तु उसमें कोई गल्ती रह गई हो तो वह गल्ती आयन्दा ठीकरी जासकती है और उस गल्तीकी वजहसे वह दाखलात मियाद बाहर नहीं समझी जावेगी किन्तु वह दाखलात ठीक समयमें दी हुई ही मानी जावेगी।

कर्जखवाह (Creditor)—इसकी परिभाषा दफा २ (१) (९) में दी हुई है अर्थात्त कर्जखवाहसे अभिप्राय उस व्यक्ति है जो कि फौरम अपने कर्जके वसूल करनेका इकदार हो और जो उस कर्जके चुकतेकी शर्त देखसकता हो परन्तु इस एकके अनुसार केमाभी कर्जखवाह दाखलात देसकता है जो अपने कर्जके उसी समय वसूल कर लेनेका इकदार न हो किन्तु मविषयमें उसके पानेका इकदार हो।

यह आवश्यक नहीं है कि दाखलात देने वाला कर्जखवाह उस समयभी कर्जखवाह बना रहे जबकि दिवालीया करार दिये जानेका हुक्म दिया जावे इसकाही पर्याप्त होगा कि वह कर्जखवाह दाखलात देने समय कर्जखवाह था। देखो—51 M. L. J 680=A. I. R. 1927 Mad 153

जबकि किसी रज बहन अपने कर्जदारों दिवालीया करार दिये जानेके छिये दाखलात दी हो तो वह कर्जखवाह अपना कर्ज दिवालीये की वार्निमें साबित कर सका है उसमें साबित करनेके लिये अन्तःदा सामान्य दायर करनेकी जरूरत नहीं है देखो—A. I. R. 1923 Rang. 21. यदि कर्जकी तादादके लिय कोई शकका हो तो अदालत दिव लिया की अधिकार है कि वह ऐम सुनके तोय कर सकती है देखो—A. I. R. 1925 Lah. 430, A. I. R. 1926 Lah. 638.

जमाअत (Corporation) न कम्पनीमी बहमियत कर्जखवाहके दिवालीया करार दिये जानेके लिये अपने कर्जदारके खिलाफ दाखलात देसकती है जबकि किसी कर्जखवाह अपने मजबूतीके लिये अन्तःदा सामान्य दायर करनेकी जरूरत नहीं है देखो—A. I. R. 1923 Rang. 21. यदि कर्जकी तादादके लिय कोई शकका हो तो अदालत दिव लिया की अधिकार है कि वह ऐम सुनके तोय कर सकती है देखो—A. I. R. 1925 Lah. 430, A. I. R. 1926 Lah. 638.

जमाअत (Corporation) न कम्पनीमी बहमियत कर्जखवाहके दिवालीया करार दिये जानेके लिये अपने कर्जदारके खिलाफ दाखलात देसकती है जबकि किसी कर्जखवाह अपने मजबूतीके लिये अन्तःदा सामान्य दायर करनेकी जरूरत नहीं है देखो—A. I. R. 1923 Rang. 21. यदि कर्जकी तादादके लिय कोई शकका हो तो अदालत दिव लिया की अधिकार है कि वह ऐम सुनके तोय कर सकती है देखो—A. I. R. 1925 Lah. 430, A. I. R. 1926 Lah. 638.

कि उसको विश्वास न हो जाये कि कर्जदार किसी विशेष कारण वश बहाल होनेकी दृष्टिवात्त नहीं दे सकता था या उसकी पैरवी नहीं कर सका था या इस दूसरी दृष्टिवात्तमें कोई भिस कारण दिखलाया गया हो जो पहिले दिवालिया करार दीजानवाली दृष्टिवात्तमें नहीं दिखलाया गया था ।

व्याख्या—

१ सालवेसी एक्ट ११ सन् १९२० ई० [Insolvency (Amendment act) XI of 1927] के अनुसार क्लान (२) में (Made under this act) व स्थान पर 'Who there made under the Presidency Towns Insolvency Act 1909 or under this act' कर दिया गया है इस संशोधन का असर यह होता है कि यदि कोई व्यक्ति प्रसावेता यज्जत व साधवर्ग एव के अनुसार भा दिवालिया करार दिया गया हो तो भी उस पर इस दफामें बतलाये हुए नियम लागू होंगे ।

कर्जदार दिवालिया करार देने जानिकी दस्तखत उम शय में देसकना है जबकि वह अपन कर्जका अदा न कर सकना हो तथा उसके साथ २ बन्धन (१) क (ए) (बी) व (सी) में बनलाने हुए बानामें कोई बान उपस्थित हो । यह आवश्यक नहीं है कि वह सन बोले सा । २ उपस्थित हाने अर्थात् (i) कर्जदार यदि अपन कर्जको अदा न कर सकना है व उसक कर्ज ५००) २० स कम न हाव ता वह दिवालिया बन सकता है, (ii) इसा प्रमाण जबकि वह अपने कर्जका अदा न कर सकना हो और भिसा इतराय बिक्रम भिपना होता भी वह दिवालिया बननेका इकदा है, (iii) उस सूरतमेंभा जबकि वह कर्ज अदा न कर सकता है और उसकी आगना इतराय बिक्रम पुक हो गई हो वह दिवालिया करार देने जानिकी दस्तखत दे सकता है ।

यदि ऊपर बताने हुए शर्तोंमें कोई भा शर्त उपस्थित न हाने ता अदालत एसा दस्तखतना खानिन कर सकती है देखो—69 I C 622, 40 Bom 707 दिवालियाकी दस्तखत गजनीयतासे व सहाहाता चाहिये वह कबल अदालतमें बेना कायदा उठानेकी मशाने ही न होना चाहिये । दख—30 All 80, 44 Cal 899

यदि दिवालिया इस एक्टमें बतलाई हुई शर्तका पूरा कर दव तो अगलकी कानूनन दिवालिया करार देनेका हुकम देना पड़या अदालत उस दशम गजनी इच्छतुमार एसा हुकम दतसे इन्कार नहीं कर सकता है । दख—44 Cal 505; 15 A. L. J 87; 96 All 250; 41 All 486, A. I R 1926 Cal 905

जबकि कोई कर्जदार अपनी दस्तखतमें वह बान दिखलावे भिसक आधार पर वह दिवालियाकी दस्तखत दे सकता है तो अदालतकी चाहिये कि वह दफा २५ में बतलाये हुए नियमपर कानूनन चार करे आ तब या ता जतकी दस्तखत खानिन कर दव था उसे गज्ज कद । दख—लक्ष्मणगयन बानम वृ गज्ज 40 All 663

अपन कर्जोंको अदा नहीं कर सकता है—इसमें अभिप्राय यह है कि अदालत दस्तखत पर हुकम देनेमें पहिले यह समझ लव कि आया दस्तखत दन बोले कर्जदारका इच्छा जा नसूत्र किया जासकता है उमक कर्जोंमें कायदा तो नहीं है यदि उसका इच्छा (Assets) उमक कर्जोंसे ज्यादा समझ पड़े ता एभी दशम कर्जदार दिवालिया करार देने जानका इच्छा नहा है । पिछले एक्टक अनुसार इस प्रसारका बाधन नहीं था, हा दस्तखतमें यह कह दना आवश्यक था कि वह कर्ज अदा नहीं कर सकता है पर ३ एक्टके अनुसार अगलतरी इस बातक विश्वास दिखाना आवश्यक है कि वह अपने कर्जोंको अदा नहीं कर सकता है । इस बाधनो साविन वगवज भिये कि वह कर्जोंको अदा नहीं कर सकता है कोई बहुत सघुतकी आवश्यकता नहीं है केवल वतनाहा सघुत कदा हागा जिननेस अगलतरी विश्वास हा जाव कि दस्तखत वह अपन कर्जोंको अदायगीका प्रव व नहीं कर सकता है । दख—A I R 1923 Mad 680

यः वाद कि कर्जदार अपने कर्जों को क्या करने के लिये तैयार नहीं है अदायत कानून तब बरे और इस मामले पर अदायत अन विचार प्रथम कर दें। देखो—A. I. R. 1924 All 800.

उपपन्ना (१)

फलाज (ए) इस कलाजमें वत कर्जों तादाद बढ़ाई गई जिसका कसमें कम होना आवश्यक है उन कि उसकी दरखास्त मजिस्ट्रेट जातेगी जबकि कोई कर्जदार अथ कर्जदारों के सम्पत्ति किसी कर्जों अदायगी का विरोध हो और वह कर्ज सवस या उनमेंसे किसीसे उत्पन्न किया जा सकने हो तो ऐसी दशामें वह कर्जदार उस कर्जों के आधार पर दिवालिवा करार दिये जानेकी दरखास्त देसता है। देखो—मदराम बनारस रामचन्द्र 20 I. C. 259, गुडामंदर बनारस मगलमेन देसतन A. I. R. 1926 Lah. 235

जबकि दिवालिवा करार दिये जानेकी दरखास्त दी गई हो और उसमें तादाद कर्ज ५००) करनेसे कम हो उसके बाद दूसरा कर्जदार उस कर्जों पर करने के लिये सम्मिलित किया गया हो तो जितना सम्मिलित यह दूसरा कर्जदार सम्मिलित किया गया हो उस तारीखसे दिवालिवा करार दिया जानेवाला हुक्म काममें लाया जा सकेगा। देखा—26 A. L. J. 941.

फलाज (बी) इस कलाजके अनुसार दिवालिवा दरखस्त देने समय कर्जदार का वह या दिशामतमें होना आवश्यक है यह पर्याप्त नहीं है कि वह गिरफ्तार किया गया था। इस प्रकार जबकि कोई कर्जदार किसी इलाक़ा किमोम गिरफ्तार किया गया हो पालु उसके कुछही घंटों बाद बाँक दिया गया हो तो ऐसी दशामें इस गिरफ्तारी के आधार पर वह कर्जदार दिवालिवा करनेकी दरखास्त नहीं देसता है। देखो—25 All. 209.

इसी प्रकार दरखस्त देनेसे पहिले ही उसकी गिरफ्तारी हो जाना चाहिये यह पर्याप्त नहीं होगा कि वह दरखास्त दिये जानेके बाद गिरफ्तार किया गया हो और तब वह इस गिरफ्तारी के आधार पर दिवालिवा बनवा चहिये। देखो—दिलमल बनारस सहाय लाल A. I. R. 1927 Lah. 88 इस कलाजमें देखो बाद आता रहने कोर है कि इसमें 'Arrest' म 'Imprisonment' दोनों शब्दोंका प्रयोग किया है कि य कि गिरफ्तारीकी हाजतें तथा जेलमें बंद होने पर दोनों दशाओंमें कर्जदार को दरखस्त देनेका इशारा है।

फलाज (सी) इस कलाजके अनुसार आयदादनी कुंशी किसी दानेकी डिक्लीन (For payment of money decree) म होना चाहिये। दिवालिवा दरखस्त देने समय आवदाद डिक्लीन हुई होना चाहिये यह नहीं कि वह कुंशी छूट गये हो या वह बिक्रि हुई हो ऐसी दशामें हाजतें ज़ारदाद डिक्लीन नहीं समझी जानेगी और यह कुंशी कर्जदारकी आयदादनी होना चाहिये। देखो—मदराम बनारस सुहमद अजीमचरी 25 All 204

जबकि किसी हक़ दिये पक्षियों एक विधा तथा दो दुन होवें और यह दिखलाया गया हो कि कर्ज उन पुरोंमेंने एक्के लिया था तो उस वक्त तक पिछा तथा दूसरा पुन एके कर्जों अग्रम पर दिसायेया करार नहीं दिया जायगा जब तक कि यह साबित न हो जाय कि कर्ज परिवारका आवश्यकताके लिये दिया गया था। देखो—मदराम बनारस अजीमचर A. I. R. 1926 Lah. 354

यदि दिवालिवा करार दिये जानेकी पहिली दरखस्त अदायत प्रेषन करनेकी बग़लमें खिज हो गई है तो दूसरी दरखास्त दी जानेकी कर्जों पहिली दरखस्त पर कोई बदलाव उनको सच्चा आदिके बाने नहीं दिया गया था वः कि काय वह अग्र तर्जिका सुस (Re-judicata) दफ़ा १) अनुसार दिवालिवाके अनुसार नहीं माना जावेगा। देखो—इसनदीन बनारस नृप राम A. I. R. 1928 Lah. 374

उपदफा (२)—इस उपदफाको बनाकर यह कोशिशकी गई है कि जिसमें कोई कर्जदार अदालतको बेना दमते परेशान न करे अर्थात् यह कि आज किसी कर्जाल्वाहसे परेशान होकर वह दरखास्त देने व इसके बाद उस कर्जाल्वाहसे समझाता हो जाने पर बहाल होनेसे लिये कोई पैवली न करे या नवाजकी दरखास्त योंही लागू होनासे देवे उसके बाद दुबारा फिर जब कोई दूसरा कर्जाल्वाह अपने कर्जोंके लिये उसे परेशान करे तब फिर दरखास्त अदालतमें देदेवे या इसी प्रकारके और किसी तर्गकेसे अपना बेना फायदा न अदालतको बेना परेशान करनेकी कोशिश करे। कर्जदारको मनमानी कार्रवाईसे रोकनेके लियेही यह उपदफा बनाई गई है कि जिसमें मेकनीपतीसे काम करने वालेही कर्जदारको इस एक्टके अनुसार काम उठानेका अवसर प्राप्त हो सके।

इसालेखे ही एमेन्डमेन्ट एक्ट ११मर्च १९२७ई० (Insolvency Amendment Act XI of 1927) के अनुसार इस उपदफामें यह भी बदा दिया गया है कि यदि प्रेसिडेन्सी टाउन्स इन्साल्वेन्सी एक्टके अनुसार भी कोई शफ्स दिवालिया करार दिया गया हो तो उसके लिये भी यह उपदफा लागू होगी।

जबकि कोई व्यक्ति दिवालिया करार दिया गया हो तब उसको यह हुक्म दिया गया हो कि वह छ. माहके अन्दर बहाल होनेकी दरखास्त देवे और उसकी जायदाद व लहना आकिशियल रितीवर वी सुपुर्गामें के लिये गये हो तथा उस जायदाद आदिके दाम भी रितीवरके हाथ आगये हो परन्तु किसी कर्जाल्वाहने अपना हिस्सा रसदी न लिया हो और न दिवालिये ने बहाल होने की दरख्ताम्न द्य हो तथा ऐसी दशाम दिवालिया करार देनेका हुक्म मसूख कर दिश गया हो तो दरखास्त देने वालकी हक होगा कि वह दुबारा नई दरखास्त दिवालिया करार देनेके लिये दे सकता है। यह तय हुआ था कि घूके जायदाद आकिशल रितीवरकी ही सुपुर्गामें है और इसी कारण दिवालियाको सुमकिन है यह स्थान रहा हो कि जब तरु रितीवरके दशाम कर्जाल्वाहानकी रुपया न बट जाने तब तक उसे बहाल होनेकी दरखास्त देनेकी आवश्यकता नहीं है अतः इस दशामें अदालतको चाहिये कि उसे दुबारा दरखास्त देनेकी आज्ञा प्रदान करदे। देखो—A. L. R. 1928 Lah 452.

दफा ११ वह अदालत जहां दिवालेकी दरखास्तें दीजावेंगी

हर एक दिवालेकी दरखास्त उस अदालतमें दी जावेगी जिसके अधिकार सीमामें कर्जदार अधिकतर भिवास करता हो या व्यवहार करता हो या लाभके लिये कोई कार्य करता हो और अगर वह गिरफ्तार किया गया हो या कैदमें हो तो उस अदालतमें जिसके अधिकार सीमामें वह हिस्सनमें (घन्दी) होवे। परन्तु अगर उस अदालतमें जिसमें कि दरखास्तकी सुनवाई हुई है जल्दीसे जल्दी कोई एतराज इस बातके लिये न किया जावे कि दरखास्त किस जगह देना चाहिये और और जगह दरखास्त देनेके कारण कोई अन्याय न हो गया हो तो अपील या निगमनीमें कोई इस प्रकारका एतराज न माना जावेगा।

ब्याख्या—

हर एक दिवालेकी दरखास्त चाहे उसे कर्जाल्वाह देवे या वह कर्जदार द्वारा दी गई हो उस अदालत दिवालियामें दी जाना चाहिये जिसके अधिकार सीमामें दिवालिया करार दिया जाने वाला व्यक्ति अधिकतर निवास करता हो या व्यापार करना हो या फायदेका और कोई काम करता हो। परन्तु जबकि दरखास्त देने वाला कर्जदार गिरफ्तार हुआ हो तो वह उस अदालतमें दरखास्त देसकता है जिसके अधिकार सीमामें वह बन्दी होवे।

अधिकार सीमाके लिये एतराज जिनकी जल्दी होसके किया जाना चाहिये अर्थात् जिस अदालतमें दरख्ताम्नकी सुनवाई हो रही हो, वही अदालतमें अल्दसे अल्दी एतराज करना चाहिये वरना बाद फैसला दरखास्तके तब प्रकारका एतराज अदालत आगील या निगमनीमें उस बतत तक न सुना जावेगा जबतक कि यद्यत् जगह सप्रत्य होवेकी वजहसे कोई विशेष हानि न पहुँची हो तथा अधिकतर सीमाका एतराज अदालत मानद्वतमें जल्दीसे जल्दी न उठाया गया हो।

अधिकतर रहता हो या व्यापार करता हो—यदि छतर रहनेसे पत्रियाय-यह समझना चाहिये कि जहा पर यह व्यक्ति खाता हो पीता हो या सोता हो या जहा उसका परिवार या नौकर खाता पीता या सोता हो । किसी आदमीके रहनेकी जगह वह मानना चाहिये जहा खसबतसे उसका मजान रहने व सोनेका होवे देखो—38 Cal. 394. यह व्यापक नहीं है कि बहुत दिनोंमें वहा रहता हो यदि थोड़ा समयसे भी व स्थित खास कामकी वसूहतभी वह वहा रहता हो तो यह मान लिया जावे कि वह उसके रहनेकी जगह है और जगहछतकी सुननेका अधिकार हो जावेगा । देखो—17 C. W. N. 405, A. I. R. Mad. 585

यदि बहुतसे लोग फायदा उठावेंगीं । पारससे अपने उसको रहनेकी जगहको छिया कर दूसरी दूरकी जगह दिवालिया बनने की घोषणा करते हैं जिसमें अन्तर्गुच्छादि फॉर्म (विरोधक) सामने न आताके या उन्हें सामन आनेमें पोशानी छडाना पके इसलिये एकदम यह रक दिया गया है कि जहां अधिकतर कर्त्तदार निवास करता हो वही दरखास्त दाखाना चाहिये । जगहछतको दरखास्त सुनने समय यह निश्चास कर लेना चाहिये कि दरखास्त दते समय दिवालियाने उनके अधिकार सीमाके अन्दर अपनी सजुनत कायम काड़ी या । इसी प्रकार जबकि कोई व्यक्ति अपने रिश्तेदारोंके साथ थोड़े समयमें रहने लगता हो तो ऐसे रहनेमें जगहछत दिवालियाको उसकी दरखास्त सुननेका हक है देखो—39 I. C. 463.

जगर कमी न वह जगह रहनेकी जगह छोड़कर चला जाता हो तो यह नहीं समझा जावेगा कि वह लगातार उस जगह पर नहीं रहता है । परन्तु इसके यह न मान लेना चाहिये कि यदि कोई जल्लत पलायातरी अपने किसी रिश्तेदारके सहा ठहर जावे तो उसका इस प्रकाश उठना बहाते रहनेके बराबर मान लिया जावेगा देखो—18 C. W. N. 1050

यदि कोई व्यापारी जिन जगहोंमें रहकर व्यापार करता हो तो वह उस जगह द्वारा दिवालिया करार दिया जासकता है जिसकी अधिकार सीमामें उसका पुनेना मजान व जमीन होवेगी देखो—(1925) M. W. N. 797. रहनेकी जगहका सर्वांग एक वाक्याती सर्वांग है और अधिकतर वह जगह जहाँ वह सारा भर नगर मिल सके उसके रहनेकी जगह मानना चाहिये उस व्यापारियोंके लिये जो जगह वसतग व्यापार करते हैं रहनेकी जगह वही समझना चाहिये जहा वह अपना रोमानाका काम करते हो व जीविका उपार्जन करते हो । देखो—22 A. L. J. 457.

जबकि कोई व्यक्ति किसी व्यापारमें सम्मेल रहता हो और उसके कार्यों भाग लेता हो और उसकी चीज नक में शामिल हो तो यह मान लिया जावेगा कि वह उस व्यापारको करता है और ऐसे व्यापारकी जगहमें वह दिवालेकी दरखास्त देसकता देखो—19 A. L. J. 626. किसी व्यापारका चाह रहना उस वक्त तब समझा जावेगा जबतक कि उसके वहाँ न रहने और उसका लहना बसूल करनेको बना रहे (यदि देखो—48 Mad 798

व्यापारके लिये यह आवश्यक नहीं कि कर्त्तदार स्वयंही उस व्यापारकी करता हो किन्तु यदि व्यापार उसका, ऐजेंट याता या नौकर करता हो तो वह मानलिया जावेगा कि वही उस व्यापारकी करता है (देखो—A. I. R. 1922 All. 337. इस प्रकार यदि किसीके खास व्यापारकी जगह दूसरी हो परन्तु जहाँ परभी वह व्यापार करता हो वहाकी जगहछत उसे दिवालिया करार देसकनी है । देखो—A. I. R. 1926 Sind 18=97 I. C. 446.

• यह शब्द कि 'स्वयं या किसी ऐजेंटके ज़रिये' (Either personally or through an agent) इस कारण रखे गये हैं कि जिससे अदालत दिवालियाने अधिकार सीमाके अन्दर काम करने वाले बाहरी व्यापारियोंके साथ भी प्रम जाता रहे यदि वह एजे टोंके ज़रिये या मनजोंके ज़रिये जो खासकर काम करनेके लिये नियुक्त किये गये हैं काम करते हो परन्तु इसमें उस कर्म विक्रयकी गणना नहीं होगी जो किसी कमीशन ऐजेंट (अदातिय) के ज़रिये किया जावे देता—A. I. R. 1929 Sindb. 24.

हफा १२ दरखास्तकी तस्दीक

हर एक दिवालियाकी दरखास्त लिखकर दीजावेगी और उस पर हस्ताक्षर व तस्दीक उसी प्रकार होगी जिस प्रकार जाबता दीवानोंमें दिये हुए नियमोंके अनुसार अर्ली दावा पर हस्ताक्षर व तस्दीक होती है।

व्याख्या—

जैसा कि आगता दीवानोंके आर्डर ६ क्ल १४ में दिया हुआ है दिवालिया करार दिये जाने वाली दायताएँ पर हस्ताक्षर देने बाधके तथा उसके बचीबचे होना चाहिये यदि दरखास्त देने वाला अपनी पैदागी या किसी खास कारणवश उपरिष्ठ न हो तो उक्त नियमपूर्वक निपुण किता हुआ एगेंट उसकी सफाये हस्ताक्षर कर सकता है इसी प्रकार आर्डर ६ क्ल १५ के अनुसार दायताएँके नीचे दायताएँ कुनिन्दा की तस्दीक आगत द्वारा होना चाहिये या किसी ऐसे ब्यक्तिके द्वारा होना चाहिये जो उन सब बातोंको जानता हो। यदि कोई दायताएँ बाकबश तरदीककी हुई नहीं होवेगी तो उस पर दिवालिया करार दिया जाने बाधा हुकम नहीं दिया जावेगा। यदि दरखास्तमें आ तस्दीक आगतमें कोई गलती हो जाने तो उसका सवोधन बादमें किया जानकटा देवे—22 All 55.

हफा १३ दरखास्तमें दिखलाई जानेवाली बातें

- (१) कर्जदारकी दी हुई दरखास्तमें यह बातें दिखलाई जाना चाहिये :—
- (ए) यह बयान कि कर्जदार अपने कर्ज अदा करनेके योग्य नहीं है।
- (बी) यह कि वह अधिकतर कहाँ रहता है या कहाँ रोजगार करता है या कामके लिये काम करता है और अगर गिरफ्तार हुआ हो या कैद हो तो वह किस जगह हिरासतमें है।
- (सी) किस अदालतके हुकम द्वारा वह गिरफ्तार या कैद हुआ है या किसके हुकम द्वारा उसकी जायदाद कुर्ककी गई है इसके साथ २ उस डिफीका हालभी देना चाहिये जिसके तिलसिलमें ऊपरका आर्डर दिया गया हो।
- (डी) अपने कर्जोंकी तादाद व उनकी तफसील व उनके साथ २ कर्जद्वाराओंके नाम व पते अहां तक उसको मातुस हों या अहां तक वह अवित परवाह न प्रयत्न द्वारा जान सके।
- (ई) अपनी कुल जायदादकी तादाद और उसका हवाला और उसके साथ साथ
 - (i) रुपयेके अतिरिक्त जो जायदाद हो उसका मूल्य
 - (ii) वह जगह व जगहें अहां वह जायदाद हो
 - (iii) इस इच्छाकी घोषणा कि वह अपनी कुल जायदाद अदालतके सुपुर्दे करने को प्रस्तुत है केवल उन वस्तुओंकी छोड़कर जो जाबता दीवानों व अन्य किसी प्रचलित कानून द्वारा कुर्क या नीलाम नहीं होसकती हैं परन्तु इन वस्तुओंमें दिसाबकी किताबें नहीं हूट सकती हैं।

(एक) इस बातका ध्यान कि आया उसने दिवालिया बननेकी कोई दरखास्त पहिले कभी दी है या नहीं और अगर दी है तो

(i) अगर यह दरखास्त खारिज हुई है तो उसके खारिज होनेका काय क्या था, या

(ii) अगर कर्जदार दिवालिया करार दिया जा चुका है तो उस दिवालिका संक्षिप्त विवरण देना चाहिये जिसमें यह भी दिखलाया जावे कि आया पहिले दिवालिया करार दिये जाने वाला हुक्म मंजूर हुआ है या नहीं और अगर मंजूर हुआ है तो किन कारणोंसे

(२) जबकि दिवालिकी दरखास्त कर्जस्वाह या कर्जस्वाहों द्वारा दी जावे तो उसमें कर्जदारके बारेमें यह सब बातें दिखलाई जावेंगी जिनका उल्लेख (१) (बी) में है और यह भी दिखलाया जावेगा कि—

(ए) कौनसा दिवालिका काम हुआ है और कर्जदारने उसे किस तारीखमें किया है ।

(बी) कर्जस्वाहोंके खिलाफ दरखास्त देने वाले कर्जस्वाह या कर्जस्वाहोंके कर्जोंकी क्या तादाद है ।

ध्यास्या—

यह दफा दो उपदफाओंमें विभक्त है उपदफा (१) में उन बातोंका उल्लेख है जिनका दिखलाया जाना कर्जदार द्वारा दो हुई दरखास्तमें चाहिये है तथा उपदफा (२) में वह बातें बतलाई गई हैं जो कर्जस्वाह द्वारा दी हुई दरखास्तमें दिखलाई जाना चाहिये । पहिली उपदफा में श्रावण है और उन कर्जोंके बारेमें जो ठीक ठीक बात हो दरखास्तमें दिखलाई जाना चाहिये दूसरी उपदफा में यह बतलाया गया है कि पहिली उपदफाके प्राव (बी) की बातें होना चाहिये तथा उनके अतिरिक्त दोबारा और होना चाहिये जो उपदफा (१) के प्राव (ए) व (बी) में बतलाई गई हैं ।

जबकि अमेरिकी एक्टमें (Shall) शब्दका प्रयोग किया गया है इससे यह स्पष्टता चाहिये कि जिन बातोंका ज़रूर इस दफा में दिया गया है वह अवश्य दिखलाई जाना चाहिये परन्तु यदि कोई कर्जदार अपनी दरखास्तमें कर्जोंकी तालीकाल पालतू दिखलाई अर्थात् कर्जोंके ब्यादा का कम दिखला देवे या अपनी जायदादकी विधि जावे तो इस बिना पर तलबी दरखास्त नामका नही भी जावेगी अर्थात् वह पालतू होवे हुए भी यदि खानापूर्वी दुस्त हो तो यह दिवालिया करार दे दिया जावेगा परन्तु यदि वह पालतू भूलते हो गई हो तो हुक्म कराई जासकती है वा अगर वह दायरिया जानबूझकर की गई है तो उस कर्जदार पर कानून दिवालियामें बतलाया हुआ खर्च लागू होगा और उसकी वस्तु अपने सामने होने पर उसके अनुसार दंड दिया जासकेगा यदि सब लब्ध दरखास्तमें न दिखलाया गयी हो तो इस बिना पर दिवालिया करार दिया जानेका हुक्म नहीं दिया जावेगा दफे—A. I. R. 1922 Bom. 80.

उपदफा (१)

खोज (ए) जबकि कर्जदार अपना कर्ज नहीं कर सकता हो तभी वह दिवालिया बननेकी दरखास्त देसकता है ।

दफा १० में इसके बारेमें काफी चिन्ता जा चुका है इस बातकी आवश्यकता नहीं है कि कर्जों न अन्त कर सकनेका प्रभु धर्मरूपसे साबित किया जाये केवल इतनाही साबित कर दिया जाना कि सादिग वह कर्जदार अन्त कर्ज नहीं कर सकता है इस शर्तकी आवश्यकतासे पूर्ण करनेके लिये परीत होना ।

फलाज (बी) अधिकांश खेतों की जगह आदिका उच्छेद इस कानून में किया गया है दफा ११ में इसके बारे में काफी कहा जाया है उसमें देखनेसे इस कानून का अभिप्राय स्पष्ट हो जावेगा ।

फलाज (सी) इसमें भित्तियाँ व कैद आदिका उच्छेद है इसके बारे में भी दफा ११ में काफी लिखा जा चुका है उसमें देखनेसे इस कानून का अभिप्राय भला भ्रष्ट प्रकट हो जावेगा । दरखास्त देने समय गिरफ्तारी या कैदी की दशा कायम होना चाहिये ।

फलाज (डी) इस कानून में बतलाने हुए सब मामलों में अभिप्राय उन सब मामलों व कर्जों का है जो इस एक्ट के दफा ३४ (१) के अनुसार साबित किये जा सकने हैं । यदि दरखास्तमें किसी कर्जदार का कर्ज दिखला दिया जावे तो वह रिहा किया जाना उस कर्ज का इकत्ता दफा १९ कानून मियाद के अनुसार सप्तमा जावेगा देखो— 16 C. W. N. 346. रोटी कपड़े के खर्च का बकाया जो कर्जदार के सिधे बाकी हो उसका कर्ज समझा जावेगा और वह कर्ज भी कर्ज की सूची में दिखलाया जाना चाहिये, देखो—5 Cal. 536. कर्जों का साथ सब कर्जदारों के नाम महा दफा मालूम होमके उनका पूरा पता भी दरखास्तमें बतलाना चाहिये जिसमें उनकी सुविधा पूर्वक सूचना दी जा सके तथा वह दरखास्तमें बतलाये हुए कर्जों का सचाई व सुझाई का समझ कर अपना एतदाज पेश कर सकें व अपना ठीक कर्ज साबित कर सकें ।

फलाज (डी) इस कानून के अनुसार कर्जदार को अपनी सब जायदाद व छहना बतलाना चाहिये यदि कर्जदार को प्राविडेंट फंड (Provident Fund) से कपया मिलने वाला हो तो उस कपये की भी छहनामें दिखलाना चाहिये । देखो—10 Bom. 913.

उपफलाज (१) में कपये के आदितिक जो जायदाद होने उसकी कीमत का अन्धाजा भी दिया जाना चाहिये ।

(11) के अनुसार उन जगहों का बतलाना चाहिये जहाँ पर कि यह सब जायदाद होने, तथा

(111) के अनुसार एक जाबना ऐलान कर देना आवश्यक है कि वह अपनी सब जायदाद को अदालत की सुपुर्दगी में देने की प्रस्तुत है, जो ऐसा ऐलान चाहे किया जावे या न किया जावे दिखलिया करार दिये जाने का हुकम होने पर सब जायदाद अदालत या रिीवर की सुपुर्दगी में आ जाना है अर्थात् उनकी उस पर कब्जा कर लेने का अधिकार हो जाता है इस कानून में यह भी बतलाया गया है कि वह चीजें जो जाबना दीवानी या अन्य किसी प्रचलित कानून के आधार पर छुर्कें या भीष्म नहीं हो सकती हैं उनके सुपुर्दगी का सवाल पैदा नहीं होता है परन्तु हिनामकी किनारे जो जाबना दीवानी के अनुसार छुर्कें नहीं की जा सकती हैं इस एक्ट के अनुसार छुर्कें की जा सकेंगी और कर्जदार को वह वित्तों अदालत या रिीवर की सुपुर्दगी में देने को तैयार रहना चाहिये ।

अन्य किसी प्रचलित एक्ट से अभिप्राय इन एक्टों से है जो प्रचलित हैं तथा जिनके नियमों के अनुसार कोई जात जायदाद छुर्कें या गीला मामूली कानूनी तरीकेसे नहीं की जा सकती है जैसे कि बुन्देलखंड लैंड एलियेशन एक्ट (Bundel Khand Land Alination Act) तथा प्राविडेंट फंड एक्ट (Provident Fund Act) आदि ।

नज़ (एफ) यदि दफा १० के कानून (१) के अनुसार उन दिखलिया के लिये बकायद रखती गई है जिन्होंने विच्छेद दिवालिया की तरफाई या उनकी पैसी नेमनीयती नहीं की है इस कारण दरखास्त पेश करते समय ही यह बात प्रकट कर देना उन लोगों के लिये आवश्यक समझा गया है जिसमें जायदाद की उत्पत्ति जानी रहे व कोई शक्य जसली मामलों के किानर घोसल दे सकें । इस कानून में दोनों बातों का तर्काल

कर्जदार द्वारा दी गई हैं। इस प्रकार जब एकही कर्जदारके विरुद्ध कई कर्जस्वाहोंने दिवालिया करार देनेकी दरखास्तें दी हैं तो वह सब दरखास्तें एकही साथ सुनी जा सकती हैं या जबकि संयुक्त कर्जदारोंने खिलाफ भिन्न २ दरखास्तें दी गई हैं तो ऐसी दरखास्तोंकी सुनवाई भी एग्री साथ होना चाहिये। यह आवश्यक नहीं है कि ऊपर बतवाई हुई सभी दरखास्तें एक साथ अवश्य सुनी जाना चाहिये अदालतको आधिकार है कि भिन्न दानोंके साथ व जिन २ दरखास्ताका वह साथ सुना चाहे सुन सकती है अर्थात् जिन दरखास्तोंको सुविधापूर्वक एक साथ सुना जा सकता है उनमेंही साथ सुना चाहिये। एग्न हार्डवेरने A. I. R. 1925 Rang. 36 में यह तय किया था कि एक वर्गानिवासी व उसकी स्त्री दानोंके खिलाफ दिवालिया करार दिये जानकी संयुक्त दरखास्त दी जा सकती है जबकि वह दानों कर्जस्वाहोंके कणा हों तथा उन दोनोंने दिवालिया काय किया है।

इसी प्रकार मद्रास हार्डवेरने 44 Mad 810 में यह तय किया था कि संयुक्त हिंदू परिवारके श्रेष्ठोंके खिलाफ संयुक्त दरखास्त दिवालिया करार दिये जाने पर उस समय दी जा सकती है जबकि उन्होंने संयुक्त दिवालिया काय किया है। परन्तु आगरा हार्डवेरने A. I. R. 1926 Lab. 235 में यह तय किया था कि कई एक मद्रास मिशनर एक साथ दिवालिया करार देनेकी दरखास्त नहीं दे सकते हैं।

दफा १६ कार्रवाईका तर्ज बदलनेका अधिकार

जबकि दरखास्त देने वाला कर्जस्वाह अपनी दरखास्तकी पैरवी उचित प्रयत्नके साथ न करता हो तो अदालतका अधिकार है कि वह उसका स्थानपर किसी ऐसे दूसरे कर्जस्वाहको दरखास्त देने वाला माने जिसका कर्जा कर्जदार पर उस तादादके अनुसार हो जो एकदम दरखास्त देने वाले कर्जस्वाहके लिये बतलाई गयी है।

व्याख्या—

इस दफा द्वारा अदालतको अधिकार दिया गया है कि वह एक कर्जस्वाहकी जगह किसी दूसरे कर्जस्वाहकी दरखास्त देने वाला मानले बशर्ते कि उस कर्जस्वाहका कर्जा वह कर्जदार होने तथा उसके भी कर्जारी तादाद ५०० से कम न होवे। यह अधिकार इस कारण दिया गया है जिसमें दिवालियों दरखास्तकी पैरवी भली भांति हो सके तथा दूसरे कर्जस्वाहोंको किसी प्रकारकी हानि न होवे क्योंकि एक कर्जस्वाह द्वारा दरखास्त दिये जानका अधिग्रहण यह होता है कि वह केवल अपनी सामर्थ्य दरखास्त नहीं देता है किन्तु उसकी दरखास्तमें सब कर्जस्वाहानका लाभ उठावेका अवसर प्राप्त होता है। इसीसे यदि बाद दरखास्त दिये जानेके दरखास्त देने वाला कर्जस्वाह अदालतमें मिल जावे और पैरवी दरखास्त न करे अर्थात् मोटिस आदिवाला सर्व न दाखिल करे तो दूसरे कर्जस्वाहोंको मोक्ष दिया जासके जिसमें यदि वह चाहे तो कर्जदारके दिवाले के फायदे लाभ उठा सके तथा उस दिवालिया करार दिलाकर अपना व दूसरे कर्जस्वाहोंका मुक्तान न हान देवे।

दूसरे कर्जस्वाहोंका दरखास्त देने वाला मान लेनेसे वह दरखास्त उन्ही कर्जस्वाहोंकी दरखास्त समझा चाहिये तथा उसी तारीखसे समझना चाहिये जिस तारीखने पहिली दरखास्त दी गई हो और इसीलिये यह पर्याप्त है कि इस दूसरे कर्जस्वाहका कर्ज उस पहिली तारीख पर साबित किया जासकता था। जबकि किसी कर्जस्वाहने दिवालिया करार दिये जानेके लिये दरखास्त दी हो तथा मोटिस दूसरे कर्जस्वाहानक नाम जारी किये गये हों परन्तु इसका बाद अपनी दरखास्त देने वाला पैरवी छोड़ दे तथा अदालतने दूसरे कर्जस्वाहने पैरवीकी आज्ञा दे दी हो और यह साबित होके इस दूसरे कर्जस्वाह का कर्ज इस शामिल होने का गैर तालख पर प्रमाणिक अन्तर न आता हो तो यह तय किया गया कि उस कर्जस्वाहका शामिल किये जानेका हुक्म ठीक है और उस कर्जस्वाहका श्राव ऐसी दशम साबित किया जासकता है, देखो—A. I. R. 1928 Mad 608

दफा १७ कर्जदारके मर जानेपर कार्रवाईका चालू रहना

अगर कोई कर्जदार जिसने दिवालिकी दरखास्त दी है या जिसके खिलाफ दिवालिकी दरखास्त दी गई है मर जाये तो उस सूरतमें जबकि अदालत कोई खिलाफ हुक्म न दये कार्रवाई उस हद तक चालू रखी जायेगी जिस हद तक कि उसकी जायदादको घसूल करने प धाँटनेके लिये आवश्यक हो।

व्याख्या—

यह दफा उन दोनों प्रकारकी दरखास्तोंके लिये लागू है जो चाहे कर्जदार द्वारा या चाहे कर्जदार द्वारा दी गई हों। इस दफाके अनुसार कर्जदार (दिवालिया) के मर जानेपर भी दिवालिकी कार्रवाई चालू बनी रहेगी अर्थात् रिसीवर या अदालतकी अधिकार होगा कि वह दिवालिकी मृत्युके पश्चात् भी उसकी जायदाद या उसके अर्धनेकी घसूल कर सके तथा उसके कर्जदारोंमें उस सम्पत्ति को बँटवारा विभाजित कर सके।

दिवालिकी कार्रवाई समाप्त होनेसे पहिले यदि कर्जदार मर जाये तो उसके लड़के रिसीवरसे अपना हक वापिस नहीं माँग सकते हैं यदि रिसीवर उनके हककी भागके जीवनभरमें ले सकता हो। देखो—A. I. R. 1926 Mad 994.

अभिप्राय यह है कि दिवालिकीके मरनेपर रिसीवरके हाथमें सुदृढ़ी हुई जायदाद नहीं बिक्री सरती है। देखो—गोकुलसिंह बनाम किरण A. I. R. 1925 Lah 306.

अदालतकी अधिकार है कि कर्जदारके मर जानेके बादभी उसे दिवालिया करार देदे। देखो—A. I. R. 1928 Mad 476 (2); A. I. R. 1928 Mad. 480.

यदि दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मके खिलाफ अपील की गई हो और अपील सुने जानेसे पहिले दिवालिया मर जाये तो वह अपील उसके मरनेसे समाप्त हो जायेगी। देखो—नरायणसिंह बनाम गुणकृष्णसिंह A. I. R. 1928 Lah 119 (1).

दफा १८ दरखास्तोंके लेनेका तरीका

जिस प्रकार सन् १९०८ ई० के क़ायदा दीवानोंके अनुसार अर्ज़ें दावे लिये जाते हैं उसी प्रकार दिवालिकी दरखास्तें जहां तक उनका सम्बन्ध होगा ली जायेंगी।

व्याख्या—

इस दफाके जावना दीवानोंकी किसी खास दफाका खंडा नहीं है केवल यह बतलाया गया है कि जिन नियमोंका प्रयोग अर्थात् अर्जके लिये जानेमें किया जाता है वही नियमोंका प्रयोग दिवालिकी दरखास्तोंके लिये जानेमें भी किया जावेगा अर्थात् नियम प्रसार दीवानोंकी नालिशोंके दाखिले आदिम रजिस्टर रक्ता जाता है उसी प्रकार दिवालिकी दरखास्तोंके दाखिले होनेका भी रजिस्टर रक्ता जावेगा तथा उनमें तारीख दाखिले नामर मुकदमा आदिमा इत्यादि भी उरी प्रकाश होगा इस प्रकार दीवानोंकी नालिशोंका होता है दरखास्त दिवालिया चाहे कर्जदार द्वारा दीजावे चाहे कर्जदार द्वारा दोनोंमें ऊपर बतलाया हुआ नियम बर्तना चाहिये।

दफा १९ दरखास्तें लीजानेके बादकी कार्रवाई

(१) जबकि अदालतने कोई दिवालिकी दरखास्तको लेलिया हो तो यह उसके सुननेके लिये कोई तारीख नियत करनेका हुक्म देगी।

(२) दफा १६ (१) के अनुसार दिये हुए हुक्मका नोटिस कर्जस्वाहानको नियत किये हुए ढंग पर दिया जावेगा ।

(३) जबकि कर्जदारने स्वयं दिवालीकी दरखास्त नहीं दी हो तो दफा १६ (१) के अनुसार दिये हुए हुक्मकी सूचना कर्जदारको उस ढंग पर दी जावेगी जिस प्रकार सम्मन दिये जाते हैं ।

व्याख्या—

क्लाज (१)—यह क्लॉज अनुसार उस समय जबकि दरखास्त जैल, गई हो अदालतका कर्जस्वाहाना कि वह अपनी आत्मा द्वारा उस दरखास्तके सुननेके विषय कोई तारीख नियुक्त करे । दरखास्तका लिया जाना उस समय समझना चाहिये जबकि इस दृष्टिमें बनलाये हुए नियमोंके अनुसार दरखास्त लिखी गई हो तथा उसी टीक दमते अदालतमें दाखिल की गई हो ।

क्लाज (२)—यह क्लॉज कर्जदार व कर्जस्वाह दोनों द्वारा दी हुई दरखास्तोंके लिये लागू समझना चाहिये देखो—A. I. R. 1926 Lah. 360.

नियतरी हुई तारीखकी सूचना कर्जस्वाहानको दी जाना चाहिये उस समय जबकि किसी कर्जस्वाहाने दरखास्त दी हो तो शर्त कर्जस्वाहानके सूचनादी जानी चाहिये । नियत किने हुए दमते अधिनाय यह है कि इस दृष्टिमें बनलाये हुए नियमोंके अनुसार इस प्रकारकी सूचना दी जाना चाहिये यह नहा कि कोई निजीतरी पर कर्जस्वाहको सूचना देवने । सूचना कर्जस्वाहके ऐसे एजटको भी दी जासकती है जिसके हुक्म गुस्तारनामा आम हो, देखो—कल्यानना बनाम बैंक आफ मद्रास 39 Mad. 693

इस उपदस्ताके अनुसार दिये हुए नोटिसके लिये यह आवश्यक नहीं है कि उसकी जाती तामील होवे । यह सूचना रजिस्ट्री द्वारा जतके आये भी दी जासकती है यदि दाखलानके लिये या खास कर रजिस्ट्रीमें टीक पने पर सूचना भेजी जावे तो यह मान लिया जावे कि सूचना टीक प्रसारित हो गई है । जबकि रजिस्ट्री द्वारा पत्र जैल आने और उस पर लिखा हो कि लेनेमें इन्कार है तो यह मान लिया जावेगा कि उसके नाम वह रजिस्ट्री गईभी उसके सूचना निष्ठ गई है, देखो—गिरीशचंद बनाम गिरीशमोहन 23 C. W. N 319.

इस उपदस्ताके अनुसार दिये हुए नोटिस दरखास्तके सुने जानेसे पहिलेही कर्जस्वाहानके पास पहुँचना चाहिये जिसमें यदि वह चाहे तो अपन एतरात आदि पेश कर सके ।

क्लाज (३) यह क्लॉज केवल उसी दरखास्तोंके सम्बन्धमें है जो कर्जस्वाहान द्वारा दी जावे इस क्लॉजके अनुसार नोटिस उस प्रकार नहीं दिया जाना चाहिये जिस प्रकार क्लॉज (२) में कर्जस्वाहोंके लिये दिया जाना बनलाया गया है किन्तु इस नोटिसकी तामील कर्जदार पर टीक उगी प्रकार होनी चाहिये इनत प्रकार सम्मनकी तामील होती है अर्थात् जावता दवालीके आर्डर ५ में बनलाये हुए नियमोंके अनुसार ऐसे नोटिस की तामीलकी जाना चाहिये ।

दफा २५ (१) के अनुसार अदालतको अधिनाय दिया गया है कि यदि उसकी रायमें कर्जदार पर नोटिसकी जाकी तामील नहीं हुई हो तो यह ऐसी दरखास्तको खारिज कर देवेगा इस प्रकारकी बात कर्जस्वाहोंके नोटिसके सम्बन्धमें नहीं कही गई है कारण इसका यह प्रतीत होता है कि कर्जदारका नोटिसका पहुँचना बहुत आवश्यक है तथा उसके पास बिना नोटिस पहुँचे हुए जो कार्यवाई की जावेगी वह सब नकारात्मक समझा जावेगी व कर्जदारको एकतरफा की गई कार्यवाई को मसूना कराना भी हक होगा इत्यादि ।

दफा २० दरमियानी रिसीवरकी नियुक्ति

अदालतको अधिकार है कि वह दिवालकी दरखास्त लिये जानेका हुक्म देते समय या उसके बाद उस समय जबकि कर्जदारने स्वयं दिवालकी दरखास्त दी है जरूर कर्जदारकी कुल जायदाद या उसके कुछ हिस्सेके लिये दरमियानी रिसीवर (Interim Receiver) नियुक्त करे जो कि उस जायदाद या उसके किन्हीं खास हिस्सेका कब्जा फौरन लेले और ऐसी सूत्रसे उसे दरमियानी रिसीवरको अदालत द्वारा दिये हुए वह अधिकार प्राप्त होंगे जो सन १६०० ई० के आधुना धीमाओंके अनुसार रिसीवरको प्राप्त होसकते हैं। अगर इस प्रकार कोई दरमियानी रिसीवर नियुक्त नहीं किया गया है तो भी अदालतको अधिकार है कि दिवालिया करार देनेसे पहिले किसी दूसरे समयमें दरमियानी रिसीवर नियुक्त कर देवे और उसकी नियुक्तिमें इस दफाके नियमोंका उपयोग किया जायेगा।

व्याख्या—

इस दफा द्वारा दिवालियेकी जायदाद पर कौन कम्पा कर लेनेका अधिकार अदालतको प्राप्त है अर्थात् जिन समय दरखास्तका किया जाना मजूर किया जाव उसी समय रिसीवर जायदाद पर कब्जा लेनेके लिये नियुक्त किया जासकता है इससे दो बातोंकी सुविधा होगी। है एकतो यह कि जायदाद बरबाद होनेसे बच जाय है दूसरे वह कर्जदार जायदादकी दरखास्त देनेके बाद अलहदा नहीं कर सकेगा और सब उच्छेदादोंमें जायदादसे पूरा फायदा उठानेका साधन मिल सकेगा।

यदि कर्जदार द्वारा दरखास्त दी गई हो तो दरमियानी रिसीवर अवश्य नियुक्त किया जाना चाहिये अर्थात् इस दशामें अदालतका कर्तव्य होगा कि वह रिसीवर नियुक्त करे परन्तु जब कर्जदार द्वारा दरखास्त दी गई हो तो अदालतकी अधिशार है कि वह चाहे रिसीवर, दरखास्त लिये जाने समय नियुक्त करे या उस समय न करे जहा आवश्यकता अदालतकी उस समय सम्पन्न पड़े—इसका कारण यह भी हो सकता है कि कर्जदार द्वारा दरखास्त देनाही दिवालिया कानून बतलाया गया है इस कारण उनके दरखास्त देतेही अदालत यदि रिसीवर नियुक्त करे तो कोई अशुक्ति न होगी परन्तु कर्जदारकी दरखास्त कभी न नेना दनाक कारणसे व फोसान करनेकी गरजतर्था ही जायसकती है इसलिये उस पर दरखास्त लिये जाने समझी रिसीवर नियुक्त कर देना एक प्रकारसे कर्जदारके ऊपर अशुद्धी होगी और इसीलिये बाद समाप्त होने व आवश्यकता समझने ही पर रिसीवर नियुक्त किया जाना चाहिये।

दरमियानी रिसीवर (Interim receiver) के अधिकार—दरमियानी रिसीवरको बड़ी अधिकार दिये जा सके हैं जो आधुना धीमाओंके अनुसार नियुक्त लिये जानेवाले रिसीवरको प्राप्त हो सके हैं।

अदालत दिवालियाई अधिकार दे कि वह दरमियानी रिसीवरको उस समय दिवालियाई जायदाद पर कब्जा के लेनेका हुक्म दे देव या किसी शर्तों के साथ न जा लेनेका हुक्म देवे अदालत दरमियानी रिसीवर चुनकर कम्पेका हुक्म देते समय उस हुक्ममें न शर्तोंको उल्लेख कर सक्त है जो वह उस समय उस रिसीवरको दिया चाहती हो, देखो—42 Cal 289 दरमियानी रिसीवर तथा रिसीवरम अंतर है क्योंकि दरमियानी रिसीवरको जायदाद पर कब्जा ले लेनेकी अधिकार होता है तथा वह अधिकार उसे प्राप्त नहीं होने है जो अदालत उसके लिये अपन हुक्म द्वारा अदा न को परन्तु रिसीवर (Regular) रिसीवर दिवालिया कानून दिये जानेके बाद होता है और दिवालियाई सब जायदाद उसकी संपूर्णता में आता है तथा वह सब जायदाद उसकी मालकी जाना चाहिये। इस एकके अनुसार जो रिसीवर नियुक्त किया जावे उसे (Public Officer) जानना रिसीवरकी दफा २ के अनुसार समझना चाहिये तथा उसके विरुद्ध कोई दावा करनेसे पहिले दफा ८० अनुसार रिसीवरको नोडित दिया जाना आवश्यक है, देखो—50 I. C. 411.

दफा २१ कर्जदारके खिलाफ दरमियानी कार्रवाई

दिवालेकी दरखास्तके लिये जानेका हुक्म देते समय या उसके बाद दिवालिघा करार देनेका हुक्म देनेसे पहिले अदालतको अधिकार है कि वह स्वयंही या किसी कर्जस्वाहके दरखास्त देने पर नीचे दिये हुए हुक्मोंमेंसे एक या एकसे अधिक हुक्म देसकती है:—

(१) कर्जदारको उसकी उस घकरी हाजिरके लिये उचित जमानत देनेका हुक्म देसकती है जबतक कि दिवालेकी दरखास्त पर आखिरी हुक्म न हो जावे ।

(२) कर्जदारके कर्जे या उसकी हुक्मतमें जो जायदाद हो उस सबको या उसके किसी हिस्सेको बजरिये हुक्म कुर्कीके कब्जा लेंनका हुक्म देसकती है लेकिन इससे वह सब चीजें अलावा हिसाब किताबकी किताबोंकी बरी हैं जो सन् १९०८ ई० के ज़ावता दीवानी या किसी अन्य प्रचलित एक्ट द्वारा कुर्की व नीलामसे बरी हैं ।

(३) कर्जदारकी गिरफ्तारीके लिये जमानती या विला जमानती धारण निकाल सकती है और यह हुक्म देसकती है कि वह दीवानी जेलमें उस तक तक कैद रक्खा जाये जबतक कि दिवालेकी दरखास्तकी समात (सुनवाई) न हो लेंव या वह जमानत आदि उन मुनासिब शर्तों पर छोड़ दिया जावे जो उचित व आवश्यक प्रतीत हों ।

परन्तु बलाज (२) व (३) के अनुसार अदालत उस समय तक हुक्म न देगी जब तक कि उसको यकीन न होजावे कि कर्जदार अपने कर्जस्वाहोंकी वस्तुओंमें देर करने या उनके कर्जोंको मानेकी इच्छासे या अदालतके सम्मन न तामील होने देनेकी इच्छासे:—

(i) अदालतकी अधिकार सीमामें छिप गया है या भाग गया है या छिपने या भागने वाला है या बाहर बना हुआ है, या

(ii) उसने ऐसे कार्रगर्जोंको जो समात मुकद्दमेमें कर्जस्वाहोंके लिये फायदेमंद साबित होंगे छिपा दिया है, या बरबाद कर दिया है या दूसरेको दे दिया है या अधिकार सीमासे हटा दिया है या छिपाने वाला है, या बरबाद करने वाला है या दूसरेको देने वाला है या सीमासे हटाने वाला है, या ऊपर बताई हुई चीजोंको छेड़ कर अपनी कोई जायदाद इस प्रकार हटायी हो ।

ब्याख्या—

इस दफ्तेमें अदालतकी वह अधिकार दिये गये हैं जिनका प्रयोग वह दिवालिघा करार दिये जानेका हुक्म देनेसे पहिले कर सकती है इन अधिकारोंका प्रयोग चाहे दारखास्त कर्जदार द्वारा दीगई हो चाहे कर्जस्वाह द्वारा दोनों दशाओंमें किया जासकता है । अदालत स्वयंही या किसी कर्जस्वाहके दरखास्त देने पर इस दफ्तेमें बतलये हुए अधिकारोंका प्रयोग कर सकती है । इस दफ्तेमें बतलये हुए अधिकारोंका प्रयोग करनेमें दरखास्तके सुन जानमें सुविधा रहेगी तथा कर्जदार कार्रवाईमें लगबग या बाधा नहीं डाल सकग और कर्जदारकी हाजिरीया इत्यादि कठिनाई होवेकेगो वशाकि या तो उसे हाजिरके लिये जमानत देनी पड़ेगी या फिर वह दावाभी जेलमें बंद रक्खा जानकेगो जैसी आवश्यकता समकानूनान समझी जावेगी ।

इस दफ्तेमें बतलये हुए अधिकारोंका प्रयोग या तो न्यायपालिका सिद्ध जाने समकानूनान सिद्ध हो । अदालतको छिप सम्पत्ति मांगी जावेगी या उसके बाद दिवालिघा करार दिय जानेका हुक्म दिये जानेका पावुल प्रयोग किया जावेगा ।

दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म देदिये जानेके बाद इस दफ्तेमें बतलये हुए नियमोंका प्रयोग नहीं हो सकता है क्योंकि उसके बाद यदि आवश्यकता सम्पन्ना जावे तो दफा ३२ के नियमोंका प्रयोग किया जासकता है ।

क्लाज (१) चर्चिण जमानतकी निर्णय अदालतकी करना चाहिये अर्थात् अदालत वाकियातकी समझकर तथा विचार कर जो जमानत देना निश्चित करे वहीं उचित जमानत स्मरणा चाहिये परन्तु जमानत बहुत अधिक भी न होना चाहिये कि जिसका प्रमथ दिवालिया करही न सके व उसे जेलहीमें रहनेके लिये बाध्य होना पड़े । जमानत लेनेका अभिप्राय यह है कि उसे शक्ति होनेके लिये बाध्य होना पड़े यह अभिप्राय हीमें न नहीं है कि उस जमानतके हुक्मसे दिवालियेको परेशान किया जावे ।

क्लाज (२) इस कालमें दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म दिये जानेसे पहिले दिवालियेकी जायदाद कुर्क किये जानेका उद्देश है । इस दफ्तेके अनुसार कुर्कका जो हुक्म दिया जावे वह खासतः दीवानोंमें दिये हुए नियमोंके अनुसार दिया जाना चाहिये देखो—इरमनकीनी नयाम भगवानदास 36 All 65

जिस जायदादकी कुर्कका हुक्म दिया जावे वह जायदाद बर्जदारके कब्जे या उसकी हुक्मनमें होना चाहिये ।

जिन चीजोंकी कुर्क जावता दीवानों या अन्य किसी प्रचलित एक्टके अनुसार नहीं की जासकती है उन चीजोंकी कुर्क इस एक्टके अनुसार भी नहीं कीजानेका केवल हिसाब कितानकी रीतिसे इस एक्टके अनुसार कुर्कका जासकता है गो यह किताने जावता दीवानोंके अनुसार कुर्क नहीं की जाना चाहिये जैसा कि जानना दीवानोंकी दफा ६० में दिया हुआ है ।

प्राबोउथ फाउ बर्जेलवाइके मामले पर कुर्क नहीं किया जासकता है इसी प्रकार न तो रिसीवर न कोर्ट बर्जेलवाइकी दिवालियाके रेलवे प्राक्टीश्ट फाउकी कुर्क करा सकता है देखो—56 Ind Cas 450, 24 C W N. 288.

क्लाज (३) इस कालके अनुसार अदालतकी अधिरार प्राप्त है कि वह स्वयंही या किसी कमलावाइके दरवास्त होने पर दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म देनेसे पहिलेही बर्जदारकी गिरफ्तार कराने व उसकी कैद करके साथही साथ अदालतकी यहभी अधिकार प्राप्त है कि वह बाद गिरफ्तारी जमानत लेकर बर्जदारकी छोड़नी देवे अर्थात् जमानतका अभिप्राय यह है कि यदि बर्जदारकी उपरिपनि इच्छाश्रितकी दरवास्त सुनी जाते समय आवश्यक समझ पड़े या यदि उसकी जायदाद पर अधिकार करने आदिके लिये उसकी मददकी आवश्यकता प्रतीत हो और साथही साथ यह भी जान पड़े कि वह बर्जदार इस प्रकार उपरिगत न होगा या वह इस प्रकारकी सहायता प्रदान करनेसे हटगा तो अदालत अपने इस ज्ञानमें दिये हुए अधिकारका प्रयोग कर सकती है तथा वह निश्चित है। जाने पर कि वह उचित समय या खरमर पर हजरि होनेसे नहीं हटगा उसे छोड़नी सक्ती है हाजिरकी किये कचिन जमानत लेने का अदालतकी ऐसा विश्वास हो सकता है । परन्तु अदालतकी ऐसी गिरफ्तारीका हुक्म बहुत सोच समझ कर देना चाहिये जैसा कि एक्टके नियमोंसे प्रकट होता है क्योंकि बर्जदार को ऐसे हुक्मसे बड़ा गड़ पहुँचनेकी आशंका है ।

दफा २२ कर्जदारके कर्तव्य

जब कि दिवालेकी दरवास्त लिये जानेका हुक्म हो जाये तब कर्जदारको हिसाबकी सब कितानें पेश करना पड़ेगी और उसके बाद कितीभी समय अपनी जायदादकी फहरिस्त देना पड़ेगी व अपने कर्जदारोंको व उनके कर्जोंकी तादाद तथा अपने कर्जदारों व उनसे लिये जाने वाले कर्जोंकी तफसील भी देना पड़ेगी और अपनी जायदाद या कर्जदारोंके धारमें जांच करना पड़ेगी और अदालत या रिसीवरके सामने हाजिर होना पड़ेगा वस्तावेज लिखना पड़ेगी और अधिकतर वह सब काम व याते अपनी जायदादके सम्बन्धमें करना पड़ेगी जो अदालत या रिसीवर नियमके अनुसार उससे कराना चाहेंगा ।

व्याख्या—

इस दफा में कर्जदारके कुछ कर्न योंका नश्वन है और इन कर्न-योंका अधिकतर सम्बन्ध अदालतके साथ है अर्थात् यदि इस दफा में बतलाये हुए नियमोंका अनुसार दिवालिया क्रम न करे ता उमरा यह क्रम अदालतके विरुद्ध समझना चाहिये न कि किसी कर्जालाके देखा—54 I C 740.

इस दफा में बतलाये हुए कर्तव्योंका न करना एक प्रमाणसे अदालतके निर्धारित नियमोंके विरुद्ध काम करना समझना चाहिये किन्तु उसे कोई कौनदायीन जुर्म न मानना चाहिये, देखो—39 All 171

हिसाबकी किताबें दरखास्त दिवालियाके लिये जते समय दाखिल करदी जाना चाहिये तथा उसके पश्चात् कर्ज-हवाहोंकी केहरिल कर्जोंकी तादाद व उनका व्योरा आदि भी दाखिल करना आवश्यक है परन्तु यह बात दरखास्त लिये जानेके बाद भा किसी समय दाखिल की जासकती है चूँकि बिना हिसाब किताबके देख कर्जों आदिके बारेमें पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता है इस कारण उनका दाखिल होना प्राग्भवीने अनिवार्य समझा गया है परन्तु इस बात किताबें दाखिल हो जानेकीसे काम नहीं चलेगा कर्जदारको उसका पश्चात् अपनी जायदादकी तफ्तील कर्जोंकी केहरिल तथा उनका व्योरा आदि भी दाखिल करना पड़ेगा अर्थात् अपने कर्तव्योंकी तथा कर्जदारोंके नाम व उनसे सम्बन्ध किया जाने वाला या उनको दिया जाने वाला कर्ज तथा उससे सम्बन्ध रखनेवाली जानने योग्य सब बातोंका व्योरा दाखिल करना आवश्यक है ।

किताबों व कर्जों आदिका व्यास दाखिल होजानके बाद भी अदालत या रिसीवर जब चाहे कर्जदारको हिसाब समझनेके लिये तथा कर्जों आदि की असली हालत जाननेके लिये बुला सकता है और उस समय कर्जदारका कर्तव्य होगा कि वह अदालतकी व रिसीवरकी उन सब बातोंके समझनेमें सहायता प्रदान करे तथा उन सब बातोंका उत्तर दे जो उससे पूछा जावे या उन सब बातोंको कर जो अदालत या रिसीवर उस सम्बन्धमें उससे कराया चाहे ।

अदालत दिवालियाको अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति को २०० गीन्स अधिक फायनेसे भी उसकी जायदाद आदिके सम्बन्धमें जाच करनेके लिये बुला सकती है देखो—13 Bom 114, 39 Bom 462

इस दफाके अनुसार कर्तव्य करानेके लिये अदालत दिवालिया या रिसीवर कर्जदारको बाध्य कर सकता है । यदि रिसीवरकी नियुक्ति दरखास्त लिये जाते समय होजावे तो कर्जदारका कर्तव्य होगा कि वह रिसीवरने मिले व रिसीवरको तब चाहिये कि उससे जानने योग्य सब बातोंकी केहरिल दाखिल करले तथा कर्जदारने अपनीभी वह सब बातें समझते जिनका समझना आवश्यक प्रतीत हो । अदालत या रिसीवर जब चाहे इस दफा में बतलाये हुए कर्तव्योंके पालनके लिये कर्जदारको बुला सकते हैं यह आवश्यक नहीं है कि कर्जदार डिलित आता दाराही बुलाया जावे । देखो—बुगमल बनाम आदिलाल एसाहानी 47 Cal. 56

इस दफा में बतलाये हुए नियमोंका पालन न करने पर कर्जदार दण्डका भागी होगा यदि जानबूझ कर कर्जदार नियमोंका पालन न करेगा तो उसे दफा ६९ के अनुसार दण्ड दिया जासकता गिमेके अनुसार एक वर्ष कागवास तकका दण्ड दिया जासकता है ।

दफा २३ कर्जदारकी रिहाई (छुटकारा)

(१) जबकि कर्जदार किसी इजराय डिक्लीमें रपयेंकी घमेलीके लिये जेल या हिरासतमें होवे तो अदालतको अधिकार है कि दिवालीकी दरखास्तके लिये जानेका हुक्म देते समय या उसके बाद दिवालिया क्रम देनसे पहिले कर्जदारको जमानत आदिकी शर्तों पर जो उसे उचित व आवश्यक प्रतीतहो छोड़ देवे ।

(२) अदालतको अधिकार है कि वह किसी ऐसे व्यक्तिको जिसे उसने इस दफाके अनुसार छोड़नेकी आज्ञा दी है उसे फिर गिरफ्तार करवा लेवे या फिर उसे हिरासतमें भेजदे जहाँसे वह मुक्त किया गया था ।

(३) इस दफाके अनुसार हुक्म देते समय अदालत अपने हुक्म देनेका कारण लिख कर बतलावेगी ।

व्याख्या—

इस दफा द्वारा अदालत दिवालियाको अधिकार प्राप्त है कि वह दिवालिया कथार दिये जानेका हुक्म दिये जानेसे पहिलेही कर्जदारको जेल या हिरासतसे मुक्त कर सके यदि वह कर्जदार किसी रुपयेके बसूलीकी डिक्तीके आधार पर गिरफ्तार किया गया हो । इस अधिकारका प्रयोग करना न करना अदालतके हाथमें है परन्तु जिस समय अदालत कर्जदारको जेल या हिरासतसे जमानत लेवामी घोषितसे इन्कार करे तो उसे वह कारण लिखकर देखलाना पड़ेगा कि मिनरी बजहसे वह कर्जदार का छोड़ा जाना उचित नहीं समझती है । देखो—A. I. R. 1924 Pat. 559.

कर्जदारको छुटकारा केवल रुपये बसूलीकी डिक्तीसेही मिल सकता है वह डिक्ती चाहे जिस अदालत द्वारा दी गई हो परन्तु छोड़े जानेका हुक्म देनेसे पहिले अदालत उचित जमानत कर्जदारसे लेवारी है । अदालत दिवालियाका इस दफाके अनुसार हुक्म बतौ दशमें होवेगा जब कि कर्जदार गिरफ्तारीकी हालतमें होवे अर्थात् या तो वह दीवानीकी जेलमें होवे या हिरासतमें लिया जा चुका हो । इस दफाके अनुसार हुक्म जहाँ कर्जोके सम्बन्धमें दिया जावेगा ओ इस एक्टके अनुसार सावित किये जानावते है । देखो—होराणाज बनाम तुलसीधाम 80 L. C. 946

इस दफाके कलाज (१) में अदालतको यहमी अधिकार दिया गया है कि वह कर्जदारको जेल या हिरासतसे मुक्त करनेका हुक्म देनेके पश्चात् उसे जब चाहे फिरसे गिरफ्तार करवावे परन्तु अदालत ऐसा हुक्म किसी विशेष कारणके उपस्थित होनेवाले पर देवेगी इस कलाजकी भाषासे यहमी प्रकट है कि अदालत दिवालिया कथार देनेके पश्चात् भी कर्जदारको गिरफ्तारका हुक्म दे सकती है परन्तु वह दिवालियाके बहाल हो जानेके बाद इस प्रकारकी गिरफ्तारीका हुक्म नहीं देवेगी क्योंकि यह बात न तो इस दफाकी भाषातः प्रकट होती है न एक्टमें और किसी जगहही इस प्रकारका उल्लेख मिलता है । बहाल होानेके बाद यदि दिवालियेकी कोई अनुचित कार्रवाई सावित होतो दफा २६ के अनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाईकी जासकती है ।

कलाज (२) के अनुसार अदालत बाध्य है कि वह कलाज (१) या (२) के अनुसार हुक्म देते समय उन कारणोंके सहित वह अपने हुक्मको लिखे ।

दफा २४ दरख्वास्तके सुनेजानेका तरीका

(१) दरख्वास्तको सुननेके लिये नियतकी हुई तारीख पर या उसके बाद यद्वारहूई तारीख पर अदालत नीचे दी हुई बातोंका सुवृत्त लेवेगी :—

(५) यह कि कर्जद्वारा या कर्जदारको जिसने दरख्वास्त दी हो दरख्वास्त देनेका हक है या नहीं परन्तु जबकि कर्जदार दरख्वास्त देने वाला व्यक्ति है तो वह इस बातको सावित करनेके लिये कि वह अपने कर्जोंको अदा करनेके योग्य नहीं है केवल उतनीही शहादत देगा कि जिसमें अदालतको यकीन होजावे जाहिरा तौर पर कर्जदारका कहना ठीक है और अदालतको जब यह यकीन हो जावे तो वह इस बातके लिये और शहादत लेनेके लिये बाध्य नहीं है ।

(बी) जबकि कर्जद्वारा दस्तखस्त देने पर कर्जदार हाजिर नहीं हो, तो यह साबित होना चाहिये कि उसके पास दस्तखस्तके लेलिये आनेके हुक्मका नोटिस पहुँच चुका है।

(सी) यह कि कर्जदारने दिवालिका काम किया है जिसका करना उसके लिये बताया जाता है।

(२) अगर कर्जदार हाजिर होवे तो अदालत उसका भी बयान उसके धर्तावे, व्यवहार व जायदादके सम्बन्धमें उन कर्जद्वाराओंके सामने लेंगी जो उस पेशी पर मौजूद हों और कर्जद्वाराओंकी भी अधिकार होगा कि वह कर्जदारसे उन बातोंके सम्बन्धमें प्रश्न कर सकें।

(३) अगर पर्याप्त कारण दिखलाया जावे तो अदालतको अधिकार होगा कि वह कर्जदारया किसी कर्जद्वाराको उस शहादतको देनेके लिये अपसर देवे जो उसकी रायमें दस्तखस्तका ठीक २ फौसला निर्णय करनेके लिये आवश्यक प्रतीत हो।

(४) कर्जदारके बयानों तथा दूसरी जयानी शहादतके सारका लेखा अदालत रक्खेगी और वह लेखा मुकद्दमेकी कार्रवाईका भाग समझा जायगा।

व्याख्या—

इस दफा में उन नियमोंका वर्णन है जिनका प्रयोग दिवालियारी दस्तखाल सुने जाने समय किया जाना चाहिये चाहे वह दस्तखाल कर्जदारने दी हो या वह दस्तखाल उसने किसी कर्जद्वाराहें दिला दी गई हो इस दफा में यह भी बतलाया गया है कि किस प्रकारका सुवृत्त दस्तखालकी गामिन करनेके लिये आवश्यक है। सबसे पहिले अदालत यह देखेगी कि आया दस्तखाल देने वाले कर्जदार या कर्जद्वाराको दस्तखाल दिवालिया पेश करना इक है या नहीं यदि दस्तखाल देने वाला कर्जदार है तो उसका इक दस्तखाल दिवालिया देनेवाला वह समय जल्दा जावेगा जबकि वह अपने कर्जोंकी अदा न कर सकता हो तथा उसके साथ साथ या तो उसने कर्जोंकी तादाद ५०० से अधिक हो या वह किसी रूपके वस्तुओंकी धिकीके सम्बन्धमें गिरफ्तार किया गया हो या उसकी जायदाद कुल्फी गई हो। कर्जदारको यह बात साबित करके लिये कि वह अपने कर्जोंकी अदा नहीं कर सकता है केवल इतनाही सुवृत्त देना पड़ेगा जिससे अदालतको यह विश्वास हो जावे कि वह प्रकट रूपमें कर्जें अदा नहीं कर सकता है अदालत इससे अधिक सुवृत्त इस बातके साबित करनेके लिये सुननेको बाध्य नहीं है।

फगनु यदि दस्तखाल देने वाला कोई कर्जद्वाराहें तो उसका इक दस्तखाल दिवालिया पेश करनेका वह समय समझा जावेगा जबकि वह साबित करे कि कर्जदारने वह दिवालियेका काम किया है जिसका उल्लेख दस्तखालतम किया गया हो तथा कर्जोंकी तादाद ५०० से अधिक हो और जिन कर्जोंका उल्लेख दस्तखालतम में है वह वस्तु लिये जासकते हैं साथही साथ वही दस्तखालतका नोटिसभी कर्जदार पर नियम पूर्वक तामील हो जाना चाहिये। उपर बताई हुई बातोंका वर्णन उपदफा (१) में किया गया है।

उपदफा (२) में यह बतलाया गया है कि यदि दस्तखाल दिवालिया सुने जावे समय कर्जदार मौजूद हो तो अदालतका तर्क्य है कि वह कर्जदारका बयान अवश्य लेवे और कर्जदारका इस प्रकार बयान देने समय उसके कर्जद्वाराओंको इक है कि वह उससे निगद कर सकें अर्थात् दस्तखाल चाहे कर्जदार द्वाराही गई हो या उसके किसी कर्जद्वाराहें दिया हो अदालत दोनों दशाओंमें कर्जदारके मौजूद होने पर उसके बयान अवश्य लेवेगी तथा कर्जद्वाराओंकी भी कर्जदारमें प्रश्न करनेका अधिकार इसी प्रकार प्राप्त है कर्जदारका बयान अवश्य होना चाहिये चाहे उस समय और किसी गवाहोंके बयान लिये जावे या न लिये जावे देतो—बनारसी बनाप बनारसी 9. A. L. J. 239; A. I. R. 1926 Lah. 508.

इस दफा में बतलाये हुए नियम ऐसे नहीं हैं कि जितनी अवहेलना की जा सके अर्थात् उनके अनुसार अदालत कार्य करने की बाध है इसलिये कर्जदार की उपस्थिति में उसका बयान लिये बिना यदि कोई हुक्म दे दिया जावे तो वह हुक्म ठीक नहीं समझा जावेगा देखो—39 I C 745, A I R. 1927 Cal 32.

कर्जदार का इस प्रकार जो आग्रह बयान लिया जावेगा वह केवल उसकी दिलछाप प्रयोग किया जा सकेगा किसी दूसरे के खिलाफ नहीं प्रयोग किया जावेगा। इस प्रकारका बयान लिये जाने का तात्पर्य यह है कि जितनी जल्दी हो सके कर्जदार की सब जायदाद ग्राह्य हो सके तथा वह भी मालूम हो सके कि कर्जदार ने अपनी जायदाद के सम्बन्ध में क्या काम किये हैं जिससे कि कर्जदार या रिश्तेदार दिवालिया की सब जायदाद का ठीक पता पार्कर उसे समेट सके तथा बहाल होने की दारखास्त पेश होते समय भी कर्जदार इस प्रकार की बातों को जानकर उसकी बहाल की दारखास्त में विरोध कर सके हैं। देखो—गिरधारी बनाम जयनारायण 32 All. 645.

उपदफा (३) में पर्याप्त कारणसे तात्पर्य उन कारणों से समझना चाहिये जो जायदाद की बानगी के आर्डर (XVII) १० क्ल १ के अनुसार पर्याप्त कारण माने जा सकते हैं। शहादत खवानी या लिखित दोनोही से तात्पर्य है तथा दोनों ही के देने के लिये मौका दिया जा सकता है। गवाहान व सुदूत के कायनात उसी प्रकार तलब किये जा सकते हैं जिस प्रकार जायदाद की बानगी के अनुसार तलब किये जा सकते हैं।

[- उपदफा (४) में शहादत लिये जाने का उद्देश्य है शहादत उस प्रकार खींचने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि दीवानगी, अदालतों में लांगामी है इसमें उस प्रकार खींचा जा सकता है जैसा कि सरसी या रॉबर्ट करने में खींचा जा सके पारलु जो शहादत खींचने की उसको लिखा जाना चाहिये तथा उसकी जसदी सब बतों अदालत की नोट कर लेना चाहिये वह अदालत की मिसिल में शामिल रहेंगे।]

यदि कर्जदार के लहने का मूल्य कर्ज से अधिक हो तो कर्जदार इस बिना पर यह नहीं कह सकता है कि कर्जदार अपने कर्ज को चुकाने में असमर्थ नहीं था देखो—हरनाम सिंह बनाम गोपालदास देसराज 109 I C 370, यदि अदालत किसी कर्जदार की दारखास्त इस बिना पर खारिज कर देवे कि उसे दारखास्त देने का कोई हक नहीं था तो अदालत का यह हुक्म और कर्जदार के खिलाफ अग्र तन्वीज शुदा (Resjudicata) नहीं समझा जावेगा। केवल इनके पास कोटि पट्टे जावेगी यह नहीं मान लिया जावेगा कि वह हर मानके लिये कर्ज का हुक्म बना लिये गये हैं। देखो—110 I. C 730 (2)=A I R 1928 Sindh. 121.

यदि दिवालिये का दारखास्त किसी कर्जदार ने दी हो तो दिवालिया करार देने का हुक्म देने समय अदालत के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह पूर्ण रूप से दारखास्त में दिलाये हुए कर्ज की जानकारी करे या उन बातों की खोज कर जिससे कर्जदार का जायदाद ठीकाना या धीरे धीरे जायदाद का हटाया जाना साबित हो। ऐसी बातों की जानकारी दिवालिया करार दिये जाने के बाद तथा उस समय की जाना चाहिये जबकि दिवालिये की जायदाद रिश्तेदार या अदालत से सुपरी में आ जावे। देखो—109 I. C. 552.

दिवालिये करार देने की दारखास्त पर विचार करते समय अदालत की चाहिये कि वह जायदाद की मौजूदा कीमत का जिससे कि उसके कर्ज चुकाये जावेगे या वह रखे तथा यह देवे कि आधा दफा २४ (९) का ध्यान रखते हुए कर्जदार ने अपने कर्ज को न अदा कर सकने की बात साबित कर दी है या नहीं देखो—A. I. R 1928 Nag. 226.

कर्ज न अदा कर सकने की बात साबित करने के लिये यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि कर्जदार का लहना उसके कर्जों के कम है क्योंकि यदि कर्जदार अदालत को निश्चास दिल दे कि गो उसका लहना उसके कर्जों के कम नहीं है किन्तु वह अपने कर्जों को चुकाने के लिये अपनी सब जायदाद प्रयत्न कर देने पर भी असमर्थ है तो अदालत को यह मानना

चाहिये कि वह कर्जदार अपने कर्जों में चुसमोंमें असमर्थ है। देखो—109 I C 552=A I R 1929 Lah. 87. इसी मामलेमें यह भी तय हुआ था कि दिवालयियों द्वारा दख्खान देने वाले कर्जदारों का कर्तव्य है कि वह अदालतोंके सामने पेश हो तथा उपरिष्ठ कर्जदारोंसे उनके प्रभु करने पर अपनी जायदाद तथा बर्जों आदिसे वारमें पूरा हाल बतलाव। यदि कोई कर्जदार यह बयान करे कि वह कर्जों अदा नही कर सकता है तथा यदि उसका जायदादमें तत्काल रुपया वसूल नहीं होसकता है तो कर्जदारका यह कदम कि वह अपने कर्जोंमें अदा नहीं कर सकता है अवश्य ठीक मान लेना चाहिये जबतक कि यह सचिज न हो जाये कि उसके सब बर्जों कर्जों हैं या उसने कित्ता दूध हा उदरमें दिवालेह दख्खान दी है तबल इस बातसे कि कर्जदारके पास बहुतसी जायदाद है यह न समझ लेना चाहिये कि वह अपने कर्जोंमें अदा कर सकता है। A I R. 1928 Mad 1193.

दफा २५ दरखास्तका खारिज होना

(१) जबकि दिवालयी दरखास्त कर्जतबाह द्वारा की गई हो और अदालतका यह यकीन न हो कि उसे दरखास्त देनेका हक है या इस बातका यकीन न हो कि दरखास्तके लिये जानके हुक्मका नोटिस कर्जदारको पहुँच गया है या बलाये हुए दिवालयके कामका यकीन न हो या कर्जदार इस बातका यकीन दिला देय कि वह अपने कर्जोंको अदा कर सकता है या किसी दूसरे मुनामिय कारणसे यह स्वयम्में आवे कि कोई हुक्म न दिया जाना चाहिये तो अदालत दरखास्तको खारिज कर देगी।

(२) जबकि दरखास्त दिवाला कर्जदारने दी हो और अदालतको यह यकीन न होय कि कर्जदारको दरखास्त देनेका हक है तो वह उस दरखास्तको खारिज कर देगी।

व्याख्या—

इस दफामें उन मामोंका उल्लेख है जिनसे कारण दरखास्त दिवाला खारिजका शक्तता है यह दफा २५ में स्पष्ट बनाई गई है निम्न कि कर्जदार अपने कर्जोंमें बचने या गिरफ्तारसे बचनेका चाहते दरखास्त दिवाला देकर बना क्रायदा न उठा सके देखो—A I R. 1924 All 800

इस दफाके आधार पर दरखास्त खारिज की जाने पर बारी अर्जी हाईकोर्टमें की जासकती है देखिये दफा ७५ (१) गेकि दफा २५ के अनुसार कर्जदारका जाना होते समय उसमें उसकी जायदाद आदिसे सम्बन्ध पश्न निय माममें है परन्तु फिर भी दफा २५ में यह नहीं बतलाया गया है कि यदि कर्जदारकी बदनामी स्पष्टिज्ञ हो तो वह दिवालयी कारण नहीं दिया जाना चाहिये जर्थात् बदनामी अधिक कारण कर्जदार दिवालयी बननेमें नही रोका जासकता है किन्तु बहाल हानेरी दरखास्त देने समय उसकी बदनामी आदि प्रश्न स्पष्टता निर्या जासकता है और उनमें लाभ उठ पा जासकता है। दला—गिरवारगी बनाम जनगणन 32 All 40, 60 I C 848

इसी प्रकार यह भी तय हुआ है कि इन दफा २५ अनुसार तदर्थकित करने समय इस प्रश्नका तय करनेकी आवश्यकता नहीं है कि कर्जदारने अपनी राय जायदाद ठीक ठीक दित्याह है या न। इस प्रश्नका प्रत्यक्ष निर्याह देकर दिने जानका हुक्म दिये जानेपर बाद तय किया जासकता है देखो—46 Bom 107. दिवालयी जानका प्रश्न उस वक्त उत्पन्न होता है जब कि बहाल होनेरी दरखास्त देने उसमें पहिले नहीं दाखे—A I R. 1926 Mad 494.

इन बातोंसे यह न समझ लेना चाहिये कि गुप्तमें रजिस्ट्रारने उसकी नकल चलि सधायमें कोई प्रसही नहीं पूछे जासकते है गो इन प्रस्तावों निगणय शुल्क नही दिया जाना चाहिये किन्तु कि भी ऐसे प्रश्न उत्पन्न जासकते हैं तब

पुढावा चाहिये जिसमें जल्दीमें जल्दी कर्जदारके सम्बन्धी ठीक बातों का पता लग सके तथा अधिकतर उनमें उचित लाभ उठाया जा सके । देखो—36 Mad 402.

जिस या दायित्वगत दिवाल्यके खातिर करनेसे यदि अत्यन्त कम कर्जदारों के बिना काम-काज पूर्ण रूपसे सम्पन्न हो जायित्त तब तथा दायित्वगत खातिर करनेके कारणों को अपने हकमें दिवंगत इलाहाबाद हाईकोर्टने एक्टिंग चाफ जस्टिस (Acting Chief Justice) वाश (J Walsh) गृहस्था कल्याण था कि यह दफा उन जजों के लिए जो मापदंडों में सम्मिलित प्रथम नहीं करते हैं एक प्रकरण का है देखो—तात्पर्यवान् बनाम सुकुलकिशोर 46 All 71-22 A L J 684.

दरखास्त दिवाला खातिर किये जानेके कारण यह हो सकते हैं:—

(१) उस समय जबकि किसी कर्जदारके दरखास्त हो—

(अ) यदि कर्जदारको दिवाल्यके दरखास्त देने का एक दफा २ के अनुसार प्राप्त न हो

(आ) यदि कर्जदार या दिवाल्यके दरखास्त शुनस्तक नोटिसमें शामिल न हुई हो

(ई) यदि दरखास्तमें दिवाल्यका हुआ कर्जदारके दिवाल्यके नाम साबित न होवे

(ए) यदि कर्जदार यह साबित करे कि वह अपने कर्जोंसे ज्यादा कर सकता है

(ई) यदि दरखास्त नाममात्र करने के लिये पर्याप्त कारण हों ।

(२) उस समय जबकि कर्जदारने स्वयं दिवाल्यके दरखास्त या हो—

(ए) यदि कर्जदारका दफा २० के अनुसार दरखास्त देने का एक पास न हो जेबल कर्जदारकी इस बिना पर एक सक्ता है कि वह अपने कर्जों का चुकानेमें असमर्थ नहीं है दूसरे कोई व्यक्ति इस बिना पर नहीं लक्ष्य करता है जसे कि यदि कर्जदारने जिसके हकमें जापनाद कर या हा हा विसक हकमें जापनाद करेगा वह के बड़े इस बात पर महा लक्ष्य करता है कि कर्जदार दिवाल्यका दायित्व दिने जाने समय अपने कर्जों का चुका सकता था । तथा—A. I. R 1929 Lah. 79

यदि दरखास्त कर्जदार उद्योग या कोई हो तो भी वह इस बिना पर खरिदनी जा सकती है कि कर्जदार अपने कर्जोंको अदा कर सकता है अथवा नहीं । अर्थात् कर्जदार द्वारा दी हुई दरखास्त पर यह मानने हाने पर कि वह अपने कर्जोंका अदा कर सकता है यह आवश्यक नहीं है कि दरखास्त दाता बिना पर खातिर करता जावे देखो—मिथुना बनाम कल्याण 32 All 647, 41 I C. 850, 73 I C 74

जिसका कारण यह जायदा है कि कर्जदारका दरखास्त कबल हमारा बिना पर खरिदनी जा सकती है कि हमारे दरखास्त दिवाल्यके नाम पर या एक पास न हो कि कर्जदारके दरखास्त दिवाल्यके नाम पर कबल दफा १० में है और यदि दफा २० में कर्जदार हुए निम्नोका पात्रन पूर्ण रूपसे महा होता है तो कर्जदारकी दरखास्त दिवाल्यका खातिरकी जा सकती है । परन्तु यदि दफा २० में कर्जदार हुए निम्नोका पात्रन पूर्ण रूपसे हुआ है तो दरखास्त दिवाल्यका अवश्य मजबूत की जाना चाहिये । अतः करने के निम्नोके नाम कायदा खानेकी बिना पर दरखास्त दिवाल्यके खातिर किये जाने का उचित दाय दफा नहीं है ।

इस दफाके हाईकोर्टने बहुतों महा निमित्तन किया था कि यदि दरखास्त अदा करने के निम्नोका बिना कायदा उद्योगी मगान दी गई हो तो एसा दरखास्तका अदागत इस बिना पर खातिर कर सकता है परन्तु 44 Cal. 535 में किसी कायदागत उद्योगी मगान यह दफा का दिया है कि दरखास्त कबल इस बिना पर खातिर महा कर देना चाहिये कि नस

अदालत नियमों में वेना कायदा जमाने की सरतसे दायर है यदि इस एकमें बतलाये हुए सब नियमों का पालन किया गया हो। कर्जदार की दरखास्त दिखला इस बात पर खारिज नहीं कानूनी कि उसने अपनी दरखास्तमें कुछ गणनादकी जमाया है या अपना जामदारूत वसमें चालत धार दिया है या अपने कर्जों का ठरक २ व्याय नष्ट दिया है दूतों—आपन बनाम साइनल 8 I C 1115; 38 I C, 822.

इसी प्रकार यदि कर्जदार बाकायदा दिमाक किया नहीं रखा हो तो इसका बिना पर उसकी दरखास्त दिखाना नाममात्र नहीं की जा सकती है देखो—A I R. 1927 Lah 27 दरखास्त इस बिना या भी खारिज नहीं की जा सकती है कि कर्जदार व कर्जदार का गाई मुअरता है और वह भारी शामक दरखास्त नहीं किया गया है दूतों—40 All 75 दिवालिया दरखास्त इस बात पर खारिज नहीं कानून धारिय कि कर्जदारने बददीयता का फाय लिया है तथा वसने पोषादहीत जामदारूत अन्ध कर दिया है दूता—12 C L J 400, 40 All 665

दरखास्त दिखाना इस बात पर भी खारिज नहीं की जा सकती है कि कर्जदारने दरखास्त दूते के बाद तथा उसके सुने जानेसे पहिल किमी कर्जदारको रुपय की अग्रगणी की है देखो—तागाचद बनाम उगुलकिओर 46 All. 713 दरखास्त इस बिना पर भी खारिज नहीं की जा सकती है कि कर्जदारने उमम कुछ फल्य कर्म दिये हैं दूता—हुसालास बनाम भगवानदास 26 I C 24, 37 All 252

केवल इस बिना पर कि नज्दत एक नईमान आदमी है उसकी दरखास्त दिखाना खारिज नहीं की जा सकती है गो उसके बहाल होने समय तब बात पर पूर्ण रूपसे तबचार किया जाना चाहिये देता—निरमलाल बनाम अयोध्याप्रसाद 37 I. C 391.

अदालत इस दफामें बतलाये हुए किमी दूतों पर्याप्त कारणों के आधार पर केवल उन्हीं दरखास्तों को खारिज कर सकती है। कर्जदार का दामाद ही है अर्थात् कर्जदार द्वारा दायरे दरखास्तों से ऐतिहासिक दूतों पर्याप्त कारणों के आधार पर खारिज नहीं करेगा दूतों पर्याप्त कारण वह प्रकारके हो सकते हैं जिनका निगम करना अत्यन्तक शक्य है बहाल रूप पर यदि कर्जदार यह दिखलावे कि उसके कुछ निगमण उसके तब कर्जों की पूर्ण रूपसे अग्रगणी प्रयत्न कर दैये ता यह पर्याप्त कारण समझा जा सकती है इस प्रकार कर्जदारका यह सविद करना कि उसके कुछ मापों चल रहे हैं तथा उनके तब जानेने वह अपने सब कर्जों से घुरा रहेगा पर्याप्त कारण समझा जा सकती है देखा—तागाचद बनाम उगुलकिओर 46 All 713

दफा २६ हर्जेका मिलना

(१) जबकि कर्जदार द्वारा दी हुई दरखास्त दफा २५ (१) के अनुसार खारिज हो जाये व अदालतको यह यकीन होजाये कि दरखास्त फिजूल है या पेशान करनेकी गरजसे थी गई थी तो कर्जदारके दरखास्त देनेपर अदालतको अधिकार है कि वह दिवालियों दरखास्त देने वाल कर्जदारहसे (१०००) एक हजार रुपये तक जैसाकि वह मुनासिब समझे वतौर हर्जेक कर्जदारको उसके खर्च मुकदमा व नुकसानके बावत जो उस उस दरखास्त दिवालाके सम्बन्धमें उठाना पड़ा है दिलावे और यह हर्जा बतौर सुमानिक वसूल किया जासकता है।

(२) इस दफाके अनुसार यदि कोई हर्जा दिला दिया जावेता तो उस दरखास्त दिवाला या उसकी कार्यवाहियोंके सम्बन्धमें कोई हर्जेकी नालिश नहीं चलेंगी।

व्याख्या—

(त दफाके अनुसार अदालत दिवालियों अधिकार प्राप्त है कि वह (१०००) एक हजार रुपये तक बतौर हर्जेक

कर्मचारियों को हाथेबांधे जबरन दंड दिया गया। इस आधार पर प्रयोग उस समय होगा जबकि अदालत को विश्वास हो जावे कि दरबारत घुटा है तथा कर्मचारियों को जबरन काम कराया गया हो। ऐसे कर्मचारियों को अदालत के अधिकारों से तथा इस दफ्तर में दिए हुए नियमों से लाभ उठाने पर बन्धन जर्जर कर दिया जायेगा। अदालत में इनका दावा कर्मचारियों के विरुद्ध नहीं कर सकता है।

इस दफ्तर में प्रयोग कर्मचारियों द्वारा दी हुई दरबारतों के सम्बन्ध में नाच बतगई हुई दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए जाया जायेगा (१) यह कि वह दरबारत दफ्तर २५ (१) के अनुसार जारी कर दी गई हो तथा (२) यह कि वह दरबारत कि दरबारत घुटा है या परेशान करने का मन्थन है यह है अदालत इस दफ्तर में बतगई हुए अधिकारों के प्रयोग को समय से ही जान बूझकर हस्त लिखे दार-दारा देवेगा।

॥॥ दफ्तर में बतगई हुआ इसी कर्मचारियों को उनके स्वयं या उनके मुकदमाने बदले में दिया जायेगा अतः अदालत इनके रूप में निविदा करने समय उन्हें बतगई हुआ कानून से निवारण करने हुए अपनी मुद्रिका अनुसार होने की सम्मति निविदा करेगी। इस प्रकार दिया हुआ इसी बातों को अर्थात् बतगई किया जायेगा अर्थात् या तो उसकी जायदाद कर्म व दीर्घाव तक करके बतगई किया जायेगा या जायदाद दीर्घाव तक अर्थात् अर्थात् बतगई किया जायेगा।

यदि इस दफ्तर में दिये हुए अधिकारों का प्रयोग करके अदालत कर्मचारियों को इसी दफ्तर में तो कि कर्मचारियों को इसी मामले के सम्बन्ध में दफ्तर में दफ्तर में नही कर सकेगा यह बात कर्षण (२) में साफ कही गई है इस दफ्तर में अतः दिये हुए कर्मचारी अपनी दफ्तर में ही आसानी है। देखा—दफ्तर ७५ (१) तथा सूची नं० १ (Schedule 1)

दफ्तर २७ दिवालिये करार दिये जानेका हुक्म

(१) अगर अदालत दरबारत को खारिज नहीं करे तो वह दिवालिया करार देनेका हुक्म देवेगी और उस हुक्म में यह भी बतलावेगी कि दिवालिया कितने समयके अन्दर बहाल होने की दरबारत दे सकेगा।

(२) यदि फाँसी बजह दिखलाई जावे तो अदालत को अधिकार है कि वह बहाल होनेकी दरबारत देनेका समय और बड़ाई और ऐसी वशों से वह इस हुक्म की सूचना जिस प्रकार उचित समझे प्रकाशित करेगी।

व्याख्या—

पिछले एनके अनुसार अदालत को बतगई होनेका दरबारत देने का समय निश्चित करनेकी आवश्यकता नहीं थी न कर्षण (२) में बतगई हुए नियमों के अनुसार उस समय में बतगई होनेका बतगई उद्देश्य था इस प्रकार यह दफ्तर एक प्रकारसे नई बतगई गई है। इस दफ्तर में बतगई गया है कि यदि अदालत दफ्तर २५ के अनुसार किसी दरबारत दिवालिया को खारिज न करे तो उसे कर्मचारियों को अवश्य दिवालिया करार देना पड़ेगा अर्थात् अदालत कर्मचारियों को दिवालिया बतगई के लिए उस समय या यह होगी वह अपनी इच्छा अनुसार इस प्रकार चाहे उस प्रकार बतगई नहीं दे सकेगी।

दिवालिया बतगई देने जानेके हुक्म के साथ वह समय भी बतगई दिया जावेगा जिसके अद दिवालिया, बहाल होनेकी दरबारत दे सकेगी। यदि अदालत कर्मचारियों के सम्मति जाय बतगई दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म होनेके पश्चात् अधिकार होनेका है न विशेष का वही समय होती है जब कि दिवालिया बहाल होने की दरबारत देने इच्छा समझा निश्चित कर दफ्तर अवश्य समझा गया या निर्णय दिवालिया उपाय अद दरबारत बहाल होनेका दे सके और

उसके दायरास्त देने पर उसका कार्याया भली प्रकार जांच होनेसे पश्चात् इस एकमे बन्द्याप- हुए विमोके अनपार कजग-
दण्डा भागी दहाया आसक यदि उसन कोई ऐसा कार्य किया हा । 1- न्जिके लर भी एउ प्रकाशक सुवधा हा गई है
क्योंकि वह भागित समयके अंदर बहान्नी दख्खान देकर अपने विगड हुए पिछल कामने छुटगा पामकता यदि
उसने बन्दोपनामे दख्खान नहीं दी है या उसने कोई अनियमित कार्य नहीं किया है ता अदालत उसे अवश्य बहान्नी
देगा उपदफा (२) के अनुसार बहाल होनेका दायरास्त देनेका समय, अवसर तथा आवश्यकताके अनुसार बहाल भी
पामकता है इस प्रकार समय हुक्ममें वनम्य हुए समयके समाप्त हो जानेसे पश्चात् भी बहाल जासकता है दली—A I
R 1924 Cal 777, A I R 1926 Sind 94, A I R 1929 Nag 11 (१).

समय बहानेकी दख्खान फर्जदार व फर्जदार दोनों हा दे सकत है क्याकि इस दफाके जामनामे यह नहीं बतलाया
गया है कि दख्खान किस दना चहिये । दली—A I R 1928 Lah 82, A I R 1927 Lah.
763 (1); गोपालाम बराम मगनीम (A. I. R 1928 Pat 318) में यह तय हुआ था कि जदामतकर
कर्म्य ह नि बड अपने हुक्ममें बहाल होनेका समय अवश्य दिखता उके । बाद हुक्ममें बतलाय हुए समयके अंदर बहाल
हानेकी दख्खान न दी गई हो तो भी अदालतने उस समय तक आर समय बहा देनका अपिनार है अन तक कि दिवालि या
जगार दिये जानेका हुक्म ममूल न लिया गया हो । हुक्ममें दिये हुए समयक समाप्त हा जानेक पश्चात् दिवालिया करार
देना हुक्म अपन आप ममूल नहीं हो जाता है ।

दिवालिया करार दिये जानेके हुक्मकी अपील हाईकोर्टमें की जासकती है फन्नु यदि उपदफा (२) के अनुसार
समय न बहाया गया हा ता एह हुक्मकी अपील नहीं हा लेनेका देखा—A I R 1926 Oudh 186 तथा 105
M L J 837

दफा २८ दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मका असर

(१) दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मक होजाने पर दिवालिया अपनी शक्ति भर
अपनी जायदादके बसूल होने तथा उसकी कीमत कर्जदारोंमें ठेक सौर पर घटनेमें मदद देगा ।

(२) दिवालिया करार दिये जाने बल हुक्मके होने पर दिवालियेकी सय जायदाद
अशालत या किसी रिलीवरकी जैसा कि आगे दिया हुआ है समझी जावगी और उसके बाद
इस एन्टमें दिये हुए ब्रह्मचरोंका छुंडकर दिवालियेके किसी कर्जदारको किसी ऐसे कर्जेक
सम्बन्धमें जो इस एन्टक अनुसार साबित किया जासकता है दिवालिकी कार्यवाईके दौरानमें
दिवालियेकी जायदादक खिलाफ किसी कार्यवाईके करनेका हक न होगा और बिला अशालत
की आशाके या उसकी शर्तके खिलाफ कोई मुकदमा या दूसरी अशालती कार्यवाई करमेका
हक भी न होगा ।

(३) दफा २८ (२) के लिये घट सय माल दिवालियेका समझा जायेगा तारीखके
दिन जिस पर कि हुक्म दिया गया हो दिवालियेके कज्जे, हुक्मत या निगरानीमें उसने व्यापार
या कारोबारके सिलसिलेमें असली मालिककी रजामन्दी व इजाजतके साथ ऐसी शकलमें हागा
कि लोग उसको उस मालका मालिक समझत हों ।

(४) दिवालिया करार दिय जाने वाले हुक्मके बाद बहाल होनेसे पहिले जो जायदाद

दिवालिया पैदा करेगा या पावेगा वह अदालत या रिसीवरको समझी आवेगी और उस जाय-जानक सम्पत्तिमें दफा २८ (१) के नियम लागू होंगे ।

(५) इस दफाके अनुसार वह सब चीजें 'हिंसाबकी किताबोंको छोड़कर' जो जायता दीवानी या किसी दूसरे प्रचलित कानूनके जरिये कुर्बी व नीलामसे बरी है दिवालियाकी जायदाद नहीं समझी जावेगी ।

(६) यह दफा महफूज कर्जवाहके उन अधिकारोंमें कोई बाधा नहीं डालेगी जो उसे अपनी जमागत वसूल करने या जमागतके लिये और कोई कार्रवाई करनेके लिये प्राप्त हैं और यह उसी प्रकार कार्रवाई कर सकेगा जिस प्रकार वह इस दफाके न होते हुए कर सकता था ।

(७) जिस तारीखको दिवालिया करार दिया जाता है उसी तारीखसे दिवालिया करार देने वाला हुक्मका सम्बन्ध समझा जावेगा और उसी तारीखसे वह कार्यरूपमें परिणित होवेगा ।

व्याख्या—

उपदफा (१) यह उपदफा बिल्कुल नई है इसमें दिवालिया करार दिये जानेके बाद दिवालियाका जो कर्तव्य है वह बतलाया गया है जसा कि दफा २२ में दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म दिये जानेसे पहिले दिवालियाका कर्तव्य बतलाया गया है ।

दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म (Adjudication)—ये अभिप्राय उक्त हुक्ममें है जिसके द्वारा कोई कर्जदार जिसने या तो स्वयं दिवालियापन दम्बजस्त दी है या जिसके विरुद्ध दिवालियापन दावास्त दी गई हो अदालत द्वारा दिवालिया घोषित किया जावे अर्थात् अदालत यह स्वीकार करे कि दरअसल वह कर्जदार कानून अपने कर्तव्यों अदा करनेमें असमर्थ है और ऐसे हुक्मका प्रभाव यह होता है कि वह कर्जदार अपने कर्जोंकी सिमेटरीसे मुक्त हो जाता है तथा उस हुक्मके बाद उसकी सब जायदाद व एहवा अस्तित्व या अदालत द्वारा नियुक्त किये हुए रिसीवरके अधिकारोंमें आनाती है जिसमें कि उसके लहनेकी वसूल करके उसके कर्जोत्पादोंमें हिस्सा रसरीके हिसाबसे बांटा जायने । साथही साथ इस उपदफाके अनुसार दिवालियापन भी यह कर्तव्य बताया गया है कि वह ऐसे हुक्म होनेके बाद अपनी शक्ति भर अपनी जायदादकी बसूनी तथा उसके उचित रूपमें विभाजित होनेमें सहायता प्रदान करे ।

उपदफा (२) इस उपदफामें दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मका जो कानूनी अन्तर पैदा होता है उसका उल्लेख है पहिले सामने यह दिखलाया गया है कि इस हुक्मके बाद क्या २ होवेगा तथा दूसरे सामने यह बतलाया गया है कि क्या २ काम न हो सकेगा । दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म होते ही दिवालियापन सब जायदाद अदालत या अदालत द्वारा नियुक्त किये हुए रिसीवरकी सुपुर्दगीमें संपूर्ण जावेगी और वह जायदाद दिवालियापन के कर्जोत्पादोंमें बांटी जावेगी ।
देखो— A I R. 1922 All 448.

तथा कोई कर्जोत्पाद जिसका कर्ज इस हुक्मके अनुसार स्थापित किया जायकता है अपने कर्जोंके लिये दिवालियापनकी जायदादके विरुद्ध कोई दूसरी कार्रवाई उस समय तक नहीं कर सकेगा जब तक कि वह दिवालियापन गायब समाप्त न हो जावे और न अदालत दिवालियापनकी आज्ञा बिना लिये हुए कोई मुकद्दामों चला सकेगा ।

जबकि कोई फर्म (Firm) दिवालिया करार दी गई हो तो उक्त फर्मका हर एक साझेदार दिवालिया समझना चाहिये और इसी कारण उस फर्मके किसी भी साझेदारके विरुद्ध सिवा अदालत दिवालियापनकी आज्ञाके कोई दावा नहीं किया जासकता है । देखो—100 I C. 112

- चूँकि दिवालियेकी जायदाद दिवालिया करार दिये जाने वाले हुबनके अनुसार रिसीवरके आधिकारमें उस समयसे सम्पत्ती जाती है जबसे कि दिवालिया करार दिये जानेकी दस्तखस्त दी गई हो इसलिये उस जायदादकी अन्तर्गत हानन भी उसी तारीखहोसे सम्पत्ती चाहिये और यदि उस जायदाद पर उस तारीखके बाद कोई बर हो जाने चाहे वह किसी अदालतकी डिक्कान अनुसार पेदा हुआ हो या और किसी प्रकार पेदा हुआ हो तो उसमें पाव नहीं रिसीवर पर नहीं सम्पत्ती जानेकी देवो—A I. R 1928 Loh 738. (A I R 1928 Lah. 258) में यह तय हुआ था कि डिक्कान दिवालिया मददतकी गोपनीयताके लिये इच्छा द्वारा कर्तव्यके उस बत तक नडा कर सकता है जब तक कि वह अज्ञान दिवालिया स्वीकृत न होवे । बिना अदालतकी आज्ञाके दिवालिया करार दिये जानेके बाद दिवालियेके सम्बन्ध मुकदमा नहीं चल सकता है देवो—A I. R 1928 Lah. 28

यदि कोई सयुक्त हिन्दू परिवार गायब करता हो तथा उस परिवारमें एक या इमेने अधिक नाबालिग बच्चों और उस नाबालिगोंका पिता मरजर (कर्ता) न होय तथा उस परिवारके सब बालिग बन्धन मय मेनेजर (कर्ता) के इत्तानिया करार दे दिये गये हों तो सयुक्त परिवारकी जायदादको व्यापार सम्बन्धी कर्तव्यके अन्तर्गत लिये अज्ञान करनेके या अधिकार मेनेजरको प्राप्त है वहा अधिकार रिसीवरको प्राप्त हो जायगे और रिसीवर नाबालिगके हितको ध्यान कर सकता है देवो—55 M. L. J. 721—A. I. R 1929 Mad. 166

यदि अदालत दिवालियाके अनिश्चित किसी दूरमें अदालतमें दिवालियेके विरुद्ध किसी समयके करनेके लिये (Specific performance) बिसय करनका नारा उसन दिवालिया करार दिये जानेसे पहिले किया हो दावा दायर किया गया हो तो उस अदालतको यह तय करनेका अधिकार नहीं है कि दिवालियेने किसी एक कर्तव्यवाहसे दूसरेके मुकामल धाया दक्ष लग पड़नेका प्रयत्न किया है देवो—A I R 1928 Mad 860.

यदि अदालत दफा ४२ के अनुसार दिवालियाको बहाल होनेका हुबन न देवे ता उससे यह नहीं समझा जायेगा कि दिवालियाकी कर्तव्य सम्पत्ती होगई है और बिना अदालतकी आज्ञाके जैसाकि दफा २८ (२) में बतलाया गया है कोई मुकदमा दिवालियेके विरुद्ध दायर न किया जायके देवो—A I R 1928 Rang 109 यदि अदालतकी आज्ञा लिये बिना कोई मुकदमा चलाया गया हो तो वह चल नहीं सकता है देवो—110 I. C 386 (1)

दिवालियेकी दस्तखस्त दिये जानेके पश्चात् दिवालिया अपने किसी कर्तव्यवाहका उचित रूपमें बर्तन जरा नहीं कर सकता है और यदि इस प्रकार कोई कथना दिया गया हो ता उसका कोई प्रभाव रिसीवर पर नहीं होगा देवो—78 I. C 16.

दिवालियेकी जायदाद रिसीवरके अधिकारमें आनेके पश्चात् रिसीवरकी दिवालियेके कर्तव्यों चुका सकता है । यदि दिवालियेने या उसकी तरफसे किसी दूसरे व्यक्तिने कोई कथना रिसीवरके छिपकर कर्तव्यवाहको दिया हो तो यह कर्तव्य विरुद्ध बेकामया है और इस प्रकार जो कथना दिया गया हो वह रिसीवरको बाधित दिया जाना चाहिये परन्तु इसके कि अदालत आपसमें तसकिया (Composition) करनेके इच्छाजन दवे देवो—A I. R. 1926 Mad 1168

यदि दिवालिया किसी कथेवर सम्पत्तीमें साक्षात्कार होवे तो उसके उस कथेवर शराकताके हिसेपा रिमाइन्का अधिकार सम्पत्ती चाहिये देवो—A. I. R. 1924 Mad. 223.

जबकि किसी कर्मके शरीकदारोंमेंसे कुछ दिवालिया करार दे दिये जायें तथा कुछ दिवालिया करार न दिये गये हों तो रिसीवरको यह अधिकार नहीं है कि वह उस कर्म शराकतीके कुल बाल पर अकेले ही कब्जा कर लेवे किन्तु वह दिवालिया न करार दिये हुए शरीकदारोंके साथ बाल शराकतीका धारिक होगा और यदि रिसीवर चाहे तो दिवालिया करार दिये हुए शरीकदारके हिसेपा उस कर्मसे लेसकता है देवो—42 Cal 225 तन्मन्वाह भी इस दफाके अनुसार जायदाद मजान चाहिये देवो—21 I. C 950

अदि किंवा मित्र द्वारा भिन्नाना पिता दिवालिया करार दिया गया हा तो रिमीवर उस परिवारके समुक्त वावायिपि लडतीरी जायदाद पर भा अधिार कर सकता है बतने कि पिताका कण व्यापकार आदके लिये न भिया गया हो देखा—
44 All 319, 47 All 263, A. I. R. 1926 Mad 52.

इसी प्रकार यह भी तय हुआ है कि यदि किसी समुक्त हिंदू परिवारका कोई मन्वर दिवालिया करार दे दिया जावे और उसमें मम १ आयदाद हा उ में उससे लडने व पातोहा भा हक पत्रवता से तो रिमावर उस जायदादसे उमा प्रसार आहूदा कर सकता है। मम प्रसार वह मन्वर स्वयं अपने लामने लिये अहदा कर सकता था देखो—A. I. R. 1925 Pat. 117, A. I. R. 1924 Mad 350 (A. I. R. 1925 Pat. P. 89) में यह तय हुआ था कि गौ लडकेकी जायदाद पर बारने दिवालिया कण लिये जाने पर रिमीवरकी नहीं समझता चादिहे किंतु किताभी रिमीवरको अधिार है कि वह या अलग जायदाद लडने पर भी करता यह समझने दृष्ट करले कि वापरा कर्त चुकाना लडकेका भी कर्त है हराय मित्र और भा दया—48 All 400, A. I. R. 1926 All 262

ममान हाईकोर्टी पुनर्वचने यह तय किया है कि दिवालियेक लडफत आविभक्त हिस्सा रिमीवरकी सुपुर्देगीमें नहीं जाता है किंतु उसकी सुपुर्देगीमें वापरा वह अधिकार आजाता है जो उसे अपन लडकीरी जायदादका अहदा करनेके लिये प्राप्त है और इसी कारण रिमावर समुक्त हिंदू परिवारकी कुल जायदाद देव सकता है देखा—A. I. R. 1926 Mad 994, A. I. R. 1927 Mad 1

सीर व मौलसी काइत—किसी मालगुजतके दिवालिया करार दिए जाने पर उसकी सीरकी समीन रिमीवरके तहतम आजाता है किंतु उसका मौलसी काइत नहीं जावेगी देखो—A. I. R. 1924 Nag. 15b इस दफाके अनुसार दिवालियारी मालकी (Occupancy holding) सन रिमीवरकी सुपुर्देगीमें नहीं जाती है और अजायत दिवालियागो उनके अहदा करने आदिवा अधिार प्राप्त नहीं है देखो—43 All 510.

सरकारी या रेलवेके प्राविडेन्ट फण्ड—मे जा रकम मनजान दाखिल कराई जाती है वह जायदाद दीवानीके अनुसार काइत नहीं है और इलायि को मिसार भी जो इस एकके अनुसार नियत किया गया हा ऐसी रकम पर अधिार कानेका हकदार नहीं है देखो—सेकेरी आक स्पेड बनाम राजकुमार 50 Cal. 347.

इसी प्रकार पोलिटिकल पण्डन (Political Pension) भी अजायत या रिमीवरके अधिारमें नहीं जासकती यदि ऐसी पण्डनका कुछ हिस्सा अदा करनेका हुकम दिवालियागो दिया जावे तो यह कानून अन्वा नहीं है देखो—4 I. C. 145, 20 A. L. J. 172

यदि कोई कर्त ऐसा हो जो हम एकके अनुसार मादित नहीं भिया जासकता है या कोई जायदाद ऐसी है जो दिवालियारी नहीं है वा एमे रकम या जायदादके लिये यह दफा लागू नहीं होना देखो—39 All 204, 1925 A. I. R. Nag 77

उपदफा (२) अगम टेनेस एक्ट (Agra Tenancy Act) के अग्रे लागू नहीं है इसलिये लगान का दावा किया जासकता है और उसकी डिमी वजयवा कराई जासकती है किंवा इस बात पर ध्यान दिये कि कोई मारिदाई अजायत दिवालियामें है या नहीं देखो—L. R. 3 A. 339 (Rev) 44 All. 296.

उपदफा (२) में यह नहीं मतयाया गया है कि कदाचित् कबल उर्दू कर्जवाहोके भिये होगी मिनतो बादिम पहुँच चुका है या मय कर्जवाहोके भिय पग्लु अवधमें एक मामलेम यह तय हुआ है कि कदाचित् उर्दू कर्जवाहोके भिये सपक्षना चादिहे नि ह नोमिम हा चुका है उन लोकोर भिये नहीं जिहें वाटिस नहा भिमा है देखो—25 I. C. 708.

हो चुका है तो वह या तो उस कार्टवार्डको बंद कर देगी या उन शर्तों पर चालू रखलेगी जो उसे मुनासिब मालूम होंगे ।

व्याख्या—

यह दया नहीं है हमसे पहिले यह बनलाया जा चुका है कि दिवालियेके विरुद्ध कोई नया मुकदमा नहीं चलाया जायेगा इस दफ्तेमें यह बनलाया गया है कि यदि कोई मामला या मुकदमा पहिलेसे चल रहा हो न उसके पश्चात् दिवालिया क़ारार दिये जानेका हुक्म दिया गया हो तो ऐसे हुक्मकी सूचना मिलने पर उस मामलेकी सुनने वाली अदालत या तो उसका सुनना बंद कर देगी या उचित शर्तोंके ऊपर उसकी समाप्त करता रहेगी । अदालत उसी मामले या शर्तोंकी शर्त सहाय है या उस पर शर्त लगा सकती है जो उसके मामले पर हों तथा उसी समय ऐसा करेगी जब यह भावित कर दिया जावे कि दिवालिया क़ारार दिये जानेका हुक्म दिया जा चुका है देखो—A. I. R. 1925 Mad 1051-48 Mad. 750.

यदि किसी कर्जकी वसूलाया मामला चल रहा हो और सुप्रीम दिवालिया क़ारार दे दिया जावे तो यह उचित होगा कि वह मामला रोक दिया जावे तथा कर्जकारको अपना कर्ज अदालत दिवालियामें साबित करनेके लिये छोड़ दिया जावे देखो—34 All 106.

111 दफ्तेके अनुसार मामलेकी रोक देनेसे यह अभिप्राय है कि जिसमें कर्जकारका अदालत दिवालियामें अपना कर्ज साबित करनेका अवसर मिल सके परंतु कर्जकार अगल ऐसा चाहे तो कर सकता है बल्कि यदि न चाहे तो उसी मामलेकी जाहू रखनेके लिये अदालतसे यह सज्जा है देखो—उपर शरीफ नवाम अलाउद्दौल्लाह A. I. R. 1924 Nag. 300

जबकि कोई शरीफ दिवालिया क़ारार दे दिया जावे तो अदालतकी चाहिये कि दूसरे क़रीनके हुक्म देने में अतिशय रितीवारी न हो 'करीफ मुकदमा' बना लेवे और यदि आक्रियल रितीवारी करीफ मुकदमा न बनना चाहे तो अदालत निज शर्तों पर चाहे मुकदमोंकी सुन सकता है देखो—A. I. R. 1926 1146.

दिवालिया क़ारार दिये जानेका हुक्म होनेके पश्चात् यदि दिवालियेकी जायदाद दीवानीकी किमी इमरान किमी हाथ बेची गई हो और उसकी सूचना रितीवारी न दी गई हो तो ऐसी इमरानके नीजाममें खर्चद्वारे बालम कर्ज एक रकम न होगा और रितीवारीकी जाहू है कि वह अदालत दिवालियामें दफ्तरात देकर ऐसे बेंचे जानेका मसूदा कर देवे । देखो—44 Mad. 524.

इस दफ्तेके अनुसार पश्चात् केवल उन्हीं मामलोंकी लिये नहीं की जायेगी जो दिवालिया क़ारार दिए जाते पहिले दायर किये गये हों किन्तु उन मामलोंके लिये भी की जा सकती है जो उसके पश्चात् दायर किये गये हों परन्तु इमरान दायरसल कर्ज इस दायर किये समय न रहा हो । देखो—A. I. R. 1924 Nag. 300.

इस दफ्तेमें यह साफ तौर पर प्रकट है कि मामलेकी सुनने आदिना कोई प्रश्न उस समय तक दायरसल न होयेगा जब तक कि दिवालिया क़ारार दिये जानेका हुक्म न दे दिया जावे देखा—A. I. R. 1926 Mad. 432. इस तौर पर यदि कोई दिवालियेकी दायरसल देदी गई हो परन्तु उस पर दिवालिया क़ारार दिये जानेका हुक्म न दिया गया हो तो केवल इसी बातसे इनपय डिक्रीकी कारवाही बंद नहीं की जासकेगी देखो—A. I. R. 1924 All. 707.

इस दफ्तेमें यह साफ नहीं किया गया है कि अदालत किस प्रकारके मामलोंकी दफ्तरात रोक देगी तथा किस प्रकारके मामलोंको जाहू रखेगी यह बाब अदालतकी इच्छा पर ही छोड़ दी गई है तथा जिस प्रकारका मामला हो या जितनी सूचना अवसर पर सज्ज हो सके करीब आधिकार अदालतके पास है इस प्रकार क़रारकी मायलेमें या हुक्म इत्यादी अर्थात्

मामलेमें चाद रखनेका हुक्म देनाही उचित प्रतीत होता है जब कि जानकी (Maintenance) का दावा उत वक्त मुद्दाकेद्वारे विरुद्ध चाद रखा जासकता है जबकि रिपीवर गी मुद्दाकेद्वारे बना लिया जाये देखो—A. I. R. 1927 Mad 403. इस दफामें जो दूसरी कार्रवाईका चिक है उससे तत्पर उस कार्रवाई समझना चाहिये जो मुकद्दमेंके तौर पर होने या या किसी मुकद्दमेंके दौरानमें करी हो देखो—A. I. R. 1928 Cal. 782 (F. B).

दफा ३० दिवालिया करार देने वाले हुक्मकी सुस्तरी

१) दिवालिया करार देने वाले हुक्मका नोटिस सरकारी प्राप्तिक गजटमें या अन्य किसी नियत किये हुए रूपमें प्रकाशित किया जावेगा और उस नोटिसमें दिवालियेका नाम, पता व पेशा रहेगा तथा उस मियादका भी उल्लेख रहेगा जिसके भीतर दिवालियेको अपने बहालकी दुरवस्थात दे देना चाहिये और उसमें उस अवसलतका भी नाम होगा जिसने उसे दिवालिया करार दिया हो ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार दिवालिया करार दिये जानेके पश्चात् इस हुक्मका सरकारी गजट या अन्य किसी निर्धारित रूपमें प्रकाशित किया जाना आवश्यक बनलाया गया है तथा यह भी बतलाया गया है कि इसमें निम्न लिखित बातें प्रकाशित की जानी चाहिये ।

- (१) दिवालियेका नाम पता व पेशा
- (२) दिवालिया करार दिये जानेकी तारीख
- (३) वह मियाद जिसके आदर दिवालियेकी बहाल होनेकी दुरवस्थात देना चाहिये, और
- (४) उस अवसलतका नाम जिसने कि दिवालिया करार दिया हो ।

नोट —यदि दिवालिया करार दिये जाने वाला हुक्म गजटमें प्रकाशित होनेसे रद्द जावे तो यह कैदक देनारीकी समझना चाहिये तथा इसकी वजहसे दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म रद्द नहीं समझा जावेगा या उसका अमर नहीं जाता रहेगा देखो—10 P R. 1900.

दिवालिया करार दिये जानेके बादकी कार्रवाई

दफा ३१ दिवालियेकी रक्षाका हुक्म

(१) दिवालिया करार दिये जानेके बाद दिवालिया अपनी रक्षाके लिये अवसलतमें रद्द मुद्दात देसकता है और अवसलत उस दुरवस्थात पर दिवालियेको कैद व हिरासतसे बचानेका हुक्म दे सकती है ।

(२) रक्षाका हुक्म कर्जदारके सब कर्जोंके लिये या उसके किसी एक कर्जोंके लिये दिया जासकता है जैसा कि अवसलत उचित समझे और यह हुक्म उस वक्त व उतने समयके लिये लागू होगा जिसके लिये अवसलत हुक्म देवे और अवसलत उस हुक्मको रद्द कर सकती है या और बढ़ा सकती है ।

(३) जिस कर्जके सम्बन्धमें रक्षा हुन दिया गया हो उसके लिये दिवालिया जेल या हिरासतमें नहीं रहेगा और अगर कोई दिवालिया ऐसे हुनके विरुद्ध कैद किया गया या रोका गया हो तो वह छोड़ दिये जानेका इकद्वार होगा ।

परन्तु शर्त यह भी है कि इस किरमका कोई हुन जबकि वह मंजूर कर दिया गया हो या जबकि दिवालिया करार देने वाला हुन रद्द कर दिया गया हो कर्जएवाहके अधिकारोंके प्रयोगमें रुकावट नहीं डाल सकेगा ।

(४) हर कर्जएवाहको अधिकार है कि वह हाजिर होकर उसके हुनकी मंजूरीमें सुखालिफत करे ।

व्याख्या—

पिछले एक्टके अनुसार दिवालिया करार दिये जानेके बाद दिवालिया बिना किसी दरवास्त आदिसे दिये हुए ही हिरासत आदिसे बचनस हकदार से जाना था परन्तु इस एक्टके अनुसार दिवालिया करार दिये जानेके बाद दिवालियाके दरवास्त देने पर यदि अगल चारे ती उत्तरी रक्षा हुन दे सकता है । इस दफ्तरा प्रयोग दिवालिया करार दिये जानेका हुन है । जानेक पश्चात् ही लिया जावेगा देखो—A. I. R. 1924 Mad 893

इस प्रकार दिवालिया करार दिये जानेके बाद दिवालिया अपनी रक्षाके लिये अदालतमें दरवास्त दे सकता है ।

ऐसा स्पष्ट होता है कि इस एक्टके अनुसार रक्षा इतनाई हुन नहीं दिया जासकता है जो दफा २३ के अनुसार बन्दर दिवालिया करार दिये जानेमें पहिले ही कैद या हिरासतसे मुक्त किये जानना अधिकारी है । देखो—A. I. R. 1926 Cal 1011 में यह तथ हुआ था कि जब तब दिवालिया ग्यार दिये जानेका हुन होनासे तब तक रक्षाके लिये हुन इतनाई नहीं जारी लिया जासकता है ।

इस बात पर भी ध्यान देना आवश्यक है कि अदालत दिवालिया करार दिये जानेके बाद रक्षा हुन देनेके लिये माग नहीं है अपितु वह अपनी इच्छानुसार हुन दे भी सकती है तथा उसके देनेसे इनकार भी कर सकती है । रक्षा हुन देने समय अदालतको चाहिये कि उपस्थित अवस्था तथा दिवालिया द्वारा दिये हुए कार्योंका ध्यान रहे और यदि दिवालियेने बर्तमान व बचनीयतासे किञ्चल खर्च आदि करके अपनी यह दशा बरती हो तो अदालत ऐसी दशामें रक्षा हुन नहीं देवेगा देखो—40 Bom 461.

उपदफा (२) अदालतको यह भी अधिकार है कि वह रक्षा हुन सिरी एही बजेंके सम्बन्धमें देवे या दिवालियाके सब बजेंके सम्बन्धमें दे देवे अदालतको जाने हुनमें यह दिवना देना चाहिये कि रक्षार्थ हुन सब बजेंके लिये दिया गया है या किसी काम लिये दिये दिया गया है यदि हुनमें कोई ऐसा बजेंक न हो तो यह समझना चाहिये कि रक्षा हुन सब बजेंके लिये है ।

अदालतको यह भी अधिकार है कि वह रक्षार्थ हुन किसी खास मियार्के लिये देवे तथा यह भी निश्चित कर देवे कि कबसे वह रक्षाके हुनका प्रयोग समझना चाहिये अदालत जाने रक्षाके हुनको रद्द भी कर सकती है व साथही बढ़ा भी सकती है । रक्षार्थ हुन जो दस दफाके अनुसार दिया जावेगा वह केवल उन्हीं बजेंके सम्बन्धमें हो सकता है जो इस एक्टके अनुसार स्थापित किये जासकते हैं देखो—हायल नगम तुम्सीराम A. I. R. 1925 Nag 77.)

उपदफा (३) कर्जएवाहको अधिकार है कि वह रक्षार्थ हुन देवे समय उपस्थित होकर उस हुनके देनेमें विशेष करे । इस उपदफामें यह बात स्पष्ट है कि रक्षार्थ दरवास्त पर निचार करनेसे पहिले उसकी सूचना उग कर्जएवाहको

भी हो जाना चाहिये जिनका उग दायित्वमे सम्बन्ध है देखो—25 C L J 456, 25 C. L J. 149. कन्यादान रक्षा दायित्वमा विषय उस पर हुनम हमिसे पाइयेही कर सक्ते हैं हुनम होनानक परान्त् बह हाजि होर उदरा विरोध नही कर सक्ते ।

अदालत दिवालियाको तरफसे कर्जे (Crown debts) के सम्बन्धमें एगान हुनम देनेका कोई अधिकार नहीं है देखो—A. I. R. 1928 Rang 81=109 I C 145

दफा ३२ दिवालिया करार दिये जानेके बाद गिरफ्तारीके अधिकार

अगर दिवालिया करार दियेके बाद कोई कर्जदारगह या रिसीवर इन बातकी दरखास्त देवे कि दिवालिया छिप रहा है या अशालती अधिकार सीमासे बाहर इस इनादेसे बता गया है कि जिसमे वह अपने कर्तव्यकी पूर्तिके लिये बाधित न किया जासक या इस एक्टके अनुसार कोई कार्यवाई उसके बिच्छु न की जासके और अदालतको एसी दरखास्त पर यकीन हो जावे तो उसे अधिकार है कि यह दिवालियाकी गिरफ्तारीके लिये बाराहट जारी कर सकती है इसके पश्चात् दिवालियाके हाजिर होने पर या उसके गिरफ्तार होने पर अगर यकीन हो जावे कि वह छिपा हुआ था या ऐसी इच्छासे भागा हुआ था तो उसे जमानत आदि की उन शर्तों पर छोड़ सकती है जो उचित व आवश्यक मतीन हों और अगर जमानत न दी जावे तो यह हुक्म दे सकती है कि वह दीवानीकी जेलमें रखा जाव लेकिन यह हुक्म तीन महीने तकके लिय दिया जा सकता है ।

धाराया—

दिवालिया करार देनेके बाद अदालत आवश्यकता मतीन होने पर दिवालियाको गिरफ्तार कर सकता है तथा उसे जेल दीवानीमें भी तीन माह तक रख सकती है परन्तु यह कार्यवाई अदालत उन्ही समय कभी जबकि गिरफ्तार या कोई कर्जदारगह उसके अगले या भागनके सम्बन्धम दरखान देवे तथा अदालतको भी विगस्त हो जावे कि दरअसल दिवालिया उसके अधिकार सीमासे बाहर जाना चाहता था जिसमें वह अपने कर्तव्योंकी पूर्तिके लिय बाध 7 किया जाये तो अदालत उसके गिरफ्तार होनेका हुक्म देसगी परन्तु गिरफ्तार हानके बाद भी अदालत जमानत लेस या किसी दूसरे इगसे यह विदवात होनाने पर कि दिवालिया भागेगा नहीं किन्तु अपने कर्तव्योंका पूर्तिके लिय प्रस्तुत इगना उसे मुक्त कर सकती है ।

अदालत इस दफाके अनुसार कार्यवाई करनेके लिये राय नहीं है किन्तु वह अपनी इच्छानुसार समयावकूष हुक्म दे सकता है जिसमे कि दिवालेस कार्यवाहीमें भी कबायत न पड़े तथा दिवालियाको भी किसी गहार बना तरफको पोराना 7 हाना 7

दफा ३३ कर्जखानहानकी सूची

(१) जबकि इस एक्टके अनुसार दिवालिया करार देनेका हुक्म दिया जाचुका है तब यह सय कर्जखान जो इस एक्टके अनुसार अपने कर्ज साबित कर सकते हैं अपने अगन कर्जोंके लिये सुवृत्त पेश करंगे कि उनका कितना कर्ज है व बिस् किम्बका कर्ज है और अशालत अपने हुक्म द्वारा यह निश्चित करेगी कि कौन २ लॉगोंने अपनको कर्जदारगह साबित किया है और उनका कितना कितना कर्ज है इन लोगोंकी व उनके कर्जकी प्रक सूची तैयार करेगी । परन्तु अगर अशालतकी रायमें किसी कर्जकी तादाद ठीक तौरपर निश्चित नहीं की जासकती है तो अशालत इसी क्रिमका हुक्म लिख देगी और इस पर वह कर्ज सूचीम सम्मिलित नहीं किया जावेगा ।

उपद्रफा (१) इस एक्ट के अनुसार दो प्रकारके वर्जों हैं जो शक्ति नहीं मिले जायेंगे अर्थात् एक वे कहे और शिमेदारिया जिनकी कौमरता अदाया अदालत द्वारा नहीं लगया जायगा और जो इसी कारण सुचाते कि वह दिये गये हैं दूसरे वे मांगें जिनका दर्जा निश्चित नहीं किया गया है या धुआहिदा शिकमी व अपानर्तमें लयानन सम्बन्धी इन्हें साबित मिले जासकते हैं उदाहरण स्वरूप हमारे आदि सम्बन्धी वर्जोंमें ऐसी मांग सम्बन्धी चाहिये मिलना कि वर्जों निश्चित नहीं किया गया है तथा महर सुवचन (Deferred dower) में साबित करने योग्य वर्जों नहीं हैं क्योंकि यह भविष्य होने वाला कर्म है और यह नहीं कहा जायगा कि वह कर्म होवेगा या होवेगा ही नहीं देखो—50 I C 774.

उपद्रफा (२) उन दो प्रकारके वर्जोंमें छोड़ कर जिनका उद्धृत उपद्रफा (१) में किया जाचुका है नाकी सब कहे व शिमेदारिया (चाहे वह मौजूदा हों या भविष्यमें होने वाली हों चाहे वह निश्चित हों या अनिश्चित) साबितका ज्ञान योग्य है वर्जों में कि वर्जदार दिवालिपिया करार दिये जाने समय उनका पाबन्द हो या बद्दल होनेमें पहिले उनका पाबन्द हो जावे और यह पाबन्दी दिवालिपिया करार दिये जाने वाले हुक्ममें पहिले मिले हुए कामके कारण हुई हो यदि कोई शिमेदारी दिवालिपिया करार दिये जानेके बाद हुई हो तो वह इस एक्ट के अनुसार साबित नहीं की जायगी है देखो—48 I C 913.

यदि भाँवर २४ रूल् ६ के अनुसार किसी न वनवाई गई हो अर्थात् यदि रद्दनामके वर्जोंका मतानुसारके किये किसी न वनवाई गई हो कि तु वह मतानुसार निरुद्धता हो तो कर्जदार ऐसे वर्जोंके साबित करनेमें बाधित नहीं रहा जासकेगा । कर्जदार दिवालिपियके लिये यह साबित होना आवश्यक है कि वर्ज दरअसल निरुद्धता है देखो—A. I. R 1925 Pat. 438 यदि दिवालिपियाने कोई बड़ा दिवालिपिया करार दिये जानेके बहुत देर बाद लिया हो तो ऐसे प्रकारके वर्जों साबित नहीं किया जासकेगा परन्तु इस रूल्के सम्बन्धमें आहूदा कर्जदारोंकी जासकेगी देखो—A I R 1925 Oudh 668.

दिवालिपिया करार दिये जानेके बाद यदि दिवालिपिये कोई शिमा निरुद्धता हो तो उस शिमाके किये यह नहीं माना जावेगा कि वह दिवालिपिया करार दिये जाने समय निरुद्धता था और इस कारण इस दफाके अनुसार साबित नहीं किया जासकता है देखो—A I R 1922 Oudh 73.

जबकि किसी सयुक्त हिंदू परिवारका एक मेमबर दिवालिपिया करार दिया गया हो तो वर्जस्वाहको चाहिये कि अपना पूरा कर्ज (Joint debt) अदालत दिवालिपियाने साबित करे और वह उस सयुक्त कर्जका दिवालिपिया व इतर दिवालिपिया सम्बन्धमें बाँट कर अलहदा नहा दिखलावे देखो—A. I. R 1923 Nag 257.

दिवालिपिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी मंजूरी

दफा २५ दिवालिपिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी मंजूरीके अख्तियार

जबकि अदालतकी रायमें किसी कर्जदारको दिवालिपिया करार नहीं देना चाहिये था या जबकि अदालतको यकीन हो जावे कि कर्जदारके सब कर्ज पूर्ण रूपसे चुकता हो गये हैं तो कर्जदार या किसी दूसरे सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तिने दरखास्त देने पर अदालत लिखकर दिवालिपिया करार देने वाले हुक्मको रद्द कर देगी और अदालत स्वयं ही या रिसीवर अथवा किसी कर्जस्वाहके दरखास्त देने पर भी दिवालिपिया करार दिये जाने वाले हुक्मको उस समय रद्द कर सकती है जबकि कर्जदार अपनी ही दरखास्तके कारण दिवालिपिया करार दिया गया हो परन्तु यह दफा १० (२) के अनुसार ऐसी दरखास्त देनेका अधिकारी न होगे ।

व्याख्या—

इस दफा में नीचेका हिस्सा इस एकटके बन जानेके पश्चात् जोड़ा गया है अर्थात् दिवालिज ससोधक एन० १० सन् १९२७ ई० के अनुसार यह भाग सम्मिलित किया गया है । दिवालिज कगार दिखे जान बाल हुक्मकी मसूखीके लिखे दो बातें बतलाई गई हैं एक (१) तो यह कि जब अदालतकी रायमें दिवालिज कगारही नहीं दिया जाना चाहिये था (२) यह कि जब दिवालिजके सब कर्जे पूरे रूपमें चुका दिये जावें । परन्तु अब ससोधित एकटके अनुसार उस समयभी इस हुक्मकी रद्द किया जासकेगा जबकि अदालतकी रायमें कर्जदारको दफा १० (२) के अनुसार दरखास्त देनेका हकही न रहा हो । किन्तु ऊपर कही हुई दोनों बातों या दो म से एक भी बावक साबित होने पर अदालत दिवालिज कगार दिखे जाने वाले हुक्मकी रद्द कानेके लिख बाध्य है परन्तु इस ससोधित भागके अनुसार हुक्मका रद्द करना तथा न करना अदालतके अधिकात्में है ।

दिवालिज यह नहीं रद्द सकता है कि कर्जदारको सूचना नहीं दी गई है इस कारण मसूजीका हुक्म उचित नहीं है दफा—A. I. R. 1926 Mad 123.

इस दफाके अनुसार हुक्म रद्द किये जानेका दरखास्त दिवालिज रजय भी दे सकता है तथा दूसरे लोग भी दे सकते हैं अर्थात् गिमीबर कर्जदारों तथा अन्य कोई व्यक्ति जिसका मसूखीके हुक्ममें लाभ पहुँचना हो ऐसी दरखास्त दे सकता है । अदालत रजय भी बिना किसी दरखास्तके और हुक्म रद्द कर सकता है । दिवालिज कगार दिखे जानेका हुक्म थोड़ाहीकी बिना पर अथवा इस बिना कि अदालतकी रायमें ऐसा करना फायदा उठाया गया है मसूख किया जासकता है देखो—44 Cal. 899. इस बिना पर भी मसूख किया जासकता है कि अदालत दिवालिजाने उसकी अधिकतर सीमा न होते हुए वह हुक्म दे दिया था देखो—रामकमल बनाम बैंक आफ बंगाल 5 O IV N 91

इस बिना पर भी मसूख किया जासकता है कि वह हुक्म दिया ही नहीं जाना चाहिये था क्योंकि जिस दिवालिजके कामके आधार पर वह हुक्म दिया गया था वह दरखास्त मौजूदी नहीं था देखो—A. I. R. 1926 Mad. 1159.

यदि कोई बच्चा (Infant) दिवालिज कगार दे दिया गया हो तो अदालत ऐसे हुक्मको रद्द कर देगी देखो—18 A. L. J. 611.

इस दफा में अदालतसे बेजा लाभ उठानेका कोई उल्लेख नहीं है और इसीलिए यदि दिवालिज इस एकटकी सब बातों की पूरा करदे जिससे कि वह दरखास्त देनेका अधिकारी समझा जासक तो यह नहीं कहा जावेगा कि उसने अदालत की रायसे बेजा फायदा उठाया है इसी कारण यह दफा ३५ के अनुसार दिवालिज कगार ही नहीं दिया जाना चाहिये था । जब कि दिवालिजाने अदालत द्वारा नियत की हुई मियादके अंदर बहाल होने की दरखास्त दा हा और सब जग ऐसी दरखास्तों मसूख न करे तथा अपील किये जाने पर जजने भी बहालकी दरखास्त मसूर न की हो तथा वह दिवालिज कगार दिखे जान बाले हुक्मकी भी रद्द कर देवे तो यह तब हुआ कि जज हा ऐसा हुक्म उभक अधिकारसे बाहर था देखो—A. I. R. 1928 Mad 609

कर्जे अदा हो जाने पर हुक्मकी मसूखी उसी समय हो सकेगी जब कि जब जज पूर्ण रूपसे चुका दिये गये हों 38 Bom 200 बादेके सूदका भी कर्ज ही समझना चाहिये और यदि यह बादका सूद अदा न हुआ हो तो कर्जका पूर्ण अदागमी न समझा जावेगी देखो—48 All 272

यदि दिवालिजाने अपने कर्जदारोंका बाहरा तौर पर यह तय कर लिया हो कि वह सब लोगोंको उनके कर्जोंका चौथाई अदा कर दगा तथा वह लोग उसी चौथाईसे अपना पूर्ण कर्ज चुकाया समझवेगे ता ऐसे समझीके कारण दिवालिज कगार दिखे जाना हुक्म रद्द दफाके अनुसार रद्द नहीं किया जासकता देखो—43 Mad 71

अपन १५वां सम्बन्धी लिख दिया था । यह भा पता लगा कि रावलपिण्डा के कर्षाहासको वर्तमानमें कुछ सुसज्जता कर लिया है और वह लोग रावलपिण्डा जायदादसे अपने कर्मों में मोठा हिस्साही चुकाने के लिये बा मजत हो गये हैं — इन कारिणों पर हाईकोर्ट ने आदेश यह दिये कि दिवाणियों को कर्षावाही दाना जमात में पट्टे रह तथा यह बात अपने बड़ी अदायगी तब तक करेगी कि उनमेंसे किम अपना दिवाणिया करार दिय जानेका हुक्म मसूख करवा चाहे देता — A I R 1928 Lah 848-109 I C 648

दफा ३७ मंसूखीके आदका कार्रवाई

(१) जबकि कोई दिवाणिया करार दिये जानेका हुक्म मंसूख कर दिया जाये तो वह सब दयनामें व जायदादके तकसीम नामेय वह सब रूपों की अशय्यो तथा मृत मय काम जो इस मंसूखीके हुक्मसे पहिले किये जा चुके हैं ठीक समझे जावेंगे । परन्तु ऊपर दी हुई बातको मानते हुए दिवाणिया करार दिये जाने वाले कर्जदारकी जायदाद उस शर्त की मिलगी जिस अशय्य लत नियुक्त करे या अगर ऐसा कोई व्यक्ति नियुक्त न किया जाये तो वह जायदाद कर्जदारही को उस हद तक उन शर्तोंके साथ जो अदालत अपने लिखित हुक्म द्वारा घोषित करे व पिसि खली जावेगी जिस हद तक कर्जदारका हक व हिस्सा उस जायदादमें पहुँचता हो ।

(२) दिवाणिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी मंसूखीका नोटिस प्रान्तिक सरकारी गजटमें तथा अन्य किसी नियत किये हुए स्थानसे प्रकाशित किया जावेगा ।

व्याख्या—

यस दफा में यह बताया गया है कि दिवाणिया करार दिये जाने वाले हुक्मका मसूजीमें पाहल अदालत या निमात्र जिन कामों की कर चुकता वर सब काम बन्द हो जाय जात्रग तथा मसूखीका हुक्म हात में रह जायदाद दिवाणिया की बाधिम नहीं मिल सकेगा किन्तु अदालतको चाहिये कि कर्षावाहासक हकोंका रक्षा करे मसूखीका हुक्म देत समय किम एम व्यातका नियुक्त करे वर जो जायदाद पर कर्षावा सके देता—A I R 1926 Lah 370, A I R. 1925 Sindh 159

यस में जब कि अदालत द्वारा जायदाद पर कर्षावा लेने के लिये कोई एम व्यक्ति नियुक्त न किया गया हो वर वह जायदाद दिवाणियों की बाधिम भित जात्रग । यदि समावरक पास या उस समय कोई जायदाद बची हो तो वर भी दिवाणिया हा बा बाधिम भित जात्रग । जब कि दिवाणिया का कोई जायदाद या लहना मसूखीमें पहिन्ही बरबाद हो चुका है ता उसका किय कोई सहायता पदी है कि तु सिमावरका खर्च आदि मिहालनेके पश्चात् तो बचेगा दिवाणिया काम के पानेका अधिकारी है दली—मुन्चद बनाम खजर A I R 1925 All 735, अरुविली बनाम आकिशाल सिमावर 98 I C 1000

यदि दिवाणियों कर्षावाहीके दौरानमें सिमावर दिवाणियाका साक्ष दगेंके बिना दिवाणियोंके भागने लिये जात्रा करे और इसका बाद दिवाणियों कर्षावाही मसूख करवा जाव ता इससे वह दावा समाप्त नहीं हो जावेगा कि तु दिवाणियोंके अधिकार है कि वह उस दावेकी उस समय अपने नामस चालू रख सक देवो—11 All 200

जिसी कर्षावाहीकी दखलास्त पर दो माई दिवाणियों करार दिये गये व होन नियत किये हुए समयके अंदर ददाल होनेकी दखलास्त नहा दो इस कारण अदायता दफा ४३ के अनुसार दिवाणिया करार दिये गये वाले हुक्मकी मसूख कर दिया जाय इससे पश्चात् अपने दफा ३७ के अनुसार उनमेंसे एकस जायदादकी मा सिमावरके अधिकारमें आयेगी

उसको वापिस कर दिये जानेवा हुम दे दिया । परन्तु अर्थात्में यह हुम हुआ कि आपदाद पुगने रिहावरके अधिकारमें रखा जासकतो या । पहिले इसके कि कर्जवाह कोई कर्जवाह को उस पुगने रिहावरके आपदादको बँच डाला तथा उसे सूचीके कर्जवाहानमें दिखाने सादसे तकभोम^१ दिया—आदोर हाईकोर्टने यह तय किया कि आपदादका बँच जाना तथा उसका रहस्य नौरसे बचा जाना कानूनन उचित है देखो—A. I. R. 1928 Lah 453

उपद्रा (२) में बतलाया गया है कि मसूखीका हुम प्रार्थिक मर्यादे गजटमें अवश्य प्रकाशित किया जाना चाहिये तथा निर्धारित निय हए बिना दूसरे रूपमें भी उसे प्रकाशित कर देना चाहिये । मसूखीका हुम होते समय दिवालिये की आपदादका कि ॥ शर्तोंके साथ दिवालियेको बिस्मनेके लिये जो हुम लिया जान उसकी अर्थात् हाईकोर्टमें दफा ७५ (२) व शिष्टपुत्र १ के अनुसार हो सकती है देखो—100 I. C 137.

तसफिया तथा तय करनेका तरीका

दफा ३८ तसफिया तथा तय करनेका तरीका

(१) अगर कोई कर्जदार दिवालिया करार दिये जाने वाले हुम हो जानेके पश्चात् अपने कर्जोंके तसफियाके लिये रहे या अपने मामलोंको तय करनेके लिये कोई तरीका बतलावे तो अदालत उसे प्रस्ताव पर विचार करनेके लिये कोई तरीका नियत करेगी और सब कर्जवाहों को नियत ढंग पर मोडिस दिया जावेगा ।

(२) अगर प्रस्ताव पर विचार करनेके पश्चात् कर्जवाह कसरत रायसे और जिनका संयुक्त कर्ज कुल कर्जके १/३ कीमतसे कम न हो तथा उनके कर्ज साबित किये जाचुके हों और वह तोय स्वयं हाजिर हों या उनके वकील मौजूद हों इसप्रस्तावको मंजूर करलें तो यह मान लिया जावेगा कि कर्जवाहोंने उस प्रस्तावको भली भाँति स्वीकार कर लिया है ।

(३) कर्जदारको अधिकार है कि वह प्रस्ताव स्वीकृत होते समय उसे संशोधित कर सकता है अगर अदालतकी रायमें वह संशोधन अधिकतर कर्जवाहानकी भलाईके लिये है ।

(४) अगर अदालत निश्चय किये हुए रिसेवरकी रिपोर्ट सुनकर तथा कर्जवाहों द्वारा या उनकी तरफसे किये हुए पत्राचारोंको समझकर यह राय कायम करे कि कर्जदारका प्रस्ताव उचित नहीं है या अधिकतर कर्जवाहोंके लाभके लिये नहीं है तो वह उस प्रस्तावको मंजूर करनेसे इनकार कर देगी ।

(५) अगर कोई ऐसी बातें साबित हो जावे जिनके साबित होने पर अदालत यहाल करनेका हुकम न देसके या रोक दे या उसके साथ शर्तें लगा दे तो अदालत उस तक तक उस प्रस्तावको मंजूर करनेसे इनकार कर देगी जब तक कि बिला महफूज कर्जोंके लिये जो कर्जदार की आपदादके खिलाफ साबित किये जासकते हैं कमसे कम ६ आना की रुपयकी अदायगीका इन्तजाम न हो जावे ।

(६) कोई तसफिया या स्कीम उस तक तक मंजूर नहीं की जावेगी जब तक कि उसके द्वारा उन कर्जोंकी अदायगीका इन्तजाम पहिले न हो जावे जिनकी अदायगी दिवालियेकी आपदादसे पहिले होना चाहिये ।

(७) और किसी दूसरी सूत्रमें अदालतको अधिकार है कि वह चाहे प्रस्तावको मंजूर करे या नामंजूर करदे ।

व्याख्या—

दिवालिया करार दिये जानका हुकम से जानेके पश्चात् दिवालिया अपने कर्त्तव्यों निपटानेके लिये जो बर्गवाई कर सकता है उसका उद्भव इस दफामें दिया हुआ है ।

समस्या (Composition) से तात्पर्य उस समयवाले समझना चाहिये जो कर्जदार व कर्जखवाहोंके दामियान उनके कर्जों तथा किये जानेके लिये किया जावे तथा जिसके अनुसार कर्जखवाहान अपने कर्जसे कम लक्ष्य पूरा कर्जाई अदायगी मान लेंगे । जब कोई ऐसा प्रस्ताव अदालतके सामने उपस्थित हो ता अदालतका कर्तव्य है कि वह इसकी सूचना कर्जखवाहान को दवे तथा इस दफाके अनुमतिका हुई सभा (Meeting) में उस प्रस्ताव पर विचार करे और यदि कर्जदारान जिनके कर्जों साबित हो चुके हैं बहुमतसे तथा इनके कर्जोंका योग कुल साबित किये हुए कर्जोंके तीन चत्वारिसे न्यून न होवे तथा जो स्वयं या जिनके बर्गीक उपस्थित हों उस प्रस्तावको स्वीकार करलें ता अदालतका चाहिये कि वह इस बातको नोट करके कि वह प्रस्ताव कर्जखवाहानसे मंजूर कर लिया है । परन्तु यदि स्वयं या बर्गीकों द्वारा उपस्थित कर्जखवाहान जिनके कर्जों साबित किये जाचुके हैं बहुमतसे या जिनके कर्जों तीन चत्वारि साबित किये हुए बताते कम न हों उस प्रस्तावको मंजूर न करें तो वह प्रस्ताव अस्वीकृत समझा जावगा अदालतकी उस प्रस्तावको अस्वीकारके लिये चाहे जो कुछ राय रही हो । यदि प्रस्ताव कर्जखवाहान द्वारा स्वीकृत कर लिया गया हो तो अदालतका कर्तव्य है कि वह इस बात पर विचार करे कि आया वह प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिये या नहीं । अदालतको ठिये यह आवश्यक नहीं है कि कर्जखवाहान द्वारा स्वीकृत किया हुआ प्रस्ताव अवश्यही स्वीकार करल दलो—30 I C 694

इस दफामें बताये हुए नियमोंका पालन पूर्ण रूपसे किया जाना चाहिये अथवा कोई समझौता माननके लिये बर्ज खवाहान बाधन नहीं होंगे और न ऐसा समझौता कानूनी समझौताही समझा जावेगा दलो—A I R 1926 Lah 87 समझौता कर्जखवाहानकी स्वीकृतहाने माननीय नहीं समझा जावगा कि तु उसका माननीय बनानेके लिये अदालतकी स्वीकृति आवश्यक है दलो—A. I R 1926 Lah 489

यदि किसी कर्जखवाहकी सूचना न पहुँचनेका कारण समझौता ठाक न रहे तो कर्जखवाहका अधिकार है कि वह अपने कर्जदारकी जापदादको कुर्क कर लेवे दलो—A I R. 1926 Lah 87

उपदफा (२) तथा अगरी उपदफाअसे यह प्रतीत होता है कि समझौतेके प्रस्ताव पर विचार करनेके लिये एक सभा (Meeting) की जा जावेगा यदि कर्जखवाहान समझौतेको मंजूर कर लव तो यह मान लिया जावेगा कि वह प्रस्ताव पास हो गया है ऐसे प्रस्ताव पर वोट देनेका अधिकार उस कर्जखवाहको नहीं दया जाता कि कर्जों साबित नहीं किया गया है तथा जिसका नाम जब द्वारा सूत्रामें सम्मिलित नहीं किया गया है दलो—15 A. L. J. 146=40 I C 156

उपदफा (३) के अनुसार कर्जदार अपने प्रस्तावमें समझौत कर सकता है यदि अदालतकी रायमें उस समझौतसे कर्जखवाहानका लाभ पहुँचना हो ।

उपदफा (४), (५) व (६) में यह बतलाया गया है कि अदालत जिन २ दफाओंमें कर्जदारके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा ।

उपदफा (७) में उन मामलोंका सम्बन्ध कहा गया है जिनका उल्लेख इससे पादिने नहीं किया गया है अदालत

का एमे माफके रीतिर कामे व न खांसार कामेमें पूर्ण स्वतन्त्रता है उदाहरण स्वरूप यदि दिवालियाने रिलीवरसे डिफाउर किया कतरवाइसे रुपया दिया दा ता बदावत ऐसी दणमें समझौता नामचर कर सक्ती है देखो—A. I. R. 1926 Mad 1166 अतिरिक्त एमे प्रस्तावोंकी स्वाहृत लिखित हुक्मक अङ्गारसी की जाना चाहिये किन्तु एमे अवसर भी आजाते है जिनमे यह समझा जासके कि स्वाहृत प्रदान कर दी गई है यद्यपि उसके सम्बन्धमें कोई निश्चित हुक्म न दिया गया हो देखो—A. I. R. 1926 All 361.

दफा ३९ मंजूर करने पर हुक्म

अगर अदालत प्रस्तावको मंजूर करले तो सब शयें अदालतके हुक्ममें लिख दी जायेंगी और अदालत दफा ३३ के अनुसार एक सूची तैयार करेगी व दिवालिया करार दिये जाने वाला हुक्म मंजूर कर दिया जावेगा और दफा ३७ में दिये हुए नियमोंका प्रयोग किया जावेगा और तसकिया या स्कीम उन सब कर्जदारोंके लिये माननीय होगी जिनका उल्लेख सूचीमें है और जहां तक उनका तारलुक सूचीमें दिये हुए अपन कर्जोंसे है।

ब्याख्या—

जब कि अदालत प्रस्तावकी रीतिर कर लेवे तो अदालतके चाहिये कि वह अपने हुक्ममें प्रस्तावकी सब बातोंको दिला देने तथा दफा ३३ में बतलाये हुए नियमोंके अनुसार कर्जदारोंको व कर्जोंकी सूची तैयार करे और साथही साथ तसकिया करार दिये जाने वाले हुक्मको रद कर देने इसके परवात् दफा ३७ में बतलाई हुई कर्जदारों काय होगी देखो—24 A. L. J. 441 यदि प्रस्तावकी रीतिरके साथ कोई शयें न लगाई जायें तो दिवालिया अपनी स्वाभाविक दशा को पात हो जावेगा और रिलीवर अपनी कर्जदारोंका बरग बंद कर दगा देवे—A. I. R. 1926 Mad 1187.

समझतेकी रीतिरके केवल अर्धों कर्जदारों पर लागू होगी जिनके कर्जों माफित किये जाउरे है तथा जिनका नाम सूचावे जिला न्याया है। वह रजिस्ट्राराने समझतेकी अवज्ञता नहीं कर सकने देखो—A. I. R. 1925 Lath. 316 वह कर्जदार जिनका नाम सूचीमें नहीं आया है अपनी डिफा इनका क्या सहा है देखो—A. I. R. 1926 Cal 489

दफा ४० कर्जदारको फिर दिवालिया करार देनेका अधिकार

अगर तसकिया या स्कीममें तय की हुई किनी कितकी अदायगी न हो सके या अदालत को यह मालूम हो कि जिला रजिस्ट्रारकी या देर किये हुए उस पर अमल नहीं किया जातकता है या अदालतको यह यकीन हो जावे कि उसे धोखा देकर मंजुरी ली गई है तो वह अगर मुनासिब समझे कर्जदारको दुबारा दिवालिया करार दे सकता है और तसकिया या स्कीमको रद कर सकती है लेकिन वह सब इतनाल जायदाद अदायगी तथा दूसरे काम जो तसकिया या स्कीमके अनुसार दिये जाचुक है ठीक समझे जावेंगे।

जब कि कर्जदार इस दफाके अनुसार दुबारा दिवालिया करार दिया जावे तो वह सब कर्जों भी जो दुबारा दिवालिया करार देनेसे पहिले लिये हैं और जो इस एक्टके अनुसार साबित किये जातकते हैं साबित किये जासकेंगे।

व्याख्या—

इस दफा में मजसते के आधार पर गत किये हुए दिवालिफे के द्वारा दिवालिफे करार दिये जानेवाले उद्देश्य के तथा समझनेवाले रहस्य या उद्देश्यवाले खुल कर देनेवाले भी वर्णन है । अदालत नाम दी हुई वातावरण पर समझ तथा स्वीकृति की हुई समझने पर यह वातावरण के तथा दिवालिफे के जिस द्वारा दिवालिफे करार दे सक्ती है ।

- (१) यदि समझने के अनुसार तयारी हुई किसी अदालती के समय पर न होने, या
- (२) यदि समझने के अनुसार पर बिना बेइमानी या देश किये हुए अमल न किया जाय, या
- (३) यदि अदालती स्वीकृत घोषणा देकर ली गई हो ।

इस दफा के अनुसार समझनेवाले अधिकार देनेवाले जानेवाले वातावरणवाले अदालत अथवा अदालती के लिये समझने में दिवालिफे हुए कर्तव्य वातावरण पर नहीं होगी तथा उप समय पर भी बने दिवालिफे आगमन न हो । समझनेवाले स्वीकृति के बाद किंतु उक्त रह होनेसे पहिले किये गये हों ।

बहाल होना (Discharge).

दफा ४१ बहाल होना

(१) दिवालिफे करार दिये जानेके बाद किसी समय भी लेकिन उस दिवालिफे के अन्तर्गत जो अदालतने दी हो, दिवालिफे बहाल होनेकी दरखास्त अदालतने दे सकती है और अदालत कोई दिन उस दरखास्त तथा उस पर किये जाने वाले एतराजोंको सुननेके लिये मुकदमे करेगी तथा उसकी सूचना नियत किये हुए दफा पर दीजावेगी ।

(२) इस दफा के नियमोंका ध्यान रखते हुए कर्तव्यवालोंके एतराजोंको सुननेके पश्चात् तथा जिनमें रिहोवर नियुक्त किया गया हो उसमें उसकी रिपोर्ट देखनेके पश्चात् अदालतको अधिकार है कि यह :—

- (ए) पूर्ण रूपसे बहाल करनेका हुक्म दे सकती है या उसके देनेसे इन्कार कर सकती है, या
- (बी) या किसी नियत समयके लिये बहाल होने वाले हुक्मको कार्यान्वित होनेसे रथगित कर सकती है, या
- (सी) या उन शर्तों साथ बहाल कर सकती है जो उसे उसकी आयन्दा आमदनीके सम्बन्धमें या आयन्दा मिलने वाली आयदादके सम्बन्धमें देना हों ।

व्याख्या—

इस दफा में दिवालिफे के बहाल किये जानेका उद्देश्य है किन्तु एतके अनुसार दिवालिफे की अधिकार था कि वह दिवालिफे करार दिये जानेका हुक्म होनेके पश्चात् किसी समय भी बहाल होनेकी दरखास्त दे सकता था परन्तु इस एवमके अनुसार दिवालिफे उम्मीद दिवालिफे अन्तर्गत बहाल होनेकी दरखास्त दे सकता है जो कि दिवालिफे करार दिये जाने समय अदालतने उम्मीद दी हो । बहाल होनेकी विधि इस प्रकार समझना चाहिये कि पहिले दिवालिफे अदालत द्वारा निर्धारित किये हुए अथवा दफा २० (१) के अनुसार उसके द्वारा बहाल हुए समयके अन्तर्गत बहाल होनेकी दरखास्त देगा । ऐसी

दरबार की जाने पर अदायत मोई तारीख उनके समनेके लिये नियत करीगें तथा इस नियतकी हुई तारीखकी सूचना कर्तव्यार्थको निर्धारित दम पर दी जानेगी तब कर्तव्यवाहक विवेक उस दरबारके लिये सुचारु तथा नियुक्त किये हुए रितीनका रिपोर्ट देकर अदालत अपना हुक्म देवेगी। अदालत अपने हुक्म तीन प्रकारका इस सम्बन्धमें दे सकती है जिनमें उद्देश्य उपद्रव (२) के अन्त (९), (बी) व (सी) में किया गया है अर्थात् (१) या तो दिवालिगो बिल्कुल बहाल कर देगी या बहाल करनेसे इनकार कर देगी, (२) बहाल नो कर देगी परन्तु साथ साथ यह पक्क लफा देगी कि बहालका हुक्म एक निषा किये हुए समयके पश्चात् प्रयोगमें आयेगा, तथा (३) किमी ऐसी शर्तों साथ उसे बहाल करेगी कि उसे अपनी आपत्तियों की रीति निर्वचन भाग या बाइस प्राप्त होने का र्थ जायदाद बहाल हो जानेके बाद भी देना पड़े। यदि कर्तव्यवाहक व कर्तव्यवाहक दायित्वान इस प्रकारका समझाना हो जावे कि वह कर्तव्यवाहक बहाल होने की दरबारत फा बगल नहीं करेगा तो ऐसा समझौता केअग्र समझना चाहिये अर्थात् ऐसी समझौतेके हो जाने पर भी वह कर्तव्यवाहक बहाल की दरबारतका विशेष कर सकता है देखो—20 Bom 616

उपद्रव (२) बहालका हुक्म देना अदालतका इच्छा पर निर्भर है उसके देनेके लिये वह बाध्य नहीं है। दफा ४२ में इन बातोंका उल्लेख है जिनके होने पर अदालत बिल्कुल बहाल देनेका हुक्म नहीं देवेगी यदि बहालका हुक्म देनेसे इनकार कर दिया जाये तो यह नहीं समझना चाहिये कि दिवालिगो अगर देनेका हुक्म मसूख कर दिया गया है। दिवालिगो व उस समय तक जारी रहेगा जब तक कि दिवालिगो की मसूखीका हुक्म गफा कोर पर न दे दिया जावे देखो—55 M. L. J. 54

बगल होनेके हुक्मको रणगित किये जानेसे अभिप्राय यह है कि किसी नियत समय तकके लिये दिवालिगो बहाल न समझा जायेगा किन्तु उस समयके यहीन होनेके पश्चात् दिवालिगो बहाल समझा जायेगा। जितने समयके लिये अदालत बहाल होनेके हुक्मको रणगित करना चाहे उतना उद्देश्य अपने हुक्ममें कर देना चाहिये अर्थात् अनिश्चित समयके लिये उस रणगित न करना चाहिये जैसा कि क्रास (बी) से प्रकट होता है। यदि बहाल होनेकी दरबारत नाममात्र किये जायेके बाद रक्षा (Protection) की दरबारत दी जावे तो अदालत उस पर बहुत मोच समझ कर हुक्म देगा। यदि दिवालिगोने वेसमके वृक्ष तथा नर्ममानीसे तमाम कर्जें लाने लिये हों तो ऐसी दशामें अदालतको चाहिये कि वह कर्तव्यवाहको ऐसा मौका मिलने दे जिसमें वह बर्हमान दिवालिगो को उसके कर्जोंका कूल देसके अर्थात् इसे कैद कर सके। रक्षा हुक्मको देना न देना बिल्कुल अदालतके हाथ है जब कि अदालतको यह मालूम हो कि बिजुल खर्चा आदि करके दिवालिगो वसनेका मौका कारदारकी मुलायम गया है तथा कर्तव्यवाहको कर्जोंका बिल्कुल भ्रान न देने हुए रुपया बराबर दिया गया है तो अदालतको चाहिये कि वह रक्षाका हुक्म देनेसे इनकार कर देवे देखो—40 Bom 461.

दिवालिगोने बहाल होनेमें बाधगी कर्तव्य तथा नादमें प्राप्त होने वाली जायदादके सम्बन्धमें शर्तें लगा देनेसे अभिप्राय यह है कि जिसमें कर्तव्यवाहको यदि मौका हो तो कुछ अधिक प्राप्त हो सके। शर्तें साथ बहाल होनेका अभिप्राय यह नहीं है कि दिवालिगो तब कर्तव्यवाह समझ दे गये दम्भी कारण बाधम जाने वाला कर्तव्यवाह भी अपने कर्जोंको लायित कर सकता है देखो—A. I. R. 1925 Pat 438

दफा ४२ पूर्ण रूपसे बहाल करनेका हुक्म अदालत द्वारा न दिये जानेके कारण

(१) अदालत नीचे दी हुई बातोंमें से किसी एकको भी सार्वित होने पर दफा ४१ के अनुसार पूर्ण रूपसे बहाल करनेका हुक्म नहीं देवेगी:—

(२) यह कि दिवालिगोकी जायदादकी क्रीमस उसके बिना महफूज कर्जोंके लिये रुपयों आठ आना में अरा कानके लायक नहीं हैं, जयतक कि दिवालिगो अदालतको

यह यकीन न दिला देवे कि उसकी जायदादसे बिला महफूज कर्जोंकी आधी अदा-यगीका इन्तजामका न हो सकता ऐसे कारणोंसे होगया है जिनके लिये वह उचित रीतिसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जासकता है।

(धी) यह कि दिवालियेके पास यह हिसाबकी किताबें नहीं हैं जो अमूमन उसके ऐसे रोजगार करने वालोंके पास रहना उचित है और जिनसे उसके रोजगारका तथा माली हालतका हाल काफ़ी तौरसे दिवालिये कमनेसे तीन साल पहिले तकका मालूम होसकता है।

(सी) यह कि दिवालिया अपनेको दिवालिया जानते हुए भी रोजगार करता रहा हो।

(डी) यह कि इस एन्टक अनुसार साबित होने वाला कोई कर्म दिवालिपने यह न जानते हुए लिया हो कि उसे उस कर्जेका अदा करनेका उचित अवसर न मिलेगा इसके साबित करनेका बार सुधूत दिवालिया पर होगा।

(ई) यह कि दिवालिया भले प्रकार यह नहीं साबित कर सका है कि उसके लहनेमें कमी क्यों हुई या उसके लहनेसे उसके कर्जोंकी अदायगी क्यों नहीं हो पाई।

(एफ) यह कि उसका दिवाला उसके जल्द ब ख़तरनाक सौदाँके करनेके कारण हुआ है या उससे दिवाला निकलनेमें मदद मिली है या उसके अनुचित रूपसे बहुत अधिक खर्च करनेके कारण हुआ है या जुधा ख़ेलनेके कारण या अपने व्यापारके अनुचित रूपसे अदबालना करनेके कारण हुआ है।

(जी) यह कि दिवालको दरखास्त दिये जानेके पहिले तीन माहके अन्दर जबकि वह अपने कर्जोंको अदा नहीं कर सकता था उसने किसी खास कर्जद्वाराको देजा तौर पर तर्जिह दी हो।

(एच) यह कि दिवालिया इनसे पहिले भी दिवालिया करार दिया जाचुका है या वह कोई समझौता या तसफिया अपने कर्जद्वाराहोंके साथ कर चुका है।

(आई) यह कि दिवालिपने अपनी जायदाद या उसका कोई हिस्सा छिपाया है या हटा दिया है या और किसी प्रकारकी धोखादेही या अमानतमें सयानतका धोख़ाका काम किया है।

(२) इस दफाके लिये रिखीवरकी रिपोर्ट शहादत मानी जावेगी और अदालतको अधिकार है कि उसमें दी हुई किसी बातकी सच्चाईको मानले।

(३) अदालतको अधिकार है कि बहाल करनेके हुदमको स्थगित करने या उसके साथ शर्तें लगाने, दोनों बातोंको एक साथ भी कर सकती है।

व्याख्या—

इस दफामें दिवालियेके व्यापार प्राग किये हुए वह सब साम दिलसवेगये हैं जिनके सन्नि होनेसे अदायत दिवालियेकी पूर्ण रूपसे बहाल करनेमें तैयार नहीं होवेगी।

कात (५) से लया कर कात (जारी) तक जो बने दिखलाई गई है वह सब एक प्रकारसे दिवालयीकी बदौलती भेजदोरी तथा बुनपयोग के काम हैं यदि दिवालयी इन कामोंमें किया कामका बोरी समझा जावे तो वह कानून दिवालयी से इन बाने प्रायदोरी कावेन खसता जावेगा । इस दफाका सम्बन्ध केवल दफा ४१ (२) के प्राज (५) के साथ समझना चाहिये अर्थात् इस दफामें बतलाई हुई बातोंमें होने पर कात (५) के अनुसार पूर्ण बहालका हुक्म नहीं दिया जावेगा । इस दफाका प्रभाव दफा ४१ (२) के प्राज (नी) व (छी) पर नहीं समझना चाहिये अर्थात् इस दफामें बतलाई हुई बातोंके साहित होनेके कारण बहाल हुनमें जहाँ या काई अवधि न बहा देना चाहिये देखो—39 I. C. 916.

जब कि दिवालयीके एहमसे उसका छापा बर्जों में न चकाया जायजना हो और दिवालयीके कबोकी बसूलमें गिनीयके छिये बराबरे बाकी हो तो ऐसे दिवालयीके बहाल करनेमें इनकार कर देनेका हुक्म उचित हुक्म है देखो—A. I. R. 1925 Oudh. 112.

दिवान किताब न रखने पर ही पूर्ण बहाल किया जाना ठीका जायजता है देखो—A. I. R. 1927 All. 352 जब कि किसी अगलत दिवालयीमें किसी दिवालयीकी बहालका हुक्म देनेमें इनकार कर दिया हो तो वह अगलत करने में फासिने हुक्मकी बदल नहीं करता है देखो—32 I. C. 575 परतु इससे यह न समझना चाहिये कि यदि बहाने हुनमें इनकार कियेका हुक्म तबैव आरंभ बना देगा देखो—A. I. R. 1925 Mad. 915.

सिटीयरकी रिपोर्ट एक प्रकारकी साक्षरत समझी जावेगी और जब तक कि कोई बात उसके विरुद्ध न दिखलाई जावे वह रिपोर्ट ठीक समझी जावेगी देखो—36 I. C. 906, 37 All 429 यदि किसी दिवालयीके मामलेमें कौनसे आठ बाने हुन दिये गये हों और कर्त बहाल होनेका हुक्म एक अर्थ तक विरुद्ध रहे दे तो जमकर देखा हुक्म विरुद्ध कानूनक विरुद्ध है देखो—A. I. R. 1928 Oudh 263.

बहालका हुक्म देने समय केवल यह मिल देना नहीं है कि सिटीयरकी रिपोर्टमें कोई बात दिवालयीके बहालमें बराबर चलन बाधा नहीं है जहाँ इस बातका निश्चात कर लेना चाहिये कि दाखल दिवालयीकी कोई बहानेकी वनने अथवा रजम वसूल हुनमें बाधा नही पड़ा है अर्थात् दिवालयीकी वेबमेंसे ऐसा हुका है । बिना इस किस्मकी समबोत बिने हुए अगलतका फैसला कानूनक उचित नहीं है । देखा—A. I. R. 1928 Cal 843.

उपदफा (३) एक प्रकारसे दफा ४१ में सम्मिलितकी जानेके योग्य है क्योंकि उसमें यह बतलया गया है कि जहाँ कानून व अवधिकी बहानेमें हुक्म साथ २ गी दिये जायजने हैं अर्थात् दफा ४१ (२) के प्राज (नी) व (छी) की फासियाएँ एक साथी की जायजती हैं ।

दफा ४३ बहालकी दाखलास्त न दिये जानेपर दिवालयीकरार दिये जाने वाले हुक्मकी मंजूरी

(१) अगर दिवालयी बहालकी दाखलास्त सुने जाने वाले दिनेया अदालतसे मुकरर किये हुए यादके किसी दिन पर हाजिर न हो या दिवालयी अदालतसे ही हुई मिश्रादकी अन्दर बहाल होनेकी दाखलास्त न देवे तो दिवालयी करार दिये जाने वाला हुक्म मंजूर कर दिया जावेगा और उसके बाद दफा ३७ की कार्रवाईका प्रयोग होगा ।

(२) जबकि कर्जदार इस हुक्मके अनुसार हिसाबतसे छोड़ा गया हो और दफा ४३ (१) के अनुसार उसके दिवालयी करार दिये जाने वाला हुक्म मंजूर कर दिया जावे तो अदालतकी अधिकार है कि अगर वह मुनासिब समझें तो कर्जदारको फिर उसी हिसाबतमें बंदे और जलका खर्चपर जिसकी सुपुर्गीकी कर्जदार इस प्रकार हुयाग दिया जावेगा उसको अपनी सुपुर्गीमें

सुपुर्दगीके हुक्मके अनुसार से लेवेगा और उस तक यह सब कार्यवाहियां जो कर्जदारकी ज्ञातके खिलाफ उसके छोड़े जानेके समय लागू थीं इस प्रकार चालू समझी जावेंगी मानो कोई दिवा-लिया क़रार दिये जानेका हुक्म दिया ही नहीं गया था ।

व्याख्या—

इस दफामें यह बात प्रकट है कि दिवालिघेके लिये बहस होनेकी दरखास्त देना अति आवश्यक है वरना वह इस एक्टके नियमोंका लाभ उठावेसे बाधित रहता आसरेगा । बहस होनेकी दरखास्त अदाकृत होना नियत लिये हुए समयके अन्दरही हो जाना चाहिये अदालत हाथी हुई मियादके समाप्त होने पर दिवालिघा अपने आपही बहाल नहीं हो जावेगा किन्तु उसके बहाल होनेके लिये अदालतका हुक्म देना आवश्यक है देखो—49 All. 201. दिवालिघेके हुक्मके मसूखी तथा नशान होनेका हुक्म दोनों (1) एक्टके अनुसार एवही चीज नहीं है देखो—A. I. R. 1925 Lah. 376. यदि दिवालिघा क़रार दिये जानेका हुक्म देने समय बहाल होनेके लिये कोई मियाद नहीं दी गई हो तो यह दफा लागू नहीं होगी और बहालकी दरखास्त न देनेके कारण दिवालिघेका हुक्म मसूख नहीं किया जावेगा देखो—A. I. R. 1926 Lah. 24.

उपदफा (१) इस दफाके अनुसार दिवालिघेका हुक्म नीचे दी हुई किसी बातके होनेपर मसूख किया जासकेगा

(१) यह कि जब दिवालिघा बहाल होने की दरखास्त देने जानेकी तारीख पर हाजिर न होवे

(२) यह कि जब वह तारीखके बाद जाने पर उस बड़ी हुई तारीखके दिन हाजिर न होवे

(३) यह कि जब दिवालिघा दफा २७ के अनुसार नियतकी हुई म्यादके अन्दर बहाल होनेकी दरखास्त न देवे ।

इस दफामें वक्तव्ये हुए नियमकी पाठ्य करनेके लिये अदालत कायदे A. I. R. 1926 Sind. 94.

इसलिये यदि दिवालिघा क़रार वक्तव्ये हुई कोईभी गलती करे तो मसूखीका हुक्म होनाका चाहिये और दिवालिघा उस समय जायना दिवालिघेके आदेश के अनुसार भी सहायता नहीं पायकता है अर्थात् मान वनकर सादिककी बर्बादी भी नहीं कर सकता है यदि दिवालिघे से गलती किसी अनिवार्य कारणकी हो तोयही होतो वह दफा १० (२) से लाभ उठा सकता है अर्थात् इसके अनुसार फिर दरखास्त दिवालिघा देसकता है देखिये 49 Mad. 935; A. I. R. 1924 Mad. 635.

अदालत इस दफा के अनुसार स्वयं करीबनी वक्तवती है तथा ऐसा करीबनाइसी जिससे दिवालिघेके हुक्ममें हासि पहुँची हो मसूखी के लिये दरखास्त देसकता है देखो—A. I. R. 1924 Mad. 635.

इस एक्टकी दफा ४३ आज्ञा कायि है और अदालत की नियतकी हुई मियादके समाप्त होनेके पश्चात् समय बढ़ानेका अधिकार नहीं है म्याद सुर्जमा के अन्दर दिवालिघा या कर्जदारका म्याद बढ़ानेकी दरखास्त देसकते हैं परन्तु नहीं ऐसा नहीं किया गया हो वहा दफा ४३ के अनुसार बर्बादीकी जानी चाहिये A. I. R. 1928 Mad. 265.

परन्तु अग्रा साहके मामलेमें यह तय हुआ था कि दिवालिघे के हुक्ममें ही हुई मियादके बाद भी समय बढ़ाया जा सकता है ।

दफा ४३ (१) दफा २७ के साथ पढ़ी जाना चाहिये और अदालत को अधिकार है, जित अधिकार की उसे कानूनी दम से वहीना चाहिये कि यदि मातृक अदाकृतने समय बढ़ादिता होतो वहभी समय बढ़ा रहने दे सिवा तबमें हाईकोर्ट एहि हुक्मका हटा नहीं सकता है देखो—1928 M. W. N. 441.

कजैस्वाद इमानज लेकर इस दफा के अनुसार दिये हुए हुक्मकी अपील करसकता है 100 I. C. 137.

आज यदि अपील मन्त्र कही जात तो यह मान लिया जावेगा कि इमानज छानाबुकी है A. I. R. 1928

दफा ४४ बहाल होनेके हुक्मका असर

(१) बहाल होनेका हुक्म दिवालियेको नीचे दी हुई बातोंसे बरी नहीं होने देगा.—

(ए) किसी सरकारी कर्जसे

(बी) धोखेबाजीसे या धोखा देकर अमानतमें खयालत करके अगर कोई कर्ज या जिम्मेदारी पैदा हुई है और जिसमें दिवालियेका भी हाथ रहा हो

(सी) अगर धोखेबाजीमें शरीक रह कर किसी कर्ज या जिम्मेदारीसे बरी होगया हो तो ऐसे कर्ज व जिम्मेदारीसे, या

(डी) अगर सन् १८६८ ई० के ज्ञायता कौजदारीकी दफा ४८८ के अनुसार कोई हुक्म परपरिशुका उसके खिलाफ दिया जावे तो ऐसे हुक्मकी जिम्मेदारीसे ।

(२) पहिली उपदफा अर्थात् ४४ (१) में दी हुई बातोंको छोड़ कर दिवालिया बहाल होनेके हुक्म हो जाने पर और सब कर्जोंसे मुक्त हो जायगा जो इस एक्टके अनुसार साबित लिये जासकते हैं ।

(३) बहाल होने वाले हुक्मसे ऐसा व्यक्ति बरी जिम्मा नहीं होगा जो दिवालिकी दर-फ्यास्त बिये जाते समय दिवालियेका साक्षी या संयुक्त ट्रस्टी रहा हो या जिसकी दिवालियाके साथ संयुक्त जिम्मेदारी या संयुक्त मुआहिदा रहा हो या जो दिवालियेके लिये जामिनदार रहा हो ।

व्याख्या—

बहाल होनेके हुक्म दिये जानेपर दिवालिया उन सब कर्जोंसे मुक्त होगाता है जो कानून दिवालियेके अनुसार साबित किये जासकते हैं परन्तु वह ऐसे कर्जोंसे मुक्त उस समयभी नहीं मगता जबकि भिनका वल्लेख इस दफाकी उपदफा (१) के खान (ए), (बी), (सी) व (डी) में किया गया है मुक्त होजाने से अभिप्राय यह है कि वह कर्ज समाप्त समझे जावेंगे । इस एक्टके अनुसार साबित किये जाने योग्य कर्जोंका वल्लेख दफा ३६ में किया गया है ।

यदि किसीने किसी कर्जको रद्दी न वसूल न किये जाने योग्य समझकर जोड़ दिया होतो दिवालिया बहाल होने पर ऐसे कर्जको वसूल कर सकता है व उसको मुनकिल कर सकता है, ३१ All. 223. यदि बहाल होनेकी दरखास्त एक बार नामखार करदी गई हो तोभी दिवालिया फिर दूसरी दरखास्त दूसरी बातों पर इसके लिये दे सकता है एक्टमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे यह मान लिया जावे कि बादकी बहाल होने की दरखास्त नामखार किये जानेका प्रमाण आगम तक कायम रहेगा देखो—A. I. R. 1925 Mad 915.

दफा ४४ (१) के अनुसार दिवालियेका बहाल होनेका हुक्म होजाने के पश्चात् उन सब कर्जोंसे मुक्त समझना चाहिये जो इस एक्टके अन्तर्गत साबित किये जासकते हैं । यदि किसी कर्जस्वाहने जान बूझ कर साबित करने योग्य अपने कर्जको साबित न किया हो तभी इससे मुक्त नहीं हो सकता है, देखो—A. I. R. 1928 Nag 336

जामिनदार अपने अमानतकी जिम्मेदारी साबित कर सकता है । यदि मुद्दै किसी कर्जदारका जामिनदार होने और वह कर्जदार दिवालिया प्रचार दिये जानेके पश्चात् दफा ४१ के अनुसार बहाल कर दिया गया हो तथा इसके बाद कर्जस्वाह उस जामिनदारसे अपना कर्जा वसूल करले तो वह जामिनदार बहाल हुए कर्जदारके विरुद्ध अपना अपना वाणिज्य पानेके लिये दावा करे तो यह तय किया गया कि कुछेक वह कर्ज दफा ३६ (२) के अन्तर्गत नहीं आता है अतः कर्जदार (बहाल किया हुआ दिवालिया) उस कर्जकी जिम्मेदारीसे दफा ४४ के अनुसार मुक्त हायुक्त है, देखो—A. I. R. 1928 All. 306.

तीसरा प्रकरण

कजोंके साधित करनेका तरीका (जायदादका प्रबन्ध)

धृषा ४५ आइन्दा अदा होने वाले कर्जों

अगर किसी कर्जखाहका रुपया कर्जदारसे लेना हो लेकिन वह दिवालिया करार दिये जाते समय बाजिमुख अदा न हो बल्कि आयन्दा चल कर उसकी अदायगी होना चाहिये तो भी उस कर्जखाहको अधिकार है कि वह अपना कर्ज इस प्रकार साधित करे जैसे कि उसका कर्ज उम्मीदवार मिलना चाहिये और उसको दिवालियाकी जायदादसे हिस्सा रसदी दूसरे कर्जखाहों की तरह विलम्बाया जासकता है लेकिन उसके कर्जकी तादादसे उतना रुपया कम कर दिया जावेगा जो ६) रुपया सैकड़ा माहवारी सूदके हिसाबसे रसदी बैंटनेक वकसे उसके कर्जकी असली अदायगीके वक्त तक निकलेगा ।

व्याख्या—

इस धृषाके अनुसार भविष्यके कर्जों पर भी हिस्सा रसदा प्राप्त हो सकता है अर्थात् यदि किसी कर्जखाहका कोई कर्ज दिवालियासे लेना हो परन्तु वह कर्ज दिवालिया करार दिये जाते समय बसूल न किया जासकता हो परन्तु उसके बाद भविष्यमें वह कर्ज बसूल किये जाने योग्य होवे तो भी कर्जखाह अपने उस कर्जसे मौजूदा कर्जोंभा भानि इस एकटके अनुसार साधित कर सकता है परन्तु उसकी तादाद इस प्रकार निमित्तकी जावेगी कि पहिले यह देखना चाहिये, कर्जकी तादाद उस तारीख पर जबकि वह बाजिमुखअदा है क्या होगी अर्थात् मय व्यापक उस तारीख पर कर्जखाहका कितना रुपया दिवालियासे मिलना चाहिये उसके पश्चात् यह देखना चाहिये कि क. रुपया सैकड़ा साठवानी दरसे रसदी बांटे जानेवाले तारीख से असली अदायगाई तारीख तक कितना व्याज होगा तब माइलकी रकमसे वह व्याजकी रकम निम्नलिखित देना चाहिये और बाकी बचा हुई रकमके हिसाबन हिस्सा रसदा मिलना चाहिये ।

धृषा ४६ आपसका व्यवहार व मुजरई

जब कि दिवालिया व किसी कर्जखाहके दूरमियान आपसका व्यवहार रहा हो व दोनों का लेना देना होवे और इस एकटके अनुसार वह कर्ज साधित किया जा रहा हो तो इस बातका हिसाब किताब किया जावेगा कि एक फरीकको दूसरे फरीकसे इस व्यवहारके सम्बन्धमें क्या लेना देना है और एकका लेना उसके दोनोंसे घटा दिया जावेगा और उसके बाद जो रुपया देना लेना चलगा बचल वही एक दूसरेसे पानेका मुस्तहक होगा ।

व्याख्या—

यदि किसी कर्जखाह व दिवालिया दोनोंके एक दूसरेसे लेना देना होवे या ऐसी दशामें दोनोंके लामार्थे इस दशामें यह चलनाया गया है कि लम्बमस दोनो रकम पठा कर या रकम बच उसीकी हिस्सा रसदी या बसूलके लिये असली कर्ज समझना चाहिये । वषाक बाद दिवालियाका कर्ज उमल पूरा बसूल कर लिया जावे परन्तु उस उमल वक्त पर जोर कर्ज-

बैंकोंकी भांति केवल हिस्सा रखी ही दिया जावे तो उसका नुकसान रहेगा । इसी प्रकार यदि कर्जस्वाह अपने कर्जों पर हिस्सा रखी छे लिये परन्तु उसे दिवाळियेका कर्ज अदा न करना पड़े तो दिवाळियेका लहना कम वसूल हो सकेगा । इस तार पर यदि किसी कर्जस्वाहका कर्ज उसके देनेसे अधिक होवे तो वह अपने इस अधिक कर्जोंके लिये हिस्सा रखी दिवाळियेकी जायदादसे और कर्जस्वाहोंकी भांति भागिया परन्तु यदि उसका देना उसके कर्जोंसे अधिक हो तो उसको वह अधिक निकलती हुई रकम रिसीवर या अदालतमें देना पड़ेगी । समुक्त कर्जोंकी छुजवाई जेठे कर्जके सम्बन्धमें नहीं की जासकती है जैसे कि यदि किसी बैंकके डिपॉजिटर्सने छुआछेह पर समुक्त बन्नेरी बिना पर नमिशकी हो और उनमेंसे किसी एक छुआछेहका कुछ बचप बँकमें समा हो तथा वह चाहे कि उस बचपकी छुजवाई दावेमें कर दी जावे तो यह छुजवाई इस बिना पर नहीं की जायकेगी कि हिस्सा दोनो, दो प्रकार है प्रकृ दूरसे छेन देनेके तौर पर नहीं है, देना—45 Bom. 1219.

यह दफा उसी समय लागू होगी जबकि फ्रांसेनके दायियाय एक दूसरेसे छेने देनेका व्यवहार रहा हो देखो—A. I. R. 1925 Sindh 158.

हिस्सा होजानेके बाद छुजवाई होना चाहिये । इस दफामें यह नहीं बतलाया गया है कि किंत तारीख तक हिस्सा क्लियर होना चाहिये परन्तु यह प्रकट होता है कि हिस्सा उस तारीख तकका होना चाहिये जबकि रखी बांटी जाने वाली होवे या उस समय तक होना चाहिये जबकि कर्जों साधित किया जाने वाला हो ।

दफा ४७ महफूज कर्जस्वाह

(१) जबकि महफूज कर्जस्वाह अपनी जमानत वसूल करले तो वह बाद् मुजरारि उस कुल रुपयोंके जो उसे जमानतसे वसूल होचुका है अपने बच्चे हुए कर्जोंको साधित कर सकता है ।

(२) जबकि महफूज कर्जस्वाह अपनी जमानतको और सब कर्जस्वाहोंके साथ फायदा पठानेके लिये छोड़ देवे तो वह अपने कुल कर्जोंके साधित करनेका मुस्तहक है ।

(३) जबकि महफूज कर्जस्वाहने न तो अपनी जमानत वसूलकी और न उसको छोड़ताही है तो वह सूचीमें अपना कर्ज लिखवानेसे पहिले अपने कर्जोंका ब्योरा साधित करेगा और वह कीमत भी देगा जिसका उस अन्दाजा है और उस वक्त उसी रुपये पर रखी पानेका मुस्तहक होगा जो उसके असली कर्जोंमेंसे अन्दाजा लगाई हुई कीमत घटानेके बाद बचे ।

(४) जबकि जमानतकी कीमतका अन्दाजा इस प्रकार लगाया जावे तो अदालतकी अधिकार होगा कि वह वसूलीसे पहिले किसी समय उस कर्जस्वाहकी अन्दाजा लगाई हुई कीमतको देकर उस जमानतको छुड़ा लिये ।

(५) जबकि कर्जस्वाह अपने जमानतकी कीमतका अन्दाजा लगानेके बाद उस जमानतमें रुपया वसूल करले तो इस प्रकार जो रुपया वसूल किया जायेगा वही जायदादकी कीमत समझी जायेगी वजाय उस कीमतके जो कर्जस्वाहने उसकी पहिले लगाई हो और वह संशोधित कीमत सब मामलोंके लिये मानी जायेगी ।

(६) जबकि महफूज कर्जस्वाह इस दफाके अनुसार कार्रवाई अमलमें न लाये तो उसको वसूलीमेंसे कोई हिस्सा रखी नहीं मिलेगा ।

व्याख्या—

इस दफामें महफूज कर्जस्वाहके उन हकोंका वर्णन है जो वह अपनी जमानतके सम्बन्धमें कर सकता है तथा उसके

उन इकाईका भी वर्णन है जिसके अनुसार वह दिवालियेकी जायदादसे हिरा राखी प्राप्त कर सकता है। इस बातका रहना चाहिये कि यह दफा केवल उहीं कर्जाल्वाहोंके लिये है जो दासतब महजून कर्जाल्वाह है लेकिन जबकि महजून होनेका प्रश्न अभिविचन देने तो पहिले यह प्रश्न तय कर दिया जाना चाहिये तब यह दफा लागू हो सकेगी देखते।
A. I. R. 1923 All. 159

महजून कर्जाल्वाहके यह हक समझना चाहिये कि, — या

- (१) वह अपने जमानतदारी पर भरोसा कर सकता है व अपना कर्ज न साबित करे, या
- (२) वह अपनी जमानत बसूत कर लेवे उसके पश्चात् बचे हुए रुपयोंको साबित करे यदि कुछ निकलते हों,
- (३) वह अपनी जमानत छोड़ देवे व अपना पूरा कर्ज साबित करे, या
- (४) वह अपनी जमानतकी कीमतका अन्दाजा लगा देवे तथा उससे अधिक जो रकम उसकी निकलनी हो साबित करे पशु ऐसी दशमें उनकी जदासा लयाई हुई कीमत उसे दी जाएर उगकी जमानत जून नामकेगी। दिवालियेकी वरिवाईका कोई प्रभाव महजून कर्जाल्वाहके कर्ज पर नहीं पड़ता है देखते—
A. I. R. 1923 All. 159. महजून कर्जाल्वाह (Secured creditor) की परिभाषा दफा २ (१) कानून (ई) में दी गई है। जमानतकी वसूलीसे यह तात्पर्य है कि वह जापदाद में बच जावे व उसकी बिक्रीकी कीमत के ली जावे देखते— 41 All. 481.

उपदफा (२) जमानतका छोड़ना या न छोड़ना महजून कर्जाल्वाहकी इच्छा पर निर्भर है वह अपनी जमानत छोड़नेके बिना बाध्य नहीं है यदि लिखनेके किसी महजून कर्जाल्वाह (मुनैडिन) की यह नोटिस दिया हो कि वह जापदादकी बिक्री करके बचनना चाहता है व मुनैडिन इस पर खामोश रहा हो तो उसकी इस खामोशीसे यह नहीं मान लिया जावे कि उसने अपनी जमानत छोड़ी है देखते—47 Mad. 603 इस प्रकार जमानतका छोड़ा जाना दूसरे बावों या भावों नहीं माना जातकेगा। निम्न महजून कर्जाल्वाहको चाहिये कि वह अपने आप जमानतको छोड़नेकी इजाजत देवे। इस दफा महजून कर्जाल्वाहके कर्जसे तात्पर्य उसके उम कर्जका समझना चाहिये निम्नकी जमानत है, यदि उसका कोई बिक्री महजून कर्जों में होवे तो वह बिक्री लिहाज इस दफाके आर कर्जाल्वाहोंके कर्जोंकी तरह साबित किया जायकेगा केवल महजून कर्जों केलिये वह इस दफामें बतलाये हुए नियमोंका प्रयोग कर सकता है यदि वह उसे जमानतकी कीमतसे अधिक समझता हो।

दफा ४८ सूद

(१) अगर कोई कर्ज या रुपया जो कर्जदारके ज़िम्मे उस धन निकलता हो जबकि यह दिवालिया क़ारार दिया गया हो और जो इस एक्टके अनुसार साबित किया जासकता है तबकि उसके लिये कोई सूद मुकर्रर नहीं किया गया है और न तयशी हुआ है तो कर्जाल्वाह ६) रुपय सैकड़ा सालानासे अधिक सूद साबित नहीं कर सकता है।

- (ए) जबकि कर्ज या रुपया किसी दस्तावेजके आधार पर किसी खास समय अदा होना चाहिये या तो सूद उस अदायगीके समयसे दिवालिया क़ारार दिये जानेके समय तक (अगर कहे हुए छः रुपय सैकड़ा सालानाके या हिसाबसे मिलेगा)
- (बी) जबकि कर्ज या रुपया किसी दूसरी सूतमें अदा होना चाहिये या और नोटिसके अखिरिये उसकी अदायगीके लिये कर्जदारसे कहा गया हो कि तुमको सूद अदा

करना पड़ेगा तो नोटिसकी तारीखसे सूद उस वक्त तक मिलेगा जबकि कर्जदार दिवालिया करार दिया जाय ।

(२) जबकि कोई कर्ज इस पक्षके अनुसार साबित किया जा चुका हो और उसमें सूद मिलित हो या सूदकी जगह कोई और मुनाफा लगाया गया हो तो हिस्सा रसदी देते समय वह सूद मुनाफा ६) रुपया सैकड़ा सालानाके हिसाबसे लगाया जावेगा परन्तु उस सूदमें जबकि और व कर्ज बूट तौर पर दिवालियेकी जायदादकी कीमतसे अदा किये जा चुके हो वचे हुए रुपयोंसे कर्जदारके असली सूदकी अदायगी होगी चाहे वह इससे अधिक दरका होवे ।

व्याख्या—

इस १४वें यह बतलाया गया है कि सूद किम दरसे लगाया जाना चाहिये ।

उपदफा (१) यदि कोई सूद न ठाढ़ हो तो ६) रुपया सैकड़ा सालानाकी दरसे अधिक सूद नहीं लगाया जाना चाहिये । जबकि कोई कर्ज किसी खास समय पर किसी दस्तावेजके अनुसार अदा किया जाना चाहिये या तो सूद उस अदायगीके समयसे दिवालिया करार दिये जाते समय तक ७) रुपया सैकड़ाकी दरसे लगाया जावेगा इसी प्रकार जबकि जो और किसी प्रकारसे अदा किया जाने वाला होवे तथा कर्जदारको सूद अदा करनेके वास्तव नोटिस दिया गया हो तो उस नोटिसकी तारीखसे दिवालिया करार दिये जाते समय तक ७ रुपया सैकड़ा सालानाकी दरसे सूद मिलेगा ।

इस उपदफाके ब्राज (५) व (६) दोनोंहीके अनुसार सूद दिवालिया करार दिये जानेके हुक्म तक दिया जा सकेगा ।

ब्राज (६) में जो नोटिसका जिक्र है वह लिखित नोटिस होना चाहिये जबानी नोटिससे काम नहीं चलेगा ।

उपदफा (२) के अनुसार हिस्सा रसदी असल रकम व उस मूद या मुनाफाईके अनुसार मिल सकेगी जो रुपया सैकड़ा सालानाके हिसाबसे निकले अर्थात् यदि किसी कर्जद्वारा अपने अपना कर्जा साबित करते समय कुछ असल रकम दिखाई हो तथा कुछ सूद दिखाया गया हो और वह सूद ६) रुपया सैकड़ा सालानाकी दरसे अधिक हो तो हिस्सा रसदी देते समय उसकी असल रकम व उस पर ६) रुपया सैकड़ा सालानाकी दरसे जो सूद होता हो उसीके अनुसार उससे हिस्सा रसदी मिल सकेगी परन्तु इस उपदफामें यह भी सक्रम कर दिया गया है कि अगर दिवालियेकी जायदादमें उसके सब में पूर्ण रूपसे अदा किये जा चुके व उसके बाद कुछ कालिख रकम बचे तो उस कालिख रकमसे कर्जद्वाराके असली सूदकी अदायगीकी जायेगी जो कि हिस्सा रसदीके समय उसके कर्जसे कम कर दी गई हो इस प्रकार कर्जद्वारा कालिख रकम निकलने पर घटेमें नहीं लगे जावेगा । इस दफामें उर्ही कर्जोंके सूदका जिक्र है जो दिवालिये पर होवे वन कर्जोंका जिक्र नहीं है जो दिवालियेको अपने कर्जदारोंसे बसूल करता हो इस कारण दिवालियेके कर्जदारों यह बतये रामझना चाहिये कि यह निमित्तकी हुई दरके अनुसारही सूद अदा करे देखो—18 I. C. 205

मदकूम कर्जद्वारा (Secured creditor) को अधिकार है कि वह निमित्तकी हुई दरके अनुसार अपना सूद दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मके पश्चात् कर्ज बसूल होनेकी तारीख तक ले सके देखो—A. I. R. 1924 Rang 352. दिवालिया करार दिये जानेकी तारीखके बाद अदायग ६) रुपया सैकड़ाकी दरसे अधिकका सूद नहीं दिया जा सकेगा—A. I. R. 1926 All 361.

दफा ४९ साबित करनेका तरीका

(१) इस पक्षके अनुसार कर्ज साबित करनेके लिये कर्जकी तारीखमें हलफनामा अदा-
लतमें दाखिल किया जासकता है या वस्तुस्थिति रजिस्ट्रीके भेजा जासकता है ।

ह्राप मामला रख हुआ हो तो कर्जदारके दख्खामस्त देने पर अदालत ऊपरकी तरह सहकीकात फरक सूचीके इस्तख्वाफकी खारिज कर सकती है या कर्जको घटा सकती है ।

व्याख्या—

इस दफ्ते अदालत उस अधिकारका वर्णन है जिसके अनुसार वह सूचाम दिसागये हुए कर्जों। सूचाम दया सकती है या उसे कम कर सकती है । अदालतको चाहिये कि उस दफ्तेके अनुसार कर्जवाहें कगते समय स्वयं हो जाच कर आर उसके चाचका मार रिहारे पर न छाड देवें देखा—61 I. C 767, A. I. R 1926 Mad 1019 अर्थात् इस दफ्तेके अनुसार रितावरको अधिकार नहीं दिया गया है कि वह स्वयंही रिता वर्जित रह वगद अमरा सूचामे हगदे ।

अदालत दिवालियाको चाहिये कि वह कर्जदैनकी उपस्थितिमें या उनका अधिन सूचाम दिवे जाने पर वचात् कानूनन इस प्रश्नकी तय करे कि सूचीमें रिता नामको बढाना या घटाना चाहिये अथवा नहीं । अदालत बिना एसा रख हुए नाम बढा या घटा नहीं सकती है देखो—अमीरखन्दा बन्नाम अनुवृत्तवद 1. I. R 1926 Cal 160

जब कि सब कर्जवाहें समाप्तकी आचुके और वह फर्गन जिसको हानि पहुँच रही हो सब कारवाहें कर चुका हो तो कर्जवाहें समाप्त हो जानेके बाद सूचा नहीं सुगगी जामकती है देखो—51 I. C. 55 इस दफ्तेमें यह प्रकट है कि अदालतको अपने आपही इस दफ्तेके अनुसार कर्जवाहें न करना चाहिये किन्तु रिता न रिनाफ दख्खाल दून पर इस दफ्तेके अनुसार कर्जवाहें करना चाहिये ऐसी दख्खामस्त उपदफा (१) के अनुसार रितावरके हाग तथा उपदफा (२) में रिती वर्जकराह या कर्जदार हाशरी जाना चाहिये । इस दफ्तेके अनुसार कर्जवाहें करनेसे पहिले अदालतको चाहिये कि वह कर्जमें सम्मन्ध रखन वाले कर्जदारकी सूचना देवे जिसमें कि उसके निम्नक्त बाई हुकम बिना उसको सूचना मिल हुए न रिता जासके । यदि कोई तमाशे वर्जो बिना जाने हुए सूचीमें दर्ज हो गया हो तो उसका दर्ज हो जाना इस दफ्तेके अनुसार अनुचित है और इसी कारण उनको सूचीसे निपात्त दिया जाना चाहिये । एर कर्जकराह दूसर वर्जकराहके रजोस बिशय कर सकता है देखो—37 All 252.

आकिशक रितावरका कर्जकराहानकी सूची तैयार करना कोई कानूनी या आनिग निर्णय नहीं है बिशय कर उन मामलोंके लिये जिनमें छगङ्गा हो और इसीलिये उसके सूचा तैयार कर देनेमें अदालतमें अधिकार सूचामे वर्जो निराल देनके सम्मन्धमें जाता नहीं हैग दखो—45 I. C 67. बाद इस दफ्तेके अनुसार सूचाम बाई कर्ज निराल दिया जावे या कम कर दिया जाव तो उसकी अपील दफा ७५ (२) व सूचा न० १ के अनुसारही जासकेगा देखो—A. I. R 1926 All. 361

पहिले किये हुए सौदों (Transactions) या कारवाहियों पर दिवालेका असर

दफा ५१ इजरायमें कर्जकराहानके हक्कोमें रुकावट

(१) जबकि कर्जदारकी जायदादके खिलाफ डिफ्टी जरीकी आचुकी है तो रितावरके मुकाबिले किसी शख्सको उस इजराय में लाभ उठानेका हक्क न होगा परन्तु दिवालीमें दख्खामस्तके लिय जनेसे पहिले इजरायके खिलसिलेमें नीलाम या और किसी तरीक़ेस जो अस्सारा कर्जदार का हथ्य अ.रा हो उसमें यह बात ल.गू न होगी ।

(२) अगर कोई महफूज कर्जहवाह अपनी डिक्ली ज.यदादके खिलाफ जारी कराये तो उसके अधिकारोंमें कोई असर नहीं पड़ेगा ।

(३) जो खरीदार नेकनीयतीसे हजरत द्वारा नीलाममें जायदाद खरीदे उसको रिसीवर के मुकाबले हर मामलेमें अच्छा हक पहुँचगा ।

व्याख्या—

इस दफा का अभिप्राय यह समझना चाहिये कि जजोंदारी जायदाद दिवालियों की कार्रवाई की जानेसे पश्चात् सन कर्नलवाहानके लाभार्थ बचाई जासके अर्थात् कोई कर्जहवाह दिवालियों द्वारा सन अल्लिये जनेके पश्चात् की हुई (अपनी कार्रवाईमें अनेके काम नहीं उठा सकेगा ।

इस दफासे कर्जहवाहोंके इन्तजाम बचाव पटनी है किन्तु इनकाय कर्जहवाहों अदालतके अधिकारोंमें कोई कमी नहीं पड़ती है क्योंकि वह अपने अधिकारके अनुसार इनकायकी कार्रवाई कर सकती है । इस कारण यदि अदालत किसी इमरायमें कोई जायदाद नीलाम करे तो दिवालियोंकी कार्रवाई काजाने पर वह नीलाम बन्द नहीं ठहराया जायगा देखो—A. I. R. 1925 Lah. 158. पालू ऐसी दशामें आगे बतलाई हुई दफा ५२ की परिचरिका जयोंग किया जासकेगा ।

पुनर्ने अर्थात् सन १९०७ ई० के एक्टके अनुसार रिसीवरको कोई अधिकार नहीं था कि वह डिक्लीदारसे वह बयान लेसके जो उसने दिवालिया करार दिये जाने वाले हुबसे पहिले वसूल कर लिया हो देखो—41 All 274. पालू इस एक्टके अनुसार ऐसा नहीं है दिवालियोंके द्वारा सन ले लिये जाने (Admission) के बाद रिसीवरको हस्तक्षेप करनेका अधिकार प्राप्त है उसमें पहिले जो वसूल हो चुके वह डिक्लीदारकी समझना चाहिये । इस बातको भली भाँति समझ लेना चाहिये कि दारुवास्तके लिये आन (Admission) से पहिले इनकाय नीलाममें जा सके वसूल हो चुकेगा बड़ी बच सकेगा और इस दफाका यही तात्पर्य समझना चाहिये देना—A. I. R. 1925 Mad. 224; A. I. R. 1926 Sind 199.

इस प्रकार यदि दारुवास्त लिये जानेसे पहिले (Before Admission) नीलाममें हो चुके पालू बयान बादमें वसूल हो तो यह रकम रिसीवरकी समझना चाहिये इनकाय कराने बाधा डिक्लीदार उसके पानेका हकदार न होकर देखी—A. I. R. 1925 Mad 248 में खनेदार नाकामने कामत खरीदना खीपाई बयान देदिया था और बाकी बयान जमा किये जानसे पहिले पदचूनन दिवालियों द्वारा वसूल दक्ष था तब इस मामलेमें यह तय हुआ था कि डिक्लीदारको नीलामका बयान नहीं मिलना चाहिये इस दफाके अनुसार नेवल कुर्के सनने वाले डिक्लीदारकी बयान नहीं बच सकता है किन्तु वह बयान भी बच सकता है जा दूसर डिक्लीदारोंका जानना दावानीकी दफा ७३ के अनुसार खीर हिस्सा रखीके मिलना चाहिये क्योंकि हिस्सा समी हा जानेपर सन उन डिक्लीदारोंका हो जाता है और पदचूनन उसमें कोई हक नहीं रह जाता है और इस कारण वह दिवालियोंकी कार्रवाईके सम्बन्धमें नहीं लिया जासकता है अर्थात् यदि दारुवास्त दिवालियोंके लिये जानेसे पहिले (Before Admission) किसी इनकाय डिक्लीदार द्वारा सन हिस्सा रखी लगाने वाले डिक्लीदारोंमें बट गया हो तो वह बयान भी रिसीवर पानका अधिकार नहीं होगा देखो—A. I. R. 1922 Mad 31—381 C. 512.

यदि कोई बयान कुछ होकर अदालतके हाथ आर्डर २१ रूल ५२ जानना दावानीके अनुसार आया हो पालू इस बयानको दिये जानेसे पहिले पदचूनन दिवालिया करार दिय जानेकी दारुवास्त देखी गई हो और आकिशर रिसीवर हुब समझना (Interim) रिसीवर नियुक्त कर दिया गया हो तो एसी हालतमें यह तय किया गया कि रिसीवरको उन बयानके लिये हस्तक्षेप करनेका अधिकार प्राप्त है जिसमें वह एन दिवालियोंके दफा ५२ (१) के अनुसार सन कर्जहवाहोंके लाभार्थ लिया जानके देखो—A. I. R. 1928 Sind 165. दिवालियोंके दारुवास्त ले लिये जान (Admission)

क पक्ष न कुं वगने नाठि डिक्लीटका इक कुंईरी हुई जायदाद पर नहीं पहुँचता है और वह जायदाद दिवालियाहोना नहीं रहती है तथा दिवालिया अंगर दिये जानके बाद वह रिमायन्स हो जाती है । अमेजी कानूनके अनुसार कुंई वगने वाल डिक्लीटका इक जायदाद पर हो जाता है आर एमो मागन वह कुंईरी हुई जायदादमें बच पर अपना वकै वगुन कर सक्ता है परन्तु भागवतमें ऐसा नहीं है बदाक कानूनके अनुसार कुंई कराने वाला डिक्लीटार यदि दरख्तास्त दिवालियाके श्रिये जानमे पहिले नीलाम कराके अपना रुपया न ले चुका हो ता उसका कोई इक कुंईरी हुई जायदाद पर नहीं पहुँचता और उसकी वही स्थिति समझना चाहिये जो दिवालियाके दूसरे वर्जकाहोती है आर वह नीलामकी कमिडमे केवल हिस्सा रसदाही और वकैलवाहोके साथ पासकेगा देला —44 Cal 1016

यदि दिवालियाका कोई वर्जकाह उसका रिस्त डिक्लीटो जो उसने किसी तीसरे शक्त्तके खिलाफ दावाया हो चुक जाले तो वह वर्जकाह इस कुंईमे लाभ नहीं उठा सकगा क्योंकि दिवालिया अंगर दिये जाने पर इमाग कानेका इक रिमीवरना हो जायेगा देलो—18 All 86

अस्सासा (Assets) से तात्पर्य उस चीजमे है जो इनसगमे कुंईरी हुई जायदादके मोताब होते पर वसूल होने ।

अस्सासा का वसूल होना (Realization of assets) उस वक्त मसझा जावेगा जबकि वह अस्सासाके हाथमे भाजक देलो—18 Cal 242, 28 Cal 264, 19 Mnd. 72, 9 A L J 707

यही बात नीचे दिये हुए मामलोंमें भी तयकी जाचुगी है देखी—44 Mad 100, A I R. 1923 Mad 505, 34 All 628, 101 I C 848 (Sindh.) इस 101 I. C 848 के मामलमें यह भी तय किया गया था कि यदि कुंई करनेवाली अदालत न वह अदालत जसमे रुपया कुंई किया जाने वाला होवे एकही होवे ता वह रुपया दफा ५१ (१) के अनुसार वसूल किया हुवा अमाग समझा जावेगा जो अदालत मद्रूनकी डिक्लीटके वकैल वाले डिक्लीटारके हकमें आने हुवा दावा मुल्तजिल पर दिया होवे ।

यह दफा उहा वक्त लागू होगी जब कि रुपया किसी डिक्लीटो इंगायमें वसूल किया गया हो हमलिये यदि अदालतमें कोई रुपया कमानतका अमाग हो तो उसके श्रिय यह नहीं रहा जावेगा कि वह रुपया इनसगमें वसूल किया गया है देला—31 I C 573, 19 A L J 898

उपदफा (२) यहकून वर्जकाह इस दफाते वगी है यहकून वर्जकाहके दफा वर्णन दफा ५ (२), १८ (६) आर दफा २८ में है ।

उपदफा (३) यदि किसी व्यक्तिने वेरनीयनीसे नीलाममें जायदाद ठेकी हो तो उसकी शक्त्त वर्णन इस उपदफाम दिया गया है । नकनीयनीसे नीलाममें जायदाद खर्गानने अभिप्राय यह है कि खर्गार नीलामकी गालास मय यह न मोहद हो कि मद्रून नीलामने मय दिवालिया था आर न मद्रून तोसे बोशिश करने पर वह यह माझाही कर सक्ता था कि दिवालिया हुवा मद्रूनके खिलाफ दिवा जाचुगा है दफा—34 I C 829

दफा ५२ जायदादके खिलाफ डिक्लीट इजराय करनेमें अदालतके कर्तव्य

अगर कोई डिक्लीट कर्जदारकी उस जायदादके खिलाफ जारीकी जाने जो इजरायमें वकै आचकती है और नीलामसे पहिले इजराय करने वाली अदालतको नोटिस मिल जावे कि कर्जदार द्वारा याउनके खिलाफ दीहुई दिवालियाके दरख्तास्त लेती गई है तो अदालत दरख्तास्त आन पर जायदादको अगर वह अदालतके वकैले होगी रिमीवरके सुपुर्दे करनेका हुक्म देगी परन्तु उस सुपुर्देमेंका सुर्चे जिन्मे डिक्लीट हुई है तथा इजरायका खच उस जायदादसे सबसे

पहिले वसूल किये जायें और रितीवरको अधिकार है कि वह कुल जायदाद या उसके किसी हिस्सेको इन खर्चोंकी अदयगीके लिये क्रयस्थ कर देवे ।

व्याख्या—

इस दफाका वह अभिप्राय है जैसा कि पिछली दफाका था कि दिवालियेकी जायदादसे उसके सब कर्जस्वाहोंकी लाभ पहुँचना चाहिये कोई एक कर्जस्वाह उस जायदादसे अग्रद्वारा जायदाद न उठा सके । यदि दिवालियेकी जायदाद लिये जाने (Admission) के पत्तापर दिवालियेकी कोई जायदाद नीलाम होने बाणी होने तथा नाश्या करने वाली अदालतको उस दिवालियेके दाख्वास्तकी सूचना मिल जावे तो वह रितीवरको उस जायदाद पर कब्जा देनेका हुक्म दे देवगा अगर जायदाद अग्राजतके कर्तव्य होवेगो । पिछले एक्टके अनुसार दिवालिया क़ार दिए जानेके बाद इस प्रकारका हुक्म दिया जातकता था परन्तु इस एक्टके अनुसार दख्वास्त दिवालियाके लिये जाने (Admission) परही ऐसा हुक्म दिया जावेगा अदालत इस दफाके अनुसार हुक्म देनेके लिये बाध्य है जैसा कि 'Shall' शब्दसे जो अपेक्षाके एक्टमें प्रयोग किया गया है प्रकट होता है ।

इस दफाके लिये यह आवश्यक नहीं है कि दाख्वास्त दिवालिया कर्तदार द्वारा दा गई हो या किसी कर्जस्वाह द्वाराही दी गई हो । दाख्वास्त दिवालिया चाहे जिसके द्वारा दा गई हो इस दफाके अनुसार कर्जस्वाह कीमतनेकी केवल इतना आवश्यक है कि वह दाख्वास्त लेखी गई होवे ।

यह बात भी ध्यानमें रहना चाहिये कि इस दफाके अनुसार कर्जस्वाह बरानेक क्रिये दाख्वास्त दिये जानेकी आवश्यकता है अर्थात् इस मामले लिये अदालत इसमामे दाख्वास्त दी जाना चाहिये कि वह जायदाद रितीवरके सुपुर्दगी जावे यदि इस प्रकारका दाख्वास्त न दी गई हो औऱ अदालत नोटिस मिल जानेके बाद भी जायदादकी नीलाम कर देवे तो ऐसे नीलामका विरोध रितीवर या कर्जस्वाह नहीं कर सक्ता है देखें—A. I. R. 1925 Lah 158

इस दफाके अनुसार कर्जस्वाहकी जानेके लिये इनाम कर्जदारकी जायदादके खिलाफ होना चाहिये अर्थात् यदि इनाम कर्जदारके अन्तर्गत किसी दूसरे व्यक्तिकी जायदादके खिलाफ होगी या ऐसी जायदादके खिलाफ होगी जिसमें कर्तदार व अन्य लोगोंका भी हिस्सा होवे तो इस दफाके अनुसार कर्जस्वाह नहीं कीजाना चाहिये । इस दफामें यह भी बतलाया गया है कि इनाम किसी ऐसी जायदादके खिलाफ होने गो जगहमें भेची जातकती हो । इस एक्टके दफा ४ व २८ में बचे जाने योग्य जायदादका विवरण दिया हुआ है तथा जीवना दाबालीकी दफा ६० में भी इसका विवरण मिलगा ।

इस दफामें जो अभिप्राय उल्लेख है उसमें उस इच्छाका तात्पर्य नहीं है जो रहनवासकी बिक्री हो या किसी महकूज कर्जस्वाहका जमानतके सम्बन्ध हासिलकी गई हो देखें—A. I. R. 1926 Mad 194

इस दफाका यह अभिप्राय नहीं है कि दिवालियेकी दाख्वास्त लिये जांतरा नोटिस मिल जाने पर अदालत सदस्योंकी जायदादकी नीलाम करनेसे नाचित रसे देखें—A. I. R. 1925 Lah 158

यह दफा उन्ही समय लागू होगी चाहिये जबकि इनाम करने वाली अदालतको इस बातके लिये दाख्वास्त दी गई हो कि वह जायदाद रितीवरकी सुपुर्दगीमें देदे । इससे यह प्रकट होता है कि दफा उन्ही समय लागू होगी जबकि कोई रितीवर नियत किया गया हो । इसी प्रकार यह तय किया गया था कि यदि दायिमानी (Interim) रिमाइनों दिवालिये की जायदाद पर कब्जा लेना आवश्यक अदालत द्वारा नहीं दिया गया हो तो उस सूरतमें अदालत इसमामे कोई दाख्वास्त जायदादका कब्जा उससे देनेके लिये नहीं दी जासकती है देखें—A. I. R. 1926 Mad 606

इस दफामें जो नोटिसका मिलना अदालतके लिये कहा गया है उसके तात्पर्य यह नहीं बतलाया गया है कि नोटिस किसके द्वारा दिया जाना चाहिये । ऐसा मान्य होता है कि इस प्रकारका नोटिस कोई भी व्यक्ति देसकता है । नोटिस इस बातका

माना चाहिये कि दिवालियेरी दायदास्त उठा गई है चाहे वह दायदास्त दिवालिये द्वारा उठा गई हो या उसके किसी कर्तव्यदाह द्वारा उठा गई हो इसने कोई भद्द नहीं पड़ा । यदि नोट्स मिल जाने पर तथा जायदाद पर सितीवरका कब्जा दिये जानेकी दायदास्त द दिये जाने पर भी अदायत नीग्राम कर देने तो ऐसे नालामके अनिश्चित समयका चाहिये तथा ऐसे नीग्रामके छरीदार नीग्रामके कोई हक नहीं पहुँचना है क्योंकि इस दफ्तेके अनुसार अदालत सितीवरकी कब्जा लेनेका हुक्म देनेके लिये बाध है । इस दफ्तेके अनुसार सितीवरकी उमा जायदाद पर कब्जा लेनेका हुक्म दिया जासकेगा जा अदायत कब्जेका होनेसे यह स्पष्टता है कि मनवूला (Moveable) जायदाद परकी कब्जा लेनेका हुक्म हो सकेगा देखा—A. I. R. 1926 Sindh. 199 में यह तथ हुआ था कि, चूँकि इस दफ्तेमें यह दिया हुआ है कि इस जायदाद पर कब्जा दिया जावेगा जो अदायतके कब्जेमें होने इससे यह मान्य होता है कि दफ्तेके उम मनवूला (Movable) जायदादके लिये लागू है जिस पर अदायत कब्जा कर लेवे या जो इस प्रकार कुर्ककी गई हो कि उस पर अदालत कब्जा लेसके । रोमनवूला (Immoveable) जायदाद पर कब्जा दायदास्त कब्जेके तौर पर नहीं किया जाता है किन्तु उस पर बा बा लेनेके लिये पहिले मद्रूलेके नाम इस प्रकारका हुक्म जारी किया जाता है कि वह उसे किसी प्रकार अलहरा न करे और इसी कारण इस प्रकारकी जायदाद (अर्थात् रोमनवूला जायदाद) इस दफ्तेके अन्तर्गत नहीं आती है देखो—A. I. R. 1924 Sindh 69

इस दफ्तेमें यह भी बताया गया है कि यदि इस दफ्तेके अनुसार नीग्रामके पहिले जायदाद पर सितीवरका कब्जा होनेका हुक्म दे दिया जावे तो उस जायदादमें दायदास्त खर्च तथा उस धुकदमेका खर्च जिसमें इनरयरी जान वामी किसी प्राप्त हुई थी पहिले दियेबाया जावेगा तथा सितीवरको इसकी पूर्तिके लिये यह अनिवार प्राप्त है कि वह उस जायदादकी या उसके किसी हिस्सेकी उस खर्चकी चुकानेके लिये बंध देवे । इन बातोंका अभिप्राय यह है कि यदि कोई किसीद्वारा नालामका पूरा जायदाद उठाके लेक दिया जावे तो ऐसी दफ्तेमें उसका अमली खर्च न माग जाना चाहिये अर्थात् वह इनरयरीके खर्च को पावेगा तथा उस खर्चकी भी पावेगा जो उसे किसी हासिल करनेमें करना पड़ा हो परन्तु साथ साथ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि वह उन्हीं खर्चोंका वास्तविकता जो कि कानून उमको दिलाय गय हो या कानूनन सिनेके पावेगा वह अधिकारी समझा जावे अर्थात् प्राइड खर्च व वह खर्च जो कानून उसको नहीं मिल सके हैं नहीं दिलाय जा सकते हैं ।

दफ्ता ५३ अपने आप किये हुए सौदाकी मंजूरी

अगर कोई इन्तकाल जायदाद दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मसे दो सालके अन्दर किया गया हो परन्तु जो किसी शरीक बदलभ तथा पहिले न किया गया हो अथवा जो नेकनीयतीले किसी खरीदार या जाभिनदार (Incumbrancer) के हकमें समुचित मूल्य लेकर न किया गया हो तो ऐसा इन्तकाल जायदाद सितीवरके मुकाबले रह किया जा सकता है और अदालतको अधिकार है कि उसे मंजूरा कर दे ।

व्याख्या—

कानून दिवालियाका एक प्रधान उद्देश्य यह है कि दिवालियेरी जायदाद उसके मर वर्जकदाहोंमें उचित रूपसे नदी जासके और इस उद्देश्यका पूर्तिके लिये यह आवश्यक है कि दिवालिया अपने आपकी (Voluntary) या धोलेके इन्तकाज न कर सके । इसी कारण इस दफ्तेमें यह बताया गया है कि दिवालिया क्लाम दिये जानेके हुक्मके कारण दिवालियेके किये हुए सिनेके इन्तकाल रह किये जायसके हैं और वह इन्तकाल अदालत मंजूर कर सकती है देखो—62 I. C 924 यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि अग्रणी एकमें 'Voidable' शब्दका प्रयोग किया गया हो इस कारण यदि उस इन्तकालको रह करानेका प्रयत्न न किया जावे और मंजूरीका हुक्म न दिया जावे तो वह इन्तकाल वैध है ।

तेसा कायम रहेगा । किसी इतकाल जायदादके ठीक होनेका प्रश्न उसी वन उभारा जासकेगा जबकि दिवालिया जगार दिये जानेका हुक्म हो चुके और उससे पहिले अदालतसे कोई अधिगार नहीं है कि वह ऐसे प्रश्न पर विचार कर सके दफा—
A I R 1927 Lah 95 पुनर्देखनेकी दफा ३६ इस दफामे मिलती हुई थी परन्तु उसमें (अमेनो एक्टमें) 'Void' शब्दका प्रयोग था जिसपर तात्पर्य यह था कि उस प्रत्येक इन्तकाल अपने आपसे रद्द समझे जाते थे परन्तु इस एक्टमें 'Voidable' शब्द इ निसका तात्पर्य यह है कि रद्द कथना जासकता है जसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है ।

इस दफामे अदालतमे तात्पर्य अशुद्ध दिवालियाय समझना चाहिये जूनि अदायत दिवालियाहीके दिवालिऐकी जायदादके सम्बन्धमें बर्गवार्ड बनेका अधिवार प्राप्त है इसलिये दिवालिये करार दिये जानेके बाद वही अदालत दिवालियेके लिये हुए इन्तकाल जायदादकी रद्द भा कर सकती है । जबकि अदायत इस एक्टमें अनुभाग कोई बर्गवार्ड करे तो उसे चाहिये कि खास तौरसे इस एक्टके नियमोंका प्रयोग कर परंतु इसमें यह न समझना चाहिये कि वह आम कानूनी मामले मामूला दीवानों अंगतानों तरह तय नही कर सकती है दफा—41 All 71.

किंतु यदि दिवालिऐका उपबार्ड करते समय कोई आम कानूनी मसला तय करना बहुत जरूरी न होने हो अदालत दिवालिऐकी चाहिये कि वह दफा ४ क अनुसार आम दीवानों अदालतपर अधिगारोंसे न बन बल्कि उस सल्लेखी अदालत दावाना द्वारा तय किये जानेके लिये छोड़ देवे देता—A I R 1923 Mad 631.

यदि कोई जायदाद अदालत दिवालिऐका अधिवार सीमासे बाहर भी होवे तो अदालत दिवालिऐा वसके सम्बन्धमें किये हुए इन्तकाल जायदादका मसूजा कर सकती है देखो—7 I C. 765 परंतु विदित भारतमें अदालतका यह अधिवार नहीं है कि वह चार छक्का जायदाद सम्बन्धमें किये हुए इन्तकालका मसूजा कर सके देखो—A I. R. 1922 Nag 221

इस दफाके अनुसार अदायत किसी भी इन्तकाल जायदादका रद्द करना लिये बाल्य नहीं है किन्तु उसका रद्द करना न करना अदालतकी न्याय पर निर्भर है । अग्रणी एक्टमें 'May be annulled' शब्दोंका प्रयोग किया गया है जिससे यहां अभिप्राय निरलगा है कि यदि जाकिपाको दायन हुए उचित प्रतीत हो तो अदालत मसूजा कर देवे यदि अग्रणीमें 'May' शब्दके बजाय 'shall' शब्दका प्रयोग हुआ तो बात दूसरी था व अदालतका मसूजा करनेका हुक्म दना लाजिमी होता परंतु इस दफाका तात्पर्य यहां समझना चाहिये कि अदालत मामलेकी उचित रूपसे सुनन व समझनेके पश्चात् सम्बोधित कार्य करे ।

अदालतको चाहिये कि वह अपने इस दफामें दिए हुए अधिगारोंका रिमैबर था बिना मानवत अदालतको न द देवे देखो—36 All 549 यह दफा उसा समय लागू था सकेगा जबकि इन्तकाल जायदाद रद्द वाला न्याय दिवालयका करार द दिया गया था तथा इस दफाकी लागू करनेके लिये नीचे दी हुई बातोंकी आवश्यकता समझना चाहिये —

(१) यह कि जायदाद अलहदा नो गई हो,

(२) यह कि इतकाल जायदाद किसी विवादके बन्देमें तथा पहिले नहीं किय गया हो,

(३) यह कि वह इन्तकाल किसी ऐसे स्वरीदार या जामिनदार (In-umbrancer) व इन्में नहीं किया गया हो जिसने नवनायतास व सजुलिन मूल्य देकर जायदादको लिया हो, और

(४) यह कि वह इन्तकाल, दिवालिऐा करार दिये जानेसे पहिले दो सालहके अन्दर किया गया हो अपाव उस इतकाल जायदादके बाद २ सालहके अन्दर वह दिवालिऐा करार दिया गया हो ।

दो सालके अन्दर—से तात्पर्य यह है कि यदि कोई इतकाल जायदाद, दिवालिऐा करार दिये जाने वाल

हुकममे पहिले उसके दो सालों अदर किया गया हो ता वही १६ किया जा रहा और यदि वह इतनाल जायदाद दिवालिये का दायताव दिये जाने पहिले दो सालके अदर किया गया हो ता ऐसा इतनाल जायदाद इस दस्तक अदर नहीं जाता है यदि किसी इतनाल जायदादको हुए दिवालिया करार दिये जाने पहिले दो सालके अतिरिक्त होय हों पान्तु जा दिवालिये की दायताव दिये जानम दो सालके अदर पड़ता हो ता ऐसा इतनाल जायदाद इस दस्तके अर्थात नहीं जाता है देखो—
A 1 R. 1925 Bom 480, A 1 R 1926 All 470, A 1 R 1924 Lah 374, A. I. R 1927 Sindb 66, A I R 1928 Rang 148, A I R. 1928 Lah 381 (F B)

उपर कहे हुए सब धकदमों साथ तोलते गये तब किया गया है कि दो साल की मियाद दिवालिया करार मिये जाने वाले हुकममे ही लागत चाहिये वह मियाद दिवालिये की दायताव दिये जानम के लिये नहीं ली जायता है। यदि कोई इतनाल २ सालमे पहिले का इतिहास बनइत उस दस्तक अनुसार रद न किया जायता हो तो उस इतनालके लिये दफा ५३ कानून इतनाल जायदाद अनुसार समस्त जालिजमे रद करनेका यातावतों जासनी है। अतः प्रत्यक्ष दिवालिया यदि दिवालिये का यातावतों के निगमन के हिसा इतनाल जायदादों इस दस्तके अनुसार रद न कर सकता तो वह इतनाल अतः लीवानीसे समूल रखा जायता है देखो—A. I R 1928 All 470, A I R. 1922 All 443

बार सुवृत्त—जो व्यक्ति इतनाल जायदाद रद कराय जायता हो उसे पहिले यह साबित करना पड़ेगा कि वह इतनाल जायदाद होने दो सालके अदर किया गया है और जब यह साबित कर दिया जाय तो बार सुवृत्त उमेय हद जायगा और तब मित व्यापक इकम इतनाल किया गया है उक्त कर्तव्य होना कि वह नेकनीयती तथा समुचित मूल्यका अदर किया जाना साबित करे देखो—A. I. R 1923 Nag 97, 39 All 90, 46 All 86।

ऐसा प्रतीत होता है कि वह सब मोदे जो दिवालिया अपनी जायदादके सम्बन्धमे दिवालिया होनेसे गे साल अदर करे ताहि अतः समस्त जाना चाहिये और यदि कोई व्यक्ति इस विषय साबित किया चाहे तो उसको चाहिये कि उस सादेका नेकनीयतासे किया जाना तथा उक्त कि समुचित मूल्यका दिया जाना साबित करे देखो—A. I R 1924 Mad 867, A I R 1926 Lah. 307

जबकि यह इतनाल जायदाद इतने कष्ट का अतः प्रतीत किया गया हो ता बार सुवृत्त इतनाल करार वाले व्यापक पर नहीं रहेगा किन्तु अतिमल रसीवाकी यह साबित करना पड़ेगा कि वह इतनाल बदनोपतीम करारा गया है देखो—A I R 1926 Sindh. 140. अतः प्रतीत करने है कि वह यह निश्चित करने समय कि वह इतनाल जायदाद नेकनीयतासे किया था है या नहीं उन सब बातों का ध्यान रखे जो इतनालम सम्बन्ध रखती हैं। अतः जो इतनाल जायदाद इतने समय उपस्थित हों तथा उमेय पहिले या उमेय बाद फर्निचर अन्यवाते समस्त पद देखा—26 Bom 571, A I R 1924 Mad 865

नेकनीयतासे सम्बन्ध रखने वाली हर एक बातको अलदहा अलदहा नहीं समझना चाहिये किन्तु उन बातोंको एक दूसरेके सम्बन्धसे देखना चाहिये तथा सब बातों पर एक साथ ध्यान रखते हुए नेकनीयता या बदनोपतीके प्रपन्ना निश्चित करना चाहिये देखो—A. I R 15 27 Nag 166. जबाब किसी दन मेहर (Dower debt) के ठार हावका प्रपन्ना उपस्थित हो तो दन बातों पर विचार करना आवश्यक समझना चाहिये (१) यह कि किन्ता मेहर दायन्य वाली था, (२) यह कि किम प्रपन्ना मेहर था, (३) यह कि इतनाल निम नीयत किया गया (४) यह कि जो जायदाद उमेय बदल्ये दो गई है उसका मूल्य क्या है, तथा (५) यह कि मेहर का रुपया अदा करने देर किम बाधा आई थी देखा—39 All 95 यदि इस दस्तके अनुसार किसी देनवालेको रद करनेकी दायताव दी जावे तो ऐसा दायतावके दिये जानेसे अलत दाखनाकी अधिकार देनवालेका मुहताब तब कलक सम्बन्ध नहीं जाता रहेगा। यदि कोई दायन्य

मुद्रमा चल रहा हो और आकिशत रितीवर उस रेहननामकी रद्द करनेके लिये अदालत दिवालियामें दाखल करने से उचित तरीका यह होगा कि हम दाखलानेके फैसले लिये जाने तक वह मुद्रमा रोक दिया जाने दो—A. I. R. 1926 Mad. 1051.

इस दफाके अनुसार कार्रवाई उसी समय हो सकेगी जबकि दिवालियेमें कार्रवाई चल रही हो अर्थात् वह सम्पत्ति हो गई हो। यदि हम दफाके अनुसार किसी इतकाज जायदादमें रद्द करना हो तो इसकी सूचना उस व्यक्तिमें अवश्य दी जाना चाहिये जिसे हमें वह इतकाज दिया गया हो तथा उसे अपना मामला ठीक तौरसे अदालतके सम्मुख उपस्थित करनेका अवसर दिया जाना चाहिये देखो—50 I. C. 117. इस दफाके अनुसार कार्रवाई करनेके लिये यह आवश्यक नहीं है कि पूरी कोर्ट को लगाकर अर्थात् दावाके तौर पर दाखला दी जाना चाहिये किन्तु इस लिये जो दूसरी बात दी जाने उसमें माफ तौरसे उन सब बातोंको देखला दना चाहिये जिसके आधार पर किसी इतकाज जायदाद रद्द करना हो। अदालत दिवालियाको यह अधिकार नहीं है कि वह इस दफाके अनुसार कार्रवाई करने समय सहकीमतसे सि. प्र. २, सेक्सि या किसी दूसरी मातङ्ग अदालतके पास भेज देवे किन्तु उसका कर्तव्य है कि ऐसी दाखलानेकी अति पर इसका सूचना उचित रूपसे उस व्यक्तिको देवे जिसके इत्तम जायदाद लिखी गई हो तथा इसके परवर्तु दोनों ओरके सार्व सुनकर रखी उस दाखलानेका फैसला करे दो—36 All. 549. रिवाजकी भी हम दफाके अन्तर्गत १९ हरे दाखलानेकी सुनन तथा उनके तब करना अधिकार नहीं है। केवल अदालत दिवालियाही इस दफाके अनुसार दाखलानेके सती है तथा इतकाज जायदादको मसूख कर सकती है या उसके मसूख करनेमें इनकार कर सकती है। यदि रिवाज स्वयं ऐसी दाखलानेका फैसला करे तो इसका अर्थ यह होगा कि वह स्वयं अपने मामलेके लिये जज बन गया है दो—A. I. R. 1926 Mad. 1019

हम दफाके अनुसार कार्रवाई मामूली मुद्रमोंकी तरह की जाना चाहिये सरसरी कार्रवाई न करना चाहिये देखो—39 All 39. अर्थात् इस दफाके अनुसार यदि कोई प्रश्न उपस्थित होवे तो उनको सरवर्दमें तप न कर दना चाहिये किन्तु उनको कानूनी तहजीबके बाद भली भाँति समझ कर तप करना चाहिये देखो—A. I. R. 1926 Mad 801.

रितीवरकी रिपोर्ट देने मामलोंके लिये कानूनी शाहस्त न सम्पत्ति चाहिये और न ऐसी रिपोर्टोंके आधार पर कोई प्रमाण इस दफाके अनुसार लभ हो कर देना चाहिये देखो—36 I. C. 906, 36 All. 549, 46 All 864.

यदि इस दफाके अनुसार कोई इतकाज जायदाद रद्द कर दिया जावे तो उसके बाद वह जायदाद रिवाजकी सम्पत्ति चाहिये और वह जायदादमें दिवालियेके कर्तव्यवाहोंको हिस्सा रखे उनकी और जायदादकी तरह दिखानेका। यदि कोई बयनामा इस दफाके अनुसार रद्द किया गया हो और उस बयनामाने लिये किसी रिजके रेहननामका बयनामा मसूख किया गया हो तो वह रेहननामका बयनामा नकार करके सम्पत्ति जावेगा और बयनामाने मसूख हो जानेके बाद भी रेहननाम करने वालका वह बयनामा जो उसने रेहननामका अदालतमें दिया है नकार करके मसूख सकेगा अर्थात् वह जो रेहननामका साथ उस करके लिये हिस्सा रखी पानेगा देवी—A. I. R. 1925 Nag. 73.

इस दफाके अनुसार किया हुआ फैसला अत्र तन्त्राज्य युद्ध (Resjudicata) सम्पत्ति जावेगा और किं वही फौजैनक दासियान उही मसलको तप करानेके लिये मामला नहीं चल सकेगा देखो—49 All 71, A. I. R. 1927 Cal 474.

यदि इस दफाके यह नहीं बन गया है कि दाखलाने किस समय हो जाना चाहिये हमने यह सम्पत्ति चाहिये कि इस दफाके अनुसार दाखलाने दान कार्रवाई दिवालियामें किसी समय भी दी जा सकती है। देखो—दरार्मिद नाना

कृजीनल A. I. R. 1924 Lah. 553. यदि इस दफाके अनुसार कोई इन्तकाल जायदाद मसूज किया जावे तो ऐसे इन्तकालीन जायदाद में दफा ७५ (२) के अनुसार कोशिका होती है ।

दफा ५४ कुछ मामलोंकी कीहुई तरजीहकी मसूखी

(१) अगर दिवालिया करार दिये जानेके तीन माहके अन्दर किसी एक कर्जश्चाहके हकमें उसको दूसरे कर्जश्चाहोंके मुकामपर तरजीह देते हुए कोई इन्तकाल जायदाद या अदायगी या हक पैदा करना या कोई अदालती कार्यवाई उस कर्जदार द्वाराकी गई हो जो यह जानता हो कि वह अपने कर्जोंको अदा नहीं कर सकेगा तो यह सब कार्यवाहियां उस घफ धोखेदेहीकी कार्यवाहियां समझी जावेंगी जबकि तीन माहके अन्दर उसके खिलाफ दिवालीकी दरखास्त दी गई हो और यह दिवालिया करार दे दिया जावे और रिसीवरके मुकामपर वह रह समझी जावेंगी और अदालत उनको मसूज कर देगी ।

(२) इस दफासे उस शर्तके हकमें कोई असर नहीं पड़ेगा जिसने नेकनीयतीले काफ़ी मुआविज़ा (Consideration) देकर दिवालियेके किसी कर्जश्चाह या उसके ज़रियेसे उस हकको हासिल किया हो ।

व्याख्या—

इस दफामें भी पिछली दफाकी तरह यह बतलाया गया है कि दिवालिया करार दिये जाने वाले इकमल जसर पिछले स्रोतों पर क्या पड़ता है । इस दफाके अनुसार उन कर्जश्चाहोंके अधिकारोंकी रक्षा की गई है जिनके कर्जोंको मारनेके लिये कर्जदारने अपनी जायदाद किसी एक कर्जश्चाहके हकमें उसे देना फायदा पहुँचानेकी परकसे करदी हो । परन्तु इस दफाके लिये इस बातका ध्यान रखा चाहिये कि वही स्रोत वह समझा जावेंगे जो दिवालियेकी दरखास्त दिये जानेके तीन माहके अन्दर किये गये हों अगर तीन माहसे पहिलेके कोई स्रोत होवे तो उन पर इस दफाका प्रभाव नहीं पड़ेगा । इस दफाके अनुसार कोई लोहा उसी समय रह समझा जावेगा जबकि नीचे दीहुई चारों बातें उपस्थित होवें (१) यह कि उस स्रोतके लिये जाने समय कर्जदारके पास अपने सब कर्जोंको अदा करनेका साधन न होवे (२) यह कि वह सादा किसी कर्जश्चाह या कर्जश्चाहके टूट्टीके हकमें किया गया हो (३) वह स्रोत यह जानबूझ कर किया गया हो कि उससे उस कर्जश्चाहकी देना फायदा पहुँचे अर्थात् दूसरे कर्जश्चाहोंके मुकामपर उसे फायदा पहुँचानेकी इच्छासे वह स्रोत किया गया हो (४) यह कि वह स्रोत दिवालियेकी दरखास्त दिये जानेके तीन माहके अन्दर किया गया हो तथा उस दरखास्त पर कर्जदार दिवालिया करार दे दिया जावे । देखो—A. I. R. 1928 Rag. 106

यह बात भी याद रखनी चाहिये कि अदालत इस दफाके अनुसार कर्तवाई उसी समय कर सकेगी जबकि कर्जदार दिवालिया करार दे दिया जावे अन्यथा नहीं देखो—मूलसिंह बनाम लक्ष्मीदेवी 95 I. C 1055 यदि ऊपर दिखलाई हुई सब बातें उपस्थित होवें तो वह स्रोत वह समझा जावेगा और चूँकि वह स्रोत अपने आपमें रह होवेगा इसलिए अंगलतका कर्तव्य सप्रमना चाहिये कि वह ऐसे स्रोतको रह कर देवे । अमेरी एक्टकी इस दफामें (Void) शब्दका प्रयोग किया गया है जो इसमें पिछली क़ानून अपात् दफा ५३ में (Voidable) शब्दका प्रयोग किया गया है अतः इस बातसे यह स्वभावतः प्रकट है कि पिछली दफाके अनुसार बातोंके उपस्थित होने पर स्रोत रह करार दिया जासकता है परन्तु इस दफाके अनुसार बातोंके उपस्थित होने पर स्रोत अपने आपमें रह होता है । इस दफाके अनुसार यह आवश्यक है कि दिवालियेकी मशालोखादेहासे किसी एक कर्जश्चाहकी दूसरे कर्जश्चाहोंके मुकामपर फायदा पहुँचानेकी रहीं यह आवश्यक

नहीं है कि जिसके इकमें सोदा किया गया हो उसकी मश इस प्रकारकी रही हो दखो—109 I. C. 370, A. I. R. 1929 Lah 79

भोलादहीसे बेना लाभ पहुँचानेसे तात्पर्य यह है कि सोदा होने समय दिवालियेकी क्या इच्छा थी अर्थात् क्या वह सोदा तिसा एक कर्जेश्वारको दूसरे कर्जेश्वारोंके मुकामके बेना फायदा पहुँचानेकी मशाके किया गया था देखो—42 Mad. 510, A. I. R. 1928 Mad. 860

दफा ४४ में यह नहीं भी नहीं दिया हुआ है कि इसके अनुसार सोदा किस समय मसूख किया जानक्या है परन्तु दफामे यह बात अथ भाते प्रकृ ह कि दिवालिया करार देदिय जानेके बाद यह सोदा रद किया जाना चाहिये क्याकि दिवालिया करार दिये जानेसे पहिले अदाकतको कोई अधिकार इस दफाके अनुसार कार्यवाई करनेका नहीं है । अर्थात् अदाकत मातहतने दिवालिया करार दिये जानका हुकम इसी बिना पर दिया हो कि दिवालियेने कोई सोदा धाक देदीका किया है तब दिवालिया करार दिये जानेका हुकम और धोखादहीसे किये हुए सादकी मसूखीका हुकम एक साथ दिया हो और उस सोदेका मसूखीका हुकम पहिले लिख गया हो परन्तु दिवालिया करार दिये जाने वाला हुकम उसके बाद लिखा गया हो ता यह तब हुआ कि इस प्रकारकी चलती एक प्रकारसे लिखनेकी मशकी है अगर इस कारण अदाकत मातहतका हुकम ठीक है अर्थात् अदाकत सादेका मसूखी व दिवालिया करार दिये जानेका हुकम एक साथ दे सकती है तथा उनके आगे वंके लिख जानेसे हुकममें कोई असर नहीं पड़ता है तथा वह हुकम ठीक समझना चाहिये दखो—हामसिंह बनाम गोपालदास देसरान 109 I. C. 370, A. I. R. 1929 Lah 79.

सोदेके मसूखीकी दारम्भान इस दफाके अनुसार दिवालियाकी कार्यवाई मयात होनेसे पहिले किसी समय की हो जासकती है । इस बातका अवश्य ध्यान रचना चाहिये कि वहाँ सादे इस दफाके अनुसार रद मयात जानेको नो दिवालियेकी दारवास्त दिय जानेसे पहिले तीन माहके, अन्दर किये गये हों तीन महीनेका समय जोइने समय वह दिन जिस दिनकी दारवास्त दायरे हो नहीं जोका जानेगा ।

१५ दिसम्बर सन १९२६ ई० को अमीराण्ट्स १ व २ न अपने एक कर्जेश्वारके दिवालिया करार दिये जानकी दारवास्त दी परन्तु उस कर्जेश्वारको जा कर्जो इन दोनोंको अदा करना था वह ५००) पाचस रुपयेन कम था इस कारण २८ जनवरी सन १९२७ ई० को अमीराण्ट्स न० ३ भी उस कर्जेश्वारके विरुद्ध दारवास्तमें शामिल होगया और वह कर्जेश्वार १८ फरवरी सन १९२७ ई० को दिवालिया करार देदिया गया । १ मार्च सन १९२८ ई० को अमीराण्ट्सन अदाकतमें दफा ५४ (१) के अनुसार उन सोदाकी रद करारदेनकी दारवास्त दी जो दिवालियेने १५ दिसम्बर सन १९२६ ई० से पहिले तीन माहके अंदर किये थे तो यह तब किया गया कि २८ जनवरी १९२७ ई० का अंतर्को तारीख समझना चाहिये जबकि दिवालियेकी दारवास्त दीगई था और उसी दारवास्त पर कर्जेश्वार दिवालिया करार दिया गया था इस कारण वह सादे आ इस तारीखमें पहिले तीन माहके अन्दर नहीं हुए हैं इस दफाके अनुसार रद नहीं समझे जासकते हैं देखो—28 A. L. J. 941, A. I. R. 1928 All 676

जैसाकि ऊपर बतलाया जाचका है इस दफाका प्रयोग होनेके लिये यह आवश्यक है कि सोदा किये जाने समय कर्जेश्वार अपने कर्जोंको चुकानेमें अमर्थ हो अर्थात् यदि कर्जेश्वार पास काफ़ी रुपया हो या ऐसा सुभाना हो कि जिससे वह अपने सब कर्जों चुका सकता हो और उस समय वह किसी एक कर्जेश्वारके इकमें दूसरे कर्जेश्वारोंके मुकामके कोई सोदा कर दब तो उस समय इस दफाका प्रयोग नहीं हो सकेगा क्योंकि ऐसी दशामें वह दिवालियादी करार दिये जाने योग्य न होगा परन्तु यदि उसके पास उस समय अपने कर्जोंको चुकानेका सुभीता न होव ता वह सोदा इस दफाके अनुसार और शर्तोंके पूरा होने पर रद होगा । असमर्थ होनेसे तात्पर्य यह है कि कर्जेश्वार उस समय अपने कर्जोंको अपने आप नहीं

जुदा समता हो यदि पर्याप्त रुपये न होनेके कारण वह बड़े बसके रुपये कैसे होनेके कारण जिसकी वजहसे वह अपने कर्जोंकी अदायगीका प्रबन्ध उस समय न कर सकता हो। इस बात पर प्रमाण A. I. R. 1927 Lah 136 में डाला गया है इसी प्रकार इस बातकी भी आवश्यकता है कि सौदा होते समय दिवालियेकी यह मंशा रही हो कि किसी एक कर्जस्वाहकी दूसरे कर्जस्वाहोंके मुकाबिले विशेष लाभ पहुँचे वरना वह दफा लागू नहीं हो सकेगी देखो—दोस्तपम बनाम देवरीनन्दन A. I. R. 1924 Lah. 686.

कोई सौदा केबल इसी बातसे रद्द नहीं समझा जावेगा कि उसमें एक कर्जस्वाहकी दूसरे कर्जस्वाहोंके मुकाबिले लाभ पहुँचा है जब तक कि यह साबित न हो जावे कि कर्जदारका ऐसा करनेकी मंशा थी देखो—मोतीलाल बनाम बीअरारा A. I. R. 1926 Lah. 281.

यह अनवरा साबित होना चाहिये कि किसी एक कर्जस्वाहकी अदायगी होने समय कर्जदारकी असल मंशा विशेष पर थी रही हो कि उस कर्जस्वाहकी ओंसेके मुकाबिले रुपया मिल जावे तथा उस कर्जस्वाहोंने उसका रुपया हिस्सा रखनेके दिवाले न पाया जानके देखो—37 I. C. 250.

यह मानिन रखनेके लिये कि किसी कर्जस्वाहकी धोखेसे लाभ पहुँचानेके लिये दूसरे कर्जस्वाहोंके मुकाबिले तर्जिह दी गई है केवल रतनाही साबित करना आवश्यक नहीं है कि एक कर्जस्वाहकी दूसरे कर्जस्वाहोंके मुकाबिले तर्जिह दी गई है किन्तु यह भी मानिन होना आवश्यक है कि उस सौदेसे कबले समय कर्जदारकी मंशा उस कर्जस्वाहकी तर्जिह देनेकी थी और रही नीयतसे वह सौदा किया गया था। यह पर्याप्त नहीं है कि उस सौदेमें एक कर्जस्वाहकी दूसरेके मुकाबिले लाभ पहुँचा है किन्तु यह भी मानिन होना आवश्यक है कि एककी दूसरेके मुकाबिले लाभ पहुँचानेकी मंशा रही हो देखो—42 Mad. 510; 44 Mad 810.

यदि सौदा कबले समय कर्जदारकी असल मंशा यह रही हो कि इससे स्वयं उसे लाभ पहुँचे न कि उस कर्जस्वाहकी निमित्त हकम वह सौदा किया जायगा तो ऐसा सौदा इस दफाके अनुसार धोखेसे लाभ पहुँचानेका सौदा नहीं समझा जावेगा देखा—43 All 427; A. I. R. 1929 Lah 686 इस प्रकारके मामलोंकी समझनेके लिये यह देखना आवश्यक है कि आया वह सौदा कर्जदारके अपनी मंशाके लिये किया है या अपने किसी एक कर्जस्वाहकी लाभ पहुँचानेकी मंशा न भिन्न है देखो—A. I. R. 1925 Mad. 1089 यदि किसी सौदेमें केवल इस बातका धारणा हो कि वह सौदा एक कर्जस्वाहकी दूसरेके मुकाबिले लाभ पहुँचानेकी मंशासे किया गया है तो केवल धारणाके कारण यह दफा लागू नहीं होगी देखो—43 Cal 640

जबकि दिवालिया किसी दवालेके कारण कोई सौदा कगता है या रुपयकी अदायगी करता है या कोई ऐसा सौदा करता है जिसका कि डेबेव इस दफामें है तो इससे यह नहीं माना जावेगा कि उसने धोखेसे किमती तर्जिह देना चाही था देखो—37 I. C. 250. इस दफाके अनुसार जो तर्जिह देनेका क्रिम है वह तर्जिह किसी कर्जस्वाहके लिये होना चाहिये या जल्दके लिये नहीं इस दफाके लिये कर्जस्वाहका अभिप्राय महफूज कर्जस्वाहमें भी समझना चाहिये देखो—A. I. R. 1922 Nag 233. पल्लु कलकत्ता हाईकोर्ट इस मामले महमन नहीं है देखो—A. I. R. 1923 Cal 689 यदि कोई व्यक्ति उन सौदाके होनेकी वनहते ओ कि रद्द करया जानेको है कर्जदारका कर्जस्वाह बन जाके वा ऐसा दानकाम कर्जस्वाहकी इस दफाके अनुसार समझा जावेगा देखो—43 All 427

यदि कोई जामिनदार (Surety) जिसका कर्जदारका बर्ज अपने पाससे जुदा देने तो वह जामिनदार भी उस कर्जदारका कर्जस्वाह बन जावेगा और यदि ऐसे जामिनदारके हकमें कोई गौदा उत्तरी और कर्जस्वाहोंके मुकाबिले

बेना फायदा पहुँचानेकी मंशासे किया जावे तथा वह सौदा किसी खास दस्तावेज बन्धमे न किया गया हो तो ऐसा सौदा धोखादेहीसे फायदा पहुँचानेका सौदा इस दफ्तेके अनुसार समझा जावेगा, देखो—A I R. 1923 Rang 149

तर्जिह (Preference) से तात्पर्य यह है कि एक कर्जदारको लाभ पहुँचि तब उसके कारण दूसरे कर्जदारको हानि उठाना पड़े । जैसा कि ऊपर कहा जाचुका है धोखादेहीमे तर्जिह देनेमे अभिप्राय यह समझना चाहिये कि जो सौदा किसी एक कर्जदारको दूसरे कर्जदारकोके मुकाबिले लाभ पहुँचानेके लिये किया गया हो तथा सौदा होने सम कर्जदारकी ऐसीही मंशा रही हो ।

जबकि किसी सौदाके लिये यह कहा जावे कि वह इस दफ्तेके अन्तर्गत आता है तो इस बानके ठीक तरीके समझनेके लिये यह दफ्ता आवश्यक है कि जहाँ कर्जदारने उस सौदेको गेफनीपरीमे किया है या उसकी आँखे उमने कोई बेना लाभ उठानेकी मंशासे किया है, देखो—A I R 1925 Nag 225. यदि कोई सौदा किसी मौजदारीमे मामलेमे बचनेकी चाहसे द्वायमे आकर किया गया हो तो ऐसा सौदा स्वयं किया हुआ सादा नहीं है और वह धोखादेहीमे तर्जिह देनेका सौदा नहीं है, देखो—59 I C 576 कानूनी चारमोहीका दबाव चाहे वह शीतानीके सामनेका होवे या मौजदारीके सामनेका दबाव (Pressure) का समझा जावेगा, देखो—53 Cal. 640 आर जबकि दिवालिया कानूनी कार्रवाई होनेके मयमे कोई सौदा कर देवे तो उसे तर्जिह (Preference) न समझना चाहिये, देखो—A. I R 1924 Cal 946

यदि कोई कर्जदार नालिशमे बचनेकी चाहसे तथा अपनी दशा दूसरों पर प्रभावित न होनेके लिये किसी कर्जदारको हकमे रहन कर देवे तो ऐसे रहनको धोखादेहीसे तर्जिह देना नहीं कहा जावेगा, देखो—A I R 1923 Lah. 602. यदि किसी कर्जदारको विपक्ष मुआदिदेके अनुसार कृपा अदा किया जावे तो उसमे धोखादेहीकी तर्जिह नहीं समझी जासकती है देखो—20 I C 398 यदि कोई कर्जदार अपने किसी समाया विधेदारको उसका कर्ज जाकि उस समय नजिबुलअदा नहीं है बुझा देवे तथा उस समय कर्जदार दिवालियाकी हालतमे होवे तो ऐसी अदायगीसे देना लाभ पहुँचानेकी मंशा समझी जावेगी, देखो—55 I. C 57, A I R 1925 Nag 225

यदि सौदा करने समय कर्जदारकी दरअमल यह मंशा न रहा हो कि उसने उसके किसी कर्जदारको और कर्जदारों के मुकाबिले फायदा पहुँचे किन्तु उसकी यह मंशा रही हो कि उस सौदाके करनेमे वह स्वयं फायदा उठावेगा तो ऐसा सौदा धोखादेहीसे लाभ पहुँचानेका सौदा नहीं समझा जावेगा, देखो—48 All. 427

यदि यह बात साबित हो जावे कि कर्जदारने धोखादेहीमे फायदा पहुँचानेकी मंशासे किसी इन्तकाफ (Transfer) को किया है तो कर्जदार इस बातमे लाभ नहीं उठा सकेगा कि उसने वह इन्तकाफ नकलीपनासे कराया है देखो—21 C. L J. 176 इसमे यह प्रष्ट है कि कर्जदारकी मंशा या नेतनापनीका कोई अथ इस दफ्तेके अनुसार किये हुए सौदों पर नहीं पड़ता है यदि कर्जदारने अपने कर्जोंकी अदायगमे पैसापानीको कोई इन्तकाफ रगया हा तो उसमे यह नहीं माना जावेगा कि वह इन्तकाफ खरूदा है अगर यह साबित हो जावे कि दिवालियाकी मंशा उस कर्जदारको और कर्जदारकोके मुकाबिले अधिक लाभ पहुँचानेकी रही है, देखो—A. I R. 1926 Mad 338.

एक कर्जदारने जो अपने सब बर्जोंका अदा नहीं कर सकता था अपनी मर्द कीमती जायदादको अपने कुछ कर्जदारोंके पास उनका पूरा कर्ज अदा करनेके लिये रेंडन कर दिया और कुछ कृपा नकर अपन लिये ले लिया । इस सौदेमे तीन मासके अंदर दूसरे कर्जदारोंने उसके दिवालिया कुरार दिये ज्ञानके लिये दरखास्त देदी और वह कर्जदार दिवालिया कुरार देदिया गया तो यह तथ हुआ कि वह सौदा (रेंडनाया) कुछ कर्जदारोंको दूसरे कर्जदारोंकोके मुकाबिले

छात्र पहुचानेकी मंशासि किया गया था और इसीछिये मसूख भिये जाने लायक है, देखो — 13 I. C 68. यदि कोई कर्जदार अपने पुराने कर्जदारोंमें कुछ और कर्ज लिया चाहता हो परन्तु वह कर्जस्वाह अपने पिछले कर्जोंके लिये समानत्र भिये बिना दूसरा कर्ज देनेको तीसरा न होवे और इस पर वह कर्जदार अपनी जायदाद पिछले कर्जोंके सम्बन्धमें उसके पास रहन कर देवे तो इने घोस्वादेहीसे तर्जिह देना (Fraudulent preference) नहीं कहेंगे क्योंकि उसको बहुत अशुभ थी, देखो — A. I. R. 1924 Lah. 686.

इसी प्रकार यदि कोई कर्जदार घुसीपतमें पड़ा हो और उसकी कुछ और कर्जोंके लेनेकी आवश्यकता हो तथा उसका कोई कर्जस्वाह अपने पिछले कर्जों व इस नये कर्जके सम्बन्धमें उसकी जायदाद रहन का लेवे तो ऐसे सोदेको घोस्वादेहीसे तर्जिह (Fraudulent preference) देना नहीं समझना चाहिये, देखो — A. I. R. 1920 Lah 291.

यदि कर्जदारने जायदादकी नीलामसे बचानेके लिये कर्जस्वाहके हकमें रहननामा कर दिया हो व हकके बाद वह दिवालियेकी दारुलरात देवे तो इससे यह नहीं माना जावेगा कि घोस्वादेहीसे तर्जिह दी गई है, देखो — A. I. R. 1929 Lah. 159 यदि किसी दिवालियेके लिखाफ डिक्ती हो गई हो तो रिसीवर पर उसकी जाबदारी लाजिमी नहीं है क्योंकि घुमकिन है वह डिक्ती कर्जदारने मिल कर कर्जगी होने या कर्जदारको इस बातकी कोई परवाह ही न होवे कि उस पर चाहे जितनेकी डिक्ती हो जावे, देखो — A. I. R. 1925 All. 33. यदि रजामन्दोंसे कोई डिक्ती कराई गई हो तो उसकी भी जाबदारी लाजिमी नहीं है और अदालत दिवालियाकी अधिकार है कि वह उस डिक्तीके ठीक होने की बात निश्चिन कर सके और यदि ऐसी डिक्ती इन दफ्तेके अनुसार रह कर दी जावे तो अदालतको चाहिये कि इस प्रश्न पर विचार करे कि कर्जदारकी असल मशा उस समय क्या थी देखो — 93 I. C 331. जबकि कोई सौदा घोस्वादेहीसे तर्जिह (Fraudulent preference) देना समित होनेके कारण रह करार दे दिया जावे तो रिसीवरको अधिकार होगा कि वह अधिक दिया हुआ बचपना उस व्यक्तिसे वसूल कर लेव जिसके हकमें वह सौदा किया गया हो ।

इसी प्रकार यदि उस व्यक्तिने जिसके हकमें वह सौदा किया गया हो कोई बचपना दूरअसल अदा किया हो तो उस सोदेकी मसूखी पर वह अपना बचपना बापिस पानेका अधिकारी है देखो — 51 I. C 720. इस दफ्तेके अनुसार किसी सोदेकी मसूख करानेकी दारुलरात रिसीवर के सकता है देखो — 52 I. C 188

इस दफ्तेके अनुसार बर्खास्त चाद करनेमें पहिले रिसीवरको अधिकार है कि वह कर्जोंके सम्बन्धमें उस कर्जस्वाहसे बचपना जमा कर लेवे जो उस सोदेकी मसूख करानेके लिये कहता हो और यदि अदालत दिवालिया इने मजूर न करे तो वह अदालत जरीलमें इस मामलेको ले जासकता है । देखो — 47 Mad. 673 यदि कोई रिसीवर नियुक्त न किया गया हो तो कर्जस्वाहकी अधिकार है कि वह इस दफ्तेके अनुसार किसी सोदेके मसूख कर सकता है देखो — A. I. R. 1925 Nag. 225. जिसके हकमें मसूख कराया जाने वाला सौदा किया गया हो उन व्यक्तियों ऐसे मामलमें फरीक झकड़ना अवश्य बनाना चाहिये देखो — 52 I. C 761. यदि कोई सौदा दिवालियेकी दारुलरात गुजरनेसे कुछही पहिले किया गया हो तो उससे यह शक अवश्य होता है कि वह सौदा घोस्वादेहीसे किसी कर्जस्वाहकी छात्र पहुचानेकी मशाने किया गया होगा परन्तु इस बातको निश्चित करनेके लिये कि आपा दिवालियेकी दारुलरात की क्या मशा थी सभी मौजूदा बातों पर गौर करना चाहिये अर्थात् केवल शकहीसे यह न मान लेना चाहिये कि वह सौदा इस दफ्तेके अनुसार रह है जब तक कि यह मशी माति समित न हो जावे कि कर्जदारने बेना कायदा पहुचानेकी मशासे उस सोदेको किया है देखो — A. I. R. 1924 Rangoon 308

इस दफ्तेके अनुसार बर्खास्त सरसरी की बर्खास्त नहीं है परन्तु इस दफ्तेके अनुसार बर्खास्त उस समय की जाना चाहिये जबकि उस व्यक्तिने जिसके हकमें सौदा किया गया हो पूरा मौका जवाबदेहीका दे दिया जावे तथा इसक परचाव

समझ वृक्ष कर हुनद दिया जाना चाहिये देखो—A I R 1922 Lah 214 अर्थात् इस दफाके अनुसार कार्यवाई उसा प्रकार होना चाहिये जिस प्रकार कि दीवानीना मुकदमा तय किया जाता है और रितीवरका मुद्दकी इमियतसे मामला साबित करना चाहिये तब सब मामला समझ कर अदालतकी फैसला देना चाहिये ।

जबकि कोई सोदा धालादहीत तर्जिह देनेकी बिना पर रद कथया जानेमो होवे तो बार सुवृत् रीतीवर पर या उस व्यक्ति पर हागा जो उस सोदेकी रद कथना चाहे देखो—53 I C. 692, 21 C. L. J 167; A. I R 1924 Lah 686, A I. R. 1928 Rang 166, A I R 1929 Lah 159.

यदि दिवालिघेने किसी कर्जखवाहकी घोखदेहीसे बेना कायदा पहुचानेका मशामे कुछ अदायगीकी हो तो भा पाहिले रीतीवरका यह कर्तव्य होगा कि वह इस बातकी साबित करे कि इस मशआहमे वह अदायगीकी गई है परन्तु यदि वह अदायगा दिवालिघा हामेसे कुछही पहिलेकी गई हो और दिवालिघा इसके लिये कोई खास अबाब न दमके तो जहिरा यह मान लिया जावेगा कि घोखदेहीस बेना कायदा पहुचानेकी मशआहसे वह अदायगी की गई है और तब इसके विरुद्ध साबित करनेके लिये बार सुवृत् दिवालिघे पर होवेगा देखो—A I R. 1926 Sindh 128. इस दफाके अनुसार फैसला होनाम पर इस प्रश्नके लिये कोई नया मुकदमा चाद नहीं रिया जासकेगा देखो—42 Mad 322, 39 All. 626, 49 All 71.

यदि कानून दिवालिघेकी दफा ५४ के अनुसार दरखास्त दी जावे तो पहिले रितीवरका यह कर्तव्य होगा कि वह साबित करे कि काहिरा दिवालिघेने घाखादहासे बेना कायदा पहुचानेकी मशआसे वह सोदा रिया है परन्तु यदि निमी पिछले कर्जका अदायगी दिवालिघा होनेसे कुछही पहिले की गई हो तो यह साबित होने पर बार सुवृत् उस कर्जखवाह पर या उस व्यक्ति पर हो जावेगा जिसके हकमें वह सोदा किया गया हो । और यदि ऐसे सदिक होनेके कारण भली भांति अदालतकी न समझाया जावे ता अदालत यही मान लेगी कि बेना कायदा पहुचाने की मशआहसे वह सोदा किया गया पा देखो—107 I C 210.

दफा ५४ (ए) मसूखीकी दरखास्त कौन लोग देसकते हैं

दफा ५३ के अनुसार किसी इस्तकालके मसूखीकी दरखास्त या दफा ५४ के अनुसार किसी इस्तकाल अदायगी, बार या कानूनी कार्यवाईकी मसूखीकी दरखास्त रितीवर देसकता है अथवा अदालतकी अहवा लोन पर वह कर्जखवाहमी देसकता है जिसने अपना कर्ज साबित कर दिया हो और जो अदालतकी इस बातका विश्वास दिलावे कि रितीवरसे ऐसी दरखास्त देनेके लिये कहा जाचुका है परन्तु वह इसके देनसे इन्कार करता है ।

व्याख्या—

यह दफा निम्नलिखित है और सन १९२६ ई० के संशोधित एक्टके अनुसार बढ़ाई गई है यह संशोधित एक्ट “ The Amending Act of 1926 (XXXIX of 1926) कहलाता है । यह दफा इस कारण बनाई गई है जिसमें कि यह प्रश्न ठाक तौरसे तय हो जाव कि आया कोई कर्जखवाह किसी सोदेकी मसूखीके लिये दरखास्त दफा ५३ व ५४ के अनुसार दे सकता है या नहीं यों तो पिछली नज्जोमें यह तय किया जाचुका है कि यदि रितावर निपुत्त न रिया गया हो वा कर्जखवाह किसी सोदेकी मसूखीके लिये अदालतमें दरखास्त दे सकता है देना—A I. R. 1925 Nag. 225; A I R. 1924 Nag. 361. परन्तु इस दफामें साक तौरसे कर्जखवाहोंकी भी मसूखीकी दरखास्त देना अधिकार दिया गया है । इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि कर्जखवाह ठाक उस आजादक साथ एमा दरखास्त

नहीं दे सकते हैं जसा कि रिसीवर कमें कि जर्ज ग्रामे उमरवार देगे पक्षिक नचि दी हुई देखो शर्तों में पुन होना चाहिये ।
(१) यह कि कर्जदार अदायगी इमारा २० ॥ दरखास्त दे सकता है, दूसरे (२) यह कि कर्जदार को चाहिये कि वह अदायगी इस बानका इच्छात दिनादि कि सितावने ऐसी दाखलस्त देनेके लिये कहा गया था परन्तु उसने दाखलस्त देनेसे इनकार कर दिया है । इसका कारण यह है कि रिसीवर को हर समय मसूखानी दाखलस्त दफा ५३ व ५४ के अनुसार दे सकता है परन्तु कर्जदार उसी समय दाखलस्त दे सकता जबकि रिसीवर ऐसी दाखलस्त देनेसे इनकार कर देने तथा अदायगी भी आता इसके लिये मिल जाने अथवा नहीं ।

47 Mad 073. में यह बतलाया गया है कि यदि रिसीवरने किसी सौदेकी मसूख कानूने लिये कहा जाने तो समस्त कर्तव्य है कि पहले वह करने चाहिये यह सुगठे कि वह अपने दायित्व का सुबूत रखना है उक्त पत्रात् कर्जदारोंके नाम में लिखित निम्नलिखित बातें यह उक्त दाखलस्तका विरोध कर सके तब यदि रिसीवरने समझ पड़े कि दाखलस्त कोई सौदा भोलादेवीस किया गया है तो उसकी मसूखीके लिये अदायगी दाखलस्त देने और यदि उसे इस बातमें मसूखी न मादूम हो परन्तु कोई कर्जदार चाहे कि वह सौदा वास्तु मसूख कथना जाना चाहिये तो रिसीवर उससे पैसे कायिक कराने वह बतली मसूखीके लिये तब अदायगी करे । अदायग दिवालयवा भी यह कर्तव्य मादूम होता है कि वह केवल मसूखानी दाखलस्तों को लेही न लेवे किन्तु उन पर न्याय पूर्वक विचार करे जहाँ यदि अदालतके सामने कोई मसूखीका प्रश्न उपस्थित किया जावे ता वन पर उक्त विचार करना चाहिये चाहे वह प्रश्न सितावर द्वारा उपस्थित किया गया हो अथवा उसे कोई कलखल उपस्थित करे । अदालत स्वयं ही ऐसा प्रश्न सामने उपस्थित हो जाने पर विचार कर सकती है देखो—A. I. R. 1924 Nag 861.

दफा ५५ नेकनीयतीसे किये हुए सौदोंकी रक्षा

इस एकटमें अबतक दिये हुए इजराय सम्बन्धी दिवाल परके असरको ध्यान रखते हुए तथा उन इन्तकालात व सरजीहातको ध्यानमें रखते हुए जो मसूख किये जासकते हैं और कोई यात दिवालके सम्बन्धमें नीचे दिये हुए कामको रद्द नहीं कर सकेंगी ।

(ए) अगर दिवालय किसी कर्जदारको कोई अदायगी करे ।

(बी) अगर दिवालियेको कोई अदायगी या सुपुर्दगी कीजावे ।

(सी) अगर दिवालय काफी मुआविजा लेकर कोई इन्तकाल ('Transfer') करे ।

(डी) अगर दिवालियेके साथ कोई मुआहिदा या व्योहार काफी मुआविजेके पवजमें किया जावे ।

परन्तु यह उसी वक्त ठीक होगा जबकि यह इन्तकालात दिवालय द्वारा दिये जाने वाले हुजमसे पहिले किये गये हों और जिम शरुकेके साथ यह सौदे हुए हों जिते सौदाके समय नहीं मालूम रहा हो कि कर्जदारने कोई दिवालिके दाखलस्तदी है या उसके खिलाफ कोई ऐसी दाखलस्त दी गई है ।

व्याख्या—

इस एकटमें उन सौदोंके उल्लेख है जो इस एकटके अनुसार रद्द नहीं किये जाना चाहिये । इस एकके भाग (१), (बी), (सी) व (डा) में उन सौदोंकी दिवालया गया है परन्तु साथही साथ यहभी बतला दिया गया है कि यह सौदे

उसी समय रद्द नहीं किये जासकेंगे जब कि नीचे दिये गये होती हों तथा वह पीछे नतलाये हुए किसी कानूनके अन्तर न आती हो अर्थात् इस एक्टकी दफा ५१, ५२, ५३, व ५४ के अनुसार जो सौदे रद्द हो सकते हैं वह यदि ब्राज (ए), (बी), (सी) व (डी) के अन्तरभी आते हों तो भी वह गृह किये जासकते हैं ।

इसी प्रकार इन श्रांतिमें नतलाये हुए सौदे उसी समय रद्द होनेस नच सकेंगे जबकि वह सौदे दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मके होनेसे पहिले किये गये हों तथा जिसके हकमें वह सौदे किये गये हों उसको उस वक्त तक इस बातका श्म न होने कि जो व्यक्ति सौदा कर रहा है उसने दिवालियेकी दारुप्राप्त देदी है वा उसके विरुद्ध किसी और ने दिवालियेकी दारुप्राप्त देदी है । यह दफा एक प्रकारसे नेक्नीयासे किये हुए सौदोंकी रखाकिये बनाई गई है अर्थात् इससे दिवालियेके कर्मदार व उसके कर्मचारि दोनोंकी रक्षा होती है यदि कोई सौदा नेक्नीयासे किया गया हो ।

क्लाज़ (ए) में उन अदायगीकी बचतका उल्लेख है जो दिवालिया अपने किसी कर्मचारीको करे व क्लॉज (बी) में उन अदायगीकी बचतका उल्लेख है जो दिवालियेका कोई कर्मदार उसे करे । इसी प्रकार क्लॉज (सी) व (डी) में उन शीरो व इन्तकामातका उल्लेख है जो काफ़ी घुआविता (Valuable Consideration) लेकर दिवालिये द्वारा या उसके हकमें किये गये हों । परन्तु इन क्लॉजोंकी देखते पहिले यह बतला दिया गया है कि इस दफासे पहिले जो नर्त बतलाई जाचुरी है उनकी अवहेलना नहीं की जावेगी अर्थात् उन सबका ध्यान रखते हुए ही इस दफाके अनुसार कार्यवाई हो सकेगी । इस एक्टकी दफा ५१ व ५२ में यह बतलाया गया है कि इनका पर दिवालियेकी कार्यवाईका क्या प्रभाव पड़ेगा तथा दफा ५३ व ५४ में यह बतलाया गया है कि कौन कौनसे सौदे व इतकालात् रद्द होंगे या रद्द किये जासकेंगे । इस प्रकार दफा ५१, ५२, ५३ व ५४ का ध्यान रखते हुए ही इस दफाके ब्राज (ए), (बी), (सी) व (डी) में नतलाये हुए सौदोंकी बचत हो सकेगी और साथही साथ उन शर्तोंके पूर्तिभी भी आवश्यकता है जो इस दफाके अन्तमें बतलाई गई है तथा जिसका उल्लेख ऊपर किया जाचुका है अर्थात् दिवालिया करार दिये जानेसे पहिले सौदा होना तथा सौदा करने वाले व्यक्तिको सौदा होनेके समय दिवालियेकी कार्यवाई होनेस श्म न होना इन दोनों शर्तोंकी भी पूर्ति होना चाहिये ।

यदि दिवालियेने कोई इन्तकाम जायदाद अपनी बीबीके हकमें उसके मरनेके पूर्वसमें कानून मोहम्मदी (Mohammed Law) के अनुसार कर दिया हो तो ऐसे इन्तकामकी रक्षा ब्राज (सी) के अनुसार हो सकती है । देखो—43 I. C. 280.

यदि इस्लामिक कर्मदारकी जायदादने हिन्दू रक्षकके हिसाबसे बांटेके लिये ले लिया हो तो ऐसे काफ़ी घुआविता समझना चाहिये तथा इस इन्तकामकी रक्षाकी जाचकती है, देखो—43 I. C. 602.

इस बातका भी भली भांति ध्यान रखना चाहिये कि बड़ी सौदे इस दफाके अनुसार रक्षके पात्र होंगे जो दिवालिये करार दिये जानेसे पहिले किये जाचुके हों अर्थात् दिवालिया करार दिये जानके पश्चात् यदि कोई सौदे हुए हों तो उनकी रक्षा इस दफाके अनुसार नहीं हो सकेगी, देखो—A. I. R. 1921 Bom 49.

जायदादका वसूल करना

दफा ५६ रिसीवरकी नियुक्ति

(१) अदालतको अधिकार है कि वह दिवालिया करार देते समय, उसके पश्चात् किसी समय दिवालियेकी जायदादके लिये रिसीवर मुक़रर करदे और उसके बाद वह जायदाद रिसीवर को मिलेगी ।

(२) नियत किये हुए नियमोंका ध्यान रखते हुए अदालतको अधिकार है कि वह:—

[ए] रिसीवरसे उस कदर जमानत दाखिल करनेकी कहे जो उसे मुनासिब समझ पड़े इस चास्ते कि वह जायदादके सम्बन्धमें जो पवित्रता उसका हिसाब देगा ।

[बी] इस बातका आग्रह या खास हुक्म देवे कि रिसीवरको दिवालियेके लहनेसे कितना मतालवा उसके काम करनेके पवजमें उसे बतौर उज़रतके मिलेगा ।

(३) जबकि रिसीवर नियुक्त किया जावे तो अदालतको अधिकार है कि अगर जायदाद किसी दूसरे व्यक्तिकी देखरेख या कब्ज़में होवे तो उस शख्सको हटा देवे। परन्तु इस एक्टके अनुसार अदालतको ऐसे शख्सको क़त्त ज़ या हिफ़ाज़तसे हटानेका इ़तिफ़ार न होगा जिसे हटानेका मौजूदा अधिकार दिवालियेको नहीं है ।

(४) जबकि इस दफ़ाके अनुसार नियुक्त किया हुआ रिसीवर:—

[ए] अपना हिसाब नियत किये हुए समय पर तथा नियत किये हुए ढंग पर दाखिल नहीं करे, या

[बी] अदालतके हुक्मके मुबाफ़िक़ बचा हुआ रुपया अदा नहीं करे, या

[सी] यह जानते हुए अपनी मलतीसे या बड़ी लापरवाहीसे जायदादको नुक़सान पहुँचता हो ।

तो अदालतको अधिकार है कि उसकी जायदादको कुर्क य नीलाम करादे और उस नीलामके रुपयेसे उस नुक़सानकी पूर्ति करे जो उसकी बजहसे हुआ है या उस वक़्तमें मुजरे से जो उसके पास रही है ।

(५) इस दफ़ामें दिये हुए नियम दफ़ा २० के अनुसार नियुक्त किये हुए दरमिथानी (Interim) रिसीवरके लियेभी लागू होंगे ।

व्याख्या—

इस दफ़ाका अभिप्राय यह है कि दिवालिया करार दिये जानेके फ़ौरान अदालत दिवालियेकी सब जायदाद पर क़ब्ज़ा के लिये जिसके बिना उसके कर्ज़ेदारोंमें हिस्सा रमदीके हिस्सामें बाँटी जासके और चूँकि अदालतके लिये स्वयं इस प्रकारका काम करना कठिन है इस कारण रिसीवरकी नियुक्ति का क्रम रख दिया गया है । दफ़ा २० के अनुसार दिवालियेके जायदादकी रक्षाके लिये दरमिथानी (Interim) रिसीवर का नियुक्त किया जाना बनवाया गया है जो कि दिवालिया करार दिये जानेसे पहिले नियुक्त किया जासकता है । परन्तु इस दफ़ाके अनुसार रिसीवरकी नियुक्ति बाद दिवालिया करार दिये जानेके होगी तथा वह दिवालियेकी जायदादकी वसूल करने तथा उसके कर्ज़ेदारोंमें हिस्सा रमदीके हिस्सेसे चाहेके लिये नियुक्त किया जावेगा । रिसीवरकी नियुक्ति करनेमें अदालतको भी अधिकार प्राप्त है तथा उसकी नियुक्ति होनेके फ़ौरान अदालतकी उसके क़ाबमें हस्तक्षेप करनेके जो अधिकार प्राप्त है उनका उल्लेख भी इस दफ़ामें किया गया है साथ साथ यह भी बनवाया गया है कि दरमिथानी (Interim) रिसीवरके लिये भी इस दफ़ामें बनलये हुए नियमोंका प्रयोग किया जावेगा जब तक कि उनका इन नियमोंसे सम्बन्ध न हो ।

उपदफा (१) रिश्वर, दिवालिया करार दिये जाने। हुकम होते समय या उसके पश्चात् हम उपदफाके अनुसार नियुक्त किया जा सकता है यदि दिवालिया करार दिये जाने वाले हुकमको ७ साल का गय हो तो हम देखेंगे जनेहीके कारण रिश्वरकी नियुक्ति केनार नहीं किया जायगा अर्थात् हम समयकी दिवालियेकी जायदादके लिये आवश्यकता पड़ने पर रिश्वर नियुक्त किया जासकेगा देखो—A I R 1924 Cal. 849 ऐसा प्रगट होता है कि दिवालियेकी जायदादके कुछ हिस्सेकी के लिये रिश्वर नियुक्त नहीं किया जा सकता है अर्थात् रिश्वरकी नियुक्ति दिवालियेकी सन जायदादके लियेही होनी चाहिये उनके जुन हिस्सेकी के लिये नहीं देखो—A I. R. 1925 Rang 224.

अबकि रिश्वरकी नियुक्ति न की गई हो तो दिवालियेकी सन जायदाद दफा २८ (२) के अनुसार दिवालिया करार दिये जानेके समयसे अदालतकी समझा जावेगी अतः यदि रिश्वरकी नियुक्ति दिवालिया करार दिये जाने वाले हुकमके पश्चात् की जावे तो पहिले दिवालियेकी जायदाद अदालतकी होगी उसके पश्चात् रिश्वरकी नियुक्ति होने पर वह जायदाद अदालतसे रिश्वरकी समझा जावेगी ।

इस दफामें यह नहीं बताया गया है कि कौन व किस प्रकारका व्यक्ति रिश्वर नियुक्त किया जाना चाहिये । देखो—39 All. 159 में यह तय हुआ था कि बर्जम्बाहमें से कोई व्यक्ति रिश्वर नियुक्त किया जा सकता है परन्तु इसके पश्चात् देखो—L R 3 A. 85 में यह तय किया गया कि अदालतकी चाहिये कि वह दिवालियेके किसी वक्ताकी उसकी जायदाद वस्तु सर्वेक्षित लिये रिश्वर नियुक्त न रहे ।

यदि रिश्वरके बर्जियोंको करनेके लिये कानूनी योग्यताकी आवश्यकता है अतः वह उचित प्रतीत होता है कि कोई कानूनी योग्यता रखने वाला व्यक्ति रिश्वर नियुक्त किया जावे देखो—50 L. C. 117. रिश्वरकी नियुक्ति तथा उनका इशारा जाता देखो बान् अदालत पर निर्भर है अर्थात् दोनोंका अधिकार अदालतकी श्रास है देखो—46 Mad. 405, A. I. R. 1923 Mad. 355

रिश्वरको अदालत नहीं समझता चाहिये किन्तु वह अदालतका एक अङ्ग है जिसके द्वारा अदालत दिवालियेकी जायदाद पर कब्जा रखती है तथा उस पर अपने अधिकारका प्रयोग करती है देखो—42 IC 799 अदालत अपने कानूनी अधिकार (अर्थात् पैसला करनेके अधिकार) रिश्वरको नहीं दे सकती है किन्तु आवश्यकतानुसार वह रिश्वरको किसी मामलेका तहकीकात छुट्टी कर सकती है जिसमें रिश्वर बाद तहकीकात अपनी प्रिपर्ट अदालतके सामने पेश कर सके । श्रास काय कामके लिये रिश्वरकी प्रिपर्ट बनाए जाइएके समझी जावेगी देखो दफा ३२ (२) तथा ३८ (३) 86 L. C 908.

दिवालियेके रिश्वर तथा दीवानोंके और मामलोंमें नियुक्त किये हुए रिश्वरके अधिकार एक्ट में नहीं हैं किन्तु उन दोनोंकी श्रासमें अंतर है देखो—A I R 1924 Pat 259, A. I R. 1924 All. 40 जिसमें कि यह बताया गया है कि जबकि दीवानोंके अनुसार किसी जायदादके लिये नियुक्त किया हुआ रिश्वर उस जायदाद पर अदालतकी तरफसे कब्जा रखता है । वह जायदाद उसकी नहीं हो जाती है और न वह उस जायदादका किसी प्रकार प्रतिनिधित्व है और यदि उसके फकीक मुकद्दमा बनाए जायदाद पर पबन्दा लगा हो तो अदालतकी आज्ञासे वह फकीक मुकद्दमा इसके लिये बताया जाया चाहिये । परन्तु कानून दिवालियाके अनुसार जो रिश्वर नियुक्त किया जाता है वह उसके निष्कर्षोंके विषय में वह बस अदालतका अङ्ग नहीं है किन्तु दिवालियेकी जायदाद उसकी हो जाती है और वह उस जायदादका प्रतिनिधि हो जाता है और सभी कारण यदि दिवालियेकी जायदादके सम्बन्धमें कोई मुकद्दमा चलाया जावे तो उसे अवश्य फकीक मुकद्दमा बताया जाना चाहिये और उसकी फकीक मुकद्दमा बनाते समय अदालतकी आज्ञा लेनेकी आवश्यकता नहीं है । इस एक्टके अनुसार रिश्वर नियुक्त किये जातेही दिवालियेकी जायदाद उसकी हो जाती है और इस बातकी आवश्यकता नहीं है कि अदालत आज्ञा देने कि दिवालियेकी जायदाद रिश्वरकी हो गई है । मगर हाईकोर्टने यह तय किया है कि दिवालिया

प्रकार दिये जानेका हुक्म होतेही दिवालियेकी जायदाद आफिशल रितीवारकी नहीं हो जावेगी किन्तु इस दफ्तरके अनुसार उसे रितीवार नियुक्त करनेका हुक्म दिया जाना चाहिये अर्थात् दूसरे शब्दोंमें जायदादकी सुपुर्दगीका हुक्मही जाना चाहिये और बिना इसके वह दिवालियेकी जायदादके सम्बन्धमें कोई कार्य नहीं कर सकता है देखो—47 Mad. 462, A. I. R. 1924 Mad. 461.

इस कारण यदि ऐसी नियुक्तिका हुक्म न दिया गया हो तो आफिशल रितीवारसे खर्चदने वालका ठीक इक जायदारमें नहीं पहुँचेगा देखो—A. I. R. 1927 Mad. 1 यदि इस प्रकारका हुक्म होनेसे पहिले आफिशल रितीवार किसी जायदादकी बेंच देवे तो बेंचनेके बाद भी ऐसा हुक्म दिया जासकता है तथा उस हुक्मके होने पर वह सौदा ठीक समझा जासकेगा देखो—A. I. R. 1925 Mad. 249

जबसे कि दिवालियेकी जायदाद रितीवारकी सुपुर्दगीमें आनाभरी है वह उस दिवालियेके कर्जदारोंका एक प्रकारसे प्रतिनिधि हो जाता है और उसको चाहिये कि वह उनके हकोंकी रक्षा हर प्रकारसे करे। और यदि वह किसी मामलेकी उनके लाभके लिये ब्याज करना आवश्यक न समझे परन्तु कोई बर्जएवाह यह चाहता हो कि मामला अवश्य चालू किया जावे तो रितीवारकी चाहिये कि वह उस बर्जएवाहसे मुकद्दमोंके खर्चके लिये इत्तमीनान कर लेनेके बाद उस मामलेकी ब्याज कर देवे देखो—38 I. C 771.

उपधका (२)—रितीवारके सम्बन्धमें जो नियम ॥१॥ एक्टके लिये बनाये गये हैं उनका मानना आवश्यक है उन नियमोंका पालन करते हुए अदालतकी अधिकार है कि वह रितीवारसे जमानतकी लेलेवे जिसमें कि वह उस जायदादके सम्बन्धमें हिसाब दाखिल करा सके जोकि रितीवारके क़ाबज़में आई हो तथा अदालतका यह भी अधिकार है कि वह दिवालियेकी जायदादमेंसे रितीवारकी उसके काम करनेके एजमें कुछ क़यास मंतर उमरतके दिलवनेका हुक्म देदेवे। यदि अदालत जमानतकी शर्तके माफ रितीवार नियुक्त करनेका हुक्म देवे तो जब तक जमानत दाखिल न हो जावे रितीवारकी नियुक्ति पूरी रूपसे न समझना चाहिये और यदि रितीवार अदालतके हुक्मके अनुसार जमानत देदेवे तो उसकी नियुक्ति उस तारीखसे मानी जावेगी जबसे कि अदालतका हुक्म उसकी नियुक्तिके लिये हुआ है। और यदि अदालतके हुक्ममें जमानतके सम्बन्धमें कोई जिक्र न हो तो रितीवारकी नियुक्ति उसी तारीखसे पूरी मामली जावेगी।

रितीवारके श्रमफल (Remuneration) के बारेमें निश्चित करना अदालतका कर्तव्य है चाहे वह इसे अपने आप हुक्म द्वारा निर्धारित कर देवे अथवा वह इसके बारेमें कोई खास हुक्म कर देवे। इससे यह प्रगट है कि रितीवार एक प्रकारसे अदालतका अनुचर है और वह किसी दूसरे व्यक्ति अपना श्रमफल पानेका अधिकारी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अदालतकी आज्ञा लिये बिना रितीवारकी उसका श्रमफल देनेका वादा कर देवे तो यह एक प्रकारसे बदा अनुचित कार्य होगा और इस प्रकारका समझौता करने वाले व्यक्ति अदालतका अपमान करनेके भागी होंगे देखो—22 Cal 648.

फ़ीस श्रमफल (Honorarium)—कितना होना चाहिये इस बातकी अदालतही तय करेगी। बहुधा यह श्रमफल सेरबा पीछे या कमीशनके तौर पर तय किया जाता है परन्तु अदालतकी अधिकार है कि वह इसके बजाय माहवारी बेंचनके रूपमें भी यह श्रमफल दिलवा देवे यह क़यास दिवालियेकी जायदादकी से दिलवाया जावेगा और दिवालियेके उत्तराधिकारी आता तीसरे इसके अदा करनेके ज़िम्मेदार नहीं हो सकेंगे देखो—26 I. C 583 जायदादके सब नफ़े (Charges) को चुकानेके पत्रचालू जो ज़ासता (Assets) रितीवारके पास बचेगा उस पर रितीवारके कमीशन या श्रमफलका भार रहेगा।

यदि रितीवारने दिवालियेकी जायदादकी वसूल किया हो तो वह उससे अपना कमीशन पानेका हक़दार हो जावेगा और यदि दिवालिया क़ार दिये जावे बांठा हुक्म मसख़गी कर दिशा जावे तो भी वह अपना कमीशन पानेका हक़दार बन रहेगा देखो—8 Mad. 79

बनई हाईकोर्टके अनुसार रितीवरका कर्षाशन ५) रूपया बैंकसे अधिक नहीं नियत किया जाना चाहिये तथा यह कमीशन उन रूपयोंके अनुसार मिलना चाहिये जो बचौर हिस्सा रखनेके बाद जाने वाला होवे, देखो—A. I. R. 1925 Bom 172. रैतकी हुई जायदादमें रितीवरकी कमीशन उहाँ रूपयोंके अनुसार मिल सकेगा जो रैतके बारको निशान देनेके बाद बच पूर्ण जायदादकी कीमतके अनुसार नहीं मिलेगा, देखो—12 Bom. 272, 21 All 227, 36 Cal. 990, A. I. R. 1925 Nag 150, A. I. R. 1928 Rang. 23.

उपदफा (३)—इस उपदफाके अनुसार अदालतको अधिकार है कि वह रितीवरकी नियुक्तिके पश्चात् यदि दिवालियेकी जायदाद किसी दूसरे व्यक्तिके अधिकारमें होवे तो उसे उस व्यक्तिके अधिकारसे लेके परन्तु ऐसी जायदाद उसी व्यक्तिसे छुड़ाई जासकेगी जिससे कि दिवालिया स्वयं छुड़ा सकता हो अथवा नहीं इस बातके अनुसार जायदाद उस व्यक्तिसे कब्जेसे नहीं छुड़ाई जासकती है जो *Adverse possession* (अधिकाधिकार) रखता हो या जो बिना अदालती कार्यवाईके दिवालिये द्वारा भी नहीं हटाया जासकता है, देखो—46 L. C. 377, 49 Mad. 762 यदि किसी व्यक्तिका कब्जा जायदाद पर किसी इतकाल जायदाद (Transfer) के जरिये हुआ हो और चाहे वह इतकाल दफा ५४ के अनुसार कबिल मसूली होवे तो भी ऐसे व्यक्तिमें जायदादका कब्जा इस उपदफाके अनुसार नहीं किया जासकता है, अब तक कि वह इतकाल रद्द न कर दिया जावे, देखो—A. I. R. 1925 Rang 224 इस उपदफाके अनुसार कार्यवाई करते समय अदालतको चाहिये कि दीवानाके माफकारी तरह समझ बूझ पर कार्यवाई करे और माफलेकी बाकायदा सुने जैसे कि दीवानाके मामले सुने जाते हैं, देखो—37 All 65

इस दफाके अनुसार कार्यवाई करनेसे पहिले अदालतको चाहिये कि वह कोई स्थाई रितीवर नियुक्त कर देवे अर्थात् इन्टरिया (Interim) रितीवरकी नियुक्त न करावने दे, देखो—A. I. R. 1926 Pat 291 यदि दिवालिया क्रयार दिये जानेके बाद तथा रितीवर नियुक्त किये जानेके बाद दिवालियेकी कोई जायदाद इनकारमें बँच दी गई हो तो रितीवरको अधिकार है कि वह ऐसे नीतिमयी मसूली तथा बँची हुई जायदाद पर कब्जा लेनेकी दायवारा इस दफाके अनुसार अदालत दिवालिशायी दे सके, देखो—44 Mad. 524.

॥ उपदफाके अनुसार केवल रितीवर ही दाखलास्त नहीं दे सकता है किन्तु वह व्यक्ति भी दे सकता है जिसने रितीवरसे जायदादकी खरीदना इति, देखो—45 Mad 434, A. I. R. 1922 Mad. 147. यदि इस उपदफामें दी हुई शर्त (Proviso) का ध्यान न रखते हुए अदालत कोई फैसला कर देवे तो उस फैसलेके फलितके इक पूर्ण रूपसे निश्चित किये हुए नहीं माने जायेंगे, देखो—49 Mad. 762 अर्थात् जो अदालतको दफा ४ के अनुसार किसी एकको तय करनेका अधिकार प्राप्त हो, परन्तु इस उपदफा की शर्त (Proviso) उसमें बाधक पड़ती हो तो अदालतको दफा ४ के अनुसार कार्यवाई नहीं करना चाहिये । और इसी कारण ऐसे प्रयत्नोंको इल करना एक प्रयास अदालत दिवालिशायीके लिये समय नष्ट करता है और उसे चाहिये कि वह ऐसे प्रयत्नोंको नगरी नालिशमें तय होने देवे देखो—A. I. R. 1924 Mad. 387. इस दफामें यह नहीं बतलाया गया है कि रितीवरको किस विधायके अन्दर कब्जा ले लेना चाहिये अर्थात् रितीवर दिवालियेकी कार्यवाईके दौरानमें किसी समय भी कब्जा प्राप्त कर सकता है ।

उपदफा (४) इस उपदफाके अनुसार अदालतकी रितीवरके कार्योंमें हस्तक्षेप करने तथा उससे इना आदि नसूल करनेका अधिकार प्राप्त है अर्थात् अदालत आवश्यकताप्रकार रितीवरके उचित दण्ड दे सकती है इस उपदफामें रितीवर द्वारा की जाने वाली सब गलतियाँ नहीं दिखाई गई हैं केवल याचकी धनियोंको उल्लेख करके (ए), (बी) व (सी) में कर दिया गया है और न इस उपदफामें उन सब सम्पत्तियोंकी वर्णन है जो रितीवरका उसकी प्रशक्तियोंके धाम्य दी जासकती है क्योंकि इनमें सिर्फ रितीवरकी जायदादको वर्णन करने तथा उसमें उससे हुज्जती पूर्ण करनेकी का शिष्ट

है। जब अदालत रिसीवरको नियुक्त कर सकता है तो उसे उससे इत्यनेन भी अधिकार अवश्य प्राप्त सम्भवा चाहिये। इस प्रकार जिस प्रकारसे जुर्माने रिसीवर सेगा उसा प्रकारका दण्ड पानेका भागी होगा। इस उपद्रवाम यह नहीं बननाया गया है कि रिसीवरकी गलतियाँ अदालतका सैन बनना सरेगा परन्तु यह बात प्रष्टही है कि अत्यन्त यदि किसी गलतीसे दंड तो वह स्वयंही उस गलतीका पम्ब सकती है तथा उमके अनुसार रिसीवरको दण्ड दे सकती है और चूकि रिसीवर एक पब्लिक सर्वेंट है इस कारण कोई भी व्यक्ति उसकी गलतियोंको अदालतके सामने रख सकता है। अर्थात् जिस किसी भी व्यक्ति को रिसीवरकी गलतियोंकी बजहसे हानि उठाना पड़ उसे अधिकार है कि वह रिसीवरकी उस गलतीको अदालतके सामने रख देवे जिसमें अदालत तहकाकानके बाद रिसीवरको उचित दंड दे सके। रिसीवरकी अदालतका एक अफसरही सम्भना चाहिये वह स्वयं अदालत नहीं है और इसी कारण उमें कोई गलती जातुनर तय करनेका अधिकार प्राप्त नहीं है और न वह कानूनी अफसरोंकी ताई किसी मामलेकी कानूनी तहकाकत ही कर सकता है।

जो रिसीवर अदालत नहीं दे निन्तु उमके कार्योंमें हस्तक्षेप करनेमें अदालतकी तोहनीया हर्म लगाया जासकता है चूकि वह अदालतका एक प्रकारका एजेंट है इस कारण उमके कार्योंमें कडावट डालना या हस्तक्षेप करना एक प्रकारमें अदालतके हुक्मकी अवहेलना करना है और र्मालिये अदालतकी तोहनी (Contempt of Court) का हर्म लगाया जासकता है, देखो—6, B. L. R 486, 9 1 C 485, 28 Cal 790; 26 C. L. J. 345.

उपद्रवा (५) इस उपद्रवमें यह बननाया गया है कि दफा २० के अनुसार नियुक्त किये हुए दफियाकी रिसीवरके लिये भी वही बात लागू होगी जो कि र्मालिये लिये बनलाई गई है और जहा तक उसका तात्त्विक उनसे है।

दफा ५७ सरकारी रिसीवरोंको नियुक्त करनेके अधिकार

(१) प्रान्तिक सरकारको अधिकार है कि वह जिन लोगोंको उचित समझे किसी खास मुकदमा दंडके लिये इस एक्टके अनुसार रिसीवर बना देवे यह रिसीवर सरकारी रिसीवर (Official Receivers) कह लायेंगे।

(२) अगर किसी अदालतकी अधिकार सीमाके लिये कोई सरकारी रिसीवर नियुक्त किया गया हो तो वह रिसीवर अदालतके रिसीवर या दफियानी रिसीवर नियुक्त करने वाले संय हुक्मोंके अनुसार काम करेगा जब तक कि अदालत इसके विरुद्ध किसी विशेष कारणवश कोई दूरी आज्ञा न दे।

(३) जो रुपया दफा ५६ (२ बी) के अनुसार सरकारी रिसीवरको उसके कामकी वजहसे मिलना चाहिये वह रुपया प्रान्तिक सरकार द्वारा निश्चित किये फाइमें जमा किया जावेगा।

(४) उस फाइसे या और किसी जगहसे सरकारी रिसीवरको उतनाही रुपया धमफल के रूपमें मिलेगा जितना प्रान्तिक सरकार इस मदमें निश्चित कर देगी और उस निश्चित किये हुए रुपयसे कुछ भी अधिक बतौर धमकल (Remuneration) के सरकारी रिसीवरको न मिलेगा।

व्याख्या—

उपद्रवा (१) इस दफामें सरकारी रिसीवर (Official Receiver) नियुक्त किये जायेंगे वर्णन है। अन्तिम सरकारी अधिकार प्राप्त है कि वह सरकारी रिसीवरको नियुक्त कर सके तथा ऐसे नियुक्त किये हुए रिसीवरकी

अधिवार सीमा भी निर्धारित कर सके । चूकि अगरेजी एक्ट की हम दफा १११ की नियुक्त मध्य में (May) शब्द प्रयोग किया गया है इससे यह प्रष्ट है कि सरकारी रिसीवर (Official Receiver) की नियुक्ति के लिये शक्ति सरकारी बाध्य नहीं है किन्तु यदि वह चाहे तो नियुक्त कर सकती है और यदि न चाहे तो नियुक्त न करे ।

उपदफा (२) यदि किसी जगह के लिये सरकारी रिसीवर (Official Receiver) नियुक्त कर दिया गया हो तो अधिकतर वहाँ रिसीवर इस एक्ट की दफा २० व ५६ में बतलये हुये रिसीवर का काम करेगा और बिना किसी छाप बन्दहे अदालत उन जगहोंमें आकिश्वर रिसीवरके अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति को रिसीवर नियुक्त नहीं करेगा 46 Mad. 405. अर्थात् जिन जगहोंके लिये प्राधिकृत सरकार द्वारा आकिश्वर रिसीवर नियुक्त का दिया गया हो तो वहाँ रिसीवर दायित्वाली रिसीवर (Interim Receiver) या रेगुलर रिसीवर (Regular Receiver) नियुक्त किया जावेगा परन्तु अदालतको अधिवार है कि यदि वह किसी खास कारणसे किसी अन्य व्यक्ति को दायित्वाली या रेगुलर रिसीवर नियुक्त किया चाहे तो नियुक्त कर सकती है । यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि दिवालिवा करार दिये जानेवाले हुकम होने ही दिवालिवा की जायदाद जमाने जायदाद आकिश्वर रिसीवरकी नहीं हो जायदाद किन्तु अदालतका हुकम होने पर वह दिवालिवा की जायदाद वास्तविक और ऐसा हुकम होनेमें पहिले उसे दिवालिवा की जायदादके सम्बन्धमें कोई कार्य करनेवाँ अधिवार नहीं है और न वह उसकी जायदाद बैंक का जमानेवाँ ही पूरा हर पक्षवा मन्त्रा है देखो—63 I. C. 896; 1924 Mad 461. परन्तु यदि कोई आकिश्वर रिसीवर सुपुर्दगीका हुकम होनेमें पहिले दिवालिवा की किसी जायदादकी बैंक देखे तो अदालत द्वारा दिये हुए बादके हुकममें वह सीधा ठीक किया जायसकता है अर्थात् जायदाद बैंक जाने समय तो एक प्रकारसे वह इन्टरमिट्ट जायदाद घटकही है और उसमें खरीदने वालों को कोई हक नहीं पहुँचना है परन्तु यदि अदालत बादमें उसकी मंजूरी दे देवे तो वह बचतवा सीधे सम्पत्तिवा चाहिये देखो—43 Mad 869, A. I. R. 1925 Mad. 249.

आकिश्वर रिसीवरको वह सब अधिवार प्राप्त होंगे जो दायित्वाली रिसीवर या मामूली रिसीवरको जो दफा २० या दफा ५६ के अनुसार नियुक्त किये जाते हैं प्राप्त हो सकते हैं इनके अतिरिक्त 'उने वह भी विशेष अधिवार प्राप्त हो सकेंगे जिनका उल्लेख दफा ८० में किया गया है और उस दफाके अनुसार वह जो काम करेगा या हुकम देगा उसे अदालतका काम या हुकम समझा जावेगा । इन प्रकार दफा ८० के अनुसार कार्यवाई करनेके सम्बन्धमें आकिश्वर रिसीवरको एक प्रकारसे अदालतके अधिवार प्राप्त हैं परन्तु हर मामलेके लिये उसे अदालत नहीं समझना चाहिये ।

उपदफा (३) आकिश्वर रिसीवर तथा मामूली रिसीवरकी हालतमें कुछ अन्तर है । मामूली रिसीवरको बड़ी सम्पत्ति (Remuneration) मिल सकती है जो अदालत उसके लिये दफा (२) (बी) के अनुसार निर्दिष्ट करे परन्तु आकिश्वर रिसीवरके सम्बन्धमें वह सम्पत्ति (Remuneration) एक फार्ममें जमा किया जावेगा तथा वह इस फार्ममें से वहाँ नियत किया हुआ वेतन प्राप्तवेगा जो प्रान्तिक सरकार उसके लिये निर्दिष्ट कर देवेगी । अदालतकी अधिवार है कि वह किसी खास कारणके उपरिष्ठ होने पर आकिश्वर रिसीवरको हटा देवे देखो—46 Mad 405

दफा ५८ अदालतके अधिकार जत्र कि रिसीवर नियुक्त न किया गया हो

अधिक कोई रिसीवर नियुक्त नहीं किया गया हो, तो अदालतको वह सब अधिकार प्राप्त होंगे जो इस एक्टमें रिसीवरके लिये दिये गये हैं तथा वह उन सब अधिकारोंका प्रयोग कर सकती है जो रिसीवरके लिये बतलाये गये हैं ।

व्याख्या—

इस दफामें यह बतलाया गया है कि यदि किसी मामलेमें रिसीवरकी नियुक्ति न की जावे तो उस समय अदालतको

स्वयं वह सब अधिकार प्राप्त होंगे जो रिसीवरके लिये बतलाये गये हैं। इससे यह न समझ लेना चाहिये कि अदालत जो काम रिसीवरके करेगी वह रिसीवरकी हैसियतमें कोगी अर्थात् इस दफ्तरके अनुसार अदालत जो काम करेगी वह अदालतकी हैसियतमें कोगी और उनके अदान्तका कामही समझना चाहिये देखो—62 I. C. 307. जो अदालतकी इस दफ्तरके अनुसार वह सब अधिकार प्राप्त होंगे जो रिसीवरके लिये बतलाये गये हैं परन्तु यह आवश्यकता नहीं है कि अदालत उन सब अधिकारोंका प्रयोग अवश्य करे अर्थात् अदालत जिन अधिकारोंका प्रयोग किया चाहे कर सकती है तथा जिन अधिकारोंका प्रयोग न किया चाहे नहीं कर सकती है। उनका प्रयोग करना न करना आवश्यकता व अवसरके अनुसार समझना चाहिये जैसा कि अंग्रेजी एक्टरी इस दफ्तरमें दिये हुए (May) शर्तमें प्रकट होता है। अदालत स्वयं दिवालियेकी जायदाद पर कब्जा ले सकती है तथा दूसरेकी साबित होने पर उसे छेड़ सकती व इसी प्रकार वह किसी बर्जखवाइके कइने पर किसी इतकाफ जायदादको मसूल कर सकता है अर्थात् वह तब काम कर सकता है जो नियुक्त किया हुआ रिसीवर कर सकता है देखो—A I. R. 1923 Nag 97, 78 I. C. 140.

दफा ५९ रिसीवरके कर्तव्य व अधिकार

इस एक्टमें दिये हुये नियमोंके अनुसार रिसीवर जितनी जरूरी हो सकेगा कर्जदारकी जायदाद वसूल करेगा व उन कर्जखवाहोंमें उसे तकसीम करेगा जो पानेके मुस्तहक हैं और ऐसा करनेके लिये वह —

- (ए) दिवालियेकी सब जायदाद या उसका कोई हिस्सा बेंच सकता है।
- (बी) जो रुपया उसे मिले उसकी रसीद दे सकता है और अदालतकी स्वीकृत लेकर भीच दिये हुये सब या कोई काम कर सकता है।
- (सी) दिवालिया का रोजगार उस हद तक चालू रख सकता है जिससे कि वह सुभीतेके साथ बंद किया जासके
- (डी) दिवालियेकी जायदादके लिये मुकद्दमा या कोई अदालती कारवाई शुरू कर सकता है या उसकी जवाबदेही कर सकता है या दायर हुये मामलोंको चालू रख सकता है
- (ई) अदालत द्वारा स्वीकृत प्राप्त हुये रोजगार या कारवाईके करनेके लिये वकील या कोई दूसरा एजेंट नियुक्त कर सकता है
- (एफ) दिवालियेकी जायदाद इस शर्त पर बेंच सकता है कि उसकी सीमात आयन्दा मिलेगी लेकिन जमानत या दूसरे किसमकी उन शर्तोंके साथ ऐसा करना चाहिये जो अदालत उचित समझे
- (जी) दिवालियेकी जायदाद का कोई हिस्सा रहन या गिरवी रख सकता है जिससे उसके कर्जों की आवश्यकताके लिये रुपया वसूल किया जा सके।
- (एच) कोई भगड़ा पंच फैसलेके लिये दे सकता है और निश्चित की हुई शर्तोंके अनुसार सब कर्जों दावों व जिम्मेदारियोंमें राजीनामा कर सकता है

(आई) जब कि कोई जायदाद अपनी अजीव शकल या किसी दूसरे कारणसे फौरन या फायदेके साथ बेची नहीं जा सकती हो तो उसे उसकी मौजूदा शकलमें उसकी अम्दाज लगाई हुई कीमतके अनुसार कर्जखाहमें बांट सकता है ।

न्याय—

इस दफा में रिश्वरके बतौरों तथा उनके अभिप्रायोंका उल्लेख किया गया है । तथा यह बतलवाया गया है कि इस एकट सम्बन्धी नियमारा ध्यान रखते हुए रिश्वरको चाहिए कि वह अन्तम जन्दा दिवालिया कदना वसूल करके उसके उन कर्त-रुनाहोंमें बाट देने जा उस लहनेरी पावक हुकूम है । रिश्वर लहनेरा अन्दावसूल करने तथा उसरा हिस्सा रसदाक हिस्सा वस बाटनेके सम्बन्धमें उन सब बाणोंरा या उचमेंसे किया बातरा प्रयोग कर सकता है गिदरा वर्णन प्राय (९) से लेकर प्राय (आठ) तक किया गया है । परन्तु इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि वह प्राय (९) व (बी) के अनुसार बर्तवाई अपनी । अनुसार कर सकता है अर्थात् इसका क्रिय उम अदालतका आज्ञा बिना क्यम लनकी आवश्यकता नहीं है परन्तु प्राय (सा) से लेकर प्राय (आठ) तक जो बाँव था बतलाई गई है उनके बरनेके क्रिये उसे अदालतसे आज्ञा लेना आवश्यक है । चूकि रिश्वर एक समकारी अकूमर है इसीसे उसको चाहिये कि वह अदालतकी आज्ञाके अनुसार ही बर्तवाई करे अपौर जिन कामोंके लिये अदालतकी आज्ञा लेना मतलाया गया है यदि वह उन कामोंसे बिला अदालतका आज्ञा करे तो वह काम ठाक नहीं माने जावेंगे । यदि रिश्वरके विरुद्ध कोई शिकायत अदालतमें इस विषयकी की जावे कि उसने किसी बयनामके लिये मजबूर नहीं दा है ता रिश्वरका कर्तव्य होगा कि वह अदालतके सामने उपस्थित होवे तथा उम विषयक सम्बन्धी सब बात उक्त सामने रखे—A. I. R. 1924 Mad 147

कलाज (ए) रिश्वरकी दिवालियाकी जायदाद बेचनेसे पूर्ण अधिकार प्राप्त है वह उसी सब जायदादकी या उम जायदाद क किसी हिस्सेसे बेच सकता है ।

जायदाद (Property) सन्दरी परिभाषा दफा २ (२) (बी) में दी जाचुकी है रिश्वर का यह भी कर्तव्य है कि वह दिवालियाकी जायदादको जितना जल्द हो सका बेच देवे । चूकि रिश्वर स्वय अशक्त नहीं है इसलिए उसके द्वारा जायदादके बेच जाने में यह तात्पर्य न समझना चाहिये कि वह जायदाद अशक्त द्वारा बेची गई है और इसी कारण रिश्वर द्वारा किये हुए बयनामके सम्बन्धमें वह नियम लागू नहीं है जो अदालत द्वारा किये हुए नीलाममें लागू होते हैं देखो—50 Mad 135. यदि रिश्वरने किना जायदादको बेचा हो या वह बयनामा रिश्वरके साक्षिपत्र ही दा देने मानने पूरा नहीं हो जायगा निरु रिश्वरकी चाहिये कि उसके क्रिये बाकायदा दस्तावेज बयनामा तहरीर कर ओर उस पर कानून के अनुसार रकम लगाया चाहिये तथा फायदेके अनुसार उनकी राजस्वी भा रवाई जाना चाहिये । बयनामाकी अनिवार्य बँसोही करी जायगा जेसी साधारण बयनामाकी दखो—46 Cal 887.

रिश्वर जायदादको बचनेके लिय उसको आम नीलाममें बेच सकता है तथा यदि वह चाहे तो उसे प्रायः तौर पर भी बेच सकता है अगर जायदादकी सुगुणसिद्धी खमिन लगे देखा—60 I C 745 रिश्वरके शिवाका या हुकूमकाना मामला चलाया जा सकता है जबकि उसने जायदादको इस दफाके अनुसार बचा हो देखा—27 All 670

रिश्वर द्वारा किये हुए बयनामका प्रसूतीक क्रिय आर्डर २१ रू १० जानना दीवानीक अनुसार दारवास्त नहीं दी जाननी है 44 I C 883 रिश्वर स्वय भा अपने क्रिय हुए बयनामों को मम्मा नहीं कर सकता है वरोंक उस बयनाममें उसके तथा खरीदारके दम्भियान एक प्रकार सुआदिदा पूरा हो जाना है और उस सुआदिदका तादन या उयक विरुद्ध कस का कोई अधिकार अपने आप रिश्वर के पास नहीं रह जाता देखो—1926 M W 688.

परन्तु यदि जायदादके बँचनेमें वतलीबीकी गई हो या कोई बदलीवर्तसे काम किया गया हो तो अदालत को अधिकार है कि वह ऐसे बयानों को मसूल कर देने देलो—A. I. R. 1923 Mad. 350, 40 All 582.

यदि आर्किवल रिसीवरने कोई सम्पत्ति अदालतकी आज्ञा लिये बिना कर लिया हो अर्थात् किसी मामलेकी कुछ वसूलीके तय कर लिया हो तो इस प्रकारका सम्पत्ति रद्द नहीं सम्झा जावेगा और जब तक कि यह सम्पत्ति रद्द न कर दिया जावे तब तक माननीय होगा इजाजत का लेना एक इतजामी हुक्म है व उसका सम्भव रिसीवरसे ही देखो—A. I. R. 1929 Sindh 41.

फलाज (बी) रिसीवरको अधिकार है कि वह दिवालयिये का खर्चा वसूल करके उसके लिये रसीद दे सकता है इससे तात्पर्य यह सम्झना चाहिये कि यदि दिवालयिये सम्बन्धमें कोई व्यक्ति अपना देकर रिसीवरसे रसीद हासिल कर लेवेतो वह रसीद पर्याप्त होगी तथा दुबारा उस व्यक्ति से इस प्रकार जमा किया हुआ खर्चा नहीं माया जासकेगा। जिन कार्योंका उल्लेख ज्ञान (सी) से लेकर ज्ञान (आई) तकमें किया गया है उन कार्योंके करनेके लिये रिसीवरका कर्तव्य है कि वह अदालतकी आज्ञा प्राप्त करे।

एकदम यह कहें भी नहीं बतलाया गया है कि अदालतकी आज्ञा किस प्रकार लेना चाहिये परन्तु यह अवश्य तय किया गया है कि इसके लिये लिखित आज्ञाके लेनेकी आवश्यकता नहीं है और न इस बातकी आवश्यकता है कि वह आज्ञा किसी खास प्रकारकी होना चाहिये देखो—A. I. R. 1926 Nag 156

परन्तु अदालतकी आज्ञा काम करनेसे पहिलेही छी जाना चाहिये यदि काम करनेसे पहिले अदालतकी आज्ञा न ली गई हो तो केवल इसी कारण वह काम रद्द न सम्झना चाहिये क्योंकि आज्ञाका लेना रिसीवर तथा अदालतके बीचका काम है और कामके बादभी यदि अदालत उस कार्यके लिये अपनी स्वीकृति देदेवे तो इसे शर्की आज्ञा समझी जावेगी यदि आर्किवल रिसीवरने बिना अदालतकी आज्ञा लिये हुए कोई मुकदमा चालू किया हो और वह उस मुकदमेमें हार जावे तो वह उस मुकदमेका खर्च दिवालयियेकी जायदाद पर नहीं डाल सकता है देखो—45 Mad. 167.

यदि रिसीवर नियुक्त किये जाने समय उसे कानूनी दफ्तरे किराया आदि वसूल किये जानेके अधिकार प्रदान किये गये हों तो इससे यह मान लिया जावेगा कि उसे मुकदमा दायर करनेके भी अधिकार दिये गये हैं देखो—18 Cal. 477.

रिसीवरका कर्तव्य है कि वह सन जरूरी मामलोंमें अदालतका आदेश लेकर काम करे देखो—19 Bom 660.

यदि जाबता दीवानोंके अनुसार किसी मामलेके लिये रिसीवर नियुक्त किया गया हो तो उसके विरुद्ध मामला चालू करनेके लिये सबसे पहिले अदालतकी आज्ञा लेलेना आवश्यक है परन्तु यदि कोई मामला-रिजल आज्ञा लिये हुए चालू कर दिया गया हो तो उसके लिये बादमें भी आज्ञाकी आवश्यकता है देखो—41 I. C. 802 दिवालयियेके मामलोंमें जो रिसीवर नियुक्त किये जाते हैं वह ऊपर कहे हुए रिसीवरसे कुछ भिन्न हैं और उनके विरुद्ध मामला चालू करनेमें पहिले अदालतकी आज्ञा लेनेकी आवश्यकता नहीं है देखो—53 I. C 973, A. I. R. 1924 All 40 वगैरह दार्शनिक मत है कि चूंकि रिसीवर एक पब्लिक ऑफिसर (Public Officer) है और इस कारण जाबता दीवानोंकी दफ्तरोंके अनुसार नोटिस दिये जानेकी आवश्यकता है देखा—44 Bom. 895.

यदि रिसीवर किसी मुकदमेके लिये जरूरी फीस न होने तो उसके विरुद्ध मामला चालू करनेमें आज्ञा लेनेकी आवश्यकता नहीं है जैसेकि यदि कोई जायदाद रिसीवर द्वारा बँचनी गई हो और कोई व्यक्ति उस जायदाद पर अपना हक स्थापित करनेके लिय मुकदमा चालू करे तो ऐसे मामलेमें रिसीवरकी फीस मुकदमा बनाना बहुत जरूरी नहीं है। केवल इसी बातसे कि रिसीवरका नाम किसी मामलेमें बहसित पृष्ठअन्वेषके आता है तथा रिसीवरको फीस मुकदमा बनानेके लिये आज्ञा

नहीं ली गई है वह मामला कानून आरिन होनेके नहीं है अर्थात् मामला ऐसी दशामें भी चल सकता है देखो— 41 I. C 809, 48 All. 821

कलाज (सी) रितीवारको अधिकार है कि वह अदालतकी आज्ञा लेने पर दिवालियेके कारोबारकी चालू रख सके परन्तु उसे व्यापार इन्होंने कारण चालू रखना चाहिये तथा उसी हद तक चालू रखना चाहिये जिसमें कि वह फायदेके साथ समझा जासके देखो—40 Cal. 678.

कलाज (डी) रितीवारको अदालतकी आज्ञा लेने पर मुकदमे चालू करने तथा उनकी पैरवी करने रहनेका अधिकार प्राप्त है अर्थात् वह दिवालियेकी आज्ञाशुद्धि सम्बन्ध रखने वाले मुकदमोंको चला सकता है । इस तौर पर इस उपद्रव के अनन्तर यदि रितीवारकी सुपुर्दगीमें किसी दिवालियेकी वह जायदाद आई हो जो अनिमित्त हिन्दू परिवारकी जायदादका आभ्यान्वित भाग होवे तो रितीवारको अधिकार है कि वह बन्दोबस्त मुकदमा उस जायदादके लिये दावा कर देवे देखो—A. I. R. 1923 Oudh. 154.

रितीवार उनकी मामलोंको चालू कर सकता है या चालू रख सकता है जिनका सम्बन्ध दिवालियेकी जायदादसे होवे अन्यथा नहीं इसलिये यदि दिवालियेके विरुद्ध किसी रूपमें दावा दावे तथा उसी बीचमें वह दिवालिया करार दे दिया गया हो तो रितीवार उस मुकदमेमें फीक मुकदमा नहीं बनाया जाना चाहिये देखो—29 I. C 30. दिवालियेकी जायदादसे सम्बन्ध रखने वाले सब मामलोंमें रितीवार फीक मुकदमा बनाया जाना आवश्यक है और यदि रितीवारकी अल्पपरिधिमें दिवालियेकी जायदादके सम्बन्धमें कोई हुकम दिया जावे तो उसे पर कानूनी समझना चाहिये और अपात्रमें यदि उसे फीक मुकदमा बनानेकी कोशिशकी जावे जब कि वह शुरूमें फीक न बनाया गया हो तो इससे वह कर्तव्यहीन ठीक नहीं हो सकेगा देखो—30 I. C 703; 41 I. C 802.

कलकत्ता हाईकोर्टने यह तय किया है कि यदि दिवालियेके विरुद्ध बकाया क्रियिका दावा किया जावे तो उसमें रितीवारको फीक मुकदमा बनाना जरूरी नहीं है देखो—46 I. C. 395.

यदि कोई रितीवार फीक मुकदमा बनाये जानेके बाद बदल जावे तो उसकी जगह जो दूसरा रितीवार नियुक्त होगा उसे फीक मुकदमा बनाया जाना चाहिये देखो—28 Mad. 157.

यदि रितीवार किसी मुकदमेमें हार जावे तो उसे उस मुकदमेका खर्च स्वयं उस वक्त तक बरदाश्त नहीं करना पड़ेगा जब तक कि यह न साबित कर दिया जावे कि उसकी बेउममानियोंकी वजहसे वह मुकदमा खराब हुआ है देखो—A. I. R. 1925 Mad 786

यदि रितीवारने किसी बर्जन्दादके बहुत जोर देने पर कोई मुकदमा चालू किया हो तो अदालत उसे कर्तव्यवाहीसे मुकदमका तर्ज बसूल किये आदेश दे सकती है देखो—46 I. C 377

इन बातके लिये निश्चित रूपसे नहीं कहा जासकता है कि रितीवार मुकदमोंमें दावा कर सकता है या नहीं परन्तु प्रकट रूपमें ऐसा मालूम होता है कि मुकदमोंमें वह दावा कर सकता है इन्डागान्ड हाईकोर्टने यह निश्चित किया है कि यदि कोई बर्जन्दाद मुकदमोंमें कोई दावा लड़ रहा हो और उसी बीचमें वह दिवालिया घोषित कर दिया जावे तो रितीवार उस मामलेकी मुकदमोंमें बिना कौन्सिल अथवा किये चालू रख सकता है देखो—16 A. L. J. 440=47 I. C. 577.

कलाज (ई) इस कानूनमें रितीवारकी वहील या दूसरे एजेण्टोंको नियुक्त करके अदालत द्वारा वतखये हुए मामलोंके बरतना अधिकार दिया गया है अर्थात् यदि रितीवार किसी कर्तव्यको स्वयं न कर सकता हो अपना उसकी देखरेख न कर सकता हो तो उस वह कर्तव्य-दूसरे व्यक्तिके द्वारा कर सकता है इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि इस कानूनके अनुसार कर्तव्य कर्तव्यके लिये जो अदालतकी आज्ञा लेना आवश्यक है ।

लाज (पक्ष) रितीर दिवालियेकी जायदाद इम शर्त पर भी बँच सकता है कि इसे उपाय कीमत जायदाद मिलेगी परन्तु ऐसे मामलोंमें वकील नामानव आदि लेगी जाना चाहिये और इमके बिधे भी अदालतकी आज्ञानुसार ही कार्य किया जाना चाहिये ।

लाज (जी) इस कानूनके अनुसार अदालतकी आज्ञा देने पर रितीर दिवालियेके कर्जोंमें बुझानेके लिये उसकी जायदादको देन कर सकता है ।

लाज (पक्ष) अदालतकी आज्ञानुसार रिताजकी दिवालियेके समग्रमें तमजिया करनेका भी अधिकार प्राप्त है और इम हालमें उसके इन्हीं अधिकारोंका उद्देश है ।

लाज (झाई) इस कानूनमें यह बतलाया गया है कि यदि दिवालियेकी कोई जायदाद बेची न जासके या उमरे बेचनेमें मुकदमा होता हो तो अदालतकी आज्ञा लेकर गिम्बर उम जायदादकी कीमतका अंदाजा लगा कर उसे दिवालियेके कर्जपवाहोंको उनके कर्जोंके अनुसार बाट मंजूर ।

धारा ५९ (ए) दिवालियेकी जायदादके सम्बन्धमें हाल दर्शाप्त करनेके अधिकार

(१) यदि प्रान्तिरु सरकार किसी अदालतकी या अदालतके किसी हाकिमको अपनी मज्हा द्वारा पास वीरसे अधिकार देवे तो वह अदालत या हाकिम किसीर या किसी ऐसे उर्जदारके दखलवास्त देने पर जिसने अपना कर्ज मायित कर दिया है दिवालिया करार दिये गानेके बाद किसी समयकी किसी भी व्यक्तिको नियमित रूपसे तलय (Summon) कर सकता है । यदि यह मामल हो जाय कि उसके पास दिवालिये की जायदाद है या उसके कर्जमें दिवालियेकी जायदाद होने का शक है अथवा उस पर दिवालिये का कर्जदार होने का शक है या वह व्यक्ति अदालत या दूसरे हाकिमकी रायमें जैसा अबसर होवे दिवालिया, उसके व्यवहार अथवा जायदादके सम्बन्धमें सूचना दे सकता हो और अदालत तथा दूसरा हाकिम जैसा कि अबसर होवे ऐसे व्यक्तिसे दिवालियासे सम्बन्ध रखने वाली अथवा उसके व्यवहार या जायदाद के सम्बन्ध रखने वाली किसी भी दस्तावेज को जो उसके कर्ज या अधिकारमें होवे पेश करा सकता है ।

(२) यदि कोई इस प्रकार तलय किया हुआ व्यक्ति जबकि उसे उचित व्यय दे दिया गया हो अदालत या हाकिमके सामने उपस्थित होनेसे इनकार करे या किसी दस्तावेजको पेश करनेमें इनकार करे और इसके बिधे कोई जानूगी रकायत न होसी हो जिसकी सूचना अदालत को देदी गई हो तथा अदालतने उसे मंजूर कर लिया हो तो अदालत या हाकिमको अधिकार है कि उसके लिये धारण जारी कर देवे जिसमें वह बयान देनेके लिये लाया जासके ।

(३) यदि इस प्रकार कोई व्यक्ति अदालत या हाकिमके सामने लाया जावे तो अदालत या हाकिम उसका बयान दिवालियेके सम्बन्धमें तथा उसके व्यवहार या जायदादके सम्बन्धमें लेसकती है और ऐसे व्यक्ति की पैसी वकील द्वारा की जा सकती है ।

व्याख्या—

यह दफा कानून विचालिया संशोधन ऐक्ट न० ६९ एन् १९२६ [Provincial Insolvency Amendment Act 1926 (XXIX of 1926)] द्वारा जोड़ा गई है

उपदफा (१) इस दफा में दिये हुए अधिसूचना प्रयोग उसी समय किया जा सकेगा जबकि प्रांतिक सरकारने इसके लिये खास तारने किसी अदालतको या अदालतके दूसरे हाजिमको आज्ञा दे दी हो अथवा किसी अदालत या हाजिमको इस दफाके अनुसार कार्य करनेका अभिप्राय प्राप्त न होया। दिवाणिया नगर दिया जानकर हुक्म होकर पश्चात् हा अधिसूचना प्राप्तकी हुई अदालत या हाजिम इस दफाके अनुसार रखाई कर सकता है। इस दफाके अनुगम कार्यवाई कराने के लिये किसी दरबारन द सनका ह तथा वह कर्तव्यदाह भी दाखलान द सकता है जो अपना कस साबित कर लुका ह अथवा किसी तीसरे व्यक्ति का अथवा उस कर्तेरवाइको निम्न कस साबित नहीं किया जा चुका ह इस दफाके अनुसार वरिष्ठा, कमाना अधिवार प्राप्त महा है इस दफाके अनुसार वह व्यापक तत्त्व नियम का सकत है मितक र-कम में इवालिपका जायदाद होन या निनक क-कम में इवालिपकी जायदाद होनेवा हाफा हाब वह व्यक्ति या तत्त्व विद्यता मत है जा दिवालयके कसदार समझ लगे इस प्रकार व व्यक्ति भी तत्त्व हो सकत है निनकी दिवालयके सम्बन्ध या उसक व्यवहार अपना जायदादके सम्बन्ध बाबत मादूम होने यही न। कि ऐसे व्यक्ति तत्त्वदा किये जाव किन्तु उनमें दिवाणिये अथवा दिवाणियक व्यवहार व जायदाद सम्बन्धो दस्तविजेंभी पेश नही जातकी है।

उपदफा (२) इस उपदफामें यह बतलाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति कानूने दस्तावेज तत्त्व किया गया हो तथा उसे उसक अपने लिये उचित धन भी दिया गया हो और वह अदालतमें आनेमें इनकार कर देवे अथवा दस्तावेज महा पराने इनकार कर देवे तो अदालतने अधिकार है कि वह ऐसे व्यक्तिके विरुद्ध वारण्ट जारी कर देवे तथा उस न्याय दनेके लिये मकदूम बुलवा लेवे परंतु साथ साथ यह भी बतलाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति मकदूम कानून दाखल का तत्त्वम हाजिर न हा सनका हो या दस्तावेज पेश न कर सनका हा तथा वह अदालतने अपना यह मनूरी कानूनपर उसक मज्बूता ले लेन तो ऐसे व्यक्तिके हाजिर न हाल पर उसके विरुद्ध वारण्ट जारी नहीं किया जावगा। उचित धनने अधिप्राय यह है कि उनका उसकी लुका, हाइ सर्व, आदिके सम्बन्धमें पेशा धन मितक चाहेय इसक लिय जातिवावाया या दवालीन जनरल रूल (General Rules Civil) देखना चाहिये तथा उनमें बतलाय हुए नियमोंके अनुसार तत्त्व किया हुए व्यक्ति हैसियतका ध्यान रखने हुए उसकी पर्याप्त धन दिया जाना चाहिये अथवा इस उपदफाके यह प्रवृत्ति तत्त्वका हा अथवा व्यक्ति पर्याप्त सर्व पानका अधिप्राय है और वह तत्त्व हा जानेके बाद भा अदालत या तत्त्व नरा बाब हाजिमम यह व्यय मन्तु जन हा हुक्म पान का इतराह हा हा उपदफामें बतलाय हुए वारण्टका कानून तथा पिछी उपदफाके बतलाय हुए समनका बाबवर्द निर्धारित नियमोंके अनुसारनी जाना चाहिये अथवा तावता दवालीन में या इस एक्ट म बतलाय हुए नियमोंके अनुसार ही समन या वारण्ट तामील किये जाना चाहिये।

उपदफा (३) अदालत या दूसरा हाजिम यस प्रकार तत्त्व नियम हुए व्यक्तिमें दिवाणियके सम्बन्धों तथा समक व्यवहार व जायदादके सम्बन्धों पूछताह कर सकता है अर्थात् इन बातोंके अनिवारित अथवा नानके लिये उसस कुछ पूछने का अधिसूचना नहीं है इस उपदफामें यह भा बतला दिया गया है कि यदि इस दफाके अनुसार तत्त्व किया हुआ व्यापक आन मददके लिये बशेल किया चाह हा कर सकता है या बशेलके लिये जवाबदाह कर सकता है।

दफा ६० गैर मनकूला जायदादके लिये खास नियम

(१) अगर किसी जगह सन् १९०८ ई० के जायदादीवानीकी दफा ६६के अनुसार घोषणा की गई हो और उसका अमल जारी हो सो उस गैरमनकूला जायदादको जिसपर सरकारी माल-

गुजारी अदाकी जाती हो या जिस पर काश्त होती हो या जो काश्तके लिये उठाई गई हो किसीपर नहीं बँचेगा, लेकिन जबकि दिवालियेकी सब जायदाद वसूलकी जाचुकी हो तो अदालत तय करेगी कि

(प) जो रुपया वसूल किया जा चुका है उसके अलावा कितना रुपया इस एक्टके अनुसार साबित किये हुए कर्जोंकी चुकानेके लिये चाहिये

(वी) दिवालिये की कितनी गैरमनकूला जायदाद बिकने से बची है

(सी) और अगर यार हो तो उस पर कितना यार है

और ऊपर दी हुई बातों की तफसील कलक्टरके पास भेजेगा और तब कलक्टर उस फोड़ (जायता दीवानी) की तीसरी सूचीके पैराग्राफ २ से लेकर १० तक में दिये हुए नियमोंके अनुसार उस कदर रुपया लेवेगा जिसकी जरूरत बतलाई गई है और उन अधिकारोंके प्रयोग करनेसे जो रुपया आवेगा यह सब जहां तक उन पैराग्राफोंके अनुसार काम करते हुए होसकेगा अदालतकी बाँटनेके लिये दे देगा

(२) अगर किसी अन्य प्रचलित कानूनोंके द्वारा गैरमनकूला जायदादके खिलाफ डिफ्टी इजाजत या हुक्मोंकालेकी कोई मुमानियत या रक्षापट हो तो इस एक्टमें दी हुई बातोंका कोई असर उन कानूनोंके नियमों पर नहीं पड़ेगा और वह नियम इस एक्टके अनुसार दिवालिया फ़ौरन दिये जाने वाले हुक्मके अमलमें उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि कोई डिफ्टी या हुक्म ।

व्याख्या—

इस दफ्तेमें एक खास प्रकारकी गैर मनकूला जायदादके सम्बन्धमें निम्न नियमोंका प्रयोग किया जाना चाहिये उनका उल्लेख है । यह नियम उस गैर मनकूला जायदादके लिये प्रयोग किये जासकेंगे जिनमें सरकारी मालगुजारी अदाकी जाती हो या उस जमीनके लिये किये जासकेंगे जिस पर गन्त होती होवे या जो कालके लिये उठाई जाती हो ।

इन नियमोंका प्रयोग केवल उन्हीं जगहोंमें होवेगा जहां कि दफा ६८, जायता दीवानीके अनुसार घोषणाकी जाइतीहो ।

दफा ६८ जायता दीवानीमें दिया हुआ है कि—“प्राप्तिक सरकारों अधिनियमोंके बिना सरकारी वक्कीर जनरल हिन्दुकी आज्ञा लेनेके पश्चात् प्राक्तिक सरकारी गट्ट द्वारा यह घोषित कर देवे कि किसी खास जगह पर इजाजत डिफ्टीकी बर्तवाई इजाजतके लिये उस जगहके कलक्टरके पास भेज दी जावगी वही इजाजत डिफ्टी इस दफ्तेके अनुसार भेजी जावेगी जिनमें अदादतने किसी गैर मनकूला (Immovable) जायदादकी बँचनेका हुक्म दिया हो या जो किसी खास बिस्मकी ऐसी डिफ्टी होवे अथवा जिस डिफ्टीमें किसी खास बिस्म की जायदाद या उमरा इका बँचा जानकी होवे ।”

इस दफ्तेमें रतलाया गया है कि यदि किसी गैर मनकूला जायदादके सम्बन्धमें दफा ६८ जायता दीवानीके अनुसार घोषणाकी जाचुकी तथा बर्तमान कलक्टरों हुई बातोंका प्रयोग जारी हो तो स्थितपर उस जायदादकी नहीं बँचेगा किन्तु जब ऐसी जायदादके अनिश्चित दिनांककी ओर सब जायदाद बँची जाचुकी हो तो अदालतको चाहिये कि पाँचके इन तीन मामलोंका निर्णय करे कि (१) दिवालियेके बकाया कर्जोंकी अदा करनेके लिये कितने धनकी आवश्यकता है (२) दिवालियेकी जितनी जायदाद बिकनेसे बची है (३) उस पर बितना यार है और यह निर्णय करनेके पश्चात् अदालत इसकी रिपोर्ट कलक्टरके पास भेज देवे और तब कलक्टर चाहे हुए रुपयेके वसूल करनेका प्रयत्न उस जायदादके जायता दीवानीके शिख्यूल तीन (Schedule III) के पैराग्राफ (Paragraph) २ से १० तकमें बतलाये हुए नियमोंके अनुसार करेगा । और कलक्टरको उन नियमोंके प्रयोग करने पर जो रुपया वसूल होगा वह उस रुपयेमें अदालतके सुई पर देगा ।

जायदादीवाणीकी सूची नं० ३ (Schedule III) में कलक्टर द्वारा ज्ञान वाली इजराय डिक्रीके नियमोंका उल्लंघन है बाबत दीवानगी तारीख सुबा (Schedule III) क अतिरिक्त (Article) २ से १० तक नीचे दिये जाते हैं ।

शिड्यूल नं० ३ कलक्टर द्वारा इजराय डिक्रीका होना

२ खास मामलोंमें कलक्टर की कार्यवाही—यदि कोई डिक्री धुआहिदके अनुसार किसी गैर मतवृत्ता जायदादकें बेंचे जानके सम्बन्धमें नहीं दी गई हो तथा वह १ का सदे रुपये का डिक्री द्वारा पण्डित उस डिक्री इजरायमें कोई गैर मतवृत्ता जायदादकें करा कर नामाममें चढ़वाई गई हो और एसा इजराय कलक्टर पास भजा जाव ता कलक्टर उचित तहकीकानक बाद यह निश्चिन करेगा कि आपा जायदादका बिना नामाम कराय हुए मद्रूतनस कुल कर्ते धुकाया जानकता है या नहीं और यदि उसे इन बातनस इस्वास्त हो जाव ता वह भाच दिये हुए हुक्मक अनुसार कार्यवाई करेगा ।

३ डिक्रीदारको नोटिस दिया जाना और उनको जो जायदादका दावा करते हों—
(१) वेगप्राक १ में बतलाय हुए मामलेके सम्बन्धमें कलक्टर एक नोटिस प्रकाशित करेगा जिसकी पाबन्दाक लिय १० दिनोंका समय दिया जावगा तथा उस नोटिसक अनुसार —

(ए) हर शस्स गिराही सदि रुपयेक गिरा मद्रूतनस गिराक हावे तथा जिस डिक्रीमें उसका जायदाद नामाम करई जासके तथा डिक्रीदार जायदादका नामाम करणा चाहता हो अपना किसी कलक्टर पास पत्र करे अथवा यदि बिनाने अपनी साक्ष डिक्रीके इजरायमें जायदाद नामाममें चढवानका का नाह न हो ता वह अदालत इजरायका सार्थकिकेत पत्र करेगा जिसमें कि यह माझूम हो मके कि ऐसी डिक्रीके अनुसार कितना रुपया डिक्रीदार पानेना अधिकारी है ।

(बा) यदि उस जायदाद पर किसी शरतका कोई हक हाव तो उसे भी चहित कि वह कलक्टरके पास अपने इस हकक बारेमें बयान द्यावल करे तथा सापहस साव बाद कोई दम्माबमें हावे ता उस इक्क सुगमें पत्र करे ।

(२) इस प्रकारका नोटिस उस अदालतके एक आम जगह पर चिराया जावेगा जिसमें कि उन जायदादके बेंचे जानेस हुक्म शुरूमें दिया हो तथा उन जगहोंमें भा चिपकया जावगा जहा कि कलक्टर पुन सिब समय और यदि किसी डिक्रीदार या दावदारका पना माझूम हो ता नोटिसका नकल बेचिस गिराक या और किसी ताहस उस डिक्रीदार या दावदारके पास भेजी जावगी ।

४ डिक्रीका मतलिया निश्चिन करना और जायदाद गैर मतवृत्ताका उसने लिय मुहैया करना — (१) इस निब दके समाप्त होनेके पश्चात् कलक्टर कोई तापल नियत करेगा जिसमें उस निब डिक्रीदार दावेदार या मद्रूतन अपने अपने मतले पत्र कर सकें तथा वह स्वय मद्रूतनका जायदादक सम्बन्ध जो बात जानना चाह जान सके कि जिस प्रकारकी जायदाद है तथा कितनी जायदाद है और यह भा जान सके कि उस पर डिक्रीदारों या दावेदारों का क्या हक पहुँचता है कलक्टर समय समय पर कपातका तथा तहकीकानकी ताहस भा पत्रा सकता है ।

(२) यदि इस बातक लिय कोई जगहा न होव कि मद्रूतनके विरुद्ध कानूनी हुई जाणा या गिरा ठाक नहीं है तथा इस बातके लिय भी कोई जगहा न पड़ता हो कि कानूनी कन पाहल धुकाया जाना चाहिय तथा कानूनी न स और न इस बातका क लिय कोई जगहा हाव कि कौनसे कानूनी पाबन्दा जायदाद पर है तो कलक्टर एक बयान तयार करेगा जिसमें कि डिक्रीक सम्बन्धमें बसूल किया जान बाता सब कथा दिखलाया जावगा तथा यह लपचाया जावगा कि डिक्री या दावे किस कपसे उजाय जावेगा और जिस कदर पर मतवृत्ता जायदाद इन कसोंका चुनावन लिय है ।

(३) यदि कोई इस प्रकारका श्रमका उपस्थित होने तो कलक्टर श्रमकेन हवाला देने हुए तथा अपनी राय प्रकट करने हुए मामले में फ़ैसले के लिये उस अदालत के पास भेज देगा जिसे कि नीलापका हुक्म लुप्त दिया हो और जब तक कि इसका जवाब नहीं आयेगा नीलापकी कार्यवाही को रोक देगा । यदि मामले अधिकार सीमा के अन्दर होगा तो वह अदालत इस मामले को तय कर देगी या उस मामले को किसी ऐसी अदालत के पास फ़ैसले के लिये भेज देगी जिसे उसके तय करने का अधिकार प्राप्त है और उस मामले में जो आखिरी फैसला होगा उसे कलक्टर के पास भेज देवेगी और तब कलक्टर इस फ़ैसले के अनुसार ऊपर बतलाया हुआ कथन तैयार करेगा ।

५ जय जिले की अदालत ने नोटिस जारी कर दिया हो—कलक्टर स्वयं नोटिस जारी करने या दफा ३ व ४ के अनुसार तद्विधान करने के बजाय एक कथन इस बात का तैयार करके कि मरुतकी क्या हालत है तथा उसकी पौर मरुतकी जायदाद की जहा तक कि कलक्टर को स्वयं मालूम है या जहा तक भित्तिस से मालूम होता हो क्या हालत है लिख कर अदालत जिला (District Court) के पास भेज सकता है और तब वह अदालत नोटिस जारी करेगी तथा दफा ३ व ४ के अनुसार तद्विधान करेगी और उसका मरुतकी हालत कलक्टर को लिख भेजेगी ।

६ अदालत के फ़ैसले का अन्तर—दफा ४ व ५ के अनुसार यदि किसी श्रमकेन अदालत निपटा देगी तो वह फ़ैसला कौनसे दरमियान एक प्रकार की टिकी समझी जावेगी और उसी की तरह वह जारी कराया जासकेगा तथा इसकी अमील भी की जासकेगी ।

७ रुपया देने के लिये विचार—(१) यदि पैराग्राफ ४ व ५ के अनुसार यह तय किया जायता हो कि कितना मालिक है तथा कितनी जायदाद है तो कलक्टर—

(ए) यदि उसे यह मालूम हो कि जायदाद को बिना बेचे हुए खरचा बसूल नहीं हो सकता है तो वह उसके बेचने की कार्यवाई शुरू करेगा ।

(बी) यदि उसे यह मालूम हो कि पूरा कथन व सूद जो डिफ़ॉर्म दिखाया गया हो या जो कायदे से मिलना चाहिये जिला नीलाम जायदाद के बसूल किया जासकता है तो वह जायदाद को बिना बेचे हुए उस पर नीचे दिये हुए दग पर न्याय मय ब्याज के बसूल कर सकता है (1) यह कि कुछ जायदाद को या उसके किसी हिस्से को पैदा की कथना लेकर हमेशा के लिये अपना किसी खास मियाद के लिये बटा सकता है (ii) यह कि कम जायदाद को कुछ या उसके किसी हिस्से को रोक कर सकता है (iii) यह कि उस जायदाद के किसी हिस्से को बेच सकता है (iv) यह कि तारीख नीलामने २० साल तक के लिये खेती के लिये बटा सकता है तथा उसका इन्तजाम स्वयं या किसी दूसरे के लिये कर सकता है (५) यह कि ऊपर बतलाये हुए तरीकों से कुछ रुपया किसी तरीके से ब कुछ किसी दूसरे तरीके से या किसी अन्य तरीकों से बसूल कर सकता है ।

(७) कलक्टर को अधिकार है कि कुछ जायदाद या उसके किसी हिस्से को प्रत्यक्ष करते समय वह उस जायदाद के मालिक के तौर पर काम कर सकता है ।

(२) कलक्टर को अधिकार है कि वह कुछ जायदाद या उसके किसी हिस्से को कर्षण बढ़ाने की शरत से अपना या इस नाम के कि वह ज्यादा शर्तों के लिये उठाई जायके या वह किसी बान के लिये नीलाम न की जासके चाहे खरचा कर सकता है या उसकी अदालतों के लिये समझता कर सकता है चाहे उसकी अदालत उस समय होने वाली होवे या उसके बाद और ऐम बार्कन अदालतों के लिये वह जायदाद के किसी हिस्से को रोक या बच कर सकता है तथा उसे उठा भी सकता है जैसा कि मुनासिब समझ पड़े । यदि ऐसे बर (Incumbrance) की अदालतों के सम्बन्ध में कोई श्रमका खडा हो जावे तो उसे

, अधिकार है कि वह मुनासिब अदालतमें उसके बारेमें मुकदमा दायर कर देवे यह मुकदमा कलक्टर अपने नामसे या मद्दूनके नामसे दायर कर सकता है या कलक्टर इसका हिसाब समझ सकता है अपना छगडेकी निपटारके लिये दो पचोंके सुपुर्द कर सकता है जिन्हें कि दोनों फ्रीकैनेन एक एक अपनी तरफसे चुना हो या ऐसे सरपचके ऊपर छोड़ सकता है जिसे कि इन दो पचोंने चुना हो ।

(४) इस पैराग्राफके अनुसार कार्रवाई कलक्टर उन्हीं नियमोंके आधार पर करेगा जो कि प्रांतिक सरकारने इस विषयके लिये बनाये होंगे ।

॥ **वाकीफा बसूल करण**—यदि दफा ७ के अनुसार जायदाद उधार गई हो या उसका प्रत्यक्ष लिया गया हो और उसकी मियाद समाप्त होने पर यह बाध्न होवे कि कुछ वर्ष इस पर भी नहीं चुका है तो कलक्टर इस बातकी लिखित सूचना मद्दूनकी या उसके उत्तराधिकारीको देवेगा और उसमें यह भी लिख देगा कि यदि बक्या मनालिखा है इन्हेन अदर नहीं चुका दिया जावेगा तो वह कुछ जायदाद या उसके किसी पर्याप्त हिस्सको बेच देवेगा । और यदि वह इन्के अन्दर रुपया अदा नहीं होगा तो कलक्टर नोटिसके अनुसार कुल या कुछ जायदादको बेच देवेगा ।

६ **कलक्टरका हिसाब देना अदालतको**—(१) कलक्टर समय समय पर उस अदालतकी जिसने जायदादके नीलाम किये जानेका हुक्म पेश्वर दिया है सब हिसाब भेजना रहेगा जिसमें कि रुपये की बसूली तथा इस शिद्दपूलके अनुसार प्राप्त अधिकारोंके आधार पर जायदादके लिये जो खर्च किये गये हों उनका उल्लेख होगा और नबतका कया उस अदालतकी सुपुर्दगीमें कर देगा ।

(२) उन खर्चोंमें सरकारी कर्ज व ज़िम्मेदारिया जो समय समय पर कुल या कुछ जायदादके सम्बन्धमें हो जावें शामिल समझी जावेगी तथा वह लगान भी शामिल समझा जावेगा जो कि उस जायदाद या उसके किसी हिस्सेके लिये अपनेसे अच्छा हक रखने वाले कायदगारका निबलता होवे और यदि कलक्टर हुक्म देवे तो इन गवाहोंका खर्च भी जो उसने तत्तब किये हों लगाया जावेगा ।

(३) नया हुआ कया अदालत इस प्रकार व्यय करेगी —

(ए) यहकि वह कया मद्दूनके परिवारके उन लोगोंकी परवशिमें लगाया जावेगा जो उसकी जायदादकी आमदनी से परवशिष्ट किये जानेके अधिकारि हैं हर एक मम्बरके लिये उस जदर करना नतीर परवशिष्टके दिया जावेगा जिनका कि अदालत मुनासिब समझे ।

(बी) यदि कलक्टरने पैराग्राफ (Paragraph) १ के अनुसार कार्रवाई की हो तो उस डिक्तीके बुकनेमें लगाया जावेगा जिसके एन्वयमें जायदाद नीलाम कराई गई हो या फिर दफा ७३ के अनुसार जैसा कि अदालत अवित समझे ।

(सी) यदि कलक्टरने पैरा बी के अनुसार कार्रवाई की हो तो (१) जायदादके बार (Incumbrance) का सूद बुकनेमें देवेगी (II) यदि मद्दूनके पास जीविकावा पर्याप्त साधन न होंवे तो उसकी जाविकोंके लिये उस जदर जितना कि अदालत मुनासिब समझे देवेगी (III) पहिले डिक्तीदार तथा अन्य डिक्तीदारोंका जिन्होंने नोटिसकी पावन्दगी की तथा जिनका मनालिखा बसूल किया जानेका हुक्म हो चुका हो उनका कया रखी तौमि बुकनेमें देवेगी ।

(४) इस जायदाद भा धने हुए खर्चमेंसे किसी सारी डिक्ती वाले दूसरे डिक्तीदार को कया बत बत तक नहीं दिया जा सकेगा जब तक कि उन डिक्तीदारोंको कया जिनके सम्बन्धमें हुक्म हो चुका है न चुकाया ना सके और अन्धमें बचा हुआ कया मद्दूनकी या ऐसे शस्सको दिया जावेगा जिसके लिये अदालत हुक्म देवे ।

१० कैसे बचा जायगा—जबकि कलक्टर इस शिष्टाचार के अनुसार जायदादों पर कर तो वह जायदादों पर मुक्त या भिन्न २ भागों में आय नीलाम द्वारा संग्रहित करनी और उते वह भी अधिकार है कि वह —

(ए) उहा हिरसे (Lot) के लिये कोई उचित ब्यापन नियत कर देवे

(बी) नालामकी वचित समयके लिये उचित कारणोंके आधार पर जो उचित जाना चाहिये मुक्तता कर देने जबकि उसे यह मांग हो कि मतलबी होनेसे जायदादकी आधी ब्यापन आ सकेगी ।

(सी) नीलाममें जायदादों पर छद्म से और फिर दुबारा उसे नीलाम आम हाथ बेच देने या बादमें भी सीदेसे बेच देने जसा कि उसे उचित प्रतीत हो ।

उपरवी दफाओंमें दायरेमें यह सभी भाति प्रकट है कि कलक्टर अपने यहां आई हुई इनपुट निर्वाही कार्रवाई को किस प्रकार अग्रिम में ला सकता है । भिन नियमों का उपर बर्णन है कलक्टर उही नियमोंका प्रयोग करेगा । उस अदालत को जिसने जायदाद नीलामके लिये भेजा हो वही जजिस्टर हस्तक्षेपके श्राव्य होने जो इन नियमोंमें बतलाये गये हैं अर्थात् वह ऐसे ही क्षणोंको तब का सजेगी जो कलक्टर तब होनेके लिये उससे पास भेजे ।

यदि इस दफाके अनुसार कलक्टर द्वारा इनपरवी कार्रवाई हो रही हो तो अदालत दायिनीको कोई अधिकार नहीं है कि वह जायदाद नीलाम करने वाले शर्तियों पर ध्यान देकर करे । यदि जायदादों नीलाममें या उसके नीलामकी कार्रवाई में कोई शिष्टाचार होने तो वह शिष्टाचार उसी अदालतके सामने पेश की जाना चाहिये जो नीलामकी कार्रवाई कर रही हो और उसी अदालत अदालतको ऐसे प्रमाणों पर विचार बर्णन आग्रिम है देखो—49 A. 272. A. I. R. 1927 All. 203, यदि अदालत निर्वाही इस दफामें बतलाई हुई जायदादकी बेच देने अर्थात् इस दफाके नियमोंके विरुद्ध काम करे तो वह ब्यवसाय अनुचित होगा तथा वह अग्रिम में नहीं लाया जा सकता है देखो—A. I. R. 1925 Oudh. 299.

इस दफाका प्रयोग उन मामलोंके लिये भी हो सकेगा जो कलक्टर लिये उठाई जाती हों या भिन पर वास्तवी जाती है । नीलकी खेतीका हीन वास्तवादीका काम है परन्तु नीलकी शिष्टियोंका तैयार किया जाना कलत्र नहीं है 31 Cal. 174. बागके लिये उठाई जाने वाली कमीन कारखानी कमीन नहीं है देखो—24 Cal. 160. आरु वना व सरकारी आदि बोये जानेवाले जमीन वास्तवादीकी कमीन है देखो—25 Mad 627. परन्तु कलक्टर हरिशेठोंके अनुसार सरकारी बोने तथा नास या फलोंके दूरस्थ छगाने वाली जमीन वास्तवी कमीन नहीं है देखो—27 Cal. 205. यदि किसी प्रचलित कानूनमें अनुसार किसी और मनूका जायदादकी इनपुटके सम्बन्धमें बतली रोकने आदिने लिये कोई नियम बनाये गये हों तो उन नियमों का ध्यान रखते हुये ही इस एक्टका प्रयोग किया जा सकेगा ।

राहौर हरिहरदेव देखो—A. I. R. 1929 Lah. 66 में तब किया है कि अदालत दिवालिखा, उचित अवसर उपस्थित होने पर दिवालिखी जायदादोंको हमेशाके लिये भी अग्रहदा कर सकता है । इस मामलेमें एडमनप्रसाद अर्थात् ए इन् १९१५ ई० में दिवालिखा करार दिया गया था । वकिल पास बहुत सा मामला भी निरस्त रूपया बसूच फर्मकी बहुत कोशिशवा गई परन्तु कुछ बमूल नहीं हो सका तब वह फर्मिन उसके एक रिजिस्टारके पास रहन कर दिये जाने का हुक्म हुआ इसी हुक्मकी अपालकी गई है अर्थात्में जमाने तब किया कि वाकि दिवालिखा नगरा कदाचित् बालता रहा है तथा अपने पास जीवकता दूसरा साधन भी उपस्थित है ऐसी दशामें उसकी वह कमीन रहनी जाना चाहिये दफा ६० (१) (सी) और दिवालिखी अपील खारिजी गई ।

तकसीम जायदाद

दफा ६१ कर्ज़ोंका पेशतर चुकाया जाना

(१) दिवालियेकी जायदादको बांटने समय नीचे दिये हुए कर्ज़ और सब कर्ज़ोंके पहिले चुकाये जावेंगे :—

(ए) वह सब कर्ज़ जो गवर्नमेंट या स्थानिक सरकारको देना हों

(बी) क्लर्क नौकर या मजदूरकी बीस रुपयेसे कम वह सब तनखाह या उजरत जो उन लोगोंको दिये लेकी दरखास्त गुजरनेसे ४ महीने पहिले किये हुए कामके लिये चाहिये है ।

(२) उपदफा (१) अर्थात् ६१ (१) में दिये सब कर्ज़ आपसमें बराबर हैलियतके समझे जावेंगे और पूरे पूरे चुकाये जावेंगे लेकिन अगर दिवालियेकी जायदाद काफी न हो तो वह रसदी तौरसे सब कर्ज़ कम कम चुकाये जावेंगे ।

(३) अगर दिवालियेकी जायदाद काफी हो तो उपदफा (१) में दिये कर्ज़ उन रुपयोंको अलहदा करनेके बाद जो इन्तजाम या दूसरे तर्जके लिये जरूरी हों फौरन चुका दिये जावेंगे ।

(४) जहां साझेका काम हो वहां पहिले साझेकी जायदादसे साझेके कर्ज़ चुकाये जावेंगे और साझेदारोंकी जुदागाना जायदाद पहिले उनके जुदागाना कर्ज़ोंके चुकानेमें लगाई जावेगी । जब कि साझेदारकी जुदागाना जायदादसे कुछ बचे तो वह साझेकी जायदादका हिस्सा समझी जावेगी और साझेकी जायदादमें साझेदारके जो जुदागाना हिस्से होंगे उसीके अनुसार वह उस साझेदारके हिस्सेमें समझी जावेगी ।

(५) इन परबके नियमोंका ध्यान रखते हुए वह सब कर्ज़ जो सूचीमें दर्ज होंगे अपनी तादादके अनुसार तथा थिला कोई तरजीह दिये हुए रसदी तौर पर चुकाये जावेंगे ।

(६) ऊपर दिये हुए कर्ज़ोंकी अशायगीक याद अगर कुछ बचे तो उससे सूचीमें बदे हुए कर्ज़ोंका सूद ६ १/२ सैकड़ा सावधानके हिस्सासे दिवालिया कतार देनेके बरतसे चुकाया जावेगा ।

व्याख्या—

इस दफामें दिवालियेकी जायदादको बांटे जानेके नियम दिये हुए हैं तथा यह बतलाया गया है कि कौनसे कर्ज़ पहिले चुकाये जाना चाहिये तथा इनमें कर्ज़ बांटने सबसे पहिले यह दिया गया है कि दो प्रकारके कर्ज़ सबसे पहिले चुकाये जाना चाहिये (१) एक तो वह कर्ज़ जो सम्राट या स्थानिक सरकार (Local Authority) को अदा किये जाने वाले हों तथा (२) दूसरे २० रुपयेसे कम वह मजदूरी व तनखाह जो दिवालियेके प्रत्येक नौकर या मजदूरको उस कामके एवजमें मिलना चाहिये जो उसने दिवालियेकी दरखास्त गुजरनेके चार माहके अंदर किया हो ।

उपदफा (२) यह दोनों प्रकारके कर्ज़ एक ही हैलियतके समझे जाना चाहिये तथा पूरे पूरे चुकाये जाना चाहिये परन्तु यदि दिवालियेकी जायदाद इनको पूरा पूरा चुकानेके लिये पर्याप्त न होनी हो तो हिस्सा रखनेके हितानसे वह कर्ज़ कम करके चुकाये जाना चाहिये । यह बात ध्यानमें रखना चाहिये कि देनदारोंके कर्ज़ोंका वार देनदारों द्वारा जायदाद पर समझे

पढ़े होता है अर्थात् सरकारी कजोंको उस पर तर्जिह (Perference) नहीं दी जासकती है देखो—29 All. 537; 28 Mad. 420 दूसरे कजोंके मुकामिले सरकारी कजों मन्ते पढ़िजे चुकाये जाना चाहिये। स्थानिक सरकार (Local Authority) से अधिप्राप्त प्युनिसिपल्टी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आदिमें दे।

उपदफा (३) दिवालयिनी जायदाद वसूल करने या समुक्त प्रबंध करनेके लिये जो सब आवश्यक हुंसा पढ़िजे वर निवाला जाना चाहिये इसके पदनाम उपदफा (१) में बतलाये हुए कजोंके जुमानेका प्रबंध नियम पूर्वक किया जाना चाहिये।

उपदफा (४) जहाँ साझेका काम होये वहाँ पढ़िजे साझेकी जायदादसे साझेके कजों चुकाये जावेंगे और साझेदारोंकी जुदागाना जायदाद पढ़िजे उनके जुदागाना कजोंको चुकाये जानमें रगार मानेगी। यदि साझेदारोंकी जुदागाना जायदाद उसके जुदागाना कजोंके चुकाये जानके बाद बचे तो उसे साझेकी जायदादके नीर पर इस्तेमाल किया जानकेगा इसी प्रकार यदि साझेकी जायदाद साझेका कजों चुकाये जानके बाद बचे तो वह हिसरा रसदीका हिस्सामें साझेदारोंके जुदागाना कजोंका चुकानेमें इस्तेमालकी जासकती है।

उपदफा (५) इस उपदफामें यह बतलाया गया है कि इस प्रकारके नियमोंका प्यान रखते हुए वह सब कजोंको कजोंकी सूचीमें दर्ज किये गये हों हिसरा रसदीके हिसाबसे चुकाये जावेंगे और उनमें किन्ही एकरी दूसरेके मुकामिले तर्जिह नहीं दी जावेगी।

उपदफा (६) दिवालयिना अगर दिये जानेके बाद भी सूद दिखानेकी व्यवस्था न हो उपदफाके अनुसार की गई है क्योंकि अनुमन सूद बाद दिवालयिना अगर दिये जानेके नहीं मिलता है परन्तु इस उपदफाके अनुसार दिवालयिना अगर दिये जानेके बादसे वसूली तकका सूद ६ रुपये तकका मासानाहीं दूरे दिवाला पासकरना है यदि दिवालयिनी जायदादमें उसका सब कर्त पूर्ण रूपसे चुकाये जायके तथा उसके बाद कुछ रकम फाइजल बच रहे देखो—A. I. R. 1926 All. 361 फलफला हाईकोर्टने एक मामलेमें यह तय किया है कि यदि (अ) को (ब) का कोई कर्त चुकाना हो परन्तु (अ) वह कर्त (स) से बसूल कर सकता हो तो (अ) के दिवालयिना अगर दिये जाने पर (स) का (अ) का कर्त बसूल किया जासकता है परन्तु उस बसूलमें से (ब) अपना कर्त चुका पानेका अधिकारी है अर्थात् उस बसूलमें से पढ़िजे (ब) का कर्त चुकाया जावेगा देखो—A. I. R. 1929 Cal. 205.

दफा ६२ डिबीडेण्ड, हिसरा रसदीका लगाया जाना

(१) डिबीडेण्डका अन्दाजा लगाने समय रिस्तीवर नीचे दिये हुए मर्होंके लिये वाशी रकम हाथमें रख लेगा:—

- (ए) उन कजोंके लिये जो इस एकटके अनुसार साबित किये जा सकते हैं और जिनको दिवालयिना अपने ध्यानमें दिखलाया है या जो और किसी तरहसे मालूम हुए हैं लेकिन जिनके काजेंप्याह इतनी दूर रहते हैं कि मामूली तौरकी इत्तिला पर उनको काफी समय अपने कजोंके साबित करनेका नहीं मिला है
- (बी) जिन दावोंका मसला तब तक तय नहीं किया गया है लेकिन जो इस एकटके अनुसार साबित किये जा सकते हैं
- (सी) जिन मामलोंके साबित होनेमें या दावोंमें झगडा हो, और
- (डी) जायदादके इतनाम या दूसरे कामोंके लिये जिन खर्चोंकी ज़रूरत हो

(२) उपदफा (१) में दिये हुए नियमोंका ध्यान रखते हुए वह सब रूपया जो हाथमें होगा डिवीडेण्डके तौर पर तत्कालीन कर दिया जावेगा ।

व्याख्या—

इस दफा में हिस्सा रखी (' dividend) बांटे समग्र निग बालोंका ध्यान रखना तथा निग रकमोंका रोक्ना आवश्यक है उनका उल्लेख दिया गया है अर्थात् दिवालियेकी आयदादसे बमुल्की हुई सब रकम एक साथ ही व ही कर्जोंके चुकानमें न लगा दो जाना चाहिये जो साबित किये जा चुके हैं किन्तु और कर्जोंका या ध्यान रखना चाहिये ।

हिस्सा रखी (Dividend) बांटेने पहिले रिसीवरकी चाहिये कि वह कासी रकम उन कामोंके लिये रोक लेवे निगका उल्लेख उपदफा (१) के अंत (ए), (ना), (सी), व (डी) में किया गया है ।

क्लाज़ (ए) में उन कर्जोंको बतलाया गया है जो साबित किये जा सके हैं परन्तु निगको साबित करनेका पर्याप्त अवसर नहीं मिल सका है ऐसे कर्जों वही हो सकेगे जिन्हें दिवालियेने स्वयं तस्लाप किया हो या निगके बारेमें अदालतको किसी दूसरे जरियेसे इतनीमान होजाये तथा साधदी माथ अदानतको यह भी माहूम होजावे कि उन कर्जोंको पानेके इक्यार इतना दूर रहने हैं कि मामूली तारकी इच्छा पर उनको आन कर्जोंके साबित करनेका पर्याप्त अवसर नहीं प्राप्त हो सका है ।

क्लाज़ (बी) में उन कर्जोंका उल्लेख है जो इस एकटके अनुसार साबित किये जा सकते हैं परन्तु उनकी तादाद उस वक्त तक निश्चित नहींकी जा सकी है ।

क्लाज़ (सी) में उन कर्जोंका उल्लेख है निगके साबित होने या दावेमें झगडा हेवे ।

क्लाज़ (डी) में दिवालियेकी आयदादके इन्तजाम आदिके सम्बन्धमें निग लखोंके होनेकी सम्भावना है उनका वस्लेख किया गया है अर्थात् क्लाज़ (ए), (बी), (सी) व (डी) में बन्दर्द् हुई मदोंके लिये कासी रूपया रोक लेनेके बाद रिसीवरकी चाहिये कि हिस्सा रखी तत्कालीन करे ।

उपदफा (२) में वह बतलाया गया है कि रिसीवर उपदफा (१) में बतलाये हुए कामोंकी लिये कनये रोक सकता है अथवा नहीं उसका कर्तव्य है कि वह बाकी सब रूपया कर्जखानोंमें तत्कालीन कर देवे अर्थात् रिसीवर अपन पास कोई काबिल रकम नहीं रोक सकता है ।

दफा ६३ डिवीडेण्ड जाहिर किये जानेसे पहिले जिस कर्जखाने कर्ज साधित नहीं किया है उसके हक

अगर किसी कर्जखाने किसी डिवीडेण्ड जाहिर किये जानेसे पहिले अपना कर्ज साबित नहीं किया हो तो वह उस यक़ायी रूपयेसे जो रिसीवरके पास होगा उस डिवीडेण्ड को पानेका हकदार होगा जो आयन्दा तत्कालीन किये जानेको है लेकिन वह उस डिवीडेण्डमें गड़बड़ी नहीं डाल सकेगा जो उसके कर्ता साबित करनेसे पहिले तय किया जा चुका है ।

व्याख्या—

इस दफा में उस कर्जखानेके लिये हिस्सा रखी पानेकी व्यवस्था बन्दर्द् गई है जिसका कर्ज देमें साबित किया जावे । अर्थात् यदि उसका कर्ज साबित किये जातेसे पहिले हिस्सा रखी उन कर्जखानोंमें तत्कालीन किया जाचुका हो निगका कर्ज पहिले साबित किया जाचुका है तो वह उस तत्कालीनमुदा पतारकेमें गड़बड़ी नहीं डाल सकेगा और उसे उसमेंसे कोई

हिस्सा समझी नहीं मिल सकेगी पालु उसका बजो साधित होने के बाद जो हिस्सा समझी (Dividend) बाग जावेगा उसमें उसे भी हिस्सा समझी मिल सकेगा बशर्त उसके कर्ज साधित होने के बाद जो रकम गिरीवर के हाथमें बची होगी उसमें उसका भी हक होगा और वह बचल इतनी बराबरी में उसका ७०० देरों साधित हुआ है वह रकम में अपना हक पाने में बचित नहीं रहता जावेगा ।

दफा ६४ आखिरी डिवीडेण्ड

जब किसी बर दिवालिये की कुल जायदाद या जायदादका घट हिस्सा जो अदालत की शायमें बिना फिजूलगी देर गिरीवरों में किये हुए बसूल किया जा सकता है, बसूल करने, तो वह आखिरी डिवीडेण्ड घोषित कर देगा । लेकिन ऐसा करनेसे पहिले वह उन लोगों को नोटिस दे देवेगा जिनके कर्जोंका जिक्र हुआ है लेकिन जो साधित नहीं किये गये हैं कि अगर वह लोग नोटिसमें दी हुई मियादके अन्दर अपने कर्ज साधित नहीं करें तो उनके हकोंका खिला लिहाज किये हुए आखिरी डिवीडेण्ड दे दिया जावेगा । नोटिसमें दी हुई मियादके समाप्त होने पर या उस मियादके समाप्त होने पर जो किसी कर्जवाहने अपना कर्ज साधित करने के लिये अदालत से ली हो दिवालिये की जायदाद उन कर्जवाहनों में बांट दी जावेगी जिनका नाम सूचीमें दर्ज है और किसी दूसरे कर्जवाहने के दावोंका खयाल नहीं किया जावेगा ।

उपारण—

आखिरी हिस्सा समझी कौन से समय जिन बातों का ध्यान रहना चाहिये उनका उल्लेख इस दफ्त में किया गया है । आखिरी हिस्सा समझी (Final Dividend) उनी समय बांटा जावेगा जब कि दिवालिये की कुल जायदाद बसूल की जा चुकी हो अपना दिवालिये की जायदाद उस कदर हिस्सा बसूल किया जा चुका हो जो अदालत की शायमें बिना फिजूलगी देर किये हुए गिरीवर बसूल कर सकता है । परन्तु आखिरी हिस्सा समझी तब तक करनेसे पहिले गिरीवरों का बतौर है कि वह ऐसे कर्जवाहनों की निर्धारित नियमों के अनुसार सूचना दे देवे जिनके कर्जों का जिक्र तो दिवालियों के दफ्तरास्तमें हुआ हो या तु जिनका कर्ज साधित न किया गया हो । अर्थात् जिन कर्जवाहनों का कर्ज साधित होकर दर्ज देहरिय न हुआ हो उन कर्जवाहनों की आखिरी हिस्सा समझी बांटनेसे पहिले सूचना दे दी जाना चाहिये । नोटिस इस बातका उनको दिया जावेगा कि वह नोटिसमें दी हुई मियादके अन्दर अपना कर्ज साधित कर दे अथवा बिना उनके कर्जों का खयाल दिये हुए आखिरी हिस्सा समझी बांट दिया जावेगा ।

नोटिसमें दी हुई मियादके समाप्त होने पर दिवालिये की जायदाद सूचीमें दर्ज युक्त कर्जवाहनों में बाँचमें हिस्सा समझी के हिस्से बांट दी जावेगी और उस वक्त दूसरी कर्जवाहनों का कोई ध्यान नहीं रहता जावेगा । या तु यदि किसी कर्जवाहने अपना कर्ज साधित करने के लिये अदालतमें कुछ मोहलत लखी होवे तो उस मोहलत के समाप्त होने के पश्चात् या अथवा हिस्सा समझी बाँचने की वरिदाई अमरुत दर्ज जावेगी । इस दफ्त में अनुसार नोटिस उन्हीं कर्जवाहनों को दिया जावेगा जिनके कर्जोंका जिक्र आचका है परन्तु जिनके कर्ज साधित नहीं किये गये हैं । आप लोगों को नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है देखो—10 I. C. 791. यदि किसी कर्जवाहने कर्ज सूचीमें दर्ज न किया गया है तो वह बिना सर्टीफिकेट बराबर शामिल किये हुए हिस्सा समझी पाने का हकदार है देखो—49 Mad. 952.

इस दफ्त में अनुसार कर्जवाहनों को आखिरी हिस्सा समझी देने तक अपना कर्ज साधित करने तथा उस समयके बाद बाँट जाने वाले रुपयेमें से हिस्सा समझी प्राप्त करने का हक दिया गया है । यदि वह इस दफ्त में अनुसार दिये हुए नोटिसमें

मियादें अदा भी अपना कर्ज मानित न करें तो फिर उनसे और कोई सूच । नहीं दा जलिया और उनके कर्जों का दिवा
रपाल लिये हुए दिवालियों की वचा हुई जायदद आगिने तौर पर उड़ी कर्जकारोंमें जद दी जलिया जिनका नाम सूचीमें
दर्ज है । (डीवीडण्ड (Dividend) शब्द अंग्रेजों हिस्सा सदासे हिस्सासे बांटे जानका है । आगिने दिवालिया
वर्तमान कि वह मोगिस केवल उन्हीं कर्जकारोंको नहीं देवे गिन्हें अपने कर्ज आदि किता है किंतु उन कर्जकारोंको भी
देवे जिनका कत उससे दिवालिया या क्ति कर्जकारों द्वारा बनलाया गया है अर्थात् नोटिस केवल उन्हीं लोगोंको नहीं होना
चाहिये जिनका किता दफा ६२ (१) के (बी) व (सी) क्लॉजमें है किंतु उन लोगोंको भी होना चाहिये जो क्लॉज (६)
में भी ह । देखा—A I R 1928 Sindh 100=107 I C 439

दफा ६५ डिबीडेण्डके लिये कोई दावा नहीं हो सकेगा

रिडीयरके खिलाफ डिबीडेण्डके लिये कोई मुकद्दमा नहीं दायर किया जायगा, लेकिन
अगर रिडीयर किसी डिबीडेण्डके देनसे इन्कार करे तो सूचीमें दर्ज नाम धर्म कर्जकारोंके
वरद्वारा उन पर अदालतको अधिकार है कि यह, रिडीयरको डिबीडेण्ड अदा करनेका हुक्म
देवे और यह भी हुक्म देवे कि वह अपने पाससे सूच व सूच उस मुद्दतका अदा करे जिस मुद्दत
तक उसने अपना रोक रक्खा हो ।

व्याख्या—

इस दफामें यह बनलाया गया है कि यदि रिडीयर किसी डिबीडेण्ड (Dividend) न देवे और उसका नाम
कर्जकारोंकी सूचीमें दर्ज हो तो ऐसा व्यक्ति अदालतसे दूरजाय दे सकता है और अदालतसे उस वक्त अनिरा है कि
वह रिडीयरको उस कर्जकारोंका हिस्सा रसवी अदा करनेका हुक्म देवे तथा रिडीयरसे रोक हुई क्रमका सूच व दूरजायका
कर्ज भी उस कर्जकारोंकी दिवालिया इस दफामें यह भी बनलाया गया है कि डिबीडेण्डके लिये रिडीयरके विरुद्ध कोई एकदम
दायर नहीं किया जा सकता है इस बातका ध्यान रखा जाय कि इस दफाके अनुसार दरद्वारा देवल वही कर्जकारोंके दे
सकते हैं जिनका नाम कर्जकारोंकी सूचीमें दर्ज हो गया हो कोई दूसरा व्यक्ति इस दफाके अनुसार दूरजाय नहीं दे सकता है ।

दफा ६६ दिवालियों द्वारा इन्तजाम व उसका भत्ता

(१) अदालतको अधिकार है कि यह दिवालियोंकी उसकी कुल या गज जायदादका
इन्तजाम सुपुर्द करदे या अगर कोई रोजगार हो तो उसका चलानेका भार कर्जकारोंके फायदेके
लिये उसे सुपुर्द करदे या और किसी तौरसे जायदादके इन्तजाममें मदद करनेका भार जिस
किस्मसे या जिन शर्तोंके साथ चाहे उसे देदे ।

(२) अदालतको अधिकार है कि वह समय समय पर दिवालियोंकी जायदादसे उस
क्रूर भत्ता दिवालियों या उसके सान्धानकी परवरिशके लिये नियत करदे जितना मुनासिब
मालूम हो या दिवालियोंके कामके पयजमें अगर वह अपनी जायदादके रुमदानमें काम कर
रहा हो कुछ भत्ता नियत कर देवे; लेकिन इस प्रकारका भत्ता किसी समय भी घटाया बढ़ाया या
बन्द किया जासकता है ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार स्वयं दिवालियों ही को उसकी जायदादसे प्रवचना भार दिया जा सकता है चाहे वह उसकी सन

जायदादके लिये होवे अथवा नह उसकी जायदादके किसी खास हिस्सेके लिये होवे इस प्रकार यदि दिवालिखा करार दिये जानेसे पहिले दिवालिखा किसी रोजगारकी करता रहा हो तो उस रोजगारकी चाटू रखनेका कार्य भी उसी दिवालिखेकी सुपुर्दगीमें दिया जा सकता है परन्तु इस प्रकार दिवालिखेको जो काम सुपुर्द किया जावेगा वह अपने लाभके लिये नहीं करेगा किन्तु अपने कर्त्तव्यार्थके लाभार्थ करेगा अदालत दिवालिखेसे जायदाद आदिके इन्तजाममें मदद भी ले सकती है परन्तु इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि अदालत जिस प्रकार तथा जिन शर्तोंके साथ दिवालिखेसे काम लिया चाहिगी ले सकती है अथवा दिवालिखा मन माने इसके उस कामसे नहीं कर सकता है बल्कि कि वह दिवालिखा करार दिये जानेसे पहिले करता रहा हो।

दिवालिखा इस प्रकार सुपुर्द किया हुआ जो काम करेगा उसकी आमदनी कर्मस्वाहाहनके लाभार्थ समझी जावेगा और उस पर किसीतरफा अधिकार उसी प्रकार होगा जिस प्रकार उसका अधिकार दिवालिखेकी और सब जायदाद पर है उपद्रव (१) में बतलाया गया है कि यदि दिवालिखेने उसकी जायदाद नसूज करेके समर्थम काम लिया जावे तो उस कामके पूर्वजामे उसे कुछ भत्ता दिया जा सकता है परन्तु इस भत्तेको घटाना बढ़ाना या बन्द करना अदालतके अधिकारमें है और अदालत समय समय पर ऐसे भत्तेकी योजना कर सकती है।

उपद्रव (२) में यह भी बतलाया गया है कि अदालत दिवालिखेकी जायदादसे दिवालिखा तथा उसके परिवारके पोषणके लिये समय समय पर कुछ भत्ता दे सकती है परन्तु यह भत्ता भी ऊपर बतलाये हुये भत्तेके समान हर समय घटाना बढ़ाया बन्द किया जासकता है इस दफामें बतलाये हुए भत्ते (Allowance) की देनेके लिये अदालत बाध्य नहीं है किन्तु उसका देना न देना उसकी इच्छा पर निर्भर है।

यदि दिवालिखेको तनखाह मिलनी होवे तो उसे कोई खास भत्ता देनेकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह अपनी तनखाह में से कामदेके मुआविके बाधा पानेका इम्कान है देता—21 I. C. 950, 38 I. C. 410, 40 All. 211. परन्तु इत्यादिवाद हाईकोर्टने इसके विरुद्ध 45 All 384 में यह तय कर दिया है कि अदालतकी अधिकार है कि वह दिवालिखेको उस इमरे अधिभूते भी उसके तथा उसके परिवारकी आवश्यकते लिये कुछ भाग भत्तेके रूपमें दिलवा देवे अर्थात् आर्था तनखाहके अतिरिक्त नकशा आधी तनखाहमें भी उसे भत्ता दिलवाया जा सकता है अदालतकी यह भी अधिकार है कि जब चाहे इस भत्तेकी घटा बढ़ा भी देवे तथा जब चाहे उसे बन्द कर देवे।

दफा ६७ बचे हुए पर दिवालिखेके अधिकार

अब कि सब कर्जस्वाहोंके कर्ज पूर्ण रूपसे मय सुद्धके जैसा कि इस एक्टमें दिया हुआ है अदा हो जावे और उनके अनुसार की हुई कार्रवाहोंके सर्व भी चुक जावे तो जो कुछ इस अध्यायकी शर्त बचेगा वह दिवालिखेकी मिलेगा।

व्याख्या—

यदि दिवालिखेने सब कर्जस्वाहोंका कर्ज उसकी जायदादसे अदा कर दिया जावे तथा उनका सूर भी जैसा कि इस एक्टमें बतलाया गया है चुक दिया जावे और वह स्वयं भी जो दिवालिखेकी कार्रवाईके शिलसिलेमें किया गया है निवाह लिया जावे तो उसके बाद जो रूपया या जायदाद बचेगी उसे दिवालिखा पानेगा दिवालिखा बचे हुये रुपये पानेका अधिकारी है परन्तु वह रूपया उसी समय मिल सकेगा जब कि ऊपर बतलाई हुई तीनों शर्तें पूरी हो गई हों अर्थात्

(१) कर्जस्वाहोंका पुगन रूपया चुक जावे

(२) इस एक्टके अनुसार बतलाया सूद अदा कर दिया जावे, और

(१) दिवालियेके निष्पत्तिमें भी हुई कार्रवाइयोंका सर्वे चला कर दिया जावे

इस एक्टकी दफा ४८ में मूल दिशानिषे जावका उल्लेख है तथा दफा ६१ में भी नाद अदागी सब कर्षा जानेके दवाइया कगर दिने जानेके बादका सुद दिनाप जानेका उल्लेख है इस प्रकार सब कर्षाकारोंका कर्षा पूर्णमें सब सूरके निमता मित्र दफा ४८ व ६१ में है इससे जानेके बाद जा कर्षा बचेगा वही बचा हुआ बरता समझा जायेगा पन्तु इस बातका भी ध्यान रचना चाहिये कि दिवालियेकी कार्रवाईके सम्बन्धमें जो सर्वे होंगे उन सबकी अदापयी भी दिवालियेकी जायदाद ही से ही जायेगी और तभी बरतण उन खर्चोंकी भी ऊदा कर देनेके बाद जो कर्षा गिनावके हयमें रह जाइया वही दिवालियेके निष तर्कका अंशकी एककी इस दफामें (Shall) शब्द का प्रयोग किया गया है जिससे यह प्रकट होता है कि दिवालिया ही अजका उन बचे हुए कर्षके पानेका अधिकारी है नह कर्षा किमी और सबकी नही दिया जा सकना है । इतना अवगत होगा कि दिवालियेके न रद्दे पर उसके कस्तानिकागी उस बच हुए बचसे पानेके अधिकारी होंगे ।

दफा ६७ (ए) जांचकी कमेटी

(१) अंशालतको अधिकार है कि यदि वह उचित समझे तो उन कर्षाकारोंको जिन्होंने अपने कर्षोंको साबित कर दिया है एक जांच करने वाली कमेटी बनानेका अधिकार देवे जिसने कि यह कमेटी रिसीवर द्वारा दिवालियेकी आयदादके प्रपन्थका निरीक्षण कर सके ।

(२) जांच करने वाली कमेटीके सदस्य वही कर्षाकारहान हो सकेंगे, जिन्होंने अपना कर्षा साबित कर दिया है या जो ऐसे कर्षाकारहानके मुहतर आम होंगे ।

(३) जांच करने वाली कमेटीको रिसीवर द्वारा की हुई कार्रवाइयोंके सम्बन्धमें वही अधिकार प्राप्त होंगे जो उसके लिये निर्धारित कर दिये जावें ।

व्याख्या—

यह दफा प्रांतिक कानून दिवालिया सक्षेपण एक्ट १९, सब १९२२ के अनुसार बढाई गई है इस एक्टके विषे १ सितम्बर सन् १९१६ ई० को गवर्नरजनरल हिन्दु प्रदेशमें अपनी स्वीकृत प्रदावकी थी । यह दफा इस कारण बनाई गई है कि जिसमें रिसीवरके प्रपन्थका अन्त जाति निरीक्षण किया जा सके । अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें (May) शब्द का प्रयोग किया गया है जिससे यह प्रकट है कि अदागत जाव कमेटी नियुक्त करनेके लिये बाध्य नहीं है किन्तु उसका नियुक्त करना या न करना उसकी इच्छा पर निर्भर है अर्थात् जाव कमेटीकी नियुक्तिके लिये आज्ञा अदागत उसी समय देखे जब कि उसे ऐसी कमेटीके नियुक्त करनेकी आवश्यकता प्रतीत हो । ऐसी कमेटी बनने जानेका आज्ञा होने पर वह कर्षाकारहान इस कमेटीको बनायेगे निवले कर्षों सम्बन्ध में जा पुर है अर्थात् दिवालियेके हर एक कर्षाकारहानके ऐसी कमेटी बननेका अधिकार प्राप्त नहीं है और न किसी और शक्क हो का ऐसी कमेटी बनानका कोई अधिकार है ।

यह कमेटी गिनावके प्रपन्थका निरीक्षण करनेके लिये बनाई जावे । जिसमें कि दिवालियेकी जायदादका ठीक ठीक प्रपन्थ किया जासके तथा उसके निम्नता अधिक कर्षा वसूल किया जासके वसूल किया जावे और वह किसी प्रकार बर्बाद न हो सके ।

उपदफा (२) में यह बात भी साफ कही गई है कि जाव कमेटीके मेबर भी वही कर्षाकारहान होंगे जिसका कर्षा साबित किया जावता है या उनके पुनराजम होंगे अर्थात् कमेटीके मेबर चाके अनिश्चित और कोई भा ग्याते नहीं हो सकेंगे । अंग्रेजी एक्टका इस उपदफामें (Shall) शब्द का प्रयोग किया गया है जिससे यह प्रकट है कि जाव कर्षाकारहानके नियमका प्रावकी अवस्थाकी बना चाहिये ।

उपदफा (३) में यह नतलया गया है कि जाच कंटीको रिसीवरकी कर्तव्य पर वही अधिकार होंगे जो उसके लिये निर्धारित किये गये हों ।

रिसीवरके खिलाफ अदालतमें अपील

दफा ६८ रिसीवरके खिलाफ अदालतमें अपील

अगर रिसीवरके किसी काम या फैसलेसे दिवालिवा या कोई कर्जखवाह या अन्य कोई व्यक्ति असंतुष्ट होये तो वह अदालतमें उसके विरुद्ध दारख्वास्त दे सकता है और उस पर अदालतको अधिकार है कि वह रिसीवरके उस काम या फैसलेको बहाल रखे या पलट दे या संशोधित कर दे और ऐसा हुक्म मुसालिय समझे दे देये ।

लेकिन इस दफाके अनुसार इस प्रकारकी कोई शिकायत किये जाने वाले काम या फैसलेसे २१ दिनके बाद न चुनी जावेगी ।

व्याख्या—

इस दफाका प्रयोग ऊर्दी मामलोंके सम्बन्धमें किया जासकेगा जो रिसीवरने दिवालिवाकी आयदादके सम्बन्धमें दिवालिवा की दारखानोंके सिद्धमिलेमें किया हो दख्ता—39. All. 204, A. I. R. 1925 Bom. 283.

इस दफाके अनुसार अदालतसे अपील करनेका अधिकार रिसीवरके किसी खास काम या हुक्मके लिये ही नहीं है किन्तु रिसीवरके किसी भी काम या हुक्मकी अपील इस दफाके अनुसार अदालतमें की जासकती है । इस दफाके अनुसार अदालतसे अपील कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसे रिसीवरके किसी काम या हुक्मसे हानि पहुंचती हो अर्थात् दिवालिवा स्वयं इस दफाके अनुसार अपील कर सकता है, दिवालिवासे कोई भी कर्जखवाह इस दफाके अनुसार अपील कर सकता है इसी प्रकार कोई और शास्त्र भी जिसे रिसीवरके कामसे या हुक्मसे हानि पहुंचती हो इस दफाके अनुसार अपील कर सकता है । ऐसी अपीलके होने पर अदालतकी अधिकार है कि वह रिसीवरके वह काम या हुक्मको जिसके विरुद्ध अपीलकी गई हो जैसेका तैसा बहाल रखे या उससे पलटदे या उसमें कोई संशोधन कर देवे । और साथही साथ जैसी आज्ञा वाचित समझे उसके लिये देदेवे ।

अंग्रेजी एक्टकी इस दफाके (May) शब्दका प्रयोग किया गया है जिससे यह बली भाति प्रकट है कि अदालत इस दफाके अनुसार अपीलकी जाने पर किसी खास हुक्मके देनेके लिये बाध्य नहीं है किन्तु उसका देना अदालतकी आज्ञा पर निर्भर है । अदालत शिवायत लिये हुए काम या हुक्म पर बिचार करनेके पश्चात् तथा उसकी जाँच करके बाद समुचित जे आज्ञा देना मुताबिक समझे दे सकता है अर्थात् रिसीवरके काम या हुक्मसे जेमका तैसा बना रहने दे या उसे पलट दे या उसे संशोधित कर देवे । साथही साथ यदि वह कोई हुक्म हुक्म दिया चाहदे तो दे सकता है परन्तु इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि इस दफाके अनुसार अपील २१ दिनके अन्दरही की जाना चाहिये अर्थात् जिस काम या हुक्मके विरुद्ध शिकायत होवे तो उसके होनेके बाद २१ दिनही के अन्दर उसकी अपील अदालतमें कर देवे अन्यथा शिवायत करने वालेको इस दफाके अनुसार अपील करनेका अधिकार जावा रहेगा । यदि रिसीवरका कोई काम बेवर्तिय होवे और उससे कर्जखवाहोंके हितोंको आघात पहुंचाता हो वा अदालत रिसीवरके ऐसे हुक्मको रद्द कर सकती है देवे—73 I.O 374

यदि किसी व्यक्तिने दिवालिवाकी किसी आयदादको रिसीवरसे छेदी हो तो वह इस दफाके अनुसार अदालतमें दारख्वास्त दे सकता है कि उसकी कोई मालकी जाने तथा दूसरी खरीदारीकी मोटी रक क्लार देकर मसूर न की जावे । अदालतको ऐसी

दाएस्त इन दफ्ते अनुसार सुननेका अधिकार है । इस लिये कोई नाकायदा मुकदमा चलानेकी आवश्यकता नहीं है देवो—
66 I. C. 524.

यह दफा ऊर्ध्व रिश्वरको कर्मा या हुक्मों का देवोगी जो इन एकडे अनुसार नियुक्त किये गये हैं और यदि कोई रिश्वर नाकायदा नियुक्त न किया गया हो तो उसके कर्मोंके सम्बन्धमें यह दफा लागू नहीं समझना चाहिये देखो—A. I. R 1924 Mad. 461.

यदि इस दफाके अनुसार अदालत कोई हुक्म देवे तो उस हुक्मकी अन्तिम हुक्म नहीं समझना चाहिये किन्तु उसकी अपीलकी आवश्यकता है देखो—40 Mad 752.

यदि इस दफाके अनुसार करिवार्ड करनेके लिये कोई व्यक्ति बाध नहीं है इसलिये यदि कोई व्यक्ति नियत किये हुये समयके अन्दर इस दफाके अनुसार दिये हुये काम या हुक्मकी अपील आशुक्रममें न करे तो वह उसके परवाह भी रिश्वरके विरुद्ध मामूली दीवानीका मुकदमा दायर कर सकता है यदि उसे उस हुक्म या कामसे हानि पहुँचती हो अथवा दूसरी इस दफामें (May) उदाहरण मीमांसा किया गया है निम्नमें यह प्रगट है कि यदि हानि उठाने वाला व्यक्ति चाहे तो इस दफाके लाभ उठा सकता है देखो—A. I. R 1924 All. 40-46 All. 16. जब कि दिवालियेकी करिवार्ड समाप्त हो चुकी हो तो हरिकोटको कोई अधिकार नहीं है कि वह आकिशुन रिश्वरके व्यवसायी या व्यवसायीको दीवानी का विवाद में उसे अधिकार है कि किसी खास काममें वह जज दिवालियेको सहाय आदि देवे देखो—A. I. R 1927 All. 260.

यदि रिश्वर किसी कर्तव्यवाहके कहने पर कोई काम न करे या उसके करनेसे इन्कार कर देवे तो केवल अपनी ही बातको दिवालियेका काम इस दफाके अनुसार नहीं माना जावेगा । देखो—47 Mad. 673.

यदि रिश्वर दफा ५३ या ५४ के अनुसार करिवार्ड करनेसे इन्कार कर देवे तो कर्तव्यवाहको इस दफाके अनुसार अपील करनेकी आवश्यकता नहीं है किन्तु वह स्वयं भी उस दफाओंके अनुसार अदालतसे करिवार्ड कर सकता है । देखो—
दफा ५४ (५) इस दफाके अनुसार करिवार्डकी अन्तिमके लिये यह आवश्यक नहीं है कि कोई न कोई दाएस्त अवश्य ही जाने यदि अदालत चाहे तो स्वयं भी रिश्वरके किसी काम या हुक्ममें पकड़ सकती है या सहायित्व कर सकती है और ऐसा करनेमें इस दफासे कोई बाधा नहीं पड़ेगी देखो—1 Lah. 307-38 I. C. 6.

जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है कोई भी व्यक्ति निम्न रिश्वरके काम या हुक्मसे हानि पहुँचती हो इन दफाके अनुसार अदालतसे अपील कर सकता है । हानि पहुँचनेसे अभिप्राय यह है कि उसे कानूनी हानि पहुँचती हो यह नहीं कि वह हुक्मके हो जानेकी वजहसे उसके आपदाके किसी लाभमें बाध पड़ेगी । यदि रिश्वरके किसी कामके कारण कोई व्यक्ति बाधग्रस्त पड़ेगा तो उसे इस दफाके अनुसार अपील करनेका अधिकार है, देखो—51 I. C. 118. इस कारण यदि कोई उल्लंघन न पकड़ी हो या कोई कानूनी हानि न होती हो तो दफा ५८ लागू न होगी ।

एक छुट्टिने अपनी डिर्मामें देहकी हुई जायदादकी नीतिमें खरीद किया और इसके परवाह करनेदार मरतुन दिवालिया फ्लार दे दिया गया तथा उसकी जायदादके लिये रिश्वर नियुक्त कर दिया गया । रिश्वरने उस छुट्टिने द्वारा खरीदकी हुई जायदादको बेचना चाहा तो यह तय हुआ है कि छुट्टिनेके रिश्वरके इस मामले में कोई कानूनी हानि पहुँचती है क्योंकि यह जायदाद दिवालियेकी नहीं है और यदि रिश्वर ऐसी जायदादको बेच भी देवे तो इसमें छुट्टिने खरीदारके हक पर कोई असर नहीं पड़ेगा अर्थात् इस प्रकार जायदादका बेच नामा एक किस्मका काम होगा देखो—20 I. C 683 यदि रिश्वर किसी कर्तव्यवाहके कर्मों में बाध न करे तो ऐसे मामले में कर्तव्यवाहकी हानि समझना चाहिये और वह कर्तव्यवाह इस दफाके अनुसार अपील कर सकता है, देखो—78 I. C. 857. यदि आकिशुन रिश्वर यह तय करे कि दिवालियेको कोई

करी अदा करना है तो ऐसे हुक्मसे दिवालियेको हानि पहुँचती है और इसकी अपील इत दफाके अनुसार की जा सकती है, देखो—62 I. C. 441.

यदि रितीवर किसी दूसरे व्यक्तिकी जायदादको दिवालियेकी जायदाद समझ कर ले लेवे तो वह व्यक्ति जिसकी जायदादकी कोई है इस दफाके अनुसार अपील कर सकता है देखो—36 All 8, 35 All 410, 47 I. C. 62 (Cal)

परन्तु यदि रितीवर किसी दूसरेकी जायदादको दिवालियेकी जायदाद कतार देकर बँच देवे तो दिवालियाको इस दफाके अनुसार अपील करनेका अधिकार नहीं है क्योंकि उसको इस मामले कोई हानि नहीं पहुँचती है, देखो—41 All. 243, 49 Mad 461.

मराठ हार्बोर्टने एक मामलेमें यह भी तय किया है कि यदि विवाहपर परिवारके पिताने कोई जायदाद बँचती होवे और अदालत उस मरणागामी भंखूज कर देवे तो उसके रुककोंकी यह अपील नहीं होगी कि वह रितीवर द्वारा उस जायदादके सम्बन्धमें की जाने वाली किसी कार्रवाईमें रुकावट ला सकें, देखो—A. I. R. 1927 Mad. 282.

यदि रितीवर किसी और शख्सकी जायदाद पर सन्ततीसे कब्जा कर लेवे तो उस और शख्सके लिये दो तर्गके खूले हुए हैं, वह इस दफाके अनुसार कार्रवाई कर सकता है और अगर वह चाहे तो अदालत दिवालियामें कोई कार्रवाई न करे किन्तु वह मामूली दीवानी अदालतमें अपनी जायदादकी वापिसके लिये दावा उस प्रकार कर देवे जैसे कि अनधिकार कब्जा करने वालके विरुद्ध दावा किया जाता है, देखो—39 All. 626, 40 I. C. 122; 41 All. 378, A. I. R. 1924 Oudh 294

इस दफाके अनुसार अपील उसी अदालतमें की जाना चाहिये जिस अदालतने रितीवरकी नियुक्त किया हो यदि रितीवरने किसी जायदादको दिवालियेकी जायदाद कतार देकर उसने नौगणकी घोषणाकी हो और कोई दूसरा व्यक्ति जिसने दिवालिया कतार दिये जानेसे पहिले उस जायदादको दिवालिपमे खरीदा हो, इस दफाके अनुसार दरखास्त देवे परन्तु उनकी दरखास्त २१ दिनों बाद हानके कारण खारिज कर दी जावे तो इसने यह नहीं समझना चाहिये कि उस व्यक्तिके इस दफाके अनुसार कार्रवाई करनी है किन्तु वह व्यक्ति अदालत दीवानांमें रितीवरके विरुद्ध दावा दायर कर सकता है, देखो—44 All. 620. परन्तु 47 Bom 548. में यह तय किया गया है कि यदि रितीवर दिवालियेके कर्तव्योंके विरुद्ध कोई हुक्म दे देवे तो वह लोग इसी दफाके अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं तो उनकी दूसरा मुकदमा चलेनेका अधिकार नहीं है।

यदि कोई व्यक्ति इस दफाके अनुसार कार्रवाई करेगा तो उसे मुकदमा दायर करनेका हक नहीं रहेगा और यदि वह मुकदमा दायर करेगा तो उसे इस दफाके अनुसार कार्रवाईकी आवश्यकता नहीं है अर्थात् वो में से एकही प्रकारकी कार्रवाई की जा सकती है, देखो—41 All. 378.

यदि अदालत इस दफाके अनुसार किसी प्रश्नको तय कर देवे तो द्वारा उस प्रश्नको तय करनेके लिये कोई दूसरा मुकदमा नहीं चलाया जावेगा क्योंकि वह अदानतता फैमल आर्जेंट फैमल समझना चाहिये और उसे अब तनवीन शूदा (Resjudicata) समझना चाहिये, देखो—39 All 626, A. I. R. 1923 All 293. परन्तु इस प्रश्नके लिये सन हार्बोर्ट एक दूसरेसे सहमत नहीं हैं बल्कि हार्बोर्टने यह तय किया है कि यदि अदानत दिवालिया क्रिमी ऐसी जायदादके सम्बन्धमें किये हुए एग्राजकी नामशूर कर देवे जो दिवालियेकी जायदाद कतार देकर कुर्क व नौगणकी गई हो तो हानि वाले फीकको अधिकार है कि वह अपने हुक्मों तय करनेके लिये वाकयादा नालिया दायर कर सकता है, देखो—A. I. R. 1923 Lah. 224.

इस बातके लिये कोई मतभेद नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति जिस रितीवरके काम या हुक्मसे हानि पहुँची होवे इस दफाके अनुसार अदालत दिवालियासे अपनी शिकायत शुरू करनेको न करे तो उसे मामूली दीवानांका हाना दायर करके अपनी

सिद्धांत दूर करनेका अधिकार है, देखो—46 All. 16 यदि दिवालिया किसी नायदादके बेंचे जानेमें एतदात करे और रिसीवर उस एतदातका बिला कुछ स्थान्त लिये उस नायदादको बेंच देवे और इसके पन्नात् रिसीवरके इस कामके विशुद्ध अदालतमें कोई एतदात न किया जावे तो दिवालिया दुबारा उसी बिना पर इस बयनामें के विरुद्ध यह नहीं कह सकता है कि यह बयनामा चरत किया गया था, देखो—A. I. R. 1924 Mad. 147.

इस दफाके अनुसार तहसीलान करने समय यह आवश्यक नहीं है कि अदालत दुबारा शहदत लेवे किंतु वह रिसीवर द्वारा ली हुई शहदत ही पर विचार कर सकती है और न रिसीवरको उस दुरवदास्तके विषे फरीक मुकद्दमा ही बगना करती है, देखो—A. I. R. 1924 Mad. 830.

परन्तु जहाँ तक होमके अदातको रिसीवर द्वारा ली हुई काँवर्ड पर विचारण न करना चाहिये किंतु उसे स्वयं दोनों फरीकोंकी बात समझ चाहिये तथा आवश्यकतानुसार तहसीलान भी करना चाहिये जिसमें कि ठीक इन्ताफ किया जासके देखो—39 All. 626. यदि कोई नाकायदा मुकद्दमा इस बातके लिये चलाया जावे कि जो नायदाद रिसीवरने बेंचा है उसमें दिवालिबेका कोई हक नहीं था तो रिसीवर उस मुकद्दमके लिये एक जरूरी करीक है और अदालत दिवालियाकी आशा लिये बिना वह फरीक मुकद्दमा बगना जासकता है, देखो—46 All. 16.

इस दफाके अनुसार दुरुजान देनेके लिये २४ दिनों मियाद नियत की गई है डिस्ट्रिक्ट जज अर्थात् अदालत दिवा-
लियाको २४ दिनों पहिले रिसीवरकी रिपोर्ट मजूर करनेका अधिकार नहीं है परन्तु फरीकनकी सजाय पर इसमें पहिले भी रिपोर्ट मजूर की जासकती है २७ दिनों अन्दर यदि किसी कर्तेस्वाह आदि की कोई एतदात काना हो तो वह एतदात कर सकता है जिसमें वह रिपोर्ट बदला जायके या उसमें समायोजन किया जासके, देखो—A. I. R. 1926 Cal. 826. अदालत दिवालियाकी कोई अधिकार नहीं है कि वह रिसीवर द्वारा किये हुए बयनामों पर समुच्च कर देवे जबनक कि प्रोत्तरेही साजिश, खास बेनतीरी, बेंचनेमें बड़बड़ी या बेउनमानों न साबित होजावे जिसकी वजहसे नायदादों दुस्मान पहुँचता हो या जब कि रिसीवरने अपने अधिकारोंसे बाहर उस सौदेगी न किया हो, देखो—A. I. R. 1928 Rang 60; 107 I. C. 172.

चौथा प्रकरण

दण्ड (सजा)

दफा ६९ दिवालियेके जुर्म

अगर कोई कर्जदार दिवालिया कपार दिये जाने पाछे हुक्मके होनेसे पहिले या उसके बाद—

(ए) दफा २२ के अनुसार बताये हुए अपने कर्तव्योंको जानते हुए नहीं करता है या अपनी जायदादके किसी हिस्सेका कब्जा जो उसके कर्तव्यवाहोंमें इस एक्टके अनुसार बचना चाहिये और जो उसके कब्जे या निगरानीमें है अदालतको या अदालत द्वारा कब्जा लेनेके लिये नियुक्त किये हुए किसी दूसरे व्यक्तिको नहीं देता है; या

(बी) घोखा देहीसे अपने कानकी हालत छिपानेकी इच्छासे या इस एक्टके अनुसार काम न होने देनेकी इच्छासे—

(i) किसी दस्तावेजको जिसका इस एक्टके अनुसार होने वाली सहकीकातसे सम्बन्ध हो बरपाद कर दिया हो या जान बूझ कर रोक दिया हो या जानते हुए पेग न होने दिया हो, या

(ii) झूठी किताबें रखी हों या रखवाई हों, या

(iii) किसी दस्तावेजमें जिसका सम्बन्ध इस एक्टके अनुसार होने वाली सहकीकातसे है ग़लत इन्द्राज कर लिये हों या किसी इन्द्राजको न किया हो या जान बूझ कर इन्द्राजको बदल दिया हो या ग़लत कर दिया हो, या

(सी) घोखा देहीसे अपने कर्तव्यवाहोंमें तक़सीम किये जाने वाले रुपयेको कम करनेकी ग़रज़से या अपने किसी कर्तव्यवाहको बेजा कायदा पहुँचानेकी ग़रज़से—

(i) उस कर्तव्यवाहके कर्ज़को चुका दिया हो या उससे लेने वाले कर्ज़को छिपाया हो, या

(ii) अपनी किसी क्रिमकी जायदादको अलहदा कर दिया हो, या उस पर बार कर लिया हो या उसको छेद कर दिया हो, या छिपा लिया हो,

तो जुर्म साबित होने पर उसको एक साल तककी सज़ा दी जासकेगी।

न्याय्य—

रिपेयिंग एक्ट १९२७ [Repealing Act 1927 (XII of 1927)] के अनुसार अंग्रेजी देशमें इस दफाके आद्वारे "By the Court" यह शब्द हटा दिये गये हैं अर्थात् पहिले यह था कि जुर्म साबित होने पर (अदालत द्वारा) ब्रह्मणे एक साल तककी सज़ा दी जासकेगी अब "अदालत द्वारा" यह शब्द नहीं रहे गये हैं।

इस दफ्ते दिवालिये द्वारा किये जाने वाले अपराधों तथा उनके होने पर जो दण्ड दिया जानेको है उसका वर्णन है । इस दफ्ते में उन सब कार्योंको उल्लेख है जो इस दफ्तेके अनुसार दण्डनीय अपराध समझे जाने चाहिये ।

इसमें दिये हुए अपराध एक प्रकारसे कायदेके अनुसार वर्णन करनेके अपराध हैं यह उन अपराधोंकी भांति नहीं हैं जैसे कि फौजदारीके लम्बे हमले हैं देखो—39 All. 171; 54 I. C 740. इस दफ्ते में बतलाये हुए अपराध यदि दिवालिया करार दिये जानेसे पहिले किये गये हों चाहे वह दिवालिया करार दिये जानेके बाद किये जावे दोनों दशाओंमें सब दण्डनीय होंगे । यह बात भली भांति प्रकट नहीं है कि 'पहिले' से अभिप्राय कितने समय पहिलेसे है अर्थात् दिवालिया करार दिये जानेसे चाहे मितना पहिले इस दफ्ते में बतलाया हुआ अपराध किया गया हो वह दण्डनीय अपराध ही समझा जावेगा परन्तु जिन अपराधोंका उल्लेख है उनसे यह प्रकट होता है कि अधिकतर दिवालियेके मामलोंकी तत्कीर्तके सम्बन्धमें जो मसले पेश आयेगे वही दण्डनीय समझना चाहिये देखो—A. I. R. 1927 All 352.

अदालतसे इस दफ्तेके अनुसार फौजदारी कितनी समय भी कहीं जासकती है और उस वक्त अदालतका कर्तव्य होगा कि वह इस प्रश्न पर विचार करे कि आया दिवालियेके दण्डसूचक अपराध किया है या नहीं वह आवश्यकता नहीं है कि जब दिवालिया महाल होनेकी (Discharge) दाखलास्त देवे तभी उसके अपराधोंका फैसला किया जाना चाहिये, ऐसी—49 I. C 55

महाज (ए) इस क्राजमें दो प्रकारके कार्योंका उल्लेख है एक तो यह कि दिवालिया जानबूझ कर पृष्ठा १९ में बतलाये हुए कर्तव्योंका पालन न करे व दूसरे यह कि वह जानबूझ कर जावदारी कब्जा अदालत या रितीवरकी न देवे । जिन कार्योंका उल्लेख इस क्राजमें है वह वही समय अपराध समझे जासकेंगे जब कि दिवालियेके जानबूझ कर उस कामकी किया हो ।

जिस जायदादके कब्जा देनेका प्रश्न इस क्राजमें किया गया है वह ऐसी जायदाद होना चाहिये जो कर्तव्यद्वारासे बन्दी जासकती हो तथा वह जायदाद उस समय दिवालियेके कब्जे या अधिकारमें होवे दफ्ता १८ में उन जायदादोंका जिक्र है जो कर्तव्यद्वारासे बन्दी जासकती हैं । जो कृषय रेलवे फण्डमें जमा हैं वह इस प्रकार बाध जासकता है इस लिये ऐसे कृषयके सम्बन्धमें यह क्राज लागू नहीं समझना चाहिये, देखो—44 Bom. 673. इसी प्रकारकी बात दूरकी जायदाद, पोलिटिकल पेंशन तथा कास्तकारीकी जमीन आदिके लिये समझना चाहिये ।

कृषाज (बी) इस क्राजमें जिन कार्योंका उल्लेख है वह वही समय अपराध समझे जावेंगे जब कि दिवालियेके वही अपने अमली हालतकी डिप्लोमके मशारे किया हो या इस दफ्तेके अनुसार होने वाली कार्रवाईको रोकनेकी मशारे किया हो और वह काम घोषादेहीकी ओरतसे किये गये हों । इस क्राजके अनुसार यदि कोई ऐसी दस्तावेज बाध करदी जावे या पेश न होने दी जावे जिसका सम्बन्ध दिवालियेके मामलेसे हो तो यह अपराध समझा जावेगा । दस्तावेजका बर्बाद किया जाना उसी समय मान्य जासकता है जब कि उसका होना साबित कर दिया जावे इसी प्रकार कितनी दस्तावेजके पेश होनेका प्रश्न भी उसी समय उपपत्ति हो सकेगा जब कि यह साबित हो जावेकि कोई उस प्रकारकी दस्तावेज मौजूद है । इस क्राजके दूसरे भागमें यह बतलाया गया है कि यदि घड़ी चिनार खरीदी या रखवाई जावे तो वह भी अपराध है । तीसरे खण्डमें गन्तु इन्टरानस करना तथा किसी इन्टरानस गलत कर देना भी लम्बे मन्दापा गया है परन्तु जैसा ऊपर कहा जा चुका है यह सब बातें उसी समय लम्बे समझी जावेंगी जब कि घोषादेहीकी मशारे दिवालियेके अपने मामलेके डिप्लोम अपवा इस दफ्तेके अनुसार फौजदारीके प्रकार कर्तव्यी मशारे किया हो ।

क्लान (सी) इस क्लानमें नतनाये हुए कार्य उसी समय अपराध समझ जावगे जब कि दिवालिगन धोखादेहीकी मशाले कनेखाहोंमें बांधी जाने वाली रकमको कम क्लानकी मशाले बिधा हो। अथवा इन मशाले किया हो कि जिसमें उसके किसी खास कनेखाहकों केना लाम पहुँच जावे। इस क्लानक पादिल माममें यह बालाध गया है कि यदि दिवालिया अपने छने या देने वाले कनेका बिगारे या उन घुका देवे तथा दूसरे भागमें यह नतनाया गया है कि अगर वह अपनी जालदारकी बिगारे या उसे हथिये या उसे रेलन वरद अथवा उस पर कोई बार हो जाने दे तो दोना दशाओंमें ऊपर बतलाई हुई गतेके पूरा होने पर इस प्रकारके काम दण्डनीय अपराध समझे जावगे। यदि कोई अपीक दिवालिगनेरी दशा होवे या अपनी दूरानसे पाठ इस मशाले हथिये कि जिसमें उसके कनेखाहान उस पाठका न पासके तो ऐसे कामका अपराध समझना चाहिये, देखो—A. I. R. 1927 All. 352. यदि हा दफामें बतलाया हुआ कोई अपराध साबित होवे तो अपराधीको (बचते कारावास का दण्ड दिया जासकता है। इस दफामें यह नहीं बतलाया गया है कि वास्तवानका दण्ड कतार (Rigorous) दण्ड होना चाहिये अथवा साधारण (Simple) परन्तु प्रकट रूपमें ऐसा मान्य होता है कि दोनों प्रकारका दण्ड दिया जासकता है। इस दफामें यह नहीं बतलाया गया है कि जिसक कहने पर इस दफाके अनुसार कारावासी जानेगा। ऐसा मान्य होता है कि अदालत स्वयं ही किसी कनेखाहके कहने पर इस दफाके अनुसार कारावासी पाठ कर सकती है देखा—14 All. 145. रिलीवर भी अदालतन इस दफाक अनुसार दिवालिगनेके निरुद्ध करानाई पाठ करेगा कह सकता है।

इस प्रकार अपराधी ठहरानेके लिये बाकायदा मामला चलाया जाना चाहिये और जो जुर्म छपाया जावे उसके साबित होने पर दिवालिया दोरी ठहराया जान आर तभी वह दण्डका भागी होगा। उसको चहिले यह बतला दिया जाना चाहिये कि उसने कौनसा अपराध किया है जिसमें उसे काका जवानदहीका पाका भिन्न जावे, देखा—17 Cal. 209

यदि अशुद्धकी इस बाइका विश्वास हो जाव कि दिवालिगने इतदफाके अनुसार जर्मे किया है तो अदालत इन प्रकारका फैसला लिख सकती है तथा किसी कस्टे क्रास मजिस्ट्रेटके पास जिसकी अधिकार सीमा में वह मामला हुआ हा उस मासखरी थालू करनेके लिये भेज सकती है देखो दफा ५०।

दफा ७० दफा ६९ का जुर्म लगाने पर कार्रवाई

जब कि अदालतको आवश्यकतानुसार प्रारम्भिक जांच करनेके पदचात् विद्यमान हो जावे कि दफा ६६ में बतलाये हुए अभियोगोंमें से किसी अभियोगकी जांच होना आवश्यक है और वह अभियोग दिवालिग द्वारा किया हुआ प्रतीत होता है तो अदालत अपनी तजवीज इस बातके लिये लिख सकती है और उस जुर्मका इस्तगाल लिखकर उस अग्रथल वर्जके (First Class) मजिस्ट्रेटके पास भेज सकती है जिसकी अधिकार सीमा (Jurisdiction) होवे और वह मजिस्ट्रेट उस अभियोगका उसी ढंगसे सुनेगा जैसा कि सन् १८६८ ई० के जायदा फौजदारी (The Code of Criminal Procedure 1898) में बतलाया गया है।

दियालिया—

दफा ६९ में नतलाये हुए दुर्गोषी तहकीकत किय जानेवा नियम इस दफामें बतलाया गया है। यह दफा नहीं है और दिवालिया सशायन एक्ट सन् १९२६ ई० के अनुसार पुाना दफाके नयाय रहीं गई है। इस दफाक बतया जानेसे पुाने नियममें एक कता परिवर्तन सा हो गया है क्योंकि पिछली दफाके अनुसार अदालत दिवालियाको भी अधिकार था कि

बहु दफा ६९ में मनगये हुए जुर्माने लिये जाने पर उनका तहकीकात कर लके तथा अधिपुनर्क होना निर्धारित होने पर उसे दण्ड दे सके परन्तु इस दफाके अनुसार उसे केवल प्राथमिक ज्ञान ही वसूला अधिकार है न इसके परवार्तु वह अधिकार रखने वाले परफेक्ट मजिस्ट्रेट को पास मापनेको भेज सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरे बाल भौंकी जो पिछली दफा में भी नष्ट यह है कि कानून दिवालयिके अनुसार किसी जुर्माने लगाये जानेसे पहिले उसमें नोटिस दिवालयिके दिया जाना आवश्यक था परन्तु इस नई दफाके अनुसार बिना ऐसे नोटिस देनेकी आवश्यकता नहीं है यदि अदालत आवश्यकतानुसार प्राथमिक ज्ञान करनेके पश्चात् अतन समझे कि अभियोग चलाया जाना चाहिये तो वह मापनेकी चार्ज करनेके लिये मजिस्ट्रेटके यहा भेज सकता है। पिछली दफा नीचे दी जानी है जिसके देखनेम पाठकोंतो दोनों दफाओंका करक भली भाँति विदित हो जावेगा।

पिछली दफा ७० जो रद्द की जाचुकी है:—

दफा ७० दफा ६६ के अनुसार लगाये हुए अभियोगकी कार्रवाई

(१) जब कि अदालतको यकीन हो जाये कि दफा ६६ में दिये हुए किसी जुर्मानेकी तहकीकात करनेकी वजह (जकरत) है तो अदालत हुक्म देगी कि कर्जदारको नोटिस इस बातका दिया जाये कि यह वजह जाहिर करे कि उसके खिलाफ एक या उससे अधिक जुर्माने क्यों ल लगाये जायें तथा यह नोटिस इस प्रकार भेजे जावेंगे जिस प्रकार सम्मन ज़ाबता दीधानी के अनुसार भेजे जाते हैं।

(२) नोटिसमें जुर्माना (मुद्दआ) बताया जावेगा और एरुही नोटिसमें एकसे अधिक जुर्मानोंका हवाला दिया जासकता है।

(३) उस नोटिसके अनुसार समाप्त करते समय और उसके अनुसार लगाये हुए जुर्मानेकी समाप्त करते समय अदालत जहाँ तक हो सकेगा उस प्रकार कार्रवाई करेगी जैसा कि सन् १८६७ ई० के जायता फौजदारीके २१ वे प्रकरणमें चारण्ट क्लेज (मानलॉ) के लिये जिनकी सुनवाई हाइकोर्ट या लेगल कोर्टमें होती है दी हुई है।

(४) इस दफाके अनुसार चाहे जितने जुर्माने हों सब एक साथ लगाये जासकते हैं। परन्तु किसी कर्मदारको इकट्ठा दो सालसे ज्यादाके लिये सज़ा नहीं दी जासकेगी जबकि उसमें उसी दिवालयिकी कार्रवाईके तिलसिलेमें इस एक्टके अनुसार जुर्माने किये हों।

(५) अदालतको अधिकार है कि वह दफा ६६ के अनुसार किसी जुर्मानेकी तहकीकात स्वयं करनेके बजाय उसका इस्तगाला लिखकर सबसे नजदीकी फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट (दर्ज ऑफ़िस) के पास जिसे अधिकार समाप्त होवे भेज सकती है और उस हालतमें वह मैजिस्ट्रेट उस इस्तगालासेको उसी प्रकार सुनेगा जिस प्रकार सन् १८६८ के ज़ाबता फौजदारीमें दिया हुआ है। परन्तु उसमें मुस्मगील (वादी Complaint) का बयान लेना जरूरी नहीं है।

व्याख्या—

पहिली जनवरी सन् १९२७ ई० से एक्ट ९ सन् १९२६ ई० गवर्नर जनरल हिन्दु मसौदामे आजातुमार कार्यान्वित किया गया था और तभीसे ऊपर दी हुई पुरानी दफाके बजाय नई दफाका प्रयोग प्रारम्भ हुआ।

चूकि सिविल जस्टिस कमेटीने यह समझा कि हाईकोर्ट तथा अदालत चिल्लाते समय दफा ६९ में बतलाये हुए छोटे मोटे प्रयोगों की तहकीकातमें बहुत नष्ट होगा तथा यह बचिन समझा कि ऐसे खर्चों की जाच बखूबी तौरसे कर्तव्य प्राप्त मजिस्ट्रेट कर सकते हैं इस कारण तथा अन्य भी बहुत सा बातोंका सोचत हुए पुरानी दफाके बजाय इस नई दफाका प्रयोग में लाया जाना उन लोगोंकी अनुमतिमें उचित प्रतीत हुआ तथा यह नई दफा निर्माणित की गई । चूकि दफा ६९ में बतलाये हुए खर्च एक प्रकारसे फाजदारीक खर्च हैं इस कारण उन खर्चोंका तहकीकात या जाचना फाजदारीक नियमोंके अनुसार होना बतलाया गया है अदालत दिवालिया इस दफाके अनुसार किसी मामलेकी तहकीकात मजिस्ट्रेटके सुपुर्द करनेके लिये बाध्य नहीं है और जब उसको विश्वास हो जाय कि दिवालियाने दफा ६९ में बतलाये हुए खर्चों में से किसी खर्चको चाहिए तौर पर किया है तब वह मजिस्ट्रेटके पास मामला भेज सकती है । अपने विश्वास करनेके लिये अदालत दिवालियाकी अधिवार है कि वह प्रारम्भिक जाच कर उब इस दफाके अनुसार यह आवश्यक है कि अदालत दिवालिया तहकीकात शिकायत उस खर्चकी मजिस्ट्रेटके पास भेजे । मजिस्ट्रेट दर्जो फ्लवला होना चाहिये अर्थात् इस दफाके अनुसार दर्जो दीपम व सोमके मजिस्ट्रेट तहकीकात नहीं कर सकते हैं और उभा मजिस्ट्रेटके पास मामला जाना चाहिये जिसका अधिवार सीमा (Jurisdiction) होवे । जब इस दफाके अनुसार कोई मामला मजिस्ट्रेटके पास भेजा जावे तो मजिस्ट्रेटका कर्तव्य होगा कि वह बतली जाच जाचना फाजदारीके नियमोंके अनुसार करे । अमेजी एक्टकी इस दफा में "shall" शब्द दफा प्रयोग किया गया है जिससे यह प्रकट है कि मजिस्ट्रेटकी ऐसे मामलोंकी जाच अवश्य करना चाहिये तथा उसकी जाच जाचना फाजदारीमें बतलाये हुए नियमोंके अनुसार होना आवश्यक है किमी दिवालियेके विरुद्ध मामला चाड करनेसे पहिले अदालतकी इस बातका विश्वास कर लेना चाहिये कि प्रकट रूपम उसन अवश्य उस खर्चको किया है केवल शरही पर यह फाजदारीका मामला चाड नहीं करना चाहिये, देखो—A. I. R. 1926 Mad 1159.

इस दफामें यह नहीं बतलाया गया है कि अदालतको इस प्रकार इस बातका विश्वास करना चाहिये कि दिवालिये द्वारा खर्च किया गया है इससे यह प्रकट होता है कि या तो अदालत मिलिक (Record) से ऐसी बातका विश्वास कर सकती है या किसी फरीदम इसका विश्वास कर सकती है प्रारम्भिक जाचमें वह दूसरोंसे भा पूछ ताड करके इस प्रकारका विश्वास कर कर सकती है । इस दफाके अनुसार कोईवाही बाह्ययुक्त अमलमें कोई जाना चाहिये अर्थात् दिवालियेकी लाहना हाइकोर्टके आधारकी पर अभियुक्त निर्धारित करना चाहिये उहाँ गवाहोंकी शहादत मानना चाहिये जिससे दिवालियेकी जिद करनेका अवसर दिया गया हो । इसीवरीकी रिपोर्टों की उसने दिवालियेके विरुद्ध दी हो दिवालियेको दफा निर्धारित करनेके लिये पर्याप्त नहीं है जो उस रिपोर्टके आधार पर तहकीकातके बहाल (Discharge) होने में तथा तत्समीपा आदि होने में अमर पक सकता है, देखो—46 All 864, A. I. R. 1926 All. 29, 37 All 429. यदि खर्च भी ठाक उसी दफाकी भावमें लगाया जाना चाहिये जिसमें इस जुमका उल्लेख है और उसमें दिवालियेके बस कामका निक होना चाहिये, जिसके अगर पर वह खर्च लगाया जा रहा हो देखो—A. I. R. 1927 All 852

अदालत दिवालियाका अधिवार है कि वह दफा ७० के अनुसार प्रारम्भिक जाच करे या न करे और अगर वह जाच करना निश्चित करे तो वह ऐसा जाच कर सकती है जिसमें उसे निश्चिन्त हो जावे कि दफा ६९ का कोई अपवाद किया गया है । मजिस्ट्रेट दफा ७० के अनुसार अदालत एवतका भी हुक्म दे सकता है तथा दिवालियेकी नामाचरणियों भी इस दफाके अनुसार हुक्म दिया जा सकता है जब कि जिस कर्त्तव्याहने शिकायतोंकी दखलान दी हो और जजन दानो फराकोक बगिचोंकी काम सुनन तथा रिश्वतका रिपोर्ट देखोके पश्चात् दिवालिया पर मामला चलाये जाना हुक्म दे दिया हो तो ऐसी दशामें यह तय हुआ कि जजने जिस तरीकसे काम किया है वह जातान्व उचित तरीका है, देखो—55. Cal 783, A. I. R. 1928 Cal 211.

दफा ७१ बहाल होने या तस्फीया होजानेके बाद फौजदारी मामलोंकी ज़िम्मेदारी

अगर दिवालिया दफा ६६ में बतलाये हुए जुर्मोंका मुजरिम है तो उसके खिलाफ ऐसे जुर्मोंकी कार्रवाई की जायेगी चाहे वह बहाल हो चुका हो या तस्फीया हो गया हो या स्कीम मानली गई हो या मंजूर हो गई हो ।

व्याख्या—

इस दफामें यह बतलाया गया है कि दिवालियाके बहाल हो जाने पर या उसके मामलेश तस्फीया आदि हो जाने पर भी दफा ६६ में बतलाये हुए जुर्मोंकी तदर्थकार्रवाई नामकती है । अर्थात् यदि दिवालियेने कोई छप दफा ६६ के अनुसार किये हैं तो वह उनमें रिहा हलतमें नच नहीं सकता है चाहे वह बहाल ही क्यों न हो गया हो या उसका मामला आपसमें तय हो कर समाप्त हो क्यों न हो जावे ।

दफा ७२ बिला बहाल किया हुआ दिवालिया अगर कर्ज लेवे

(१) अगर कोई बिला बहाल किया हुआ दिवालिया किसी शख्ससे बिला बतलाये हुए कि वह दिवालिया है पचास रुपये या उससे अधिक कर्ज लेवे तो उसके खिलाफ यह जुर्म साबित होने पर उसे मजिस्ट्रेट छः महीने तदकी सज़ा या जुर्मानकी सज़ा या दोनों सज़ायें दे सकेगा ।

(२) जब कि अदालतको विश्वास हो जाये कि किसी बिला बहाल हुए दिवालियेने उपदफा (१) में दिया हुआ जुर्म किया है तो वह शुनासिन इस्तदाल तदकीकार्रवाई करनेके बाद मामले को फैसलेके लिये सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट दफा अव्वलके पास भेज सकती है और मुलाजिम को भी हिरासतमें भेज सकती है या उससे उस मजिस्ट्रेटके सामने हाज़िर होनेके लिये फाफ़ी जमानत ले सकती है और किसी दूसरे शख्सको भी उस मुकदमेमें हाज़िर होने या ध्यान देनेके लिये बाध्य कर सकती है ।

व्याख्या—

(१) इस दफामें यह बतलाया गया है कि बिना बहाल किया हुआ दिवालिया किसी व्यक्तिने (५०) पचास रुपये या उससे अधिक उधार नहीं ले सकता है अब तक कि उधार देने वाले व्यक्तिने वह यह प्रष्ट न कर देने कि वह दिवालिया है तथा बहाल नहीं हुआ है । एक प्रकरणमें यह दफा उन लोगोंकी रक्षाके लिये बनाई गई है जिनकी दिवालियेके दिवालिया करार दिये जाने अथवा उसके बहाल होने आदि का इन्ग नहीं हुआ हो अर्थात् जिनमें दिवालिया ऐसे व्यक्तियोंको धोरा देकर उत्ते रूपया वसूल नहीं कर सके । इस दफाके अनुसार जुर्म साबित होनेके लिये केवल इतना ही साबित होना आवश्यक है कि दिवालियेने बिना अपनी हालत बताये हुए (५०) पचास रुपये या उससे अधिक कर्ज किसीसे लिया है इस बातके साबित होनेकी आवश्यकता नहीं है कि दिवालियेकी मशत पोछादेनेकी थी या इस बातके साबित होनेसे वह बच नहीं सकता है कि उसे बहुत जरूरत थी इस बातमें उम्मेद इस प्रष्ट किया था । यह बात भी इस दफामें प्रष्ट होती है कि यह पचास रुपयेका कर्ज किसी एकही व्यक्तिसे लिया गया हो अर्थात् यदि दिवालियेने थोडा थोडा रूपया कई व्यक्तियोंसे लिया हो और वह सब मित्र कर (५०) पचास रुपयेमें उभर होने होवे तो यह बात इस दफाके अंतर्गत नही आवी है । इस दफाके

अनुसार जर्म साबित होने पर दिवालियेको ६ मास तकका कायवामका दण्ड दिया जासकता है या उस पर केवल जर्मानादा किया जासकता है अथवा कायवास व जर्माना दोनों सजायें साथ साथ भी दी जासकती है ।

(२) में यह नतलाया गया है कि अदालत दिवालिया प्रारम्भिक पाच करनेके बाद विश्वास होने पर कि दिवालियेने दरअसल जर्म किया है उसे फोजदारी सुपुर्द कर सजनी है । अदालत इस दफाके अनुसार कार्रवाई करने के लिये बाध्य नहीं है किन्तु उसका करना न करना उसकी इच्छा पर निर्भर है और बिला उसके लिखे हुए इस दफाके अनुसार मामला चालू नहीं हो सकता है । ऐसे मामला सुनवाईका अधिकार अदालत दर्जेके मजिस्ट्रेट ही को प्राप्त है अर्थात् दर्जा दीयम व दर्जा सायमके मजिस्ट्रेट नहीं कर सकते है । जब कोई मामला किसी मजिस्ट्रेटके सुपुर्द इस दफाके अनुसार किया जावे तो वह मजिस्ट्रेट मामलेकी तदबीकात करने के लिये बाध्य है और अधिक तर यह मामले सबसे समीप वाले फर्टे जज मजिस्ट्रेटके पास भेज जाना चाहिये । इस दफाके अनुसार कार्रवाई उस समय तक न की जावेगी जब तक कि मामला अदालत द्वारा न भेजा गया हो । किसी प्रारम्भिक व्याक्ति के कहने पर इस दफाके अनुसार अभियुक्त दोषी नहीं ठहराया जासकता है, देखो—53 Cal. 929, A. I. R. 1927 Cal 149. अदालत इस दफाके अनुसार मामला मजिस्ट्रेट के पास भेजते समय दिवालियेकी हिसासतमें भेज सकती है या उससे उसकी इज्जतके लिये पर्याप्त जमानत ले सकती है अदालतरी यह भा अधिकार है कि वह दूसरे व्यक्तियोंको भी जिनके बयान होनेकी आवश्यकता हो मजिस्ट्रेटके सामने हाजिर होनेके लिये बाध्य करे जिसमें वह लोग बड़ा अपन नयान दे सकें । किसी फर्मने दिवालिया कलर दिये जानेकी दरखास्त दा तथा उसमें सन हिस्तेदारोंके नाम दिखला दिये गये । इस दरखास्त पर दिवालिया कलर दिये जानेका हुक्म हो गया । इसके बाद इस फर्मका एक अधीनदार दिवालिया कलर दिया गया । उस अधीनदारेके विरुद्ध दफा ७२ के अनुसार दरखास्त दी गई ता यह तय हुआ :—

(१) यह कि अदालतरी यह प्रश्न तय करेगा ये —

(ए) आया फाकिसानी बिला बहाल किया हुआ दिवालिया था ?

(बी) आया उसने ५०) या उससे अधिकका कर्ज लिया था ?

(सी) कि आया उसने दरअसल कर्ज ठेते समय कर्जदारहते यह प्रष्ट कर दिया था कि वह बिला बहाल किया हुआ दिवालिया है ?

(२) यह कि पहिले वाली दिवालियेकी कार्रवाईमें फर्मका तरफने दरखास्त था न कि किसी खास व्यक्तिकी तरफसे और इस कारण उस फर्मका हर एक मन्बर या हिस्सेदार दिवालिया कलर दिया गया था ।

(३) यह कि जब फर्मके किसी एक हिस्सेदारके विरुद्ध मामला चलाये जाना हुआ दिया गया हो तो इस बातका कोई असर नहीं पडगा कि आया वह फर्म उस हिस्सेदारने बेदसियत फर्मके हिस्सेदारका लया ह ।

(४) यदि कोई माल अमानतन इस बातके लिपिलिया गया हो कि उसे बच कर रुपया अदा कर दिया जावेगा तो ऐसे मालका लिया जाना भी इस दफाके अनुसार कर्ज लिया जाना समझा जावेगा, देखो—A. I. R. 1928 Sindh, 114, 107 I C. 442.

दफा ७३ दिवालियेकी असुविधायें (रुकावटें)

(१) जबकि कोई कर्जदार इस एक्टके अनुसार दिवालिया कलर दिया जावे या बुचाया दिवालिया कलर दिया जावे तो यह इस दफाके नियमोंका ध्यान रखते हुए नीचे दिये हुए कार्योंके लिये अयोग्य समझा जावेगा :—

- (ए) मजिस्ट्रेट नियुक्त किये जानें या मजिस्ट्रेटीका काम करनेके लिये
 (बी) जबकि किसी जगहके शिष्ट चुनाव द्वारा नियुक्ति होती हो तो उस जगहको चुने जानेके लिये या कि नी ऐसी जगह पर नियुक्त होनेके लिये या वहा पर काम करनेके लिये जिसमें कोई तनख्वाह नहीं मिलती है
 (सी) किसी लोकल पद (Local Authority) का मॅम्बर चुने जान या उसमें वोटर होनेके लिये ।

(२) इस दफाके अनुसार दिवालियोंको जो रुकावटें हैं वह हटा दी जावेंगी या जाती रहेंगी अगर :—

- (ए) दफा ३५ के अनुसार दिवालिया करार दिये जाने वाला हुक्म मंसूख होजाय, या
 (बी) उसे अदालतसे मुस्तकिल या फायममुकामी बखालीका हुक्म इस सर्टीफिकेटके साथ मिल जाय कि वह अभिम्यवश दिवालिया होगया था इसमें उसकी कोई बचनमानी नहीं थी ।

(३) अदालतको अधिकार है कि जैसा वह मुनासिब समझे ऐसे सर्टीफिकेटको दे सकती है या उसके देनसे इनकार कर सकती है लेकिन इनकार करने वाल हुक्मनी अपीलकी जा सकती है ।

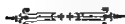
व्याख्या—

उपदफा (१) के क्राज (ए), (बी) व (सी) में दिवालियोंकी अयाथता वर्णन है क्राज (ए) क अनुसार वह मजिस्ट्रेट नियुक्त नहीं किया जासकता है और न वह मजिस्ट्रेटका कोई कामही कर सक्ता है क्राज (बी) के अनुसार वह किसी ज्वैतमिक जगह पर काम करनक्त लिय नहीं चुना जासकता है तथा क्राज (सी) क अनुसार वह किसी स्थानक पद का मॅम्बर नहा चुना जासकता है ।

इन दफाम जिन अयोग्यताओंका उल्लव किया गया है कबल वही अयाथता नहा है इनके जतिरित दिवालिया और भी बहुतसे कार्य नहीं कर सकता है इनका उल्लव दूसर कानूनोंमें किया गया है जस कि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट क अनुसार बिला बहाल हुआ । दवाालिया काउन्सिलका मॅम्बर नहीं चुना सकता है । गान्धेय एण्ड वार्ड एक्ट क अनुसार वह नानालिखती आपदादक बला हानसे इयाजा जासकता है या किसी टांके गरी हानसे अगहदा किया जासकता है इ यदि ।

उपदफा (२) म बतलाया गया है कि उपदफा (१) का अयाथता दूर भा हा सक्ता है जब कि दिवालिया करार दिये जाने वाल हुक्म दफा ३५ क अनुसार मसूख कर दिया जाए अथवा दिवाळिया बहाल (Discharge) कर दिया जावे । बहाल हानेके लिये यह भी बतलाया गया है कि चाहे दिवाळिया पूरा रूपम बहाल कर दिया जाव अथवा बड किसी शर्तक साथ बहाल किया गया हो जब कि इस प्रस्ताव सार्तीफिकेट द दिया गया हो कि वह दिवाळिया अभिम्य वश हो गया था और उसक बचनमानाकी बजहसे ऐसा नहीं हुआ था । यदि दफा २ में ननगया हुआ सार्तीफिकेट दमसे अदाउन इन्वार कर देवे ता उसका अयाथती जासकती है ।

पांचवां प्रकरण



सरसरीकी कार्रवाई

दफा ७४ सरसरीकी कार्रवाई

जबकि दिवालेकी दरखास्त किसी कर्जदारने दी हो या उसके खिलाफ दी गई हो और अदालतको हलफनामासे या दूसरे किसी तरहसे यह इतमीनान हो जाये कि कर्जदारकी आयदाद ५०० रुपयेसे अधिक मूल्यकी नहीं है तो अदालतको अधिकार है कि वह इस प्रकारका हुक्म देदेवे कि कर्जदारकी आयदादका इन्तजाम सरसरी तौरसे किया जावे और तब इन एक्टमें दी हुई कार्रवाई नीचे दिये हुए संशोधनके साथ की जावेगी:—

- (i) प्राप्तिक सरकारी गजट द्वारा नोटिसकी मुश्तहरी नहीं की जावेगी जैसा कि एक्टमें दिया हुआ है जब तक कि अदालत इसके विरुद्ध कोई आज्ञा न देवे
- (ii) कर्जदारद्वारा दी हुई दिवालेकी दरखास्तके लेलिये जाने पर उसकी आयदाद अदालतकी सुपुर्दगीमें बहेसियत रिनीवरके समझी जावेगी
- (iii) दरखास्तकी समाप्त करते समय अदालत कर्जदारको कर्जे व लहनेको दरयाफ्त करेगी और निश्चित करके अपने हुक्ममें लिखेगी और दफा ३३ में दिये हुए नियमोंके अनुसार सूचीका तैयार करना जरूरी नहीं होगा
- (iv) कर्जदारकी आयदाद जितनी उचित जल्दी हो सकेगी घसूल की जावेगी और उसके बाद जब मुमकिन हो एकही डिघीडेएडमें बांट दी जावेगी
- (v) दिवालिया क़ारार दिये जानेके हुक्मसे छः माहके अन्दर दिवालिया महाल होनेकी दरखास्त देवेगा, और
- (vi) जो कुछ संशोधन, खर्च कम करने तथा कार्रवाईको साधारण घनानेके लिये बनाये जावे उनका अमल किया जायेगा ।

परन्तु अदालतको अधिकार है कि यह किसी समय भी कर्जदारकी आयदादके सम्बन्धमें इस एक्टमें दिये हुए साधारण नियमोंके बर्तनेका हुक्म दे सकती है और तब उसके बाद इस एक्टका नियम पूर्वक प्रयोग होगा ।

व्याख्या—

यह दफा इस कारण बनाई गई है जिसमें छोटे मोटे मामलोंमें बहुत समय नष्ट न किया जावे तथा ऐसे मामलोंमें अधिक खर्च भी न हो सके और ऐसे मामले जल्दी समाप्त किये जा सकें दिवालियेकी दरखास्त चाहे कर्जदारने स्वयं दी हो या वह दरखास्त उसके विरुद्ध किसी कर्जदारद्वारा दी गई हो दोनों दशाओंमें यह दफा लागू हो सकती है यदि और शर्तें पूरी होती होंगी ।

इस दफाके अनुसार कार्यवाई उसी दशमिकी जायेगी जबकि दिवालियेकी जायदाद ५०० पावसी रुपयेमें अधिक मूल्य की न होवे इस मूल्य का योजन अदालत हलकन्यायाके दाखिल होने पर या अन्य श्रावतके डेन पर कर सकती है इस दफाके अनुसार कार्यवाई करनेके लिये अदालत बाध्य नहीं है किन्तु उसका करना या न करना उसकी इच्छा पर निर्भर है ।

अर्थात् यदि दिवालियेकी जायदाद ५०० पावसी रुपयेसे कम मात्रा की होवे तो भी अदालतकी अधिकार है कि वह इस एक्टमें बतलाये हुए मामूली नियमोंके अनुसार कार्यवाई कर सकती है और ससरीकी कार्यवाई अपवादमें न लावे ।

इस दफाके अनुसार कार्यवाईकी जानकारी अदालतको जावनेके अनुसार हुक्म देना चाहिये कि कर्त्तव्यकारी जानदादा या नाम सरसरी तौरसे किया जावेगा ।

यदि सरसरी तौरसे कार्यवाई करकेका हुक्म हो जावे तो क्लॉज (i), (ii), (iii), (iv), (v) व (vi) में बतलाये हुए नियम लागू होंगे ।

क्लॉज (i) के अनुसार प्रान्तिक सरकारों या मजदद द्वारा बोकायाको जानेकी आवश्यकता नहीं रहेगी बरन् कि जदाउत इसके विरुद्ध कोई हुक्म न दे देवे ।

क्लॉज (ii) के अनुसार दिवालियेकी जायदाद उसी प्रकार अदालतकी सुपुर्दामें आनवेगी जैसे कि गिनीवरकी सुपुर्दामें आना चाहिये ।

क्लॉज (iii) में बतलाया गया है कि कर्त्तव्यकारीकी सूची आदि तैयार किये जानेकी आवश्यकता नहीं है किन्तु अदालत स्वयंही दिवालियेके लहजे व कर्त्तव्यकारी निश्चित करेगी और उनके बारेमें निर्णयन होने जान समयही दरपान्न कर लेगा ।

क्लॉज (iv) के अनुसार दिवालियेके कर्त्ते जिनकी अच्छी हो सके श्रावत करके बाट दिय जाना चाहिये ।

क्लॉज (v) में यह बतलाया गया है कि दिवालियेका बहाल होनेकी दरपान्न व माहके अन्दर द देना चाहिये ।

क्लॉज (vi) में बतलाया गया है कि यदि कोई जोर नियम का सम्बन्धमें बनावे गए हो जिनमें खर्चमें कमी या कार्यवाई की और साधारण बनावे जासके तो ऐसे नियमोंका भी पालन किया जाना चाहिये । यह सब होने हुए भी अदालतकी अधिकार प्राप्त है कि वह आवश्यकतानुसार किसी समय भी इस एक्टके मादुली नियमोंके अनुसार कार्यवाई किये जानेका हुक्म दे सकती है अर्थात् यदि सरसरीका हुक्म देनेके पश्चात् अदालतको माहूम होवे कि दिवालियेकी जायदादना मूल्य ५०० रुपयेसे अधिक है या दिवालियेकी जायदादना प्रबंध अपवाद वसूलोंकेला समीकर द्वारा आवश्यक है तो वह एम्प दशाये गिनीवर नियुक्त कर सकती है तथा सरसरीके हुक्मसे। मसूय कर मामूली नियमोंके अनुसार कार्यवाई किये जानेका हुक्म दे सकती है ।

छठा प्रकरण

अपील

दफा ७५ अपीलें

(१) अदालत जिलाके मातहत किसी अदालतके किये हुए फैसले या हुक्मके विरुद्ध जो उसने दिएला सम्बन्धी अधिकारको धरते हुए दिया हो, अपील अदालत जिलामें की जा सकती है और उस अपील पर जो हुक्म अदालत जिलाका होगा वह अन्तिम हुक्म होगा और ऐसी अपील दिवालिया, कर्जनाह, रिसीवर या और कोई शब्द जिसको कि फैसले या हुक्मसे मुक्तसाल पहुँचता हो कर सकता है। लेकिन हाईकोर्टको अधिकार है कि वह यह जानने के लिये कि अदालत जिलाने अपीलमें जो हुक्म दिया है वह कानूनन ठीक है मुकद्दमोंको मँग सकता है तथा उसे जो मुनासिब मालूम हो वह हुक्म उसकी बाबत दे सकता है। और अगर कोई शब्द अदालत जिला द्वारा किये हुए अपीलके फैसलेसे संतुष्ट न हो जो उसने अपने मातहत अदालतके फैसले या हुक्मके बाबत दिया हो तो उसे अधिकार है कि वह दफा ४ के अनुसार जायता दीवानीकी दफा १०० (१) में दी हुई बातोंकी बिना पर हाईकोर्टमें अपील कर सकता है।

(२) अगर अदालत जिलाके उन फैसलों व हुक्मोंकी अपील जो पहिली सूची (Schedule I) में दिये हुए हैं और जिसे उसने अपने मातहत अदालतकी अपीलमें नहीं दिया है हाईकोर्टमें की जा सकती है।

(३) पहिली सूचीके अतिरिक्त जो फैसले या हुक्म अदालत जिलाने किये हों लेकिन जो मातहत अदालतकी अपीलमें न किये हों उनकी अपील अदालत जिला या हाईकोर्ट की आज्ञा लेकर हाईकोर्टमें की जा सकती है।

(४) अदालत जिलामें अपील तीस दिनके अन्दर व हाईकोर्टकी अपील ६० दिनके अन्दर की जा सकेंगी।

टिप्पणी—

इस दफा में अपीलें बणव है। शिड्यूल (Schedule I) में वह फैसले व हुक्म दिये गये हैं जिनकी अपील हाईकोर्टमें की जा सकती है। इस दफा में यह नहीं बड़ी दिखलगा गया है कि अदालत जिलाके यहां किन किन हुक्मों या फैसलों अपील की जा सकती है। परन्तु यह प्रष्ट होता है कि मातहत अदालतके सभी फैसलों व हुक्मोंकी अपील अदालत जिलाके यहां की जा सकती है जब तक कि इसके विरुद्ध कोई बात इस एक्टमें न दा गई हो।

उपदफा (१) इस उपदफाके अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसे अदालतके फैसले या हुक्मके विरुद्ध अपील हो अपील करने का अधिकार है अर्थात् दिवालिया, रिसीवर, कर्जनाह या अन्य कोई भी व्यक्ति जिसे हानि पहुँचती हो अपील कर सकता है। इस बात पर ध्यान रहना चाहिये कि कोई भी व्यक्ति अपील करने के लिये बाध्य नहीं है किंतु करना करना न करना उसका इच्छा पर निर्भर है। इस उपदफा में यह भी बतलाया गया है कि इस उपदफाके अनुसार भी

हुई जरीलगा जो केसला होगा उसे अतिम कसला समझना चाहिये परंतु साथ साथ यह शर्त लगादी गई है कि यदि हाईकोर्ट चाहे तो अपन सुतोंके लिये सुत्र हमेशा अपने देखनेके लिये गया सकता है तथा उस पर अपना मुनासिब हुकम दे सकता है और इसा प्रकार दफा ४ के अनुसार कर्जनेवा भी जाबना दीवानीकी दफा १०० (१) के अनुसार अदालत जिलेके फैमलर विरुद्ध हाईकोर्टमें अपील करनेका अधिकार है। इस उपदफामें हानि पहुँचनेसे अभिप्राय कानूनी हानिसे है अर्थात् यदि किसी व्यक्ति का अदालत दिवालियाके किसी फैमले या हुकमसे किसी वस्तुमें अधिकार जाता रहे या उससे उसके किसी हुकम आघात पहुँचना हो तो ऐसे व्यक्ति के लिये यह माना जायगा कि उसे उस हुकम या फसलेसे हानि पहुँची है, देखो—46 Mad 403 यदि अदालतके किसी हुकम या फैमलेमें किसी व्यक्तिको केवल यही असंतोष होवे कि उस हुकम या फसले में होनेसे उसे कुछ भविष्यमें लाभ पहुँचोगी सम्भरना थी तो ऐसे हुकम या फैमलेसे उस व्यक्तिकी कोई कानूनी हानि नहीं समझना चाहिये, देखो—41 I C 96.

दिवालिया कानून दिये जानेका हुकम हानिकर फलस्व दिवालियाका कोई एक आयदाद पर नहीं रह जाता है और इसीलिये उसका वसूल्य बाँके मिलसिलेमें यदि कोई हुकम दिया जावे तो उस हुकमसे दिवालियाको कोई हानि नहीं पहुँच सकती है। स प्रश्न यदि उसकी आयदादके किसी हिस्सेमें बैंक जानेकी मजूरी दी जावे तो इस मजूरीके विरुद्ध उसे अपील करनेका अधिकार नहीं है, देखा—49 Mad 461.

यदि अदालत किसी ऐसे कर्जो मजूर कर लवे ना कि साबित नहीं किया जासकता है तो ऐसे मामलेमें दिवालिया की हानि शून्य है और इसके विरुद्ध वह अपील कर सकता है, देखो—47 Mad. 120 यदि कोई कर्जदार दिवालिया करार देकर जान बाल हुकमसे मसूचीकी दख्खानत दफा ४ के अनुसार देवे और वह दख्खानत वापस करी जावे तो ऐसे हुकमके विरुद्ध उस अपील करनेका अधिकार होगा, देखा—A I R 1924 Mad 685

यदि कोई संज्ञात आयदाद दफा ५३ के अनुसार मसूद कर दिया जावे तो वह व्यक्ति जिसके हुकमें वह इतनाल किया गया था इस फैमलेके विरुद्ध अपील कर सकता है क्योंकि ऐसे हुकममें उसे हानि पहुँची है, देखो—7 I C 765. यदि आधिकार एसाबरीकी किसी हुकमसे हानि पहुँचती हो तो वह भी अपील कर सकता है, देखो—33 Mad 134 शाहबाज हाईकोर्टने एक मामलेमें यह तय किया था कि यदि दिवालियाकी आयदादके लिये किसीवर नियुक्त किया जानुश हो और कोई व्यक्ति उसकी किसी आयदादके लिये उसमें विरुद्ध दावा करे तो उसके कर्जनेवाओंमें से किसी एक कर्जनेवाइको ऐसे मामलेमें अपील करनेका एक प्रास नहीं है क्योंकि उसका हान उठाने वाला व्यक्ति (Aggrieved person) नहीं वह सबसे है देखा—39 All. 152

हाला हाईकोर्टने भा ऐसीही बात तय की थी देखो—62 I. C. 924 (Lah) परंतु मद्रास हाईकोर्ट इस तय से सहमत नहीं हैं उनमें तय किया था कि यदि किसी हुकमसे किसी व्यक्ति पर कोई धनदा आती हो और उसके हिस्सेमें आधाव पहुँचता हो तो वह हानि उठाने वाला (Aggrieved) व्यक्ति समझा जायेगा चाहे वह उसमें फ्रीक मुकदमा हो या न हो, देखो—49 Mad 794 यदि कोई कर्जो साबित कर चुकने वाला कर्जनेवाइ दिवालिया करार दिये जाने वाले हुकमसे मसूदा होने पर उस हुकमकी नजरानगी (Review) करे और वह नजरानगीकी दख्खानत खारिज हो जावे तो उसे हानि उठाने वाला व्यक्ति समझना चाहिये, देखा—A I R 1927 Mad 175 हाईकोर्टने यह किसी कर्जनेवाइकी दख्खानत जो दफा ५३ व ५४ के आधार पर दा गई हो खारिज हो जावे तो उसे अपील करनेका अधिकार प्राप्त है क्योंकि वह हानि उठाने वाला (Aggrieved) व्यक्ति हो जाता है, देखो—47 Mad 673, 44 All 71.

यदि किसी कर्जनेवाइकी दख्खानत पर दिवालिया करार दिये जानेका हुकम दिया गया हो और वह मसूद कर दिया जायता उस कर्जनेवाइकी हानि उठाने वाला (Aggrieved) व्यक्ति समझना चाहिये और वह उसमें अपील कर

सत्य है, देखो—A. I. R. 1926 Lah. 24. किमी दिवालियेकी जायदाद बेतर्जनीते बेची गई व उमने उसके विरुद्ध दरखास्त दी परन्तु वह दरखास्त नामजूर की गई तब अपने अपील की परन्तु अपीलमें यह तथ हुआ कि वह कानूनी रूपसे हानि उठाने वाला व्यक्ति नहीं है अतः उसे अपीलका अधिकार नहीं है, देखो—41. All. 243 इसी प्रकार यदि अदालत दिवालियेके विरुद्ध की हुई शिनायतकी खारिज कर देवे तो उस फर्जीवाहका जिसने इस शिनायतको दफा ६९ के आधार पर किया या हानि उठाने वाला (Aggrieved) व्यक्ति नहीं समझना और न वह अपील कर सकता है, देखो—39 All. 171, 40 Mad 680, A. I. R. 1924 Mad. 180.

इसी प्रकार यदि रिसीवरने दफा ६९ या ७० के अनुसार दिवालियेके विरुद्ध मामला चलाये जानेमें दरखास्त दी हो और वह दरखास्त खारिज हो जावे तो रिसीवरकी हानि उठाने वाला (Aggrieved) व्यक्ति नहीं समझना चाहिये और वह अपील नहीं कर सकता है, देखो—61 I. C. 802. यदि अदालत आफिशल रिसीवरकी हटा कर इनके स्थानमें कोई स्पेशल रिसीवर नियुक्त करदे तो आफिशल रिसीवरको ऐसे हुक्मसे हानि पहुँचती है और वह इनके विरुद्ध अपील कर सकता है, देखो—40 Mad 405.

यदि रिसीवरने किसी फर्जीवाहके करने पर किसी फसलका कुर्क किया हो और वह फसल कुर्कसे बोज़ दी जावे तो इन हुक्मके विरुद्ध अपील की जा सकती है, देखो—47. All. 849. यदि किसी व्यक्ति को किसी हुक्मसे हानि पहुँचती हो तो उसे अपील करनेका अधिकार होगा चाहे वह अदालत मानहतमें फरीक घुबहमा न रहा हो, देखो—53 Cal. 866 यदि अदालत जिलाका मातहत किसी अदालतके, अदालत दिवालियाके अधिकारोंके वर्तने हुए कोई हुक्म दिया हो तो ऐसे हुक्मके विरुद्ध अपील हाईकोर्टमें नहीं होगी किन्तु उसकी अपील अदालत जिलामें होना चाहिये, देखो—63 I. C. 848. गौक मातहत अदालतको दिवालिया सम्बन्धी मामलानामें वकील अधिकार प्राप्त है जो अदालत जिलाको हानि है परन्तु अपीलके लक्ष्य में इन अदालतोंको अदालत जिलाकी मातहत अदालत ही समझना चाहिये, देखा—A. I. R. 1923 Nag. 80 अतिरिक्त (Additional) जिला जन अपीलके लिये जिला जनके आधीन नहीं है, देखो—9 A. L. J. 371, 36 All. 576.

अदालत खर्फीकाके हुक्मोंके विरुद्ध जो उसने अदालत दिवालियाके अधिकार क्षेत्रमें किये हों अपील अदालत जिलामें की जायेगी, देखो—23 All. 56, 12 Mad 472, 21 Bom 45, 27 Bom. 604. दायित्वके डिस्ट्री कमिशनर द्वारा दिये हुए हुक्मके विरुद्ध अपील अदालत जिलामें की जायेगी, देखो—15 U. L. J. 239, A. I. R. 1925 Cal. 335. आफिशल रिसीवरकी इस दफाके अनुसार अदालत जिसके मातहत असलत नहीं माना जासकता है, देखो—40 Mac 752. अमेसी एक्टकी इस दफामें इन शब्दों 'Shall be final' का प्रयोग किया गया है जिससे यह प्रकट होता है कि अदालत जिलाके फैसलेके विरुद्ध अपील दोयम (Second Appeal) नहीं की जासकती है और उसके अपीलमें किये हुए फैसलेको अन्तिम फैसला समझना चाहिये परन्तु आगे चल कर इसी दफामें यह भी बतलाया गया है कि हाईकोर्टको अधिकार है कि वह तजवीजनामी (Revision) के तौर पर अदालत जिलाके फैसलेमें हस्तक्षेप कर सके इससे यह प्रकट होता है कि अदालत जिलाका अपीलमें किया हुआ फैसला एक प्रकारसे अन्तिम फैसला है क्योंकि उसकी अपील दोयम नहीं की जासकती है परन्तु उसमें भी हाईकोर्टको हस्तक्षेप करनेका अधिकार प्राप्त है।

इस बातका भी ध्यान रहना चाहिये कि कुछ मामलोंमें अपील दोयम अपात् हाईकोर्टमें भी अपील उस फैसलेके विरुद्ध की जासकती है जैसा कि इसी प्राज्ञके अंतर्गत जो शर्त लगाई गई है उनमें बतलाया गया है। इस दफाके अनुसार हाईकोर्टको रिवीजन (Revision) के जो अधिकार प्राप्त हैं वह कर्तव्य करीब उसी तरहके हैं जैसा कि उस अदालत खर्फीका द्वारा किये हुए फैसलोंमें प्राप्त हैं। जानना दीवानीकी दफा १९ के अनुसार जो अधिकार तजवीजनामी (Revision)

के हार्डवेयरों प्राप्त है उनसे यह अधिकार किसी इद तक अधिक है क्योंकि वह अधिकार केवल अधिकार सीमा (Jurisdiction) ही के मध्यममें बँटें जासकते हैं परन्तु इस दफाके अनुसार हार्डवेयरों उस वक्त हस्तक्षेप कर सकता है जब कि उसे यह मादृग पड़े कि कानूना दण्डित करिवाही नहीं की गई है ।

दफा ११५ जायसा दीवानी इस प्रकार है —“हार्डवेयरों अधिकार है कि वह अपने मातहत अदालतके तय किये हुए किसी मुकदमेकी मिसिलकी मगबाले जब कि उस फैसलेके विरुद्ध अपील न की जासकती हो और यदि ऐसा मादृग हो कि उस मातहत अदालतने (ए) उन अधिकारोंका प्रयोग किया है जो उसे कानून प्राप्त नहीं है या (बी) उसने उन अधिकारोंका प्रयोग नहीं किया है जो उसे कानून प्राप्त हैं या (सी) उसने अपने अधिकारोंको और कानूनी तरीके या बर्बा बेतरीबसे प्रयोग किया है । और हार्डवेयरों अधिकार है कि वह जो हुक्म सुनासिब समझे ऐसे मामलोंमें दे सक्ता है ।”

इस दफाके अनुसार तनवीजसानी (Revision) के भी अधिकार हार्डवेयरोंकी प्राप्त हैं उनका प्रयोग करना न करना हार्डवेयरों इच्छा पर निर्भर है वह उनको प्रयोग करनेके लिये वाप्य नहीं है जैसा कि अमेरिका एक्टरी इन दफात प्रयोग किये हुए ‘May’ शब्दसे प्रकट होता है । यदि अदालत सिलाने आलम्में यह हुक्म दिया हो कि मनीद शाश्वत ही जाना चाहिये तो ऐसे हुक्मकी तनवीजसानी हार्डवेयरोंमें हो सकती है, देखो—61 I. C. 589. परन्तु यदि किसी मजबूरी अर्पीक की जासकती हो तो उसके लिये तनवीजसानी (Revision) नहीं सुनी जासकती है देखा—A. I. R. 1926 Mad. 128. यदि अदालत सिलाने अर्पीक दफा २२ या दफा ६९ के अनुसार कार्रवाई करने पर इतकर कर देने को इसका रिवीजन (Revision) नहीं किया जासकता है, देना—56 I C 744

इस हाराके अन्तमें जो शर्तें लगा दी गई हैं उसने अनुसार अपील दोषम भी की जासकती है । यदि अदालत जिलाने किसी मामलेको दफा ४ के अनुसार तय किया हो तो उसकी अपील दोषम हार्डवेयरोंकी जासकता है परन्तु ऐसे मामलोंकी अपीलें उन्हें बाँटोंके आधार पर की जासकती हैं जिनका उल्लेख दफा १०० (१) जायसा दायामीमें है ।

जायसा दीवानीकी दफा १०० (१) इस प्रकार है —“उन बाँटोंका प्यान रखने हुए जो इत एक्टमें या अन्य किसी प्रचलित एक्टमें बतलाई गई हैं नीचे दिये हुए मामलोंकी अपील हार्डवेयरोंमें उसके किसी मातहत अदालतके अन्तर्गमें किये हुए फैसलके विरुद्ध की जासकेगी । (ए) यदि फैसले किसी कानूनके विरुद्ध होवें या किसी चलन (Usage) के विरुद्ध होवें जो कानून कानूनके बरता जाता होवे (बी) यदि फैसलेमें कोई कानूनी तनवीज या कोई ऐसा चलन जो कानूनी तौर पर बरता जाता होवे तब न किया गया हो (सी) यदि इत कोडमें बतलाये हुए या अन्य किसी प्रचलित कानूनमें बतलाये हुए नियमके विरुद्ध खास गणनी हुई हो जिसकी बजहसे फैसलेमें ठीक तौरसे मसला असली बाधवातके अनुसार तय न किया जासका हो ।”

इस प्रकार अपील दोषम उही समय हो सकेगी जब कि अदालत जिलाने दफा ४ के अनुसार किसी मामलेको तय किया हो तथा उसमें दफा १०० (१) जायसा दीवानी भी अन्त होती होवे । इन प्रकार यदि दफा ५३ के अनुसार कोई हुक्म दिया गया हो तो कानूनी मामले पर उसकी अपील दोषम हो सकेगी, देखा—A. I. R. 1224 Nag- 361.

जब कि रीसीवरने किसी जायदादमें दिवालिपेकी जायदाद फुगर देकर कुर्क किया हो और उन जायदाद पर कोई तीसरा व्यक्ति अपना हक प्रकट करे तथा अदालत उमके हककी स्वीकार कर लेते तो इसके विरुद्ध दफा ७५ के अनुसार अपील की जासकती है, देखा—A. I R 1928. Lah 556.

यदि अदालतने यह हुक्म दिया हो कि कोई हकम आफिशन रीसीवरको मिलना चाहिये तथा इसके विरुद्ध किसी तीसरे व्यक्तिने अपना हक आहिर किया हो तथा अदालत उमने हककी मजूर न करे तो वह व्यक्ति इस हुक्मकी अपील कर

समता है क्योंकि यह हुक्म एक प्रमाण दे दफा ४ के अनुसार दिया हुआ हुक्म होगा यह भी तथ्य हुआ कि कर्जस्वाहान जल्दी फीक मुकदमा नहीं है, देखा—A. I. R. 1928 Loh. 423 यदि अदालत अगिल घरे मागलेगी सुननेके पश्चात् यह राय कायम करे कि अगिलघटका मामला दरअमल कानिल अपील है जिसके लिये इनाजत दी जासकती थी तो वह अपील की इनाजत दे सक्ता है, देखो—A. I. R. 1928 Pat 398.

उपदफा (२) इस उपदफाके अनुसार अदालत जिलेके फैमले या हुक्मके विरुद्ध हाईकोर्टमें अपील की जासकती है परन्तु उसके लिये शर्त यह है कि (ए) ऊन्हीं फैमला व हुक्मोंकी अगिल हां सकगी जो सूची न० १ (Schedule 1) में दिये हुए हैं व (बी) वह फसले व हुक्म उन्हीं मामलोंमें दिये गये हों जो अदालत शिन्धने स्वयं सुने हों और वह किसी मातहत अदालतकी अपीलमें उस अदालत जिला द्वारा नहीं दिये गये हों ।

उपदफा (३) उपदफा (२) में बतनाया जासता है कि अदालत जिलेके ऊन्हीं फैमलों व हुक्मोंकी अपील हो सकेगी जिनका उल्लेख सूची न० १ (Schedule 1) में दिया गया है परन्तु इस उपदफामें यह बतलाया गया है कि ऐसे हुक्मों व फैमलोंकी भी अपील की जासकती है जो कि सूची न० १ (Schedule 1) में न दिये गये हों वनों कि उनके लिये अदालतकी आज्ञा ले ली जावे । इस बातका भी ध्यान रहना चाहिये कि इस उपदफाके अनुसार भी अगिल ऊन्हीं फैमलों व हुक्मोंकी की जासकेगी जिसकी अदालत जिलेने अपने सुने हुए मामलोंमें दिसा हो व जिनको अपने अपीलके अधिकार बतते हुए न दिया हो, अपील यदि किसी मातहत अदालतके फसले या हुक्मके विरुद्ध अदालत जिलेने कोई फैमला या हुक्म दिया हो तो ऐसे फसले या हुक्मके विरुद्ध अपील हाईकोर्टमें किसी भी दफामें नहीं की जासकती । अदालत की आज्ञा साधारण तौर पर प्रदान नहीं की जावेगी यह आज्ञा उन्हीं मामलोंमें दी जासकेगी जो लचर न हों या जिनमें कोई कानूनी मामला आता हों वरना पिछली उपदफाके बतानेकी आवश्यकता ही नहीं थी । आज्ञाका देना न देना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है और यदि आज्ञा न दी जावे तो इस हुक्मके विरुद्ध अपील नहीं की जासकती है, देखो—38 I C 818. बिला आज्ञा लिये हुए इस उपदफाके अनुसार अपील नहीं की जासकती है अर्थात् इस आज्ञाके लेनेके लिये अगिल करने वाला ध्यक्ति बाध है, देखो—36 All 8. अपीलमें वही लोग फीक मुकदमा बनाये जावेंगे जिनका सम्बन्ध अपील किये जाने वाले हुक्म या फैमलेसे होगा देखो—38 Mad 74. यदि किसी कर्जस्वारी दिवालिया करार दिये जानेकी दुरवास्त राजिज कर दी जावे तो उस हुक्मकी अपीलकी सूचना उसके कर्जस्वाहारी की काफी तादादसे दी जाना चाहिये न तबमें कि वह लोग नईसित रिपण्डेण्टके अपने घसलेसे पेश कर सकें, देखो—37 I C 391. दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मके विरुद्ध जो अपीलकी जावे उसका नोटिस आफिशल एगामनीसे दिया जाना चाहिये, देखो—A. I. R. 1925 Cal. 1215 यदि दिवालियेकी रहनेके लिये मजान न दिया गया हो और वह ऐसे हुक्मकी अपील गिरीवरकी फीक मुकदमा बिठा बनाये हुए करे तो वह कानिल चलेनेके नहीं है, देखो—57 I C 971 (Lah) यदि कर्जस्वाह दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मके विरुद्ध अपील करे तो उसमें दिवालियेका फीक मुकदमा बनाया जाना जरूरी है, देखो—A. I. R. 1924 Bom. 472. यदि अदालत जिलेने दिवालियेकी बरतनेके सम्बन्धमें विधि हुए किसी बयानमेंकी मज्दुरी देदी हो व उसके विरुद्ध अपीलकी जावे तो उसमें खरीदार नजाम व रिडीवरकी फीक मुकदमा बताना जरूरी है, देखो—A. I. R. 1923 Lab 58, 68 I C 716 यदि कोई एक कर्जस्वाह अपील करे तो यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे कर्जस्वाह या फीक मुकदमा बनाये जावें, देखो—58 I C 10. यदि सूचीमें दर्ज कोई कर्जस्वाह मर गया हो और उसके वारिधियों नोटिस न दिया जावे तो केवल इतनी बातने अपील रद्द नहीं हो जावेगी, देखो—A. I. R. 1926 Cal. 1210.

यदि गिरीवर फीक मुकदमा न बनाया गया हो व अगिलमें कोई हुक्म दे दिया जावे तो केवल उसके फीक मुकदमा

न बनाए जानेही से वह हुक्म रद्द नहीं हो जावेगा जब तक कि यह साबित न हो कि उसके द्वारा उसके द्वारा प्रकटमा न होना है यह विशेष हानि उसे पहुँचना है, देखो—**1 I R 1922 Mad 437**

जब कि इन दफाके अनुसार अपीलकी गई हो तो साबित होना चाहिए कि दफा ४१ में बतलाये हुए इन नियमानुसार प्रमाण लिया जासकता है यदि वह इस प्रकारके किसी नियमक विरुद्ध न पड़ता हो **41 Mad 904** इसमें दिया हुआ है कि किसी अपालके दाखिल हानके बाद आर्डर ४१ रूल २२ के अनुसार क्रास अपाल दाखिलता जासकती है अपालन अपील साबित हो जानेकी आर्डर ४१ रूल २० के अनुसार सर्वेके लिये अपीलान्ते बयानपत्र माग ससकता है, देखा—**43 Cal 243.**

यदि कर्मचारीने किसी दिवालियेके विरुद्ध करिवाई करना दारखास्त दी हो और वह दारखास्त बिना तहकीकातेके या बिना रिसॉरका रपार्त दखल बिना वाई कारण बतलाये हुए खारिज कर दी गई हो तो इसका अपील हो सक्ता है, देखा—**79 I C 340**

यदि अदालतने बिना किसी तामर शर्तके त्रिप हुए एतग-तम फसल किये हुए किसी आशपादक बच दिये जानका हुक्म न दिया हो तो इस विरुद्ध अपालन जासकता है, देखा—**52 Cal 662**

यदि कोई ऐसा कर्ज जो साबित न किया जासकता हो साबित मान कर मजूर कर दिया गया हो तो उसका अपालन जासकता है, देखा—**47 Mad 120**

यदि किसी केसलका नजाराताना (Review) मजूर कर ली गई हो तो उसका अपील दफा ७५ (२) के अनुसार हॉरिबोर्टमें हो सकनी है पालु ऐसी अपाल जाचना दीवानके आर्डर ४७ के अनुसारही होना चाहिये, देखा—**44 All 605.** यदि दफा ७७ के अनुसार हुक्म दिया गया हो तो इस हुक्मकी अपील हो सकती है, देखा—**100 I C 137 (Lab).** यदि दफा ७७ (२) के अनुसार समय बढानके लिये दारखास्त दा गई हो और वह दारखास्त खारिज हो जाने तो इसकी अपील नहीं की जासकती है, देखा—**89 I C 959** यदि अदालत बिना दफा २२ व २९ के अनुसार करिवाई करिसे इकार कर देता है इसके विरुद्ध अपाल नहीं जा जासकता है, देखा—**56 I C 744, 61 I C 802, 40 Mad 680, 85 I C 717.**

यदि दफा ४१ के अनुसार दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म मसूख कर दिया जावे तो अपालनकी इस अहोके विरुद्ध अपाल नहीं जा जासकती है, देखो—**100 I C. 137**

बली प्रसारदफा ५४ (१) के अनुसार दिए हुए हुक्मके लिये भी आलायेकर अपीलकी जासकती है, देखा—**46 I C 377** यदि रितावरका नियुक्त करेना हुक्म न दिया जावे तो इससे विरुद्ध भी बिना आशके अपील नहीं की जासकती है देखो—**A I R 1924 Cal 849.** यदि किसी हुक्मकी अपाल अदालत तिलामें न होता होवे परतु अदालत तिलान अपील सुन कर अपना फैसला दे देवे तो हॉरिबोर्टमें अपिहार है कि वह अपालन सिवाके किये हुए फसलेको रद्द कर देवे, देखो—**42 I C 287**

यदि किसी मृतक कर्मचारीके वारिसेको मोहित न दिया गया हो तो इसकी बजइसे फेमला रद्द नहीं हो जावेगा परतु उन कर्मिसेको यदि इनका नाम मिसिलमें नहीं आया हो उस कर्मचारीको इनाम चाहू करनका अपिहार प्राप्त है, देखो—**A I R. 1926 Cal 1210.**

इस एक्टमें कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि अपील बिना काउंसिलमें की जासकनी है या नहीं इसमें यह प्रकट होता है कि यदि प्रती काउंसिलमें अपील करनेका अपिहार प्राप्त हो तो उसके लिये इस एक्टके कारण कोई बफाउर नहीं पड़ेगी, देखो—**27 Bom 415**

यदि दफा २५ के अनुसार दिवाले की दरखास्त नामजूर कर दी गई हो और अपनी अपील भी इतिहास द्वारा आईर ४१ रुद्र ११ के अनुसार सांगित कर दी गई हो तो प्रती काउन्सिलमें अपील होना उचित है, देखो—40 Cal 685.

उपदफा (४) में अपील की मियादें बतलाई हैं । अदालत जिलामें ३० दिनों के अन्दर तथा हाईकोर्टमें ९० दिनों के अन्दर अपील दाखिल की जाना चाहिये यही मियाद दीवानों की अपीलोंके लिये भी रखी गई है । यदि अदालत द्वारा नियुक्त किये हुए रितीबरेने किसी घर शस्त्र की जायदादकी ड्रॉ कर लिया हो तथा उसका कुछ हिस्सा नीलाम कर दिया हो और जायदादके माउकानने अदालत लिटाके पड़ा हो, कहीं व नीलामके विरुद्ध दरखास्त दी हो परन्तु वह दरखास्त मियादके बाद होनेके कारण नामजूर कर दी जावे तो यह तथ्य हुआ कि डिस्ट्रिक्ट जजके इस फैसलेके विरुद्ध अपील की जासकती है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जजके इस फैसलेसे अपीलान्तरही इनि पहुँचती है, देखो—A. I. R. 1928 Cal 263 (2), 107 I. C. 467.

सातवां प्रकरण

विविध (मुतफर्रिक)

दफा ७६ खर्चा

इस एक्टके अनुसार बनाये हुए नियमोंका ध्यान रखते हुए इस एक्टके अनुसार की हुई कार्रवाईका खर्च तथा फर्जदारको दीवानो जेलमें रखनेका खर्च उस अदालतकी सचिवत पर होगा जिसके सामने मामला पेश हो ।

व्याख्या—

इस दफामें दिवालियेकी कार्रवाईके सम्बन्धमें किये हुए खर्च तथा दिवालियेकी कारागारमें रखनेके खर्चके बारेमें यह बतलाया गया है कि अदालत इस सम्बन्धमें जैसा हुक्म देना उचित समझे दे सकती है दीवानोंके मामलोंमें मददगारों जेलमें रखनेका खर्च गिरफ्तार करने वाले टिकीदारों परदाय्य करना पड़ता है परन्तु दिवालियेके मामलोंमें ऐसा नहीं है । इस दफा के अनुसार हुक्म देना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है वह खर्चा दिलाने के लिये किसी मामलेमें बाध्य नहीं है परन्तु सम्प्रेषित व वाकियातका ध्यान रखते हुए ही अदालतको खर्च पानेका हुक्म देना चाहिये । जैसे कि बहुतसे मामलोंमें खर्च दिवालियेकी जायदाद पर ही पड़ना चाहिये परन्तु बहुतेरे मामलोंमें जिनमें कि गैर शस्त्र या कोई कर्जालाह व्यापारी कार्रवाई करके पोशान करे तो ऐसी कार्रवाईका खर्च उन्हीं लोगोंसे दिववाया जाना चाहिये ।

दफा ७७ अदालतें एक दूसरेकी मदद देवेंगी

वह सब अदालतें, जिन्हें दिवालियेके मामले सुननेका अधिकार है तथा उनके हाकिम एक दूसरेकी दिवालेके मामलोंमें मदद देंगे और अगर कोई अदालत दूसरी अदालतकी मदद चाहनेके लिये कोई हुक्म देगी तो उस दूसरी अदालतको उस मदद चाहने वाले मामलेके लिये जिसका जिक्र हुक्ममें होगा वही अधिकार होंगे जो इस एक्टके अनुसार ऐसे मामलोंमें उन अदालतोंको हो सकने हैं ।

व्याख्या—

इस दफा में यह बतलाया गया है कि यदि एक अशक्त निधी दूसरी अशक्तता दिवालिया समझी जाय वस्तु के लिये लिखे तो उस दूसरा अशक्तको उस कार्यके करनेमें बड़ा अधिकार प्राप्त होंगे जो पहिले अशक्तको उस कार्यवाहीके सम्बन्धमें प्राप्त है। और साथ ही साथ यह भी बतलाया गया है कि दिवाला सम्पत्ती कार्य करने वाली अशक्तों तथा उनके हाकिमोंका वर्तव्य होगा कि वह एक दूसरेकी सहायता उन मामलोंके वर्तनेमें कर।

दफा ७८ मियाद

(१) इस एक्टके अनुसार की हुई अपीलें तथा दी हुई दरखास्तोंके लिये सन् १९०८ ई० के कानून मियाद (Limitation Act) की दफा ५ व १२ के नियम लागू होंगे तथा ऊपर कही हुई दफा १२ के अनुसार इस एक्टकी दफा ४ का प्रैक्टीस यत्तैर दिवसोंके समझा जावेगा।

(२) अगर दिवालिया कतार दिये जाने वाला हुक्म इस एक्टके अनुसार मंजूर कर दिया गया है तो, दिवालिया कतार दिये जाने वाले बक्तमें मंजूरीके बहू तत्काल समय, उन मुकद्दमे या दरखास्तकी हुक्म मियादमें से घटा दिया जावेगा जो उस बक्त चालू होते जब कि इस एक्टके अनुसार कोई हुक्म न दिया गया होता, लेकिन यह नियम उन मुकद्दमे या दरखास्तोंके लिये लागू नहीं होगा जिनके लिये अशक्तने दफा २८ (२) के अनुसार हुक्म दे दिया हो।

परन्तु अगर कोई कर्म जो इस एक्टके अनुसार साबित किया जायकता हो अगर यह साबित न किया गया हो तो ऐसे कर्मों सम्बन्ध रखने वाले मुकद्दमे या दरखास्तके लिये इस दफाकी कोई बात लागू नहीं होगी।

व्याख्या—

उपदफा (१) में बतलाया गया है कि कानून मियाद (Limitation Act) की दफा ५ व १२ के नियम इस एक्टके अनुसार की हुई अपीलें तथा दरखास्तोंमें लागू होंगे। इस दफाके बननेमें पहिले इस बातके लिये बड़ा मतभेद था कि कानून मियादकी दफा १२ व दफा ५ कानून दिवालियाके लिये प्रयोग की जायकती है या नहीं, परन्तु इस दफाके बननेसे यह सब मतभेद दूर हो गया है। चूंकि दफा ५, व १२ का साम तीरेमें उल्लेख कर दिया है इतने यह प्रकट होता है कि कानून मियादकी और दफाके कानून दिवालिया सम्बन्धी कार्यवाहीके लिये लागू नहीं है यदि उनका लागू होना और किसी तरीकेमें न पाया जाय। यह भी जान लेना आवश्यक है कि कानून मियादकी दफा १ व १२ क्या है।

कानून मियादकी दफा ५ "यदि अपील या समर्थन अशक्तको इस बात का विश्वास दिगई कि वह किसी खास कारणकी वजहसे नियत किये हुए समयके जल्द अपील नहीं कर सका था या दरखास्त नहीं दे सका था तो उसको अपील या समर्थनानी की दरखास्त (Review) मियादने बाद भी लो जायकेगी अथवा अपील करनेके लिये जाना या कोई दूसरा दरखास्त जिसके लिये कानून यह दफा लागू होगी मियादके बाद दीजासकेगी। विवरण—यदि कोई कोई ती किमो तजवीज, हुक्म या अपील आने वाली हार्जिसके कारण निधी अपील या दरखास्त कुनि दाने मियाद समयने जा कोनेदे गयती की हो तो यह मियाद बढ़ानेके लिये काफी बजह समझी जासकती है।"

कानून मियादकी दफा १२ "निती मुकद्दमे, अपील या दरखास्तके लिये मियाद ओठने समय वह दिन मित दिनसे कि मियाद ओठना चाहिये उसमेंसे छंट दिया जावेगा अर्थात् उस दिनका शुभ्रा उस मियादके अन्त न विशा जावेगा।

(२) किसी अपील नज़रसानी (Review) या अपील करने में वज़ा देने वाली दरखास्त के लिये वह दिन निम दिया कि कैसला सुनाया गया हो मियादके अन्दर नहीं गिना जावेगा और जिस कैसले या हुक्मकी अपील की जाही हो या जिसन लिये दरख्वास्त दी जाही हो उसकी नक़्ते-हासिल करनेमें जो समय लगेगा वह भी मुकर्ररमें नहीं जोड़ा जावेगा।

(३) यदि किसी डिप्टी की अपील में जाय गा उसके नज़रसानी (Review) की दरखास्त दा जावे तो जो समय उस डिप्टी की नक़्ते लनेमें लगेगा वह मियादके अंदर नहीं जाड़ा जावेगा।

(४) यदि कोई दरखास्त किसी कैसला मालूम (Award) की मसूखीके लिये दी जावे तो जो समय उस कैसला साहिबी में नक़्ते हासिल करनेमें लगेगा वह मियाद मुकर्ररमें छुटार नहीं जाड़ा जावेगा। "

ऊपर दी हुई कानून मियादकी दफा ४ व १२ की देखनेसे यह मालूम हो जावेगा कि यह दोनों दफाओं मियादको बढ़ानेके सम्बन्धमें हैं। दफा ५ के अनुसार यदि कोई व्याक्त नियत लिये हुए समयके अंदर कोई कानूनी कार्रवाई किसी खास बकाबदल वजहसे न कर सके हो तो अदालत ऐसा बिन्दास दिन्धय जान पर मियाद समाप्त होनेके बाद भी उस कार्रवाईको मज़ूर कर सकती है।

दफा १२ कानून मियाद में यह बतलाया गया है कि जो समय नक़्ते हासिल करनेमें लगेगा वह भी अन्तर्गत मियादके अंदर करने वाले या दरखास्त देने वालेको मिल सकेगा यदि उस नक़्ते हासिल करना आवश्यक हो सके हो साथ इस दफामें यह भी बतलाया गया है कि जिस दिन कैसल या हुक्म सुनाया जावे उस दिनको भी मियादमें नहीं जोड़ेंगे अर्थात् उसके दूसरे दिनसे मियादका समय जाड़ा जावेगा।

कानून मियादकी दफा ४ व १२ देखनेसे यह प्रकट होता है कि उसके अनुसार मियाद बढ़ानेके लिये अदालत बाध्य नहीं है उसका बढ़ाना न बढ़ाना अदालतका स्वाधिन निर्भर है जब कि डिप्टी एक्जम (Deputy) शर्तके प्रयोगसे प्रकट होता है परन्तु कानून दिवालयकी बर्तव्यियोंके सम्बन्धमें उस दफामें कहा ही फादा उठाया जासकता है जसा कि कायदा दीवानीके आर बायोंके लिये उठाया जासकता है।

दफा १२ कानून मियादके देखने से यह बात भली मानी प्रकट है कि नक़्ते हासिल समय व कैसला सुनाया जाने वाला दिन मियादमें हर्गिज शामिल नहीं किया जाना चाहिये अर्थात् वह अपाल करने व लेने या दरखास्त देने वालेकी अवश्य छुट्टी लिये जावेगे। इस दफामें दफाओंके कानून दिवालय की कार्रवाईमें लागू हो जानेसे दिवालेकी कार्रवाईमें बड़ी सुविधा हो गई है। इस दफामें यह भी साफ़ कर दिया गया है कि दफा ४ के अनुसार दिये हुए हुक्मकी भी कानून मियाद की दफा १२ के अनुसार तिका ही समझना चाहिये।

उपदफा (२) के अनुसार यदि कोई दिवालिख करार दिये जाने वाला हुक्म मसूख कर दिया हो तो वह समय जो दिवालिख करार दिये जाने व मसूख होने वाली तारीखोंके बीचमें पड़ता हो मियादमें बड़ा दिया जावेगा क्योंकि इन तारीखोंके दर्मियान किसी कर्मचारीको नालिश करनेका हुक़्म नहीं रहता है तथा एक प्रारतसे उसकी कार्रवाई इस दायियानमें रोक दी जासकती है इस कारण इस मियादका अमली बानूनी मियादमें जोड़ दिया जाना उचित मानी होता है और इसी मसाले से लेकर हमारे यह उपदफा इसमें जोड़ दा है। परन्तु इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि उपदफा इन दो प्रकारके मामलोंमें लागू नहीं हवेगी (१) जब कि दफा २८ (२) के अनुसार गान्धिव दायर करने या दरखास्त देने की आज्ञा दी जाबुरी हो तथा (२) जब कि नालिश या दरखास्त ऐसे कर्तव्योंके सम्बन्धमें होवे जो कि साधिन किया जासकता हो परन्तु साधिन नहीं किया गया हो। हमने यह प्रकट है कि नक़्ते हासिल तथा उपरान्त लागू तथा सचिव है मिर्हाने अपना कर्म इस एक्टके अनुसार साधिन कर दिया है।

यदि दफा २८ (२) के अनुसार नालिया करने व डिब्री इनसाय कराने की आज्ञा ऐसी शर्तों साथ दी गई हो किनकी वजहसे वह डिब्री जागी नहीं कराई जानती हो तो ऐसी आज्ञाकी कोई अतर नहीं रहता है और इस आज्ञाके होते हुए भी कर्मचारीको भिन्नार्थमें वह समय ओ दिवालिया करार देने व मसूख होने वाली तारीखोंके बीचमें पड़ता है भिन्नार्थ दिया जानेवाला, देखो—A. I. R. 1925 All. 735.

II दफाके अन्तर्में जो शर्त लगा दी गई है वह बड़े महत्व की है व उसका चिक उपर किया जायुंश है अर्थात् यह कि यह दफा उर्दी कर्तोंसे सम्बन्ध रखने वाली नालियों व दस्ताखतोंके लिये लागू होगी जो इस एक्टके अनुसार साबित किये जायकते हैं व साबित किये गये हों ऐसे कर्तोंके लिये नहीं जो साबित किये जासकते हैं पर साबित नहीं किये गये । यदि कोई व्यक्ति दिवालियाकी कर्तवाही जारी रहते हुए दिवालियाके विरुद्ध दावा कर देवे तो वह दफा ७८ से लाभ नहीं उठा सकता है । इस दफाना फायदा उठी शर्तसे भिन्न सकता है जो दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्म की मसूखीके बाद कर्तवाही करे, देखो—A. I. R. 1928 Mad 977.

जो कि दफा ७८ के अनुसार कानून भियादरी दफा ५ अर्थात् व दस्ताखतोंके लिये लागू हैं परन्तु इस दफा ५ का प्रयोग दिवालिया करार दिये जाने वाली दस्ताखतोंके लिये नहीं होना चाहिये इस प्रकारका निर्णयन दफा ७८ क अनुसार दर्शावत नहीं है इस कारण यदि तीन महीनेसे अधिक की देर हो गई हो तो इस दफाके अनुसार कर्तवाही नही हो सकती देखो—A. I. R. 1928 Smd. 177.

दफा ७९ में कर्ता सम्बन्धित बरिन्दा एक हीया तरीका बता दिया गया है लेकिन उसकी वजहसे कर्तोंके किसी दूसरे तरीकेसे साबित होने में बाधबंद नहीं पड़ता है इस कारण यदि दिवालियाके अपनी दस्ताखतमें कोई कर्म दिखला दिया हो तथा इसी प्रकार वह साबित हो चुका हो तो यह मान लिया जायेगा कि वह कर्ता साबित किया जायुंश है अतः वह कर्मचारी वह समयको मुजोर पानेवा छुटकारक है जो दिवालिया करार दिये जाने तथा दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्म की मसूखीके दायिमाम पड़ना हो अर्थात् बसे दफा ७८ के अनुसार लाभ उठानेवा अधिकार प्राप्त है, देखो—A. I. R. 1929 Cal. 169 (2)

दफा ७९ नियम बनानेके अधिकार

(१) कलकत्ता हाईकोर्ट (First Court of Judicative of Fort William in Bengal) सपरिषद् गवर्नर जनरल हिन्दीकी आज्ञा लेनेके पश्चात् तथा दूसरे हाईकोर्ट प्रांतिक सरकार की आज्ञा लेनेके पश्चात् इस एक्टकी कार्य रूपमें परिचित करनेके लिये नियम बना सकते हैं ।

(२) पिछले अधिकारोंको मानते हुए तथा उनकी अवहेलना न करते हुए इन नियमोंमें नीचे दी हुई बातें हो सकती हैं:—

(ए) सरकारी रिसीवरों (Official Receivers) को छोड़ कर अन्य रिसीवरोंकी नियुक्ति तथा उनके भत्तेके लिये नियम तथा सब रिसीवरोंके हिसाब जांचनेके लिये प्रवन्ध व उस औचार्डिक प्रवन्धका खर्च किस प्रकार होना चाहिये

(बी) कर्मचारीकी सभा किये जानेके नियम

(सी) जब कि कर्मदारके कोई दूकान (Firm) हो तो किस प्रकार कार्यवाई होना चाहिये

(डी) जिन जायदादोंका इन्तजाम सरकारीसे होना चाहिये उनमें किस प्रकार कार्यवाई होना चाहिये

(ई) किसी मामलेके लिये जो निर्धारित किया जानेको होवे या जो निर्धारित किया जासकता हो ।

(३) इस प्रकार बनाये हुए सब नियम गजट आफ इन्डिया (Gazette of India) या प्राक्तिक सरकारी गजटोंमें जैसा कि मौका हो प्रकाशित किये जायेंगे और प्रकाशित होनेके पश्चात् यह इस प्रकार समझे जायेंगे जैसे कि यह इस एक्टमें शामिल हों ।

व्याख्या—

२म दफ्तेर अनुसार सब हार्डकोर्टों को अपने अपने अधिकार सीमाओं इस एक्ट का प्रयोग करने लिये नियमों के बनाने का अधिकार दिया गया है कलकत्ता हार्डकोर्ट गवर्नर जनरल हिंदू की समीपद आक्षा लेने पर नियम बना सकता है तथा दूसरे सब हार्डकोर्ट अपनी प्राक्तिक सरकारी आक्षा लेने पर नियम बना सकते हैं । यह नियम इस एक्टमें बर्नार्ड हार्ड कोर्टों की कार्यरूपमें परिचित करने के लिये बनाये जायेंगे । इन नियमों के बनाने के लिये हार्डकोर्ट बाध्य नहीं है जैसा कि अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग लिये हुए 'May' शब्द से प्रकट होता है अर्थात् नियमों का बनाना या न बनाना हार्डकोर्ट की इच्छा पर निर्भर है ।

उपदफ्ता (२) में दिखलाया गया है कि जिन बातों या समझें लिये यह नियम बनाया जाना चाहिये साथ साथ यह भी बतला दिया गया है कि इस प्रकार बनाये हुए नियमोंके इस एक्टमें दिये हुए अधिकारोंके विरुद्ध कोई अपील नहीं करना चाहिये । नियम ऐसे बनने जायेंगे जिनमें २म एक्ट के नियमोंमें कोई बाधा न पड़े ।

फलाज (५) के अनुसार नियम सिविलरी की निशुक्ति तथा उनके अन्तर्गत सम्बन्धमें होंगे व दिसादकी जाच व उस जाच सम्बन्धी जजोंके सम्बन्धमें होंगे परन्तु आधिशिष्य सिविलरीके सम्बन्धमें यह नियम नहीं होंगे ।

फलाज (६) के अनुसार नियम वर्कम्पाइजों की मार्टिंगके सम्बन्धमें बनाये जासकेंगे ।

फलाज (७) के अनुसार वह नियम बनाये जायेंगे जिनका प्रयोग किसी फर्मके दिवाल्या करार दिये जानेमें किया जासकेगा ।

फलाज (८) के अनुसार उन जायदादोंके हस्तगतके सम्बन्धमें नियम बनाये जासकेंगे जिनका इन्तजाम सरसरी तीसरे किया जानेकी है अर्थात् जिस जायदाद का प्रबन्ध अस्थायी है ।

फलाज (९) के अनुसार नियम किसी ऐसे मामलेके सम्बन्धमें बनाये जासकते हैं जो निर्वाचित किया जानेकी होवे या जो निर्धारित किया जासकता हो । यह फलाज (९) मिलकुल नया है और यह प्राक्तिक कानून दिवाल्या सशोधक एक्ट न० २२ सन् १९२६ ई० के अनुसार जिसको गवर्नर जनरल हिंदू की स्वीकृति ५ सितम्बर सन् १९२६ ई० को प्राप्त हुई है, जोड़ा गया है ।

फलाज (१०) से यह प्रकट है कि फर्म भी दिवाल्या करार दिये जासकते हैं इससे पहिले यह बात स्पष्ट नहीं थी । फर्म अपने शरीकदारोंका एक समुदाय नाम है मगर फर्मका नाम एक प्रकारसे एक जोड़ा नाम है जो उसके हर शरीकदारक अलहदा अलहदा नामोंके बनाय रख दिया गया है, देखो—100 I. C. 112

इस प्रकार फर्म कानूनन अपने हिसाबोंसे एक अलहदा चीज नहीं है फर्मका नाम उसके सब शरीकदारोंको एक साथ प्रकट करने के लिये रख दिया गया है । यदि कोई फर्म दिवाल्या करार दिया आवे तो उससे उसके हर मेम्बरकी दिवाल्या करार दिया जाना समझना चाहिये । देखो—A. I. R. 1926 Sind 31, 100 I. C. 112 यदि कोई फर्म कर्जदार होवे तो दिवाल्या करार दिये जानेका दरखास्त फर्मके नामसे होना चाहिये, देखो—72 I. C. 60.

उपदफ्ता (३) में यह बतलाया गया है कि इस दफ्तेरके अनुसार आ नियम बनाये जायें वह गजट आफ इन्डिया या प्राक्तिक सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाना चाहिये तथा इस प्रकार प्रकाशित किये जानेके समयसे वह नियम कानून के तौर पर समझे जायेंगे । अब तक इस प्रकार प्रकाशित न होने के कारण नहीं ।

दफा ८० सरकारी रिसीवरको अधिकारोंका दिया जाना

(१) हाईकोर्ट ऊपर दी हुई आश्वासनों के लेनेके पश्चात् समय २ पर सरकारी रिसीवरों को नीचे दिये हुए सब या कोई अधिकार दे सकेगा लेकिन यह अधिकार ऊन्हीं मामलोंसे सम्बन्ध रखते हुए होंगे जिनके सुननेका अधिकार इस एक्टके अनुसार अदालतको होगा तथा अदालत रिसीवरके इन अधिकारोंमें परिवर्तन कर सकेगी :-

(बी) सूची तैयार करें और कर्जद्वाराओंके सुधूत मंजूर या खारिज कर सकें

(ई) ज़रूरी मामलोंमें दरमियानी हुक्म दे सकें

(एफ) एकतर्फीया धिला विरोध की हुई दरखास्तोंको सुन सकें तथा उनको तय कर सकें

(२) दफा ६८ में दिये हुए अपीलकें नियमोंका ध्यान रखते हुए सरकारी रिसीवर द्वारा दिये हुए हुक्म व उसके किये हुए काम जो उसने ऊपर दिये हुए अधिकारोंके अनुसार किये हों वह यतौर अदालतके किये हुए हुक्म व कामके समझे जायेंगे ।

व्याख्या—

उपदफा (१) के भाग (ए), (सी) व (डी), प्रान्तिक दिवालिया कानून सशोधक एक्ट न० २९ सन् १९२२ (ई०) के अनुसार इस दफासे निष्काट दिये गये हैं । अब इस उपदफामें केवल कलत्र (बी), (ई) व (एफ) रह गये हैं ।

फलाज (ए) में दिया हुआ था “ कि वह दिवालियेकी दरखास्तोंसे सुन सकें तथा उसे दिवालिया कला दे सकें ” तथा भाग (सी) में दिया हुआ था “ कि वह बहाल (Discharge) का हुक्म दे सकें ” तथा भाग (डी) में दिया हुआ था “ कि वह तरफिया या समझते की स्वीम मंजूर कर सकें ” इस प्रकार इन प्रांतीय अनुसार जो अधिकार रिसीवरको दिये जासकते थे अब सशोधित एक्टके अनुसार नहीं दिये जासकेंगे । इस उपदफामें उन अधिकारोंका उल्लेख किया गया है जो हाईकोर्ट प्रान्तिक सरकार या भारत सरकारकी आज्ञा लेने पर आक्षेपिय रिसीवरको दे सकते हैं । जो अधिकार अब इस प्रकार दिये जासकते हैं वह इस उपदफाके भाग (बी), (ई) व (एफ) में दिये हुए हैं ।

फलाज (बी) में अनुसार सूची तैयार करनेमें रिसीवर कोई मामला कतई तौरसे बहिस्सियन अदालतके नहीं तय करता है 41 Ind. 30 अर्थात् यदि रिसीवर किसी बर्गमैन्वाइका नाम सूचीमें एक बार दर्ज करे तो उसमें दफा ५० के अनुसार परिवर्तन किया जासकता है या दफा ५३ के अनुसार भी कार्रवाई उस सम्बन्धमें की जासकती है । इस प्रांयके अनुसार आक्षेपिय रिसीवरको सूची ही तैयार करनेके अधिकार नहीं दिये जासकते हैं किन्तु उसे कर्जद्वाराओंके सुधूत मंजूर करने तथा उनके खारिज करनेके अधिकार भी दिये जासकते हैं ।

फलाज (एफ) के अनुसार आक्षेपिय रिसीवरकी एकतर्फी दरखास्तें सुननेका अधिकार दिया जासकता है जिनका विषय न किया जा रहा हो तथा वह ऐसी दरखास्तोंका फैसला भी कर सकता है । परन्तु ऐसी दरखास्तोंका विरोध होताही उसे उस दरखास्तके सुनने या उसका फैसला करनेका अधिकार नहीं रहेगा प्राय (ई) के अनुसार वह जरूरी मामलोंमें दरमियानी (Interim) हुक्म भी दे सकता है ।

रिसीवर तथा आक्षेपिय रिसीवरमें जो अन्तर इस दफासे प्रष्ट होता है वह यह है कि आक्षेपिय रिसीवर दफा ८०

के अनुसार दिये हुए अधिकारों के कारण अदालती (Judicial) अधिकार नहीं सच्चा है फलतः मामूली रितीरिवाजों से प्रभार के अधिकार प्राप्त नहीं हैं।

उपदफा (२) दफा १८ के अनुसार आफिशियल रितीरिवाजों के हकमों की अपील अदालतों में की जा सकती है उसकी अपील इन्हें नहीं दी जानी चाहिये देखो—38 Mad. 15. यदि इस दफते के अनुसार दिये हुए अधिकारों के आधार पर आफिशियल रितीरिवाज कोई फैसला करे या हुक्म देवे तो उसे अदालत द्वारा दिया हुआ फैसला या हुक्म मानना चाहिये ॥ उस फैसले की या हुक्म की अपील अदालत में अवश्य की जा सकती है यदि अपील न की गई हो तो वह फैसला या हुक्म बदल करायें देगा व उसे अदालत द्वारा दिया हुआ हुक्म या फैसला मानना चाहिये।

दफा ८१ प्रांतिक सरकार द्वारा कुछ नियमों का प्रयोग कुछ अदालतों के लिये रोक जाना

प्रांतिक सरकार को अधिकार है कि वह सपरिषद् गवर्नर जनरल (Governor General in Council) की स्वीकृति लेने के पश्चात् प्रांतिक सरकारी गजट द्वारा यह घोषित कर देवे कि उसके शासित प्रदेश के किसी हिस्से की अदालत या अदालतों के विद्यालयों सम्बंधी कार्यवाहियों के लिये इस एक्ट के सिड्यूल न० २ (Schedule II) में दिये हुए कौनसे नियम लागू नहीं होंगे।

व्याख्या—

जुनि देश के सभी भाग एक प्रकार के नहीं होते हैं ॥ कारण यह उचित समझा गया है कि प्रांतिक सरकारों को अधिकार दे दिया जाये कि जिनमें वह अपने शासित प्रदेश के किसी भाग में यदि किसी नियम का प्रयोग किया जाना उचित न समझे तो उसका प्रयोग बन्द न होने देवे। परन्तु इस बात का ध्यान रहना चाहिये कि प्रांतिक सरकार इस दफते में कतलमें हुए अधिकार का प्रयोग उसी समय कर सकेंगी जब कि वह इसके लिये सपरिषद् गवर्नर जनरल से स्वीकृति ले चुकी हो अन्यथा नहीं। और इस बात का भी ध्यान रहना चाहिये कि यह दफा कानून विद्यालयों के हर नियम के लिये लागू नहीं है किन्तु इसका प्रयोग केवल उन्हीं नियमों के सम्बंध में किया जा सकता है जो सूची न० २ (Schedule II) में दिये हुए हैं। प्रांतिक सरकार अपने शासित प्रदेश की अदालत या अदालतों के लिये ही इस प्रकार की घोषणा कर सकती है। अंग्रेजी एक्ट की इस दफते में प्रयोग किये हुए (May) शब्द से यह प्रकट है कि कोई प्रांतिक सरकार इस दफते के अनुसार कार्यवाही करने के लिये बाध्य नहीं है किन्तु यदि वह आवश्यक समझे व जिन नियमों के लिये आवश्यक समझे इस दफा की शर्तों का ध्यान रखते हुए उक्त घोषणा कर सकती है अंग्रेजी एक्ट की इस दफते में प्रयोग किये हुए (Shall) शब्द से यह प्रकट होता है कि इस दफते के अनुसार जो हों प्रांतिक सरकार की घोषणा का मानना आवश्यक है अर्थात् उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती है। इस दफते में बतलाने हुए घोषणा प्रांतिक सरकारों गजट में प्रकाशित किया जाना भी एक आवश्यक बात है।

दफा ८२ बचत (Savings)

इस एक्ट में बतलाई हुई—

(५) किसी बात का प्रभाव प्रेसीडेन्सी टाउनस इन्सोल्वेन्सी एक्ट १९०६ (The Presidency Towns Insolvency Act 1909) या लोअर बर्मा कोर्ट्स एक्ट १९०० (Lower Burma Courts Act 1900) की दफा ८ पर नहीं पड़ेगा, अथवा

(बी) कोई बात उन मामलोंके लिये लागू नहीं होगी जिनके लिये दक्षिण एग्रीकल्चर-रिस्ट्रिक्ट रिलीफ एक्ट १८७३ (The Dekkhan Agriculturists' Relief Act 1879) का चौथा अध्याय (Chapter IV) लागू है ।

व्याख्या—

इस दफामें यह बतलाया गया है कि इस एक्टका कोई प्रभाव प्रेसीडेन्सी याउन्स इस्ताम्बुल एन्ड पं नहीं पड़गा अर्थात् वह एक्ट इतने भिन्न है तथा सस्का प्रयोग भिन्न प्रकार होना बतलाया गया है या भिन्न स्थानोंमें होना बतलाया गया है वहा उसी प्रकार किया जावेगा उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती है । इसी दफा (ए) में यह भी बतलाया गया है कि छोटा बर्मा कोर्ट्स एक्ट १९०० की दफा ८ पर भी इस एक्टका कोई प्रभाव नहीं पड़गा अर्थात् उनका भी अवहेलना नहीं की जा सकती । दफा (बी) के अनुसार दक्षिण एग्रीकल्चररिस्ट्रिक्ट एक्ट १८७९ का चौथा अध्याय उन मामलों के लिये लागू होगा उन मामलोंमें भी यह एक्ट लागू नहीं हो सकेगा ।

दफा ८३ मंसूखी (Repeals)

(१) (मंसूख होगया)

(२) यदि इस एक्टके प्रारम्भ होते समय किसी प्रचलित कानून या दस्तावेजमें सन् १८७७ या १८८२ ई० के जाबता बीबानीके बीसवें प्रकरण (Chapter XX) का हवाला दिया गया हो या उन प्रकरणोंकी किसी दफाका हवाला दिया गया हो तो जहा तक हो सकेगा, उन हवालों के लिये यह समझा जावेगा कि वह हवाले इस एक्टके हैं अथवा इसकी मिलती जुलती किसी दफाके हैं (ऊपर कहे हुए बीसवें प्रकरणमें दिवालिया मन्थूनका जिक्र है) ।

व्याख्या—

इस दफारी पहिली उपदफा रीपीलिंग एक्ट १९२७ [Repealing Act 1927 (XII of 1927)] द्वारा रद्द कर दी गई है अर्थात् अब इस दफामें केवल उपदफा (२) ही रह गई है सन् १८७७ व १८८२ ई० के जाबता बीबानीके बीसवें प्रकरणमें दिवालिया मन्थूनका उल्लेख है । इस दफामें यह बतलाया गया है कि यदि इस बीसवें प्रकरणका हवाला कहीं दिया गया हो तो उन हवालोंके लिये यह समझा जावेगा कि वह हवाले इस एक्टके हैं अथवा इसकी मिलती जुलती किसी दफाके हैं ।

सूची नं० १ (Schedule. I.)

देखो दफा ७५ (२).

यह फैसलें व हुक्म जिनकी अगल दफा ७५ (२) के अनुसार हार्डकोर्डमें हो सकती है।

दफा	फैसले व हुक्मोंका स्वभाव
४	हक (Title) (Priority) आदि सम्बन्धी प्रश्नोंका फैसला जो इन्सालवेमें पैदा हों
२५	पिढीशनको खारिज करनेका हुक्म
२६	मुआवित्त (Compensation) दिलाये जानेका हुक्म
२७	दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म
२८	सूची (Schedule) के इन्दरानके सम्बन्धमें दिये हुए हुक्म
२९	दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी मसूखीका हुक्म
३७	दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मके मसूख किये जाने पर दिवालियेकी जायदाद तिन शर्तोंके साथ दिवालियेकी मिलेगी वन शर्तोंके सम्बन्धमें दिये हुए हुक्म
४३	बहाल (Discharge) होने वाली दुरवस्था पर हुक्म
५०	सूचीमें इन्दरान न किये जाने तथा उसके इन्दरानमें कमी किये जानेके हुक्म
५३	अपने आप (Voluntary) किये हुए इन्तकाल (Transfer) की मसूखीका हुक्म
५४	इस बातका फैसला कि कोई इन्तकाल किसी कजबदारको सर्जिड (Preference) देनेके लिये किया गया है
	नोट.—रिपीलिंग एक्ट सन् १९२७ (The Repealing Act XII of 1927) द्वारा इस सूचीका आखिरी इन्दरान जो दफा ६९ के बाधत था हटा दिया गया है उसमें इस प्रकार दिया हुआ था।
६९	इस दफाके अनुसार किये जूमेके सम्बन्धमें जूम साबित होने तथा सजा दिये जाने पर (मसूख है)

सूची नं० २ (Schedule. II.)

देखो दफा ८१.

एक्टके वह नियम जिनका प्रयोग प्रान्तिक सरकार द्वारा रोक जा सकता है ।

एक्टके नियम	विषय
दफा	
३६	सुभाषितेका दिलाया जाना (Award of Compensation)
३८ उपदफा (३)	दिवालियेको कइलाने वाली जायदाद
३४,	इस एक्टके अनुसार साबित हो सकने वाले कर्जें
३८, ३९, ४०	तस्वीया व तय करनेकी स्कीम (Composition and Schemes of Arrangements)
४१ उपदफा १, २	पूर्ण रूपसे बहाल (Absolute Discharge) होनेसे इनकार करनेके सम्बन्धमें कतव्य
४५, ४६, ४७, } ४८, ४९, ५० }	कर्जों साबित करनेका ढंग
५१, ५२, ५३, } ५४, ५५ }	गिरले किये हुए सौदों (Antecedent Transactions) पर दिवालेका प्रभाव
६१ उपदफा (१) के लान (५) व उपदफा (४) को छोड़कर	कर्जोंका एक दूसरेसे पेशतर चुकाया जाना (Priority of debts)
६२, ६३, } ६४, ६५, }	हिस्सा रसदी (Dividends)
६६	दिवालिये द्वारा प्रकण्ड तथा उसको दिया जाने वाला भत्ता
७२	गिला बहाल हुए दिवालिये द्वारा कर्जें किये जाने पर उसके लिये दण्ड

सूची नं० ३ (Schedule. III.)

देखो दफा ८३.

यह सूची रिपीलिंग एक्ट १९२७ (The Repealing Act XII of 1927) द्वारा हटा दी गई है।

इस सूचीमें सन् १९०७ व १९१४ ई० के एक्टोंका उल्लेख था व यह बतलाया गया था कि वह किस हद तक मसूल कर दिये गये हैं।

कलकत्ता हाईकोर्ट रूलस (Calcutta High Court Rules)

निम्न लिखित रूलस (Rules) कलकत्ता हाईकोर्टने प्रान्तिक कानून दिवाला एक्ट नं० ५ सन् १९२९ ई० की दफा ७९ में दिये हुए अधिकारीके आधार पर बनाये हैं जिनके लिये भारत सरकार (Governor General in Council) की स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है सर्व साधारणके भूचनार्थ प्रकाशित किये जाते हैं —

प्रान्तिक कानून दिवाला एक्ट ५ सन् १९२० ई०

एक्ट ५ सन् १९२० ई० की दफा ७६ के अनुसार बनाये हुए नियम ।

१ नीचे दिये हुए नियम प्रान्तिक कानून दिवालाके रूलस कहलायेंगे । इन नियमोंमें जो नमूने (Forms) बतलाये गये हैं उनका प्रयोग सम्योचित परिवर्तनके साथ उन बातोंके लिये किया जावेगा जिनसे कि इनका सम्बन्ध भिन्न भिन्न रूपसे हैं ।

नोट : — नमून आगे चल कर भिविल प्रोसेस फार्म (Civil Process Forms) नं० ११७ से नं० १५० तक देने गये हैं ।

२ हर एक दिवालेकी दरवास्त दिवालेके रजिस्ट्रारमें चढाई जावेगी और यह रजिस्ट्रार दिवालेके सम्बन्धमें कार्रवाई कराने वाली हर एक अदालतके पास रखे आवेंगे । उस रजिस्ट्रारमें तर्तीबी सख्या (Serial Number) दी जायेगी और उस सामलेके सम्बन्धमें जो संय कार्रवाईया वादमें की जावेगी उनमें वही संख्या (Number) रखी जावेगी ।

३ दिवालिया सम्बन्धी सब कार्रवाईयाका मुआयना उन समयों पर तथा उन शर्तोंके साथ किया जासकता है जो डिस्ट्रिक्ट अज नियत करे और यह मुआयना रिमांडर, कर्जदार या कोई कर्जएवाह जिसका कर्ज साबित हो चुका है कर सकता है या इनका ओरसे इनके कानूनी मुसाहदे (Legal Representative) कर सकते हैं ।

४. जब कभी किसी नोटिस या किसी दूसरे सामलेका इस एक्ट या इन नियमोंके अनुसार सरकारी गजट (Official Gazette) में प्रकाशित किया जाना बतलाया गया हो तो एक याददाश्त (Memorandum) जिसमें कि प्रकाशित होने वाली तारीख व गजटका इवाला दिया हुआ होगा भित्तिलमें शामिल कर दी जावेगी और उसका इन्डराज शर्द अश्काम (Order Sheet) में भी भर दिया जावेगा ।

५ दफा १९ (२) के अनुसार पिटीशनके सुने जानेकी तारीख नियत किये जानेका नोटिस प्रान्तिक सरकारी गजट (Local Official Gazette) में प्रकाशित किया जावेगा तथा उन अखबारोंमें भी वह नोटिस मुद्रित किया जावेगा जिनके लिये अदालत हुजूम देवे । नोटिसको एक एक नकल रजिस्ट्रारके द्वारा सब कर्जदारोंके पास उनके उस पतेसे मानी जावेगी जो पिटीशनमें दिया गया हो । यही तरीका उन नोटिसोंके सम्बन्धमें भी प्रयोग किया जावेगा जो दफा २८ (१) के अनुसार वरक्रीयके प्रस्ताव या तय करनेकी स्कीम (Scheme of Arrangement) के लिये दिये जानेको हानेंगे ।

६. दफा २० के अनुसार दिवालिया करार दिये जाने वाले हुजूम की सूचना (Notice) प्रान्तिक सरकारी गजटमें प्रकाशित किये जानेके अतिरिक्त जैसा कि इस एक्टमें बतलाया गया है उन समाचार पत्रों

Newspapers) में भी प्रकाशित की जासकती है जिनके लिये अदाकत आज्ञा देवे । यदि कर्जदार सरकारी चाकिन (Government Servant) होवे तो इस हुक्मकी नकल उस आफिसके सबसे बड़े हाकिम Head of the Office) के पास भेजी जावेगी जहा कि वह कर्जदार नौकर होवे ।

सही तरीका (Procedure) उन हुक्मोंकी सूचना (Notice) के सम्बन्धमें प्रयोग किया जावेगा । दफा ३० (२) के अनुसार दिवालिया कारर दिये जाने वाले हुक्मकी मंजूरीके लिये दिये जावेंगे ।

७. दफा ५० के अनुसार जो नोटिस अदाकत द्वारा दिये जानेकी हों उनकी सामील कर्जदारवाह या उसके कील पर की जावेगी या वह नोटिस रजिस्ट्री खत द्वारा भेजा जावेगा ।

८. अन्तिम हिस्सा रसदी (Final dividend) बाटनेसे पहिले रिसीवर दफा ६५ के अनुसार जो नोटिस इन कर्जदारवाहोंके नाम जारी करेगा जिनका कर्जदारवाह होना उल्लेख किया जाचुका है परन्तु जिनके कर्ज आविश नहीं किये हैं वह नोटिस रजिस्ट्री खत द्वारा भेजे जावेंगे ।

९. दफा ४१ (१) के अनुसार बहाल (Discharge) की दुरुखास्त सुननेके लिये जो तारीख तयत की जावे उसकी सूचना (Notice) प्रान्तिक सरकारी गजटमें प्रकाशित की जावेगी तथा उन समाचार पत्रोंमें भी दी जावेगी जिनके लिये जज आज्ञा देवे और इसकी नकलें सब कर्जदारवाहोंके पास रजिस्ट्री खत द्वारा भेजी जावेंगी चाहे उन्होंने अपना कर्जा साबित किया हो या न साबित किया हो ।

१०. यदि पिछले नियमोंमें बतलाये हुए नोटिसोंके सम्बन्धमें आकड़ानेकी रसीद हाजिर की जावे तथा अदाकतके किसी अकनर या आफिसलू रिसीवर का सर्वेफिरेट या किसी अन्य रिसीवरका इकतनामा इस बातके लिये होवे कि नोटिस नियम पूर्वक दिये गये हैं तो वह इस बातकी कारी सहदात मानी जावेगी कि नोटिस जिसके पक्षमें भेजे गये हैं उसकी ठीक तौरसे भेजे गये हैं ।

११. प्रकाशित किये जानेके निर्धारित नियमोंके आतिरिक्त अदालतकी आज्ञाबुसार नोटिस अन्य किसी रूपसे भी प्रकाशित किये जासकते हैं जैसे कि अदालतकी इमारतमें उनकी नकलें छिपका देनेसे अथवा जिस गायमें दिवालिया रहता हो जहा मुलादी कस देनेसे ।

रिसीवर

१२. रिसीवरकी नियुक्तिका हुक्म फिल कर तथा अदालतके इस्ताहर होकर दिया जावेगा । इस हुक्म की नकल अदालतकी मोहर लगा कर कर्जदारके पास भेजी जाना चाहिये तथा वह नकलें नियुक्त किये हुए व्यक्तिके पास भी भेजी जाना चाहिये ।

१३. (१) अदालतकी चाहिये कि वह रिसीवरका अम्बल (Remuneration) नियत करते समय अधिकतर उसे कमीशन या फी सैकडाके हिसाबसे नियत करे जिसमेंसे एक भाग सहपूज कर्जदारवाहों (Secured Creditors) की जमानतों (Securities) के रुपये निकालनेके बाद जो रुपया बसूल किया जावे उसके हिसाबसे मिलना चाहिये तथा दूसरा भाग उस रकमके हिसाबसे मिलना चाहिये जो वह दिरसा रसदी (Dividend) के रूपमें तकसीम करे ।

(२) जब कि रिसीवर सहपूज कर्जदारवाहोंकी जमानत (Security) का रखरखाव करे तो अदालत उसे उस कामके हिसाबसे तथा कर्जदारवाहोंके लाभ में देवते हुए अधिक अम्बल (Remuneration) दिला सकती है ।

१४. रिसीवर रोकड़ या अन्य हिसाबकी किताबें तथा कागजात रखेगा जिसमें जायदाद सम्बन्धी उसके प्रत्येक की सूची ज्ञान हो सके और वह हिसाब किताब उन समयों पर तथा उस प्रकार दायित करेगा जिस प्रकार कि अदालत हुक्म देवे। उन हिसाबों की जांच वह लोग करेंगे जिनके लिये अदालत हुक्म देवे। हिसाब की जांच (Audit) का खर्च अदालत नियत कर देगी और वह दिवालिये की जायदादसे दिया जावेगा।

१५. वह कर्जदार जो अपना कर्ज साधित कर चुका है अदालतमें इस बातकी दुरवास्त दे सकता है कि उसको रिसीवरके कुछ हिसाब या उसके किसी हिस्सेकी नकल दी जावे जिसका कि सम्बन्ध दिवालियेकी जायदादसे होवे और जो कि रोकड़में उस तक तक दिखलाया जायता हो और उसकी वह खर्च अदा करने पर नकल दी जावेगी जो इस अदालतके नियमोंके अनुसार नकलोंके पास कम्पेक लिये बतलाये गये हैं।

१६. यदि किसी मामलेमें कर्जदारोंकी मीटिंग (Meeting) की आवश्यकता हो और यदि किसी मामलेमें कर्जदार तत्सही या तब किये जाने की स्कीम (Scheme) दफा ३८ के अनुसार ब्याहता हो तो रिसीवर ७ दिनका नोटिस कर्जदार व सब कर्जदारोंको इस बातके लिये देगा कि ऐसी मीटिंग किम तारीख पर तथा किस स्थान पर होगी। ऐसे नोटिस रजिस्ट्रीमुद्रा जत द्वारा दिये जावेंगे।

कर्जोंका साधित किया जाना

१७. कर्जदारोंका सुनूब सिविल प्रोसेस फॉर्म नं० १२१ [Civil Process Form No 146 in Volume II] के अनुसार समयावधिक परिवर्तनके साथ होना चाहिये।

१८. यदि किसी मामलेमें कर्जदारके ब्याजमें वह भालस हो कि उसके कारीगरों व दूसरे काम कामे वारों की बजत (Wages) के बहुतसे दावे हैं तो उन सबके लिये अकेले कर्जदार ही का सुनूब या उन सब कर्जदारों की तरफसे किसी दूसरे व्यक्ति का सुनूब बर्नास समझा जावेगा। इस प्रकारका सुनूब सिविल प्रोसेस फॉर्म (Civil Process Form No. 147 in Volume II) के अनुसार होना चाहिये।

यदि कर्जदार कोई फर्म (Firm) होवे तो उसका तद्विक।

१९. यदि किसी सूचना (Notice), दखान (Declaration), दरवास्त (Petition) या किसी दूसरी दस्तावेजके जर्नल (Journal) की आवश्यकता हो और उस पर किसी कर्जदारों या कर्जदारोंके फर्म के दस्तावेज फर्मके नामसे किये जावें तो जो हिस्सेदार फर्म की ओरसे दस्तावेज कर उसकी कर्तव्य भी दस्तावेज करना वही जस कि प्राथम दण्ड कम्पनी बचरिये जेरमनी फर्मका एक शरीकदार " Brown & Co by James Green a Partner in the said firm "

२०. यदि किसी सूचना (Notice) या दरवास्त (Petition) की सामील जाती तोरसे होना आवश्यक हो और उसकी सामील अदालत की अधिकार सीमाके अन्दर उस फर्मके स्वयं रोजगार की जगह पर फर्मके किसी शरीकदार पर या फर्मका प्रबन्ध या इस्तरेख करने वाले व्यक्ति पर की गई होगी तो वह मान लिया जावेगा कि उसकी सामील वाक्यावृत्ति फर्मके सब शरीकदारों पर हुई है।

२१. पिउली दफामें बतलाया हुआ नियम जहां तक मामलेके अनुसार सुमकिन होगा उस मामलेमें भी लागू होगा जब कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे नामसे अदालत की अधिकार सीमाके अन्दर कारागार करता होवे।

२२. यदि कर्जदारोंका कोई फर्म दिवालिये की दुरवास्त देवे तो उस दरवास्तमें फर्मके सब शरीकदारोंके पूरे पूरे नाम होने और यदि उस दरवास्तमें फर्म की तरफसे किसी एक शरीकदारने दस्तावेज किये हों तो उस

हर वामनके साथ उस शरीकरके एक हलफनामा लगाता रहेगा कि फर्मके सब शरीकरों की राय उस दरख्तानको देनेके लिये है ।

२३ यदि किसी फर्मके विरुद्ध दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म दिया जाये तो यह समझा जायेगा कि फर्मके वह सब शरीकर जो हुक्म देत समय शरीकर हैं दिवालिया करार दे दिये गये हैं ।

२४ सत्रोंके मामलामें कर्जदार सत्रोंके मामलोंके सम्बन्ध की सूची (Schedule) पेश करेंगे और हर एक कर्जदार अपने अलहदा अलहदा मामले की सूची भी पेश करेगा ।

२५ संयुक्त कर्जदार तथा कर्जानाओं के अलहदा २ समूह अलहदा २ तरीक्या या तय होने की स्कीमको मंजूर कर सकते हैं । जइतक मुमकिन हो सकेगा संयुक्त कर्जदारों द्वारा मंजूर ठिया हुआ महान निर्धारित रूपसे स्वीकार किया जावगा बिल इस बातका खयाल किये हुए कि किसी कर्जदार या कर्जदारोंके जुदागाना कर्जदार या कर्जदारान उस तरीक्या या स्कीम को स्वीकार नहीं किया है ।

२६ यदि तरीक्या या स्कीम का प्रस्ताव फर्म द्वारा किया गया हो अपना फर्म के शरीकरोंमें अलहदा २ तौर से किया हो तो संयुक्त कर्जदारों को किये हुए प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा और हमपर उनके बोड १५५५ आयेगे उस समय अलहदा कर्जदारोंके समूहोंका अलहदा ध्यान नहीं दिया जायेगा । और जो प्रस्ताव कर्जदारोंके किसी साथ सनून से किया गया हो उसपर यह समूह अलहदा से विचार करेगा व बोड देगा कुल कर्जदारों से उसका सम्बन्ध नहीं होगा । यह प्रस्ताव भिन्न २ रूपसे तथा भिन्न २ तरीक्येके लिख किये जा सकते हैं । जब कि तरीक्या या स्कीम स्वीकार करली जावे तो दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म अभी बंद तक मसूल होगा जहां तक कि उनका उस जयदाद से तात्लुक है जिसके कर्जदारों ने तरीक्या या स्कीम को मान लिया है ।

२७ यदि किसी शराकती फर्म के दो भा दे से अधिक मेम्बरान कोई जुदागाना फर्म चलाते हों तो उस जुदागाना फर्मके कर्जदारान एक जुदागाना कर्जदारोंका समूह समझा जावगा । और यह उसी मर्यादामें जायेगा जैसे कि फर्मके किसी मेम्बरके अलहदा से कर्जदारान होवे । यदि ऐसे जुदागाना फर्म (Assets) से कोई फाइल रकम बचे तो वह उस फर्मके शरीकरों में हिस्सा इसकी हिस्सा व उसकी अलहदाकी जायदाद में ल जाई जावेगी ।

दिवालिये की गैर मनकूला जायदाद का धेवा जाना ।

२८ यदि कोई रितिवर नियुक्त न किया गया हो और अदालत स्वयं एक्ट की दफा ५८ के अनुसार दिवालिये की गैर मनकूला जायदाद को धेवे तो उस जायदाद के लिये दस्तावेज बनाना शरीदार अपने खर्च तैयार करावेगा और उस अदालतके हाकिम के इस्तजत होंगे । यदि रीगुलरीको कोई रस्य होगा तो वह भी शरीदार बरदाश्त करेगा ।

हिस्सा रसदी (Dividends)

२९ हिस्सा रसदी (Dividend) का करवा कर्जदारोंके धारणा करने पर अपने भिगेदारी पर दाकके अरिये भेजा जासकता है ।

सरसरीकी कार्रवाई

३०. यदि दफा ७४ के अनुसार किसी जायदादका इन्तजाम भारतीय तौरमें किये जानेका हुक्म होवे तो अदालतके किसी खास हुक्मका ध्यान रखते हुए हम एक्टके नियम तथा यह नियम निम्न प्रकारसे संतापित होंगे ।

- (i) किसी कार्रवाईका प्रकाशन प्रान्तिक सरकारी गजट या अन्य किसी समाचार पत्रमें नहीं किया जावेगा।
- (ii) दरखास्त (Petition) पर तथा बादकी सब कार्रवाइयोंमें 'सरसरी का मामला' (Summary Case) लिख दिया जावेगा।
- (iii) कर्जद्वाराको दरखास्त (Petition) के सुने जानेकी सूचना (Notice) सिविल प्रोसेस फार्म न० १५० (Civil Process Form 150 Vol. II.) के अनुसार दी जाना चाहिये।
- (iv) अदालत कर्जदारका बयान उसके मामलोंके सम्बन्धमें लेगी परन्तु वह कर्जद्वाराको सीटिंग करनेके लिये बाध्य नहीं है जो कर्जद्वाराको हक होगा कि उनकी जवाबदेही सुनी जावे तथा वह कर्जदारसे जिरह कर सके।
- (v) अधिकतर रसीदोंके नियुक्त किये जानेकी आवश्यकता न होगी और अदालत दफा ५८ के अनुसार कार्रवाई कर सकती है जिसमें कि दिवालियेकी कार्रवाईमें खर्चा कम हो जावे अर्थात् खर्चोंकी बचत हो सके।

खर्चा।

३१. उन सब कार्रवाइयोंका खर्च जो दिवालिया करार दिये जानेके हुकम तक होगा तथा जिसमें दिवालिया करार दिये जानेका हुकम भी शामिल है कार्रवाई करने वाले व्यक्ति पर रहेगा परन्तु जब दिवालिया करार दिये जाने वाला (Adjudication) हुकम हो जावे तो दरखास्त देने वाले कर्जद्वाराका उचित खर्च दिवालियेकी जायदादसे विलगाया जावेगा।

३२. यदि तत्कीया या स्कीम अदालत द्वारा स्वीकार न की जावे तो तत्कीया या स्कीमकी दरखास्तके लिये तथा उसके सम्बन्धमें किये हुए कर्जदारके खर्चोंको उसकी जायदादसे नहीं विलगाया जावेगा।

सिविल प्रोसेस नं० १३७.

कर्जदारकी दरखास्त

दफा १३ प्रान्तिक कानून दिवालिया

अदालत सादर डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०
.....सायल

मैं (ए) अधिवक्ता (बी) का रहने वाला हूँ (या मैं व्यापार करता हूँ या लाभके लिये काम करता हूँ अथवा (सी) के हुकमके अनुसार (बी) में हिरासतमें हूँ। अपने कर्जोंकी अदायगीमें असमर्थ होनेके कारण दिवालिया करार दिये जानेके लिये दरखास्त देता हूँ। मेरे ऊपर कुल (डी) रुपयेका कर्ज है जिसका इन्दराज तफसीलवार इस दरखास्तके साथ दी हुई सूची (ए) में दिया है और उस सूचीमें मेरे सब कर्जद्वाराके नाम व एवं जहाँ तक मुझको मालूम है या जहाँ तक मुझको मालूम हो सके हैं दिखे हुए हैं। मेरे पास जितनी जायदाद है उसकी तादाद व तफसील सूची (बी) में जो इसके साथ दी जा रही है दिखलाई गई है और उस सूचीमें रख्योंके अतिरिक्त जो जायदाद है उसकी तफसील तथा जिस जगह या जिम्मे जगहोंमें वह जायदाद है उनका उल्लेख भी किया गया है।

मैं अपनी सब जायदाद अदालतकी मुसुदगीमें देने को तैयार हूँ केवल उन चीजोंको छोड़ कर जा कानून किसी इजराय डिक्लीमें कुक व विलियम होनेसे बरी हूँ (परन्तु हिसाबकी किताबोंको उन चीजोंमें नहीं समझना चाहिये) मैंने इससे पहिले कभी दिवालिया करार दिये जानेके लिये कोई दरखास्त नहीं दी है (या मैं सूची (सी) में दिवालिया करार दी जाने वाली दरखास्त या दरखास्तोंकी तफसील (ई) देता हूँ । तबरीक ह्वास्त उसी प्रकार होना चाहिये जैसे कि अभी दावाकी तस्दीक होती है ।

दस्तख्त " " " " " " " "

नोट :-जहां पर (ए) दिया हुआ है वहां कर्जदारका नाम व पता दिया जाना चाहिये ।

जहां पर (बी) लिखा हुआ है वहां जगहका नाम व पता होगा चाहिये ।

जहां पर (सी) लिखा हुआ है वहां अदालतका नाम तथा उस डिक्ली की तफसील व इवाला होना चाहिये जिसके इजरायमें वह गिरफ्तार हुआ हो या जिसके इजरायमें जायदाद कुक हुई है ।

जहां पर (डी) लिखा हुआ है वहां पर यह दिखलाना चाहिये कि कौनसे वर्ग मसफूत हैं व वह किस प्रकार मसफूत हैं ।

जहां पर (ई) लिखा हुआ है उसमें यह बातें दिखलाई जाना चाहिये ।

(१) यदि दरखास्त दिवालिया कारिम की गई हो तो वह किस कारण कारिम की गई थी ।

(११) यदि कर्जदार पहिले दिवालिया करार दिया जा चुका हो तो उसके दिवालिया करार दिये जानेका ध्येय और यह भी बतलाना चाहिये कि आपा कोई पिछड़ी दिवालिये की दरखास्त मसूल (Annul) की गई थी या नहीं और यदि मसूल हुई थी तो क्यों ।

सिविल प्रोसेस नं० १३८

दिवालिये की दरखास्त सुने जानेका नोटिस जो कर्जद्वाराओंको दिया जाना चाहिये

दफा १९ प्रान्तिक कानून दिवालिया

अदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि० " " " " " " " "

दरखास्त दिवालिया न० सन् १९ ई०

जुंकि

ने इस अदालतमें प्रान्तिक कानून दिवालियाके अनुसार दिवालिया करार दिये जाने की दरखास्त ता० सन् १९ को दी है और उस कर्जदारने जो कर्जद्वाराओंकी फिहरिस्त दाखिल की है उसमें तुम्हारा नाम भी दिखलया है तुमको इतका ही ज्ञाती है कि इस अदालतने ता० सन् १९ उस दरखास्तके सुने जानेके लिये तथा कर्जदारके बयानके लिये मुकदर की है । अगर तुम इस मामले की पैरवी किया चाहो तो या तो स्वयं हाजिर हो या पूरी हिरासत देकर किसी वकीलके जरिये हाजिर हो । तुम्हारा कर्ज जो दरखास्तमें दिखलया गया है उसकी तफसील इस प्रकार है ।

द० जज

सिविल प्रोसेस नं० १३६

दिवालिया कर्जदार दिये जानेका हुक्म

दफा २७ ग्रान्ठिक कानून दिवालिया

बमदास्त साहय डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०.....

दरखास्त दिवालिया नं० सन् १९ ई०

इस दरखान्त मुबारका सन् १९ जो खिलाफ (यहां पर कर्जदारका नाम व पता होता चाहिये) के गुजरी है व इस दरखास्त (यहां पर रिजिस्टर, कर्जदार या कर्जवाहका नाम होगा चाहिये) के व इस दरखान्तको पढ़ने व सुननेके बाद यह हुक्म दिया जाता है कि वह कर्जदार दिवालिया करार दिया जावे तथा वह दिवालिया करार दिया जाता है ।

यह भी हुक्म दिया जाता है कि कर्जदार मजदूर आज की तारीखसे के अन्दर अपने षहाल (Discharge) किये जाने की दरखास्त देवे ।

तारीख

सन् १९ ई०

द० जज

सिविल प्रोसेस नं० १४०

उस कर्जवाहकी दरखास्तका नोटिस जिसका नाम सूचीमें दर्ज नहीं है

दफा ३३ (२) ग्रान्ठिक कानून दिवालिया

बमदास्त साहय डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०.....

अमुकवामा

दिवालिया

नं०

सन् १९ ई०

बनाम

चूंकि इस अदालतमें

ने जो कि अपनेको एक कर्जवाह आदिर करता है एक

दरखास्त इस अग्र की गुजरानी है कि उसको अपना कर्जा साबित करने की आज्ञा दी जावे तथा उसका नाम कर्जवाहकी फिदरिम्में उस कर्जेके सरन्धर्भमें लिख लिया जावे जिसे कि वह साबित कर देवे इसलिये तुमको इत्तला दी जाती है कि वह दरखास्त ता० सन् १९ को इस अदालतमें सुनी जावेगी और यदि तुमको उसका विरोध करना हो तो तुम स्वयं या बरीलके जरिये उस तारीख पर हजर हो सकते हो ।

मैंने दरखान्त व अदालतकी मुहरसे यह नोटिस आज ता०

सन् १९ को जारी किया गया ।

द० डिस्ट्रिक्ट जज

सिविल प्रोसेस नं० १४१

दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्म की मंजूरीका हुक्म

दफा ३५ प्रान्तिक कानून दिवालिया

अदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जिन०

दरखास्त दिवालिया नं० सन् १९ ई०

..... सायल

... ..के दरखास्त देने पर तथा उसको पढ़ने व सुननेके पश्चात् यह हुक्म दिया जाता है कि दिवालिया करार दिये जाने वाला हुक्म सुननेवाला सन् १९ जा जिलाफ के दिया गया था मंजूर किया जावे व वह हुक्म मंजूर किया जाता है।

तारीख सन् १९ ई०

द० जज

सिविल प्रोसेस नं० १४२

तस्फीया या तय करनेकी स्कीम पर गौर करनेके लिये जो तारीख नियत की गई हो उसकी

सूचना कर्जदारको देना

दफा ३८ (१) प्रान्तिक कानून दिवालिया

अदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज जिन०

दरखास्त दिवालिया नं० सन् १९ ई०

..... सायल

तुमको सूचना दी जाती है कि इस अदालतमें तारीख जब तस्फीया या स्कीम पर गौर करनेके लिये सुननेकी है जो कर्जदारने इस अदालतमें दी है उस तारीखसे पहिले जिस कर्जदारका कर्जा साबित नहीं हो चुकेगा वह उक्त मामले पर विचार होते समय वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा। यदि तुम ऊपर बतलाई हुई सुनवाईके समय उपस्थित होना चाहो तो स्वयं या किसी ऐसे वकीलके जरिये हाजिर हो सकते हो जिनसे इस मामलेके सम्बन्धमें पूरी हिदायत देदी गई हो।

द० जज

इस फार्माकी पुश्त पर इस प्रकार दिया जाना चाहिये।

सम्मान दाखिल किये जानेकी तारीख

तारीख जब कि सम्मान मागिरके पास भेजा गया हो

वह तारीख जब कि सम्मान तामील करने वाले चपरासीको दिया गया हो

सम्मान तामील करने वाले चपरासीके लैटालनेकी तारीख

वह तारीख जब कि सम्मान मागिरने अदालतको लौटाया हो

सिविल प्रोसेस नं० १४३

उन कर्ज क़र्वाहोंकीफ़िहरिस्त जो कि तस्फ़ीया या तय करने वाली स्कीम पर
विचार करते समय होवे

दफा ३८ (२) प्रान्तिक क़ानून दिवालिया

य अदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज महादुर जि०.....

दरखास्त दिवालिया न०

सन् १९ ई०

सीटिंग

ता०

सन् १९ को हुई

मन्दी	उन सब कर्जक़र्वाहोंके नाम जिनके मुद्दत माने जानुके हैं	यहाँ यह दिखलाना चाहिये कि किन २ कर्जक़र्वाहोंमें बंट दिये हैं सगा क़र्वाहोंमें बंटस्वयं दिये हैं या बकीलके जरिये	असासा (लहनेकी सादाद)	साबित किये हुए कर्जोंकी तादाद

यह सत्या जो बहुमतके किये आवश्यक है.....

आवश्यक तादाद

ह०

सिविल प्रोसेस नं० १४४

कर्जक़र्वाहोंको बहाल होने की दरखास्तकी सूचना

दफा ४१ (१) प्रान्तिक क़ानून दिवालिया

य अदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज महादुर जि०.....

सुकदमा दिवालिया न०

सन् १९ ई०

.....सायल

तुमको इत्तला दी जाती है कि अब दिवालियाने इस अदालतमें अपने बहाल (Discharge) किये
जानेकी दरखास्त दी है और अदालतने ता० सन् १९ वक्त यज्ञे यस
दरखास्तको सुननेके लिये नियत किया है ।

आज

तारीख

सन् १९

ई०

द० जज

नोट :—इस फार्मकी पुस्त पर दफा ४२ (१) में बतलाये हुए नियम दिये जाना चाहिये ।

सिविल प्रोसेस नं० १४५

आपन्दा होने वाली आमदनी या मिलने वाली जायदादके सम्बन्धमें शर्त लगा कर
बहाल होनेका हुक्म दिया जाता

दफा ४१ (२) (ए), (बी), या (सी) प्रान्तिक कानून दिवालिया

अदालत साहय डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०

मुकद्मा दिवालिया नं०

सन् १९

ई०

... .. सायल

दिवालियेके दरखास्त देने पर जो कि तारीख सन् १९ को
देवालिया करार दिया जायका है तथा रिसीवरकी रिपोर्ट पर विचार करनेके बाद व कर्जदारानके
उनके बाद यह हुक्म दिया जाता है कि दिवालिया मजकूर (ए) बहाल किया जावे ।

या (बी) तारीख बहाल किया जावे । या (सी) आपन्दा होने वाली
आमदनी या मिलने वाली जायदादके सम्बन्धमें जो शर्तें दी हुई हैं उन शर्तोंके साथ बहाल किया जावे ।

दिवालियेकी धारदा होने वाली आमदनी या मुनाफा अथवा मिलने वाली जायदादसे सुरक्षित
रहना साक्ष्य उसकी तथा उसके परिवारकी परवरिशके लिये निकालनेके पक्षवात् यादों की रचना बचे (या
इस अवस्था की खालि हिस्सा) वह अदालत या आर्कोर्ट रिसीवरको उसके कर्जदारानमें तकलीफ करनेके
लिये दे दिया जावेगा । दिवालिया हर साक जमवारीकी पक्षी तारीखको या उसके १४ दिनोंके अन्दर हुक्म
दिया अदालतमें दाखिल करेगा जिसमें उसकी आमदनी आपन्दा होने वाली जायदाद तथा साल मर्क
आमदनीका हाल दिखलाया जावेगा और इस दिवालेके अनुसार जिस कदर बचनका रूपया उसे अदालत
दाखिल करना चाहिये वह रूपया अदालतमें दाखिल किया जावेगा या रिसीवरको दिया जावेगा यह हरमा
दिया दाखिल होनेके १४ दिनोंके अन्दर दाखिल हो जाना चाहिये ।

तारीख

सन् १९

ई०

द० जज

सिविल प्रोसेस नं० १४६

कर्ज साधित किया जाना—आम तारीख

दफा ४९ प्रान्तिक कानून दिवालिया

अदालत साहय डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०

दरखास्त दिवालिया नं०

सन् १९

ई०

... .. सायल

में मुकद्मा नं० सन् १९ में हलफ लेता हूँ (या हलफिया व ठीक तीसरे बयात
करता हूँ) कि दिवालियेकी दरखास्त दिये जावे
वाली तारीख अर्थात् ता० सन् १९ को कर्जदार मेरा
कर्जदार या और अर को वापस र० के मेरा मही तीसरे कर्जदार है यह कर्ज हम दरखास्तके साथ

दाखिल किये जाने वाले हिस्साबमें दिखलाया गया है तथा यह कुछ कर्ज़ या इसका कोई हिस्सा मुझे या मेरे किसी आदमीको मेरे हकमें वसूल नहीं हुआ है और न उसके लिये कोई जमानत ही दी गई है सिवाय नीचे दिये हुए रूपों या जमानतके.....

रूपोंके लिये बंद
भाला गया }

इलक की जाने वाली जगह
तारीख
किसके सामने

{ इलकनामा दाखिल करने
वालेके दस्तखत

द० जज या आफिशल रिसीवर

द० कमिश्नर

सिविल प्रोसेस नं० १४८

रिसीवरके नियुक्ति का हुकम

दफा ५६ प्रान्तिक क्रानून दिवालिया

बम्बदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०

समुकदमा दिवालिया

नं०

सन् १९ ई०

शुद्धि सुसम्मी

इस अदालतके हुकमके अनुसार ता०

सन् १९ ई०

को दिवालिया करार दिया गया है और अदालतको यह प्रतीत होता है कि दिवालिया मजकूरकी जायदादके लिये रिसीवर नियुक्त किया जावे इसलिये दिवालियेके बिन्दु जायदादकी वसूलीका हुकम दिया जावे तथा जायदादकी वसूलीका हुकम दिया जाता है और (या आफिशल रिसीवर) दिवालिया मजकूर की जायदादके लिये रिसीवर नियुक्त किया जाता है और यह भी हुकम दिया जाता है (यदि वह आफिशल रिसीवर न होवे तो) कि रिसीवर मजकूर रूपोंकी जमानत दाखिल करे और उसका श्रमफल (Remuneration) प्रति सैकड़ा नियत किया जावे :-

तारीख

सन्

ई०

द० जज

सिविल प्रोसेस नं० १४८

अन्तिम हिस्सा रसदी पाटनेका नोटिस जो कर्जब्याह बतलाये जाने वाले लोगोंको दिया जाना चाहिये ।

दफा ६४ प्रान्तिक क्रानून दिवालिया -

बम्बदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०

समुकदमा दिवालिया नं०

सन् १९ ई०

..... साबल

तुमको इतिला दी जाती है कि ऊपर बतलाये हुए मामलोंमें अन्तिम हिस्सा रसदी (Final Dividend) बंटे जानेका विचार है और यदि तुम अपना मतालिख ता० सन् १९ तक या उससे पहले अदालतमें संतोषजनक रूपसे साबित नहीं करोगे (या उस तारीख तक जब तक कि मोहलत अदालत दे देवे) तो तुम्हारा दावा खारिज समझा जावेगा और तुम्हारे दावेका कित्ता लिहाज किये हुए मैं अन्तिम हिस्सा रसदी बंट दूंगा ।

तारीख

सन् ई०

द० रिसीवर (पता)

सिविल प्रोसेस नं० १५०

कर्जद्वाराहानको सरसरीकी कार्यवाहका नोटिस

दफा ७४ प्रान्तिक कानून दिवालिया

बमदात्म सादर डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०

मुकदमा दिवालिया न०

सन् १९

..... साधक

तुमको इसला दी जाती है कि एक कर्जदारने वा० सन् १९ को एक दरवास्त
 इस अदालतमें दिवालिया करा दिवने जानेके लिये दी है और अदालतको वा० सन् १९ को
 इस बातका यकीन कर लिया है कि कर्जदार मजकूरकी जायदाद मुकल्लिग ५०० रुपयेके जायद नहीं है और
 इसलिये अदालतने यह हुक्म दिया है कि दरवास्त मजकूर सरसरी तौर पर सुनी जाये और अदालतने वा०
 सन् १९ दरवास्त मजकूरकी मजिद समातके लिये मुकदर की है और उसी तारीख पर कर्जदारका
 ध्यान भी दिया जावेगा ।

तुमको इस बात की भी इतिला दी जाती है कि यदि अदालत चाहिगी तो इसी तारीख पर कर्जदार
 मजकूरको दिवालिया कार दे देवेगी तथा कर्जदार मजकूरके लहनेको तकसीम कर देवेगी । तुमको अधिकार है
 कि तुम इस तारीख पर हाजिर हो तथा अपनी शहादत पेश करो । यदि तुम कोई कर्ज साबित किया चाहो तो
 वसका सुन तुमको इस तारीखसे पहिले या इस तारीख तक अवश्य दाखिल अदालत कर देना चाहिये ।

मेरे दस्तखत व अदालतकी मोहर होकर
 जारी किया गया ।

आज वा०

सन् १९

है०

द० जज

इलाहाबाद हाईकोर्ट रूलस

दफा ७९ प्रान्तिक कानून दिवाला सन् १९२० ई के अनुसार
बनाये हुए नियम

दफा ७९ प्रान्तिक कानून दिवालिया सन् १९२० ई० के अनुसार गवर्नमेंन्ट की आज्ञा लेनेके पश्चात्
सन् १९११ ई० के जनरल सिविल रूलस (General Civil Rules) में निम्नलिखित संशोधित किये गये हैं।

सेक्शन २६ में दिये हुए नियमोंके स्थान पर निम्नलिखित नियम समझना चाहिये

१. इन नियमोंको आगरा प्रान्तिक दिवालिया नियम (The Agra Provincial Insolvency Rules) कहा जावेगा। काम नं० १३८ से लेकर १५२ तकका प्रयोग समयावृत्त परिवर्तनके साथ इन मामलोंके लिये किया जावेगा जिनमे कि उनका अलङ्घन अलङ्घ्य सम्भव होवे।

२. दिवालियेकी हर एक दरखास्त (Petition) उम रजिस्ट्रमें चढ़ाई जावेगी जो दिवालिये या काम करके बाकी अदालतें दिवालियेकी दरखास्तोंके लिये रखेंगी और उनमें तर्तीबी संख्या (Serial Number) दी जावेगी तथा उसके बादकी सब कार्रवाइयोंमें जो इसी मामलेके लिये की जावेगी वही नम्बर डाला जावेगा।

३. दिवालियेके सम्बन्धकी सब कार्रवाइयोंका सुभाषना उन समयों पर तथा उन नियमोंके अनुसार किया जासकता है जिनके अनुसार कि अदालतकी दूसरी सिमिकोंका हो सकता है यह सुभाषना रिसीवर, कर्जदार, व वह कर्जस्वाह जो अपने कर्जोंको साबित कर चुका हो या उनके वकीली नुमायन्दे (Legal representative) कर सकते हैं।

नोटिस

४. जब किसी नोटिस या किसी दूसरे मामलेका इस एक्टके अनुसार सरकारी गजटमें प्रकाशित किया जाता बतलाया गया हो या इस एक्टके अनुसार बनाये हुए नियमोंके आधार पर कच्चा किसी स्थानिक समाचार पत्रमें प्रकाशित किया जाना बतलाया गया हो तो एक याददाश्त (Memorandum) जिसमें कि प्रकाशित होना बाकी तारीख व गजटका हवाला दिया हुआ होगा मिलिके साथ निकाल कर दी जावेगी और उसका इन्टरजक्टिव ऑर्डर (Order Sheet) में भी कर दिया जावेगा।

५. दफा १९ (२) के अनुसार निदेशनके सुननेकी तारीख नियत किये जाने वाले हुक्मका नोटिस प्रान्तिक सरकारी गजटमें प्रकाशित किये जानेके अतिरिक्त उन दूसरे समाचार पत्र व पत्रागम भी प्रकाशित किया जावेगा जिनमें अदालत आज्ञा देवे। नोटिसकी एक एक नकल सब कर्जस्वादोंके पास राजस्त्री खतके द्वारा उस पतेसे पहुँचाई जावेगी जो दरखास्त (Petition) में दिया हुआ हो। वही तरीका उन नोटिसोंके लिये उपयोगमें लाया जावेगा जो दफा ३ - (१) के अनुसार सरकारी या स्कूल पर विचार करनेके सम्बन्धमें दिये जावेगे।

६. दफा ३० के अनुसार दिवालिया करार दिये जाने वाला हुक्म प्रान्तिक सरकारी गजटमें प्रकाशित किये जानेके अतिरिक्त जैसा कि एक्टमें बतलाया गया है उन दूसरे स्थानिक अखबार या अखबारोंमें प्रकाशित किया जावेगा जैसा कि अदालत उचित समझे। यदि कर्जदार सरकारी मुलाजिम होवे तो हुक्मकी एक नकल

उस आफिसके सचिव बड़े हाकिम (Head of the office) के पास भेजी जावेगी जहा कि वह काम करता हो। यह तरीका उन नोटिसों व हुजूमोंके सम्बन्धमें प्रयोग किया जावेगा जो दफा ३७ (२) के अनुसार दिवालिया करार दिये जाने वाले हुजूमकी मसूचीके सम्बन्धमें दिये जावें।

७ दफा ५० के अनुसार जो नोटिस अदालत द्वारा जारी किये जावेंगे उनकी तामील कर्जदारों पर या उनके वकीलों पर की जावेगी या वह बजरिये रजिस्ट्री खतके भेजे जावेंगे।

८ दफा ६४ के अनुसार रिसीवर अन्तिम हिस्सा रमदी (Final Dividend) बाटनेसे पहिले जो नोटिस उन कर्जदारोंके नाम जारी होगा जिनका कर्जदार होना घोषित किया जा चुका है परन्तु जिनके कर्ज साबित नहीं किये गये हैं वह नोटिस रजिस्ट्री खत द्वारा डायरानेमें भेजे जावेंगे।

९ बहालकी दरदवास्त (Application for Discharge) सुननेकी तारीखके नोटिस जो दफा ४१ (१) के अनुसार दिये जावेंगे प्रान्तिक सरकारी गजटके अतिरिक्त उन समाचार पत्रोंमें प्रकाशित किये जावेंगे जिनके लिये आज आशा देवे और उनकी नकलें सब कर्जदारोंके पास रजिस्ट्री कार्रके जरिये भेजी जावेगी चाहे उन्होंने अपना कर्ज साबित किया हो या न साबित किया हो।

१०. यदि पिछले नियमोंमें बतलाये हुए नोटिसोंके सम्बन्धमें डाकखानेकी रसीद दाखिलकी जावे तथा अदालतके किसी अकम या अफिसल रिसीवरका सर्टीफिकेट या किसी अन्य रिसीवरका हलफनामा इस बातके लिये होवे कि नोटिस नियम पूर्वक दिये गये हैं तो यह इस बातकी काफी गवाहदत मानी जावेगी कि नोटिस जिसके पहले भेजे गये हैं उसको ठीक तौरसे भेजे गये हैं।

११. प्रकाशनके निर्धारित नियमोंके अतिरिक्त अदालतकी आज्ञानुसार नोटिस अन्य किसी रूपसे भी प्रकाशित किये जा सकते हैं जैसे कि अदालतकी इमारतमें उनकी नकलें चिरकरा देनेसे अथवा जिस गावमें दिवालिया रहता हो वहा मुनादी करा देनेसे।

रिसीवर

१२. रिसीवरकी नियुक्तिका हुजूम लिखकर अदालतके इन्स्पेक्टरोंसे दिया जावेगा। इस हुजूमके नकलकी तामील अदालतकी मोहर होकर कर्जदार पर की जावेगी तथा वह नकल जितनी किये हुए व्यक्तिके पास भी भेजी जावेगी।

१३. (५) अदालतकी चाहिये कि वह रिसीवरका भ्रमफल (Remuneration) नियत करते समय अधिकतर उसे कमीशन या फी सैकडाके हिसाबसे नियत करे जिसमेंसे कि एक भाग महफूज कर्जदारों (Secured Creditor) को जमानत (Security) के रुपये निकालनेके बाद जो रुपया वसूल किया गया हो उसके हिसाबसे मिलना चाहिये तथा दूसरा भाग उस इकमके हिसाबसे मिलना चाहिये जिसे कि वह हिस्सा रसदी (Dividend) के रूपमें तकसीम करे।

(६) जब कि रिसीवर महफूज कर्जदारोंकी जमानत (Security) का रुपया वसूल करे तो अदालत उसे उस कामके हिसाबसे तथा उससे होने वाले कर्जदारोंके लाभको देते हुए और अधिक भ्रमफल (Remuneration) दिला सकती है।

१३. रिसीवर रोकड़ घड़ी या अन्य हिमायकी कितने तथा कागजात रखेगा जिससे जायदाद सम्बन्धी उसके प्रत्येक एक शीक शीक जान हो और वह हिसाब किताब वन समयों पर तथा वस प्रकार दायित्व करेगा जिस प्रकार कि अदालत हुकम देवे । उन हिमायकी जाच वह लोग करेंगे जिनके लिये अदालत हुकम देवे । हिमायकी जाच (Audit) का खर्च अदालत नियत कर देंगा तथा वह खर्च दिवालयिकी जायदादमें दिलाया जावेगा ।

१५. अधिकतर रिसीवर वह सब रुपये जो वह वसूल कर सरकारी खजानेमें जमा करेगा या जहाँ किसी खास राजहमे रुपये किसी बैंकमें जमा किया जावे जिसके लिये कि अदालतने स्वीकृत देदी हो जो बंधी हुई रकम (Fixed Deposit) में जिस पर कि ब्याज आता हो जमा किया गया हो तो ब्याज को रुपये दिवालयिकी जायदादमें जमा किया जावेगा ।

१६. रिसीवर उन सब मामलोके जाय दायका हिसाब जिनम कि वह रिसीवर नियुक्त किया गया हो हर तिमाहीके तिमाही अदालतमें दाखिल करेगा और यह हिसाब तिमाही समाप्त होनेके बाद वाले महीनेकी १० तारीखसे पहिलेही दाखिल कर दिया जावेगा ।

१७. जबकि रिसीवरके हाथमें दिवालयिकी जायदाद का कोई रुपया न होवे और वह किसी कर्जवाह से रुपयेकी मदद लेव तो उसको बोलिये कि यह रुपये दिवालयिकी जायदादके हिसाबमें दिखलावे ।

१८. वह कर्जवाह जो अपना कर्ज माहित कर चुका है अदालतमें हम बातकी दुरावास्त दे सकता है कि उसको रिसीवरके कुछ हिसाब या उसके किसी हिस्सेकी नकल दी जावे जिसका कि सम्बन्ध दिवालयिकी जायदादसे होवे और जो कि रोकड़ पहिले उस वन तक दिखलाया गया हो । यह नकल उसको वह खर्च अर्दी करने पर दी जावेगी जो अदालतके नियमोंके अनुसार नकलोंको प्राप्त करनेके लिये बतलाये गये हैं पेसी नकलों के लिये किसी कोर्ट फीसके अदा करनकी आवश्यकता नहीं है ।

१९. यदि किसी मामलेमें कर्जवाहोंके मीटिंग (Meeting) की आवश्यकता होवे और यदि किसी मामलेमें कर्जदार तरफ़ीया या तय किये जानेकी स्कैम (Scheme) रफ़ा ३८ के अनुसार चाहता हो तो रिसीवर कमसे कम १४ दिन पहिले नोटिस कर्जदार व सब कर्जवाहोंको मीटिंगके समय व स्थानके लिये देगा ऐसे नोटिस रजिस्ट्री प्लत द्वारा भेजे जावेंगे ।

कर्जोंका साधित किया जाना

२०. कर्जवाहोंका सुवृत अयोगिडक्स (Appendix) में दिये हुए फार्म न० १३३ के अनुसार समयानुसूत परिवर्तनके साथ दिया जायकता है । इसी फार्म न० १३३ इसी दार्इकोर्टका ।

२१. यदि किसी मामलेमें कर्जदारके बयानसे यह मालूम हो कि उसके कारीगरो या दूसरे काम करने वालोंकी उगरत (Wages) के बहुतसे दावे हैं तो उन सबके लिये अकेले कर्जदार ही का सुवृत या वन सब कर्जवाहोंकी तरफसे किता एक ब्याक्ति का सुवृत पर्याप्त समझा जावेगा इस प्रकार का सुवृत अयोगिडक्स (Appendix) में दिये हुए फार्म न० १३३ के अनुसार होना चाहिये ।

यदि कर्जदार कोई फर्म होवे तो उसका तरफ़ी

२२. यदि किसी सूचना (Notice) देलान (Declaration) दस्तवेस्त (Petition) या किसी दूसरी दस्तवेजके तम्बूक (Attestation) की आवश्यकता हो तब उस पर किसी कर्जवाहों या कर्जदारों

के फर्मके दस्तावेज फर्मके नामसे किये जायें तो जो हिस्सेदार फर्मकी ओरसे दस्तावेज करे उसको अपने मालिक दस्तावेज करना पड़ेगा जैसे कि "प्राउन एन्ड कम्पनी वरियर जेम्सग्रिन" एक शरीकदार फर्म भेंट कर ।

२३. यदि किसी सूचना (Notice) या दारवास्तकी तामील जर्ती तौरसे होना आवश्यक हो और उसकी तामील अदालतकी अधिकार सीमा (Jurisdiction) के बन्दर् फर्मके खास रोजगारकी जगह पर फर्मके किसी शरीकदार पर या फर्म का प्रबन्ध करने वाले या देख रेख करने वाले ब्यक्ति पर की गई हो तो यह मान लिया जावेगा कि उसकी तामील बाकायदा फर्मके सब शरीकदारों पर हुई है ।

२४. पिछली दफामें बतलाया हुआ नियम जहाँ तक मुमकिन होगा वुम मामलोंमें भी लागू होगा । जब कि कोई ब्यक्ति अपने नामके बजाय किसी दूसरे नामसे अदालतकी अधिकार सीमामें कारांवार करता हो ।

२५. यदि कर्जदारोंका कोई फर्म दिवालकी दरखास्त देवे तो उस दरखास्तमें फर्मके सब शरीकदारोंके पूरे पूरे नाम होंगे और यदि उस दरखास्त पर फर्मकी ओरसे किसी एक शरीकदारने दस्तावेज किये हों तो वम दरखास्तके साथ उस शरीकदारको एक हलफनामा भी इस बातका छगाना पड़ेगा कि फर्मके सब शरीकदारोंकी राय वम दरखास्तकी देनेके लिये है ।

२६. यदि किसी कर्जदारने दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म दिया जावे तो यह समझा जावेगा कि फर्मके वह सब शरीकदार जो हुक्म दिये जाते हैं शरीकदार थे दिवालिया करार दे दिये गये हैं ।

२७. साझे मामलोंमें कर्जदार साझे मामलोंके सम्बन्धकी सूची (Schedule) पेश करेंगे तथा हर एक कर्जदार अपने अलहदा अलहदा मामलोंकी सूची भी पेश करेगा ।

२८. संयुक्त कर्जवाह तथा कर्जवाहोंके अलहदा अलहदा समूह अलग तस्फीया या तय होने की स्कीमकी स्वीकार कर सकते हैं । जहाँ तक मुमकिन होगा संयुक्त कर्जवाहों द्वारा स्वीकृत हुआ प्रस्ताव ही निर्धारित रूपसे संजूर किया जावेगा बिना इस बातका स्थाक किये हुए कि किसी कर्जदार या कर्जदारोंके जुदागाना कर्जवाह या कर्जवाहोंने उस तस्फीया या स्कीम (Scheme) को स्वीकार नहीं किया है ।

२९. यदि तस्फीया या स्कीमका प्रस्ताव फर्म द्वारा किया गया हो और वम फर्मके शरीकदारोंने अलहदा अलहदा तौरसे भी किया हो तो संयुक्त कर्जवाहोंके लिये किये हुए प्रस्तावों पर विचार किया जावेगा और उन पर उनके वोट लिये जावेंगे वम समय अलहदा कर्जवाहोंके समूहोंका अलहदा ध्यात नहीं दिया जावेगा और जो प्रस्ताव कर्जवाहोंके किसी खास समूहके लिये किया गया हो उस पर वह समूह अलहदासे विचार करेगा व वोट देगा कुल कर्जवाहोंसे उसका सम्बन्ध नहीं होगा । यह प्रस्ताव भिन्न भिन्न रूपसे तथा भिन्न भिन्न रादादके लिये किये जासकते हैं । जब कि तस्फीया या स्कीम स्वीकार कर ली जावे तो दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म वमी इद तक मंसूख होगा जहाँ तक कि उसका उस जायदादसे सम्बन्ध है जिसके कर्जवाहोंने तस्फीया या स्कीमको मान लिया है ।

३०. यदि किसी बराकती फर्मके दो या दो से अधिक मेसजान कोई जुदागाना फर्म चलाते हों तो उस जुदागाना फर्मके कर्जवाहान एक जुदागाना कर्जवाहोंका समूह समझे जावेंगे और वह वमी प्रकार समझे जावेंगे जैसे कि किसी शरीकदारके अलहदामे कर्जवाहान होवे यदि ऐसे जुदागाना फर्मके लट्टने (Assets)

से कोई फ़ाजिल रकम बचे तो वह उस फ़र्मके शरीकदारोंमें हिस्सा रसदीके हिसाबसे उनके हिस्सेके अनुसार उनकी श्लहदाकी जायदादमें खे बाँट जावगी।

दरखास्तें व नोटिस

३१ (ए) यदि इन नियमोंमें कोई बात अथ प्रचारसे न चललाई गई हो अथवा अदालत किसी खास मामलेमें कोई अन्य हुकम न देवे तो अदालतमें दी जाने वाली वह सब दरखास्तें लिख कर दी जावंगी तथा उनकी ताईदमें मायल का हलफनामा भी दाखिल होगा जो कि रिसीवर द्वारा या किसी कज़ेवाइ द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी जावे जो कज़ेदारके लहजेमें अपने को हुकद्वारा बतलाया हो या रिसीवरके किसी काम की शिकायत करे और जो खास कर इन नियमोंकी बिल अवहेलना किये हुए दफा ४, ५१, ५२, ५३, ५४ व ५५ के अनुसार हुकम दिये जानेके लिये दी गई हो।

(बी) जिस हुकम या दादरसीके लिये दरखास्त दी जावे उसका उल्लेख पूर्ण रूपसे हर दरखास्त में किया जावेगा उनमें इस पुकटकी दफाओंकी जिनके अनुसार दरखास्त दी गई हो तथा उन बग़ाँ का जिनके कारण वह हुकम या दादरसी खासे जाती हो तथा अन्य किसी पुकटकी दफाओं का भी जिनके आधार पर दरखास्त दी गई हो उल्लेख किया जावेगा।

(सी) इस प्रकारकी हर एक दरखास्तमें यह भी लिखलाया जावेगा कि भाया सायल दरखास्त की ताईदमें गवाहान लख किया जाइता है या नहीं और उसमें ~~यह भी लिखलाया जावेगा कि~~ भी लिख दगा जिनके कि वह आधार मानना हो।

(डी) यदि रिसीवरके अतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्ति इस प्रकारकी दरखास्त देवे तो उस दरखास्त की नकल तथा उसकी ताईदमें दिये हुए हलफनामकी नकलकी तामील रिसीवर पर की जावगी और उन दस्तावेजोंकी नकल भी जिनका जिक्र ऊपर की (सी) क़ानूनमें किया गया है उसको दी जावेगी परन्तु यदि दस्तावेज बहुत सी हों अथवा बहुत बड़ी हों तो अथवा उनकी नकल अग़नेके नोटिस द्वारा रिसीवरको उनके बारेमें बतला दिया जावेगा और रिसीवरको दरखास्त सुन जानेस पहिले पूरे सत्त दिन का मौज़ा असल दस्तावेजोंका मुनायमा करनेके लिये दिया जावेगा।

(ई) यदि ऐसी दरखास्त रिसीवर द्वारा दी जावे तो उसकी ताईदमें जो हलफनामा लगाया जावेगा उसमें कज़ेदारके इस बयानका हवाला होगा जो या सा मिथिलमें दामिल होवे या रिसीवरके कज़ेमें होइ तथा जिसके आधार पर रिसीवरने दरखास्त दी हो।

(एफ) दरखास्तके हर एक फ़रीककी अधिकार होगा कि वह असल दस्तावेजका मुनायमा कर सके जो कि या तो दाखिलकी गई हो या दरखास्तकी ताईदमें दिये हुए हलफनामामें जिसका उल्लेख होव या जिसकी प्रकृष्टका हवाला हलफनामामें दिया गया हो।

(जी) उपदफा (ए) में बतलाई हुई ~~एक~~ दरखास्त व हलफनामके नकलकी तामील रिसीवर पर की जावेगी चाहे रिसीवरके विरुद्ध कोई हुकम या दादरसी चाही गई हो या न चाही गई हो।

दिवाखियेकी ग़ैरमनक़ूला जायदादका बेचा जाना

३२ यदि कोई रिसीवर नियुक्त न किया गया हो और अदालत स्वयं इस पुकटकी दफा ५८ के अनुसार दिवाखियेकी ग़ैरमनक़ूला जायदादको बेचे तो उस जायदादके लिये दस्तावेज बयानामा ख़रीदार अपने खर्चमें

‘या’ कायदा और अदालत हाकिमक दस्तखत उस पर हाने यदि रजिस्टा कर नेमें कोई खर्च पड़ता तो
उस भी खरादर वरदान्त कराया ।

१३ दिव्या रसीद का हप्ता (Dividend) वरदाह (Creditor) क प्रार्थना करने पर तथा
किसी निम्न गरी पर डाक जमिये भेजा जा सकता है ।

सरसरी की कारवाही

१४ यदि दफा ७४ क अनुसार किसी जायदाद का इन्तगाम सरसरी तोले किये जानेका हुक्म
होए तो अदालतक खास हुक्मों का ध्यान रखते हुए इस एक्ट के नियम तथा वह नियम निम्न प्रकार
मन पित हा जावेग ।

- (१) किसी कारवाई का प्रकाशन प्रान्तिक सरकारी गजट या म. य किसी समाचार पत्रमें महकिया जावेगा ।
- (२) दरवास्त (Petition) पर तथा बाहरी खर्च कारवायोंमें सरसरी का मामला (Summary Case) लिख दिया जावेगा ।
- (३) कौन बाहरी का दरवास्त (Petition) क सुन जानेकी सूचना (Notice) अर्गण्डिस (Appendix) के काम नं० १५१ के अनुसार दी जावेगी ।

~~(४) कौन कारवाई का घटान उसके मामलोंके सम्बन्धम लगी परन्तु वह कसेवाओं की मीटिंग
(Meeting) करने के लिये समीचीन नहीं है आ कारवायों को टुक होना कि इसकी सुनवाई की
जावे उम्मा वह कारवायों निरह कर सकें)~~

(५) अधिकतर रिसीवरके नियुक्त किये जानेकी आवश्यकता न होगी और अदालत द्वारा
अनुसार कारवाई कर सकती है जिसमें कि दिवालिघा के कारवायोंमें खर्च कम हा जावे ।

खर्च

१५ उन खर्च कारवायों का खर्च जो दिवालिघा के लिये दिये जायके हुक्म तथा जिसमें दिवालिघा
कारार दिये जाने का हुक्म और शामिल है कारवाई करने वाला व्यक्ति हर रकम परन्तु नव दिवालिघा वरार
दिये जाना बाका (Adjunction) हुक्म हा जावे तो दरवास्ता वेच वाल कनवराह का खर्च खर्च
दिवालिघा की जायदादसे दितवया जावेगा ।

१६ यदि तस्फीया या स्कीम अदालत द्वारा स्वीकार न की जावे तो तस्फीया या स्कीमकी
दरवास्तक किये तथा उसके सम्बन्धम किये हुए कनवराह खर्चका जामदादत नहीं दिवाया जावेगा ।

१७ यदि कौनवरीक खर्च दरवास्त दोर पर वह दिवालिघा करार दिया गया हो और अदालत
विस्मय हो जाय कि वह प्रान्तिक सरकारी गजटमें उपबानि जाये का खर्च तथा एक्ट की दफा १० में वतकय
हुए नोटिस का खर्च वदालत में ही कर सकता है तो अदालत इस बात का हुक्म दे सकती है कि उसका खर्च
दिवालिघा की जायदादकी वीमत्तम अदा किया जाये । यदि दिवालिघा पास कोई जायदाद न होवे अथवा उस
जिन्दाकी कीमत न काफी होवे तो उसका खर्च या न बसूक दिया जा सके वाला मलकियत गण कर दिया जावेगा ।

फार्म नं० ६

रिसीवरकी नियुक्ति का हुक्म

दफा ५६ क्रानून दिवालिया सन १९२० ई०

य अदालत साइब डिस्ट्रिक्ट जज महादुर जि०

य मुकद्दमा दिवाकिया

न० सन् १९ ई०

धुंकि (नाम दिवालिया) अदालतके हुक्म द्वारा तारीख सन् १९ ई० को दिवालिया करार द दिया गया है और अदालतको यह अचित्त प्रतीत होता है कि दिवंगतये मजकूरकी लायदादके लिय रिसीवर नियुक्त किया जावे अतः यह हुक्म दिया जाता है कि रिसीवरके सिद्ध वसूलीक हुक्म दिया जावे और दिवालिये मजकूरके विरुद्ध रिसीवरको हुक्म दिया जाता है और (या आफिशल रिसीवर) दिवालिये मजकूरकी लायदादके लिये रिसीवर नियुक्त किया जाता है और यह भी हुक्म दिया जाता है (यदि आफिशल रिसीवर नियुक्त न किया गया हो) कि रिसीवर मजकूर तरकी अमानत दायिल करे और उसका अमफल (Remuneration) हिलाबसे हासल ।

तारीख

सन् १९

ई०

द० जज.

फार्म नं० ७

पजौका सुदूत (Proof of Debts)

आम तरीका (दफा ४९ क्रानून दिवालिया)

उनवान (Title)

य अदालत साइब डिस्ट्रिक्ट जज महादुर जि०

हरकबास्त दिवालिया न०

सन् १९ ई०

..... सायल

मानला नम्बरी

(यहाँ पर नोटिसका नम्बर डोना पादिये) सन् १९ ई० में

(नाम व पता) हलफसे कहता हूँ (या ईमानदारी व दिलसे बयान करता हूँ)
 कि (नाम व पता कर्जदार) तारीख सन् १९ ई० को मेरा
 (लादाद) रुपयेका कर्जदार या व अब भी है जिसकी तकसील इसके साथ दाखिल किये
 जाने वाले हिसाबमें दिखलाई गई है इस रुपयेका कोई हिस्सा मुझ या मेरी ओरसे किसी आदमीको वसूल नहीं
 हुआ और न उसको कोई अमानत दी हुई है सिवाय नीचे दिये हुए रुपयेके

घोटेकलिये जो लादाद रुपयेका मानी गई हो } हलफ जहा की गई हो { हलफ लेने वालेके दस्तपूत
 गज या आफिशल रिसीवर } आज तारीख { कमिशनर
 जिसके सामने हलफ की गई हो }

फार्म नं० ८

मजदूरके कर्जोंका सुवृत्त (Proof of Debts of Workman)

उनधान (Title)

अभिलेखित साक्ष्य डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर सि० - - - - -

दस्तावेज दिवालिया नं०

सन् १९ ई०

----- सायल

मैं (नाम व पता हलफनामा दाखिल करने वालेका) हलफसे कहता हूँ
(या ईमानदारी व दिलसे ऐलान करता हूँ) कि मैं तारीख
सन् १९ ई० को केहरिस्तमें दिये हुए लोगोंका उनके सामने दिखाये हुए दफ्तोंके लिये कर्जदार था व अब भी
हूँ और यह कर्जा उन लोगोंकी मजदूरीके बारेमें है जो उन्होंने किसीबरी नियुक्तिसे पहिले केहरिस्तमें दिखलाये
हुए समय तक हमारे पासकी थी। यह कर्जे या इन कर्जोंका कोई भाग अब तक नहीं चुकाया गया है और न उसके
लिये कोई जमानत दी हुई है।

बोटके लिये जो तादाद रुपया मानी गई हो जब या आकिसक किसीदर	} वह अगर जहा हलफनामा किया गया हो शरीख हलफ लेनेकी जिसक सामन हलफ ली गई हो	{ हलफ लेने वालेके दस्तावेज कमिश्नर

फार्म नं० ६

तस्फीया या तय होनेकी स्कीमका नोटिस जो कर्जस्वाहोंको दिया जाना चाहिये

दफ्ता ३८ (१) प्रान्तिक कानून दिवालिया सन् १९२० ई०

अभिलेखित साक्ष्य डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर सि० - - - - -

दस्तावेज दिवालिया नं०

सन् १९ ई०

----- सायल

हमको इतना ही ज्ञाती है कि अदालत हाजाने कर्जदारके तस्फीयेकी दरखास्त पर विचार करनेके लिये
सारांश सन् १९ ई० नियतकी है। वह कर्जदार जिसका कर्जा एक तारीख तक या उससे पहिले
साबित नहीं हो जायेगा इस तस्फीये पर बोट देनेका अधिकारी नहीं होगा यदि तुम उस तारीख पर हाजिर होना
चाहो तो स्वयं या किसी बकीलके जरिये मय सुन्नेके हाजिर हो सकते हो।

द० जज

फार्म नं० १०

कर्ज़व्याहोंकी फेहरिस्त जो तत्कीया या रसीम पर विचार करने समय बनाई जावे

दफा ३८ (२) प्रान्तिक क़ानून दिवालिया १९२० ई०

मअदालत साइब डिस्ट्रिक्ट जज सहादुर जि०

बसुकरहमा दिवालिया नं०

सन १९ ई०

संदिग्ध तारीख

सन १९

ई० को

(जगहका नाम)

में की गई

नम्बर	उन सब कर्ज़व्याहोंके नाम जिनके कर्ज़ साबित हो चुके हैं	इसमें उन कर्ज़व्याहोंकी दिवखाना चाहिये जिनोंने वोट दिये हैं और यह भी दिखलाना चाहिये कि स्वयं वोट दिये हैं या बरालके जरिये	रहनेकी तादाद	वह तादाद जिनका सुधून माना गया है

बहुमतके लिये होने वाली संख्या

चाही हुई कीमत

रुपये

फार्म नं० ११

अन्तिम हिस्सा रसदी यांजनेसे पहिले कर्ज़व्याहोंको दिया जाने वाला नोटि

दफा ६४ प्रान्तिक क़ानून दिवालिया सन १९२० ई०

मअदालत साइब डिस्ट्रिक्ट जज

बसुकरहमा दिवालिया नं०

सन १९

ई०

..... सायक

तुमको इतना दी जाती है कि उक्त मामलेमें अन्तिम हिस्सा रसदी बांटे जानके लिये तारीख सन १९ ई० नियतकी गई है और यदि तुम उस तारीख पर या उससे पहिले अदालतमें अपना कर्ज़ साबित न कर दोगे या मोहरत दी जाने पर मोहरत वाली तारीख तक न साबित कर दोगे तो तुम्हारा कर्ज़ निकाल दिया जावेगा और उसका बिला स्थाल किये हुए अन्तिम हिस्सा रसदी बांट दिया जावेगा ।

तारीख

सन १९ - ई०

द० रिडीबर

फार्म नं० १२

दिवालिखा करार दिये जाने वाले हुक्मकी मंस्खीका हुक्म
दफा ३७ प्रान्तिक क़ानून दिवालिखा १९२० ई०

..... (नाम व पता दरखास्त देने वालेका) की दरखास्त पर तथा
उसे सुनने व पढ़नेके बाद यह हुक्म दिया जाता है कि (दिवालियेका नाम) के
विश्व दिवालिखा करार दिये जानेका हुक्म जो तारीख सन् १९ ई० को दिया गया था
मंस्ख किया जाने तथा वह मंस्ख किया जाता है ।
तारीख सन् १९ ई० द० जज

फार्म नं० १३

बहाल होनेकी दरखास्तका नोटिस जो क़र्जद्वारोंको दिया जाना चाहिये
दफा ४१ (१) प्रान्तिक क़ानून दिवालिखा १९२० ई०

उनवान (Title)

मुमको इत्तला दी जाती है कि ऊपर बतलाये हुए दिवालियाने बहाल होनेकी दरखास्त इस अदालतमें दी है
और अदालतने इसके सुननेके लिये तारीख सन् १९ ई० नियतकी है ।
तारीख सन् १९ ई० द० जज

फार्म नं० १५

सरसरीकी कार्रवाई (Summary Administration) दफा ७४

उनवान (Title)

मुमको इत्तला दी जाती है कि ऊपर बतलाये हुए कर्जदारने ता० सन् १९ ई० को
एक दरखास्त दिवालिखा करार दिये जानेके लिये इस अदालतमें दी है और ता० सन् १९ ई०
को अदालतने इस बात पर विश्वास कर लिया है कि उक्त कर्जदारकी जायदाद ५०० रुपयेसे अधिक कीमतकी
नहीं है और इसी कारण उसकी जायदादका प्रबन्ध सरसरी तौरसे किया जाना भिश्चित किया है इस अदालतने
तारीख सन् १९ ई० फिर उस दरखास्तको सुननेके लिये नियतकी है और उसी
तारीख पर कर्जदारके भी बयान होंगे ।

मुमको इस बातकी भी इत्तला दी जाती है कि मुमकिन है अदालत इसी तारीख पर उस कर्जदारकी
दिवालिखा करार द देने व उसका लहजा बाट देये । मुम यदि चाहें तो उस तारीख पर हजर होकर गवाहद दे
सकते हो यदि मुम कोई कर्ज साबित किया चाहें तो उस तारीख पर या उसके पहिले साबित कर सकते हो ।

इस अदालतकी मोहर व मेरे दस्तखतमे आज

तारीख सन् १९ ई० को जारी किया गया द० जज

प्रान्तिक कानून दिवालिया १९२० ई० (The Provincial Insolvency Act) के अनुसार जिन वस्तुओं का दिया जाना बतलाया गया है उनमेंसे कुछ नमून नीचे दिये जाते हैं ता कि समयाचित परिवर्तन के साथ प्रयोग किये जा सकें हैं । एक्ट के नियमों का ध्यान रखते हुए दखलाते इन नमूनों के अनुसार विशेष बातों का उल्लेख करते हुए दी जाना चाहिये:—

(नमूनेका फार्म) नं० १

कर्जदार का पिटीशन अर्थात् कर्जदार द्वारा दिवालिया करार दिये जानेकी दखलास्त

वफा १० (१) प्रान्तिक कानून दिवालिया एक्ट ५ सन् १९२० ई०

बध्नायत सादर डिस्ट्रिक्ट जज बदायुन जिले.....

मुकदमा दिवालिया सन् १९ ई०

दखलास्त वफा १० (१) प्रान्तिक कानून दिवालिया १९२० ई०

(नाम) वरद साकिन सायल

सायल निम्नलिखित मार्गना करता है —

१. यह कि म्यागल अधिकतर (निवास स्थान का नाम) का रहने वाला है और अब तक (स्थान का नाम व पता) में व्यापार करता रहा है और यह स्थान इस अदालतकी अधिकारी सीमा में स्थित है ।

२. यह कि सायल को अपने व्यापारमें बड़ी हानि उठानी पड़ी है क्योंकि (यह पता हानि होनेके कारणों का बखलेल दिया जाना चाहिये) व ते वज यह है और इसी कारण सायल पर बहुत सा कर्ज लद गया है ।

३. यह कि सायलको एक व्यापारसे अब कोई लाभ नहीं है और सायलके पास कोई दूसरा लाभका शस्ता भी निशाय (यदि कोई आमदनी का जरिया हो तो उसका बखलेल किया जाया चाहिये) नहीं है और इसी कारण सायल अपना कर्ज चुकानेमें असमर्थ है ।

४. यह कि सायल पर जो इस बात कर्ज हैं वह सब मिलकर इनमेंके हैं (यह कर्ज पांच सौ रुपयेसे अधिकके होना चाहिये कमके नहीं) या

सायल किसी इजराय मन्त्री सन् १९ ई० अदालत मुसिक या (अथ अदालत) सादर

मुकदमा (नाम डिस्ट्रिक्टर) को खिलाफ मुस सायलके है इसके

अनुसार दखलास्त या जेलमें है या

सायलकी जायदाद मुकदमा इजराय मन्त्री सन् १९ ई० (मुकदमें व अदालत का नाम व पता दिया जाना चाहिये) के अनुसार कुंठे किया जायका हुकम हुआ है और यह हुकम अब भी जायदाद सायलके खिलाफ जारी है ।

५. यह कि सायलके कर्जों का ब्योरा इस पिटीशनके साथ दायिलकी जाने वाली सूची ए में दिया हुआ है और उस सूचीमें सब कर्जोंवालों का नाम व पता जहाँ तक सायलको मालूम है व जहाँ तक सायल उनका पता लगा सका है दे दिया गया है ।

६. यह कि सायलकी जायदाद व रुइनेकी तादाद व उसका ब्योरा सूची (बी) में दिया गया है और उस सूचीमें जायदादकी कीमत व उन स्थानों का भी उल्लेख कर दिया गया है जहां पर वह जायदाद स्थित है ।

७. यह कि सायल अपनी सब जायदाद अदालतकी सुपुर्दगीमें देनेके लिये प्रस्तुत है (सिवाय उन चीजोंके जो जायदाद दीवानी या अन्य प्रचालित कानूनके अनुसार कुछ व नौकाम नहीं की जा सकती है परन्तु उनमें हिसाबकी किताबोंको नहीं समझना चाहिये ।

८. यहकि सायलने इससे पहिले कोई दरखास्त दिवालिया करार दिये जानेके लिये नहीं दी है या उसके विरुद्ध कोई दरखास्त दिवालिया करार दिये जानक लिये नहीं दी गई है ।

अथवा

सायलने एक दरखास्त (अदालत का नाम व पता) में दिवालिया करार दिये जानेके लिये दी थी या उसके विरुद्ध दरखास्त दी गई थी और वनके अनुसार सायल तारीख सन् १९ ई० को दिवालिया करार दिया गया था और तारीख सन् १९ ई० को सायल बहाल हो चुका है या दिवालिया करार दिया जाने वाला हुक्म मसूख कर दिया गया था (यहाँ पर अपनी कारवाही दिवालिया की तफसील तथा मसूखी आदिके कारण सब दिखल दिये जाना चाहिये)

अतः कारणोंस सायल सबिनस्य प्रार्थना करता है कि सायल दिवालियर करार दे दिया जाये या अदालत इस सम्बन्धमें कोई दूसरी उचित आज्ञा देनेकी कृपा करे और सायल सदैव इसके लिये कृतज्ञ होगा ।

नाम हस्ताक्षर सायल " " " "

मैं (नाम व पता) तस्दीक करता हूँ कि समझून दफा १ में तक सब मेरे इल्ममें सही है और समझून दफा का सही होना उम इत्तला पर मन्गी (निर्भर) है जो मुझे मिली है ।

तारीख व जगह का नाम नहीं पर तस्दीक इशारतकी गई हो

हस्ताक्षर

(नमूने का फार्म) नम्बर २

कर्जस्वबाह का पिटीशन अथवा कर्जस्वबाह द्वारा कर्जदारके विरुद्ध दी जाने वाली दिवालियकी दरखास्त

दफा १ (१) व १३ (२) प्रान्तिक कानून दिवालिया १९२० इ०

अदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०

मुकद्दमा दिवालिया

सन् १९ ई०

(नाम व पता)

साकिन

..... = सायल

अतः सायल निम्नलिखित प्रार्थना करता है ।

१. यह कि सायल अधिकतर (स्थान का नाम व पता) का रहने वाला है या (स्थान का नाम व पता) में व्यापार करता है अथवा लाभके लिये काम करता है ।

२. यह कि सायल का व्यापारिक सम्बन्ध (दिवालिया करार दिये जाने वाले व्यक्ति का नाम व पता) से इस अदालतकी अधिकार सीमाके अन्दर था या (जम कर्जदार का नाम व पता) जो कि इस अदालतकी अधिकार सीमाके अन्दर रहता करता व्यापार करता है सायलमे सौदा लिया करता था (अथवा अपने सायलमे कर्ज लिया है)

३. यह कि घसिलखिल व्यवहार सायलको उक्त (कर्जदार) से (तादाद) रखा होता है जिते कि उसने जब तक अदा नहीं किया है ।

४. यह कि उक्त कर्जदारने कर्जन्वाहका कर्जों मारनेकी इच्छामे अपना हगोकार बंद कर दिया है या तारीख सन् १९ ई० से अपनी दुकान बंद कर दी है और जम वन्दे कराकर छिपा हुआ है जिसमे कि कोई कर्जन्वाहान उससे पत्र व्यवहार नहीं कर सके या उसने आजकी तारीखसे तीन माहके अन्दर अपनी जायदादको बदनीयतीमे कर्जन्वाहानका कर्ज मारनेकी मन्नामे अकाहिदा कर दिया है (अथवा दफा ९ में बतलाई हुई किमी बातका स्पष्टीकरण दिखलाना चाहिये जिससे कि कर्जदार का दिवालिये का काम साबित हो सके ।

छिद्दाना दूरवास्त हाजा गुश्रान कर उम्मेदवार हूँ कि (१) उक्त कर्जदार दिवालिया करार दिया जावे,

(२) उक्त कर्जदारकी जायदाद पर कब्जा लेनेके लिये दूरवासी रीसीवर नियुक्त किया जावे ।

(३) उक्त कर्जदारसे उसको सब ठिसाबकी किताबें वापिस करवाई जायें व उससे सब कर्जोंकी तहसील गौरा दाखिल कराई जावे ।

इबारत तर्दीक मय सारीख व जगह तर्दीकके की जाना चाहिये ।

तारीख सन् १९ ई० दस्तखत

नोटः—कर्मचारी ताथद ५०० से अधिक होना चाहिये । दूरवास्त कई कर्जन्वाह साथमें होकर भी दे सन्थे हैं ।

(नमूने का फार्म) फार्म नं० ३

दूरवास्त वास्ते वापिस लेने मुकद्दमा (दफा १४)

दूरवास्त हरत्र दफा १४ प्रान्तिक कानून दिवालिया सन् १९२० ई०

अदालत साहय डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर गि० -

मुकद्दमा दिवालिया नं० सन् १९ ई०

..... सायल

अन सायल निम्नलिखित प्रार्थना करता है

१. यह कि मुस सायलने इस अदालतमें तारीख सन् १९ ई० को एक दूरवास्त दिवालिया करार दिये जाने के लिये दी थी । कर्जन्वाहान के नाम नोटिस जारी किये आचुके हैं और दूरवास्त अभी जे तजवीज है (या उसके सुने जाने के लिये ता० सन् नियत की गई है)

२. यह कि वन दूरवास्त को देने के बाद मुस सायलको (नाम व रिकना) से वसीयतन (या अन्य किमी कारण जिसका उल्लेख यहा किया जाना चाहिये) पर्योस्त घन प्राप्त होने की सम्भावना है जिसमे कि सब

हस्ताक्षर

(नमूने का फार्म) नं० ५

दरखास्त हस्त दफा २१ प्रान्तिक कानून दिवालिया १९२० ई०

च अदालत सादर डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०

मुकद्दमा दिवालिया नं०

सन १९ ई०

..... सायल

म (नाम) कर्जवाह निम्नलिखित प्रार्थना करता है

१. यह कि मुझ कर्जवाहने एक दरखास्त लिखा (नाम व पता कर्जदार)

के तारीख सन् १९ ई० को वास्ते दिवालिया करार दिये जानेके इस अदालतमें दी है ।

२. यह कि अदालतने उस दरखास्त को सुननेके लिये तारीख सन् १९ ई०

नियतकी है और दरखास्तकी सूचना नियम पूर्वक कर्जदार मजकूरको मिल चुकी है ।

३. यह कि सूचना पानेके बाद जत कर्जदारने अपनी बर्बा खुची जायदादको कर्जवाहानसे बचानेके लिये अपने रिस्तेदारोंके पास हटा दिया है और वह स्वयं भी इस अदालतकी अधिकार सीमाने बाहर जाने वाला है जिनकी सूचना मुझ कर्जवाहको बिद्वस्त सूत्रसे मिली है और मुझ कर्जवाहको विश्वास भी है कि वह सूचना सच है ।

४. यह कि उक्त कर्जदार का तारीख मुकररा पर हाजिर होना परम आवश्यक है इस कारण मुझ कर्जवाहकी प्रार्थना है कि वक्त कर्जदार वायण्टके जरिये गिरफ्तार किया जावे जिसमें कि वह नियत तारीख पर हाजिर किया जा सके अथवा उससे पचास अमानत उसकी हाजिरीके लिये ली जावे जिसमें कि वह दिवालिया करार दिये जाने वाले हुकम तक अदालतमें शक्ति व आवश्यक अवसरों पर हाजिर हो सके आशा है कि वक्त प्रार्थना स्वीकारकी जावेगी जिसके लिये मैं कर्जवाह बड़ा कृतज्ञ होऊंगा

तारीख सन् १९ ई०

हस्ताक्षर

नोट:— यदि वक्त दरखास्तके लिये अदालतमें विज्ञापित दिखानेके लिये इतफाफाकी आवश्यकता है तो वह भी दाखिल किया जाना चाहिये ।

(नमूने का फार्म) नं० ६

कर्जदार के मुक्त किये जाने के लिये दरखास्त दफा २३

दरखास्त हस्त दफा २३ प्रान्तिक कानून दिवालिया सन १९२० ई०

च अदालत सादर डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर

मुकद्दमा दिवालिया नं०

सन १९ ई०

..... सायल

वक्त सायल निम्नलिखित प्रार्थना करता है

१ यह कि मुझ सायल ने माली इन्तज बहुत खराब होजाने के कारण इस अदालतमें दिवालिया करार दिये जाने के लिये दरखास्त देखली है और वह दरखास्त तारीख सन् १९ ई० को अदालत द्वारा लेली गई थी उस दरखास्त के सुन जान के लिये तारीख सन् १९ ई० नियत हुई है ।

२. यह कि मुझ सायल की वत दरखास्त ल लिये जानेके बाद (नाम डिब्रीदार) ने मुझ सायलको इजराय डिब्री न० इजलासी अपनी सादा रूपयेकी डिब्री गिरफ्तार कराया है मैंने डिब्रीदार मजकूरका नाम अपनी दाखिलकी हुई कर्जवाहानकी फहरिस्तमें दखल दिया है और वनमें उसका कर्ज भी सब दिखला दिया गया है अब मैं उस डिब्रीकी इकलतमें गिरफ्तार हूँ ।

३. यह कि वत डिब्रीदारने मुझ सायल पर नाजायज दबाव डालने व बेजा फायदा उठानेकी गरज मुझ सायलको गिरफ्तार कराया है जिसमें कि उसका कत बमुकामले और कर्जवाहानके वसूल हा सके डिब्रीदार मजकूरको मुझ सायलकी दरखास्त दिवालिय व माली हालत का पूरा इल्म है ।

४. यह कि अगर मैं सायल कौरम आजाद न कर दिया गया तो दरखास्त दिवालियकी पैरवी भली भाँति न हो सकेगी और मुझ सायल का लड़ना भी वसूल न हो सकेगा (मुझ सायलने अपनी सब जायदाद अदालत द्वारा नियत किये हुए रिसविरके सुपुर्दे कर दी है या सुपुर्दे करनेके लिय तैयार है) सायल यह भी चाहता है कि उसके सब कर्जवाहानको हिरसारमदी उसकी जायदादसे मिल सके इसलिये सायल का गिरफ्तारिस मुक्त किया जाना आवश्यक है ।

५. यह कि सायल अपनी दरखास्त दिवालियमें सब बातें दिखला चुका है कि अनायासी इसकी माली हालत गड़बड़ हो गई है व इस पर उसका कोई बस नहीं था ।

६. यह कि सायल अपने मुक्त किये जानेके लिये नियमानुसार अविल जमानत भी देनेके लिये तैयार है व कारणोंसे प्रार्थना है कि अदालत सायलका गिरफ्तारी या जेलमें मुक्त किय जानेकी आज्ञा प्रदान करे या अन्य कोई उचित आज्ञा देनेकी कृपा करे जिसके लिये सायल बड़ा कृतज्ञ होगा ।

तारीख

सन् १९ ई०

हस्ताक्षर

नोट:— आवश्यकतानुसार इल्फनाया भी इस दरखास्तकी तर्जमें लगा देना चाहिये —

(नमूने का फार्म) न० ७

दफा ३१ के अनुसार प्रोटेक्शन आर्डर (Protection Order) की दरखास्त
दरखास्त हस्त दफा ३१ प्रान्तिक कानून दिवालिया सन १९२० ई०

अदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर

मुकदमा दिवालिया न०

सन् १९ ई०

..... सायल

वत सायल निम्नलिखित प्रार्थना करता है

१. यह कि मुझ सायलने इस अदालतमें एक दरखास्त न० सन् १९ ई० दिवालिया करार दिये जानेके लिये दी थी और अदालत द्वारा वत दरखास्तको सुनने व उस पर विचार करनेके बाद मुझ सायलको अपने हुक्मसे तारीख सन् १९ ई० को दिवालिया करार दे दिया है ।

२. यह कि मुझ सायलके एक कर्जवाहाने जिनका नाम दरखास्तके साथ दाखिलकी हुई फहरिस्त कर्जवाहानमें दिखला दिया गया है मुझ सायलके खिलाफ अपने कर्जके लिये अदालतसे

डिफेंस नं० सन् १९ ई० हासिल कर रखी है और अब वह उस डिफेंसकी इजरायमें मुस सायलको गिरफ्तार कराना चाहता है जिसके लिये उसने उक्त अदालतमें दरखास्त दे रखी है जो कि अभी जर तजवीज है ।

१ यह कि मैं सायल अपनी मजदूरीकी वजहसे इस दिवालियेकी दशाको पहुंचा हूं और मुस सायल ने अब तक कोई भी उतमानी अपने कर्जम्बाहान का कर्ज भरणे या किसीको बेना फायदा पहुंचानेके लिये नहीं की है । मुस सायलने अपनी सब जायदाद भा बहुम अदालत तिसीवरकी सुपुर्दगीमें दे दी है ।

२ यह कि ऊपर बतलाये हुए कारणसे मैं सायल किसी डिफेंसमें गिरफ्तार न किया जाना चाहिये और इसीलिये प्रार्थना करता हू कि दफा ३१ प्राप्तिक कानून दिवालियाके अनुसार इस अदालतसे एक हुक्म इस प्रकार का दे दिया जावे कि मैं अपने किसी कर्जकी डिफेंसमें गिरफ्तार न किया जाऊं या कोई अन्य उचित भला दी जावे जिसमें कि मुस सायलको बेना तिसीवर परधान न किया जा सके अपवा कमसे कम ऊपर बतलाई हुई डिफेंसकी इकलतमें गिरफ्तार किये जानेसे बचने का हुक्म दिया जावे ।

तारीख

सन् १९

ई०

हस्ताक्षर

नोट :—आवश्यकानुसार समर्पित हुक्मनामी यी ऐसी दरखास्तके साथ दाखिल करना चाहिये ।

(नमूने का फार्म) नं० =

ज़मानतनामा

अदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर सि०

मुकदमा दिवालिया नं०,

सन् १९

ई०

..... सायल

यूकि उक्त मुकदमेमें अदालतने कर्जदार (नाम व पता) से जिनके विरुद्ध दिवालियेकी दरखास्त पर अदालत विचार कर रही है अन्तिम हुक्म होने तक उसकी हाजिराके बावजूद रुपयेकी जमानत तलबकी है इस लिये मैं अपनी इच्छासे उक्त कर्जदार के लिये जामिनदार होता हूं और इस बातके लिये जिम्मेदारी लेता हूं कि जब कर्जदार अदालतकी आज्ञानुसार जब अदालतमें आवेगी उपस्थित होगा तथा अदालत जिन हुक्मोंको करनेके लिये उसे आज्ञा देगी इनको वह करेगा और यदि वह हाजिर न होवे या हुक्मकी पाबन्दी अन्तिम हुक्म होने तक न करे तो मैं रुपयेके लिये स्वयं व अपने वारिसान व क़यम मुकामानको जिम्मेदार करता हूं और अदालत मुझसे मेरे वारिसान या क़यममुकामानसे रुपये तक जिस तरह पर चाहे वसूल कर सकती है ।

तारीख

सन् १९

ई०

हस्ताक्षर

गवाह (१)

गवाह (२)

(नमूने का फार्म) नं० ६

अर्जी मिनजानिब कर्जदार वावत दिलख जगे हर्जा हस्य दफा २६

दरखवास्त हस्य दफा २६ प्रान्तिक कानून दिवालिया सन १९२० ई०

अदालत साहय डिस्ट्रिक्ट जज बडापुर जि०

मुकदमा दिवालिया नं० सन् १९ ई०

... .. सायल

उक्त कर्जदार निम्नालिखित प्रार्थना करता है

१. यह कि (नाम व पता दरखास्त देने वाले कर्जदार का) ने एक दरखास्त खिलाफ मुझ कर्जदारके इस अदालतमें वाचन दिवालिया करार दिये जानेके दो थी उसने उस दरखास्तमें अपनेको मुझ सायल का एक कर्जदार अर्थात् किया था व बिल्कुल गलत बयानीके साथ दरखास्तको दिया था जो कि बर्दाश्त अदालत सारीख सन् १९ ई० को खारिज कर दी गई है।

२. यह कि दिवालियेकी उक्त दरखास्त बिल्कुल कर्जों व मुझ सायलको परेशान करने व सीडीन करनेकी गरजसे दी गई थी (या इस अवधिमें दी गई थी जिसमें मैं प्रान्तिक व्यवस्थापक सभाका मेम्बर बन सकूँ)

इस लिये सायलकी प्रार्थना है कि मुझ सायलको १०००) रुपया वाचन इन्हीं उक्त दरखास्त बुनिन्दा (कर्जदार) से दिलया जावे क्योंकि उनकी वजहसे मुझ सायलको किराने खर्चा करना पडा है तथा एवामी व निम्नानी कुल्लाम उठाना पडा है या अदालत जो कुल्लाम मुतासिब समझे सादिर कर्माये सायल इसके लिये रका हुवा होगा।

सारीख सन् १९ ई० हरशाकर

इसके साथमें एक हलफनामा भी तस्वीक होकर दाखिल किया जायकता है।

(नमूने का फार्म) नं० १०

दरखवास्त वास्ते गिरफ्तार किये जाने दिवालियाके दफा ३२.

दरखवास्त हस्य दफा ३२ प्रान्तिक कानून दिवालिया सन १९२० ई०

अदालत साहय डिस्ट्रिक्ट जज बडापुर जि०

मुकदमा दिवालिया नं० सन् १९ ई०

... .. सायल

... .. कर्जदार (या रिखार)

उक्त कर्जदार निम्न लिखित प्रार्थना करता है।

१. यह कि उक्त मुकदमेमें..... कर्जदार सारीख सन् १९ ई० को पहिलम अदालत दिवालिया करार दे दिया गया है।

१ यह कि उक्त दिवालियाको इस अदालतने यह हुक्म दिया था कि यह अपनी हिस्साका कितनोंको दाखिल करे ॥ अपनी सब सनकूला (Moveable) जायदादको कहरिस्त तैयार करके उसको रिमीनर (या किसी व्यक्ति के सुपुर्द करे ।

३ यह कि दिवालियाकी सनकूला जायदाद अधिकतर पैसी है औ बिना उसकी मददके पैसा नहीं जासकती है ।

४ यह कि दिवालिया इस अदालतकी अधिकार सीमासे बाहर इस संशय यथायक भला गया है जिसमें कि उसको हिस्सावरी कितनों में दाखिल करना पड़े या अदालतके हुक्मकी तामील करनेसे बच जावे । इसके इस कामसे मुझ कर्जवाह तथा बाकी अन्य कर्तारवाहोंको नुकसान पहुँचता ।

इस लिये मुझ कर्जवाहकी मायना है कि दिवालिया मजदूर वजतिये शान्त गिरफ्तार करा लिया जावे जिसमें वह इस अदालतके सामने पैसा किया जायके या अदालत जो हुक्म मुनाविद समझे मादिर फर्मावे ।

तारीखें सन् १९ ई०

हस्ताक्षर

नोट:—उक्त दरखास्त रिमीनर या कोई भी कर्जवाह दे सकना है उक्त दरखालके साथ इरफनामा दाखिल । जाना भी आवश्यक है ।

(नमूने का फार्म) नं० ११

कर्ज साधित करनेकी दरखाम्त दफा ३३

अर्जी हस्त दफा ३३ कानून दिवालिया सन १९२० ई०

अदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०.....

मुकद्दमा दिवालिया नं० सन् ११ ई०

.....सायब

मैं

कहू

कृतववाह

मैं

(नाम व पता कर्जवाह)

बहलक ध्यान करता हूँ कि

(नाम कर्जदार) ने

मुझसे तारीख सन् १९ ई० को

रकपा धनौर कर्ज लिया था वह रकपा अवतक

अदा नहीं हुआ है दिवाज कर्ज का इस दरखाम्त के साथ दाखिल की जाने वाली कहरिस्त में दिखलया गया है यह कर्ज सब सचवा है बार इसमें मे एक पैसा भी मुझे या मेरे किसी आदमी को अदा नहीं किया गया है और । इस कर्ज की कोई धामानत ही की गई है ।

तारीख

सन् १९ ई०

हस्ताक्षर

जिस अगद हलफ की गई हो उसका नाम वतारीफ और हलफ देने वाले कसिद्वारके दस्तखत होना चाहिये ।

(नमूनेका फार्म) नं० १२

दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी मंजूरीके लिये दी जाने वाली
करजदारकी दख्खास्त (दफा ३५)

दख्खास्त हस्व दफा ३५ प्रान्तिक कानून दिवालिया सन १९२० ई०

अदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर त्रि०

मुकद्दमा दिवालिया न०

सन् १९ ई०

सायल

उक्त सायल निम्नलिखित प्रार्थना करता है:—

१ यह कि मुझ सायलके बिरादरे ने जो कि अपनेको मुझ सायलका एक कर्जदार
बतलाता है इस अदालतमें एक दख्खास्त दिवालिया करार देनेके लिये दी थी वरत दख्खास्तके अनुसार
मैं तारीख सन् १९ ई० को दिवालिया करार दे दिया गया हूँ ।

२ यह कि उक्त कर्जदारने बिलकुल गलत बयानीके साथ दख्खास्त की थी उसका कर्त मुझ सायल पर
५००) स कहो कम है ।

३ यह कि उक्त कर्जदारने अपनी दख्खास्तमें यह गलत बतलाया है कि मैंने अपना कारोबार बन्द कर
दिया है या उसके बन्द किये जानक बात कोई सूचना इसके दी है ।

४ यह कि मुझ सायलका कारोबार बाहर चल रहा है व मैं अपने सब कर्त मकी प्रकार चुका सकता हूँ ।

५ यह कि दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म होनेके पश्चात् सब कर्जदारोंके कर्त चुकाये जाचुके हैं ।

इस लिये मुझ सायलकी प्रार्थना है कि दिवालिया करार दिये जाने वाला हुक्म जो खिलाफ मुझ सायलके हुआ है
मसूख किया जावे या अखिल आ हुक्म मुनासिब समझे दे दवे । सायल इसके लिये बड़ा कृतज्ञ होगा ।

तारीख सन् १९ ई०

हस्ताक्षर

नोट, — इस दख्खास्तके साथ यदि मुनासिब हो ता हुक्मनामा भी दालिज करना चाहिये । अधिकतर हक्मनामोंके
दालिज किया जाता ही अछा है ।

(नमूनेका फार्म) नं० १३

दख्खास्त कर्जदारके आस्ते मंजूरी हुक्म दिवालिया (दफा ३५)

अर्जो हस्व दफा ३५ प्रान्तिक कानून दिवालिया सन १९२० ई०

मिन्नामिब

कर्जदार

अदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर त्रि०

मुकद्दमा दिवालिया न०

सन् १९ ई०

सायल

उक्त कर्जदार निम्नलिखित प्रार्थना करता है

१ यह कि उक्त दिवालियेके ह्वाय एक दख्खास्त इस अदालतमें देकर अपनेको दिवालिया करार दिला लिया है ।

२ यह कि उक्त दिवालिया अधिकतर मैं रहता है जो कि इस अदालतकी अधिकार सीमाके

बाहर स्थित है और इसी कारण इस अदालतका उक्त दिवालियेकी दख्खास्त मुननेका अधिकार प्राप्त नहीं है ।

३ यह कि मुक्त कर्जस्वादा पर किसी जेजिसकी तामील नहीं हुई जिसके कारण मैं कर्जस्वादा पैदा मुकदमा नहीं कर सका और अधिकार सीमाका विरोध भी नहीं कर सका ।

४ यह कि उक्त दिवालियाने अपने कर्जोंकी तादाद ५०० से अधिककी दिखलाई है जो दरअसल उसने जो कर्ज दरखास्तमें दिखलाये हैं अधिकतर कर्जों व नुमायशी हैं और यह असली कर्जस्वादानका कर्ज मारनेकी शरतसे दिखलाये गये हैं ।

५ यह कि उक्त दिवालियाकी माली हालत काफी अच्छी है और वह बभासानी अपने असली कर्जोंको चुका सकता है ।

६ यह कि उक्त कारणोंसे यह भली भाँति प्रकट है कि दिवालिपने इसी दरखास्त लेकर और प्रसक्तियतको छिपाते हुए अदालतसे बेजा तरीके पर यह हुजम साँ ३९ ई० को हासिल कर लिया था जो कि काबिल मंजूरी है ।

इसीलिये प्रार्थना है कि दिवालिया करार दिये जाने वाफा हुजम मसूख किया जाने अथवा कोई अन्य मुनासिब हुजम दिया जाने जिसके किये में फर्जेस्वादा बका क़तर होऊगा ।

तारीख

सन् १९

ई०

हस्ताक्षर

नोटः—स दरखास्तके साथ भी इसकी पुष्टि इलक़नामा तदीक़तुदा दाखिल किया जाना चाहिये ।

(नमूने का फार्म) नं० १४

तस्वीया या तय करनेकी स्वीमका प्रस्ताव पेश करनेकी दरखास्त (दफा ३८)

अर्ज़ी हर्ष अर्दिर ३८ प्रान्तिक कानून दिवालिया सन् १९२० ई०

यमहाकत सादर किस्किज अत्र बहादुर कि०

मुकदमा दिवालिया न०

सन् १९

ई०

.....सायल

एक सायल निम्नलिखित प्रार्थना करता है

१. यह कि इस अदालतके हुजम द्वारा मैं सायल तारीख सन् १९ ई० को दिवालिया करार दे दिया गया हू ।

२. यह कि मुक्त सायलको दिवालिया करनेकी नौबत इस कारण पहुँची कि बाजारकी हालत आम और पर गदबद है व मुक्त सायलकी क्षाम तौरसे अपने व्यापारमें नुक़सान उठाना पडा था । मुक्त सायलकी ओतमें कोई येउनमानी अमलमें नहीं लाई गई थी और न मुक्त सायलने किसी या सब कर्जस्वादों का कर्ज मारनेकी को गरजसे कोई बेजा काम किया है कोई फिज़ूल खर्ची भी अलममें मुक्त सायलकी ओतसे नहीं आई है ।

३. यह कि अब मुक्त सायलका विचार है कि मैं सायल फिरसे अपने व्यापारको करूँ और मुक्त सायलको पूरी उम्मेद है कि उसमें जरूर फायदा होगा ।

४. यह कि इसी कारण मुझ सायलने यह तय किया है कि अपने सब कर्जस्वाहानके कर्मे का समझौता करके कठोबार अपना बंदस्तूर शुरू करके। कर्जस्वाहानने भी कसरतरायसे मुझ सायलका प्रार्थनाको मंजूर कर लिया है और वह लोग रुपयेमें सात भागे अपने पूरे कुर्सेकी अदायगीमें लेनेको तैयार हैं।

५. यह कि जबकि मुझ सायलकी जायदाद व लहानसे इस समय रुपयेमें खार भाने भी बसूल होता मामुमकिन है और मुझ सायलके यकीन दिलानमें कर्जस्वाहानने तय शुदा सात भागे दो विस्तरोंमें जो छमाही २ में अदाकी जावेगी लेना मंजूर कर लिया है इसलिये समझौतेकी यह स्कीम अदाकत द्वारा मंजूर किया जाना बहुत सुनासिच है।

इसलिये वक्त कारणोंसे प्रार्थना है कि मजलसत ऊपर बतलाये हुए समझौतेके प्रस्तावको रूपया स्वीकार करे और दिवालिया क़ारार दिये जाने वाले हुक्मको असूल फर्मावे जिसके लिये सायल बचा कृतज्ञ होगा।

तारीख

सन् १९

ई०

हस्ताक्षर

(नमूनेका फार्म) नं० १५

दरखास्त वास्ते बहाल किये जाने (दफा ४१)

दरखास्त हस्त दफा ४१ प्रान्तिक कानून दिवालिया सन् १९२० ई०

वधदाकत साहय डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०

मुकदमा दिवालिया नं०

सन् १९

ई०

.....सायल

जब सायल निम्नलिखित प्रार्थना करता है

१. यह कि इस अदाकतने मुझ सायलको तारीख दिया था व सापही साथ यह भी हुक्म दिया था कि मैं सायल की दरखास्त दे दू।

सन् १९ ई० में दिवालिया क़ारर माइके अन्दर बहाल (Discharge)

२. यह कि मुझ सायलने अपनी सब जायदाद अदाकत द्वारा नियुक्त किये हुए रिसीवरकी सुपुर्दगीमें देदी थी और रिसीवर मजकूरने मुझ सायलका सब लहना व जायदादसे बसूल करके डिबिटेंट (हिसाब रसदी) कर्जस्वाहानमें तफ़्सीम कर दिया है जिससे उनका कर्मे रुपयेमें भी भागेके हिसाबसे चुका दिया गया है।

३. यह कि मुझ सायलने कोई जायदाद या कर्मे नहीं छिपाया था और न मुझसायलकी ओरसे कोई व सनमानो या हुक्म उद्दकी ही कमी दौरान मुकदसेमें की गई है।

४. यह कि व्यापारम घाटा होनेके कारण मुझ सायलको बुकमान उठाना पड़ा था और उस वक्त कर्जों केनेके समय मुझ सायलकी उनकी अदायगीके लिये शराभी शक नहीं था व वह पूरी तौरसे चुकाये जा सकते थे। इस लिये मुझ सायलकी प्रार्थना है कि वह पूर्ण रूपसे बहाल किया जावे।

तारीख

सन् १९

ई०

हस्ताक्षर

रिसीवरकी रिपोर्टका पेश होना भी आवश्यक बात है कर्जस्वाहान इस दरखास्तका विरोध भी कर सकते हैं।

नोटः—इस दरखास्तके होने जानेकी सूचना सब कर्जस्वाहानको उसी तरीके पर दी जाना चाहिये जिस तरीके पर दरखास्त दिवालियाकी दी जाती है।

(नमूने का फार्म) नं० १६

दरखास्त वास्ते बहाल किये जानेके (दफा ४१)

दरखास्त हरब दफा ४१ प्रान्तिक कानून दिवालिखा सन् १९२० ई०

बजटालत साहय डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर नि०.....

मुकदमा दिवालिखा न० सन् १९ ई०

..... सायल

वक्त सायल निम्न लिखित प्रार्थना करता है

१. यह कि मैं सायल बहुमम अदालत तारीख सन् १९ ई० को दिवालिखा करार दिया गया

था और अदालतने बहाल (Discharge) की दरखास्त देनेके लिये ६ माहकी मुदत दी थी।

२. यह कि मुझ सायलके पास कोई आयदाद नहीं थी और इसलिये किसी रितीवरकी निवृत्ति भी नहीं की गई थी।

३. यह कि मुझ सायलकी रोजगारमें यकायक घाटा पड़ जाने या बचनद थोमारी एक साल तक अपने कामकी पूरी देख भाल व कानेकी बजहसे इस हालत पर पहुँचना पड़ा था।

४. यह कि मुझ सायलने जिस वक्त यह कर्जें लिये थे उस वक्त सब अदायगी का पूरा जुभीता मुझ सायलके पास था और कमी मुझ सायलकी नियत कमी किमी कर्जोंके मारनेकी नहीं रही है।

५. यह कि मुझ सायलके पास बराबर बचनपदा हिसाब किताब रहा है व मुझ सायलने किमी कर्जवाहको दूसरे कर्जवाहों पर तर्जौद नहीं दी है और न कोई बेवजहानी असलमें कमी लाई गई है और न कोई आयदाद बाव दिवालिखा होने मुझ सायलके पास नहीं आई है।

६. यह कि जपर दिखलाई हुई बातोंसे अली भालि प्रकट है कि दिवालिखा बननेके लिये मैं किसी प्रकार दीपी नहीं हू किन्तु अचानक व अभायपन ही मुझ सायलको दिवालिखा बनना पड़ा था।

इसलिये प्रार्थना है कि मैं सायल पूर्ण रूपसे बहाल किया जाऊँ जिसमें कि फिरसे अपना काराबार शुरू कर सकूँ क्योंकि दिवालिखा होनेके बादमे बराबर तकाद हूँ।

तारीख सन् १९ ई०

हस्ताक्षर

(नमूने का फार्म) नं० १७

बहालकी दरखास्तके विरोधमें दी जानी वाली दरखास्त (दफा ४२)

अर्जी हरब दफा ४२ प्रान्तिक कानून दिवालिखा सन् १९२० ई०

बजटालत साहय डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर नि०.....

मुकदमा दिवालिखा न० सन् १९ ई०

..... सायल

मैं कर्जवाह निम्नलिखित प्रार्थना करता हूँ

१. यह कि सायलने जो इस अदालतसे तारीख सन् १९ ई०

को दिवालिखा करार दिया गया था बहाल होनेकी दरखास्त इस अदालत में दी है जिसमें सूचना मुझ कर्जवाहको मिली है।

२. यह कि उन सायलजी यह दरखास्त इन कारणोंसे हार्मिज काबिल मंजूरी नहीं है ।
- (ए) यह कि दिवालिये मजकूर का लहना उसके कर्जोंके रुपयेमें आठ आठ चुकानेके लिये पर्याप्त नहीं है या उससे कर्जोंकी अदायगीमें सिर्फ रुपयेमें एक आठ हो बसूल हो सकी है ।
- (बी) यह कि दिवालिया करार दिये जानेसे पहिले उसने अपनी बहुतसी आयदादकी छिपा दिया था या अपने रिस्तेदारों से गौरहके पाम्प छुटा दिया था ।
- (सी) यह कि उसने (दिवालिये) मुझ सायलका कर्ज भारनेकी गारंजसे बहुतसे कर्जों कर्ज अपने रिस्तेदारों से कोसोंके दिखाने दिये थे ।
- (डी) यह कि दिवालिये अपने लहनेके बसूल किये जानेमें कोई अद्द रिस्तेदारकी नहीं ही जिससे कि उसका बहुत सा लहना बसूल होनेसे रह गया ।
- (ई) यह कि बाद दिवालिया करार दिये जानेके उसने बराबर छिपकर दूसरोंके नामसे कारोबार किया है जिसमें कभी रकम पैदाकी है और वह उस रकमको छिपाये हुए है ।
- (एक) यह कि उसने दिवालियेकी दरखास्त देनेसे पहिले अपनी गरमनेकला आयदाद के एकमें कर दी थी वह इस तौर पर उसने को बेना तर्जिह दूसरे कर्जदारों पर दी थी (और यह कि वह इस्तकाल जायदाद कभी करार दिया जाकर रह किया जा चुका है)
- (जी) यह कि दिवालिया मजकूर बराबर हिम्माय किताब रक्कत या लेकिन अपने बराबर हस्तम करने रकम कर्जवादान अपनी हिस्साकी किताबोंकी छिपा रक्कत है उनको पत्र नहीं किया है ।
- (एन) यह कि दिवालिया मजकूरने तमाम रुपया फिजल प्रथम बराद कर दिया है ।
- (आर्) यह कि दिवालिया मजकूरने बहुतसे कर्ज यह जानेसे छुप लिये थे कि वह उनको अदा नहीं कर सकेगा ।
- (ओ) यह कि दिवालिया मजकूर तरह २ की बेतनमानी शुरूसे अब तक अमलमें लावा रहा है जिसके कारण वह हार्मिज बहाल किये जान योग्य नहीं है ।

३. यह कि अगर दिवालिया बहाल कर दिया गया तो आयदाद उससे किसी एकमें बसूल होने की उम्मेद नहीं रहेगी ।

४. यह कि रिस्तेदारकी रिपोर्टसे भी ऊपर बनलाई हुई बहुतसी बातें साफ तौर पर जाहिर होंगी । इसलिये मार्यना है कि दिवालिया मजकूर हार्मिज बहाल न किया जावे (या वह ऐसी बातों साथ बहाल किया जावे जिसमें कि उसकी आयदाद आमदनी या जाने वाली आयदादसे कर्जवादानको कुछ धरपा आर बसूल हो सके)

तारीख

सन् १९

ई०

हरनाथर

नोटः—(१) ऊपर उज्जदारीकी ताईदमें यदि उचित हो तो इन्फनामा भी दाखिल किया जाना चाहिये —

(२) दरखास्तकी दफा २ में जो बख्शहात दिखलिये गये हैं उनमेंसे सब या धानी जो मुन्नामिब मासूम हो दिखलाई जाना चाहिये ।

(३) बहाल पूर्ण रूपसे होका जा सकता है व जायदाद देने वाली आमदनी या जाने वाली आयदादके समय में इन्फन देकर बहाल किया जा सकता है अथवा किंगी निमतमी हुई अनधिके बाद बहाल हुनेकी आशा दी जा सकती है ।

(नमूने का फार्म) नं० १८

दरखास्त वाचत मंजूरी इत्तकाल जायदाद (दफा ५३ व ५४ ए)
 दरखास्त हस्ब दफा ५३ व ५४ ए कानून दिवालिया सन् १९२० ई०

अदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०

मुकदमा दिवालिया नं०

सन् १९ ई०

सायल

उक्त मायलेमें निम्नलिखित प्रार्थना है

१. यह कि दिवालिया स्वयं अपनी दरखास्त पर इस अदालत द्वारा ता० सन् १९ ई० को दिवालिया करार दे दिया गया था ।

२. यह कि अदालतके हुक्म द्वारा ये उक्त दिवालियाकी जायदादके लिये रिसीवर नियुक्त किया गया है

३. यह कि दिवालिया भजकुरने अपनी जायदाद परारिये दस्तावेज रजिस्ट्रीया मुबर्किा

अपने एक रिस्तेदार मुसम्मि के नाम दरखास्त दिवालिया देनेके बाद साह पडिहे (अयान् अन्वर दो सालके) कर दी है और यह दरवायेज बिलाबदल व कर्जी यी व अपनी जायदादको बचाने व उसकी अपने कर्जखानाने बचानेकी गरजसे लिखा था जो कतबिल कायम रहनके नहीं हैं ।

४. यह कि मुझ रिसीवरने को जिनके हुक्में दस्तावेज भजकुर लिखी गई थी हत बातकी हलका दे दी थी कि वह जायदाद का कब्जा मुझ रिसीवरको दे देंगे लेकिन उन्होंने बसकी कोई मुनवाई नहीं की और न जायदाद पर कब्जा ही दिया ।

५. यह कि उक्त कार्योंसे ऊपर बतलाया हुआ इत्तकाल जायदाद बिल्कुल कर्जी है व मुझ रिसीवरके बिना कोई असर नहीं रखता है और जायदाद भजकुर का कब्जा मुझ रिसीवरको मिलना चाहिये जिसमें वह कर्जखानाभमें तकसीमकी जा सके ।

इस लिये प्रार्थना है कि उक्त इत्तकाल जायदाद कर्जी व बिलाबदल करार देकर मसूल कनोया जावे । मुझ रिसीवरके डिक्लाफ बिल्कुल बेअसर बरार दिया जावे या कोई अन्य मुनासिब हुक्म दिया जावे ।

सातक

सन् १९

ई०

इस्ताफर

नोटः—जायदादकी पूरी तकसीम दी जाना चाहिये और यदि मुनासिब हो तो इत्तहा देने वाले व्यक्ति का इल्फनामा भी इस दरखास्तमें पुरटेम बाबत रिता बंगाराके लगा देना चाहियेः—

(नमूने का फार्म) नं० १९

धोखादेहीसे तर्जिह देने वाले इत्तकाल जायदादकी मंजूरीके लिये दी जाने वाली
 दरखास्त (दफा ५३ व ५४ ए)

दरखास्त हस्ब दफा ५३ व ५४ ए. प्रान्तिक कानून दिवालिया सन् १९२० ई०

अदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०

मुकदमा दिवालिया नं०

सन् १९ ई०

सायल

रिसीवर

पिटिशनर बनाम कर्जखाना

फौकसानी

उक्त पिटिशनर (रिसीवर) की निम्नलिखित प्रार्थना है,—

१. यह कि सायल अपनी ही दरखास्त पर इस अदालतके हुक्म द्वारा सातक सन् १९ ई० को दिवालिया करार दे दिया गया था व मैं पिटिशनर उसकी जायदादके लिये रिसीवर नियुक्त किया गया हूँ ।

२. यह कि उक्त दिवालियाने तारीख
हस्ताकाल करके वसमेंसे मुकदमा २००७)

को जो उसका कर्जवाह है अपने तीगर कजवाह के
मुकदमा तर्जिह देकर द दिया है । जायदाद के हस्तकाल की तत्काल इस दरखास्त के साथ दाखिल की जाने वाली
फिरिस्तमें दिखलाई गई है ।

३. यह कि उक्त हस्तकाल जायदाद व नीज अदावगी रुपया ऐस समयमें की गई थी जब कि
दिवालिया मजकूर अपने कर्जोंको चुकानेमें अयमर्थ था और यह काम दिवालिया की दरखास्त दिव जानसे तीन
साहके अन्दर किया गया है ।

४. यह कि ऐसी दशामें यह सौदा कानूनन नाजयज है और मुक्त रिस्तिवरके विरुद्ध कानून कायम
रहनेके नहीं है और इसी कारण मसूख किया जाना चाहिये ।

५. यह कि मुक्त रिस्तिवरने फरीकमाना (कर्जवाह जिसके हकमें रुपया अदा हुआ था) को इसकी
पुचना देदी थी व इससे इस रुपयेको वापिस होने या सादाको मसूख करानेको कड़ा धारणनु करने वसे नहीं माना ।

इसलिये मायना है कि उक्त सौदा नाजायज करार दिया जावे या कोई अन्य बखित हुकम दिया जावे ।

तारीख

सन् १९

ई०

हस्ताक्षर

नोटः—इस पिदाशनके साथ जायदाद की तत्काल दाखिलगी जाना चाहिये व यदि आवश्यकता हो तो जानने वाले
मतिश इसकनामा वाक्यतकी पुष्टिमें लगाना चाहिये ।

(नमूने का फार्म) नं० २०

दरखास्त कर्जवाह धारते मसूखी हस्तकाल जायदाद (वफा ५४ व)

वरखास्त हस्त वफा ५४ ए प्रान्तिक कानून दिवालिया सन् १९१० ई०

अभदालत साहब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर जि०

मुकदमा दिवालिया न०

सन् १९

ई०

..... सायक

मिनशानिब

कनेल्वाह

यह कनेल्वाह निम्नांशित मार्गना करता है:—

१. यह कि उक्त सायक स्वयं अपनी दरखास्त पर इस अभदालतके हुकम द्वारा तारीख
सन् १९ ई० को दिवालिया करार दिया गया था और इसकी जायदादके लिये
अभदालत द्वारा रिस्तिवर नियुक्त किये गये हैं ।

२. यह कि दिवालिया मजकूर अपनी जायदादको बखरिये दस्तखत फर्जी सुवरक्षा
अपने एक रिस्तेदारके हुकम बिला बदल लिख दिया है जिसे तखमिनन साहके (दो साहके अन्दर का समय
होना चाहिये) हुप है ।

३. यह कि हस्तकाल जायदाद दिवालिया मजकूर अपनी जायदादको बचानेके लिये इस गरजसे किया है
कि जिसमें वह इसके कनेल्वाहानको न मिल सके व जिस समय यह हस्तकाल किया गया था दिवालिया अपने स्वयं
कर्जोंको चुकानेके लिये समर्थ नहीं था व दरखास्त बिला बदल व फर्जी तारसेकी गई थी जो हातमें काबिल मसूखी है ।

४. यह कि मुक्त कनेल्वाहने उसकी मसूखीके बावत रिस्तिवर साहबसे बारहा कड़ा व वनको
तारीख सन् १९ ई० को नोटिस भी इसके बावत दिया था लेकिन वह इसके
लिय तैयार नहीं हुए जिनाम मजकूर मुक्त कनेल्वाहको उसकी मसूखीके लिये दरखस्त देना पड़ी ।

५. यह कि यदि कानून मुक्त कर्जवाहक विला इजाजत अदा करत ऐसे इन्तकालके मसूख कराने एक नहीं है इस कारण उसकी इजाजतके लिये यह दरवास्त दी जाती है ।

इसलिये प्रार्थना है कि अदालत मुक्त कर्जवाहको उक्त इन्तकाल जायदादकी मसूख करानेकी इजाजत दी जावे या अन्य-कोई उचित हुक्म दिया जावे और साथ ही साथ प्रार्थना है कि उक्त इन्तकाल मसूख फर्माया जावे ।

तारीख

सन् १९

ई०

हस्ताक्षर

नोट: — दरवास्तकी पुष्टिके लिये हक्कनामा भी आवश्यक है ।

(नमूने का फार्म) नं० २१

दरवास्त याचक लहकरीकात जुर्म दिवालिया (दफा ७०)

दरवास्त हसब दफा ७० प्रान्तिक कानून दिवालिया सन् १९२० ई०

अदालत स हब डिस्ट्रिक्ट जज बहादुर सिंह.....

मुकद्दमा दिवालिया नं०

सन् १९

ई०

..... सायत

मिलजानिब

रिसीवर

उन रिसीवर निम्न लिखित प्रार्थना करता है —

१. यह कि सायल अदालतके हुक्म द्वारा तारीख सन् १९ ई० को दिवालिया फरार दिया गया था और मैं उसकी जायदादके लिये रिसीवर नियुक्त किया गया हूँ ।

२. यह कि मुक्त रिसीवरने दिवालिया मसकूरसे बारहा अपनी सब हिसाबकी किताबें पेश करने व सूचीमें दिखलाई हुई जायदाद पर कब्जा देनकी कड़ा मगर दिवालियेने उसकी कोई परनाह नहीं की । मुक्त रिसीवरने उसको कारतेसे इसला भी तारीख सन् १९ ई० को दी है इस पर भी न तो दिवालिया खुद मरे पास आया है और न मरे कहनेकी इसला ही की है ।

३. यह कि दिवालिया मसकूर अपनी जायदादको कर्जवाहानसे बचानेकी नीयतही से यह सब कारवाइया कर रहा है । या

दिवालियाने अपनी हिसाबकी किताबोंको बन्द कर दिया है या उसे अपनी हिसाबकी किताबोंमें गुलत हुन्दराज वगैरा असली हालतकी लिखानेकी मशाले कर लिये हैं । या

अपनी हिसाबकी किताबोंको पेश नहीं कर रहा है । या

दिवालियेने सूचीमें दिखलाई हुई जायदादमें अपनी बहुतसी जायदाद नहीं दिखाई है या उनमेंसे कुछको रेशन वगैरासे मलहदा कर रखा है और यह सब कारवाइ अपने कर्जवाहको को नुकसान करने व बेजा लाभ उठानेकी मशाले ही से की है ।

इसलिये प्रार्थना है कि अदालत ऊपर दिखलाये हुए जुर्मकी लहकरीकात करे और हसब दफा ७० प्रान्तिक कानून दिवालिया कारवाइ अमकलमे लावे या कोई अन्य मुमानिष हुक्म सादर फर्मावे ।

तारीख

सन् १९

ई०

हस्ताक्षर

प्रेसीडेन्सी टाउन्स क्रानून दिवालिया

एक्ट नं० ३ सन १९०९ ई०

Presidency Towns Insolvency Act, No. 3 of 1909.

यह क्रानून सिर्फ
कलकत्ता, बम्बई, मदरास, रंगून और कराची शहरोंमें लागू है

सर्वाङ्गपूर्ण व्याख्या और हाल तककी समग्र
नज़ीरों एवं उदाहरणों तथा अन्य
क्रानूनोंके पूरे हवालों सहित

लेखक :—

बाबू रूपकिशोर टागोर

एम० ए०; एलएल० बी०; एम० आर० ए० एस० परबोकेट

प्रकाशक :—

पं० चन्द्रशेखर शुक्ल

मुद्रित :—

क्रानून प्रेस, कानपुर

Presidency Towns Insolvency Act.

Act No. III of 1909.

प्रेसीडेंसी टाउन्स कानून दिवालिया

एक्ट नम्बर ३ सन १९०९ ई०

१२ मार्च सन १९०६ ई० को गवर्नर जनरल हिन्दकी स्वीकृति प्राप्त हुई,

यह एक्ट प्रेसीडेंसी टाउन्स (Presidency Towns) व रंगूनके कानून दिवालियाको
संशोधन करनेके लिये बनाया गया है

प्रस्तावना (Preamble)

इसके यह आवश्यक प्रतीत होता है कि प्रेसीडेंसी टाउन्स तथा रंगूनके कानून दिवालिया
में संशोधन किया जावे अतः निम्नलिखित कानून बनाया जाता है:—

[यह एक्ट लिफ्ट कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, रंगून और कराची इन ५ शहरोंमेंही लागू होगा
उनके अतिरिक्त अन्य किसी स्थानमें यह एक्ट लागू नहीं होगा]

दफा १ नाम व प्रारम्भ .

(१) यह एक्ट प्रेसीडेंसी टाउन्स कानून दिवालिया सन १९०६ ई० (The Presi-
dency Towns Insolvency Act 1909.) कह लायगा ।

(२) यह एक्ट पहिली जनवरी सन १९१० ई० से लागू होगा ।

व्याख्या—

भो कि इस एक्ट का नाम प्रेसीडेंसी टाउन्स कानून दिवालिया है किन्तु प्रेसीडेंसी टाउन्सके अतिरिक्त कुछ अन्य
स्थानोंमें भी इसके प्रयोग किये जाने की व्यवस्थाकी गई है अर्थात् प्रेसीडेंसी टाउन्स के अतिरिक्त इसका प्रयोग एतद् शहर व
कराचीमें भी किया जाता है । एतद् का उल्लेख तो इस एक्ट के प्रारम्भ भा में कर दिया गया है किन्तु कराची (Karachi)
के लिये इसका प्रयोग एक्ट ९ सन् १९२९ ई० के अनुसार किया जाना निश्चित हुआ है उससे पहिले कराचीमें प्राक्तिक
कानून दिवालिया लागू था अन्तु उस एक्टके नियमोंका प्रयोग कराची टाउनके लिये उपयुक्त नहीं समझा गया इस कारण
लिखित जस्टिस कमिटी की सिफारिश पर उस एक्ट का प्रयोग कराचासे उठा दिया गया और उसके स्थान पर वहाके लिये इस
एक्ट अर्थात् प्रेसीडेंसी टाउन्स कानून दिवालिया का प्रयोग किया जाना निश्चित किया गया । इस एक्ट (प्रेसीडेंसी
टाउन्स इन्साल्वेंसी एक्ट १९०९) के पास होनेके पादेके प्रेसीडेंसी टाउन्स (Presidency Towns) में इन्डियन
इन्साल्वेंसी एक्ट १८४८ (11 & 12 Vict Ch 21) लागू था और दिवालियोंके अधिकारों का प्रयोग
प्रेसीडेंसी टाउन्समें इन्डियन तथा ग्लूनमें चीकनर्ट किया करते थे ।

प्रान्तिक कानून दिवालिवासे भेद—प्रेसीडेंसी टाउन्स इन्सोल्वेंसी एक्ट तथा प्रान्तिन कानून दिवालिवा (Provincial Insolvency Act) एक दूसरे में भिन्न हैं तथा उनके अनुसार दिवालिवाके सम्बन्धमें जो अधिकार मिले हैं वे बड़े नहीं भिन्न हैं इस कारण यदि कोई दिवालिवाके दायित्व प्रेसीडेंसी टाउन्स कानून दिवालिवाके अनुसार हार्दवेयरमें चला रहा हो तो वह प्रान्तिक कानून दिवालिवाके अनुसार कार्य करने बाँधे अदालत जिला (District Court) में नहीं बनाया सक्त है । देखो—38 Mad 472; 53. Cal. 928.

इस एक्टका पिछले कार्यों पर प्रभाव—इस एक्ट का कोई प्रभाव पिछले किये हुए कार्यों पर नहीं पड़ेगा सिवाय उसके जिसका उल्लेख इस एक्टमें कर दिया गया हो । जो एक्ट बनाये जाते हैं उन सबका प्रयोग भविष्यमें होने वाले कार्योंके लिये होता है पिछले कार्योंके लिये नहीं । इस सम्बन्धमें यहाँके हार्दवेयर तथा विलायतनी बहुतनी नजारे हैं जिनमें यह साफ तौरसे तय किया गया है कि कानून पिछले कानूनोंके अनुसार किये हुए कार्योंका नहीं पड़ेगा किन्तु भविष्यमें किये जाने वाले कार्य उसके अनुसार किये जावेंगे । देखो—(1890) 15 A. C. 384, (1894) Q. B. 725 (737), 31 C. L. J. 463.

दफा २ परिभाषायें

यदि कोई बात विषय व महाभरके विरुद्ध न पड़ती हो तो इस एक्टमें दिये हुए नीचेके शब्दोंका अर्थ इस प्रकार समझना चाहिये:—

- (ए) कर्जकर्ता (Creditor) से अभिप्राय डिक्रीदार (Decreeholder) का भी है ।
- (बी) कर्जा (Debt) से अभिप्राय डिक्री के कर्मेसे भी है और कर्जदार (Debtor) से अभिप्राय मदीयून (Judgement debt) का भी है ।
- (सी) आफिशल एसायनी (Official Assignee) से अभिप्राय कायम मुकाम आफिशल एसायनी (Acting Official Assignee) से भी है ।
- (डी) निर्धारित किये हुए (Prescribed) अभिप्राय उन बातों का है जो नियमों द्वारा निर्धारित की गई हों ।
- (ई) जायदाद (Property) से अभिप्राय उस जायदाद का भी है जिस पर या जिससे होने वाले लाभ पर किसी व्यक्तिको व्यय करनेका अधिकार होवे और जिससे वह अपने लाभके लिये प्रयोग कर सके ।
- (एफ) नियमों (Rules) से अभिप्राय उन नियमों का है जो इस एक्टके अनुसार बनाये गये हों ।
- (जी) महाभूज कर्जकर्ता (Secured Creditor) से अभिप्राय उस ज़मींदार (Land Lord) का भी है जिसका किसी प्रचलित कानूनके आधार पर ज़मीनके लगानके लिये किसी ज़मीन पर हार होवे ।
- (एच) अदालत (The Court) से अभिप्राय उस अदालत का है जो इस एक्टके अनुसार अपने अधिकार का प्रयोग करनी हो ।

(आर्द्र) इन्तकाल जायदाद (Transfer of Property) से अभिप्राय उस इन्तकाल से भी है जो उस जायदादके किसी हक या उस पर पैदा हुए किसी हारके सम्बंधमें किया गया हो ।

व्याख्या—

अधिकतर ऊपर दी हुई परिभाषामें पूर्ण परिभाषाये नष्ट है क्योंकि उनमें केवल यह बतला दिया गया है कि किसी अन्य विषय का प्रयोग किसी खास अर्थमें समझना चाहिये जैसा कि प्रायः (ए) में कर्जवाह (Creditor) सम्झना पारभाषा नहीं दी हुई है किन्तु केवल यही बतलाया गया है कि डिक्लारा (Decree holder) को भी कर्जवाह (Creditor) समझना चाहिये ।

फलाज (ए) में केवल यह बतलाया गया है कि डिक्लारा (Decree holder) को कर्जवाह समझना चाहिये इतलिय इस हू तसे यह बात प्रकट नहीं होता है कि कर्जवाह किसे किसे समझना चाहिये । इस बातके समझनेमें दफा ४६ तथा उसका व्याख्यास सहायता प्राप्त हो सकती है क्योंकि उस दफामें कर्जा स्तित्त किये जानका उल्लेख किया गया है । किन्तु कर्जवाहके बेनामीदारका कर्जवाह नहीं समझना चाहिये, दली—नवमी बनाम सूत 20 C W N 993

फलाज (बी) में भी फलाज (ए) के भाति न ता कर्जकी आर म कर्जदारकी परिभाषा दी गई है किन्तु बतला दिया गया है कि फलाज (बी) की (Judgement Debt) को कर्ज (Debt) व मदिगुल (Judgement debtor) का कर्जदार (Debtor) समझना चाहिये । इस कारण इन दो अर्थों के या कर्जदारकी परिभाषा भा इस एक्टकी ११ दफाओं में पढ़ने तथा हाईकोर्ट द्वारा दी हुई दफाओंका देखनेमें समझा जा सकता है । इन दफाओंके लिये विशुद्ध परिभाषा नहीं दी गई है किन्तु समय समय पर इन दफाओंका प्रयोग जिन बातोंके लिये किया गया है या हाईकोर्टके फरमानोंमें इन दफाओंका प्रयोग जिन बातोंके लिये होना, बतलाया गया है उ की बात से तात्पर्य इन शब्दोंसे समझना चाहिये । यदि कोई दफा दरमल व हर हालतमें अज्ञात विषय जानिका है चाहे उसकी अद यगी उसा समयका ज नका हावे अथवा भविष्यमें किसी समय उसकी अज्ञायगी ज्ञान वाला हावे तो उस दफाकी कर्ज समझना चाहिये दली—36 Cal 94 उधार देने वाल व उधार लेने वालका सम्बन्ध आपसमें कर्जवाह व कर्जदारका होता है और जब तक इनक विरुद्ध कोई बात सुनाईदेमें न होवे, कर्जदारको दली नहीं समझना चाहिये आफिशल दयायना बनाम लिप 32 Mad 108 यदि कोई व्यक्ति अपनी कपया किसी दूसरे व्यक्तिको इस बातक लिय देन कि वह कपया किसी तीसरे व्यक्तिको दे दिया थाव तो पहिले व्यक्तिका सम्बन्ध दूसरे व्यक्तिमें कर्जवाह न कर्जदारका नहीं होगा क्योंकि इस दफामें वह दूसरा व्यक्ति एक प्रकारमें एजेंटका काम करता है दली—36 Mad. 499

फलाज (सी) में यह बतलाया गया है कि आफिशल एसायनी (Official Assignee) से तात्पर्य उस व्यक्तिकी समझना चाहिये जो उसकी जगह पर काम करनेके लिये नियुक्त किया जावे अपना जो काम पदवी पर काम करता हो । आफिशल एसायनीकी नियुक्ति सम्बन्धम आग चल कर बतलाना दिया हुआ है ।

फलाज (डी) में अंजली एकाग्र प्रयोग किय हुए (Prescribed) शब्दके बरतमें दिया हुआ ज्ञान उसक उल्लेख (Prescribed) से दल ता पय इन बातोंका समझना चाहिय जो नियमांक अनुसार निर्धारित हैं ।

फलाज (ई) में जायदाद (Property) शब्द कोसे निरा हुआ है, परन्तु इस शब्दका पूरा पारभाषा नहीं दी गई है एक्टकी दूसरी दफाओंमें जहां जहां पर बतलाया गया है कि दिवालीयेकी सैनसा अ दशद

उसके कर्जस्वारोंमें प्राथी जा सकती है या जौसो बायदाद पर अफिशल एसायर्न कन्जा ले सकता है इत्यादि । इसका विवरण ऊन्हीं दफाओंमें मिलेगा जैसे कि दफा ५२ तथा दफा १७ आदि ।

फलाज (एफ) में यह बतलाया गया है कि जहा पर नियमों (Rules) का उल्लेख मिले वहा उनसे तात्पर्य वन नियमोंका समझना चाहिये जो इस एक्टके अनुसार बनाये गये हों ।

फलाज (जी) में मद्दूज कर्जस्वार्होंका उल्लेख है परन्तु इस क्लानून इस शब्दकी पूर्ण परिभाषा नहीं दी हुई है । नार्थ हार्कोर्टने भी A. I. R. 1929 Bom. 107. में भी यही मत प्रकट किया है उसमें यह तथ हुआ था कि मद्दूज कर्जस्वार्ह (Secured Creditor) की परिभाषा पूर्ण परिभाषा नहीं है और किंग्स इंग्लिश बैंकसी एक्ट (English Bankruptcy Act) के शब्दोंका अधिकतर प्रयोग इस एक्टमें किया गया है इस कारण उन एक्टों (Acts) में जो परिभाषा दी गई हो वह माननीय समझना चाहिये अर्थात् उन परिभाषाओंको इस एक्टके लिये लागू समझना चाहिये ।

फलाज (एच) में अदालत शब्दका विवरण है और यह बतलाया गया है कि इस एक्टमें जहा कहीं अदालत (The Court) शब्दका प्रयोग पाया जावे वहा इस शब्दका तात्पर्य उस अदालतसे समझना चाहिये जो इस एक्टके अनुसार अपने अधिसूचना प्रयोग कर रही हो । इस प्रकार अदालत शब्द उस अदालतके लिये भी प्रयोग किया जाना समझना चाहिये जिसके दफा ६ के अनुसार एक्टकी दुरुस्वास्तोंको सुनने या बयान लेने आदिके अधिकार प्रदान कर दिये गये हों ।

फलाज (आई) में इन्जुनक्श जायदादका शिफ्ट है परन्तु इस शब्दकी पूर्ण परिभाषा इस क्लानूनमें नहीं दी हुई है केवल इतना बतला दिया गया है कि वस्तुसे तात्पर्य उस इन्जुनक्श (Transfer) से भी है जो उस जायदादके किसी एक या पक्ष पर पैदा हुए किसी भावके सम्बन्धमें किया गया हो । हार्थवॉर्टने इस बातको तय कर दिया है कि क्लानून दिवालियाके सम्बन्धमें इंग्रेजी फैसले (English Decisions) भी माननीय हैं क्योंकि यह क्लानून इंग्लिश बैंकसी एक्ट (The English Bankruptcy Act) से बहुत कुछ मिलता मिलता हुआ है, देखो—40 Mad. 810. इसी प्रकार परिभाषाओंके लिये भी वह एक्ट लागू है अर्थात् माननीय है । देखो—A. I. R. 1929 Bom. 107.

नोट ८—इस बातको ध्यानमें रखना चाहिये कि जिस शब्दकी परिभाषा इस एक्टमें न मिले वस्तुके लिये जनरल इन्जुनक्श एक्टमें दी हुई परिभाषा लागू होगी ।

पहिला प्रकरण

अदालतोंकी व्यवस्था व उनके अधिकार

अधिकार सीमा

दफा ३ वह अदालतें जिनको दिवालियाके अधिकार प्राप्त हैं

निम्न लिखित अदालतोंको इस एक्टके अनुसार दिवालियाके सम्बन्धमें अधिकार प्राप्त हैं ।

(ए) कलकत्ता हार्थकोर्ट, मद्रास हार्थकोर्ट तथा बम्बई हार्थकोर्ट ।

(बी) लोअर वर्मरका चीफकोर्ट ।

व्याख्या—

इस एक्टके बननेके पश्चात् बहुतसे परिवर्तन तथा संशोधन हुए हैं । इस कारण इस दफाको भी उन्हीं संशोधनोंका ध्यान रखते हुए पठना चाहिये । लोअर वर्मरके चीफकोर्टसे तात्पर्य एन हार्थकोर्टका समझना चाहिये और इस दफामें बतलाई हुई

अदालतोंके अतिरिक्त सिन्धके इंडियन कमिश्नरको भी दिवालियेके अधिकारोंका प्रयोग करने वाली अदालत मानना चाहिये वूँकि एक्ट ९ सन् १९२६ ई० के अनुसार कराची (-Karachi) टाउन (Town) में भी इस एक्ट अन्तर्गत प्रेसीडेन्सी टाउन्स इन्स्टाल्डनी एक्टका प्रयोग प्रारम्भ हो गया है इस कारण सिन्धकी अदालत आग (Highest Tribunal) को भी वही अधिकार प्राप्त हो गये हैं जो पेंटर मिर्क इस दफामें बतलाई हुई अदालतोंको प्राप्त थे ।

दफा ४ अकेला एकही जज इस एक्टके अधिकारोंको बरत सकता है

इस एक्टके अनुसार मामलों को सुनने या तय करनेका जो अधिकार दिया गया है उसका प्रयोग ऊपर बतलाई हुई अदालतों का कोई एक जज कर सकता है और चीफ जस्टिस या चीफ जज समय समय पर किसी एक जजको इस एक्टके अनुसार कार्य करनेके लिये नियुक्त करेगा ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार दिवालिये का अधिकार रखने वाले हाईकोर्ट या चीफोर्टके चीफ जस्टिस या चीफ जज का यह कर्तव्य होगा कि वह अपनी अदालतके किसी एक जजको दिवालिया सम्बन्धी मामलोंको सुननेके लिये नियत कर देवे और ऐसे नियत किये हुए जजको अकेले ही दिवालिया सम्बन्धी मामलोंको सुनने तथा उनको तय करने का अधिकार प्राप्त होगा ।

दफा ५ कमरोंमें जजोंका काम करना

इस एक्टकी बातों तथा उसके लिये बनाये हुए नियमोंका ध्यान रखते हुए अदालतके जजको अधिकार है कि वह दिवाल सम्बन्धी मामलोंकी सब बातें या उनमेंसे कुछको कमरोंमें सुन सकता है अर्थात् वह अपने दिवालिया सम्बन्धी अधिकारोंका प्रयोग कमरोंमें बैठे हुए कर सकता है ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार दिवालिया सम्बन्धी अधिकारोंको प्रयोग करने वाला जज उन अधिकारोंको अपने कक्षमें बैठे हुए भी प्रयोग कर सकता है अर्थात् उन्हीं लिये वह खुली अदालतमें सुननेके लिये बाध्य नहीं है परन्तु इसका तात्पर्य यह न समझना चाहिये कि वह दिवालिया सम्बन्धी सब कामका कमरोंके अन्दर ही करेगा । आवश्यकतासुमार वह दिवालिया सम्बन्धी सब बातोंको या उनमेंसे कुछको कमरोंमें बैठे हुए भी सुन सकता है कि तु साथ ही साथ उसका इस एक्टकी बात व इस एक्टके सम्बन्धम बनाये हुए नियमोंकी भी अवहेलना न करना चाहिये अर्थात् यदि किसी बातको खुली अदालतमें सुनना या तय करनेके लिये एक्ट या नियममें बतलाया गया हो तो उसे खुला अदालतमें ही सुनना चाहिये इसी प्रकार यदि कोई और बात कमरोंमें किसी मामलेके सुने जातेके विरुद्ध पड़ती हो तो उसका ध्यान रखना चाहिये ।

दफा ६ अदालतके अपसरोंको अधिकार प्रदान करना

(१) चीफ जस्टिस या चीफ जजको अधिकार है कि वह समय समय पर अदालतके किसी अपसरको जिसे उसमें स्वयं इसीलिये नियत किया हो, इस दफामें बतलाये हुए सब या उनमेंसे कुछ अधिकारोंके प्रयोग करनेका अधिकार दे देवे और यह अधिकार उन्हीं बातोंके सम्बन्धमें दिये जावेंगे जिनके लिये इस एक्टके अनुसार अदालतको अधिकार प्राप्त हैं । इस प्रकार नियत किया हुआ अपसर ऊपर बतलाये हुए अधिकारोंका प्रयोग करते हुए जो हुक्म देगा या काम करेगा वह हुक्म या काम अदालत ही का हुक्म या काम समझा जावेगा ।

(२) उपदफा (१) में जिन अधिकारोंका उल्लेख किया गया है वह अधिकार निम्न लिखित हैं—

- (ए) कर्जदारों द्वारा दिये जाने वाली दिवालियेकी दरद्वारोंका सुनना तथा उन पर दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म देना
- (बी) दिवालियेका सरेआममें घयल लेना (To hold public examination)
- (सी) जिन अधिकारोंका प्रयोग किया जाना कमरेमें बैठे हुए उचित निर्धारित किया गया है उनका प्रयोग करते हुए किसी हुक्मका देना या उनका प्रयोग करना
- (डी) किसी ऐसी दरद्वारत, जिसका विरोध न किया जा रहा हो या जो एक्स्पार्ट (Ex parte) होये उसका सुनना तथा उसका निदिबल करना
- (ई) अदालत द्वारा दफा २६ के अनुसार तलब किये हुए व्यक्तिका घयान लेना
- (३) इस दफाके अनुसार नियुक्त किये हुए अफसरको अदालतकी तौहीनी (Contempt of Court) के लिये मामला चालू करनेका अधिकार नहीं होगा

व्याख्या—

वर्षिका सुननाके लिये उस दफाके उपदफा (१) के अनुसार चीफ्जस्टिश या चीफ् जजमें यह निर्धारित किया गया है कि तब अदालतक किसी अफसरको कुछ मामलोंके सुनने या तय करना अधिकार दे सके जिन मामलोंके सुनने या तय करना अधिकार इस दफाके अनुसार नियुक्त किये हुए अफसरका है उनका उल्लेख उपदफा (१) में किया गया है । इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि चीफ्जस्टिश या चीफ् जज वहाँ मामलोंके सम्बन्धमें पूरा अधिकार दे सकते हैं और उनका अदालतका तय करने के अनुसार प्राप्त हो उन अधिकारोंके अतिरिक्त वह जज वहाँ के डिप्युटी जजों दे सकते हैं ।

उपदफा (२) में जिन अधिकारोंका उल्लेख है वह सब एक साथ ही दिये जानेके आवश्यकता नहीं है चाफ्जज या चाफ्जस्टिश आवश्यकतानुसार समय समय पर उनमेंसे कुछ अधिकारोंके ग्राहक प्रदान करने पर सभी अधिकारोंके दात हैं । चाफ्जस्टिश या चीफ्जज स्वयं इस कामके लिये बिना अफसरको नियुक्त करना और ऐसी नियुक्त किये हुए अफसरका जा आधार प्रदान करने के लिये उनके प्रभाव करनेके लिये वह अफसर पूरा रूपसे अधिकारी होगा । उन अधिकारोंका प्रयोग करते हुए वह अफसर जा हुक्म देगा या जा कार्य करेगा वह अदालतकी वात या हुक्म समझा जायगा ।

उपदफा (३) के अनुसार इस दफाके नियुक्त किये हुए अफसरोंको तौहीन अदालतका मामला चालू करनेका अधिकार प्राप्त नहीं होगा । यह दफा (६) के अनुसार रजिस्ट्रारको अधिकार दे दिये जाने का दफा ३८ के अनुसार उस अदालत समझना चाहिये अपाउ रजिस्ट्रारको इस दफाके अनुसार अधिकार दिया जासकते हैं—A. I. R. 1928 Cal 786

दफा ७ दिवालियेके सम्बन्धमें पैदा हुए सब प्रश्नोंको तय करनेके अधिकार

इस अक्टमें दी हुई बातोंका ध्यान रखते हुए अदालतको पूर्ण अधिकार है कि वह उन सब प्रश्नोंको तय करे जो कर्जोंकी पेश्तर अदायगीके सम्बन्धमें पैदा हों और भी हर प्रकारके प्रश्नोंको तय करे चाहे वह कानूनी होंवे या वाक्याती होंवे जो कि अदालतके सामने उपस्थित किसी दिवालियेके मुकद्दमोंमें पैदा होंवे या जिनको अदालत पूर्ण न्याय करनेके लिये उचित या आवश्यक समझे अथवा जिनको वह किसी मामलेमें जायदादको पूर्ण रूपसे वांटनेके लिये उचित या आवश्यक समझे ।

व्याख्या—

इस दफा में अदालत के अधिकारों का वर्णन है उसके अधिकार सीमा का वर्णन नहीं है। अदालत दिवालिया की उन प्रश्नों के तय करने का अधिकार है जो आफिशल एसायनी व गैर प्रश्नों (Strangers) के बीचों पड़ा हो। जैसे—20 Mad. L. T. 311 अदालत दिवालिया के दिये हुए हुक्म की रद्द किये जाने के लिये कोई मुकद्दमा दायर नहीं किया जा सकता है, देखो—40 Mad. 1178 उक्त मुकद्दमे में आफिशल एसायनी के अपीलान्ट्स के कन्वेंस को कुछ जायदाद को यह कह कर ले लिया था कि वह जायदाद बरगल दिवालिया की जायदाद है क्योंकि उसके सम्बन्ध में जा बेनामा किया गया था नह दिखल कर्सी व तुमायशी था और भिन्न कर लिया गया था। अपीलान्ट्स ने पहिले अदालत दिवालिया में इस बात की दरख्वास्त की कि वह माल उन्का करार दिया जावे अदायगने इस मामले की अस्तित्व को सुन कर अपीलान्ट्स की बात दरख्वास्त को खारिज कर दिया अपीलान्ट्स ने अदालत दिवालिया के इस फैसले की कोई अपील नहीं की किन्तु उसकी मसूला के लिये अदालत दीवाना में गारिश दायर कर दी थी उस पर यह तय किया गया था कि अदालत दिवालिया के दिये हुए हुक्म की रद्द करने के लिये कोई दीवाना मुकद्दमा नहीं चलाया जा सकता है यदि कोई हक सम्बन्धी कन्वेंशन प्रस्तुत उपस्थित होवे तो अदालत दिवालिया की चाहिये कि वह आफिशल एसायनी को ऐसे प्रश्न दीवाना की अदालतों द्वारा तय करने का आदेश कर दे। देखो—20 Mad. L. T. 311.

इसी फैसले में यह भी तय हुआ था कि अदालत दिवालिया अपने अधिकार सीमा से बाहर स्थित जायदाद के सम्बन्ध में भी फैसला दे सकती है इस दफा में एक प्रकार की सहूलियत के लिये अदालत दिवालिया को अधिकार दे दिये गये हैं। इससे यह न समझ लेना चाहिये कि इसके कारण अदालत दीवाना के उस मूल अधिकार का अपहरण होता है जो उसे उन प्रश्नों के सम्बन्ध में प्राप्त है जो कि आफिशल एसायनी व गैर लोगों के दासियान पड़ा होवे देखो—35 Bom 478.

यदि इस एक्ट में किसी प्रश्न को तय करने के लिये कोई नियम दिया हुआ हो तो उसकी मानने तथा उसके अनुसार कार्य करने के लिये अदालत दिवालिया बाध्य है। इस दफा के अनुसार अब सब प्रश्नों के तय करने के लिये अदालत दिवालिया को अधिकार प्राप्त है चाहे वह कानूनी हानि या बाधपाती। क्योंकि वेक्टर अदायगी के सम्बन्ध में नितने प्रश्न उपस्थित होवे वह सब बिना किसी बाधा के अदालत दिवालिया द्वारा तय किये जा सकते हैं। इसी प्रकार दिवालिया के मुकद्दमों के सम्बन्ध में यदि और कोई प्रश्न उपस्थित होवे अथवा अदालत इसाफ के लिये किसी प्रश्न का तय करना अचित व आवश्यक समझे तो वह ऐसे भी सब प्रश्नों को तय कर सकती है और अदालत दिवालिया द्वारा दिये हुए फैसले को दीवाना के मुकद्दमों द्वारा रद्द नहीं करया जा सकता है। अर्थात् एक प्रकार से उनकी अग्र तबवान सुदा समझना चाहिये अदालत दिवालिया को इस दफा के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि यदि कोई जस्टिस प्रश्न हक के सम्बन्ध में उपस्थित हो जाय तो उस मामले को बचाय छुद तय करने के अदालत दीवाना द्वारा तय किये जाने का आदेश कर देना चाहिये जिसमें पूर्ण रूप से इसाफ हो सके व किसी फरीज को शिनायत का अवसर प्राप्त न होवे।

अदालत दिवालिया की अधिकार है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिये जो दिवालिया की जायदाद का कर्जदार समझा जाता हो और जो २०० माल के अधिक दूरी पर रहता हो उसके विरुद्ध उसकी हाजिरी तथा बयान के लिये सम्मन जारी कर सके देखो—A. I. R. 1928 Mad. 806 दफा ७ के अनुसार हाईकोर्ट को गारिश दीवाना मामलों के सम्बन्ध में भी अधिकार प्राप्त है यदि गारिश उसकी अधिकार सीमा से बाहर भी रहता हो देखो—51 Mad. 540, A. I. R. 1928 Mad. 752 ('गारिश' यह शब्द मदगल प्राप्त है)।

यदि दफा ७ के अनुसार निम्न गवाह के वयन लिये जावे तो उसको वह सब सुविधायें प्राप्त होंगी जो कानून शहादत (Law of Evidence) के अनुसार गवाहों को प्राप्त होनी चाहिये और वह उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिये बाध्य नहीं

निया जा सकता है जिनका उत्तर वह कानून शब्दावलीके अनुसार देनेसे इनकार कर सकता है। अदालत इस दफाके अनुसार दिवालियेकी जायदादके सम्बन्धमें किसी भी व्यक्ति का क्या ले सकती है और कोई शब्दा इस कारण कि उसका मापदण्ड तब तक उस मापदण्डसे है शब्दाही देनेसे इनकार नहीं कर सकता है देखो—A. I. R. 1920 Mad. 188.

अपील

दफा ८ दिवालियेके मामलोंकी अपील

(१) अदालत अपने दिवालिया सम्बन्धी अधिकारोंको प्रयोग करते हुए जिन हुक्मोंको दे चुकी हो उन हुक्मोंकी यह नजरसानी कर सकती है उनको पलट सकती है अथवा उनमें रद्दोपलट कर सकती है।

(२) कोई भी व्यक्ति जिसने हानि पहुँचती हो दिवालिया सम्बन्धी मामलोंमें दिये हुए हुक्मोंकी अपील निम्न प्रकारसे कर सकेगा:—

(ए) दफा ६ के अनुसार अधिकार प्राप्त किये हुए अदालतके अफसर द्वारा दिये हुए हुक्मकी अपील उस जजके यहां की जावेगी जो दफा ४ के अनुसार दिवालियेके मामले सुनने या तय करनेके लिये नियुक्त किया गया हो। इसके अतिरिक्त कोई आपम्दा अपील यिला उस जजकी भत्ता लिये हुए, नहीं की जावेगी।

(बी) क्लार्क (ए) में यतलार्ड हुई धारोंका ध्यान रखते हुए इस एक्टके अनुसार दिये हुए दिवालियेके अधिकारोंका प्रयोग करते हुए किसी जज द्वारा जो हुक्म दिये जावे उनकी अपील उसी प्रकारकी जावेगी जिस प्रकार उन हुक्मोंकी अपील की जाती है जो दीवानीक मूल अधिकारोंका प्रयोग करने हुए किसी एक जज द्वारा दिये गए हों।

व्याख्या—

उपदफा (१) में यह बताया गया है कि अदालत दिवालिया अपने हुक्मों पर दुबारा और कर सकती है तथा उनपर पलटने व बदलनेका अधिकार भी अपने पास है। इन अधिकारोंसे शीघ्र उसी प्रकार समझना चाहिये जिन प्रकारके अधिकार जजका दायानीके अनुसार अदालत दीवाना द्वारा प्रयोग किये जाया बतलाया गया है। अदालत अपने हुक्मोंकी नजरसानी (Review) कर सकती है तथा वह अपने मूल अधिकारोंका प्रयोग करते हुए उन हुक्मोंको रद्द कर सकता है अथवा आवश्यकतानुसार उनमें रद्दोपलट कर सकती है किसी हुक्मकी नजरसानी (Review) उसी हाकिम द्वारा की जाती है जिसने उस हुक्मको दिया हो पन्तु यदि वह हाकिम बदल गया हो या किसी वजहसे उस जगह पर काम न करता हो और उसकी जगह पर कोई दूसरा हाकिम नाम करता हो तो ऐसा हाकिम भी पहिले हाकिम द्वारा दिये हुए हुक्मोंकी नजरसानी सुन सकता है। नभे कि यदि किसी रजिस्ट्रारने कोई हुक्म दिया हो तो उसकी जगह पर आने वाला व्यक्ति उस हुक्मकी नजरसानी सुन सकता है। यदि हुक्म किसी एक जज द्वारा दिया गया हो तो दूसरा जज जो दिवालियेके अधिकारोंका प्रयोग करता हो पहिले जज द्वारा दिये हुए हुक्मकी नजरसानी (Review) सुन सकता है, देखो—A. I. R. 1925 Cal 786 (F. B.) यदि रजिस्ट्रारने दफा ३६ के अनुसार किसी शब्दाही तलफिका हुक्म दिया हो और वह हुक्मके विषय कोई दरखास्त दिवालियेका काम करने वाले जजके सामने दी जावे तो दरखास्त की उपरदफा (२) के क्लार्क (ए) के अनुसारकी हुई अपील समझना चाहिये, देखो—A. I. R 1928 Cal 786 इसी मामलेमें यह भी तय किया गया था कि यदि किसी जजने एसी दरखास्तकी नजरसानी (Review) समझ कर सुना हो और सुन कर एसी

कर दिया हो तो जन महोदयके हुक्मसे उपद्रवा (१) के अनुसार दिया हुआ हुक्म नहीं समझना चाहिये किन्तु उसका एक प्रमाणसे उपद्रवा (२) क्राज (बी) के अनुसार दिया हुआ हुक्म माना जासकता है । और उस हुक्मकी अपील डिवीजन बैच में की जासकती है ।

उपद्रवा (२) के क्राज (ए) में यह बतलाया गया है कि दफा ६ के अनुसार नियुक्त किया हुआ कोई अग्रजत या अफसर हुक्म देने तो उस हुक्मकी अपील दिवालिएके मामलोंका सुनने वाले जजके सामगरी जा सकती है परन्तु उस हुक्मका अपीलमें जज जो फैसला देगा उसे एक प्रमाणसे अंतिम फैसला समझना चाहिये उसकी दुबारा अपील नहीं की जा सकती है गो माथड़ी साथ यह भी बतला दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपीलमें गिरे हुए जजके फैसलेसे असन्तुष्ट होकर और उसका दुबारा अपील किया चाहे तो उसे अपील करनेमें पाईले उस जजकी आज्ञा ले लना चाहिये जिसने अपील अन्वयको सुना था तब दुबारा अपील दायर की जा सकती है । क्राज (बी) में यह बतलाया गया है कि यदि हाईकोर्ट का कोई जज अपने दिवालिएके अधिकारों का प्रयोग करते हुए पाइ फैसला करे तो उसकी अपील उसी प्रकारकी जा सकेगी जिस प्रकार जायदादीवालिके अनुसार उन फैसलोंकी अपीलकी जासकती है जो उसने अपने दीवानिके मामलोंमें अग्रजतों का प्रयोग करते हुए किये हैं । क्राज (ए) व (बी) में जो अन्तर है उसे भले प्रकार समझ लेना चाहिये अर्थात् क्राज (ए) के अनुसार जजोंमें गिरे हुए फजकी दुबारा अपील नहीं हो सकती है परन्तु क्राज (बी) के अनुसार किये हुए फैसलोंकी अपील हो सकती है दोनों हालतोंमें फैसला करने वाला जज वही है परन्तु पहिली हालतमें जज फैसला अग्रजत अपीलकी भाँति दिया है व दूसरी हालतमें अभी जज का फजका अपील का फैसला नहीं है किन्तु वह फैसला उसका स्वयं फैसला है जिस इन्तजारे फैसला वह करती है ।

दूसरा प्रकरण



दिवालिएके कामसे लेकर बहाल होने तककी कार्रवाहियाँ

दिवालिएके काम

दफा ९ दिवालिएके काम

कजईशर नीचे दिये हुए कामोंमेंसे किसी कामको करे तो माना जायेगा कि उसने दिवालिए का काम किया है—

- (ए) यदि ब्रिटिशभारतमें अथवा अन्य किसी स्थानमें वह अपनी कुल जायदादको या क्रीय २ स्वयं जायदादको अपने कजईखाहोंके लाभार्थ किसी तीसरे व्यक्तिके हकमें कर देवे ।
- (बी) यदि वह ब्रिटिशभारतमें अथवा अन्य किसी स्थानमें अपनी जायदाद या उसका कोई हिस्सा अपने कजईखाहोंके हक मारने या उनके कजईकी अदायगीमें देर करने की मंशासे अलहदा कर देवे ।
- (सी) यदि ब्रिटिशभारतमें अथवा अन्य किसी स्थानमें वह अपनी जायदाद या उसके किसी

भागके सम्बन्धमें कोई ऐसा इन्तकाल करे जो इस एक्टके अनुसार अथवा किसी अन्य प्रचलित एक्टके अनुसार घोषा देहलसे तर्जिह देने का सौदा समझ कर उसके दिवालिया करार दिये जाने पर रह समझा जा सके ।

(४१) यदि वह अपने कर्जकर्त्ताओं का कर्ज मारने या उसमें देर करनेकी नियतसे

(i) ब्रिटिश इण्डिया (British India) के बाहर चला जावे या वहां बना रहे

(ii) अपने रहनेके स्थान या अपने अधिकतर व्यापार करनेके स्थानसे चला जावे या किसी जगहसे वहां न रहे

(iii) छिप जावे जिसमें कि उसके कर्जकर्त्ताहानको उसकी खबर न मिल सके

(४२) यदि उसकी जायदाद रुपयेकी अदायगीके लियेकी हुई डिक्लीके आधार पर कुर्की की गई हो और कुर्की का हुक्म कमसे कम २१ दिनसे बना हुआ हो ।

(एफ) यदि वह दिवालिया करार दिये जानेके लिये दरखास्त देवे ।

(जी) यदि वह अपने किसी कर्जकर्त्ताको इस प्रकारका नोटिस देवे कि उसने अपने कारोबारको बंद कर दिया है अथवा वह उसे बंद करने वाला है ।

(एच) यदि वह रुपयेके अदायगीके सम्बन्धमेंकी हुई किसी डिक्लीके आधार पर कैद होवे

व्याख्या (Explanation) इस दफाके लिये एजेंटका काम उसके मालिकका काम समझा जावेगा चाहे उस एजेंटको अपने मालिक (Principal) की ओरसे उस कामकी करनेके लिये कोई अधिकार प्राप्त न होवे ।

व्याख्या—

इस दफामें दिव लियेके कामों का उल्लेख किया गया है अर्थात् वह काम बताने के लिये हैं जिनके होने या न होने पर मान लिया जावेगा कि कर्जदारने दिवालीके का काम किया है । इस दफामें या इससे पहिले कहीं पर यह नहीं बतलाया गया है कि कर्जदार किस व्यक्ति की सम्पत्ति चाहिये । दफा ४ के प्राक् (बी) में देवकालत बतलाया गया है कि मजदूर (Judgment debtor) को भी कर्जदार समझना चाहिये अर्थात् उस दफामें ही है कर्जदारकी परिभाषा पूर्ण परिभाषा इतिहास नहीं समझी जा सकती है । तथा उधार देने वाले व कया उधार लेने वालेसे जो सम्बन्ध होता है वह कर्जकर्त्ता है व कर्जदार का सम्बन्ध हुआ करता है । कर्जदार मुद्र का अं नो बहुत लोभ समझा करते हैं वही समझना चाहिये । हाई-कोर्टने अपने फैसलोंमें जहां तहां इस शब्दके अर्थमें कभी २ कुछ प्रस्ताव बनाये हैं अर्थात् उनमें यह निश्चित किया गया है कि व्यापारी व्यक्ति विशेष कर्जदार है अथवा नहीं है ।

जैसे कि मद्रास हाईकोर्टने यह तय किया है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्तिमें किसी तीसरे व्यक्ति में अर्थात् करनेके लिये कोई वस्तु लेवे तो तथा इस प्रकार लेने वाले व्यक्तिको कर्जदार नहीं समझना चाहिये देखो—36 Mad 494. इसी प्रकार यह भी तय हुआ है कि यदि कोई कर्जदार किसी मूलरक्त खानदारके कारोबारके लिये किसी व्यक्ति की सहायता में लिया गया हो तो वह सहायता ऐसे कर्जदारके लिये दिवालिया करार नहीं दिया जा सक्ता है देखो—41 Mad 824.

गैर मुद्र का रहने वाला (Foreigner) भी दिवालिया करार दिया जा सकता है यदि उस एकदमसे रहलार्ह हुई हो परी दाती होवे । मद्रास हाईकोर्टने यह तय किया था कि यदि कोई गैर मुद्र का रहने वाला जो ब्रिटिश इण्डियामें बाहर रहता

हो ब्रिटिश इण्डियामें कारोबार करता हो और वह कारोबार किसी एजेंटके जायिये बम्बईमें किया जाता हो तो बम्बईमें उसके तबदील कारोबार हो सकता है । चीफ जास्टिस मि० सारिजेन्ट यहोयने इस सम्बन्धमें अपनी यह राय प्रकट की थी कि बार मुल्क का माशुल्क अगर स्वयं कारोबार ब्रिटिश इण्डियामें न करता हा तो वह जाती तोरसे यहांके कानूनाकी पाबन्दाके लिये बाध्य नहीं है लेकिन अगर वह अपना कारोबार यहां करे और उस कारोबारसे लाभ उठाना चाहता है वह मान लिये जावेगा कि वह अपने उस कारोबारके सम्बन्धमें यहांके कानूनाकी पाबन्दाके लिये तैयार है और इसी कारण यहांकी अदालतें उसके विरुद्ध हारनाई करनेकी अधिकारिणी है । देखो—17 Bom 662

कर्तदार इस दफाके अनुसार कोई व्यक्ति भी हो सकता है तथा कोई फर्म भी हो सकता है जो लोग सही मुआहिदा कर सकते हैं वह लोग इस एक्टके अनुसार दिवालिया करार दिये जा सकते हैं यदि इस एक्टमें बतलाई हुई शर्तोंकी पूर्ति होती है । जैसे कि दिवालिया रमी कर्जदार हो सकती है जवाबिया बन्ने दिवालिया करार नहीं दिये जा सकते हैं देखो—43 Cal. 1157 इसी प्रकार पागल भी दिवालिया करार नहीं दिये जाने चाहिये ।

क्लाज (ए) में इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि कर्जदार अपनी सब जायदाद या करीब २ सय जायदादकी मुलत किल कर दे यदि वह अपनी जायदाद का कोई कुछ हिस्सा ही इस कर्जमें बतलाव हुई शर्तके साथ अलहाद कर दे तो इस क्लॉजकी पूर्ति नहीं समझना चाहिये इस क्लॉज अनुसार जायदाद किसी तीसरे व्यक्तिने इन मशयसे देना चाहिये जिसमें कि वह उसके सब कर्जस्वादानका ही जा सक । जैसे कि अपनी सब जायदाद के लिये दूरियोंका मुकदर कर देना जिसमें कि वह दूसरा उसकी जायदादकी उसके कर्जस्वादानमें बाध सके । इस क्लॉजके लिये यह आवश्यक नहीं है कि जायदाद केवल ब्रिटिशभारत (British India) ही में इस प्रकार अलहादकी गई हो उसकी बलवर्गी ब्रिटिशभारतके अनिश्चित अम जगहोंमें भी हो का सकती है । इस प्रकार इस क्लॉजसे यह तात्पर्य निकलता है कि दिवालियेका काम ब्रिटिश भारतके बाहर भी हो सकता है । जायदादका इन्तकाल इस क्लॉजके अनुसार बाकायदा किया जाना चाहिए सिर्फ जबकी वह देनसे या अधूरी तहरीसे काम नहीं चल सकता है ।

क्लाज (बी) के अनुसार यदि कोई कर्जदार अपनी सब जायदाद वा उसके किसी भागको इस नौबतस हटा देने कि जिसमें उसके कर्जस्वादाकी वसूलिये देर हैवे अपना उनकर कर्ज माग आवे तो कर्जदारके इस कामको भी दिवालिया काम माना जावेगा । इस क्लॉजके अनुसार भी जायदादका हटाया जाना ब्रिटिश भारतमें अपना उसके बाहर किया जा सकता है अर्थात् इस प्रकारका इन्तकाल जायदाद ब्रिटिश भारत ही में किये जानेकी आवश्यकता नहीं है । इस क्लॉजस भी बहू तात्पर्य निकलता है कि दिवालियेका काम ब्रिटिश भारतके बाहर भी किया जा सकता है इस क्लॉजमें यह बात ध्यान रखने योग्य है कि जायदाद कुछ या उसका कोई हिस्सा हटाया जा सकता है वो क्लॉज (ए) में ऐसा नहीं था उसके अनुसार सब जायदाद या करीब २ सय जायदाद अलहादकी जाना चाहिये इस क्लॉजके अनुसार जो इन्तकाल किया जाने वह कर्ज मान या उसकी अदायगामें देर करनेकी मशयसे किया जाना चाहिये पल्लु क्लॉज (ए) के अनुसार जो इन्तकाल किया जावेगा वह कर्जस्वादानके लाभमें किया जावेगा ।

क्लाज (सी) के अनुसार भी इन्तकाल जायदाद चाहे ब्रिटिशभारत में किया जावे चाहे उसके बाहर । इस क्लॉजके अनुसार वह इन्तकाल जायदाद ऐसा होना चाहिये जो घोरतदेहीसे तनोद देने वाला इन्तकाल समझा जावे अर्थात् यदि इन्तकाल जायदाद करने वाला कर्जदार दिवालिया करार दे दिया जावे और उसके बाद वह इन्तकाल जायदाद किसी एक कर्जस्वादानके दूसरे कर्जस्वादानके मुकानिये तर्नीह (Preference) देवे

ज्ञाना इन्तजाल करार देकर रह गया जाके तो ऐसे इन्तकाल जायदादके किये जाने पर दिवालियका काम समझना चाहिये । इस क्राजके अनुसार भी यह आवश्यक नहीं है कि कर्जदार अपनी कुंज जायदाद अन्तः कर देने वह अपनी कुल जायदाद या उसका कोई हिस्सा अन्तः कर देने पर इस क्राजके अन्त आशये । यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि इस कलाजके अनुसार किया हुआ इन्तकाल तर्जिह देने ज्ञाना होना चाहिये अर्थात् किसी कर्जदारके इन्तमें यानी बंध दूसरे कर्जदारोंके मुक्त बिके लाभ पूर्ववत् मशाले किया जाना चाहिये ।

फलाज (डी) यह तीन उपकलाओंमें विभक्त है पहिले उपकलाज (१) के अनुसार यदि कर्जदार मिटिशमायते बाहर बजा जावे अथवा यदि वह पहिलेसे बाहर गया हुआ हो और बाहरी बना रहे तो उसका यह काम दिवालियका काम समझा जावेगा । परन्तु इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि इस प्रकार बाहर जाना या बाहर रहने कर्जदारोंका कर्ज मारने या उसकी अदायगीमें देर करनेकी मशाले किया गया हो । दरम्याल दिवालियामें कर्जदारकी इस प्रकारकी मशाले साफ तौरसे दिखाना देना चाहिये परन्तु यदि दरम्याल दिवालियामें इस प्रकारकी मशाले न दिखलाई गई हो तो वरकलासती तर्जिहमें जो हलफनामा लुखिल किया गया हो उसे देखना चाहिये और यदि हलफनामामें इस प्रकारकी मशाले बतलाई गई हो तो उसे पर्याप्त समझना चाहिये अर्थात् वह उस दरम्यालके आधार पर कर्जदार दिवालिया करार दिया जासकता है, देखो—37 Mad 505 अधिकतर इस प्रकारकी मशाले कर्जदारके नामों द्वारा ही साबित हो सक्ती है । यदि किसी कर्जदार एक शरीकदार कोई बाहर बजा जावे तो केवल उसकी चले जानेके कारण कर्ज दिवालिया करार नहीं दिया जाना चाहिये क्योंकि एकके चले जानेसे सब कर्जदारोंका चला जाना नहीं माना जासकता है अपने व्यापारीकी जगहसे कर्जदारोंका कर्ज मारनेकी शरअसे बाहर जाना दोनों शरीकदारोंका होना चाहिये तभी यह कलाज लागू होगा, देखो—24 Bom L R 861. इस कलाजके उपन्यास (11) के अनुसार यदि वह कर्जदारोंका कर्ज मारने या उसमें देर करनेकी मशाले किसी प्रकार भी रीर हाजिर रहे तो उसका यह काम दिवालियका काम समझा जावेगा इस उपकलाजमें रहने वाले मकानका जो जिक्र है उससे अभिप्राय पुरस्किन् (Permanent) रहने वाली जगह ही से नहीं है किन्तु वह जगहसे भी समझना चाहिये जहां कर्जदार रहने लगा हो क्योंकि इस कलाजमें पुरस्किन् कोई उल्लेख नहीं है । रोजगारकी जगहसे तात्पर्य उस जगहका समझना चाहिये जहां अधिकतर कर्जदार रोजगार करता है क्योंकि अंग्रेजी एकटके इस कलाजमें (Usual) शब्दका प्रयोग किया गया है । इस शब्दसे यह भासित होता है कि यदि कर्जदारने किसी जगह कोई एक आव सोटा खरीदा या बेचा हो तो उस जगहकी उसकी रोजगारकी जगह नहीं मान लेना चाहिये । अगर वह किसी खास जगह पर दूकान खोल कर अपना कारोबार करता हो । इस क्राजके उपकलाज (11) के अनुसार कर्जदारका छिना जिनसे कि उसके कर्जदार उसकी खबर न पासके एक प्रकारसे दिवालियका काम है । यह छिना भी कर्ज मारने या उनके अदायगीमें देर करनेकी मशाले किया जाना चाहिये और साथ ही साथ यह छिना ऐसा होना चाहिये कि उसके कर्जदार उसमें पर ओझार न कर सके यानी जिसमें उनकी उसकी खबर न मिल सके ।

फलाज (ई) के अनुसार कर्जदारकी किसी जायदादका इजाज किसी दूसरेमें बचा जाना दिवालियका काम है । इसी प्रकार यदि कर्जदारकी कोई जायदाद इजाज, डिजमें दुर्क दुई हो और वह कुर्की २६ दिन या इससे

अधिक दिनोंसे कायम हो तो भा दिवालियेका काम समझा जावेगा । डिमी जिसका निकटम छाजमें दे वह रुपयेकी अदायगीके सम्बन्धमें जाना चाहिये । फसल सालका ठिकाना दे और उमर अनुसार याद करी हुई हो तो वह दफा (१) के अनुसार नहीं जायकता है देखा—A. I. R. 1928 Cal. 840.

यदि कर्जदार स्वयं दिवालिया करार दगा दस्तखत दे तो कर्जदारका यह काम बलाज (एक) के अनुसार समझा जावेगा ।

दफा (जी) में यह बतलाया गया है कि यदि कर्जदार अपने किसी कर्जवाहको इस बातका नोटिस देते कि उसने अपने कर्जोंका चुकाना बन्द कर दिया है या वह बन्द करने वाला है तो उसका यह काम दिवालियेका काम समझा जावेगा । इस बलाजमें यह कहीं पर नहीं दिया हुआ है कि नोटिस लिखकर ही दिया जाना चाहिये या नोटिस किसी खास किरनका दिया जाना चाहिये । इस कारण नोटिसके लिखकर ही देनेकी आवश्यकता नहीं है और न यह आवश्यकता है कि वह किसी खास तथके (Forum) ही जा देवे । इस बलाजमें बतलाया हुआ नोटिस सब कर्जवाहोंको एक साथ देनेकी आवश्यकता नहीं है किन्तु नोटिस किसी एक कर्जवाहको भी दिया जासकता है ।

दफा (एच) के अनुसार यदि कानूनी अदायगीके सम्बन्धमें का हुई डिमीके इनगाममें कर्जदार बन्द किया गया हो तो इसको भा दिवालियेका काम समझना चाहिये । इस दफाके अन्तमें जो व्याख्या (Explanation) दी हुई है उसके अनुसार एजेण्ट द्वारा किया हुआ काम भी मालिक (Principal) द्वारा किया हुआ काम समझना चाहिये चाहे उसके उस काम कमेका आशय खरोद रूपसे न दिया गया हो । यदि एजेण्ट बगैर एजेण्टके कोई काम अपने मालिक (Principal) के लिये करे तो एजेण्टका वह काम मालिकका काम मानकर वह दफा ९ के अनुसार दिवालियेका काम समझा जावेगा और मालिक ऐसे दिवालियेके कामके आधार पर दिवालिया करार दिया जायकता है ।

दिवालिया करार दिये जानेका हुकम

दफा १० दिवालिया करार देनेके अधिकार

इस एन्टमें दी हुई शर्तोंका ध्यान रखते हुए यदि कर्जदार किसी दिवालियेके कामको करे तो दिवालियेकी दरखास्त उसका कोई कर्जवाह या वह स्वयं देसकता है और अदालतको अधिकार है कि वह ऐसी दरखास्त (Petition) पर उस कर्जदारके दिवालिया करार दिये जानेका हुकम दे देवे । यह हुकम दिवालिया करार दिये जानेका हुकम (Order of Adjudication) कहलायेगा ।

व्याख्या—

कर्जदार द्वारा दिवालियेकी दरखास्तका दिया जाना दिवालेका काम समझा जावेगा और अदालत उस दरखास्त पर दिवालिया करार दिये जानेका हुकम दे सकती है । दफा ९ में बतलाये हुये दिवालियेके काम करने या होने पर तथा इस एन्टमें बतलाई हुई आर शर्तोंकी पूर्ति होने पर कर्जदार स्वयं या उसके विरुद्ध उसका कोई कर्जवाह दिवालिया करार दिये जानेके लिये दरखास्त अदालत दिवालियेमें दे सकता है और ऐसी दरखास्त शुजुने पर अदालतको अधिकार है कि वह

कर्जदारको दिवालिया करार दे देवे। इस प्रकार दिवालिया करार दिये जानेका जो हुक्म दिया जावगा उसे दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म (Adjudication order) कहेंगे। इस दफ्तर यह भली भांति प्रकट है कि अदालत दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्म देनेके लिये बाध्य नहीं है किन्तु उसका देना न देना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है। अर्थात् एप्रैल इस दफ्तर (May) शब्दका प्रयोग किया गया है। इस दफ्तरमें यह बात भी साफ तौरसे बतला दी गई है कि दरखास्त दिवालिया कर्जदार स्वयं या उसका कोई कर्जस्वाह दे सकता है नर्तने कि उस एक्टमें बतलाई हुई सब शर्तें पूरी होती होंगे। दरखास्त दिवालिया उसी समय कर्जदार मजदुरी हावेगी जब कि दफ्तर ९ में बतलाया हुआ कोई दिवालेका काम हुआ हो। पण्डित इस दफ्तरके अन्तमें जो व्याख्या दी हुई है उसके अनुसार कर्जदार द्वारा दिवालियेकी दरखास्तका दिया जाना है दिवालेका काम है इसलिये कर्जदार द्वारा दी जाने वाली दरखास्तके लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह दफ्तर ९ में बतलाए हुए किसी दिवालियेके कामके आधार हो। पर दी जाव। कर्जस्वाह द्वारा दी जाने वाली दरखास्तके लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि दफ्तर ९ में बतलाये हुए दिवालियेके कामोंमें से कोई काम अवश्य दिखलाया जावे और ऐसे कामके होने पर ही कर्जदार अपने कर्जस्वाहको दिवालिया करार दिवानेका अधिकारी होगा अन्यथा नहीं। व्याख्यासे यह भली भांति प्रकट है कि कर्जदार द्वारा दी जाने वाली दरखास्त पर भी अदालत उसको दिवालिया करार देनेके लिये बाध्य नहीं है क्योंकि ऐंजली एक्टकी इस दफ्तर (May) शब्दका प्रयोग किया गया है अर्थात् उस दरखास्त पर भी अदालत अपनी इच्छानुसार दिवालिया करार देनेका हुक्म दे भी सकती है और देनेसे इनकार भी कर सकती है। यदि कोई कर्जदार अदालतकी अधिकार सीमाके अन्दर दिवालियेका काम करे तो अदालतको अधिकार है कि वह उसके विरुद्ध जायदाद वसूल करनेका हुक्म दे सकती है और इस बातमें कोई भी शक नहीं रहेगी कि वह कर्जदार इंग्लैण्ड (England) में दिवालिया करार दिया जाइगा है अर्थात् इंग्लैण्डमें दिवालिया करार दे दिये जानेका कोई अंतर यहाँ की दिवालिया सम्बन्धी कानूनोंमें स्थावत नहीं बालेगा देखो—331 Cal. 761.

दफ्तर ११ अधिकारोंमें रुकावट

अदालतको दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म देनेका अधिकार उस समय तक न होगा जब तक कि—

- (ए) दिवालियर करार दिये जानेकी दरखास्त दाखिल करते समय कर्जदार अपने सम्बन्धमें की हुई डिक्रीके इजरायके अनुसार किसी ऐसे कारावासमें न होवे जहाँ कर्जदार दिवालीके मूल अधिकारोंका प्रयोग करते हुए अधिकतर रहने जाते हैं। या
- (बी) दिवालियेकी दरखास्त देनेसे पहिले कर्जदार एक साल तक अदालतकी मामूली दीधानीके अधिकारोंके अनुसार बतलाई हुई अधिकार सीमामें न रहा हो या उसके रहनेका मकान न होवे अथवा उसने स्वयं या किसी एजन्टके ज़रिये उस सीमाके अन्दर रोजगार न किया हो। या
- (सी) कर्जदार स्वयं अपने लामार्थ कोई काम अदालतकी सीमाके अन्दर न करता हो। या
- (डी) यदि किसी फर्मने दिवालियेकी दरखास्त दी होवे अथवा किसी फर्मके विरुद्ध दरखास्त दी गई हो तो जब तक कि उस फर्मका कारोबार दिवालियेकी दरखास्त दाखिल करनेसे पहिले एक सालसे अदालतकी ऊपर बतलाई हुई अधिकार सीमाके अन्दर न रहा हो।

व्याख्या—

यदि किसी बिक्रीमें यह हुक्म होवे कि कर्णेशी अदायगी न की जाने पर रहनेकी हुई जायदाद मौलायकी अवधिगी तो ऐसी बिक्रीका कर्णेशी अदायगीके सम्बन्धमें ही हुई किसी समझना चाहिये 28 Mad 473 इस दफामें यह बातलया गया है कि किन्तु २ दफाओंमें अदायगीसे दिवालिया करार देनेका अधिकार न हुआ। ज्ञान (ए) के अनुसार दिवालियेकी दख्खास्त दिये जाने समय कर्जदारका जेल दानानामें दाना एक आवश्यक बात है। कलाज (बी) के अनुसार दिवालियेकी दख्खास्त दिये जानेसे पाहल एक सालके अंदर तक कर्जदारका अदालतमें अधिहार सीमाके अंदर रहना आवश्यक है अथवा चाने (कर्जदारने) इस अवधि तक उस सीमामें स्वयं या किसी एजेंटके आये करोंका बरिया हो अथवा उसका रहनेका मकान उस सीमाके अंदर होवे। कलाज (सी) के अनुसार कर्जदारका अपने लाभके लिये अदालतमें अधिहार सीमा के अंदर काम करना आवश्यक बातलया गया है ज्ञान (डी) के अनुसार यदि किसी कर्मके विरुद्ध या उसमें औरसे दिवालिया करार दिये जानेकी दख्खास्त दी जावे तो उस कर्मका कामका अदालतकी अधिहार सीमाके अंदर दख्खास्त देनेसे पहिले कमसे कम एक सालतक दाना आवश्यक है।

फलाज (ए), (बी), (सी), च (डी) में बतलाई हुई शर्तोंका एक साथ होना आवश्यक नहीं है इन शर्तोंके बीच में ' या ' लिखा हुआ है। मतसे यह भला भाति प्रकट है कि उन शर्तोंमेंसे किसी एकका होना आवश्यक है अर्थात् अदायत किसी कर्जदारमें उस समय तक दिवालिया घोषित नहीं करगी जब तक ज्ञान (ए) (बी), (सी) या (डी) में बतलाई हुई कोई न कोई बात उपरिगत न जावे। इस दफाकी पाचवीं अदालतके लिये आवश्यक है अर्थात् अदालत उसकी अवहेलना नहीं कर सकती है अथवा एजेंटकी इस दफामें (Shall) शब्दका प्रयोग किया गया जिससे ऊपर लिखी हुई बातों का पूर्ण प्रकार पुटि होती है।

फलाज (बी) के अनुसार दख्खास्त दिवालियाके दिये जाने पर एक सालके अंदर कर्जदारका अदालतके अधिकार सीमामें रहना या रहनेका मकान रखना अथवा व्यापार करना आवश्यक बातलया गया है व्यापार करनेके सम्बन्धमें यह भी बातलया गया है कि कर्जदार स्वयं व्यापार करता हो या किसी एजेंटके लिये करता हो परन्तु एजेंटसे तारार्य उस एजेंटका समझना चाहिये या वाक्यानुसृतताविषय तर्कमें उसका एजेंट होवे अर्थात् जो व्यापार एजेंट द्वारा किया जाया है उसकी देव रेल स्वयं वह एक प्रमाण करता जावे एजेंटने तात्पर्य ऐसे आम एजेंटसे न समझना चाहिये कि जो अपने नामसे बहुतेरे लिये कारोबार करता हो और उन लोगोंसे बर्फीयान लेता होवे देखो—23 Mad. 458, A. I R 1929 Sind 24 अधिहार सीमाके अंदर रहना या ठममें रहना मकान हालमें तात्पर्य यह है कि तकनीयतामें उसका सम्मान अधिकार सीमामें हाव यह नहीं कि रहने वाला कहीं का जावे और मित्र दख्खास्त देनेकी नीयतसे अधिकार सागका अंदर चन्द दिनोंके वास्तव्यका आव पण्डु यदि बाहरका कोई आदमी कागजारक मिलासनेमें अदालतकी अधिहार सीमाके अंदर आ गया हो और वहीं वह रहने भी लगे अथवा उस समय कहीं बाहर उसके रहनेका स्थिति न होवे तो ऐसे व्यक्तिकी वहीश रहने वाला समझना चाहिये तथा ऐसे व्यक्तिके लिये सज्जती मकानका रहना भा कदा जा सक्ता है कलकत्ता हाईकोर्टने 21 Cal. 63 में यह तय किया गया था कि कर्जदार इन्ड्रलेण्डसे कलकत्ता आया था और वहां वह चन्द माह तक एक होम्में ठहरा रहा और रोजगारकी तन्त्रायमें रहा और उसके पश्चात् उसकी कानून दिवालियामें लाभ उठानेकी आवश्यकता पड़ा तो वह तय हुआ कि वह नेकनीयतीसे वहां आना था जिस समय कि दिवालियेकी दख्खास्त दी गई थी और उसीके साथ २ इस बातका ध्यान रखना गया था कि उसकी सज्जती जिसका दूसरी जगह नहीं थी।

एक पुरोहित दूसरी अपीलमें ११ अगस्त तक पिय २ शि यॉरे पास बन्धईमें रहा तो उसके लिये यह तय हुआ था कि उसका बन्धईमें रहना नहीं समझा जायेगा 111 Bom. 290. घूमेने मात्रके लिये जमाना बढ़ा। रहनेके बन्धन नहीं हो सकता है। रहनेके तौर पर उस जगहसे माफूम होता है जहां वह खाना पीता या सोता होवे या जहां उसने खानदानी या नौकर खान पाये या सोते होवे 38 Cal. 394. यदि किसी आबन्धक हिन्दू परिवारका कर्तो किसी अगढ़ मरीवार करता हो तो यह नहीं मान लिया जायेगा कि उस परिवारका दूसरा मेम्बर भी वहां कामकाज करता है देखो—23 Mad. 458.

क्लाज़ (डी) में उन मामलोंके बारेमें बतलाया गया है जब कि किसी कर्मके विरुद्ध दिवालिया करार दिये जाने की दारखास्त दी जाय अथवा किसी कर्मके अपने दिवालिया करार दिये जाने की दारखास्त दी हो तो कर्मके दिवालिया करार दिये जाने के सम्बन्धमें यह बतलाया गया है कि कर्मका नाम दिवालियागी दारखास्त दिये जानेसे पहिले एक सालके अन्दर अदालतकी अतिरिक्त सोमाक्रेन्डर होना आवश्यक है अन्यथा अदालत, कर्म को दिवालिया करार नहीं देगी। इस दफ्तेके चारों क़ाज़ बिनाभिन्न है एक दूसरेके आधार पर नहीं है और उनमेंसे किसी भी क़ाज़में बतलाई हुई बातके होने पर अदालतकी अधिकार सामा प्राप्त हो सकता है अथवा नहीं अदालत इस दफ्तेमें बतलाये हुए नियमको माननेके लिये बाध्य है इनकी अवहेलना नहीं कर सकती है।

दफा १२ यह शर्तें जिनके अनुसार कर्ज़स्वाह दिवालिया करार दिलानेकी दारखास्त दे सकता है

(१) किसी कर्ज़स्वाहको अपने कर्ज़दारके विरुद्ध दिवालिया करार दिये जानेकी दारखास्त देनेका अधिकार उस समय तक न होगा:—

(ए) जब तक कि कर्ज़दारसे लिया जाने वाला कर्ज़स्वाहका कर्ज़ पांच सौ रुपये ५००) न होवे परन्तु उस समय जब कि दारखास्त देने वाले एकसे अधिक कर्ज़स्वाह होवे तो उन सब कर्ज़स्वाहोंके कर्ज़का जोड़ पांच सौ रुपये होना चाहिये।

(बी) जब कि अदा किया जाने वाला कर्ज़ एक निश्चित धन राशिके रूपमें न होवे जो उसी समय अथवा भविष्यमें किसी निश्चित समय पर चुकाया जाने वाला होवे।

(सी) जब तक कि यह दिवालियेका काम जिसके आधार पर दिवालियेकी दारखास्त दी गई हो दारखास्त देने समयसे तीन माहके अन्दर न हुआ हो।

(२) यदि दिवालियेकी दारखास्त देने वाला सहफूज़ कर्ज़स्वाह (Secured Creditor) होवे तो वह अपनी दारखास्तमें यह बतलायेगा कि वह अपनी जमानतकी कर्ज़दारके सब कर्ज़-क्यादानके लामार्थ छोड़ देवेगा यदि कर्ज़दार दिवालिया करार दे दिया जावेगा अथवा उसे उस जमानतकी अन्दाज़ा लगाई हुई कीमत भी बतला देना चाहिये। जब कि वह अन्दाज़ा लगाई हुई जमानतकी कीमत बतलावेगा तो उसकी दारखास्त उस रुपयेके लिये मानी जावेगी जो उसके असली कर्ज़में से जमानतकी अन्दाज़ा लगाई हुई कीमत घटानेसे बचे और इस प्रकार निकले हुए रुपयोंके लिये वह बिला सहफूज़ (The Secured Creditor) मान लिया जावेगा।

व्याख्या—

इस दफ्तेमें इन बातोंका विवरण है निम्नके आधार पर कर्ज़स्वाह अपने कर्ज़दारके विरुद्ध दिवालिया करार दिये जानेकी दारखास्त दे सकता है। यह दफा दो भागोंमें विभक्त है पहिले भागमें आम कर्ज़स्वाहोंका उल्लेख है तथा दूसरे भागमें

महजुज कर्जस्वाहका वर्धन है । पहिले माममें तीन शर्तें बतलाई गई हैं जिनके उपरिधन होने पर ही कर्जस्वाह अपने कर्जदारके विरुद्ध दिवालयिये की दरखास्त देनेका अधिकारी हो सकता है । जैसेकी एकटा इश दफ्तमें (Shall) शब्दका प्रयोग किया गया है जिससे यह प्रकट है कि इस दरजेके लियेकी गानना आवश्यक है और उनकी अवइलना नहीं की जासकता है इस भागक ज्ञात (ए) में यह बतलाया गया है कि अगर कोई एक कर्जस्वाह अपने कर्जदारक विरुद्ध दिवालयिये की दरखास्त देवे ता उस कर्जस्वाहका बका (५००) रुपये या उससे अधिक होना चाहिये और यदि एक्स अधिक कर्जस्वाह मिउतर कामा कर्जदारक विरुद्ध दिवालयिये की दरखास्त देवे तो उन सब कर्जस्वाहोंके कर्जेका जाड (५००) रुपये या उससे अधिक होना चाहिये ।

कलाज (धी) के अनुसार जिस कर्जेके आधार पर दरखास्त दी गई हो वह एक निश्चित धन राशिके रूपमें होना चाहिये और चाहे वह धन पशि उसी समय अदारी जानेकी होवे अथवा उसकी अदायगी मन्थियमें किसी निश्चित समय पर की जानेका होवे ।

कलाज (सी) के अनुसार जिस दिवालयिये कामके आधार पर दरखास्त दी गई हो वह दरखास्त दिये जानेकी तारीखके ताल माहके अन्दर होना चाहिये अथात् दरखास्त देनेमें पाहिले तीन माहक अंदर कर्जदारने दफा १ में बतलाई हुए कामोंमें से निर्मा कामको किया हो । तीन माहके अन्दर ही दिवालयिये काम किया गया हागा तबक अदारी पर दिवालयिये की दरखास्त नहीं चल सकती है । हा यह अवश्य हो सकता है कि कोई काम ताल महीनेसे पहिले प्रारम्भ हुआ हो और वह ताल माहक अंदर तक जारी रह जसे कि यदि कर्जदार पहिलेस बाहर गया हो न वहाँ बना रह ।

उपदफा (२) में महजुज (Secured) कर्जस्वाहोंके बाबत मसला साक किया गया है उसके अनुसार महजुज कर्जस्वाहोंके लिये दो शर्तें हैं एक ता यह वह महजुज कर्जस्वाह अपनी खमान सब कर्जस्वाहानके लाभाप छूट देने अपोंद वह अपनी दरखास्तमें यह बतला देवे कि यदि कर्जदार दिवालयिया करार दे दिया जावे ता उसका कज भी और निम्न महजुज कर्जस्वाहोंकी भुजि समझा जावेगा तथा वह अपनी खमानस सब कर्जस्वाहानके लाभाप छूट देगा । दूसरा शर्त ता यह है कि वह खमानसकी हुई नायदासकी खमानस अदराना दे सकता है परन्तु जब वह ऐसा करेगा तब दिवालयिये की दरखास्त देनेके लिये उसका उतना ही कर्ज समझा जावेगा ज् उसके अपनी कर्जों से खमानसकी अदराना लगाई हुई कामन पशनेक बाद बचता । दरखास्त देने बाद कर्जस्वाहका यह कर्तव्य होता कि वह इस उपदफाम बतलाई हुई दो बातोंमें से किसी एक बातकी अवहअ अपना दरखास्तमें बतला देवे वरना उसकी दास्तास्तर्की पूर्ति नहीं होगी । इस बातका भी ध्यान रखना चाहिये कि उसका कर्ज दोनो ही दफाओंमें (५००) रुपये अथवा उसमें अधिक होना चाहिये ।

दफा १३ कर्जस्वाहकी दरखास्त पर कार्यवाई तथा उस पर हुकम

(१) कर्जस्वाहकी दरखास्तके साथ उसकी पुष्टिके लिये हलफनामा दाखिल किया जावेगा और वह हलफनामा चाहे कर्जस्वाह स्वयं दाखिल करे अथवा उसकी ओरस काइ अन्य व्यक्ति दाखिल करे जिसे हालात मालूम हों ।

(२) दरखास्त सुनते समय अदालत नीचे दी हुई बातोंका सुधून लेगी—

(ए) दरखास्त देने वाले कर्जस्वाहका कर्ज, और

(बी) दिवालयिया का काम या यदि दरखास्तमें एकसे अधिक दिवालयियेक काम बतलाये गये हों तो उनमेंसे कोई एक दिवालयियेक काम

(३) अदालत दिवालियेकी दरखास्त सुननेकी तारीख बढ़ा सकती है और यह हुक्म दे सकती है कि उसकी इच्छा कर्जदारको दी जावे ।

(४) अदालत नीचे दी हुई बातों पर दरखास्तको स्वीकृत कर देगी ।

(ए) यदि वह उपदफा (२) में बतलाये हुये सुवृत्तसे सन्तुष्ट न होवे, यां

(बी) यदि कर्जदार हाज़िर होकर अदालतको विश्वास दिला दे कि वह अपने कर्जों को अदा कर सकता है या उसने कोई दिवालियेका काम नहीं किया है या किसी अन्य पर्याप्त कारणसे कोई हुक्म उसके विरुद्ध नहीं दिया जाना चाहिये ।

(५) यदि ऊपर बतलाये हुए सुवृत्तसे अदालत सन्तुष्ट हो जावे तो वह दिवालिया क्रार दिये जाने का हुक्म दे सकती है और उस समय भी वह हुक्म दे सकती है जबकि उपदफा (३) के अनुसार तारीख बढ़ाई गई हो और उस तारीख पर काफी तामील हो जाने पर भी कर्जदार हाज़िर न होवे परन्तु वह ऐसा हुक्म उस समय नहीं देगी जबकि उसकी रायमें दिवालियेकी दरखास्त किसी दूसरी अदालतमें दाखिलकी जाना चाहिये ।

(६) जब कि कर्जदार दरखास्त पर हाज़िर होवे और दरखास्त देने वाले कर्जद्वाराहके कर्जोंको मंजूर न करे अथवा यह मंजूर न करे कि उस कर्जद्वाराहका कर्जा उतना है जिसके आधार पर वह दिवालियेकी दरखास्त दे सकता है तो अदालतको अधिकार है कि वह कर्जदारसे कर्जद्वाराहके बरामद होने वाले कर्जोंके निस्वत तथा कर्जा साबित करनेमें होने वाले खर्चोंके निस्वत जमानत (यदि वह कोई ऐसी जमानत लिया चाहें तो) लेकर उतने समयके लिये कार्रवाईको रोक देवे जितने समयमें कर्जोंके सम्यग्बका प्रश्न तय किया जासके ।

(७) अब कि कार्रवाई रोक दी गई हो उस समय अदालतको अधिकार है कि वह किसी दूसरे कर्जद्वाराहकी दरखास्त पर दिवालिया क्रार दिये जानेका हुक्म दे सकती है लेकिन वह ऐसा उसी समय करेगी जब कि कार्रवाई रुक आनेकी बराबरे देर हो रही हो या अन्य कोई पर्याप्त कारण उपरिष्ठ होवे । और अब वह ऐसा करेगी तो उस दरखास्तको जिसके द्वारा कार्रवाई शुरू हुई थी जिन शर्तोंके साथ चाहेंगी स्वीकृत कर देगी ।

(८) कर्जद्वाराहकी दरखास्त दाखिल हो जानेके बाद विला अदालतकी आज्ञाके त्रापित नहीं ली जासकेगी ।

टिप्पणियाँ—

इस दफ्तेमें अब सब वर्गवायोजन विचार दिए हुए हैं जो किसी कर्जदारके द्वारा भी हुई दरखास्तके तत्परमें आवश्यक है । यह दफा C वायोजने विमर्क है और उसमें दरखास्त दिये जानेके समयांत के अन्तर्गत अन्तिम उचित हुक्म होने तक हाउ एव दूस्तोंके पक्षपर दिया हुआ है ।

उपदफा (१) में यह बतलाया गया है कि कर्जदारके द्वारा मंजूर जाने वाली दरखास्तके मायमें उसकी पुष्टि किये हुक्मनामासे प्राप्त किया जाना आवश्यक है क्योंकि अथवा एवम्में उक्त उपदफाम (Shall) उद्धृत योगी दिया गया है इल्लुस्ट्रेशन सम्बन्धमें यह दिया हुआ है कि दरखास्त देने वाला कर्जदार या तो स्वयं उसे दाखिल कर सकता है

अथवा उसकी ओर से कोई ऐसा व्यक्ति उसे दाखिल कर सकता है जिसे हज़ारत पाउंड हो अर्थात् कर्जस्वाह स्वयं ही हज़ारनामा दाखिल करनेके लिये बाध्य नहीं है परन्तु हज़ारनामा दाखिलानेकी ताददेमें दाखिल अवश्य किया जाना चाहिये ।

उपदफा (२) में यह बतलाया गया है कि दरखास्त सुनते समय जिन जिन बातोंका सुन आवश्यक है अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें भी (Shall) शब्दका प्रयोग किया गया है जिससे यह प्रकट है कि अदालत दरखास्त सुननेके समय इस उपदफाके क्लॉज (ए) व (बी) में बतलाई हुई बातोंका सुन अवश्य लेवेगी अर्थात् दरखास्त देने वाले कर्जस्वाहके कर्जे व दरखास्तमें दिखलाई हुई दिवालियेकी कार्रवाई होनेका सुन अवश्य लिया जाना चाहिये । क्लॉज (ए) में दरखास्त देने वाले कर्जस्वाहके कर्जेका उल्लेख है तथा क्लॉज (बी) में दिवालियेके क्लॉज उल्लेख है जिसके आधार पर दिवालियेकी दरखास्त दी गई हो क्लॉज (बी) में यह भी लिख दिया गया है कि यदि दिवालियेकी दरखास्तमें एकसे अधिक दिवालियेके कामोंका किया जाना या होना बतलाया गया हो तो सुनत उन कार्यों से किसी एक ही दिवालियेके कामके सम्बन्धमें दिया जा सकता है अर्थात् यदि इनमेंमें एक ही दिवालियेका काम साबित कर दिया जावे तो इस उपदफाके लिये पर्याप्त समझा जावेगा । कर्जस्वाहके कर्जेमें तारीख यह माहूम होता है कि आया कर्जस्वाहका कर्ज दायमल है या नहीं और अगर है तो वह किनासा है जिससे कि यह माहूम हो सके कि वह इस एक्टके अनुसार दरखास्त दे सकता है या नहीं और दिवालियेके कामोंका वर्णन दफा १ में दिया हुआ है ।

उपदफा (३) के अनुसार कार्रवाई करनेके लिये अदालत बाध्य नहीं है जैसा कि अंग्रेजी एक्टकी इस उपदफामें प्रयोग किया हुआ (May) शब्दसे प्रकट होता है । अदालत यदि चाहे तो सुननेकी तारीखको बढ़ा सकती है और यदि न चाहे तो उसे न बढ़ावे । यह तारीख इस कारण बढ़ाई जा सकती है जिसमें कि उसकी तापील कर्जदार पर हो सके ।

उपदफा (४) में उन बातों का वर्णन है जिसके कारण अदालत कर्जस्वाहकी दरखास्तको खारिज कर सकती है । यह उपदफा दो क्लॉजोंमें विभक्त है । क्लॉज (ए) में यह बतलाया गया है कि यदि अदालत उपदफा (२) में बतलाये हुए सुनसे सम्बुद्ध न होवे तो वह दरखास्तको खारिज कर देगी ।

क्लॉज (बी) में यह बतलाया गया है कि यदि कर्जदार उपस्थित होकर अदालतकी इस बातमें विश्वास दिला दे कि वह अपने कर्जोंकी अदा कर सकता है अथवा इस बात का विश्वास दिला दे कि उसके विरुद्ध दी हुई दरखास्त में जिस दिवालियेके काम का उल्लेख किया गया है वह उसने नहीं किया है अथवा अन्य किसी बातमें उस बात का विश्वास अदासतको कर देने कि उसके विरुद्ध कोई हुकम न दिया जाना चाहिये तो अदालत ऐसी अवस्थामें कर्जस्वाह द्वारा दी हुई दरखास्तको खारिज कर देगी ।

उपदफा (५) के अनुसार यदि अदालतकी ऊपर बतलाये हुए सुन पर विश्वास हो जावे तो अदालत कर्जदार को दिवालिया कर दे सकती है इस उपदफामें प्रयोग किया हुआ 'May' शब्दसे प्रकट है कि अदालत इस उपदफाके अनुसार हुकम देनेके लिये बाध्य नहीं है किन्तु उसका देना न देना उसकी क्षमता पर निर्भर है । इस उपदफामें यह भी दिया हुआ है कि यदि उपदफा (३) के अनुसार नवाई हुई तारीख पर भी कर्जदार हाजिर न होवे और उस पर नोटिसकी तापील होना साबित होवे तो अदालत उसे दिवालिया करार दे देवेगी परन्तु ऐसा करनेसे पहिले अदालत इस बातकी अवश्य देख लेगी कि आया वह दरखास्त किसी दूसरी अदालतमें तो न दी जाना चाहिये ।

उपदफा (६) में यह बतलाया गया है कि यदि कर्जदार उपस्थित होकर कर्जस्वाह का कर्ज मजूर न करे अथवा यह कह कि उस कर्जस्वाह का कर्ज उसे दिवालिया करार दिलानेके लिये पर्याप्त नहीं है तो अदालत इस प्रश्नकी तय करनेके लिये कार्रवाई स्थगित कर सकती है बजाय इसके कि वह उस दरखास्तको खारिज कर देवे और स्थगित करते समय यदि अदालत उचित समझे तो कर्जदारसे कर्जस्वाहके आयन्दा बरामद होने वाले कर्जोंके सम्बन्धमें तथा कर्ज साबित करनेमें जो

सर्व होगा उसके सम्बन्धमें उसके उचित सामान्य मांग सक्ती है । इस उपदफाके अनुसार हुक्म देना अदायगी हुक्म पर बाध दिया गया है ।

उपदफा (७) में इस बातसे साफ कर दिया है कि कर्जदार स्मृति होने पर अदालत जब चाहे कर्जदारको दिवालिया करार दे सकती है अर्थात् वह दो होनेकी वजहसे अपना अन्य किसी पर्याप्त कारण बिना दूसर कर्जदारकी दारुवास्तके आधार पर कर्जदारको दिवालिया करार दे सकती है और उस समय वह उन्नि शर्तोंके साथ पाहिले दो हुक्मे दिवालियेकी दारुवास्तकी श्रांति कर देगी ।

उपदफा (८) एक महत्व पूर्ण दफा है जसमें यह बनवाया गया है कि कर्जदारकी दारुवास्त बिला अदालत आह्वाके बाधित नहीं ली जा सकती है अजसमें एक्टकी इस उपदफामें प्रयोग गिये हुए 'Shall' शब्दमें यह भी भाति पकट है कि इस उपदफामें बतलाई हुई शर्तकी आवश्यकता जाना चाहिये दारुवास्त का बाधित किया जाना उसी समय तक हो सकता है जब तक कि उसके आधार पर कर्जदार दिवालिया न करार दे दिया गया हो क्योंकि दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म होने ही कर्जदार दिवालिया बन जाता है और जब तक कि दिवालिया करार दिये जातेका हुक्म मसूमा न किया जावे अथवा दिवालिया बहाल न हो आवे तब तक वह दिवालिया ही बना रहेगा । मगर हाईकोर्टने यह तय किया था कि दारुवास्त इजाजत लेने पर भी बाधित नहीं ली जा सकती है और यह उपदफा उन्नी दारुवास्तोंके लिये लागू समझना चाहिये जिन पर फैसला नहीं हुआ है सुझावोनाम मुहम्मद देखो—88 Bom. 200.

दफा १४ वह शर्तों जिनके अनुसार कर्जदार दारुवास्त दे सकता है

कोई कर्जदार उस समय तक दिवालियेकी दारुवास्त नहीं दे सकेगा जब तक कि नीचे दी हुई बातोंमेंसे कोई बात उपस्थित न होवे ।

(ए) उसके कर्जोंकी तादाद ५०० रुपये न होवे, या

(बी) वह किसी रुपयेकी अदायगीके सम्बन्धमें दी हुई डिक्रीके आधार पर गिरफ्तार होकर कैद न किया गया हो, या

(सी) किसी रुपयेकी अदायगीके सम्बन्धमें दी हुई डिक्रीके आधार पर उसकी जायदाद कुर्क करनेका हुक्म दिया गया हो तथा वह हुक्म उसकी जायदादके विरुद्ध कायम न होवे ।

व्याख्या—

क्लाज़ (ए), (बी) व (सी) में बतलाई हुई सब बातोंके एक साथ उपहित होनेकी आवश्यकता नहीं है । यदि इन क्लोजोंमें किसी क्लोजमें बतलाई हुई बात उपस्थित होवे तो उसके आधार पर कर्जदार दिवालियेकी दारुवास्त दे सकता है अथवा नहीं अथवा यदि उसके कर्ज ५०० या उससे अधिकके हों तो वह दारुवास्त दे सकता है, या यदि वह किसी इराय डिक्रीके सम्बन्धमें गिरफ्तार होकर कैद हुआ हो तो वह दारुवास्त दे सकता है अथवा यदि उसकी जायदाद कुर्क होवे तो वह दारुवास्त दे सकता है । इस बात का ध्यान रहना चाहिये कि क्लान (बी) व (सी) में गिरफ्तारी या कुर्क चन्दी डिक्रीयोंके आधार पर होना चाहिये या रुपयेकी अदायगीके सम्बन्धमें दी गई हो यदि इस दफामें बतलाई हुई तीन शर्तोंमेंमें एकरा भी शर्त न होनी होवे तो कर्जदारके दिवालियेकी दारुवास्त देनेका हकही पेश नहीं होगा ।

दफा १५ कर्जदारकी दरखास्त पर कार्यवाई व उस पर हुक्म

(१) कर्जदारकी दरखास्तमें यह दिखलाया जावेगा कि वह अपने कर्जोंको अदा करने में असमर्थ है और यदि कर्जदार अदालतके सामने यह साबित कर देवे कि वह दरखास्त देनेका हकदार है तो अदालत उस पर दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म दे सकती है परन्तु वह ऐसा उस समय नहीं करेगी जब कि उसकी रायमें वह दरखास्त दिवालियेके अधिकार रखने वाली किसी दूसरी अदालतमें दी जाना आवश्यक हो ।

(२) कर्जदार द्वारा दी हुई दरखास्त दाखिल होनेके पश्चात् बिला अदालतकी आज्ञाके वापिस नहीं ली जा सकेगी ।

व्याख्या—

इस दफामें कर्जदार द्वारा दी जाने वाली दरखास्तके सम्बन्धमें की जाने वाली कार्यवाहियां विवर्ण हैं मन्ने पहिले उपदफा (१) में यह बतलाया गया है कि कर्जदारकी दरखास्तमें यह दिखाना परम आवश्यक है कि वह अपने कर्जोंको अदा करनेमें असमर्थ है । अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दमें इस बातकी पुष्टि होती है । साथ ही साथ अदालतके सामने यह भी साबित किया जाना चाहिये कि वह दरखास्त देनेवाला हकदार है । दरखास्त देनेवाला हक कब होगा इस बातके विषयमें दफा १४ में जवाब दिया हुआ है । ऊपर बतलाई हुई दोनों बातोंके होने पर अदालत, दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म दे सकती है अर्थात् उस समय भी अदालत दिवालिया करार देनेके लिये बाध्य नहीं है किन्तु ऐसा करना उसकी इच्छा पर निर्भर है । अदालतकी हुक्म देनेमें पहिले इस बातका भी ध्यान रखना चाहिये कि आया उस अवस्था अन्य किसी अदालतके उस कर्जदारके सम्बन्धमें दिवालियेके अधिकारोंका प्रयोग करना चाहिये कर्जदारकी दरखास्तके अन्तर्गत् अतः कर्जदारकी असमर्थताका सूचित होना चाहिये । देखो—A. I. R. 1928 Mad 394

उपदफा (२) में जहाँ बात बतलाई गई है जो दफा १३ की उपदफा ८ में कर्जदार द्वारा दी हुई दरखास्तके सम्बन्धमें बतलाई जा चुकी है अर्थात् अहाँ दाखिल होनेके बाद दरखास्त बिला अदालतकी आज्ञाके वापिस नहीं ली जा सकती है । इस उपदफाकी पाकड़ा की जाना आवश्यक है जैसे कि अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट होता है । इस दफामें भी इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि दरखास्तकी वसतिपूर्वक प्रत्येक अवस्था में समय तक उठ सकता है जब तक कि दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म न दिया जा चुका हो क्योंकि उसके पश्चात् दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी मसूदा अथवा नशा होने पर ही कर्जदार दिवालिया नहीं होगा यह उपदफा जहाँ दरखास्तोंके लिये लागू समझना चाहिये निम्न पर हम नहीं हुआ है व जो और तमबीज है, देखो—C.B. Bom 200

दफा १६ दरमियानी रिसीवरकी नियुक्तिके लिये अदालतको स्वतंत्र अधिकार

यदि जायदादकी रक्षाके लिये आवश्यकता बतलाई जावे तो अदालतको अधिकार है कि वह दिवालियेकी दरखास्त लिये जानेके बाद तथा दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म दिये जानेसे पहिले किसी समय भी आफिशल पसायनी (Official Assignee) को कर्जदारकी कुल जायदाद या उसके किसीके हिस्सेके लिये दरमियानी रिसीवर (Interim Receiver) नियुक्त कर देवे और इस बातका हुक्म दे देवे कि उसकी सब जायदाद या उसके किसी हिस्से पर फौरन कब्जा ले लिया जावे और इस पर आफिशल पसायनीको निर्धारित किये हुए वह अधिकार प्राप्त होंगे जो सन १९०८ ई० के ज्ञान्ता दीवानीके अनुसार नियुक्त किये हुए रिसीवरको प्रदान किये जा सकते हैं ।

व्याख्या—

यद्यपि इस दफ्ते में दायिगाना रितीवरकी नियुक्ति विषयमें किसी हुआ है कि अदालत दायिगाना रितीवर नियुक्त करने में नियो बाध्य नहीं है किन्तु उसका नियुक्त करना न करना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है जसा कि अमेजा एक्टका २९ दफ्ते में प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट होता है । दायिगाना रितावर दिवालियाका दारुबस्त दाखल होने के बाद तया दिवालिया करार दिया जानेका हुक्म होनेसे पहिले नियुक्त किया जासकता है क्योंकि दफ्ता १७ के अनुसार दिवालिया करार दिये जाने पर दिवालियाकी सम्पत्ति आयादाद आकिशाल एसामनीनी सुपुर्गामें आनानी है अर्थात् दिवालिया करार दिये जाने के बाद किसी दायिगाना रितीवरके नियुक्त किये जानेकी आवश्यकता ही नहीं रहती है । दायिगाना रितीवर उसी समय नियुक्त किया जासकता है जब कि कर्नरकी आयदादके बर्षाद हुनका अदेश होक और ऐसा रितीवर उसकी पूरी आयदाद या उसके रिसा भागके लिये नियुक्त किया जासकता है । इस दफ्ता के अकिशाल एसामनीनी के लिय दिया हुआ है कि वह दायिगाना रितीवर नियुक्त किया जासकता है । इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि इस दफ्ता के अनुसार नियुक्त किये जाने पर आकिशाल एसामनीनीको वह अधिकार प्राप्त नहीं होंगे जो उसे आकिशाल एसामनीनी रमियसे प्राप्त हो सकते हैं किन्तु जबकि वह अधिकार प्राप्त होंगे जो उसके लिये निर्धारित किये गये हैं और यह अधिकार वही होंगे या जवनाके अनुसार नियुक्त किये हुए रितावरको दिये जासकते हैं । रितीवरकी नियुक्तिका बर्षाद सन् १९०८ ई० की जायता दीवानाके आर्डर ४० में दिया हुआ है और वह इस प्रकार है—

आर्डर ४० जायता दीवाना रितीवरकी नियुक्ति

नियुक्ति कल १—(१) जब कि अदालतको उचित व सुविधा जनक प्रतीत हो अदालत अपने हुक्म द्वारा निम्नलिखित कार्य कर सकती है —

- (ए) किसी होनेसे पहिले या उसके बाद किसी आयदादके लिये रितीवर नियुक्त कर सकती है
- (बी) किसी भी व्यक्ति को हटा सकती है जिसका कम्ना या अधिगार किसी आयदाद पर होने
- (सी) उस आयदादको रितीवरके कृन्नेमें उसकी सरसुतामें अथवा उसके श्रव में दे सकती है
- (डी) रितीवरको आयदादके सम्पत्ति शुद्धता दायर करने उसकी जवाब देही करने तथा उसको वसूल करने प्रबन्ध करने बचाने और उसकी शुद्ध करनेके अधिकार दे सकती है, उसका कितना या मुनाफा वसूल करने आद इस प्रकार वसूल किये हुए रितावर व मुनाफाको सर्फ करनेके अधिकार भी दे सकती है और आयदादके सम्पत्ति में ऐसी दस्तावेजोंके लिखनेका अधिकार भी दे सकती है जैसे कि स्वयं मालिक लिख सकता है । या इन अधिकारोंमें से कोई भी अधिकार दे सकती है जो उसे उचित प्रतीत होने ।

(२) अदालतको इस कलके अनुसार यह अधिकार न होगा कि वह आयदादके कृन्ने या अधिकारसे किसी ऐसे व्यक्ति को हटा देने जिसके हटानेका मौजूदा अधिकार मुकद्दमेके किसी फलके प्राप्त न होने ।

अमफल कल २—अदालत अपने आम या खास हुक्म द्वारा रितीवरको उसके कार्यके लिये दिये जाने वाले श्रमफलकी नियत कर सकती है ।

कर्तव्य कल ३—इस प्रकार नियुक्त किया हुआ रितीवर नीचे दिये हुए कामोंको करेगा —

- (ए) यदि अदालत कोई जमानत उचित समझे तो वह जमानत उस आयदादके सम्पत्ति होने वाली आमदनीके हिसाबके लिये देवेगा

(बी) अपना हिसाब अदालतके हुक्मके अनुसार नियत समय पर तथा निश्चित ढंगसे देवेगा

(सी) अदालतके हुक्मके अनुसार वह कृपा देवेगा जो उसे देना है

(डी) उस नुकसानके लिये जिम्मेदार होगा जो उसका जान बूझ कर या अनि करके या बड़े लापरवाहीके कारण हुआ हो

हिसाब न देना कूल ध—(ए) यदि रजिस्टर अदालतके बगाने अनुसार तथा उसके द्वारा नियत किये हुए समय पर हिसाब न दाखिल करे, या

(बी) यदि भद्र करने हुक्मके अनुसार बंद कृपा अथ न करे जो उसके पास है, या

(सी) यदि वह जमान बूझ कर वापसी करेगा या अपना बचा लपरवाहीके कारण नुकसान हो जाने दे तो अदालत उसका जायदादके कुर्क किये जानेका हुक्म दे सकती है न उनको बच सकना है तथा बेचने पर आई हुई कीमतसे उस वसीरो पूरा कर सकती है जो उसके कारण हुई हो या उस कारणसे मुजो ले सकती है जो उससे निकलता होवे और बचा हुआ करेगा यदि कुछ होगा बर् रजिस्टरके दे देवेगा ।

कलक्टर कूल ध—जब कि कोई जायदाद ऐसी होवे जिसकी माजुबगी सरकारका आधी जाती होवे या ऐसी जमीन होवे जिसकी माजुबगी जिस दी गई हो या उदासी गई हो और अशलतको यह माजुब पके कि उससे सम्बन्ध रखने वालोंका फायदा उस समय होगा जब कि उनका प्रबन्ध कलक्टरके हाथसे किया जावे तो अदालत कलक्टरकी अनुमति लेकर उसे उस जायदादके लिये रिसावर नियुक्त कर सकती है । रजिस्टरके मन्त्र इस में अधिहार ऊपर दिखलाये गये हैं अर्थात् जिसका अट्रैल आर्डर ४० बाबत दीवानामें होना बतलाया गया है वह सब अधिकार अथवा उनमेंसे कुछ अधिकार इस दफाके अन्वयानुसार नियुक्त किये हुए दायित्वानी रजिस्टरके दिये जासकते हैं ।

दफा १७ दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मका प्रभाव

दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म हो जाने पर दिवालियेकी आयदाद चाहे वह जिस जगह पर होवे अफिशल एसायनीकी सुपुर्दगीमें आजाबेगी और वह जायदाद उसके कर्जदारोंमें बांटी जाने योग्य होगी और उसके पश्चात् इस एक्टमें बतलाई हुई बातों को छोड़ कर दिवालियेका कोई भी कर्जदार जिसका कर्ज इस एक्टके अनुसार स्वीकृत किया जासकता है दिवालियेकी कार्रवाईमें चालू रहते हुए दिवालियेकी आयदादके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा और न वह कोई मरुदमा या कोई अदालती कार्रवाई ही करने कर्जके सम्बन्धमें बिला अदालत की आज्ञाके तथा अदालत द्वारा निर्धारितकी हुई शर्तोंके कर सकेगा । परन्तु यह दफा मरुदमा कर्जदारके अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी और उसे अपनी जमानत वसूल करने या उससे अपना कर्ज वसूल करनेमें वही स्वतन्त्रता प्राप्त होगी जो कि उसे इस दफाके पार्ल न होने पर प्राप्त हो सकती थी ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार दिवालिया करार दिये जाने पर दिवालियेकी सब जायदाद अधिकृत एसायनीकी सुपुर्दगीमें आ जावेगी और उनी समयमें वह सब जायदाद कर्जदारोंमें बांटी जाने योग्य भी हो जावेगी । दिवालिया करार दिया जाने का हुक्म होनेमें पहिले अफिशल एसायनीको उस बात तक दिवालियेकी जायदादमें कोई सम्बन्ध नहीं होगा । जब तक कि वह दफा १६ के अनुसार दायित्वानी रजिस्टर नियुक्त न किया जावे । इसी दफ्तर्बद्ध भी बताया गया है कि दिवालिया करार

दिए जानेके बाद दिवालियाकी जायदादों विरुद्ध कोई कर्जपत्राह अपने कर्जेके सम्बन्धमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा और न बिना अदालतकी आज्ञाके कोई मुकदमा या अन्य अदालती कार्रवाई कर सकेगा परन्तु इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि ऊपर बतलाई हुई बात उन्हीं कर्जोंके लिये लागू होगी जो दिवालियाकी कार्रवाईमें साबित किये जा सकते हैं। इस दफ्तेमें जो अन्य कानूनी कार्रवाई का उल्लेख है उससे दीवानीकी कार्रवाईके सम्बन्धमें चाहिये फ़ाजदारीका नहीं अर्थात् इस दफ्तेमें बतलाये हुए मामलों का पालन केवल उन्हीं कार्रवाइयोंके लिये आवश्यक है जो दीवानीके तौर पर होने और फ़ौजदारीके इतरासे होने के सम्बन्ध नहीं है। देखो—मरगाद बहादुर नगम मूलशब्द 35 Bom 63 परन्तु जब कि जोड़ी कायमान शब्दिक किये गये हों तो जरा फ़ौजदारीके अनुसार फ़ौजदारी का मामला चाहे वस्तेके लिये अदालतकी आज्ञा लिये जानेकी आवश्यकता है देखो 37 Mad. 107

इस दफ्तेके साथ जो शर्तें लगा दी गई हैं वह भी नई महरगी है और उसका ध्यान रखना आवश्यक है उस शर्तके अनुसार मरगाद कर्जपत्राह अपनी जमानतकी जिस प्रकार चाहे वमूल कर सकता है और उसके लिये यह दफा लागू नहीं होगी। कोई ऐसा नियम नहीं है जिसके अनुसार अदालतकी आज्ञा मुकदमा दायर करनेके लिये दिये जानेमें पहिले दिवालियाके नाम नोटिस जारी किया जावे। नोटिसका दिया जाना व न दिया जाना हर एक मामलेके उद्भागाना बाकपात पर निर्भर है। ऐन हाईकोर्टने एक मामलेमें यह तय किया था कि यदि दिवालियाके नाम नोटिस दिला नहीं गये हुए ही अदालतकी आज्ञा दी गई हो तो वह उचित आज्ञा समझी जावेगी, देखो—6 R. 533, A. I. R. 1928 R. 326 यदि किसी मरगाद हिन्दू परिवारका जिसके लिये कि विवाहका कानून लागू हो पिता दिवालिया करार दिया जावे तो उस परिवारकी सब संपत्ति जायदाद जिसमें कि उसके लड़कोंका भी इक शामिल है अकिशल एसाबनीकी सुपुर्गीमें आजावेगी। परन्तु लड़कों को अधिकार है कि वह अपना हिस्सा यह साबित करने पर तय्यार रहें कि बापके कर्जे पर कानूनी व बेजा तौरसे किये गये थे और उन कर्जोंके लिये उनके हिस्से जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं, देखो—11 B. 37, 19 M. 14, 42 C. 225; 8 Lah 329.

यदि किसी मुकदमेके दौरानमें कोई कर्ज दिवालिया करार दे दिया जावे तो वह अपने दिवालिया हो जानेके कारण अपील करनेके अयोग्य हो जाता है। दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मके मसूदा हो जाने पर वह अपनी अपील कर सक्त है, देखो—A. I. R. 1929 Bom 20. इस दफ्तेमें यह भी बतलाया गया है कि दिवालियाकी जायदाद जहां बही होवे अकिशल एसाबनीकी सुपुर्गीमें आजावेगी अर्थात् उसका होना केवल ब्रिटिश इण्डिया ही के लिये प्रतिष्ठित नहीं है। बल्कि हाईकोर्टने यह तय किया था कि मरगाद जायदाद का शपार्हके वास्ते कोर्ट (Consular Court) की अधिकार सीमामें स्थित है बल्कि अकिशल एसाबनीकी सुपुर्गीमें हुक्म हो जाने पर आजावेगी देखो—33 Bom 462 इस एकके अनुसार साबित किये जावे योग्य कर्जोंका उल्लेख दफा ४६ में तफ़्तीलवार किया गया है। अदालतकी आज्ञा देने पर जो कार्रवाई चाही जावेगी उसके लिये अदालत द्वारा लगाई हुई शर्तों में भी पाबन्दी आवश्यक है।

दफा १८ कार्रवाईका रोक जाना

(१) दिवालिया करार दिया जानेका हुक्म हो जानेके पश्चात् किसी समय भी अदालत को अधिकार है कि वह किसी मुकदमेमें या अदालती कार्रवाई को जो दिवालियाके विरुद्ध किसी जज या जजों अथवा अन्य किसी अदालतके सामने चल रही हो रोक देवे जिसमें कि वह अदालतके निरीक्षणमें चल सके।

(२) उपदफा (१) के अनुसार दिये हुए हुक्म की मरकल अदालत की मोहर लगाकर डाकके जरिये मुद्दई या मुकदमा लड़ने वाले व्यक्तिके पतेसे अदालत द्वारा भेजी जासकती है और

ऐसे हुक्मका नोटिस उस अदालतके पास भेजा जावेगा जिसके सामने यह मुकदमा या कार्यपत्र चल रही हो ।

(३) कोई भी अदालत जिसके सामने किसी कर्जदारके दिवङ्ग मामला चल रहा हो तो इस बापका सुबूत पहुँचने पर कि वह इस एक्टके अनुसार दिशालिया करार दे दिया गया है या ता अपने यदा जमाने वाले मामले को रोक देगी अथवा उसको उन शर्तोंक साथ चालू रहने देगी जो उसे उचित प्रतीत हों ।

व्याख्या—

अज्ञात दिशालिया अस्विकार है कि यह दिशालिया करा" शिथे जाने वाले हुक्मक पक्का यदि वह चाहे तो मुकदमा व दूसरी शर्तोंका साथ ही कर दे चाहें वह एक्टके अन्तर्गत अज्ञात अज्ञातों होती होंगे । और तत्पश्चात् रोखनेवाला हुक्म दिया जावेगा यह बजटियों का मुद्दा या मुकदमा चलाने वाले निहाय अप्रतिष्ठे पास भेजा जायता है अर्थात् मुद्दा या मुकदमा चलाने वाले प्रतिष्ठे पास हुक्मका नफ़ल भेजनेके लिये अदालत बाध्य नहीं है कि उसमें जानना न जानेका अदालती इच्छा पर निर्भर है परन्तु इस हुक्मकी मूलतः उस अदालतक पास अज्ञात भेजी जाने की जितने ता न वह मुकदमा या मामला चल रहा हो जैसा कि अज्ञाती एक्टका उपदृष्ट (२) में अज्ञात दिशालिया (Dialia) करते प्रकट होता है ।

उपदृष्टा (१) व (२) में अज्ञात दिशालिया द्वारा जो जाने वाला कार्यवाह्यता लक्ष्य है अर्थात् उनमें यह बात आया है कि अदालत दिशालिया दिशालिया दिवङ्ग करने वाला मुकदमा या किना अथ अदालती का या यात्रा राक मतना के अनुसार उपदृष्टा (३) में मग्न हुक्मका गया है कि अज्ञात दिशालियाक उचित उग लक्षणता भी निम्न सामान्य दिशालियाके दिवङ्ग नहीं सम्मिलित चला रहा हो उस सम्मिलित शर्तोंमें ता निही खास रूप के साथ चालू रखनेका आदेश है । यह हुक्म अज्ञात मामलोंके उरी समय तक जाय कि उस यह सचिव हो याव हि दिशालिया करार दिया जानका हुक्म हो चला है ।

उपदृष्टा (३) में अज्ञात यह भी प्रकट होता है कि यदि दिशालिया करार दिने जानेका हुक्म होने समय कोई सम्मिलित चला हो तो भी अदालत उस सम्मिलित यह हुक्म होने पर कि दिशालिया करार दिया जानका हुक्म हो गया है या न सचिव है अर्थात् यह आवश्यक नहीं है कि राजा जान बाग सम्मिलित दिशालिया करार दिने जानेक पहिले हुक्म चला रहा हो, कदा—41 Bom. 112 चलना उद्देश्यसे यह तय किया है कि हाईकोर्टका कोई एक दफा १६ मराठेका दायत सम्मिलितकी एक्टके अनुसार कार्यवाही करत हुए डिशालिया जननी उस कार्यवाही नहीं कर सकता है जा वह प्रतिक एक्ट दिशालियाक अनुसार उरी उद्देश्यक दिवङ्ग कर रहा हो । इस दफामें वलार्ड ईई दूसरा कानून कार्यवाहीमें दिशालियाकी कार्यवाही नहीं जाना है दूसरी निर्दिष्टता उरी करत उही हाईकोर्टका सम्मिलित चाहिये जा मुकदमक तापर होव या इस तय अथवा एसा ही कोई दूसरी कानूनी कार्यवाही होये दली—A I R 1928 Cal 782 इस सम्मिलितमें कोई कार्यवाही भी ऐसी ही सचिवी है निम्न ता यह भी कहा गया है कि वह दूसरी दिशालियाकी कार्यवाही कोई ऐसा प्रकटमा या कार्यवाही नहीं है जो दिशालियाके दिवङ्ग चल रही हो इस कारण दिशालियाका कार्यवाही इस दफामें अनुसार नही जाना जा सकता है, कदा—24 Bom L R 872 A I R (1921) Bom 390

दफा १९ विशेष भेजेजरकी नियुक्तिके अधिकार

(१) यदि किरात मामलोंमें अज्ञात कर्जदारकी जायदादको या उत्तरे यात्राको अथवा

आम क्रमपूर्वाधिकारों के लाभको देखते हुए यह राय कायम करे कि कर्मदारकी जायदाद या व्यापार के अस्तकालमें आफिशल एसायनीकी मददके लिये किसी विशेष मैनेजरकी नियुक्तिकी जाना चाहिये तो उसे अधिकार है कि वह ऐसे मैनेजरकी नियुक्ति किसी निश्चित किये हुए समय तक काम करनेके लिये जिसे वह मुनासिब समझे कर देवे और उस मैनेजरको आफिशल एसायनी को प्रदान किये जाने वाले वह अधिकार प्राप्त होंगे जो उसे आफिशल एसायनी अथवा अदालत सुपुर्द करे।

(२) विशेष (Special) मैनेजरको उस प्रकारकी जमानत देना पड़ेगी तथा हिसाब बाखिल करना पड़ेगा जैसा कि अदालत हुकम देवे और उसको यह धमकड़ा (Remuneration) मिलेगा जो अदालत निश्चित करे।

व्याख्या—

उपदफा (१) में विशेष मैनेजरकी नियुक्ति के विषयमें दिया हुआ है कि यह विशेष मैनेजर उसी समय नियुक्ति किया जा सकेगा जबकि कर्मदारकी जायदाद किसी विशेष प्रश्नकी होने निम्नवा प्रत्यक्ष आफिशल एसायनी मले प्राप्त कर सकता हो अथवा कर्मदारके व्यापार या आम क्रमपूर्वाधिकारों के लाभार्थ आफिशल एसायनीकी सहायताके लिये किसी ऐसे व्यक्तिके नियुक्तिकी आवश्यकता प्रतीत होने पर। इस बात का ध्यान रहना चाहिये कि विशेष मैनेजर की नियुक्ति करना करना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है जैसा कि अनेकी एकरी इस दफा में प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट होता है—इस प्रकार नियुक्ति किया हुआ मैनेजर उतनेही समय तक काम कर सकता है जितने समयके लिये वह अदालत द्वारा नियुक्त किया जाने अर्थात् वह आफिशल एसायनीकी भांति दिवालियेकी कुछ बाँटवार्थके लिये नहीं रहेगा आफिशल एसायनीकी मदद की के लिये ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाने अर्थमें नियुक्ति आफिशल एसायनीकी अथवा पा नहीं समझना चाहिये अर्थात् उसकी नियुक्तिसे यह न समझ लेना चाहिये कि आफिशल एसायनीके सब बाँटवों वह विशेष और आफिशल एसायनी की अर्थमें नियुक्ति के पश्चात् दिवालियेकी बाँटवमें से कोई समझ रही नहीं रहेगा एक प्रकारसे ऐसा नियुक्त किया हुआ व्यक्ति आफिशल एसायनी का मातहत समझना चाहिये जिसे आफिशल एसायनीके लिये निर्धारित किये हुए कार्यमें कुछ करवोंके करने का अधिकार प्रदान कर दिया जाने विशेष मैनेजरकी आफिशल एसायनीकी मदद के लिये जाने वाले अधिकारोंमें से वह अधिकार प्राप्त होंगे जो आफिशल एसायनी अथवा अदालत सबके लिये तय कर दे।

उपदफा (२) के अन्तर्गत इस प्रकार नियुक्ति किये हुए मैनेजरसे अदालत निम्न प्रकारकी जमानत चाहे ले सकती है और उसमें हिसाब भी निम्न प्रकार वह चाहे बाखिल कर सकती है—अनेकी एकरी प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दमें यह प्रकट है कि विशेष मैनेजरकी जमानत या हिसाब सम्बन्धी हुकमोंकी पालनी करना आवश्यक है अदालत इस प्रकारके मैनेजर के लिये धमकड़ा (Remuneration) भी नियत कर देगी और वह मैनेजर इस प्रकार नियत किये हुआ धमकड़ा ही पावेगा उतने अधिक या उतने अविरत कुछ नहीं प्रायेगा।

दफा २० दिवालिया क्रगर दिये जाने वाले हुकमकी घोषणा

दिवालिया क्रगर दिये जाने वाले हुकमकी घोषणा गज़ट आफ इण्डियामें (Gazette of India) स्थापित सरकारी गज़टमें (Local Official Gazette) तथा निर्धारित किये हुए अन्य दूसरे दफास प्रकाशितकी जावेगी और उस घोषणामें दिवालियेका नाम पता व पेशा, दिवालिया क्रगर देनेकी तारीख उस अदालतका नाम जिसने दिवालिया क्रगर दिया हो और दिवालियेकी दृष्ट्यासन दिने जानकी तारीख प्रकाशितकी जावेगी।

व्याख्या—

दिवालिखा करार दिये जाने वाले हुक्मका प्रकाशन गन्त आप्रसविद्या न स्थानिक सरकारी गन्तमें किया जानेगा तथा निश्चित किये हुए अथ प्रकाशे भी किया जावेगा अथवा एकदम इस दफ्तरमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे यह प्रकट होता है कि-प्रकाशन उक्त प्रकारसे अवश्य किया जाना चाहिये । प्रकाशनमें जिन जिन बातोंका दितलाया जाना आवश्यक है वह भी इस दफ्तरमें बतलाई गई है अर्थात् दिवालिखेका नाम, पता न पेशा दिया जाना चाहिये दिवालिखा करार दिये जानेकी तारीख दी जाना चाहिये दिवालिखेकी दाखलास्त दाखिलकी जाने वाली तारीख तथा दिवालिखा करार देने वाली अदालतका नाम भी दे दिया जाना चाहिये । इस दफ्तरमें यह प्रकट है कि दिवालिखा करार देनेके पश्चात् भली भाँति-मुसदर न दिया जाना आवश्यक है ।

दिवालिखा करार दिये जाने वाले हुक्मकी मंजूरी

दफा २१ कुछ मामलोंमें दिवालिखा करार दिये जाने वाले हुक्मकी मंजूरीके अधिकार

(१) जब कि अदालतकी रायमें किसी कर्जदारको दिवालिखा करारही नहीं दिया जाना चाहिये था अथवा अदालतकी यह संतोषजनक रूपसे साबित हो जावे कि दिवालिखेके सब कर्जों पूर्ण रूपसे चुकाये जासकते हैं तो अदालतको अधिकार है कि-वह किसी सम्बन्धित व्यक्तिकी दृष्टिवात् जाने पर अपने हुक्म द्वारा दिवालिखा करार दिये जाने वाले हुक्मको मंजूर कर देवे ।

(२) यदि कोई कर्जा जिसे कर्जदार तस्लीम न करता हो परन्तु जिसकी अदायगीके लिये वह दस्तावेज मय उन जमानतोंके जिसे अदालत मंजूर करे लिख देवे तो इस दफ्तरमें लिखे यह मान लिया जावेगा कि वह कर्जा पूर्ण रूपसे चुकाया जाचुका है और ऐसे कर्जद्वारा कर्जा जिसका पता न लगता हो अथवा जिसकी शनासत न की जासकती हो यदि अदालतमें अमर कर दिया जावे तो वह भी पूर्ण रूपसे चुकाया हुआ कर्जा माना जावेगा ।

व्याख्या—

दिवालिखा करार दिये जाने वाले हुक्मको मंजूर करनेके लिये अदालतकी दो प्रकारसे अधिकार प्राप्त हैं एक तो यह जब कर्जदारकी दिवालिखा करार ही न दिया जाना चाहिये था न दूसरे उस समय जब कि कर्जदारके सब कर्जों पूर्ण रूपसे चुकाये जाचुके हैं । इस दफ्तरमें अनुसार मसूखीके लिये कोई भी सम्बन्धित व्यक्ति दाखलादे सकता है अर्थात् स्वयं कर्जदार बतला कोई सम्बन्धी या कर्जदार आदि अदालत इन दफ्तरके अनुसार मसूखीका हुक्म दे देनेके लिये वाप्य नहीं है जैसा कि कानूनी एक्टकी इन दफ्तरमें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट होता है । उक्तका देना न देना उसकी इच्छा पर निर्भर है अर्थात् ऊपर कानूनी हुई दो बातोंमें से किसी एक बातके उपरिष्ठ मान हो से मसूखीका हुक्म नहीं हो जावेगा किन्तु अदालत और भी वाक्याल पर विचार करेगी अर्थात् दिवालिखेके जोहार आदि पर यदि दिवालिखा अपने कर्जोंका अदा करनेमें धनमय नहीं था तो दिवालिखेका हुक्म इन दफ्तरके अनुसार मंजूर किया जाना उचित है, देखे—A. I. R. 1928-Mad. 395. 1082. C. 208.

दिवालिखेके कर्जोंकी पूर्ण रूपसे अदायगी हो जाना चाहिये और अदालतकी संतोषजनक रूपसे यह बात साबित भी हो जाना चाहिये तथा यह माना जावेगा कि कर्जें चुकाये जाचुके हैं दिवालिखा वा उससे पिछकर उक्तका कोई कर्जदार इस एक्टके

(२) ऊपर घतलार्ह हुई सूची निम्न लिखित समयके अन्दर दाखिल की जावेगी:—

(ए) यदि कर्जदारकी दरखास्त पर दिवालिया करार दिया जानेका हुक्म हुआ है तो उस हुक्मसे ३० दिनोंके अन्दर

(बी) यदि कर्जस्वाहकी दरखास्त पर दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म हुआ है तो उस हुक्मकी तारीख होनेसे ३० दिनोंके अन्दर

(३) यदि दिवालिया चला किसी उचित कारणके इस दफ्तामें बतलाये हुए नियमोंकी पाबन्दी न कर सकेगा तो अदालतको अधिकार है कि वह आफिशल एसायनी अथवा किसी कर्जस्वाहकी दरखास्त आने पर उस दिवालियेको जेल दीवानीमें सुपुर्द किये जानेका हुक्म देदेवे।

(४) यदि दिवालिया ऊपर घतलार्ह हुई सूचीको तैयार न करेगा या उसे दाखिल न करेगा तो आफिशल एसायनी उसकी जायदादके खर्चसे निर्धारित किये हुए ढंग पर सूची तैयार करा सकता है।

व्याख्या—

इस दफ्ताके अनुसार दिवालिया करार दिये जाने पर दिवालियेका कर्जदारको यह निर्धारित ढंग पर अपने मामलोंके सम्बन्धमें एक सूची दाखिल करे जिसकी पुष्टिके लिये उसे इल्फनामा भी देना पड़ेगा और उस सूचीमें वह सब बातें भी देगा जिनके लिये बतलाया गया है।

उपदफा (१) में (Shall) शब्दका प्रयोग अंग्रेजी एक्टमें किया गया है जिससे यह भली भाँति प्रकट है कि दिवालिया अपनी इस सिमिटरीको टाल नहीं सकता है इसी दफ्ताके उपदफा (३) में बतला दिया गया है कि हुक्मकी तारीख न करने पर वह दीवानीकी जेलमें भेजा जासकता है। सूची दाखिल करनेके लिये समय भी निर्धारित कर दिया गया है उपदफा (२) के क्लॉस (ए) के अनुसार यदि दिवालिया अपनी ही दरखास्त पर दिवालिया करार दिया गया हो तो दिवालिया करार दिया जाने वाला हुक्म होनेकी तारीखसे ३० दिनोंके अन्दर सूची दाखिल करना जाना चाहिये। क्लॉस (बी) में यह बतलाया गया है कि यदि किसी कर्जस्वाहकी दरखास्त पर कोई कर्जदार दिवालिया करार दिया गया हो तो जिस तारीखसे उस पर दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मकी तारीख हुई है। उस तारीखसे ३० दिनोंके अन्दर सूची दाखिल करना जाना चाहिये।

उपदफा (३) में जो इल्फनामा देनेकी आवश्यकता रखी गई है वह इस कारण समझना चाहिये कि जिसमें दिवालिया सूचीमें गलत सभ्य बातें न दिखाने देवे किन्तु वह सब बातोंको ठीक ही ठीक दिखाने देवे क्योंकि राकट इल्फनामा दाखिल करने पर वह गलत इल्फनामा दाखिल करनेका दोषी निर्धारित किया जाकर दण्डका भागी हो सकता है।

उपदफा (३) में जेल दीवानी भेजनेका उल्लेख है उससे यह भी समझ लेना चाहिये कि दिवालिया सूची न दाखिल करने मात्रही से जेलमें भेज दिया जावेगा। जेलमें भेजना न भेजना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है और अदालत समय न आवश्यकताअनुसार इस प्रकारका हुक्म देवेगी। इस प्रकारका हुक्म आफिशल एसायनी अथवा अन्य किसी कर्जस्वाहकी दरखास्त देने पर हो सकता है परन्तु इस बातका भी ध्यान साथ साथ रखना चाहिये कि यदि किसी उचित कारणसे दिवालिया उस सूची दाखिल न कर सके अथवा उस सूची नियत किये हुए समयके अन्दर न दाखिल हो सके तो इस उपदफाके नियमका प्रयोग नहीं किया जावेगा जैसे कि दिवालिया बोमार पड़ गया हो अथवा जिन बातोंके सुधारमें दिखाने वाली आवश्यकता हो उसके लिये दिवालियेको कुछ अवकाश मिलना चाहिये तो दोनों हान्डोंमें नियत किये हुए समयसे कुछ अधिक समय दिवालियेको मिल सकता है इसादि।

उपदृष्टा (४) में यह बतलाया गया है कि यदि दिवालिया उक्त नियमोंके अनुसार सूचा तैयार न करे या दाखिल न करे तो आफिशल एसायनरी अधिकार है कि यह उसकी आवश्यकता देखिये निर्धारित त्रिप हूप दंग पर सूचा तैयार करे दे।

पृष्ठा २५ रक्षाका हुक्म

(१) कोई भी दिवालिया जिसने कि ऊपर बतलाये हुए दंग पर सूची दाखिल कर दी हो अदालतमें अपनी रक्षाके लिये दरखास्त दे सकता है और अदालत ऐसी दरखास्त पर दिवालियेकी गिरफ्तारी या कैदसे रक्षाके लिये हुक्म दे सकती है ।

(२) रक्षाका हुक्म सूचीमें दिखलाये हुए सय कजोंके लिये अथवा उनमेंसे किसी कजोंके लिये जैसा कि अदालत मुतासिब समझे लागू हो सकता है और यह अदालत द्वारा बतलाये हुए घण्टेसे शुरू हो सकता है तथा उसके बतलाये हुए समय तक कायम रह सकता है और जैसा अदालत मुतासिब समझे उसके अनुसार खारिज किया जासकता है अथवा फिरसे जारी हो सकता है ।

(३) रक्षाका हुक्म दिवालियेको गिरफ्तारी या कैदसे उन कजोंके सम्बन्धमें बचायेगा जिनके लिये हुक्म हुआ हो और यदि कोई दिवालिया ऐसे हुक्मके विरुद्ध गिरफ्तार या कैद किया गया हो तो यह हुक्मका पानेका अधिकारी होगा । परन्तु शर्त यह है कि किसी ऐसे हुक्मसे कर्जहवाहके हकमें उस समय कोई टकावट नहीं पड़ेगी जब कि यह हुक्म खारिज कर दिया गया हो अथवा दिवालिया कपार दिये जानेका हुक्म मंजूर कर दिया गया हो ।

(४) कोई भी कर्जहवाह हाज़िर होकर रक्षाके हुक्मका विरोध कर सकता है परन्तु ज़ाहिर तौर पर यह दिवालिया रक्षाका हुक्म पानेका अधिकारी होगा जो आफिशल एस यनी का दफ़्तरी सर्टीफिकेट इस बातके लिये पेश कर दे कि उसने इस पृष्ठके नियमोंका पालन उस समय तक बराबर किया है ।

(५) अदालतको अधिकार है कि यदि यह कर्जहवाहोंके हकके लिये उचित समझे तो दिवालिये द्वारा सूची दाखिल किये जानेसे पहिले भी रक्षाका हुक्म दे देय ।

व्याख्या—

इस दफ़्ते दिवालियेकी शर्तके लिये हुक्म दिये जानेका बर्तन है । उपदृष्टा (१) में बतलाया गया है कि सूची दाखिल होनेके पश्चात् दिवालिया रक्षाका दरखास्त दे सकता है । अगली एक्टरी इस उपदृष्टाके प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे यह प्रकट है कि रक्षाका हुक्म देना न देना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है परन्तु आगे चल कर उपदृष्टा (४) व (५) में देखनेसे यह स्पष्ट होता है कि अदालत अपनी इच्छाका प्रयोग इस सम्बन्धमें अवसर बधा आवश्यकता समझने हुए करेगी और उपदृष्टा (४) में यह स्पष्ट तौरसे बतला दिया गया है कि यदि दिवालिया आफिशल एसायनरी सर्टीफिकेट इस बातके लिये पेश करे कि उसने एक्टमें बतलाये सब कर्तव्योंको उस समय तक पालन किया है तो ज़ाहिर तौर पर यह रक्षाका हुक्म पानेका अधिकारी समझा जावेगा जब तक कि इसके विरुद्ध कोई बात माहित न हो जावे । उपदृष्टा (५) के अन्वय सूची दाखिल करनेसे पहिले भी दिवालिया रक्षाका हुक्म प्राप्त कर सकता है । यह न समझ लेना चाहिये कि उपदृष्टा (४) से अदालतका रक्षाका हुक्म देने न देनेका अधिकार छीन लिया गया है बल्कि उस उपदृष्टाके वजह यह बतलाया गया है कि यदि कोई कर्जहवाह रक्षाकी दरखास्तका विरोध करे तो अदालतको किस तर्कके पर काम करना चाहिये अर्थात् अदालतकी इच्छा पर हुक्म देना न देना उस दृष्टिकोणों पर निर्भर है, देखो—35 Bom. 47.

उपदशा (३) में यह बतलाया गया है कि शिकायत दायर करने के लिए जाने पर १२ महीने का समय दिया जायेगा यदि उसी समय में शिकायत दायर नहीं की जाती तो शिकायत अस्वीकार की जायेगी। उपदशा (२) में यह भी बतलाया गया है कि शिकायत दायर करने के लिए जाने पर १२ महीने का समय दिया जायेगा यदि उसी समय में शिकायत दायर नहीं की जाती तो शिकायत अस्वीकार की जायेगी। उपदशा (२) में यह भी बतलाया गया है कि शिकायत दायर करने के लिए जाने पर १२ महीने का समय दिया जायेगा यदि उसी समय में शिकायत दायर नहीं की जाती तो शिकायत अस्वीकार की जायेगी।

दशा २६ कर्जदारों की मीटिंग

(१) दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म हो जानेके पश्चात् किसी समय भी किसी कर्जदार या अक्रिय पक्षधर द्वारा अदालत दिये जाने पर अदालत इन प्रश्नों का हल दे सकती है कि कर्जदारों की मीटिंग की आवश्यकता है कि नहीं। अदालत इस पर विचार करेगी कि कर्जदारों की मीटिंग की आवश्यकता है कि नहीं। अदालत इस पर विचार करेगी कि कर्जदारों की मीटिंग की आवश्यकता है कि नहीं।

(२) पहली सूची (First Schedule) में दिये हुए नियम कर्जदारों की मीटिंग में होने वाली कार्यवाई तथा उसके दिये जानेके सम्बन्ध में प्रयोग किये जायेंगे।

ध्यातव्य—

दिवालिया मीटिंग पर विचार करने के लिए तथा दिवालिया होनेकी अवस्था पर विचार करने के लिए अक्रिय पक्षधर को १२ महीने का समय दिया जायेगा यदि उसी समय में शिकायत दायर नहीं की जाती तो शिकायत अस्वीकार की जायेगी। उपदशा (२) में यह भी बतलाया गया है कि शिकायत दायर करने के लिए जाने पर १२ महीने का समय दिया जायेगा यदि उसी समय में शिकायत दायर नहीं की जाती तो शिकायत अस्वीकार की जायेगी।

उपदशा (२) में यह बतलाया गया है कि शिकायत दायर करने के लिए जाने पर १२ महीने का समय दिया जायेगा यदि उसी समय में शिकायत दायर नहीं की जाती तो शिकायत अस्वीकार की जायेगी।

दशा २७ दिवालिया होनेका सुझाव अदालतमें बयान

(१) जब कि अदालत दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म देवे तो वह किसी नियत किये हुए दिन पर एक सुझाव अदालत करेगी जिसकी सूचना निश्चित दिनांक पर कर्जदारों की दी जायेगी और जिसमें दिवालिया होनेका बयान होवे। दिवालिया होनेके लिए अदालत इस पर विचार करेगी कि कर्जदारों की मीटिंग की आवश्यकता है कि नहीं।

(२) दिवालिया होनेके लिए अदालत की जाने वाली सूची के लिये नियत किये हुए समय के भीतरनेके पश्चात् जितनी जल्दी सुझाव अदालत करेगी उसी समय दिवालिया होनेका बयान दिया जायेगा।

(३) कोई भी कर्जदार जो सुझाव दायर कर चुका है या उसकी ओरसे कोई भी पक्षधर दिवालिया होनेके सम्बन्ध में अदालत के सामने प्रश्न कर सकता है।

(४) अक्रिय पक्षधर दिवालिया होनेके समय भाग लेगा और इसके लिये अदालत द्वारा दी हुई अनुमति अनुसार किसी भी प्रकार का प्रश्न कर सकता है।

(५) अदालत, दिवालियासे यह प्रश्न पूछ सकती है, जो उसे अति आवश्यक होवे ।

(६) दिवालियेके बयान हलफसे लिये जावेंगे और उसका यह कर्तव्य होगा कि वह अदालत द्वारा पूछे जाने वाले सब प्रश्नोंका उत्तर देवे तथा उन प्रश्नोंका भी उत्तर देवे जिनके लिये अदालत आज्ञा दे देवे । बयान की कुछ बातें जो अदालत उचित समझे लिख लेंगी और वह या तो दिवालियेको पढ़ कर सुना दी जावेगी या वह स्वयं पढ़ लेगा और उस पर दिवालिया इरस्तखत करेगा और उसके पश्चात् वह बयान उसके विरुद्ध शहादतमें पेश किये जा सकते हैं और उसका मुआयना कोई भी कर्जाल्वाह उचित अवसरों पर कर सकेगा ।

(७) जब कि अदालतकी रायमें दिवालियेके मामलेकी पर्याप्त रूपसे जांच पड़ताल हो चुकेगी तो अदालत यह हुक्म देवेगी कि उसका बयान समाप्त हो गया है परन्तु ऐसे हुक्मसे अदालत यदि वह फिर कभी उसका अधिक बयान लेना उचित समझे तो बन्धित नहीं रहेगी ।

(८) जब कि दिवालिया पागल होवे अथवा वह किसी मानसिक या शारीरिक दोष या अयोग्यतासे पीड़ित होवे जिसकी वजहसे वह अदालतकी रायमें खुला बयान देनेके लिये अयोग्य है या वह ऐसी औरत होवे जो अपने देशके रीति रिवाजके अनुसार खुले तौर पर बयान देने के लिये मजबूर न की जाना चाहिये तो अदालतको अधिकार है कि वह ऐसे लोगोंका खुला बयान न लिये जानेका हुक्म दे देवे या ऐसा हुक्म दे देवे कि दिवालियेका बयान किसी निश्चित रूपसे तथा निश्चित समय पर लिया जावे जैसा कि अदालत आवश्यक समझे ।

व्याख्या—

दिवालिया कसूर दिये जाने वाले हुक्मके पश्चात् अदालतका कर्तव्य होगा कि वह दिवालियेके बयानोंके लिये कीड़े तारीख नियत करे और दिवालियेका बयान खुली अदालतमें लेवे । इसकी सुचना कर्जाल्वाहानको निर्धारित दिने हुए दफा पर हो जावेगी ।

उपदफा (१) की पाबन्दी आवश्यक है उसके विधियोंकी अवहेलना नहीं की जाना चाहिये जैसा कि अमली एवढी इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे जो दो मतवा इस्तमाल किया गया है प्रकट होता है दिवालियेका भी कर्तव्य होगा कि वह अपने बयानके लिये नियत किये हुए दिन पर हाजिर होवे जैसा कि इस सम्बन्धमें भी अदालत किये हुए अमली एवढे (Shall) शब्दमें भागित होता है । दिवालियेका बयान उक्त व्यवहार चलन व जापरादेके सम्बन्धमें लिया जावेगा ।

उपदफा (२) में वह समय बतलाया गया है जब कि उपदफा (१) के अनुसार बयान लिया जाना चाहिये अर्थात् दिवालिये द्वारा सूची दाखिल किये जानेके लिये जो समय नियत किया गया है उक्त बात जाने पर मिनती मन्दी हो सके उसके बयानके लिये ताराख नियत की जाना चाहिये । अदालत स्वयं सवालपत्र पूछ सकती है । वह कर्जाल्वाहान को अपने कर्जे का सुदूत दाखिल कर चुक हो स्वयं या किसी वकीलके आधे सवालपत्र पूछ सकते हैं आदिमल एसायनी भी उस समय की बरिवाइमें माग लयेगा अर्थात् उक्त कर्तव्य है कि वह उस समय उपस्थित होवे व अधिन पीबी करे । पारवी के लिये वह स्वयं भी परवा कर सकता है तथा उक्त लिये अपने और से कर्जों को भी लखा कर सकता है । इस दफाके अनुसार दिवालियेका बयान लिय जावेगी वह हुक्म देकर लिये जावेंगे और दिवालिया का कर्तव्य होगा कि वह अदालत द्वारा पूछे जाने वाले तथा पुछराय जाने वाले सवा सवाल का जवाब देवे अदालत हर सवाल का जवाब या पूर बयान लिखने के लिये बाध्य नही है कि नु वह जिन मनीसों में उचित समझ रख सकती है परन्तु अदालत वह नहीं कर

सकती है कि वह कुछ भी न लिखे अदालत का कर्तव्य होगा कि वह बयान की सच्ची बातों को लिखे जैसा कि अमेज एक्ट की उप दफा ६ में प्रयोग किये हुये (Shall) शब्द से प्रकट है । जो बयान अदालत नोट करेगा वह दिवालिये को पढ़ कर सुनाये जावेगा और उस पर दिवालिये के दस्तखत लिए जावेगा । इस प्रकार लिखे हुये बयानों का पृथक्करण एक कर्जस्त्राह बन सकता है तथा इस प्रकार दिये हुये बयान दिवालिये के विरुद्ध शह्यदत्त में प्रयोग किये जा सकते हैं । एक दफा उसका बयान हो जानेके बाद भी अदालत दुबारा दिवालिये का बयान उप दफा (७) के अनुसार ले सकती है शब्दका (८) के अनुसार अदालत पम्पानशान औरतों पागलों व अन्य किसी रोग से पीडित पुरुषों को इस दफा के अनुसार बयान देनेसे बरी कर सकती है या अगर वह चाहे तो उनका बयान जिस तरीके से सुनामिब समझ उस तरीके से ले सकती है जैसे कि कमीशन से बयान लिखे जा सकते हैं । इस उपदफा के अनुसार कार्य करना अदालत की इच्छा पर निर्भर है ।

तस्फीया तथा तय किये जानेकी स्कीम

दफा २८ प्रस्तावोंका पेश किया जाना तथा उनका कर्जस्त्राहों द्वारा स्वीकार किया जाना

(१) दिवालिया करार दिये जाने वाले हुफमके पश्चात् दिवालिये को अधिकार है कि अपने कर्जों के चुकाने के सम्बन्धमें तस्फीये का प्रस्ताव अथवा अपने मामलों को तय किये जाने की स्कीम का प्रस्ताव निर्धारित किये हुये ढंग पर पेश करे और वह प्रस्ताव आफिसल एसायनी कर्जस्त्राहों की मीटिंग में पेश करेगा ।

(२) आफिसल एसायनी दिवालिये के प्रस्ताव की नकल मय उस पर दी हुई रिपोर्टके सूची में दिखलाये हुये सब कर्जस्त्राहों या ऐसे कर्जस्त्राहोंके पास भेजेगा जो अपना सुदृढ मीटिंग में दाखिल कर चुके हैं । और यदि उस पर विचार करने पर कसरत लादाव तथा सब कर्जस्त्राहों के कर्जों के तीन चौथाई कीमत के कर्जेशालों की राय से जिनके कर्जों साबित किये जा चुके हैं प्रस्ताव स्वीकार किया जावे तो वह प्रस्ताव कर्जस्त्राहों द्वारा ठीक सीरसे स्वीकार किया हुआ प्रस्ताव माना जावेगा ।

(३) दिवालिया मीटिंगके समय अपने प्रस्तावकी शर्तोंको संशोधित कर सकता है यदि आफिसल एसायनी की रायमें उस संशोधन से उसके आम कर्जस्त्राहों को लाभ पहुंचता होवे ।

(४) कोई भी कर्जस्त्राह जो अपना कर्जा साबित कर चुका है अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति पत्र द्वारा आफिसल एसायनीके पास नियत किये हुये दिनसे एक दिन पहले भेज सकता है अर्थात् उस दिन तक आफिसल एसायनी के पास वह पहुंच जाना चाहिये और इस प्रकार की स्वीकृति या अस्वीकृति का वही प्रभाव होगा जैसे कि यह मीटिंग में मौजूद रहा हो और उसमें वोट दिया हो ।

व्याख्या—

इस दफा में दिवालियेके मामलोंका तयकीया किये जानेकी व्यवस्था बतलाई गई है । दिवालिया करार दिये जानेका हुफम होनेके पश्चात् किसी समय भी दिवालिया अपने कर्जोंको तय करनेके लिये प्रस्ताव पेश कर सकता है । यह प्रस्ताव निर्धारित ढंग पर होना चाहिये और यह प्रस्ताव आफिसल एसायनी द्वारा कर्जस्त्राहानों की मीटिंगमें रखा जावेगा । इस प्रकारका

प्रस्ताव आगे पर आफिशल एसायनीका कर्तव्य होगा कि वह प्रस्ताव की नकल तथा अपनी रिपोर्टकी सूचना उन सब कर्जस्वादानक पास भेजे जो अपना कर्ज साबित कर चुके हैं या जिनका नाम सूचीमें दिया हुआ है इस प्रकारके प्रस्तावका कर्जस्वादान दाय स्वीकार किया जाना उस समय माना जावेगा जब कि बहुमतसे कर्जस्वादानने उस प्रस्तावको स्वीकार किया हो तथा साथही साथ उन कर्जस्वादानका कर्जों कुल कर्जोंके तीन चौथाईसे कम न होने । दिवालिया अपने प्रस्तावका संशोधन भी मॉर्टिगेज समय कर सकता है पण्त्तु यह संशोधन उतरी समय हो सकेगा जब कि आफिशल एसायनी की रायमें वह संशोधन आम कर्जस्वादोंके लाभके लिये समझा जावेगा । कर्जस्वादानकी सुविधाके लिये उपद्रवा (४) में यह दे दिया गया है कि वह अपनी राय लिखकर आफिशल एसायनीके पास भेज सकते हैं और इस प्रकार लिखी हुई रायका नही प्रभाव होगा जो स्वयं उपस्थित होकर बोट देनेका होता है । इस बातका प्यान रहना चाहिये कि इससे पहिले आफिशल एसायनीके पास पहुँच जाना चाहिये अर्थात् मॉर्टिगेजसे पहिले बाचा दिन इस प्रकारकी राय पहुँचनेके लिये आखिरी दिन हवेगा ।

दफा २९ अदालत द्वारा प्रस्तावकी स्वीकृति

(१) जब कि प्रस्ताव कर्जस्वादों द्वारा मंजूर किया जाचुके तब दिवालिया या आफिशल एसायनी अदालतमें उसकी स्वीकृतिके लिये दरखास्त दे सकता है । इस दरखास्तके सुने जाने की सूचना उन सब कर्जस्वादोंको दी जावेगी जो अपना कर्ज साबित कर चुके हैं ।

(२) दिवालियेके खुले आम बयान लिये जानेसे पेश्तर ऐसी दरखास्त नहीं सुनी जावेगी किन्तु उससे पेश्तर उस दशमें सुनवाई हो सकती है जब कि सरसरीमें उसकी जायदादका इन्तज़ाम किया जानेको होवे अथवा अदालतसे उसके लिये विशेष आज्ञा लेली गई हो । कोई भी कर्जस्वाद जो अपना कर्ज साबित कर चुका है दरखास्तका विरोध कर सकता है चाहे वह कर्जस्वादोंकी मॉर्टिगेजमें उस प्रस्तावके स्वीकार किये जानेके लिये बोट दे चुका हो ।

(३) अदालत उस प्रस्तावके लिये स्वीकृत प्रदान करनेसे पहिले आफिशल एसायनीकी रिपोर्ट उसकी शर्तों तथा दिवालियेके बर्तावके बाबत सुनेगी और उन पेश्तराजोंको भी सुनेगी जो कोई कर्जस्वाद करे या जो उसकी ओरसे किये आवें ।

(४) यदि अदालत की रायमें प्रस्तावकी शर्तें उचित न प्रतीत हों अथवा उनसे आम कर्जस्वादोंको लाभ पहुँचने की सम्भावना न हो या कोई इस प्रकारका मामला होवे जिसके कारण अदालत बहाल करनेसे इनकार कर सकती हो तो अदालत प्रस्तावको मंजूर नहीं करेगी ।

(५) जब कि कोई ऐसी बातें साबित की गई हों जिनके साबित होनेके कारण दिवालिये के बहाल किये जानेसे इनकार किया जासके या वह रोका जासके अथवा उसमें शर्तें लगाई जा सकें तो अदालत प्रस्तावको स्वीकार करनेसे इनकार कर देगी परन्तु वह उस सूरतमें मंजूर किया जासकेगा जब कि उसमें उचित ज़मानत उन बिला महफूज़ कर्जोंकी रूपयमें चार आने अदायगी की गई हो जो इस एकटके अनुसार साबित किये जासकते हों ।

(६) यदि दिवालियेकी जायदादसे कोई कर्जों औरोंके मुकाबले पहिले अदा किये जाना चाहिये और तसकिये या स्कीममें उनके इस प्रकार पहिले अदा किये जानेकी व्यवस्था न की गई हो तो ऐसा प्रस्ताव या स्कीम स्वीकार नहीं की जावेगी ।

(७) अन्य किसी मामलेमें अदालत या तो प्रस्ताव को स्वीकार कर सकती है अथवा उसको अस्वीकार कर सकती है ।

व्याख्या—

दफा २० के अनुसार कर्जस्वादान द्वारा स्वीकार किया हुआ प्रस्ताव उस समय तक कार्यान्वित नहीं किया जायेगा जब तक कि अदालत उसे मजबूर न कर देवे । कर्जस्वादान द्वारा स्वीकार किये जानेके पश्चात् आक्षिप्त एरायनी या दिवालिया अदालतमें उस प्रस्तावके मजूर निये जानेके लिये दम्ब्यास्त दे सकता है और इस प्रकार दी हुई दम्ब्यास्तको सुनोके लिये जो तांगेज नियतकी जावेगी उसकी सूचना उन तब कर्जस्वादानको दी जावेगी जो अपना कर्ज सादित कर चुके हैं । इस उपदफामें बतलाई हुई सूचना अवश्य दी जानी चाहिये जमा कि अग्रणी एवटर्की इस उपदफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दका तात्पर्य मालूम होता है ।

उपदफा (२) में यह बतलाया गया है कि जब कोई कॉन्ट्राई सरसमिमें को गई हो या जब कि अदालतने प्रमाण तोरसे आशा दे दी हो तो सरसमि या प्रस्ताव दिवालिया कथार दिये जानेके बाद किसी समय भी सुना जा सकता है परन्तु और मामलोंमें इस प्रकारकी दम्ब्यास्त उस समय तक नहीं सुनी जावेगी जब तक कि दिवालियेका प्रमाण खुदो अदालतमें न हो जावे । इसी उपदफामें यह भी बतलाया गया है कि यदि किसी कर्जस्वादानने प्रस्तावके लिये अपनी स्वीकृति दी भी या शर्तें दी यह इस दफाके अनुसार दी हुई दम्ब्यास्तका विरोध कर सकता है परन्तु इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि वही कर्जस्वादाई विशेष करनेके अधिकारी होंगे जिनके कर्ज सादित किये जाचुके हैं ।

उपदफा (३) में यह बतलाया गया है कि अदालतका कर्तव्य होगा कि वह इस दफाके अनुसार पेश भिरे हुए प्रस्तावके लिये अपनी मजबूरी देनेसे पहिले आक्षिप्त एरायनीका रिपोर्टकी देखे तथा पुनराज करने वाले कर्जस्वादानके एतराकोई सुने ।

उपदफा (४) में उन दशाओंका वर्णन है जिनके उपरिष्ठ होने पर अदालत प्रस्तावको स्वीकार कर देनेसे इनकार कर देवेगी अदालत इन दशाओंमें प्रस्ताव स्वीकार करेगी—

(i) जब कि प्रस्ताव उपरिष्ठ प्रतीत न होने, या

(ii) जब कि प्रस्तावसे आश कर्जस्वादानकी लाभ पहुचनेकी सम्भावना न होती होने, या

(iii) जब कि ऐसी शिष्टि होके जिसके अनुसार अदालत दिवालियेको दफा कनेसे इनकार कर देनेके लिये बाध्य होवे । अग्रेजी एवटर्की इस उपदफामें (Shall) शब्दका प्रयोग है जिससे यह समझना चाहिये कि इस उपदफामें बतलाई हुई बातोंके होने पर प्रस्ताव हमिल मजूर नहीं किया जावेगा ।

उपदफा (५) में उन बातोंका उल्लेख है जिनके होने पर अदालत प्रस्ताव उस समय तक मजूर नहीं करेगी जब तक कि दिवा मरबूज कर्जस्वादानके कर्ज करियेमें चार आने चुकाने जायेका उचित प्रबन्ध जयान्त आदिसे न कर दिया गया हो । इस उपदफाका प्रयोग सही समय किया जावेगा जब कि वाञ्छयात ऐसे अशस्तिन देंगे जिनके उपरिष्ठिके कारण अदालत दफालका हुक्म देनेसे इनकार कर सकती हो अथवा उसके लिये जूरी लगा सकती हो अथवा समझ-बुझा सकती हो ।

उपदफा (६) में पेशर अदा किये जाने योग्य कर्जोंकी अदमनीका प्रबन्ध पेशर ही किये जानेकी व्यवस्था बतलाई गई है यदि इस व्यवस्था प्रबन्ध तरकीबि या रीतिमें न होने तो बह मसूला नदी किया जावेगा अग्रणी एवटर्की प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दने यहाँ समझना चाहिये कि उनका प्रबन्ध पेशर किया जायाही पण आवश्यक है । उपदफा (८) से लेकर ९ तक जिन नियमोंका वर्णन है उनका ध्यान रखते हुए यदि मामला अन्य किसी प्रधानका होवे तो अदालतकी अधिकार है जिस मताका हुक्म चाहे दे देने अर्थात् अवसर न बाक्यातको देखते हुए वह अपनी रज्जनुसार वांछित हुक्म दे सकती है ।

दफा ३० प्रस्ताव स्वीकार किये जाने पर हुकम

(१) यदि प्रस्ताव मंजूर किया जावे तो उसकी शर्तें अदालत अपने हुकममें लिख देवेगी और दिवालिया करार दिये जाने वाले हुकम की मसूखीका हुकम दिया जावेगा और दफा २३ की उपदफा (१) व (३) के नियम इसके पश्चात् लागू होंगे और वह तसफीया या तय होने की स्कीम स्वयं कर्जख्वाहों पर उस हद तक लागू होगी जहां तक उसका सम्बन्ध उनके उन कर्जोंसे है जो दिवालिये की कार्यवाही के सम्बन्धमें साबित किये जा सकते हैं ।

किसी सम्बन्धित व्यक्ति के दूरव्वास्त देने पर तसफीया या तय किये जाने वाले स्कीमके नियमोंकी पाबन्दी अदालत द्वारा कर्ण आसकती है और ऐसी दूरव्वास्त पर दिये हुए किसी हुकमकी उलूती करने पर अदालत की तौहीन (Contempt of Court) समझी जावेगी ।

व्याख्या—

दिवालिया करार दिये जाने वाले हुकमकी मसूखी या तो पूरा कर्जों का दिये जाने पर अथवा तसफीया जिसका उल्लेख दफा २८, २९ व ३० में है उसके अनुसार हो सकती है । इसके विपरीत यदि कोई नाइमी सप्तसात हो जावे तो उससे न तो कर्जोंकी पूरी अदायगीही सम्झी जावेगी और न वह तसफीयाही सम्झा जावेगा, दफा—43 Mad 71. इस दफाके अनुसार यदि तसफीया अदालत द्वारा स्वीकार कर लिया जावे तो उसकी सब शर्तें अदालतके हुकममें दे दी जावेगी अमली एकरकी इस दफाके प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दमें यह धरती भानि प्रकट है कि उन शर्तोंका अदालतके हुकममें दिया जाना आवश्यक है । इसी प्रकार तसफीया स्वीकार करने पर दिवालिया करार दिया जाने वाला हुकम मसूखी कर दिया जावेगा । दफा २३ के उपदफा (१) व (३) में बतलाये हुए नियम मसूखीका हुकम होने पर लागू होंगे अर्थात् दफा २३ की उपदफा (१) के अनुसार मसूखीका हुकम होनेसे पहिले किये हुए सब रोदे व हुकम जैसेके जैसे बच रहेंगे तथा आयादाद दिवालिये या अन्य किसी व्यक्ति के सुपुर्देगीमें अदालतके हुकमके अनुसार आयावेगी और दफा २३ की उपदफा (३) के अनुसार मसूखीके हुकमकी मुतादबी की जावेगी । इस दफाकी यह बात ध्यान रखने योग्य है कि मसूखीका हुकम हो जाने पर तसफीया या स्कीम जिसके आधार पर मसूखीका हुकम दिया गया हो दिवालियेके सब कर्जख्वाहों पर लागू होगा अर्थात् उन कर्जख्वाहोंके उन सब कर्जोंके सम्बन्धमें लागू होगा जो दिवालियेके कार्यवाहीमें साबित किये जा सकते हैं । ऊपर बतलाये हुए बातका तात्पर्य यह समझना चाहिये कि वह कर्जख्वाह जि होने तसफीयाके स्वीकार न किया हो अथवा वह कर्जख्वाह जो हाजिर हो व हुए हो तसफीयाके बावद होंगे । दफा २८ के अनुसार तसफीयाके प्रस्तावका मोटिस उन् सब कर्जख्वाहोंके पास भेजा जाना बतलाया गया है जिनके नाम कर्जख्वाहोंकी सूचीमें दिखलाये गये हों तथा उन कर्जख्वाहोंके पास भी भेजा जावेगा जिन्होंने अपना कर्जा साबित किया हो इस प्रकार तसफीयाके प्रस्तावकी सूचना दिवालियेके सब कर्जख्वाहोंके पास पहुँचानेकी व्यवस्था की गई है और इसी कारण उन कर्जख्वाहोंके बादमें एतादा करनेका कोई अवसर नहीं है । दफा २८ में यह भी बात बतला दी गई है कि यदि बहुमतसे कर्जख्वाहान प्रस्तावकी स्वीकार करल और स्वीकार करने वालोंका जहाँ कुल कर्जोंके हानि चौथाईसे अधिक होवे तो मान लिया जावेगा कि सब कर्जख्वाहानने प्रस्तावकी स्वीकार कर लिया है । दफा ३८ में बतलाये नियमोंके अनुसार कर्जख्वाहों द्वारा प्रस्तावका स्वीकृति हो जाने पर फिर अदालतके सामने वह प्रस्ताव पेश होगा और यह दफा २९ में बतलाये हुए नियमोंके अनुसार कर्जख्वाहानकी सूचना देनेके बाद अदालतकी मजूरी पावेगा । इसलिये यह उचित समझा गया है कि अदालतकी मजूरी होने पर तसफीया या स्कीमकी पाबन्दी सब कर्जख्वाहों पर उस हद तक होना चाहिये जहां तक उनके उन कर्जोंसे सम्बन्ध है जो अदालत दिवालियामें साबित किये जा सकते हैं । उपदफा (२) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति तसफीयाके सम्बन्धमें दिये हुए हुकमको न माने तो उससे अदालत की तौहीन सम्झी जावेगी ।

दफा ३१ दिवालियेको दुबारा दिवालिया करार देनेके अधिकार

(१) यदि ऊपर लिखे अनुसार स्वीकार की हुई स्कीम या प्रस्ताव में बतलाई हुई किसी क्रिस्त की अदायगी में ग़लती की जावे या अदालत को मालूम होवे कि बिला वेदन्साफीके या बिना देर किये हुए वह तस्फीया व स्कीम अमल में नहीं लाई जा सकती है या अदालत की स्वीकृति थोड़ा देरी से ले गई है तो अदालत यदि वह उचित समझे तो किसी सम्बन्धित व्यक्ति के दरखास्त पर कर्जदार को दुबारा दिवालिया करार दे सकती है और तस्फीया या स्कीम को रद्द कर सकती है। और इस पर दिवालिये की जायदाद आफिशल एसायनी की सुपुर्दगी में आ जायेगी परन्तु इसका कोई प्रभाव उन ट्रान्सफरों (Transfer) पर या उन अदायगियों पर विद्यमान रूप में नहीं पड़ेगा जो बाकायदा मंजूरकी हुई स्कीम या तस्फीयेके अनुसार किये जा चुके हों।

(२) जब कि कोई कर्जदार उपदफा (१) के अनुसार दुबारा दिवालिया करार दिया जावे तो साबित किये जाने योग्य यह सब कर्जें जो दुबारा दिवालिया करार दिये जानेसे पहिले लिखे गये हैं दिवालियेकी कार्रवाईके सिलसिलेमें साबित किये जायेंगे।

व्याख्या—

इस दफामें यह बतलाया गया है कि यदि दिवालिया तरायेकी शर्तों की पाबन्दी न की अथवा तस्फीया थोड़ा देरी से मंजूर कराया गया हो या वह क्वाबिल पाबन्दी न समझा जावे तो अदालत तरायेकी मंजूरीके हुक्मको मंजूर कर कर्जदारको फिरसे दिवालिया करार दे सकती है क्योंकि कर्जदार अपनी चालाकियोंसे काम नहीं उठा सकता है और न कर्जदारोंकी हक़तान ही किसी खास ग़लतीकी वजहसे पहुँचाया जा सकता है। दुबारा दिवालिया करार दिये जाने पर कर्जदार उन्हें शर्तों की पाबन्द समझा जावेगा जिन शर्तों की पाबन्द वह पहिले मर्तबा दिवालिया करार दिया जाने पर हुआ था। उसकी जायदाद आफिशल एसायनीकी सुपुर्दगीमें आगबग़ा परन्तु तस्फीयेकी मसूखीका हुक्म होनेसे पहिले तस्फीयेके अनुसार जो काम या सोदे किये गये होंगे वह सब बदस्तूर बन रहेंगे व ठीक समझे जायेंगे।

उपदफा (२) के अनुसार वह सब कर्जें भी दुबारा दिवालिया करार दिये जाने पर साबित किये जा सकेंगे जो तराये या स्कीमकी मंजूरीके पश्चात् तथा उस मंजूरीके हुक्मकी मसूखीसे पहिले किये गये हों। इस प्रकार तराईके बाद बाले कर्जेंकाही भी दिवालियेकी जायदादसे हिस्सा तस्फी प्राप्त करनेके अधिकारी होंगे।

दफा ३२ तस्फीये या स्कीमका प्रभाव

तस्फीये या स्कीमके स्वीकार किये जाने पर भी उसका कोई प्रभाव किसी कर्जदारके ऐसे कर्जों या जिम्मेदारियों पर नहीं पड़ेगा जिनसे बहाल होने पर भी इस एक्टके नियमोंके अनुसार उद्धार नहीं हो सकेगा जब तक कि वह कर्जेंकाही तस्फीया या स्कीममें अपनी स्वीकृति न दे देवे।

व्याख्या—

इस दफामें यह बतलाया गया है कि तस्फीया या स्कीमके मंजूर होने पर भी उसकी पाबन्दी ऐसे कर्जों पर लागू नहीं होगी जो दिवालियाके नज़्म होने पर भी जिनके तैरे को रहेंगे क्योंकि उनसे हुए नहीं माने जायेंगे जब तक कि उनके कर्जेंकाही तस्फीया या स्कीममें मंजूर न कर लें। दफा ४५ में उन कर्जोंका उल्लेख है जिनसे दिवालिया नज़्म होने पर भी बर्हि

नहीं समझा जावेगा । दफा ४५ वी उपदफा (१) के प्राज (ए), (बी), (सी) व (डी) में द्रो कर्ते बतलाये गये हैं सूक्ष्ममें वह कर्ते यह हैं सरकारी कर्ज, घांतेसे लिया हुआ कर्ज, घांसेने डुहाया हुआ कर्ज न आकरा कौनदारीने अनुसर दिखिने मुजबिदा कर्जों । परतु इस बातका भी ध्यान रखना चाहिये कि यदि एन कर्जका पाने वाला कर्जाल्वाह तरकीब या रबीमको मनुर कर लेवे तो उस पर उस तरकीब या रबीमरी पाने दी मनुर कर लनेके बाद उसी प्रकार हागी गित प्रकार अन्य कर्जवाहों पर ।

दिवालिघेकी ज्ञात व जायदादके सम्बन्धमें अधिकार

दफा ३३ जायदादके बतलाने व उसको वसूल करानेके सम्बन्धमें दिवालिघे के कर्तव्य

हर एक दिवालिघेका कर्तव्य होगा कि वह बीमारी अथवा किसी दूसरे पर्याप्त कारणसे न रुक जावे तो वह कर्जख्वाहोंकी उस मीटिंगमें हाजिर होगा जिसमें आफिशल एसायनी उसकी उपस्थिति आवश्यक समझे और मीटिंग जिस प्रकार चाहेगी उसको उस प्रकारका बयान या इत्तला देना पड़ेगा ।

(२) दिवालिघेका कर्तव्य होगा कि वह निम्न लिखित कामोंको उस प्रकार करे जिस प्रकार आफिशल एसायनी या विशेष मैनेजर उससे कराना चाहे अथवा जिस प्रकार निर्धारित किया गया हो या जिस प्रकार अदालत अपने विशेष हुकम द्वारा किसी विशेष मामलेंके सम्बन्धमें करनेका हुकम देवे या जिस प्रकार करनेका हुकम आफिशल एसायनी, विशेष मैनेजर किसी कर्ज-ख्वाह अथवा किसी सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा दी हुई दरख्वास्त पर दिया जावे:—

(ए) अपनी जायदादकी फिहरिस्त देवे कर्जख्वाहों व कर्जधारोंकी फिहरिस्त दाखिल और अपने लेन व देने वाले कर्जोंकी फिहरिस्त भी दाखिल करे ।

(बी) अपनी जायदाद अथवा अपने कर्जख्वाहोंके सम्बन्धमें बयान देवे ।

(सी) आफिशल एसायनी या विशेष मैनेजरके सम्मुख बतलावे हुए समय व स्थानों पर हाजिर होवे ।

(डी) मुफतारनामें, दस्तावेज इन्तकाल जायदाद और दूसरी दस्तावेजें सहरीर करे ।

(ई) अपनी जायदाद तथा उसको कर्जख्वाहानके धीचमें बांटे जानेके सम्बन्धमें की जाने वाली सब बातों व कामोंको करे ।

(३) दिवालिघा अपनी शक्ति भर अपनी जायदादको वसूल कराने तथा उसकी क्रीमत अपने कर्जख्वाहोंमें बांटे जानमें मदद देवे ।

(४) यदि दिवालिघा जानते हुए इस दफामें बतलाये हुए कर्तव्योंको पालन नहीं करेगा या वह अपनी जायदादके किसी हिस्सेका कब्जा जो उसके कर्ज या अधिकारमें होवे और जो उसके कर्जख्वाहोंमें बांटी जासकती हो आफिशल एसायनीको नहीं देवे तो वह अलवा और सजाओंके जो उसको दी जासकती हों अदालतकी तौहीन करनेका दोषी होगा और उसको उसके अनुसार दण्ड दिया जासकेगा ।

व्याख्या—

इस दफा में दिवालिये के उन कर्तव्यों का उल्लेख है जो उसे अपनी जायदाद पर तब तक करने तथा उसके बर्तन करने के सम्बन्ध में करना आवश्यक है तथा निम्न न करने पर वह दोषी समझा जा सकेगा और दण्ड का अधिकारी होगा। अथवा एकदम उपद्रव (१), (२) व (३) में (Shall) शब्द का प्रयोग किया गया है जिसमें यह तात्पर्य समझना चाहिये कि दिवालिया उन उपद्रवों में बतलाये हुए नियमों की अवहेलना नहीं कर सकता है किन्तु उनकी पाबन्दी उसने छिपे आवश्यक है।

उपद्रव (१) के अनुसार यदि आकिशक एसायनी दिवालिये से कर्मस्वाहों की किसी मीटिंग में उपस्थित होने के बड़े तो उस उस मीटिंग में उपस्थित होना पड़ेगा तथा मीटिंग में उससे जो बयान या इतरा चाही जावगी वह उसे देना पड़ेगा।

उपद्रव (२) में यह बतलाया गया है कि दिवालिये को क्लार्क (ए), (बी), (सी), (डी) व (ई) में बतलाई हुई बातों का जवाब देना होगा तथा उनमें बतलाये हुए कामों को करना होगा। इन शब्दों में बतलाये हुए कामों को करने के लिये आकिशक एसायनी, व विशेष मैनेजर कह सकता है अथवा अदालत स्वयं इसके लिये हुक्म दे सकती है।

फलाज (ए) के अनुसार जायदादी केहरिन्, कर्मस्वाहों व कर्मदायों की केहरिस्त तथा उनकी दिये जाने वाले या बनने बसूठ किये जाने वाले कर्मों का प्रयोग मा ॥ जासकता है।

फलाज (बी) के अनुसार जायदाद तथा कर्मस्वाहों के सम्बन्ध में दिवालिये के बयान लिये जासकते हैं।

फलाज (सी) के अनुसार दिवालिये को आठ घण्टा एसायनी अथवा विशेष मैनेजर के पास चाहें हुए समय व बतलाई हुई जगह उपस्थित होने की कड़ा जासकता है।

फलाज (डी) के अनुसार दिवालिये से क्लार्क नाम, दफाकेन इन्तकाज जायदाद तथा दूसरे कसबात लिखाने जासकते हैं।

फलाज (आई) के अनुसार दिवालिये से उसकी जायदाद बसूठ किये जाने तथा उसके कर्मस्वाहों में बांटे जाने के सम्बन्ध में सभी काम व बातें जो आवश्यक समझ पड़ कहई जासकता है।

इस उपद्रव में बतलाये हुए कामों को करने के लिये अदालत में कर्मस्वाह या अन्य कोई सम्बन्धित व्यक्ति भी दखलाने शक है। आकिशक एसायनी या विशेष मैनेजर भी यदि अपने अधिकारों से बाहर कोई काम इस दफा के अनुसार करवा चाहें तो अदालत में दखलाने दे सकता है और तब अदालत अपने हुक्मों के अनुसार दिवालिये को उस काम के करने के लिये मजबूर कर सकती है।

उपद्रव (३) में दिवालिये का यह कर्तव्य बतलाया गया है कि जिसकी सत्ते हो सकेगी उसकी मदद अपनी जायदाद व बसूठ करने तथा उसके कर्मस्वाहों में तकलीफ किये जाने में करेगा।

उपद्रव (४) में यह दिया हुआ है कि यदि जाने वृत्त कर दिवालिया इस दफा में बतलाये हुए कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा या वह अपने कर्तव्यों को कुछ या कुछ जायदाद से नहीं छोड़ेगा तो वह इस प्रकार किये हुए अपराध का निर्दोषी नहीं होगा और दण्ड पर दण्ड पावेगा और साथ ही साथ वह अदालत की तौहिन (Contempt of Court) का दोषी समझा जावेगा और इस अपराध का भी दण्ड पासवेगा। यदि आकिशक एसायनी दिवालिये से कोई काम बचना चाहें तो वह जाननी भी कर सकता है परन्तु यदि वह अदालत से दिवालिये का काम न बनने का बयान देना चाहिये तो लिख कर हुक्म देना चाहना चाहिये होगा और उसके साथ साथ यह भी नोटिस देना चाहिये कि यदि हुक्म की तामीन नहीं की जावेगा तो अदालत तौहिन देने की शक्ति रखेगी। (दो—47 Cal. 56.)

दफा ३४ दिवालियेकी गिरफ्तारी

(१) निम्न लिखित बातोंके उपस्थित होने पर अदालतको अधिकार होगा कि वह स्वयं ही या आफिशल एसायनी अथवा किसी कर्जव्याहक दरखास्त देने पर दिवालिएकी पुलिस आफिसर द्वारा अथवा अन्य किसी नियुक्त किये हुए अफसर द्वारा चाएटके जुरिय गिरफ्तार करा लेंगे और उसे दीवानीकी जेलमें भेज देंगे या यदि वह जेलहीमें होवे तो उसको उस समय जब तक कि अदालत उचित समझे वहां बन्द रखनेका हुक्म दे देंगे ।

(ए) यदि अदालतको मालूम हो कि पर्याप्त कारण इस पर विश्वास करनेके लिये है कि वह भाग गया है या वह इस कारण भागने वाला है कि जिसमें उसका बयान उसके मामलोंके सम्बन्धमें न लिया जा सकें या वह अपने विरुद्ध फीजाने वाली दिवालियेकी कार्याहोंको डाला चाहता है या उनमें देर करवा चाहता है या उनमें उलझन पैदा कराना चाहता है, या

(बी) यदि अदालतको मालूम हो कि पर्याप्त कारण इस पर विश्वास करनेके लिये उपस्थित है कि वह अपनी जायदादको इस नीयतसे हटाने वाला है जिसमें आफिशल एसायनी द्वारा उस पर कब्जा लिये जानमें रुकावट पड़े या देर होवे या इस बात पर विश्वास करने के लिय पर्याप्त कारण होवे कि उसने अपनी किसी जायदाद या कित्तियों या दस्तावेजों या अन्य सहरीयोंको जिनसे उसकी दिवालियेकी कार्याहोंके सम्बन्धमें उसके कर्जमुद्दाह कायदा उठा सकते हैं छिपा दिया है अथवा छिपाने वाला है ।

(सी) यदि वह यिला आफिशल एसायनीकी आज्ञाके अपनी पचास रुपयेसे ऊपरकी कीमत वाली जायदादको हटा देंगे ।

(२) इस दफाके अनुसार गिरफ्तार किये जानेके पश्चात् यदि कोई अदायगी कीजाये या कोई तस्फीया किया जावे या जमानत दी जावे और वह धोखादेहीने तर्तीह देने वाले सौदे इस एन्टके नियमोंके अनुसार होवे तो वह बरी नहीं होंगे अर्थात् वह धोखादेहीसे की हुई अदायगी, तस्फीया या जमानत समझी जावेगी ।

व्याख्या—

इस दफामें बड़े वज्रात बखलये गये हैं जिनके होने पर अदालत, दिवालिएकी गिरफ्तार करा सकती है या यदि बड़े जेलमें हीन हो उते किसी नियत समय तकके लिये वहां भेके जानेका हुक्म दे सकती है । अदालत इस दफाके अनुसार कानूनी रवय ही कर सकती है अथवा आफिशल एसायनी या किसी कर्जवाहके दरखास्त देने पर कर सकती है । इस दफाके अनुसार नारण्ट किसी पुलिस आफिसर अथवा किसी दूसरे विधीति रिये हुए अफसरके नाम दिया जासकता है इस दफाके अनुसार गिरफ्तार रिये जाने पर दिवालिया दीवानीकी जेलमें रखा जावेगा ।

उपदफा (१) के क्लॉज (ए), (बी) व (सी) में वह नौ नरखई गई हैं जिनके होने पर या किये जाने पर अदालत गिरफ्तारीका हुक्म या जेलमें भेके जानेका हुक्म दे सकती है ।

क्लॉज (ए) में यह बालाया गया है कि जब दिवालिया भाग गया हो या भागने वाला हो जिसमें उसका बयान न हो सके

या अप किसी प्रकार से उस विरुद्ध होने वाली दिवालियेकी कार्रवाई रुकने पर सब से अधिक ऐसा बात का निश्चय होने पर न्याय जागे करनी कार्रवाई कर सकता है ।

पंजाब (बी) वे अनुसार यदि दिवालिये जायदादकी हथ दिया हो । तथा दिया हो या हान वाला हथे अपना उम्मे अपनी हिसानकी निताओं या दूसरेवैतोंकी या दूसरी तरफकी छिद्र दिया हो या नष्ट कर दिया हो निम्न एक आफिशल एसायनीको कम्पा न मिल सके या निम्न उस विरुद्ध दिवालियेकी कार्रवाई सम्पन्न हो न उठाया जासक हो अतन्त ऐसा बतोंका निश्चय दिने जाने पर निम्नतादीकी कार्रवाई कर सकती है ।

पंजाब (सी) के अनुसार यदि दिवालिये बिना आफिशल एसायनीकी गुण पथान हथेकी बापने केदिशय गुणदा हथ रहे तो भी अतन्त इसा परकार कया जासकना है ।

उपपंजा (२) मे यह बतलाया गया है कि क्य दारक अनुसार निम्नता किये जानेके बाद यदि दिवालिप्या कार्रवाई करी तस्वीया करे या जमानत रहे और वह अग्रणी, तरफिया या अमानत धातादेईस तर्गई दिया जान वज सौदा हथे तो वह सौदा बसा प्रकारका याता धोखेदेईस तर्गईका सौदा ही माना जावेगा अर्थात् काबिल मसूदा होगा ।

दफा ३५ खतोंका दूसरी जगहके लिये भेजा जाना

जब कि आफिशल एसायनी दरमियानी, रिस्तीपर नियुक्त किया गया हो या जब दिवालिप्या करार दिये जाने वाला हुक्म दे दिया गया हो तब आफिशल एसायनीकी दरखास्त पर अदालत को अधिकार है कि वह समय समय पर नियत समयके लिये जो तीन महीनेसे अधिक न होगा जैसा अदालत मुनासिब समझे यह हुक्म दे देवे कि दिवालिप्येके नाम आने वाले सब रजिस्ट्रीगुदा या विला रजिस्ट्रीवाले खत, पार्सल या मनीआर्डर ओ फर्जदारके नाम किसी जगह या जगहोंके पतेसे आवें यह ब्रिटिश भारतमें स्थित डाकघाने वालों द्वारा आफिशल एसायनीके पास भेज दिये जावेंगे या अन्य किसी व्यक्तिको दे दिये जावेंगे जैसा अदालत हुक्म देवे और तब ऐसा ही किया जावेगा ।

व्याख्या—

इस दफामें दिवालिप्येके खत, पार्सल व मनीआर्डरके विषे आफिशल एसायनीको दिये जानेकी व्यवस्था बतलाई गई है । इन दफाके अनुसार हुक्म दरमियानी रिस्तीपर नियुक्त किये जाने अथवा दिवालिप्या करार दिये जानेपर हुक्म होनेके पश्चात् दिया जायसकता है । अदालत इस दफाके अनुसार हुक्म दे न मई नम अधिक समयके लिये नहीं दे सकता है । अतन्त इन दफाके अनुसार हुक्म दनेके लिये काय नहीं है जैसा कि अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें प्रयोग दिये हुए (May) शब्दसे प्रकट है । इस दफाके अनुसार अदालत इस प्रकारका हुक्म बाख्तानेके अफमयके नाम दे सकती है कि दिवालिप्येके नामसे जाने वाले रजिस्ट्री गुदा व विला रजिस्ट्री गुदा खत, मनीआर्डर या पार्सल किसी निश्चित अवधि तक बजाय दिवालिप्येके आफिशल एसायनी अपना अन्य किसी व्यक्ति को दिये जाने अथवा उनके नाम करके भेज दिये जावें । इस प्रकार दिये हुए हुक्मकी पावरी दाफ खाने वालोंकी करना हागी जैसा कि अंग्रेजी एक्टमें दिये हुए (Shall) शब्दका वाक्य निश्चय है ।

दफा ३६ दिवालिप्येकी जायदादका पता लगाना

(१) दिवालिप्या करार दिये जानेके पश्चात् किसी समय भी आफिशल एसायनी या ऐसे कर्मचारीके दरखास्त देने पर जिसेने कि अपना फर्ज सीबत कर दिया है अदालत निर्धारित

नियमोंके अनुसार दिवालिये या अन्य किसी ऐसे व्यक्तिको तलब कर सकती है जिसके कर्जमें दिवालिये की जायदाद होनेका शरु होवे या जो दिवालिये की कर्जदार समझा जावे अथवा जो अदालतकी रायमें दिवालिये या उसकी जायदाद या उसके व्यवहारके सम्बन्धमें इत्ला दे सके और अदालत उस व्यक्तिमें उन दस्तावेजोंको भी जो दिवालिये उसकी जायदाद या व्यवहारके सम्बन्धमें होवे तथा जो उसके कर्ज या अधिकारमें होवे दाखिल करा सकती है ।

(२) यदि इस प्रकार तलब किया हुआ कोई व्यक्ति समुचित द्रव्य दाखिल किये जानें पर नियत किये हुए समय पर अदालतके सम्मुख आनेसे इनकार करे या ऐसी दस्तावेज दाखिल करनेसे इनकार करे और उसके लिये कोई ऐसी कानूनी दवावट पेशीके समय न बतलावे जिसे अदालतने स्वीकार कर लिया हो तो अदालत को अधिकार है कि वह ऐसे व्यक्तिको चारण्ट द्वारा गिरफ्तार करा कर ध्यानके लिये लाये जानेका हुक्म दे देवे ।

(३) इस प्रकार लाये हुए व्यक्तिसे अदालत, दिवालिये तथा उसकी जायदाद व व्यवहारके सम्बन्धमें ध्यान ले सकती है और ऐसा व्यक्ति अपनी पैरवी बमौल द्वारा करा सकता है ।

(४) यदि ऐसे व्यक्तिके ध्यानसे अदालतको विश्वास हो जावे कि वह दिवालियेका अग्रणी है तो वह आफिशल एसायनीके दरखास्त देने पर ऐसे व्यक्तिको यह हुक्म दे सकती है कि वह व्यक्ति अपने कर्जका रुपया नियत किये हुए समय पर व नियत ढंगसे जैसा कि अदालत उचित समझे अदा कर देवे या उस कर्जका कोई हिस्सा उस कर्जकी पूरी अदायगीमें या योंही जैसा अदालत उचित समझे मय उसके धयानोंके सम्बन्धमें पड़े हुए सचेंके या विला उसके आफिशल एसायनीको अदा कर देवे ।

(५) यदि उस व्यक्तिके ध्यानसे अदालत को यह विश्वास हो जावे कि उस व्यक्तिके कर्जमें दिवालिये की कोई जायदाद है तो अदालत आफिशल एसायनीके दरखास्त देने पर यह हुक्म दे सकती है कि वह व्यक्ति दिवालियेकी जायदाद या उसके कोई हिस्सा नियत किये हुए समय पर व नियत किये हुए ढंगसे नियतकी हुई शर्तोंके अनुसार जैसा अदालतको उचित प्रतीत हो आफिशल एसायनीको दे देवे ।

(६) उपदफा (४) व (५) के अनुसार दिये हुए हुक्मोंकी तामील उसी प्रकार करायें जायेंगी जिस प्रकार जाबता दीवानीके अनुसार रुपयेकी अदायगीके सम्बन्धमें दी हुई डिक्री या जायदाद पर क़त्ता देने वाली डिक्री इजराय करायें जासकती है ।

(७) यदि कोई व्यक्ति उपदफा (४) व (५) के अनुसार दिये हुए हुक्मोंकी तामील करते हुए कोई अदायगी करे या जायदाद सुपुर्दगीमें देवे तो वह इस प्रकारकी अदायगी या सुपुर्दगीसे उस कर्ज व उस जायदाद सम्बन्धी सब ज़िम्मेदारियोंसे बरी हो जावेगा ।

व्याख्या—

इस दफामें दिवालियेकी जायदाद बरामद किये जानेके सम्बन्धमें नियम दिया हुआ है । अदालत उपदफा (१) के अनुसार बर्तारद आफिशल एसायनी या ऐसे कर्जकारोंके दाखला देने पर बरेगी जितने कि अपना कर्ज खर्चित कर दिया होवे । उपदफाके अनुसार बर्तारद दिवालिया करार दिया जाने वाला हुक्म होनेसे पश्चात् बीनासकेंगी ।

उपदफा (१) के अनुसार अदालत, दिवालय अथवा अथ किसी व्यक्ति को जिसके कर्म्ममें दिवालियेरी जायदाद होवे या जो दिवालियेरी कर्म्मदार होवे अथवा जो दिवालिये उसके व्यवहार या उसकी जायदादके सम्बन्धमें हस्तान् दे सकता है तलब कर सकता है और इस प्रकार तलब किये हुए व्यक्तिसे दिवालिये उसके व्यवहार अथवा उसकी जायदादसे सम्बन्ध रखने वाली दरावेजोंके भी अदालत दाखिल करा सकती है ।

उपदफा (२) में यह दिशा हुआ है कि यदि नियमानुसार तलब किये जाने पर कोई व्यक्ति न आवे या हस्तान् न पेश करे तो अदालत उसके लिये वारण्ट जारी कर सकती है परन्तु साथ ही साथ यह भी दिया हुआ है कि यदि किसी पक्षीस कारणसे उसके आनेमें रुकावट पड़े गई हो जैसे कि भागी आदिसे अथवा यदि किसी कारणसे वह तलबरी हुई दस्तावेज पेश करनेमें असमर्थ हो तो उसके विरुद्ध इस उपदफाके अनुसार वारण्ट नहीं जारी किया जाना चाहिये ।

उपदफा (३) के अनुसार अदालत उस प्रकारसे तलब किया हुआ व्यक्ति का बयान दिवालिये उसके व्यवहार तथा उसकी जायदादके सम्बन्धमें ले सकती है । इसी उपदफामें यह भी दिया हुआ है कि इस दफाके अनुसार तलब किया हुआ व्यक्ति अपनी पेशगीके लिये बचाल भी कर सकता है ।

उपदफा (४) में दिया हुआ है कि इस दफाके अनुसार तलब किये हुए व्यक्ति के बयानसे यदि यह माहूम होवे कि उस दिवालियेरी कर्म्मी चुकाना हे तो अदालत आफिशल एसायनीके दरखास्त देने पर उस व्यक्ति लिये यह हुक्म दे सकती है कि वह दिवालियेरी कर्म्म नियत किये हुए समय पर तथा नियत किये हुए दग पर आफिशल एसायनी को बुला दव । उस व्यक्तिसे पूरा कर्म्म या पूरे कर्म्मों अदायगीमें कुछ कम भी अदालतसे हुक्म अनुसार लिया जासकता है । उस व्यक्तिने तब प्रसार बयान लिये जानिक सम्बन्धमें जा खर्च हुआ है वह भा वसूल किया जासकता है ।

उपदफा (५) में यह मतलब गया है कि इस दफाके अनुसार तलब किये व्यक्ति के बयानसे यदि यह माहूम होवे कि उसके कर्म्ममें दिवालियेरी कोई जायदाद है तो आफिशल एसायनी की दरखास्त पर अदालत उस व्यक्ति के लिये यह हुक्म दे सकती है कि वह नियत किये हुए समयमें व नियत दग पर कुल या जुग जायदाद आफिशल एसायनी को दे देवे ।

उपदफा (६) में यह मतलब गया है कि उपदफा (३) व (५) के अनुसार दिये हुए हुक्मोंकी तात्काल उसी प्रकार कराई जावगी जैसे कि जायता दीवानीके अनुसार रुपयेकी अदायगीके सम्बन्धमें दी हुई डिका या जायदाद पर क्रमका लन वाजी डिक्रीकी इजाय करार जासकती है जायता दीवानीके आर्डर २१ में डिक्रीके इजाय करनेका वर्णन है और तब आर्डरके रूल ३० में रुपयेकी अदायगाक सम्बन्धमें दी हुई डिकाके इजायत उल्लेख किया गया है । और रूल ३१, ३५ व ३६ में जायदाद पर क्रमका देन वाली डिक्रीके इजाय करनेक नियम दिय हुए हैं ।

जायता दीवानी सन् १६०८ ई० का आर्डर २१ रूल ३० इस प्रकार है—

“ रुपयेकी अदायगीके सम्बन्धमें दी हुई डिकाके इजायमें यदि तब दीवानीकी जेलमें बन्द किया जासकता है अथवा उसकी जायदाद कुर्क व नीलम कराई जासकती है या दोनों प्रकार की कार्रवाई की जासकती है । वह डिका जिसमें कि कोई दूसरा दारदारी (Relief) दी हुई हो परन्तु साथ साथ यह भी दिया है कि उसके न करने पर रुपयेकी अदायगीकी जायदाद रुपयेका अदायगाक सम्बन्धमें दी हुई डिका समझा जावगा ”

जायता दीवानी सन् १६०८ ई० का आर्डर २१ रूल ३१ इस प्रकार है मनकूला जायदादके कर्म्मके सम्बन्धमें—

• (१) जन कि डिका किसी खास मनकूला जायदाद या उसके किसी हिस्सेके सम्बन्धमें होवे तो उसकी इजाय उस जायदाद या उसके उस हिस्से पर क्रमका लेने व उसका क्रमका उठा व्यक्ति को देने जिसने हुक्म डिक्री हावे या उसकी आसि

किसी अन्य व्यक्ति को देने में की जा सकती है या यदियूनियो दीवानी की जलमें बद करने या उसकी जायदाद कुर्क करने या दोनों प्रकारसे कार्यवाई करनेसे की जा सकती है ।

(२) जब कि कूल (१) के अनुसार कुर्क की हुई जायदाद ल याह तक कुर्क रही हो और यदियूनियो किसी की तापील न की हो तो डिफेंडरके नीलामके निये दरख्तास्त देने पर वह जायदाद नीलाम कर दी जावेगी और उस नीलामके रूपमें डिफेंडर को वतलाई हुई तादादके अनुसार या अदा तादाद न वतलाई गई हो तब उसके हर्जेके हिसाबसे जता अदायत वचित सम्पत्ति डिफेंडरको दिया सकता है और वकील कया दरखास्त देने पर यदियूनियो दिया जावेगा ।

(३) जब कि यदियूनियो किसी तापील करदी होवे और किसी इलायत नह मर्ब जो उसे अदा करता चाहिये या अदा कर दिया हो या जब कि ज महीने बीतने पर डिफेंडरके नीलामके निये दरख्तास्त न दी होवे या उसकी या हुई दरखास्त नामजूर करदी गई हो तो कुर्क समाप्त हो जावेगा ।

जायदादीवानी सन् १९०८ ई० का आर्डर २१ कूल ३५ इस प्रकार है गैर मनकूला जायदादके सम्बन्धमें—

“ (१) जब कि किसी किसी गैर मनकूला जायदाद पर कर्जा देनेके सम्बन्धमें होवे तो जिनके हकमें किसी है उसकी सम पर कर्जा दिलाया जावेगा या उसकी जायते निष्कृत करने हुए किसी अन्य व्यक्ति को कर्जा दिलाया जावेगा और यदि आवश्यकता होगी तो ऐसे व्यक्ति को हटा कर कर्जा दिलाया जावेगा जो डिफेंडरके लिये पावद हो वास्तु ब्रम्हा देनेसे इनकार करे ।

(२) जब कि किसी समुक्त कर्जेके सम्बन्धमें होवे तो ऐसा कर्जा जायदादके किसी आम जगह पर कर्जके वारंथ की नकल चिपकवा देनेसे तथा मुनादी का देने या अन्य किसी प्रचलित ठगरी कार्यवाई करनेसे दिल्वाया जावेगा ।

(३) जब कि किसी इलात या बंद जगहका कर्जा देना होवे और जिस व्यक्ति का उस पर कर्जा होवे और वह किसी की पाव दीके निये वाप्य होने पर तु आमानीमें अदर न पुखने देने को अदायत अपने अकसोंके लिये परधानशील औरतोंको जो आम लोगमें न निकलती होवें जितलनेवा मोरुा देने तथा कर्जा देने वाले व्यक्तिसे लखित आगारी देनेके बाद तादाद तुहवा कर या बिटखती तुहवा कर या बिटख तुहवा कर या अन्य किसी आवश्यक दगसे डिफेंडरको क ज दे सकती है ।

जायदादीवानी सन् १९०८ ई० का आर्डर २१ कूल ३६ इस प्रकार है—

“ जब कि किसी किसी गैर मनकूला जायदाद पर कर्जा देनेके लिये होवे और वह जायदाद डिफेंडरको कर्जेमें होवे या अन्य किसी व्यक्तिके कर्जमें होवे जो बहा रह सकता हो और वह हम किसीके अनुसार जगह खाली करनेके लिय वाप्य न होने तो ऐसा कर्जा अदालत जायदादकी किसी आम जगह पर कर्जके वारंथ चिपकवा कर या मुनादी कर्जेके अथवा अन्य किसी प्रचलित दगसे कर्जेकी घेतला करा देगी और उसमें जायदादके सम्बन्धमें दी हुई किसीका काफ़ी हवाला होगा । ”

अब ऊपर दिये हुए आर्डर २१ के कूल ३०, ३१, ३५ व ३६ की देखनेसे यह मालूम हो जावेगी कि इस दफा की उपदफा (४) व (५) के अनुसार दिये हुए हुकम भी इसी प्रकार तापील बताये जावेंगे ।

उपदफा (७) में यह दिया हुआ है कि दफाके हुकमके अनुसार यदि कोई काम किया जावेगा या अदायती की जावेगी अथवा कर्जा दिया जावेगा तो वह पर्याप्त समझा जावेगा और काम करने वाला व्यक्ति उस कामके सम्बन्धमें आपदा कर जिम्मेदारिसे बरी समझा जावेगा अथवा यदि उसने कर्जा चुका दिया है तो उससे दुबारा कर्जा नहीं सम्भव कर्या जासकिये या यदि उसने जायदाद पर कर्जा दे दिया है तो दुबारा कर्जा जायदाद पर नहीं माना जावेगा । मगरम हाईकोर्ट ने यह तय किया या कि इस दफाके अनुसार अदालत दिवालय तथा किसी लॉकर व्यक्तिके वाप्य होने वाले हक सम्बन्धी झगरी को तब नहीं छोड़ी, देखा—27 May 60 इस दफाके अनुसार कार्यवाई करनेके लिये अदायतमें जो दरखास्त

दी जाने वसमें सूक्ष्म तरीके यह दिला देना चाहिये कि तबन किये जाने वाले व्यक्तित्व पूरा जावेगा और उस घातमे दिवा-
लियेके व्यवहार या जायदादका क्या सम्बन्ध है, देखो—44 Cal. 374 इस दफ्तेके अनुसार दिवालियेके जो बयान किये
जावेंगे वह उसके विरुद्ध चलाये हुए कानूनीके मामलेमें उसके विरुद्ध प्रयोग किये जासकेंगे, देखो—46 Cal. 996

दफा ३७ कमीशन जारी करने के अधिकार

किसी व्यक्ति के बयान लेने के लिये कमीशन व प्रार्थना रूप में पत्र जारी करने के सम्बन्ध
में अदालत को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो १६०८ ई० के जायदादीयानी की दफा २६ के
अनुसार गवाहों के बयानों के सम्बन्ध में अदालत दीयानी को प्राप्त हैं ।

व्याख्या—

इस दफा के अनुसार अदालत दिवालिया गवाहों के बयान वसलिये कमीशन के करवा सकती है । कमीशन उसी प्रकार
जारी किये जासकेंगे जिस प्रकार जायदादीयानीके अनुसार जारी किये जासकते हैं । जायदादीयानी (१९०८) के आर्डर २६
में कमीशन जारी करने का हाल दिया हुआ है इस आर्डर के रूल १ से लेकर ८ तक गवाहोंके बयान के सम्बन्ध में जो कमीशन
जारी किये जासकते हैं उनका उल्लेख है इसके पश्चात् इसी आर्डर के रूल १५ से लेकर १८ तक कमीशन के अधिकारों आदि
का उल्लेख किया गया है ।

जायदादीयानी सन् १६०८ ई० का आर्डर २६ के उक्त रूल इस प्रकार हैं:—

रूल १—अदालत अपनी अधिकार सीमा के अन्दर सवागान दाखिल किये जाने पर अथवा बिना उसके कमीशन
उन गवाहों के बयान के लिये जारी कर सकती है जो इस एक्ट के अनुसार अप्रत्यक्ष में आने से बरी है या जो बीपी
अथवा कमजोरी के कारण अदालत में हाजिर होने से असमर्थ है ।

रूल २—अदालत स्वयं ही अथवा किसी फ्रीक की या खुद गवाह की दखलाने आने पर जितकी ताईद में
हलकनामा दाखिल किया गया हो या जो यों ही दी गई हो कमीशन जारी करने का हुक्म दे सकती है ।

रूल ३—यदि कमीशन किसी ऐसे गवाह के बयान के लिये जारी किया गया हो जो अदालतकी अधिकार सीमा के
अन्दर रहता है तो वह कमीशन किसी भी ऐसे व्यक्ति को दिया जा सकता है जो अदालत की रायमें उसके लिये उपयुक्त होवे ।

रूल ४—(१) कोई भी अदालत किसी भी मामलेमें निम्न लिखित लोगों के बयान के लिये कमीशन जारी कर
सकती है:—

(ए) कोई भी व्यक्ति जो अदालत की अधिकार सीमा के बाहर रहता हो ।

(बी) कोई भी व्यक्ति जो अदालत की अधिकार सीमा की उस तारीख से पहिले छोड़ना चाहता हो जिस तारीख
पर उसका बयान देने की है । और

(सी) किसी भी सरकारी सिविल या मिलिटरी अफसर के लिये जो अदालत की राय में बिना अपने सरकारी काम
को उल्लंघन पहुँचाये हाजिर न हो सकता हो ।

(२) इस प्रकार के कमीशन हाईकोर्ट के अतिरिक्त किसी ऐसी अदालत के नाम जारी किये जा सकते हैं जिसकी
अधिकार सीमा में गवाह रहता होवे अथवा किसी वकील या ऐसे व्यक्तिके नाम जारी किये जा सकते हैं जिसे कमीशन जारी
करने वाली अदालत नियुक्त कर देवे ।

(३) कमीशन जारी करनेवाली अदालत यह भी हुक्म दे देवेगी कि आया कमीशन उसी अदालतमें लौटाया जावेगा
या उसकी मानदत किसी अदालत में ।

कल ५—यदि कमीशन जाये करनेवाली अदालत से किसी ऐसे व्यक्ति के बयान के लिये कमीशन जारी कराया जावे जो बुराई इच्छा से बाहर रहता हो और उसका यह विश्वास दिया दिया जावे कि उस व्यक्ति की शहादत सच है तो अदालत कमीशन या प्रार्थना पत्र (Letter of request) जारी कर सकती है ।

कल ६—जिस अदालत के पास किसी व्यक्ति के बयान के लिये कमीशन भेजा जावेगा वह अदालत उस व्यक्ति का बयान लेवेगी या उमक अनुसार बयान लिये जाने का प्रबंध करेगी ।

कल ७—जब कि कमीशन नाकाम्यदे पूरा कर दिया गया हो तो वह वापिस भेज दिया जावेगा और उसके साथ में उसके अनुसार ली हुई शहादत भी कमीशन जारी करनेवाली अदालत की भेज दी जावेगी यदि उसके विरुद्ध कमीशन के साथ में कोई आज्ञा न दे दी गई हो और अगर ऐसा हुआ हो तो उन शर्तों के अनुसार भेजा जावेगा जो लगा दी गई हैं और आगे दी हुई कल का ध्यान रखते हुए कमीशन उसको दीया जाना तथा उसके अनुसार ली हुई शहादत मुकदमों में मिसिल में सम्मिलित समझा जावेगा ।

कल ८—कमीशनमें लिये हुए बयान उस वक्त तक सूचनमें बनौर शहादत के नहीं पढ़े जायेंगे जब तक कि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध वह पढ़े जानेवाले हैं अपनी सहमत न देवे परन्तु इसकी आवश्यकता निम्न लिखित मामलों में नहीं रहेगी—

(ए) यदि बयान देने वाला गवाह अदालत की अधिकार सीमा से बाहर रहता है या मर गया है या बीमारी अथवा कमजोरी की वजह से अदालतमें आनेसे असमर्थ है या वह ऐसा सरकारी सिविल या मिलिटरी अफसर है जो बिना अपने सरकारी कामों मुकसान पहुँचाये हुए शक्ति नष्ट हो सकता है, या

(बी) यदि अदालत आज (ए) में बतलाई हुई किसी बातके पाने जानेका हुक्म दे देवे तथा इस बातका हुक्म दे देवे कि कोई शहादत सूचनमें पढ़ी जावेगी बिना इस बातका लिहान लिये हुए कि बयानोंके पढ़ जाते समय वह बात जानी रही है जो बयानोंके लिये जाते समय उपस्थित थी ।

कल १५—किसी कमीशनके जारी करनेसे पाहिले यदि अदालत चाहे तो उसके खर्चके लिये कमीशन जारी करने वाले फीकसे कतिन खर्चके लिये रुपये दाखिल कर सकती है यह कपया नियम लिये हुए समयके अन्दर अदालतमें दाखिल कराया जा सकता है ।

कल १६—इस आर्डरके अनुसार नियुक्त किया हुआ कमिश्नर यदि नियत करने समय दिये हुए हुक्मके साथ कोई बात इसके विरुद्ध न लिखे हो गई हो तो निम्न लिखित काम कर सकता है—

(ए) कमीशनके बयान ले सकता है और किसी ऐसे गवाहके बयान भी ले सकता है जिसके वह खेद या उनमेंसे कोई पेश करे और वह किसी ऐसे अन्य व्यक्ति का बयान भी ले सकता है जो उसकी रायमें उस मामलेके सम्बन्धमें अपने बयान दे सकता हो ।

(बी) तहकीकातके लिये जो दस्तावेज आवश्यक हों उनको तलब कर सकता है व उनका मुजायना कर सकता है ।

(सी) हुक्ममें जिस जमीनका बडेल हो वहां किसी उपयुक्त समय पर जा सकता है ।

कल १७—(१) इस एक्टमें गवाहोंकी तलबी इजिजी व बयानोंके सम्बन्धमें जो नियम दिये हुए हैं और उनके लिये जो सूरत व खर्च और जो दण्ड बतलाये गये हैं वह सब बातें उन लोगोंके लिये भी लागू होंगी जिनकी शहादत कमिश्नर लिया चाहे या जिनसे दस्तावेज तलब कराया चाहे । यह सब बातें उन सब कमीशनोंके लिये लागू होंगी जो चाहे इजिजी इजिजी अदालतसे या उसके बाहर की किसी अदालतसे जाते किने गये हो इस कलमें लिये कमिश्नर की अदालत दीवानी मान लिया जावेगा ।

(२) कमिश्नर, इंडिफरेंट के अतिरिक्त अन्य किसी अदायगी के मिसकी अधिकार सीमा में गवाह रहता है। गवाह के लिये सम्मन जारी करा सकता है। उसके जारी करने की उस आवश्यकता प्रतीत होने और वह अदालत अपनी इच्छा के अनुसार जमा उसे वापिस व ठीक प्रतीत होगा वैसा इसलानामा जारी करेगी।

कूल १८—(१) जब कि इस आर्डर के अनुसार कमीशन जारी किया गया हो तो अदालत यह हुक्म दे देवेगी कि फर्तिन रख या अपन एजेंट या कर्मीन्स जारिये कमिश्नर के सामने हाजिर होंगे।

(२) जब कि फर्तकैन्मेंसे सब या कोई इस प्रकार कमिश्नर के सामने हाजिर न होवे तो कमिश्नर उनकी नामानुरूपी में कार्रवाई कर सकता है।

कमिश्नर की विमुक्त आदिने सम्बन्धों कायता श्रानार्ने के जिन नियमों का ऊपर उद्धृत किया गया है वही नियम इस एक्ट के अनुसार नियत निये जान वाले कमिश्नर व कमीशन के सम्बन्धों ल्याए समझना चाहिये। इस दफ्ते यह भली भांति प्रष्ट है कि अदालत दिवालिया दफ्ता ३६ के अनुसार किसी गवाह का बयान लेने के लिये कमीशन भी जारी कर सकती है।

दिवालियेका बहाल किया जाना

दफा ३८ दिवालियेका बहाल किया जाना

(१) दिवालिया करार दिया जानेका हुक्म होनेके पश्चात् किसी समय भी दिवालिया अदालत में अपने बहाल होनेके लिये दरखास्त दे सकता है और अदालत ऐसी दरखास्त के सुने जानेके लिये कोई तरीका नियत करेगी। परन्तु यदि इस एक्ट के नियमों के अनुसार उसका आम बयान छोड़ दिया गया हो तो वह दरखास्त उस समय तक नहीं सुनी जावेगी जब तक कि वह बयान न हो जावे दरखास्त खुली अदालत में सुनी जावेगी।

(२) इस दरखास्त को सुनते समय अदालत आफिशल एसायनी की रिपोर्ट जो उसने दिवालियेके व्यवहार तथा उसके मामलेके सम्बन्ध में दी होवे ध्यान में रखेगी और दफा ३६ के नियमों का ध्यान रखते हुए—

(ए) पूर्ण रूपसे बहाल किये जानेका हुक्म दे सकती है या उसके देनेसे इनकार कर सकती है या

(बी) बहाल किये जाने वाले हुक्म का प्रयोग निर्धारित समय के लिये रोक सकती है, या

(सी) बहाल होनेका हुक्म उन शर्तों के साथ दे सकती है जो उसकी आयन्दा होने वाली आयन्दगी या जुनाफा के सम्बन्ध में होवे या उसको आयन्दा मिलने वाली जायदाद के सम्बन्ध में होवे।

व्याख्या—

इस दफा में दिवालियेके बहाल किये जानेका वर्णन है। उपदफा (१) के अनुसार दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म हो जानेके पश्चात् किसी समय भी दिवालिया बहाल किये जानेकी दरखास्त दे सकता है और ऐसी दरखास्त के जाने पर अदालत यह कर्तव्य होगा कि वह उसका सुनने के लिये कोई दिन नियत कर देवे जैसा कि अमेची एक्ट की इस उपदफा में प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रष्ट है। परन्तु साथ ही साथ इस उपदफा में यह भी बतला दिया गया है कि यदि

दिवालियाका आम बयान किता बजहमे नहीं लिया गया हो तो जब तक उत्तर आम बयान न हो जावे तब तक उत्तरी दर-
ख्वास्त नहीं सुनी जावेगी । बहाल किये जानेका दरख्वास्त सुनी अदालतमें सुनी जावेगी अर्थात् उत्तरी समान कमरे (Cham-
ber) में नहीं ही जासकती है जेसा कि अंग्रेजी एक्टमें ॥ सम्बन्धमें प्रयोग मिले हुए (Shall) शब्दमें भासित होता है ।

उपदफा (२) में बतलाया गया है कि बहालकी दरखास्त पर विचार करते समय अदालत अफिशल एसायनीकी
रिपोर्ट जो उत्तरी दिवालियेके व्यवहार व मामलेके सम्बन्धमें दी हो देखेगी और दफा २९ क नियमोंका ध्यान रखते हुए तीन
मन्त्रके हुक्म जो प्राज (ए), (बी) व (सी) में दिये गये हैं दे सकती है ।

बहाल (ए) के अनुसार पूर्ण रूपसे बहाल किये जानेका हुक्म दे सकती है अथवा उसके देनेसे इनकार कर सकती है ।

बहाल (बी) के अनुसार बहालके हुक्म विनियमित किये हुए समयके लिये सुलतवी कर सकती है ।

बहाल (सी) के अनुसार बहालका हुक्म आपदा होने वाली आपदनी या जाने वाली जपानदके सम्बन्धमें दे सकती है ।

यदि दिवालिया किर्मा कर्ज-बाहके कर्जोंका फैसला इस शर्तके साथ कर केने कि वह उसकी दिवालियेकी दरवारका
विरोध नहीं करेगा तो इस प्रकार किया हुआ इकरारनामा यह समझा जावेगा क्योंकि यह अथ कर्जबन्दाको बाधता देते हुए
तथा कानून दिवालियाके मन्तव्यके विरुद्ध है, देखो—20. Bom. 636.

**दफा ३९ वह मामले जिनमें पूर्ण रूपसे बहाल किये जाने वाले हुक्म देनेसे
इनकार कर देना चाहिये**

(१) यदि दिवालियेमें इस एक्टमें बतलाया हुआ कोई जुर्म किया हो या लाजीमान हिन्दू
की दफा ४११ से ४२४ तकका कोई जुर्म किया हो तो अदालत ऐसे सब मामलोंमें बहाल (Dis-
charge) करनेसे इनकार कर देगी और आगे दिये हुए किसी बातके साबित होने पर, या

(ए) बहाल करनेसे इनकार कर देगी, या

(बी) किसी नियत किये हुए समय तकके लिये बहाल रोक देवेगी, या

(सी) बहालके हुक्मको उस वक्त तकके लिये रोक देवेगी जब तक कि कर्जप्राप्तियोंको
रूपमें चार आने अर्थात् कर दिये जावे, या

(डी) दिवालियेके बहाल करनेमें यह शर्त लगा देवेगी कि उसके विरुद्ध उस मतालियेके
लिये अफिशल एसायनीके दफ्तरमें डिफ्री कर दी जावे जो उस वक्त साबित किये
जाने योग्य कर्जोंके सम्बन्धमें देना बाकी निकलता होवे । और वह बचा हुआ कर्जा
या उसका कोई हिस्सा दिवालियेकी आयन्दा होने वाली आमदनी या उस आयन्दा
प्राप्त होने वाली आयदादसे उस प्रकार व उन शर्तोंके साथ चुकाया जावेगा जो
अदालत मुनासिब समझे । परन्तु ऐसे मामलोंमें डिफ्री बिना अदालतकी आज्ञाके
इकरार नहीं की जावेगी और अदालत की ऐसी आज्ञा उस वक्त प्राप्त हो सकती
जब कि यह साबित होजावे कि बहालके बाद दिवालियेको कोई आयदाद मिली है
या आमदनी हुई है जिससे उसके कर्ज चुकाये जासकते हैं ।

(२) उपदफा (१) में आगे आने वाली जिन बातोंका हवाला दिया है वह यह हैं—

- (५) यह कि दिवालिपेके लहनेकी कीमत उतनी नहीं है जिससे कि उसके पिला महकूत कर्जोंका एक रुपयेमें चार आना न चुकाया जासके अथवा कि वह अदायतको इस बातका विश्वास न दिला ऐसे कि उसके लहनेकी कीमत ऐसी घजहोंसे कम है जिनके लिये यह उचित रूपसे किसी प्रकार ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जासकता है।
- (६) यह कि दिवालिपे उस प्रकारके देसायकी कितायें नहीं रखता रहा है जैसी कि उसके व्यापारके लिये रचना आपश्यक है और जैसा कि रहने जानेका चलन है और जिनसे कि उसके दिवालिपे होनेसे पहिले तीन सालके बीचके व्यापारिक सौदे या माली दास्तत जानी जासके।
- (७) यह कि दिवालिपे अपनेको दिवालिपे जानते हुए भी व्यापार करता रहा है।
- (८) यह कि दिवालिपेने इस एकदके अनुसार साबित किया जानें योग्य कोई सौदा यह जानते हुए किया हो कि उसे उस सौदेके अदायगी की सम्भावना, सौदा करते समय नहीं थी। इस बातका भार सुबूत दिवालिपे पर होगा कि वह सौदा करते समय उसकी अदायगी की उम्मेद रखा था।
- (९) यह कि दिवालिपे अपने लहनेकी कमी या उसका नुकसान सन्तोषजनक रूपसे नहीं समझ सकता है।
- (१०) यह कि दिवालिपेने अपने देतहाया व खतरनाक सट्टेके खोपों को करनेकी घजहसे अथवा रहन सहनमें अनुचित ध्यय करनेकी घजहसे या जुपकी घजहसे या अपने व्यापारके भारोंको जानबूझ करन देखनेकी घजहसे अपनेको दिवालिपे बना लिया है।
- (११) यह कि दिवालिपेने अपने किसी कर्जबहाहका बंजा खर्च किसी ऐसे मामलेके सम्बन्धमें कर दिया है जो उसने सही तरीकेसे उसके विरुद्ध दायर किया हो और जिसमें कि उस दिवालिपेने कर्जबहाह को परेशान करनेके लिये बंजा तौरसे जवाबदेही की हो।
- (१२) यह कि दिवालिपे की दरपयास्त दाखिल किये जानेसे पहिले तीन माहके अन्दर दिवालिपेने किसी बंजा व परेशान करने वाले मामलेको खला कर अनुचित ध्यय किया होव।
- (१३) यह कि दिवालिपेने दरपयास्त दाखिल किये जानेसे पहिले तीन माहके अन्दर जब कि वह अपने कर्जोंको मश करनेमें असमर्थ था अपने किसी कर्जबहाह को बंजा तरीके पर तर्जिह दी है।
- (१४) यह कि दिवालिपेने अपनी हिसाब की किताबों या जायदाद को या उसके किसी हिस्से को दिया दिया है या हटा दिया है अथवा वह अन्य किसी धोखादेहीका या धोखादेहीसे किये हुए अमानतमें दयानत का दोषी हुआ है।
- (१५) यहालके हुक्म को मुअतिल करने (Suspend) या उसमें शर्तोंके लगानेके अधिकार एक साथ प्रयोग किये जासकते हैं।

(४) बहाल की दरमवास्तके लिये आफिशल एसायनी की रिपोर्ट आहिरा सौर पर सुपूत होवणी और अदालत उस रिपोर्टमें की हुई बातों को सच्चा मान सकती है ।

ब्याख्या—

इस दफामें उन सब बातोंका उल्लेख है जिनके अनुसार अदालत पूरी रूपसे बहाल करनेसे इनकार कर देगी व साथ ही साथ वह भी अवसरयें बतलावे गई हैं जिनके होने पर शकसे साथ बहालका हुक्म दिया जासकता है ।

उपदफा (१) में यह बतलाया गया है कि यदि दिशालिखे इस एक्टमें बतलाये हुए किसी अपराधको किया हो जगता ताकीरत हिन्दी दफा ४२१, ४२२, ४२३ वा ४२४ के अनुसार अपराध किया हो तो अगन्तका कर्तव्य होगा कि वह बहालका हुक्म देनेसे इनकार कर देवे । अंग्रेजी एक्टकी इस उपदफामें (Shall) शब्दका प्रयोग किया गया है जिससे यह प्रकट है कि इस उपदफामें बतलाये हुए नियमोंकी अवहेलना नहीं कीजाना चाहिये । इस एक्टके अनुसार किये जाने वाले अपराधोंका उल्लेख दफा १०३ में किया गया है जिसके अनुसार अपने मायकेकी असली हालतकी छिपानेसे अपना किसी कर्तव्य छिपाने या घोसोदा तौरसे कुछ देने पर या अपनी जगदाद हटा देने या उन पर किसी प्रकारका भार पैदा कर देनेसे दिशालिख अपराधी कथार दिया जासकता है । तामीरत हिन्दी दफा ४२१ से लेकर ४२४ तकमें भी जोखेते लिखी हुई दस्तावेजों व जगदादके सम्बन्धमें दिये हुए शीर्षोंका उल्लेख है ।

ताजीगत हिन्दू एक्ट नं० ४५ सन् १८६० ई० की दफा ४२१ इस प्रकार है—

दफा ४२१—“यदि कोई व्यक्ति बेईमानीसे या घोसादेहीसे किसी जगदादका हटा देवे, छिपा देवे या दूसरे व्यक्ति को दे देवे या किसी शकसे इकट्ठा इतकाक कर देवे या इसकाक बग देवे और उसके लिये कर्षाप्त मुआविका न लेवे तथा इस मसाले ऐसा काम करे कि जिसमें उसकी जगदाद कानूनके अनुसार उसके कर्तव्यदानमें भादी न जासके या वह किसी अन्य व्यक्ति के कर्तव्यदानमें न भावे जासके तो उस व्यक्ति को दो साल तकके कारावासका सजा या कठोर दण्ड अथवा जमीनेका दण्ड या दोनों प्रकारके दण्ड एक साथ दिये जासकेंगे”

दफा ४२२—“यदि कोई व्यक्ति बेईमानीसे अपना घोसादेहीसे अपना या किसी अन्य व्यक्ति का कर्षाप्त मुआविका लेके कि जिसमें वह कानूनके अनुसार उसके कर्षाप्त या उन दूसरे व्यक्ति के कर्षाप्त की अदायगीमें न दिया जासके तो उस व्यक्ति को दोनों प्रकारके दण्ड यानी कारावासका दण्ड दो साल तकके लिये दिया जासकेगा या उस पर जमीनेका दण्ड या दोनों प्रकारके दण्ड दिये जासकेंगे ।”

दफा ४२३—“यदि कोई व्यक्ति बेईमानीसे अपना घोसादेहीसे किसी ऐसी दस्तावेज या कागज पर दस्तखत करे जो छिपे या उसके लिखने जानेमें भ्रम लेवे जिसके अन्वये कोई जगदादका इतकाक किया जाना होता होवे या उस जगदाद पर भार पैदा होता होवे या उस जगदादका कोई एक उसमें जाता हो और उसमें मुआविकेका राजत बयान लिखा गया हो या जिस व्यक्ति के इकट्ठे या जिसके शायदेके लिख वह लिखा गया हो, या वह कुछ लिखा हो तो वह व्यक्ति दो साल तककी दोनों प्रकारकी सजा या जुर्माने की सजा या यह दोनों सजायें साथ साथ पावेगा”

दफा ४२४—“यदि कोई व्यक्ति बेईमानीसे अपना घोसादेहीसे अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की जगदादको छिपा दे या हटा दे या उसके छिपाने अथवा हटानेमें मदद देवे या बेईमानीसे अपने किसी इकट्ठे या भागको छोड़ दे जिसका वह मुआविके है तो उस व्यक्ति को दो साल तकके सजा या कठोर कारावास या जुर्माने का सजा या दोनों प्रकारके सजायें दी जावेंगी”

उपदफा (२) में कुछ शर्तोंका वर्णन है और उनके सामने होने पर अदालत उपदफा (१) के शर्त (१), (२), (३) व (४) के अनुसार हुक्म देवेगी ।

उपदफा (१) फलाज (ए) के अनुसार बहाल होनेवा हुकम देनेसे अदालत इनकार कर सकती है ।

फलाज (बी) के अनुसार नियत समयके लिये बहालक हुकम मुलतबी कर सकती है और उसी हुकममें यह भी दिया जासकता है कि नियत की हुई तारीखसे दिवालिवा बहाल होनेवा इस प्रकारके नियमका यह अर्थ उपपन्न चाहिये कि नियत की हुई तारीखसे बहालके हुकमका प्रभाव आरम्भ होगा, देता—44 Bom. 555.

फलाज (सी) के अनुसार बहाल किये जाने वाले हुकमको उस समय तकके लिये मुलतबी किया जासकता है जब तक कि बर्चस्वाहोंको अपने कर्ममें वपयेमें पार आना न मिल चुके ।

फलाज (डी) के अनुसार दिवालिवाके ऊपर बहाल किये जानेवा हुकम होनेके साथ साथ बर्चस्वा मतालिबके लिये निर्देशी जासकती है यह डिकी आफिशल एसायनीके हुकमों की जानेगी और उसका मतलिबा दिवालिवाके आय या होने वाली आयदानी या मिलने वाली आयदानीसे उन शर्तोंके अनुसार वसूल किया जासकेगा जो अदालत लगा देना मुनासिब समझे । इस क़ाज़में यह भी दिया हुआ है कि इस प्रकार दी हुई डिकी विरुद्ध अदालत की आज्ञाके आगे नहीं चलाई जावेगी और अदालत इस प्रकारकी डिकीके इनकार किये जानेके लिये उसी वक्त आज्ञा देवेगी जब उसको यह साबित हो जावे कि दिवालिवाके बहाल होनेके बाद जारी आयदाद पाई है या उसको काफी आयदानी हुई है जिससे कि उसके कर्ज चुकाये जासकते हैं ।

उपदफा (२) इस क़ाज़में विभक्त है इस उपदफाके क़ाज (ए) के अनुसार यदि बिला मज्जुज वज्रें वपयेमें आए और न चुकाये जासके तो अदालत उपदफा (१) के अनुसार हुकम दे सकती है जब तक कि उसको समीपजनक रूपसे यह साबित न हो जावे कि दिवालिवा का दयाको ऐसे कारणोंसे पहुँचा था जिस पर उसका कोई बस नहीं था अर्थात् जिसके लिये वह जिम्मेदार नहीं ठहराया जासकता हो ।

फलाज (बी) के अनुसार यदि दिवालिवा अपने व्यापारके सम्बन्धमें प्रचलित हिदायती कितानें न रखती रहा हो जिससे कि उसके सौदाग पता न पानी शक्य दिवालिवा होनेसे तीन साल पूर्व तककी जानी जासके तो भी अदालत उपदफा (१) के अनुसार हुकम दे सकती है । इस क़ाज़में यह भली भाँति स्पष्ट है कि केवल हिदायती कितानोंका रखनाही पर्याप्त नहीं है किन्तु उनसे दिवालिवाके व्यापार व धन सम्बन्धी शक्य भी साधन होना चाहिये । हिदायती कितानें उस प्रकारकी होना चाहिये जैसी कि बाजारके चलनके मुवाफ़िक उस प्रकारका व्यापार करने वाले रखते हैं जिस प्रकारका व्यापार दिवालिवा करता रहा हो और उन कितानोंसे दिवालिवाके व्यापारका पता दिवालिवा होनेसे पहिले तीन साल तरका साधन किया जासके ।

फलाज (सी) में यह बतलाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनेको दिवालिवा जानते हुए व्यापार करता रहा हो तो वह व्यक्ति भी उपदफा (१) के अनुसार हुकम पानेवा अधिकारी है ।

फलाज (डी) में यह दिया हुआ है कि यदि दिवालिवाके कोई कर्ज यह जानते हुए लिया हो कि उसके पास उस कर्जकी चुकानेवा कोई साधन नहीं है और वह कर्ज इस एवज्जे अनुसार साबित किया जासकता हो तो ऐसी बातके साबित होने पर भी अदालत उपदफा (१) के क़ाज़के अनुसार हुकम दे सकती है ।

फलाज (ई) में यह बतलाया गया है कि यदि दिवालिवा समीपजनक रूपसे यह न साबित कर सके कि उसका अक्षर उसके कर्जोंको चुकानेके लिये पर्याप्त क्यों नहीं है या उसके अक्षरमें कमी क्यों हो गई है तो अदालत उपदफा (१) के क़ाज़के अनुसार हुकम दे सकती है ।

फलाज (फर) के अनुसार यदि यह साबित हो जावे कि अनुबिन खर्च करने या सेवा सहेवाधीसे दिवालिवाके जानी यह

हालत कर ली है या जुर्माने अपना व्यापारिक ढीक तौल न देखने के कारण अपना कारबार विगड़ दिया है तो अदालत उपदफा (१) के शर्तोंके अनुसार हुकम देवेगी ।

फलाज (जी) के अनुसार दिवालिया यदि किसी कर्षेस्वाद्वय नेवा खर्च घुड़ी व नेवा जवाबदेहीके कारण किसी मुकदमेमें फा देव जा सहा तबसे उसका लवइ चाद किया गया हा तो भी अदालत उपदफा (१) के अनुसार हुकम दे सकता है ।

फलाज (एच) के अनुसार यदि दिवालियेने दिवालियेका हालत होनेसे पहिले तान माहक अदर बेना मुकदमे शर्ममें खर्च दिया हो तो भी अदालत उपदफा (१) का प्रयोग कर सकती है ।

फलाज (आई) के अनुसार यदि दिवालियेकी दरखास्त सुननेसे पहिले तीन माहक अन्दर दिवालियेन किसी बर्जनाहको घोखान्दहीसे तर्फीह (Preference) दी हो तो अदालत उपदफा (१) के अनुसार बरवाई कर सकती है । घोखान्दहीसे तर्फीह देनेका उल्लेख दफा ५५ में किया गया है ।

फलाज (जे) के अनुसार यदि दिवालियेने अपना इलाक बी कित्तों को हयय हो या खिया दिया हो अथवा उसने अपनी आपदाद व उसका बहरे हिस्सा लपटाया या हटाया हो अथवा उसने कोई भारता दिया हो या भारीसे अमा मतमें खयानत किया हा हा वह उपदफा (१) के अनुसार ही हुकम पानेध अधिकायी होगा ।

उपदफा (२) के अनुसार सुलतना का हुकम तथा शर्तों का रकामा जाना एक साथ किया जासकता है ।

उपदफा (४) में यह बतलाया गया है कि आक्शित एसायनी का रिपॉन् आदर तत पर सुपूत मानी जावेगी और अदालत उसको बिलकुल दाक मान सकती है ।

दफा ४० बहालकी दरखास्तका सुना जाना

अदालत द्वारा बहाल की दरखास्त सुनने जानेका नोटिस निधारित रूपसे प्रकाशित किया जायेगा और उसकी खूबना निश्चित कीहुइ तारीखसे कमसे कम एक माहके पहिले उन कर्जखानोंक पास भेजी जायेगी जो अपना कर्जा साधित कर चुके हैं और अदालत आक्शित एसायनी तथा कर्जखानों की बी यातें सुनेगी । सुनने वाली तारीख पर अदालत दिवालियेसे वह प्रश्न पूछगी और वह गहादत लेवगी जो उसे उचित समझ पड़े ।

ध्याख्या—

इस दफामें यह बतलाया गया है कि बहाल होने की दरखास्त सुने जानेके लिये जो तारीख नियत की जाये उसकी सुनारी सुनहुए निर्धारित किये हुए दिन पर की जायगा । इस मुकदमी की अवहलना नहीं कीजासकती है जैसा कि अंग्रेजी मुकदमें प्रथाग ग्रेगे हुइ (Shall) शब्दस मान्य हाता है । कर्जा साधित कर देने वाले कर्जखानोंको भी उनकी सुचना नियत की हुई तारीखसे कमसे कम एक माह पहिले दा जना आवश्यक है । बहाल की दरखास्त सुनत समय अदालत आक्शित एसायनी व किसी बर्जनाहकी जवाबदेही को भा सुन सकती है । अदालत दिवालियेसे ऐसे सवालनाद पूछ सकती है व उनके जवाब ले सकती है जिन उस सुनाधिन समझ पड़े ।

दफा ४१ बहाल होनेकी दरखास्त न देने पर दिवालिया करार देने वाले हुकमकी मंजूरी

यदि बहाल की दरखास्त सुननेके लिये नियत किये हुए दिन पर दिवालिया हाजिर न होवे अथवा दिवालिया निर्धारित किये हुए समयक अन्दर बहाल की दरखास्त न दये तो अदालत

रात अकिशाल पसायनी या किसी कर्जस्थान की दरखास्त पर या स्वयं ही विधालिया करार दिये जाने वाले हुक्मको मंजूर कर सकती है या और कोई हुक्म जो उसे मुनासिब मालूम हो वे सकती है और इस प्रकारकी मंजूरी होने पर दफा २३ में बतलाये हुए नियम लागू होंगे ।

व्याख्या—

यदि दिवाणिया बहाल होने का दरखास्त छठे अनेके दिन हाजिर न होवे या अदालत द्वारा नियत किये हुए समयके बाद बहाल की दरखास्त न देवे तो अदालत की अधिभार है कि वह दिवाणिया बहाल दिये जाने वाले हुक्मकी मंजूरी न देवे । इस प्रकारके मंजूरी का हुक्म अदालत स्वयं दे सकती है अथवा अकिशाल पसायनी या किसी कर्जस्थान की दरखास्त आने पर दे सकती है । यह भी बतलाया गया है कि इस दफाके अनुसार मंजूरीके हुक्म पर दफा २३ के नियम लागू होंगे अर्थात् दफा २३ में बतलाये हुए सौदे आदि का इस हुक्मसे पहिले किये गये हों बदस्तूर बने रहेंगे व दिवाणिये की जायदाद बसे या अन्य किसी व्यक्ति को अदालत की आज्ञाके अनुसार मिल जावेगी । दिवाणिया यदि जेलसे केजा गया हो तो वहां भेज दिया जायके व मंजूरीके हुक्मकी इच्छाही की जावेगी । दफा २३ को देखनेसे यह सब बातें भली भण्डि समझमें आसकती है ।

दफा ४२ बहाल होनेकी दरखास्तका दुबारा दिया जाना

(१) जब कि अदालत बहाल किये जाने की दरखास्त नामंजूर कर देवे तो उसको अधिकार है कि वह नियत किये हुए समयके भीत जाने पर तथा उन बातोंके उपस्थित होने पर जो निर्धारित कर दी गई हों विधालिये को फिरसे अपनी दरखास्त देने का अधिकार दे देवे ।

(२) जब कि बहाल किया जानेका हुक्म किसी शर्तोंके साथमें दिया गया हो तो उसके हुक्मके पश्चात् दो साल भीत जानेके बाद किसी समय भी विधालिया अदालतको उस बात का विद्वान दिला देवे कि कोई उचित सम्मथना इस बात की नहीं है कि अदालत द्वारा लगाई हुई शर्तों की पूर्ति की जासकेगी तो अदालत अपने हुक्म की शर्तोंमें संशोधन कर सकती है अथवा धाड़में दिये हुए हुक्म का संशोधन कर सकती है और यह संशोधन उस प्रकार व उन शर्तोंके साथ किये जावेंगे जो उसे उचित प्रतीत होवें ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार बहाल होने की दरखास्त एक बार खारिज किये जाने पर भी दुबारा दी जासकती है यद्यपि दुबारा दरखास्त अदालत द्वारा निर्धारित किये हुए समयके बाद तथा उसके द्वारा बतलाई हुई शर्तोंके उपस्थित होने पर नहीं दी जासकेगी यदि अदालतने ऐसे समय या शर्तोंके लिये कोई हुक्म दिया होवे । और अदालत की आज्ञा देने पर यह दुबारा दी जाने वाली दरखास्त दी जासकती है ।

उपदफा (२) में यह बतलाया गया है कि यदि किसी शर्तोंके अनुसार दिवाणिया बहाल किया गया हो तो उसके पश्चात् दो साल बीतने पर दिवाणिया अदालतको यह विद्वान दिला सकना है कि अब आयन्दा कोई सम्मथना नहीं है कि वह लगाई हुई शर्तोंकी तामील कर सके इसलिये उन शर्तोंसे या तो हट्य देना चाहिये या उनमें उचित परिवर्तन कर देना चाहिये । अदालत ऐसा विद्वान होने पर या तो शर्तोंकी हट्य सकती है या उनमें उचित परिवर्तन करके अपना दूसरा हुक्म दे सकती है । अदालत इस दफाके अनुसार कार्य करनेके लिये बाध्य नहीं है जैसा कि अबकी प्रथममें प्रयोग किये हुए (MAY) करते मालूम होजा है ।

दफा ४३, बहाल किये हुए विधालियेका जायदाद वसूल करानेके सम्बन्धमें कर्तव्य

बहाल किया हुआ विधालिया, बहाल हो जाने पर भी आफिशल एसायनी द्वारा चाही हुई मददको अपने उस लहने व जायदादके वसूल करने तथा उसके बांटनेमें जरूर देवेगा जो आफिशल एसायनी की सुपुर्गामीमें भागई हो और यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो वह अदालत की सौदीन करने का दोषी होगा और यदि अदालत उचित समझे तो उसके बहाल किये जानेके हुक्म को भी मंजूर कर सकती है परन्तु इस प्रकार मंजूरीके हुक्मसे पहिले तथा बहाल होनेके पश्चात् जो धननामे, इन्तकालात या अदायगी बाकायदा की गई हों या जो काम किये गये हों उन पर इस मंजूरीके हुक्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अर्थात् वह जैसेके तैसे बने रहेंगे ।

व्याख्या—

विधालिया बहाल किये जानेके बाद भी आफिशल एसायनीको अपनी जायदादके वसूल किये जाने तथा उसे कर्म-बन्धनोंमें बाँटे जानेमें मदद देवेगा । अंग्रेजी एक्टकी III दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे यह प्रकट है कि विधालिया इस दफाके नियमकी अवहेलना नहीं कर सकता व इसो दफामें यह भी बतला दिया गया है कि यदि वह उसकी अवहेलना करेगा तो दोषी निर्धारित किया जाकर दण्ड्य अधिकारी होगा । इस प्रकारका दोष अदालतकी सौदीन करना समझा जावेगा और उसके अनुसार विधालिया दण्ड पासकता है । इनकाही नहीं है किन्तु बहाल होनेका हुक्म भी मंजूर किया जा सकता है परन्तु इस प्रकारका मंजूरामें पहिले तथा बहाल किये जानेके बाद या सौदे आदि किये गये हों वह सब बदस्तूर बने रहेंगे । मंजूरीका हुक्म देना न देना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है जैसा कि अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है ।

दफा ४४ धोखेदिहीसे किये हुए सौदे

(१) यदि कोई जायदाद विवाहसे पहिले विवाहके एवजमें लिख दी जावे और लिखते समय लिखने वाला पिला इस जायदादको भी शामिल किये हुए अपने सब कर्जोंको चुकानेमें असमर्थ होवे, या

(२) यदि कोई सौदा या मुवाहिदा विवाहके सम्बन्धमें किया जावे जिससे कि कोई रुपया या जायदाद लिखने वाले व्यक्ति की स्त्री या बच्चों को अधिष्पमें मिलने वाली होवे परन्तु वह रुपया या जायदाद विवाहके समय उपस्थित न होवे या उसमें देने वाले का उस समय कोई हक न होवे (इसमें उस रुपये या जायदादसे तात्पर्य नहीं है जो उसकी स्त्री की दौध अथवा जिसमें उसकी स्त्री का हक पहुँचता हो) तो ऐसी दोनों हालतोंमें यदि लिखने वाला व्यक्ति विधालिया द्वारा दे दिया जावे या वह समझौता कर लेवे अथवा वह अपने कर्मचारीको तस्फीया कर लेवे और अदालतको यह मालूम हो कि जायदाद का उस प्रकार दिया जाना या सौदा अथवा मुवाहिदा कर्मचारीकोके कर्जों को मारने या उसमें देर करने की भंशसे किया गया था या ऐसे सौदे किये जाते समय की हालत को देखते हुए वह सौदा अनुचित प्रतीत होवे तो अदालत बहाल किये जाने वाले हुक्म देनेसे इनकार कर सकती है या उससे कुछ समयके लिये मुलतवी कर सकती है या शर्तों के साथ बहाल का हुक्म दे सकती है अथवा तस्फीये या तप किये जाने वाले मसल को स्वीकार करनेसे इनकार कर सकती है ।

व्याख्या—

इस दफा में यह बतलाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने सामान्य किसी गायबदार को अपनी स्त्री या बच्चों के हक में इस मंदागि मिल देवे कि जिसमें उसके वर्ज्यप्राप्ति के वसूल करने में देर होने या उसका कर्त्ता वसूल न किया जा सके या ऐसी ही अन्य कोई सौदा या तरहीर कर देवे तो अदालत को अधिकार है कि वह या तो दिवालिये के बहाल होने का हुक्म न देवे अथवा बहाल होने का हुक्म प्रस्तुती कर देवे या शर्तों के साथ बहाल का हुक्म देवे या तरहीर अथवा स्वीकार को मजूर न करे। इस प्रकारसे गायबदार के लिखे जाने की धोखे किया हुआ काम समझा जा सक्ता है और इसी कारण दिवालिया अपने धिये हुए भोलादेही के कामसे बच जान नहीं उठा सक्ता है। इस बात का भी ध्यान रहना चाहिये कि यदि इस दफा के अनुसार बहाल हुए सौदे अपनी स्त्री की निजी आयदाद या रुपये या इन्हें सम्बन्धमें दिये गये हों तो वह सौदे इस दफा के अनुसार दिये हुए धोखे से दिये गये माने जा सकते हैं।

दफा ४५ बहाल के हुक्म का प्रभाव

(१) बहाल का हुक्म दिवालिये को नीचे दी हुई बातों से बरी नहीं करेगा—

(ए) सरकार को चुकाया जाने वाला कर्ज़।

(बी) कोई भी कर्ज़ या ज़िम्मेदारी जो धोखादेही से या धोखादेही से की हुई अमानतमें खपानतसे पैदा हुई हो और जिसमें दिवालिये का भी हाथ रहा हो।

(सी) कोई भी कर्ज़ या ज़िम्मेदारी जिसके लिये धोखा देकर माफी ले ली गई हो और जिसमें दिवालिया का भी भाग रहा हो।

(डी) कोई भी ज़िम्मेदारी जो सन् १८६८ ई० के ज़ाबत फौजदारी की दफा ४८८ के अनुसार दिये हुए हुक्मके आधार पर हुई हो।

(२) उन मामलों को छोड़ कर जिनका उल्लेख उपदफा (१) में किया गया है दिवालिया बहाल होने पर उन सब कर्ज़ों से बरी हो जावेगा जो दिवालिये की कार्यवाही में साबित किये जा सकते हैं।

(३) बहाल किये जाने का हुक्म दिवालिये की कार्यवाही का पूरा सुवृत्त होगा और उसके सम्बन्धमें की हुई सब कार्यवाहियों का भी पूरा सुवृत्त होगा।

(४) यदि कोई व्यक्ति दिवालिये की दरखास्त दाखिल किये जाते समय दिवालिये का साक्षीदार या उसके साथ दूस्ती रहा हो या संयुक्त रूपसे किसी सौदे की अदायगी का ज़िम्मेदार रहा हो या यह ज़ाबिनदार या ज़ाबिनदार के तौर पर रहा हो तो ऐसा व्यक्ति दिवालिये के बहाल हो जाने पर बरी नहीं होगा।

व्याख्या—

उपदफा (१) में वह वर्ग बतलाने गये हैं जिनमें बहाल होने पर भी दिवालिया बहाल नहीं हो सकेगा यह वर्ग प्रायः (ए) (बी) (सी) व (डी) में दिखलाने गये हैं।

फलाज़ (ए) के अनुसार सरकारी कर्ज़ों में बरी नहीं हो सक्ता वह उस बहाल होने पर भी देना पड़ेगा।

कलाज (बी) के अनुसार यदि दिवालियेन घोखते या घोखादेईसे अमानतमें खयानत करके कोई सेदि निय हो अथवा होने दिने हो ता उन सोरोरु सग्न कों जो कच होन वह भी बन्दूर नग रहेंगे और दिवालिया बहाल होने पर भी उनका जिम्मेदार बना रहेगा ।

कलाज (सी) के अनुसार यदि दिवालियेने धात्ता दफर जिंसा कजें या जिम्मेदारीका मुआफ मन्ना लिया हा ता ऐसे कजें की अदायगीका मा वह जिम्मेदार बना रहेगा ।

कलाज (सी) में यह बतलाया गया है कि यदि खाना कोनदाग का दफा ४८८ के अनुसार गुजारा देनेके सम्बन्धमें उस पर कोई कर्ज हो जावे ता एम कजेंस भी वह बहाल हो जान पर भी उदर नहीं बखवा ।

उपदफा (२) में यह दिया हुआ है कि उपदफा (१) में बतलाई हुई बातोंका छाड कर दिवालिया बहाल होने पर उन सब कजोंसे उकान हो जावेगा जा दिवालिय का कारवाहमें माफन निय जासकत है अर्थात् यदि किसी कर्जदाराने अपना कर्ज साबित न किया हा ता भी वह बहाल होकर बाद दिवालियेमें अपना कर्ज समूच नग्न कर सकेगा ।

उपदफा (३) में यह बात साफ कर दा है कि जमा व्यक्ति के बहाल होने पर उसका समीदार या उसके साथ का दूस्ती या अथ कौन समुच जिम्मेदारी रखने वाला व्यक्ति या उसका कामिन्दार बहाल नहो हावेगा इस नियमकी पाबंदी भी अवश्य की जावेगी जैसा कि अगली एक्काई इस दफामें प्रयोग क्रिय हुए (Shall) शब्दका भाव मादप होना है ।

तीसरा प्रकरण



जायदादका प्रकरण

कर्जोंका साबित किया जाना

दफा ४६ दिवालियेके सम्बन्धमें साबित किये जाने योग्य कर्जें

(१) वह मांगें जो मुघाहिदे या अमानतमें खयानतके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकारसे पैदा हुई हों तथा जो अनिश्चित हज्जेके रूपमें होयें दिवालिया की कार्रवाईके सम्बन्धमें साबित नहीं की जासकेगी ।

(२) यदि किसी कर्जदारके विरुद्ध या उसके द्वारा दिवालिये की दस्त्यास्त दी गई हो और उसकी सूचना मिलनेके पश्चात् किसी व्यक्तिन कर्ज दिया हो या कोई दूसरी जिम्मेदारी कर्जदार पर ज्ञापन की हो तो वह व्यक्ति अपना इस प्रकारका कर्ज दिवालिये की कार्रवाईके सम्बन्धमें साबित नहीं कर सकेगा ।

(३) उपदफा (१) व (२) को छोड कर वह सब कर्जें व जिम्मेदारियां दिवालियेकी कार्रवाईके सम्बन्धमें साबित क्रिय जान योग्य कर्जें समझे जावेंगे चाहे वह मोहुरा दोयें या सति-प्यमें अदा किये जाने वाले हों अथवा चाहे वह निश्चित होयें या उनका होना किसी बातके

होने वाले होने व चीह बह निश्चिन होने अपना बनका होना किसी बातक होने पर निर्भर होने साविन निये जाने योग्य स्थिति जावेगे। इस बातका भी ध्यान इस उपद्रफके सम्बन्धमें रखना चाहिये कि यह कर्जों या ती दिवालिया करार देने जाते समय होने अपना इसत पहिले वा हुई लिखेदारके बाण्ड, बहाल होनेसे पहिले दिवालिया इनके लिये लिखेदार हो जावे।

उपद्रफा (४) में उन कर्जोंके बारेमें बतलाया गया है जिनकी कीमत निश्चित न होवे। अर्थात् यदि किसी बातके होने पर किसी वस्तुका होना निर्भर होने अपना अन्य किसी कारणसे निजी कर्जे या लिखेदारकी कीमत निश्चित पत्र साक्षिक रूपमें न होवे तो आधिकार प्राप्तपना उन कर्जोंकी कीमतका तद्वर्गीकरण लगावेगा। इस उपद्रफके साथ यह भी नर्तक होगा जो यह है कि यदि आधिकार प्राप्तपना की बातमें किसी वस्तु या लिखेदारकी कीमतका अनुमान ठीक तौरसे न लगाया जा सकता हो तो यह इस भावका सर्वाधिकृत देगा जहाँमें यह लिखेगा कि उस कर्जकी कीमत ठीक तौरसे तब नहीं हो जा सकती है और ऐसे सर्वाधिकृत देने पर यह वस्तु न साविन दिया जाने योग्य कर्ज समझा जावेगा। इस दफाके अन्तमें जो व्याख्या दी हुई है उसमें लिम्बेसरी (Liability) शब्द जिन २ बातोंके लिये प्रयोग किया जातकता है उन बातोंका उल्लेख है। इस व्याख्यासे यह प्रकट है कि चाहे वह काम बर्तमानमें होने वा भविष्यके लिये दान अपना बनका होना किसी बातके होने पर निर्भर होने उन सब मामलोंके सम्बन्धमें होने वाले कर्ज साविन निये जान योग्य समझे जातकता है।

इसी व्याख्यामें यह भी बात साफ कर दी गई है कि चाहे मुदादिदा वा वादा साफ तौरसे किया गया हो वा उपलब्ध पावनी किसी ओर इगते पेश हो गई हो अर्थात् यह आवश्यक नहीं है कि मुदादिदा आदि मुदादिदेक दगसे चुकतासा तौर पर ही निये गये हों। इस दफामें यह भी बात प्रकट है कि दिवालियाकी चर्चाईमें साविन किया जाने योग्य कर्ज निश्चित मन साक्षिक रूपमें होना आवश्यक नहीं है किन्तु उचित अनुमान निर्धारित बिधियोंके अनुसार अपना रायके अनुसार भी किया जा सकता है।

उपद्रफा (४) के अनुसार साविन किया जाने योग्य कर्ज भी न साविन किया जाने योग्य कर्ज करार दिया जा सकता है यदि उस उपद्रफामें बतलाया हुए नियमोंके अनुसार चर्चाई की गई हो अर्थात् आधिकार प्राप्तपनीका सर्वाधिकृत उस कर्ज पर न साविन करने योग्य बतला देवे परतु यह भी बात ध्यानमें रखना चाहिये कि सब कर्जोंके लिये ऐसा नहीं किया जा सकता है केवल उन्हीं कर्जोंके लिये ऐसा हो सकता है जिनकी निश्चित कीमत न होवे तथा निम्नका होना किसी दृश्य मान या बातोंके होने पर निर्भर होने अपना कोई अप देगा कारण उपस्थित हो जाने।

दफा ४७ आपसमें व्यवहार व उसकी मुजराई

यदि किसी ऐसे कर्जबन्धकके जो इस एक्टके अनुसार अपना कर्ज साविन करता हो वा साविन किया चाहें और दिवालियाके दायिम्यान एक दूसरेसे व्यवहार रहा हो तो इन बातका हिसाब किया जावेगा कि आपसके व्यवहारके सम्बन्धमें एकको दूसरेसे क्या लेना है और एकका लेने वाला कृपा दूसरेमें से मुजरा दिया जावेगा और इस प्रकार मुजराईके बाद जो बाकी निकलगा उसीके लिये दावा एकका दूसरेके खिलाफ समझा जावेगा व उसकी अदायगी कीजावेगी।

परन्तु शर्त यह है कि कोई व्यक्ति उस कर्जों की मुजराई दिवालिया की जायदादसे कराने का अधिकारी नहीं होगा जो उसने इन बातकी सूचना होते हुए दिवालिया का दिया हो कि उसके निरुद्ध दिवालिया की दायिम्यात नहीं गई है या उसने स्वयं दिवालिया की दायिम्यात दी है।

व्याख्या—

इस दफामें यह बतलाया गया है कि यदि दिवालिया वा कर्ज किसी व्यक्तिमें होता हो तथा उस व्यक्ति की भी दिवा-

नियम कुछ रूपया वसूल करना हो तो जिसका कर्ज कम होगा वह दूसरों से घटा दिया जावेगा और इस प्रकार जो कर्ज जिसके जिम्मे थादा निरलेगा वह उससे वसूल किया जावेगा । अंग्रेजी एक्ट की इस धारा में प्रयोग किये हुए (Shall) शब्द से यह प्रकट है कि जहाँ पर एक दूसरेसे लन व देने का व्यवहार हो वह इस दफ्तर नियमों की पाबदा आवश्यक है इस दफ्तर में यह भी शर्त लगा दी गई है कि यदि कर्ज दते समय देने वाला कर्जदार के विरुद्ध या उसके द्वारा दी हुई दिवालिये की दरखास्त की सूचना देवे ता ऐसा कर्ज पुनर नहीं दिया जावेगा । दिवालिये के एक कर्जन्दाई आक्रिण्ट एसायनासे कुछ रुपये यह वह कर मागे कि वह दिवालिये का काम का इतनाम कुछ सार्ने तक करता रहा है जिसके कारण उसका सुनाफेसे कुछ हिसा मिलना चाहिये लेकिन दिवालियेने आफिशल एसायनासे यह बयान किया कि वह कर्जन्दाई उसके रोजगार को खरीदना चाहता था परन्तु उसने अपना सुवाहिदा पूरा नहीं किया जिसकी वजहसे उस कर्जन्दाईने इन्के तौर पर एक अच्छी रकम वसूल की जाना चाहिये अदालतने यह तय किया कि यदि यह बात ठीक है तो इस प्रकार के व्यवहार को दफा ४७ के अनुसार एक दूसरे का व्यवहार समझा जावेगा और यदि कर्जन्दाई अपनी जिम्मेदारके सम्बन्धमें कोई जवाब न देवे कि उसके लहनेमें से कितना रुपया कम कर दिया जावे तो आफिशल एसायना ऐसे कर्जन्दाईके दायरे में नामा कर सकता है, देखो—आर्डी कानून आफिशल एसायना एक्ट A. I. R. 1928. Bangor 49. ज इसके व्यवहारका हिसाब उस रिपतिके अनुसार लिया जाना चाहिये जो रिसेबिंग आर्डरके समय अर्थात् आफिशल एसायना द्वारा कर्जदार की जायदाद पर कब्जा लेने का हुक्म होते समय होवे देखो—19 Bom. 546 इस दफ्तर कर्जन्दाई व आफिशल एसायना दोनों को लाभ है क्योंकि आफिशल एसायना दिवालियेका वह कर्ज आसानीसे वसूल कर सकता है जो किसी कर्जन्दाईसे लेना है और कर्जन्दाई भी दिवालियेके कर्ज की पुनराई अर्ने लहनेमें देकर उससे सहूलियतके साथ बर्तन हो सकता है यहाँ नहीं सिन्तु लुदागाना से वसूल करनेमें जो खर्च आदि किये जाना आवश्यक है वह सब बच जाते हैं इसी प्रकार यह दफ्तर दिवालिया सम्बन्धों को इल्का बरने तथा योग्यत पाय हो जानके लिए बनाई गई है और इसकी अवज्ञा नहीं की जा सकती है ।

दफा ४८ कर्जों साबित करनेके नियम

दूसरी सूची (Second Schedule) में दिये हुए नियमोंकी पाबन्दी कर्जों साबित करनेके तरीक़ोंमें, महफूज तथा अन्य कर्जन्दाईके कर्जों साबित करनेके हक़में सुवृत्तके मानने या न माननेमें तथा उन सब अन्य मामलोंमें की जावेगी जिनका उल्लेख उची सूचीमें किया गया है ।

व्याख्या—

इस दफ्तर में यह बतलाया गया है कि इस एक्ट की दूसरी सूची (Second Schedule) में वह नियम बतलाये गये हैं जिनके अनुसार कर्ज साबित किये जा सकते हैं । यह नियम उस सूचीके १ से लेकर ८ वें नियम तकमें दिये हुए हैं । उसी सूचीमें यह भी बतलाया गया है कि महफूज कर्जन्दाई तथा अन्य कर्जन्दाईका कर्ज साबित करनेके सम्बन्धमें क्या हक़ है । सूचीके ९ से लेकर १७ वें नियममें महफूज कर्जन्दाईके कर्जों साबित किये जानेका वर्णन है । सूचीके २५ वें नियमसे लेकर २७ वें नियम तकमें सुवृत्तके मानने व न माननेका उल्लेख है तथा उसके १८ वें नियमसे २४ वें नियम तक अन्य मामलोंका वर्णन है जैसे कि देहन्की हुई जायदादका हिस्सा लिया जाना (१८ से लेकर २१ तकमें) व सुद और भविष्यक कर्ज आदि इस प्रकार इस दफ्तरके अनुसार दूसरी सूचीमें दिये हुए सब नियमोंकी पाबन्दी दिवालियेके मामलोंके सम्बन्धमें लागू होगी बतलाया गया है अंग्रेजी एक्टकी इस धारा में प्रयोग किये हुए (Shall) शब्द से प्रकट है कि दूसरी सूचीके नियमोंका अवज्ञा नहीं की जा सकती है ।

दफा ४९ कर्जोंका एक दूसरेसे पहिले अदा किया जाना

(१) दिवालिये की जायदाद बाँटते समय नीचे दिये हुए कर्जों और कर्जोंके मुकामिले पहिले बाँटे जावेंगे —

(ए) वह सब कर्जों जो सरकार को अथवा किसी अन्य स्यानिक हाकिम को दिये जाने वाले हों ।

(बी) किसी क्लर्क (मुहारिर) नौकर अथवा मजदूर की तनख्वाह या उजरात जो उसे दिवालियेकी दरखास्त दिये जानेके चार माहके अन्दर काम करनेके पयजमें मिलना चाहिये परन्तु क्लर्ककी तनख्वाह ३००) रुपये तक व नौकर और मजदूरकी उजरात हर व्यक्तिके लिये १००) रुपये तक दिलावाई जायकेगी ।

(सी) वह किराया जो मालिक मालिकान को दिवालियेसे मिलना चाहिये परन्तु इस क्लार्कके अनुसार एक महीनेसे ज्यादा का किराया नहीं मिलेगा ।

(२) उपदफा (१) में जिन कर्जों का उल्लेख है वह आपसमें एक दूसरेके बराबरके कर्जों समके जावेंगे और वह सबके सब पूरे पूरे चुकाये जावेंगे यदि दिवालिये की जायदाद उसके चुकानेके लिये पर्याप्त होवे और यदि दिवालिये की जायदाद कम पड़ती होवे तो वह हिस्सा रसदीके हिसाबसे सबके सब कम करके चुकाये जावेंगे ।

(३) उतना रुपया रोक कर जो सम्बन्धके लिये अथवा और किसी कामके खर्चके लिये आवश्यक होवे बाकी सब रुपयसे जहां तक यह पर्याप्त होगा उपदफा (१) में दिखलाये हुए कर्जों चुका दिये जावेंगे ।

(४) जहां सामे का मामला होवे वहां सामे की जायदादसे पहिले सामेके कर्जों चुकाये जावेंगे और सामीदारों की जुदागाना जायदादसे पहिले उनके जुदागाना कर्जों चुकाये जावेंगे । यदि सामीदारों की जुदागाना जायदाद उनके जुदागाना कर्जों चुकाये जानेके बाद कुछ बचे तो वह सामे की जायदादके तौर पर सबके की जायगी और यदि सामे की जायदाद सामे का कर्जों चुकाये जानेके बाद बचे तो उससे सामीदारोंके जुदागाना कर्जों उनके हिस्सेके अनुसार हिस्सा रसदी तौर पर चुकाये जावेंगे ।

(५) इस पञ्चके नियमों का ध्यान रखते हुए वह सब कर्जों जो दिवालिये की कार्यवाईके सम्बन्धमें साबित किये गये हों, हिस्सा रसदीके हिसाबसे चुकाये जावेंगे और उनमें एकको दूसरेसे तर्जिह नहीं दी जायगी ।

(६) यदि उपर बतलाये हुए सब कर्जों को चुकानेके बाद कुछ बचे तो उससे दिवालिया करार दिये जानेके बाद का खुद साबित किये हुए सब कर्जोंके सम्बन्धमें छः रुपया सैकड़ा सालानाके हिसाबसे चुकाया जावेगा ।

व्याख्या—

इस दफामें दिवालियेकी जायदादसे उसके कर्जोंके उपाये जानेका बर्णन है । उपदफा (१) में यह बतलाया गया है कि तीन प्रकारके कर्जें भिन्ना अहेतु श्राव (ए), (बी) व (सी) में लिया गया है सबसे पहिले चुकाये जावेंगे । अगली

एवम् इम उपदफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे यह भली भाँति प्रकट है कि इस उपदफाके नियमोंकी अवहेलना नहीं की जासकती है। क़ानून (९) में सरसरी कर्जोंका उल्लेख है तथा क़ानून (१०) में नौकरों व मजदूरोंकी तनखाद व बचत का बिक्र है इस क़ानूनमें इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि क़र्जकी तनखाद २०० रुपये तक मिल सकती है व नौकर और मजदूरोंको उनका १०० रुपये का आदमी तक अधिकसे अधिक मिल सकती है। क़ानून (११) के अनुसार एक माह का किराया भी और कर्जोंके मुकामके मिल सकता है। इस दफाओं अन्य उपदफाओंमें भी (अवश्य एवम्) (Shall) शब्दका प्रयोग किया गया है जिससे इस दफामें बतलाई हुई सभी बातोंका मानना आवश्यक प्रतीत होता है अर्थात् इसके निषेधों अवहेलना नहीं की जासकती है।

उपदफा (२) में यह बतलाया गया है कि उपदफा (१) के क़ानून (९), (१०) व (११) में जो कर्जें बतलाये गए हैं वह सब एक दूसरेसे समानता रखते हैं और सबके सब या तो पूरे व चुकाये जाना चाहिये यदि जायदाद बाकी होवे अथवा यदि जायदाद उनको चुकानेमें कम पड़े तो हिस्सा रसदीके हिसाबसे वह कम करके चुकाये जाना चाहिये।

उपदफा (३) में यह बतलाया गया है कि दिवालियेकी जायदादमें उनके प्रत्यक्ष आदि के लिये आवश्यक क़ानून निष्कासनेके बाद उपदफा (१) के अथवा अन्य कर्जें चुकाये जाना चाहिये। साथिके माध्यमोंके सम्बन्धमें उपदफा (४) के अनुसार साक्ष्यकी जायदादसे पहिले साक्ष्यके कर्जें चुकाये जाना चाहिये व उनके चुकाये जानेके बाद यदि कुछ बचे तो उससे साक्ष्य-दारोंके जुदागाना कर्जें उनके हिस्सा रसदीके अनुसार चुकाये जाना चाहिये अर्थात् साक्ष्यके चारोंबारोंमें जिस क्रमर हिस्सा मिल साक्ष्यदार का होवे उसीके अनुसार बचे हुए कर्जोंमें से उसका जुदागाना कर्जें चुकाया जाना चाहिये। वही प्रकार साक्ष्यदारोंकी जुदागाना जायदादमें पहिले उनका जुदागाना कर्जें चुकाये जावेंगे व उसके बाद यदि कुछ बचे तो उससे साक्ष्यके कर्जें चुकाये जावेंगे।

उपदफा (५) में यह बतलाया गया है कि इस एक्टमें बतलाये हुए निषेधों का ध्यान रखते हुए वह सब कर्जें जो साबित किये गये हों - हिस्सा रसदीके हिसाबसे चुकाये जावेंगे और उनमें एक को दूसरेसे कोई तर्जौह नहीं दी जावेगी। यदि दिवालिये की जायदादसे उसके सब कर्जें चुका दिये जानेके बाद कुछ धन बचे तो उसके लिये उपदफा (६) में बतलाया गया है कि उससे सूद ४० रुपये सेकड़ा सालाना की दरसे साबित जुदा कर्जोंके लिये अदा किया जावेगा और यह सूद दिवालिया करार दिया जाने वाला हुक्म होनेके पश्चात् अदा किये जाते समय तक दिया जासकता है। कानून दिवालिये का यह नियम है कि सब कर्जें बराबर समझे जावें और यदि अफिशल एसायनीने कुछ कर्जोंका हिसाबसे यह साक्षात्कार कर लिया है कि यदि वह कर्जोंका हिसाबसे लिये कर्जोंका देवेंगे तो उनका कर्जें सबसे पहिले पूरा पूरा दिया जावेगा तो इस प्रकारका समझौता कानूनन रह समझना चाहिये और उस पर अगल नहीं किया जासकता है, देखो पुनरीतपदास एक्ट नम्बर 55 M. L. J. 657.

इस दफासे यह बात भी प्रकट है कि हिस्सा रसदी केवल साबित किये हुए कर्जों पर ही मिलेगा बिल्ग साबित किये हुए कर्जों पर नहीं। इस दफाका सुलासा इस प्रकार समझना चाहिये कि पहिले प्रत्यक्ष आदि के आवश्यक कर्जों को निष्कासनेके पश्चात् अनन्तर उपदफा (१) के कर्जें चुकाये जावेंगे इसके बाद और सब कर्जें हिस्सा रसदीके अनुसार चुकाये जावेंगे तब भी यदि कुछ बचे रहे तो उससे सूद दिवालिया करार दिये जानेके बाद ४० रुपये सेकड़ा सालाना की दरसे दिखवाया जावेगा। साक्ष्यी साथ बर्ग कर्जें चुकाये जावेंगे जो दिवालिया की कार्यवाहीके सम्बन्धमें साबित कर दिये गये हों।

दफा ५० दिवालिया करार दिये जानेसे पहिलेका किराया

दिवालिया करार दिये जाने का हुक्म होनेके पश्चात् उस हुक्मसे पहिलेके किरायेके सम्बन्धमें दिवालियेकी जायदाद या लहना कुर्क नहीं किया जावेगा जब तक कि दिवालिया करार दिये जाने का हुक्म मंजूर न कर दिया गया हो, परन्तु भालिक भकाल या अन्य कोई व्यक्ति जिसने कि वह किराया लेना होवे उस किराये को और कर्जों की भाँति साबित कर सकता है।

व्याख्या—

इस दफ्ते उस विधये की बमूनी का उल्लिखन कृत्याया गया है जो दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म होनेसे पहले समये लिये जाना होवे । वह विधया नगौर और कर्नोने साबित किया जासकता है अर्थात् हिस्सा सदा दिवालियेकी जायदादमे उस बकाया विधयेके लिये वसू किया जासकता है । यदि दिवालिया करार दिया जाने का हुक्म ममूज कर दिया जाय तो उस विधयेके लिये दिवालिया की जायदाद कुकै बर्रा जासकती है जयथा नही अर्थात् दिवालिया करार दिया जानका हुक्म होनेके पश्चात् उमय पहिलेके विधयेके सम्बन्धमें दिवालियेकी जायदाद या बसका खदना कुकै नही काया जासकता है । इस दफ्ते नियम की भी अवहेलना नही की जासकती है जेसा कि ऐमजी एक्ट की इस दफ्तेमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है ।

वह जायदाद जिससे कि कर्जे चुकाये जासकते हैं

धफा ५१ दिवालियेकी कार्यवाहीका सम्बन्ध

जिसी कर्जदारका दिवालिया होना नीचे दिये हुए समयसे प्रारम्भ होना माना जायगा तथा उसका सम्बन्ध उसी समयसे होगा जाहें वह अपनी दरम्बास्त पर प्रथमा अपनं किसी कर्जदारका या कर्जदारों की दरम्बास्त पर दिवालिया करार दिया गया हो ।

(ए) जिस दिवालियेके कामके आधार पर वह दिवालिया करार दिया गया हो उस कामके होनेके समयसे

(बी) यदि यह साबित होवे कि दिवालियेने एकमे अधिक दिवालियेके काम किये हैं तो दिवालिये की दरम्बास्त दायित्व किये जानके तीन माहके अन्दर जो दिवालियेका काम सबसे पहिले किया गया हो उस समयसे

परन्तु शते यह है कि कोई दिवालिये की दरम्बास्त अथवा दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म केवल इस ही कारण रद्द नहीं हो जायेगा कि दरम्बास्त देने वाले कर्जदारके कर्जेके वाद दिवालियेका काम हुआ है ।

व्याख्या—

इस दफ्ते अनुसार दिये गयेकी कार्यवाही का प्रारम्भ दिवालिये का काम होनेसे समयसे माना जायेगा अर्थात् आदि-काल एतापनी का हुक्म दिवालियेकी जायदाद पर कमी समयसे माना जायेगा जब कि दिवालिये का काम हुआ हो इस दफ्तेके लिये दिवालियेके कार्यमें तात्पर्य उस कामका सम्बन्ध चाहेकि जिसके आधार पर दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म दिया गया हो ।

धफा ५१ (बी) में भी मानकी स्पष्ट कर दिया है कि यदि एक अधिक दिवालियेके काम साबित हों तो दिवालिये की दरम्बास्त दिये जायेके तीन माहके अन्दर जो काम सबसे पहिले हुआ हो उसके होनेके समयसे दिवालियेकी कार्यवाही का प्रारम्भ माना जायेगा । ऐमजी एक्टकी इस दफ्तेमें (Shall) शब्द का प्रयोग किया गया है जिससे यह प्रकट है कि इस दफ्तेके नियमों की अवहेलना नहीं की जासकती है । इस दफ्तेके नियमोंका प्रयोग हर एक दिवालियेके सम्बन्धमें समझना चाहिये अर्थात् यदि कोई कर्जदार अपनी दरम्बास्त पर दिवालिया करार दिया जाने अथवा यदि वह किसी कर्जदारका या कर्जदारों की दरम्बास्त पर दिवालिया करार

दिया गया हो तो दोनों दशाओंमें हम दफाके निगमों को लागू सम्झना चाहिये इसी दफाके अन्तमें यह भी बात बतला दी गई है कि यदि दिवालिये की दरखास्त देने वाले कर्जेंखाहके कर्जोंके बाद कोई दिवालिये का काम होवे तो केवल इस ही कारण दिवालिवा फगर दिया जानेका हुक्म या दिवालियेकी दरखाने रद्द नहीं हो जायेगी । अर्थात् उस दिवालियेके कामके आधार पर भी दिवालिवा फगर दिया जाने वा इसमें दिवालिवा है और दिवालिये की दरखास्त चल सकती है ।

दफा ५२ जो जायदाद कर्जेंखाहोंमें बांटी जासकती है उसका विवरण -

(१) नीचे लिखी जायदादको उस जायदादमें शामिल नहीं समझना चाहिये जो कर्जेंखाहानमें बांटी जा सकती है और जो इस धर्कमें दिवालियेकी जायदाद बसलाई गई है:—

(ए) वह जायदाद जो दिवालिवा बतौर अमानत (Trust) के किसी दूसरे शब्दकी धरकसे लिये हुए होवे ।

(बी) इसकी तिजारतके सम्बन्धके औजार और आवश्यक पहिनने वाले कपड़े, बिस्तर, खाना पकानेके घरतन और उसका व उसकी चीजी व बच्चोंके लकड़ी काठका सामान (Furniture) परन्तु यह सब औजारों, कपड़ों व दूसरी ज़रूरी चीज़ोंके कुल तीनसौ रुपयेसे ज्यादा का न होना चाहिये ।

(२) ऊपर बतलाई हुई बातों का ध्यान रखते हुए नीचे बतलाई हुई तकसील की चीज़ें दिवालियेकी जायदादमें समझी जायेंगी:—

(ए) वह सब जायदाद दिवालिये की कार्रवाईके प्रारम्भमें दिवालियेकी है या जो उसको प्राप्त हो सकती है अथवा जो दिवालियेको बहाल होनेसे पहिले दिवालियेको मिल सकती है या दिवालिवा जिसको प्राप्त कर सकता है ।

(बी) वह अधिकार जो दिवालिवा, दिवालिये की कार्रवाईके प्रारम्भसे अथवा बहाल होनेके समयसे पहिले किसी जायदादके सम्बन्धमें प्रयोग कर सकता है या प्रयोग करनेके लिये कार्रवाई कर सकता है, और

(सी) वह सब माल जो दिवालिये की कार्रवाईके प्रारम्भके समय दिवालियेके कर्जोंमें होवे या उसके अधिकारमें होवे और जिसे वह अपने व्यापार या कारोबारके सम्बन्धमें असली मालिक की रज़ामन्दी व इजाज़तसे इस प्रकार रखे हुए होवे जिसमें कि वह स्वयं उस मालका मालिक प्रतीत होता होवे ।

परन्तु शर्त यह है कि क्लार्क (सी) के अनुसार उन कर्जोंके अलावा जो वसूल किये जाने वाले होवे अथवा जो उसके व्यापार या कारोबारके सिलसिलेमें वसूल किये जाने की होवे और होने वाली बातें माल नहीं समझे जायेंगे । और यह भी शर्त है कि वह माल जो क्लार्क (सी) के अनुसार कर्जेंखाहोंमें बांटी जाने योग्य समझा गया हो उस मालका असली मालिक उस मालकी कीमतको साबित कर सकता है ।

व्याख्या—

इस दफा में यह मतलब गया है कि दिवालिये की वीन वीन सी जगदाद इसके कर्जस्वाहान में बाँटी जा सकती है वीर वीन वीन सी जगदाद वीर नही जा सकती है प्रत्येक उपदफा (१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) (१३) (१४) (१५) (१६) (१७) (१८) (१९) (२०) (२१) (२२) (२३) (२४) (२५) (२६) (२७) (२८) (२९) (३०) (३१) (३२) (३३) (३४) (३५) (३६) (३७) (३८) (३९) (४०) (४१) (४२) (४३) (४४) (४५) (४६) (४७) (४८) (४९) (५०) (५१) (५२) (५३) (५४) (५५) (५६) (५७) (५८) (५९) (६०) (६१) (६२) (६३) (६४) (६५) (६६) (६७) (६८) (६९) (७०) (७१) (७२) (७३) (७४) (७५) (७६) (७७) (७८) (७९) (८०) (८१) (८२) (८३) (८४) (८५) (८६) (८७) (८८) (८९) (९०) (९१) (९२) (९३) (९४) (९५) (९६) (९७) (९८) (९९) (१००)

उपदफा (१) में यह जगदाद बतलाई गई है जो दिवालिये के कर्जस्वाहान में नहीं गयी जायेगी । यह उपदफा दो ३ जो में विभक्त है पहिले द्वाय अर्थात् प्रात (५) के अनुसार यह जगदाद जो दिवालिवा अपमानत अर्थात् बतौर दूरी के लिये हुए होवे उमकी नहीं समझी जायेगी और न वह कर्जस्वाहान में बाँटी जा सकेगी ।

अन्तर्जा (५) के अनुसार दिवालिये की कुछ आवश्यक वस्तुओं की भी कर्जस्वाहान में बटि जानेसे री कर दिया है अर्थात् उस द्वातके अनुसार व्यापार सम्पत्ती, विस्तार, खाना पकाने के बर्तन तथा आवश्यक छकरी बाँट की चीजें छोड़ दो गई हैं परन्तु री द्वातमें यह भी बतलाया गया है कि इन चीजोंके कुछ कीमतविलक (१००) रुपयेसे अधिक नहीं होना चाहिये अर्थात् ऊपर बतलाये हुए क्रियक सामान वीन सी रुपये की कीमत तक का होना आवश्यक है । गृहजन्यों का एक एक इन्सुरेंस वस्तुकी कमेन्टि तथा खानाची था । उक्त इन्सुरेंस वस्तुकी कमेन्टि वस्तुकी वस्तुकी का कुछ रुपया गवर्नमेन्ट प्रोमिसरी नोट्समें लगा देने का हुक्म दिया और गृहजन्यों के लिये कुछ देर करके यह रुपया प्रोमिसरी नोट्समें लगा दिया परन्तु उसके बाद वीन सी नही फरे दिवालिवा करार दे दिया गया तो यह तय हुआ कि वह खानते (अर्थात् गवर्नमेन्ट प्रोमिसरी नोट्स) उस कमेन्ट के पास बतौर अपमानत (Trust) के थी और हम लिये इस दफा के अनुसार कर्जस्वाहान में नहीं बाँटी जा सकती थी, देखो—समस्त वस्तु आधिकार एसायनी 35. Mad. 712. यदि कोई सोना जवाहरानों के लिये किसी व्यक्ति को दिया गया हो और वह उसके बाद दिवालिवा करार दिया जाय तो वह सोना यदि उसका ठीक तौरसे पता न लगना हो उस व्यक्ति का जगदाद समझा जावेगा देखा—28 Mad. 403.

उपदफा (२) में यह तकलीफ बतलाई है जिसके होने पर जगदाद कर्जस्वाहान में बाँटी जाने योग्य समझा जावेगा । अन्तर्जा (५) के अनुसार दिवालिये की कर्जस्वाहान में बतला देने पर बहाल होनेसे पहिले जो जगदाद दिवालिये की होने या उसकी मिल सके वह सब दिवालिये की समझा जावेगी और वह उसके कर्जस्वाहान में बाँटी जा सकती है । यह रुपया जो दिवालिये की वस्तुमें किसी समय मिलने वाला होवे आधिकार एसायनी की विधिमा जो कि यह रुपया उसी समय अदा किया जाने वाला नहीं है । देखो—26. Mad. 440 इस दफा के अनुसार किसी घुआदिदेके वह अधिकार आधिकार एसायनी की प्राप्त हो सके जो दिवालिये की उसके अनुसार मिल सके हैं, देखो—अ वनाम वाकर 40 Cal. 253. आधिकार एसायनी एक दिवालिये की रिस्पोन्स पॉलिसी (Policy of Insolvency) नीतिमा की ओर एक खरीदारने उस दिवालिये की ताकते खरीद किया । इसके बाद दिवालिया पर गया उसके बाद पर खरीदारने पॉलिसी का रुपया वसूल किया और उसे एडमिनिस्ट्रेटर अन्तराल को दे दिया । यह तय किया गया कि आधिकार एसायनी के मुताबिके वह रुपया दिवालिगिक वॉलीसीवा हो गिल्मा चाहिये । देखो—18. Mad. 24 एक कर्जस्वाहाने कुछ न बोलाम कान का हुक्म एक जमीन के निम्नत हामिल किया और इसके बाद दिवालिया करार दिया जानेका हुक्म ॥ गया तो यह तय किया गया कि आधिकार एसायनी का वह उस जमीन पर होगा, देखो—42 Cal. 72 29, Mad. 903. यदि किसी घुआदिदेके रुपया घुआदिदेके सिलसिलेमें जमा किया गया हो और बादमें डिन्की दो गई हो तो उस रुपये पर कर्जस्वाहान डिक्लारा का ॥ तय हुआ, देखो—35. Mad. 355. यदि कोई वननेके

क्रिये सेना दिया गया हो और दिवालिया करार दिये जाने पर उस सेने का ठीक ठाक पता न लगा सके तो वह सेना दिवालियरी जायदाद सम्पत्ति जावेगी और सोनेके मालिकका कोई ज्यादा हक न सम्पत्ति जावेगा अर्थात् वह माफूली कर्जेस्वाहोंकी तरह अपभा कर्ज समित कर सकता है, देखो—28 Mad. L. I. 403. तनस्वाद भी पैदा की हुई जायदादमें शामिल की जासकती है, देखो—34. Mad 183. मयास हाई-कोर्टने यह तथ किया था कि किसी समुक्त हिन्दू परिवारके कर्ता को उस परिवारकी जायदाद की अनश्वर करनेके जो अधिकार हैं वही अधिकार आफिशल एसायनीके उस जायदादके सम्बन्धमें सम्पन्न चाहिये। देखो—26. Mad. 214.

यदि काम होनेके समयमें (During business hours) किसी गोदामकी चार्ज निममें माल भरा हो दिवालियेके कब्जेमें रहता हो परन्तु उसके बादके वक्तमें वह चार्ज उस शक्त्तके पास रहता हो जिसके पास गोदाममें रखा हुआ माल रहन हो तो वह माल दिवालियेकी हिकानतमें रहने वाला माल सम्पत्ति जावेगा, देखो—22 Mad. L. I. 441. यदि दिवालियेके लानर छपुर्दार या किरायेदारके कब्जेमें कोई माल होवे तो वह दिवालिये ही के कब्जेमें सम्पत्ति जावेगा क्योंकि दिवालियेकी ही तरफमें वह माल उसके कब्जेमें रहता है। इस दफाकी अन्तर्गत उपरका का मानना आवश्यक है अर्थात् उनकी अवहेलना नहीं की जाना चाहिये जैसा कि अंग्रेजी एक्ट की इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है।

पिछले सौदों पर दिवालिया होने का प्रभाव

दफा ५३ इजरायके सम्बन्धमें डिक्रीदारोंके अधिकारोंमें रुकावट

(१) यदि किसी कर्जदारकी जायदादके विरुद्ध डिक्री जारी कर्गई गई हो तो उस इजरायसे फायदा कोई भी व्यक्ति आफिशल एसायनीके मुकामिले नहीं उठा सकेगा परन्तु यदि उस कार्रवाईके चालू करनेसे पहिले उसको दिवालिये की दरखास्त दी जाने की कोई सूचना न रही हो और वह दिवालिया करार दिया जाने का हुक्म होनेसे पहिले नीलामसे अथवा अन्य किसी प्रकारसे बख्तली की जायके तो उसके पाने का वह व्यक्ति अधिकारी होगा।

(२) इस दफा का कोई प्रभाव महफूज कर्जस्वाहके उन अधिकारों पर नहीं पड़ेगा जो उसे महफूज जायदादके सम्बन्धमें प्राप्त की हुई डिक्री की इजरायके लिये प्राप्त है।

(३) यदि कोई व्यक्ति नेकनीयतीसे इजरायके सम्बन्धमें नीलाम की हुई किसी जायदाद को खरीद करे तो उसको आफिशल एसायनीके विरुद्ध हर प्रकारके अधिकार उस जायदादके सम्बन्धमें प्राप्त होंगे।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार दिवालिया करार दिया जाने का हुक्म होनेके पश्चात् सब जायदाद आफिशल एसायनीकी सम्पत्ति जावेगी और उसे खदामाना तौर पर कोई कर्जेस्वाद नहीं प्राप्तकेगा।

उपदफा (१) में यह बतलाया गया है कि यदि इजराय करने वाले डिक्रीदार की दिवालियेकी दरखास्त दिये जाने की कोई सूचना न रही हो और दिवालिया करार दिये जाने का हुक्म होनेसे पहिले कुछ जायदाद बख्तली जायके तो वह डिक्रीदार उसके पाने का हकदार होगा अन्यथा नहीं किन्तु उस सब जायदाद का हकदार आफिशल एसायनी सम्पत्ति जावेगा।

इस प्रकार यदि सौदा रुपयेके लिखित इनाममें कोई जायदाद कुर्क होकर नीलाम पर चढ़ाई गई हो परन्तु नीलामसे पहिले मरियून दिवालिया क़ार दे दिया जावे और उसके बाद नीलाम होने पर कोई व्यक्ति दिवालियेकी जायदाद को ख़रीदे तो ऐसे ख़रीदारको कोई हक़ नहीं पहुचता है, देखो—31. Mad. 493. यदि हिस्सा सस्ती पानेके लिये किसी इनाममें दाख़्वास्त दी गई हो तो वह दाख़्वास्त इस दफ़्तेके अनुसार इनामकी दाख़्वास्त नहीं समझी जासकती है, देखो—39 Mad. 25. यदि मरियून अदालतमें दाख़िर न होवे विन्तु उसकी इतिहासके लिये कोई रूपया जमा किया जावे तो वह रूपया डिमीदार पाने का अधिकारी है, देखो—39. Cal. 1048.

उपवफा (२) में यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि इस दफ़्ता का कोई प्रभाव मरियून कर्तव्यवालोंके अधिकारों पर नहीं पड़ेगा अर्थात् वह दिवालियेकी जायदादके सम्बन्धमें प्राप्त की हुई डिमी को नियम पूर्वक इनाम कर सकता है ।

उपवफा (३) के अनुसार नेकनीयतीके साथ जायदाद ख़रीदने वालोंकी वचत कर दी गई है अर्थात् यदि किसी व्यक्तिने किसी इनामके सम्बन्धमें नीलामकी हुई जायदाद को ख़रीदा हो तो वह व्यक्ति उस जायदादके पाने का पूर्ण क़ास्ते अधिकारी समझा जावेगा और आफ़िशल एसायनी उसके अधिकारोंमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा । इस दफ़्तेके नियमों की भी अवहेलना नहीं की जाना चाहिये जैसा कि सैम्युअल एक्ट की इस दफ़्ता की प्रत्येक उपवफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे साबित है ।

वफा ५४ इजराय करने वाली अदालतोंके दिवालिये की जायदाद सम्बन्धी कर्तव्य

यदि नीलाम की जाने योग्य जायदादके विवरण डिमी जारी कराई गई और उसके मीलाम होनेसे पहिले अदालत को यह नोटिस दे दिया जावे कि मरियून विधालिया क़ारार दे दिया गया है तो इजराय करने वाली अदालत दाख़्वास्त दिये जाने पर जब कि यह जायदाद अदालतके क़ब्ज़में होवे जायदादको आफ़िशल एसायनीके सुपुर्दे किये जाने का हुक्म दे देगी परन्तु इजराय का ख़र्च उस जायदादसे सबसे पहिले वसूल किया जावेगा और आफ़िशल एसायनी को अधिकार है कि यह कुल जायदाद को या उसके किसी हिस्से को बेच कर उस ख़र्च को चुका देवे ।

व्याख्या—

इस दफ़्तेके अनुसार यदि नीलाम होनेसे पहिले इनाम करने वाली अदालत को मरियूनके दिवालिया क़ारार दे दिये जाने की सूचना मिल जावे तो वह इनामकी जायदाद ख़रीदने की शक़ देवेगी और दाख़्वास्त करने पर अदालत यह हुक्म दे देवेगी कि वह जायदाद आफ़िशल एसायनीके सुपुर्दे कर दी जावे । इस नियमकी अवहेलना नहीं की जाना चाहिये जैसा कि सैम्युअल एक्टमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है इसी प्रकार इनाम का ख़र्च भी उस जायदादसे सबसे पहिले वसूल किया जासकेगा अर्थात् वह सब पर सबसे पहिले वार माया जावेगा । इस दफ़्तेमें आफ़िशल एसायनी को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह इस नारके उद्देश्यके लिये सब जायदाद या उसके किसी हिस्से को बेच सकता है शर्तु आफ़िशल एसायनी ऐसा करनेके लिये बाध्य नहीं है जैसा कि सैम्युअल एक्टमें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट होता है ।

वफा ५५ स्वयं किये हुए इन्तक़ाल जायदाद की मसूखी

यदि किसी इन्तक़ाल जायदाद होनेके पदचात् दो सालके अन्दर इन्तक़ाल करने वाला व्यक्ति दिवालिया क़ारार दे दिया जावे और वह इन्तक़ाल जायदाद पहिले तथा किसी विधवाके

पक्षमें अथवा किसी खरीदार या बार रखने वाले मूल्यवान मुवाविजा लेकर नैकनीयतीके साथ न किया गया हो तो वह इन्तकाल जायदाद आफिशाल पसायनीके विरुद्ध रह समझा जावेगा।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार केवल वही इन्तकाल जायदाद जो दिवालिया करार दिये जानेके दो साल पहिले दिये गये हों भले प्रकार सुरक्षित समझना चाहिये। दो सालके अन्दर किये हुए वही इन्तकाल जायदाद सुरक्षित होंगे जो नैकनीयतीके साथ पर्याप्त कीमत लेकर दिये गये हों। विवाहके सम्बन्धमें तथा पहिले दिये हुए इन्तकाल भी सुरक्षित समझना चाहिये। इसके विरुद्ध यदि दो सालके अन्दर कोई इन्तकाल जायदाद दिवालिया करार दिये गये हों तो वह अफिमल पसायनीके विरुद्ध रह समझा जावेगा। इस दफाके नियम माननाय समझना चाहिये जैसा कि अंग्रेज एक्टमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है। इस दफामें जो नैकनीयतीसे इन्तकाल जायदादके दिये जाने की व्यवस्था बतलाई गई है उसका अभिप्राय यह है कि जिस व्यक्ति के हकमें इन्तकाल जायदाद दिया गया हो उसमें नैकनीयतीसे इन्तकालको कराया हों यही धुन 16 Mad. 397. से निकलती है। यदि कोई मुर्तद्दिन किसी रैकनामे को जो दो सालके अन्दर दिया गया हो पेश करे तो यह उक्त कर्तव्य होगा कि वह साबित करे कि रैकनामा नैकनीयतीके साथ मुआविजा देकर लिखाया गया था, देखो—43 Mad. 739.

दफा ५६ कुछ मामलोंमें तरजीह का रह किया जाना

(१) यदि कोई कर्जदार अथवा कि वह अपने कर्जोंको अपने रुपयेसे न चुका सकता हो किसी एक कर्जखवाहके हकमें कोई इन्तकाल जायदाद करे या कोई अदायगी करे या कोई ज़िम्मेदारी लेवे और कोई अशालती कार्यवाई करे या होने देवे और उसकी यह नियत होवे कि उस कर्जखवाह को और कर्जखवाहोंके मुकाबिले तरजीह मिल जावे और ऐसे सौदेके होनेसे तीन माहके अन्दर दिवालिये की वरखवास्त बीजाने पर यदि वह कर्जदार दिवालिया करार दे दिया जावे तो वह सब सौदे आफिशाल पसायनीके लिये धोखाधड़ीसे किये हुए सौदे माने जावेंगे तथा वह समझ जावेंगे।

इस दफा का कोई प्रभाव ऐसे व्यक्तिके अधिकारों पर नहीं पड़ेगा जिसने नैकनीयतीसे दिवालियेके किसी कर्जखवाहसे मूल्यवान मुआविजा देकर किसी अधिकारको प्राप्त किया हो।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार यह सब सौदे जो दिवालिया किसी एक कर्जखवाह को और कर्जदारोंके मुकाबिले तरजीह देनेके लिये करे ता वे वह समझ जावेंगे किन्तु इस दफाके अनुसार वह समझ जाने वाले सौदे वही समझ रह होंगे जब कि सादा करन वाला व्यक्ति दिवालिया करार दे दिया जावे और दिवालिया करार दिये जाने की दफ्तरान उक्त सौदेके होनेसे तीन माहके अन्दर दी गई हो। उपदफा (१) के नियमों का मानना आवश्यक है जैसा कि अंग्रेज एक्टमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है इसी प्रकार उपदफा (२) के नियमों की भी अवहेलना नहीं की जासकता है।

उपदफा (१) के लिये इस बात का सा ध्यान रहना चाहिये कि सादा होने समय दिवालिया अपने कर्जों को अपने रुपयेसे न चुका सकता हो। मगरा हाईकोर्टने यह तय किया है कि अंग्रेजी एक्टमें इस दफाके प्रयोग किये हुए (Shall) शब्द का तात्पर्य (Vedable) शब्दसे समझना चाहिये और सौदा हाा का तात्पर्य हाा से वह सौदा रह नहीं है किन्तु उस समयसे रह है जब कि आफिशाल पसायनी का हक उस पर पहुँचया। देखो—25 Mad. 308. महानगरका एक कर्म एक इनरारसे कम्पनीके अद्वैकटोंने उस कर्मके पास बच हुए रुपयेसे उस सरकारी बांगन खरीदने का हुकम दिया। कुछ देर होनेके पश्चात् वह कायब खरीद गये और उसने बाद फौरन ही वह महानगर दिवालिया करार दिया गया तो यह तय किया

गया कि कोई धोखारेसे तभीह ऐसे मामले नहीं दी गई थी. देखो—35 Mad. 712. यदि दिवालिया क़ारर दिये जानेसे कुछ ही पक्षिसे कोई इतकाल जायदाद दिवालियेने अपनी सौ के हकमें किया हो तो उसकी सौ को चढ़िये कि वह साबित करे कि सौदा कायम रहा जाना चाहिये अर्थात् वह रद्द नहीं होना चाहिये, देखो—24 I. C 518.

इस दफाके लिये यह भी ध्यान रखना चाहिये कि वही सौदा जो एक कर्जस्वाह को दूसरे कर्जस्वाहके मुकाबिले तर्गह देनेके लिये दिये गये होंगे रद्द समझे जायेंगे। कर्जदार की जानन बेचक उस ही बातमें नहीं समझ भेना चाहिये कि किसी सौदेके एक कर्जस्वाह को लाभ पहुच गया है व दूसरे कर्जस्वाह यांही रद्द गये हैं इसके लिये सब हम्मतों पर धीर करना चाहिये तथा इसके लिये इन्क़लबके कानून तथा बड़ाके पैसलों पर भी ध्यान दिया जासकता है अर्थात् उनके आधार पर यहांके फैसले किये जा सकते हैं, देखो—42 Mad. 510. इसी मामले में यह भी तय किया गया था कि दिवालियेने अपने लाभके लिये तथा अपने कर्जदार की बाध रखनेके लिये किसी सौदेको मिया द तो वह सौदा दरमय धोखारेसे तर्गह देने वाला सौदा नहीं समझा जायगा। तीन माहरी जो अवधि इस उपदफामें तर्गह गई है उसमें यह तर्क नहीं है कि सौदा होनेसे तीन माहके अंदर सौदा करने वाला व्यक्ति दिवालिया क़ारर दे दिया गया हो किन्तु उसका तर्क यह है कि सौदा होनेसे तीन माहके अंदर उसके विरुद्ध दिवालिये की दम्बाल दे दी गई हो इस उपदफाके अनुसार केवल इतकाल जायदाद ही रद्द नहीं समझें अर्थात् किन्तु दूसरे प्रकारके सौदे भी जैसे कि अदायगी या कोई बिम्बेदारी जो दिवालियेने किसी एक कर्जस्वाहके लिये की हो।

उपदफा (२) में सब लोगोंके बचनकी व्यवस्था बतलाई गई है नियोंने नेकनीयतीसे कोई अधिकार दिवालियेके किसी कर्जस्वाहसे या उसके मार्फत प्राप्त किया हो। इस कानून की ध्यान रहना चाहिये कि वह सौदा केवल दिवाली सौदा ही न होवे किन्तु वह मूलबाल मुकदमोंके दिये जाने पर किया गया हो।

दफा ५७ नेकनीयतीसे किये हुए सौदों की बचत

कुछ इन्क़ालात (Transfers) तथा तर्जिहात (Preferences) के लिखे जाने तथा उनको रद्द किये जानेके सम्बन्धमें जो नियम उपर दिये जाचुके हैं उनका ध्यान रखते हुए नीचे दिए हुए सौदे दिवालियेकी कार्यवाईके सम्बन्धमें इस उपदफाके अनुसार किसी बात से रद्द नहीं होंगे:—

- (५) यदि दिवालिये ने अपने किसी कर्जस्वाह को कोई अदायगी की हो,
- (६) यदि कोई अदायगी या सुपुर्दगी दिवालिये को की गई हो,
- (७) यदि दिवालिये ने कोई इन्क़ालात जायदाद पर्याप्त मुआधिजा लेकर किया हो,
- (८) यदि कोई मुबाहिदा या सौदा दिवालिये के साथ कीमती मुआधिजा लेकर किया गया हो।

परन्तु शर्त यह भी है कि ऊपर बतलाया हुआ सौदा, दिवालिया क़ारर दिया जानेका हुकम होनेसे पहिले हुआ हो तथा जिस व्यक्ति के हाथ सौदा किया गया हो उसको सौदा किये जाते समय कर्जदारके विरुद्ध या उसके द्वारा दिवालिये की दम्बालास्त दिये जाने की सूचना न रही हो।

व्याख्या—

इस दफा के अनुसार नेकनीयती से किये हुए सौदों की शर्त या प्रस्थ किया गया है। इस दफा में उन्हीं सौदों की शर्त या विधान है जो दिवालिया क़ारर दिये जाने का हुकम होने से पहिले किये गये हों तथा यह भी बात ध्यान में रहना

चाहिये कि सौदा होते समय उस व्यक्ति का जिसके हक में सौदा किया गया हो कर्जदार के विरुद्ध दिवालिये की दरखास्त दिये जाने की सूचना न हो अर्थात् यदि पञ्चदश दिवालिये की दरखास्त दे रली हो अपना उसके विरुद्ध दिवालिये की दरखास्त दे गई हो और इसके बाद कर्जदारने कोई सौदा किया हो तो उस सौदे के किये जाते समय उस व्यक्ति को दिवालिये की दरखास्त की सूचना न होना चाहिये जिसके हकमें सौदा किया गया हो वरना उस सौदे की रक्षा इस दफा के अनुसार नहीं हो सकेगी।

इस दफा के नियमों की भी अवहेलना नहीं की जा सकती है जिस कि अंग्रेजी एक्ट में प्रयोग किये हुए 'Shall' शब्द से प्रकट है। नैक-नीयतासे किये हुए सौदेही इस दफाके अनुसार सुरक्षित हैं वह सौदे जो कानून दिवालियासे बेसा काम उठाने की नीयतसे किये गये हो अपना या स्वयंही दिवालिये का काम समझे जा सकते हैं इंग्लिश दफा के पान नहीं हो सकते हैं देखो—39 Mad. 250 यदि कोई कर्जा सौदा किया गया हो तो उससे किसी व्यक्ति को हक नहीं पड़ूँ सक्ता है यदि दस्तावेज लिखकर रजिस्ट्री भी कर दीगई हो, देखो—34 L. C. 435 जिन सौदोंकी रक्षाका उल्लेख इस दफामें किया गया है वह चार भागोंमें विभक्त किये गये हैं तथा उनका वर्णन क्रम (ए), (बी), (सी) व (डी) में किया गया है।

फ्लैज़ (ए) में उस अदायगी का जिक्र है जो दिवालिया ने अपने भिन्नी कर्जस्वाह की की हो।

फ्लैज़ (बी) में यदि दिवालिये को कोई अदायगी की गई हो या कोई कर्जा दिया गया हो तो उनकी भी रक्षा इस दफा के अनुसार की जा सकती है।

फ्लैज़ (सी) के अनुसार यदि दिवालिये ने क्रीमत पर्याप्त लेकर कोई इन्स्युलर वायदाद किया हो तथा क्टान (डी) के अनुसार यदि कोई सौदा या प्रवाहिता पर्याप्त धन लेकर किया गया हो तो ऐसे सौदे इस दफा के अनुसार सुरक्षित समझना चाहिये। इस दफा से पहिले जो नियम किसी सौदे के रद्द किये जानेके सम्बन्ध दिये जा चुके हैं उनका ध्यान रखना आवश्यक है अर्थात् दफा ५३, ५४, ५५ व ५६ में बतहाये हुए नियमों का ध्यान रखने हुए इस दफा के नियमों का प्रयोग समझना चाहिये।

जायदाद का वसूल किया जाना

दफा ५८ आफिशल एसायनी द्वारा जायदाद पर कब्ज़ा लिया जाना

(१) जितनी ज़रूरी हो सकेगा आफिशल एसायनी दिवालियेके कांफ़ज़ात, किताबों तथा दस्तावेज़ों पर कब्ज़ा करेगा तथा उस सब जायदाद पर भी कब्ज़ा करेगा जिस पर दस्तवी कब्ज़ा लिया जासकता है।

(२) दिवालिये की जायदाद पर कब्ज़ा लेने तथा उस पर कब्ज़ा रखनेके सम्बन्धमें आफिशल एसायनीके वही अधिकार होंगे जो सन् १९०८ ई० के ज़ाबता दीवानीके अनुसार किसी जायदादके सम्बन्धमें नियुक्त किये हुए रिस्तीवरके होते हैं और अदालत उसकी दरखास्त पर इस प्रकार का कब्ज़ा दिलाने तथा कायम रखने की कार्रवाई कर सकती है।

(३) यदि दिवालिये की कोई जायदाद स्टॉक (Stock), सहजजके शेअर्स (Shares in Ships), अथवा अन्य किसी प्रकार की भिन्नी जायदाद होवे जो किसी कम्पनीके दफ्तर अथवा किसी व्यक्तिके कागज़ातमें एकसे दूसरेके नाममें की जासकती हो तो आफिशल एसायनी इस

प्रकारकी जायदादके इतकालके सम्बन्धमें वही अधिकार बरत सकता है जो दिवालिया स्वयं इस अवस्थामें जब कि वह दिवालिया नहीं हुआ था बरत सकता हो ।

(४) जोय कि दिवालिये की कोई जायदाद दांच की शकलमें होवे तो इस प्रकारकी बातोंके लिये यह मान लिया जावेगा कि वह बाकायदा आफिशल एमायनीके हकमें कर दी गई है ।

(५) यदि किसी खजाञ्ची या दूसरे अफसरके अथवा किसी महाजन एटार्नी या पजण्टके कजमें दिवालिये की तरफसे कोई रुपया या जमानतें होवें जो कि वह दिवालिये या आफिशल एमायनीके विरुद्ध नहीं रोक सकता है तो वह रुपया आफिशल एमायनी को अदा करेगा अथवा उसको आफिशल एमायनीके सुनुई करेगा यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसके लिये यह माना जावेगा कि उसने अदालत की तै हीन की है और इसके लिये आफिशल एमायनी की दरखास्त आने पर दण्ड का भागी होगा ।

व्याख्या—

इस दफामें दिवालिये की जायदाद पर आफिशल एमायनी द्वारा कब्जा लिये जाने का उल्लेख है । उपरका (१) के अनुसार आफिशल एमायनी का कर्तव्य है कि वह जिनकी जमीन हो सके दिवालिये की ऐसी जायदाद पर कब्जा ठे छेदे जिस पर दली कब्जा । क्या जासकता है उसमें दस्तावेजों व हिस्सों की किताबें भी शामिल है । अंग्रेजी एक्टमें (Shall) शब्दका प्रयोग किया गया है जिससे यह प्रस्ट है कि आफिशल एमायनी को ऐसी वस्तुओं पर कब्जा लेनेमें देर नहीं करना चाहिये और न इस उपद्रवके नियमों की अवहेलना ही करना चाहिये ।

उपद्रवका (२) में आफिशल एमायनीके कानूनी अधिकार का वर्णन है । इस उपद्रवके अनुसार आफिशल एमायनीके बड़ा अधिकार सम्पन्न चाहिये जो काजवा दीवानीके अनुसार जायदादके लिये नियुक्त किये हुए रितीरके होते हैं और आफिशल एमायनीके दरखास्त देने पर अदालत कब्जा केन तथा काजवा कायम रखनेके लिये दूसरोंको मजबूर कर सकती है ।

उपद्रवका (३) में शार्स (Shares) आदि ऐसी जायदाद का वर्णन है जो किसी कम्पनी आदि की किताबोंमें एकके नामसे दूसरेके नामसे की जासकती है उनके बारेमें यह बतलाया गया है कि आफिशल एमायनी वही अधिकार बरत सकता है जो दिवालिया होनेसे पहिले बतल सकता था । इस नियम की पाबंदीके लिये आफिशल एमायनी बाध्य नहीं है जैसा कि अंग्रेजी एक्ट की इस उपद्रव में प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रस्ट है अर्थात् वह आवश्यकतातुल्य कार्य कर सकता है ।

उपद्रवका (४) के अनुसार आफिशल एमायनी को दिवालियेके मामलोंके सम्बन्धमें दावे आदि दायर करनेके पूर्ण अधिकार हैं ।

उपद्रवका (५) में बतलाया गया है कि यदि किसी व्यक्तिगत या तो सन्तानही महाजन, एटार्नी या ऐमेन्ट होवे इस हिसीवतसे दिवालिये का कोई रुपया या दस्तावेजें होवें जो बाबंदते दिवालिये की बर्षित मिलना चाहिये तो उन लोगों का यह कर्तव्य होगा कि वह रुपया या दस्तावेजों आफिशल एमायनी को द देने अथवा वह अदालतकी ताहीन करनेके दोनों समझे जावेंगे और उसको आफिशल एमायनीके दरखारान देने पर उस जुर्मे का दण्ड दिया जासकता है अगला एक्टमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रस्ट है कि इस उपद्रवके नियमों की अवहेलना नहीं की जासकती है ।

दफा ५९ दिवालियेकी जायदाद पर कब्जा लेना

(१) अदालत को अधिकार है कि वह दिवालिये की किसी जायदादके लिये जो दिवा-

लिये अथवा अन्य किसी व्यक्ति के कब्जे या देखरेख में होवे कब्जा लेने का वारण्ट नियत किये हुए अफसरके नाम अथवा कानिस्टेबिलसे ऊपरके ओहदे वाले पोलिस अफसरके नाम दे देवे और इस प्रकार कब्जा लेनेके लिये दिवालियेके मकान इमारत या कमरे का दरवाजा तोड़ने का अधिकार दे सकती है जहां कि दिवालियेकी मौजूदगी का अनुमान होवे अथवा जहां पर उसकी जायदाद होने का अनुमान होवे ।

(२) जब कि अदालत को विश्वास हो जावे कि दिवालियेकी जायदाद किसी ऐसे मकान या जगहमें छिपाई गई है जो कि दिवालियेकी नहीं है तो अदालत उचित समझने पर ऊपर बतलाये हुए अफसरके नाम तलारी का वारण्ट जारी कर सकती है जो उस वारण्ट की मंशाके अनुसार कार्रवाई कर सकता है ।

व्याख्या—

मेसीडी एक्ट की १४ धारामें प्रयोग किये हुए (May) शब्द प्रकट है कि इस धाराके विषयों की प्राप्तिके लिये अदालत बाध्य नहीं है किन्तु वह अपनी इच्छानुसार समयाचित कार्रवाई कर सकती है ।

उपधका (१) में दिवालियेके मकान या कमरेमें हुमर तलारी लेने व कब्जा लेने का वट्टा है तथा उपधका (२) में दिवालियेके मकानके अतिरिक्त अन्य जगहमें पुनः तलारी लेने तथा कब्जा करनेके अधिकार का वर्णन है । इस धाराके अनुसार वारण्ट इस धराके अनुसार कार्रवाई करनेके लिये नियत किये हुए अफसरके नाम दिया जाना चाहिये अथवा ऐसे पुलिसके अफसरके नाम दिया जाना चाहिये जिसका ओहदा कानिस्टेबिलसे बड़ा होवे अर्थात् जो पनिदार, इन्स्पेक्टर आदि उस उद्योग का पुलिस अफसर होवे । वारण्ट केवल कब्जा लेने ही के लिये नहीं दिया जा सकता है किन्तु इमारत या कमरेका किबाड़ तोड़ कर पुनः व उसके अन्दर कब्जा लेने का अधिकार दिया जा सकता है । उपधका (१) के अनुसार वारण्ट मामूली तौर पर हर मामलेमें दिया जा सकता है क्योंकि दिवालियेके मकान या कमरेमें उसी की चीजोंके होने का अनुमान किया जा सकता है किन्तु उपधका (२) के अनुसार वारण्ट इसी बात दिया जासकेगा जब कि अदालत को विश्वास हो जावे कि दिवालियेकी जायदाद दरअसल किसी अन्यके मकान आदिमें छिपाई गई है वारण्ट दोनों उपधकाओंके अनुसार एका अफसरके नाम दिये जावेगे जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है तथा वह अफसर वारण्ट की मंशाके अनुसार ही कार्रवाई करेगा अर्थात् मन्सूनी न कर सकेगा नौ यह आवश्यक नहीं है कि वारण्ट की अग्रगण्यताओं की जावे अपौर वारण्ट की मंशा को समझे हुए समयाचित काम करेगा इस प्रकार इस धाराके अनुसार अदालत दिवालियेकी जायदाद पर कब्जा उसके मकान तथा अन्य जगहमें अतिरिक्त वारण्टके मकान का ताजा आदि अथ वस्तुओं की दूर करके दिया सगती है ।

धका ६० दिवालियेकी तनख्वाहका कर्जस्वाहोके लिये लिया जाना

जब कि दिवालिया फौज या जहाजी पेड़े का अफसर होवे या शाहन्शाह की हिन्दुस्थानी सामुद्रिक नौकरी में होवे या केशरीहिन्द की नौकरी में अफसर फ्लर्क या अन्य किसी प्रकार से काम करता होवे तो अफिशल पसायनी उसकी तनख्वाहका वह हिस्सा जो किसी डिक्लीमें कुर्क किया जा सकता हो तथा जिसके लिये अदालत हुक्म देवे कर्जस्वाहों में बांटे जाने के लिये ले लेवेगा ।

(२) यदि ऊपर बतलाये हुए मामलों के अतिरिक्त दिवालिया कोई तनख्वाह या आमदनी पाता होवे तो अदालत को अधिकार है कि वह दिवालिया फरार दिये जाने का हुक्म होने के पश्चात् किसी समय भी और उस समय पर जिस प्रकारका हुक्म मुनालिब समझे अफिशल

पसायनीकी अदायगीके लिये दे सकती है जिसमें दिवालिये की आमदनी या तनख्वाहका वह हिस्सा जो किसी डिमीमें कुर्क किया जा सकता हो अथवा उसका कोई हिस्सा कर्जपुत्राहोंमें बाँटे जानेके लिये आफिशल पसायनी बसूल कर सके ।

व्याख्या—

इस दफामें दिवालियेकी तनखाह तथा अन्य आयदनी के कुर्क किये जाने तथा उसके कर्जपुत्राहानमें बाँटे जानेकी व्यवस्था बतलाई गई है ।

उपदफा (१) में कौनी या जहानी बँहके अद्वार तथा सरकारी सिविल सर्विसेज अफसर या क्लर्क या दूसरे प्रकारसे काम करने वालोंके दिवालिया करार दिये जाने पर उनकी तनखाहके कुर्क किये जानेका उल्लेख है । इस उपदफाके अद्वारा इन अफसरोंकी तनखाहका बड़ा हिस्सा कुर्क किया जासकता है जो कितां डिमीमें वापस कुर्क किया जा सकता है परन्तु यह भी आवश्यक नहीं है कि उतना हिस्सा अवश्य कुर्क किया जाना चाहिये उससे कम भी कुर्क किया जासकता है किन्तु उससे अधिक कुर्क नहीं किया जाना चाहिये । अदालत जिस हिस्सेके लिये हुक्म देने बड़ी हिस्सा कुर्क होगा अदालत अपनी इच्छानुसार इसके लिये हुक्म देसकती है ।

अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे मानित होता है कि इसके नियमों की अवज्ञा नही की जाना चाहिये अर्थात् इस उपदफामें बतलाये हुए अफसरोंकी तनखाहका कुर्क किया जाने योग्य अथवा कोई हिस्सा कुर्क होकर कर्जपुत्राहानमें अवश्य बाँटा जाना चाहिये ।

उपदफा (२) में उपदफा (१) के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की तनखाह तथा आमदनीके कुर्क किये जानेका वर्णन है इसके लिये हुक्म देना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है जैसा कि अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (May) शब्द से प्रकट है इस प्रकारका हुक्म दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म होनेके पश्चात् दिया जा सकता है और उतने समयके लिये दिया जा सकता है जिनकेके लिये अदालत प्रस्तावित समझे इस उपदफाके अनुसार भी उसकी ही तनखाह या आमदनी कुर्क की जासकती है जितनी कितां इतराए डिमीमें कुर्क की जासकती है वसने अधिक नहीं किन्तु उससे कम कुर्ककी जासकती है यह आमदनी या तनखाह कुर्क होकर आफिशल पसायनी की इच्छाके मिलेगी कि वह कर्जपुत्राहानमें बाँटी जासके । इस दफाका अभिप्राय यह है कि दिवालिया स्वयं ही अपनी दिवालियेकी दशा होने पर पूरी आमदनी या तनखाहको लाभ व वट्टा इसके लिये कि उसके कर्जपुत्राहान रूपरे ही रहे किन्तु कर्जपुत्राहानों की इच्छाके अनुसार आसक्तिके लिये तनखाह आदिकी सफल में दिवालिया पावे लाभ पहुँच सके । अदालतकी इच्छा पर उस दफाके अनुसार बर्तवारा करता निर्भर है ।

दफा ६१ जायदादका एकके पाससे दूसरेके पास जाना या एकमे दूसरेको मिलना

दिवालिये की आयदाद एक आफिशल पसायनीके पाससे दूसरे आफिशल पसायनीके पास पहुँच आधेगी और आफिशल पसायनी जब तक कि वह उस हैसियतसे काम करेगा दिया-लिये का जायदादका अधिकारी होगा तथा इसके लिये किसी हन्तकाल किये जानेकी अवश्यकता न होगी ।

व्याख्या—

इस दफामें यह बतलाया गया है कि आफिशल पसायनी बिना किसी हन्तकालके अर्थात् बिना दस्तावेज आदि बिछे व रजिस्ट्री कराये दिवालिये की जायदाद का अधिकारी होगा । यदि दिवालिये की जायदाद किसी आफिशल पसायनीके अधिकारमें रहे और उस आफिशल पसायनीके स्थानमें दूसरा आफिशल पसायनी नियुक्त किया जावे या अर्थात् रूपसे कम करे तो पहिले आफिशल पसायनीके पाससे दिवालिये की जायदाद दूसरे आफिशल पसायनीके पास पहुँच आधेगी । आफिशल पसायनी

दिवालिये की जायदाद का अधिकारी उस समय तक रहेगा जब कि वह उस दिवालिये की जायदाद से लिखे आधिकार प्राप्त न रहेगा अथवा एक्ट की इस दफा में (Shall) शब्द का प्रयोग किया गया है जिससे यह प्रकट है कि इस दफा के नियमों की जायदाद आवश्यक है ।

दफा ६२ बिला लाभ की व भारी बार वाली जायदाद को छोड़ दिया जाना

(१) यदि दिवालिये की कोई जायदाद ऐसी जमीन होवे जिस पर भारी बार होवे या जो किसी कम्पनी के शेयर अथवा स्टॉक (Stock) होवे या जो बिला मुनाफे वाले मुवाहिदे होवे या इस प्रकार की जायदाद होवे जो बेची न जा सकती हो या जल्दी इस कारण न बेची जा सकती हो कि ये चने चाल पर भारी काम के करने का अथवा किसी रुपये के अदा करने का भार आजाता हो तो आधिकार प्राप्त एसायनी दिवालिया करार दिये जाने का हुक्म होने के बावजूद महीने के अन्दर ऐसी जायदाद को, उन नियमों का ध्यान रखते हुए जो आगे दिये हुए हैं छोड़ सकता है बिला इस बात का खयाल रखते हुए कि वह उस जायदाद को बेच सकता था या उस पर कब्जा ले सकता था या मालिकाना कायम करने की कोई कार्रवाई कर सकता था परन्तु शर्त यह भी है कि यदि दिवालिया करार दिये जाने का हुक्म होने के एक माह के अन्दर आधिकार प्राप्त एसायनी को ऐसी जायदाद का हक न हुआ हो तो वह उस समय से जब कि उसको हक होवे बावजूद महीने के अन्दर उस जायदाद को छोड़ सकता है ।

(२) जिस तारीख से जायदाद छोड़ी जावेगी उस तारीख से दिवालिये तथा उसकी जायदाद का सम्बन्ध हट कर जिम्मेदारी उस छोड़ी हुई जायदाद से समाप्त हो जावेगी और आधिकार प्राप्त एसायनी भी उस जायदाद के सम्बन्ध में उस वक से जाती जिम्मेदारी से बरी हो जावेगी जब से कि जायदाद उसको मिली थी । परन्तु किसी दूसरे व्यक्ति के हक पर भी इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा केवल उसना ही असर पड़ सकता है जितना सम्बन्ध दिवालिये उसकी जायदाद तथा आधिकार प्राप्त एसायनी को जिम्मेदारी से बरी करने के लिये आवश्यक होगा ।

व्याख्या—

इस दफा के अनुसार आधिकार प्राप्त एसायनी को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने ही अथवा भारी बार वाली जायदाद को छोड़ देवे इस प्रकार वह स्वयं जाती जिम्मेदारी से बच सकता है तथा दिवालिये व उसकी जायदाद को भी बचा सकता है । इस दफा के अनुसार कार्रवाई करने के लिये बावजूद महीने की अवधि बतवाई गई है परन्तु साथ साथ यह भी शर्त लगा दी गई है कि यदि दिवालिया करार दिये जाने का हुक्म होने के एक माह के अन्दर आधिकार प्राप्त एसायनी को ऐसी जायदाद का हक न होवे तो वह इस हाने पर उसके १२ माह के अन्दर उस जायदाद को छोड़ सकता है अथवा एक्ट में प्रयोग किये हुए (May) शब्दों में प्रकट है कि इस दफा के अनुसार कार्रवाई करना न करना आधिकार प्राप्त एसायनी की इच्छा पर है । यदि आधिकार प्राप्त एसायनी इस दफा के अनुसार कार्रवाई करे तो वह इस बात का दर्शा नहीं उठाया जा सकता है कि उसने जायदाद को बेचा नहीं या उसने उस पर कब्जा लेने या मालिकाना हक कायम करने की वांछ नहीं की ।

उपदफा (२) में बतलाया गया है कि जिस तारीख से ऐसी जायदाद छोड़ी जावेगी उस तारीख से दिवालिये या आधिकार प्राप्त एसायनी अथवा दिवालिये की जायदाद से उसका सम्बन्ध छूट जावेगा और इस सम्बन्ध का छूटना उसी तारीख से माना जावेगा जब कि जायदाद आधिकार प्राप्त एसायनी को मिली हो । इस उपदफा में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इस दफा के

अनुसार कार्रवाई होने पर किसी दूसरे व्यक्ति के अधिन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा केवल उतनाही प्रभाव पड़ सकता है जितना कि आदेशित एसायनी, डिवायलिये या उसकी जायदाद को बर्त करनेके लिये आवश्यक होगा अंग्रेजी एक्ट की इस उप-दफामें (Shall) शब्द का प्रयोग किया गया है जिससे यह स्पष्ट है कि इस उपदफाके नियमों की अवहेलना नहीं की जाना चाहिये ।

दफा ६३ ठेका का छोड़ा जाना

इस सम्बन्धमें बनाये हुए नियमों का ध्यान रखते हुए आफिशल एसायनी दिला अदालत की आज्ञा लिये हुए किसी ठेकेके हक को नहीं छोड़ सकेंगा और अदालत को अधिकार है कि वह इस प्रकारकी आज्ञा देनेसे पहिले अथवा आज्ञा देते समय सम्बन्धित व्यक्तियोंको जैसा नोटिस चाहे दे सकती है या आज्ञाके साथ जो शर्तें चाहें लगा सकती है और न हटाई जाने योग्य चीजों कायतकारकी बदलाई हुई चीजों तथा कायतकारीसे पैदा हुई और वार्तोंके सम्बन्धमें जैसा हुक्म मुनासिब समझे दे सकती है ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार आफिशल एसायनी अपनी इच्छानुसार किसी ठेके की या पट्टेके हक को नहीं छोड़ सकता है उसे ऐसा करनेके लिये अदालत की आज्ञा प्राप्त करना आवश्यक है जैसा कि अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है । इस दफाके अनुसार अदालत का अधिकार है कि वह आज्ञा देनेसे पहिले या आज्ञा देते समय जो शर्तें चाहे अपनी आज्ञाके साथ लगा सकती है तथा साथ ही साथ जिस जमीनके ठेके का मामला हो उस जमीन पर कालकार द्वारा बढ़ाई हुई चीजों तथा न अजहदा की जाने योग्य चीजों तथा इसी प्रकारकी अन्य बातोंके लिये जो हुक्म मुनासिब हो दे सकती है । अदालत इस दफाके अनुसार कार्रवाई करनेके लिये बाध्य नहीं है जैसाकि अंग्रेजी एक्ट की इस दफामें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है परन्तु वह अपनी इच्छाके अनुसार जसा चाहे वैसा हुक्म दे सकती है ।

दफा ६४ आफिशल एसायनी द्वारा जायदादका छोड़ाया जाना

यदि किसी जायदादसे सम्बन्ध रखने वाले किसी व्यक्तिने लिखकर आफिशल एसायनीक पास यह दखवास्त दी हो कि वह तय करे कि जायदादको छोड़ेंगा या नहीं और उसने दखवास्त साने के २८ दिनों के अन्दर अथवा अदालतकी आज्ञानुसार बढ़ाई हुई अवधिके अन्दर इस बातका नोटिस देनेसे इनकार किया हो कि वह जायदाद को छोड़ेंगा या लापरवाही की हो तो आफिशल एसायनी को दफा ६२ के अनुसार उस जायदादको छोड़नेका हक नहीं होगा । और मुवाहिदेके मामलेमें यदि आफिशल एसायनीने इसी मियादके अन्दर या अदालतकी आज्ञानुसार बढ़ाई हुई अवधिके अन्दर मुवाहिदे को नहीं छोड़ा हो तो यह मान लिया जावेगा कि उसने मुवाहिदे को मान लिया है ।

व्याख्या—

इस दफामें यह प्रकट है कि जोई जमीन योग्य जायदादमें सम्बन्ध रखने वाला व्यक्ति आफिशल एसायनीके पास इस बातके जाननेके लिये दाखवास्त दे सकता है कि वह जायदाद को छोड़ेंगा या नहीं और ऐसी दाखवास्तके आने पर आफिशल एसायनी का कर्तव्य होगा कि वह कुछ न कुछ जमान देवे और यह जमान २८ दिनोंके अन्दर दिया जाना चाहिये परन्तु यदि

जवाब देने के लिये आफिशल एसायनीने अदालतसे कोई मोहलत ले ली हो तो उस मोहलतके अन्दर जवाब देना चाहिये । यदि ऊपर मतलाई हुई मोहलतके अन्दर आफिशल एसायनी जायदाद को लेब्नेसे इन्कार करे या जवाब देनेमें लापरवाही करे अथवा कोई ठीकजवान न देवे तो यह आपन्दा उस जायदादकी नहीं छोड़ सकेगा इसी प्रकार यदि दरख्वास्त किसी मुवाहिदेके सम्बन्धमें दी गई हो और वह ऊपर मतलाई हुई मियादके अन्दर जेद न दिया जावे तो यह मान लिया जावेगा कि वह मुवाहिदा आफिशल एसायनी को मजूर है अर्थात् उसे उस मुवाहिदे को पूरा करना होगा । अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है कि इस दफाके नियमों की अवहेलना नहीं की जासकती है आफिशल एसायनी अदालतसे २८ दिनों बरतकर हुई मियादको बढ़वा सकता है परन्तु मियादके अन्दर या बड़वाई हुई मियादके अन्दर उचित उत्तर दिया जाना चाहिये ।

दफा ६५ अदालत द्वारा मुवाहिदोंके तोड़े जानेके अधिकार

यदि विधालियेके साथ किये हुए किसी मुवाहिदेके अनुसार कोई व्यक्ति आफिशल एसायनीके विरुद्ध किसी तमके उठाने का अधिकारी होवे या किसी मुवाहिदेके धारके अनुसार उस लाभके उठाने का अधिकारी होवे, तो ऐसे व्यक्तिके दरख्वास्त देने पर अदालत जैसा कि उसे उचित समझ पड़े उस मुवाहिदेके तोड़ने का हुक्म ऐसी शर्तोंके साथ दे सकती है कि किस फरीक को मुवाहिदेके अनुसार काम न करने की वजहसे कितना हर्जा देना चाहिये और इस प्रकार दिये हुए हुक्मके अनुसार जो हर्जा दिया जाने को होगा वह बतौर क़ाज़ेके दिवालिये की कार्रवाईके सम्बन्धमें साबित किया जासकता है ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार क़ाज़ाई करनेके लिये अदालत बाध्य नहीं है किन्तु उसका करना न करना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है जैसा कि अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है । इस दफाके अनुसार मुवाहिदा पूरा न करनेके कारण अदालत हर्जा दिलवा सकती है और इस प्रकार दिलवाया हुआ हर्जा नतौर बर्नेके साबित किया जासकता है । इस दफा के अनुसार करिवारे अदालत अपने आप ही नहीं करेगी किन्तु ऐसे व्यक्तिके दरख्वास्त देने पर करेगी जिसे उस मुवाहिदेसे लाभ पड़ता हो । मुवाहिदे को तोड़ने तथा हर्जा दिलाने का हुक्म सम्बोधित तथा फ़रीकके लाभ हानि का विचार रखते हुए दिया जाना चाहिये ।

दफा ६६ छोड़ी हुई जायदादके सम्बन्धमें सुपुर्दगीका हुक्म देना

(१) यदि कोई व्यक्ति जो किसी छोड़ी हुई जायदादमें अपना हक़ जाहिर करता हो या छोड़ी हुई जायदादके सम्बन्धमें जिसकी ज़िम्मेदारी न पूरी की गई हो, अदालतमें दरख्वास्त देवे तो अदालतको अधिकार है कि वह जिन लोगोंके ध्यान लेना इस सम्बन्धमें मुनासिब समझे उन्हें सुननेके बाद जायदादकी सुपुर्दगी अथवा उस पर क़ब्ज़ा लेनेका हुक्म किसी व्यक्तिके हक़में कर सकती है जिसे वह उसका अधिकारी समझे, या जिसे ऊपर मतलाई हुई ज़िम्मेदारीके कारण वह जायदाद बतौर मुआवितेके मिलना चाहिये । यह जायदाद उस व्यक्तिके ट्रस्टीको भी दी जासकती है और अदालत जो शर्तें चाहे अपने ऐसे हुक्म होनेके साथ लगा सकती है । और ऐसे हुक्म होने पर वह जायदाद बिला किसी इन्तकालके उस व्यक्तिकी हो जायेगी जिसके हक़में हुक्म दिया गया हो । परन्तु शर्त यह है कि यदि जायदाद ठंके (पड़े) के योग्य होवे तो अदालत उस जायदादकी सुपुर्दगीका हुक्म किसी ऐसे व्यक्तिके हक़में नहीं देगी जो दिवालियेकी औरसे

उसके शिकमी ठेकेदारकी हैसियतसे या मुतहिनकी हैसियतसे उस जायदादके लिये अपना हक जाहिर करता हो। लेकिन ऐसा हुक्म उन जिम्मेदारियोंके साथ दिया जासकता है जिनकी पाबन्दी दिवालिये पर उस वक्त लाजिमी रही हो जब कि दिवालियेकी दरखास्त ही गई हो और यदि कोई शिकमी ठेकेदार या मुतहिन उन शर्तोंके साथ जो अदालत लगाना मुनासिब समझे जायदाद को लेनेसे इन्कार करे तो उसका उस जायदाद पर कोई हक या जमानत नहीं रह जावेगी। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति न मिले जो दिवालिये की तरफसे अपना हक तो जाहिर करता हो परन्तु अदालत द्वारा लगाई हुई शर्तोंके साथ जायदाद को लेनेके लिये तैयार न होवे तो अदालत उस जायदादको किसी ऐसे व्यक्तिको दिये जानेका हुक्म दे सकती है जो ज्ञाती तौरसे या वारिसकी हैसियतसे अकेले या दिवालियेके साथ उस पट्टेके सम्बन्धमें पट्टेदारीके इकरारनामोंका पूरा करने का जिम्मेदार होवे और वह जायदाद ऐसे व्यक्तिको दिवालिये द्वारा पैदा किये हुए सब वार व हकोंसे साफ मिलेगी।

(२) अदालत यदि मुनासिब समझे तो ऊपर बताई हुई शर्तोंको संशोधित कर सकती है जिसमें कि उस व्यक्ति पर जिसके हकमें जायदाद मिलनेका हुक्म हुआ हो वही जिम्मेदारियाँ लागू हों जो उस वक्त होतीं जब कि पट्टा उसके हकमें दिवालियेकी दरखास्त दिये जाते समय लिखा गया हो और जैसे कि वट्टेमें बही जायदाद दिखलाई गई हो जिसका उल्लेख सुपुर्दगीके हुक्ममें किया गया है (यदि ऐसा अवसर होवे) ।

व्याख्या—

इस दफा के अनुसार कार्य करनेके लिये अदालत बाध्य नहीं है किन्तु वह अपनी इच्छाके अनुसार हुक्म देसकती है जैसा कि अमेजा एक्टका। इस दफामें प्रयोग किये हुए (May) शब्द स प्रकट है इस दफाकी योजना। इस कारण कीगई है कि यदि किसी हुई जायदादके मिलनेके लिये कोई व्यक्ति दरखास्त देवे और उस पर अपना हक या अपनी कोई जमानत आदि द्वारा पैदा हुआ अधिकार जाहिर करे तो अदालत उचित तद्कालातके बाद उसकी सुपुर्दगीका हुक्म उस व्यक्ति या अन्य किसी इकरारके हकमें कर सकती है। वह जायदाद इकरारके दुरहीरी भी दी जासकती है। अदालत इस प्रकारका हुक्म देते समय उचित शर्तें भी लगा सकती है। इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि ऐसा हुक्म देने पर जिस जायदादका शिक ज़ुबम में होवे तथा जिसके हकमें जायदाद मिलने का हुक्म होवे उसे वह जायदाद मिल जावेगी व इसके लिये किसी छुदागाना तत्काल जायदादके लिये जानेकी आवश्यकता नहीं है।

उपदफा (१) के साथ में यह भी शर्तें लगायी गई है कि इस प्रकार जायदाद दिये जानेका हुक्म दिवालियेके शिकमी पट्टेदार या मुतहिनके हकमें नहीं किया जावेगा जो ऐसा हुक्म उस दफामें दिया जा सकता है जब कि शिकमी पट्टेदार या मुतहिन उन सब जिम्मेदारियोंको बरदाश्त करे जो कि दिवालिये पर दिवालियेकी दरखास्त दिये जाने समय लागू थीं। इसी शर्त में यह भी बतला दिया गया है कि यदि शिकमी पट्टेदार या मुतहिन ऐसी शर्तोंके साथ जायदाद न लिया चाहता हो तो उसके सब हक उस जायदादसे जाने रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति अकेले ही या दिवालियेके साथ उस पट्टेके किसी इकरारनामोंका पूरा करनेका पबन्द होवे तो अदालत ऐसे व्यक्तिसे हुक्म उस जायदादको, मिलनेका हुक्म दे सकती है और उस व्यक्ति को वह जायदाद सब जिम्मेदारियों व बारात पाक व साफ मिल जावेगी।

उपदफा (२) के अनुसार अदालत को कपर बतलाई हुई शर्तोंके संशोधित करने का अधिकार भी प्राप्त है और संशोधन द्वारा जायदाद उस दफामें बतली भिन्नो जैसा कि दिवालियेकी दरखास्त दिये जाने समय वह जायदाद उसके हक

में कर दी गई हो अर्थात् केवल उसी समयकी सिम्पेदाशियां व नारबी पाषादी उस पर लागू समझी जावेगो छोटी हुई जायदाद के सम्बन्धमें इस दफ्ते अनुसार अदालत समवानुकूल हुक्म किसी भी ऐसे व्यक्ति के हक्में दे सकती है जो दाजसल उस जायदादकी पति का अधिकारी समझा जावे तथा शक्ति शर्त भी अपने हुक्मके साथ छूटा सकती है और ऐसा हुक्म होने पर इत्तफाक जायदादकी कर्तव्य अर्थात् दस्तावेजोंके लिखे जाने पर उनके रजिस्ट्री किये जानेकी आवश्यकता भी जाती रहेगी ।

दफा ६७ छोटी हुई जायदादसे जिसे हानि पहुंचती हो वह साबित कर सकता है

यदि ऊपर बतलाए हुए नियमोंके अनुसार किसी जायदादके छोड़े जाने पर किसी व्यक्ति को हानि पहुंचती होये तो वह व्यक्ति दिवालियेका कर्जखवाह उस तादादके लिये समझा जावेगा जिसकी उसे हानि हुई हो और इसीलिये वह उस तादादको यतौर कर्जके दिवालियेकी कर्तव्य के सम्बन्धमें साबित कर सकता है ।

व्याख्या—

अंशजा एकटरी इस दफ्तेमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है कि इस दफ्तेके नियमोंकी अवहेलना नहीं की जाना चाहिये । यदि किसी जायदादके छोड़े जानेसे किसी व्यक्ति को हानि पहुंचती हो तो वह अपनी हानिको दिवालिये की जायदादसे उसी प्रकार वसूल कर सकता है जैसे कि और कर्ज उस जायदादसे वसूल किये जासकते हैं और वह और कर्जस्थानों की भांति अपने इस कर्ज को साबित कर सकता है ।

दफा ६८ जायदादकी वसूलीमें आफिशल एसायनीके कर्त्तव्य व अधिकार

(१) इस एकटमें बतलाये हुए नियमोंका ध्यान रखते हुए आफिशल एसायनी सहायितक साथ जितनी जल्द हो सकेगा दिवालियेकी जायदादको वसूल करेगा और उस सम्बन्धमें वह निम्नलिखित कार्यों को कर सकता है:—

(ए) दिवालिये की सब जायदाद या उसके किसी हिस्से को बेंच सकता है ।

(बी) जो रुपया वह वसूल करे उसकी रसीद दे सकता है तथा वह अदालतकी आज्ञा लेकर नीचे दिये हुए सब कामोंको या उनमेंसे किसी कार्यको कर सकता है ।

(सी) दिवालियेके कारोबारको उस हद तक चालू रख सकता है जिस हद तककि दिवालिये के कामको समेटनेके लिये आवश्यक प्रतीत होवे ।

(डी) दिवालियेकी जायदादके सम्बन्धमें मुकदमा या कोई दूसरी क्रानून कारवाई चालू कर सकता है या उसमें अबाधदेही कर सकता है या उसे चालू रख सकता है ।

(ई) अदालत द्वारा इजाजत दिये हुए काम या कारवाई को करनेके लिये किसी वकील या दूसरे एजेंट को नियुक्त कर सकता है ।

(एफ) किसी जायदादकी कीमतमें भविष्यमें मिलने वाला वह रुपया मंजूर कर सकता है जो किसी लिमिटेड कम्पनीके पूरे अदाकिये हुए शेअर्स अथवा डिबेंचरके सम्बन्ध में या डिबेंचर स्ट्राकके सम्बन्धमें मिलना चाहिये परन्तु उन शर्तोंके साथ जो अदालत लगाना मुनासिब समझे ऐसे सौदेको कर सकता है ।

(जी) दिवालिये के काजों को चुकाने के लिये अथवा उसके कारोबार को चालू रखने के लिये दिवालिया की जायदाद को या उसके किसी हिस्से को रهن कर सकता है या गिरवी रख सकता है ।

(एच) किसी भगड़े को पंच फैसले के लिये सुपुर्दे कर सकता है और सब कर्जों, दावों व जिम्मेदारियों को तय शुद्ध शर्तों के साथ तय कर सकता है ।

(आई) यदि कोई जायदाद अपनी मूल स्थिति के कारण अर्द्धी व फायदे के साथ बँबी न जा सकती हो तो उसको उसी शर्तों में उसकी कीमत का अन्दाजा लगा कर दिवालिये के कर्तव्यार्थों में बाँट सकता है ।

(२) आफिशल एसायनी अदालत को अपना हिसाब समझावेगा और निर्धारित नियमों के अनुसार अथवा अदालत के आदेशानुसार सब रुपया अदा करेगा तथा सब जमानतों के सम्बन्ध में कारवाई करेगा ।

न्यायका—

आफिशल एसायनी कपड़ों (१) के अनुसार दिवालिये की जायदाद को जितनी जल्दी हो सकेगा बमुक्त करने के लिये चाय है अर्थात् कि अंग्रेजी एक्ट की इस कपड़ों में प्रयोग किये हुए (Shall) शब्द से प्रष्ट है इस कपड़ों में यह भी बदलाया गया है कि जायदाद बमुक्त करने के लिये वह कुछ काम बिना अदालत की आज्ञा किये हुए जिस प्रकार चाहे कर सकता है जिनका उल्लेख कानून (ए) व (बी) में है तथा कुछ काम अदालत की आज्ञा लेने पर कर सकता है जिनका जिक्र कानून (सी), (डी), (ई), (एफ), (जी), (एच) व (आई) में है जायदाद को या उसके किसी हिस्से को बँचने का काम तथा बमुक्त किये हुए बचपों की रसीद देने का काम वह बिना अदालत की आज्ञा के कर सकता है परन्तु कानून (सी) के अनुसार वह दिवालिये की कारोबार चालू रखने का काम आज्ञा लेने पर कर सकता है । इसी प्रकार मुकदमों का व अधाली काम वह आज्ञा लेने पर कर सकता है । कानून (डी) में सब प्रकार के अदालती कामों का एक प्रकार से बर्णन दिया हुआ है अर्थात् यदि कोई कारोबार दिवालिआ करार दिये जगते समय कर रहा हो तो आफिशल एसायनी उसे चालू रख सकता है तथा दूसरे हुए मामलों में जवाबदेही कर सकता है व उसे आदालत चालू कर सकता है ।

फलाज (सी) व (डी) में बतलाये हुए कामों में कामें रूप में परिष्कृत करने के लिये वह अदालत की आज्ञा लेकर कानून (ई) के अनुसार बकील या अन्य एग्जैटो को नियुक्त कर सकता है ।

फलाज (एफ) के अनुसार किसी जायदाद की उन शेअर्स आदिके एवज में भी बँच सकता है जिनका बचपा प्रतियोग में मिलने बाका होवे परन्तु ऐसा करते समय अदालत द्वारा बतलाई हुई अधातव आदि की शर्तों का प्यान रखना चाहिये ।

फलाज (जी) के अनुसार अदालत की आज्ञा लेने पर दिवालिये की जायदाद रहन की जा सकती है तथा वह गिरवी रखी जा सकती है जिसमें बचपा बमुक्त होने पर कर्जें चुकाने जाते हैं या कारोबार चालू रखा जायके ।

फलाज (एच) के अनुसार पंच फैसला व बाइयो तारते तरफिया करने का अधिकार प्राप्त है लेकिन अदालत की आज्ञा लेने पर ही ऐसा किया जावेगा ।

फलाज (आई) के अनुसार अदालत की आज्ञा लेने पर न बँबी जाने योग्य जायदाद को उसकी मौजूदा शर्तों में रूईल्वारों में बाँट सकता है ।

उपदफा (१) में यह बतलाया गया है कि निर्धारित नियमोंके अनुसार जज या अदालतके आदेशके अनुसार आफिशल एसायनी अदालतमें हिस्सा सम्प्राप्तिगा व रुपये जमा करेगा तथा जमाननोंमें बसूल करेगा । अमेजी एक्टमें शिरे हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है कि इस उपदफाके नियमोंकी पारबन्धी आवश्यक है उनमें अवहेलना नहीं की जा सकती है ।

जायदादका बांटा जाना

धफा ६९ हिस्सा रसदीका ऐलान व उनका बांटा जाना

(१) आफिशल एसायनी जितनी जरूरी सहूलियतके साथ हो सकेगा हिस्सा रसदीका ऐलान करके उसे उन कर्जव्याहोंमें बांटेगा जो अपना कर्ज साबित कर चुके हैं ।

(२) पहिला हिस्सा रसदी (यदि कोई होगा) विवालिया करार दिये जानेका हुक्म होनेके पश्चात् एक सालके अन्दर ऐलान करके बांटा जावेगा यदि आफिशल एसायनीने पर्याप्त कारण दिखला कर अदालतको यकीन दिलाकर समय ऐलानके लिये बढ़ाया न लिया हो ।

(३) इसके बाद घाले हिस्सा रसदी यदि कोई बजह इसके विरुद्ध न दिखलाई गई हो तो वह छः छः महीनेसे ज्यादाका बीच न डालकर बांटे जावेगा ।

(४) हिस्सा रसदीका ऐलान करनेसे पहिले आफिशल एसायनी इस इच्छाका नोटिस निर्धारित दंग पर प्रकाशित करेगा और उसका उचित नोटिस विवालियेकी फेहरिस्तमें दिखलाये हुए उन हर एक कर्जव्याहोंके पास भेजेगा जिन्होंने अपना कर्ज साबित नहीं किया है ।

(५) जब कि आफिशल एसायनीने किसी हिस्सा रसदीका ऐलान किया हो तो वह उन कर्जव्याहोंके पास जिन्होंने अपना कर्ज साबित कर दिया हो इस बातकी सूचना भेजेगा कि उनको कितना हिस्सा रसदी मिलेगा और कब व किस प्रकार दिया जावेगा और यदि कोई कर्जव्याह चाहेंगा तो उसको निर्धारित रूपमें विवालियेकी जायदादका न्योरा भेजा जावेगा ।

व्याख्या—

अमेजी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है कि इस दफाके नियमोंकी पारबन्धी आवश्यक है तथा उनकी अवहेलना आफिशल एसायनी की नहीं करना चाहिये ।

उपदफा (२) में ज. मर्हनेके लगभग एक सालकी अवधि पर दी गई है यह संशोधन प्रेसीडेन्सी टाउन्स इन्स्टीट्यूट एक्ट १९२९ ई० एक्ट नं० ३ के अनुसार किया गया है जिसको गवर्नर जनरल हिन्दी स्वीकृति २९ मार्च सन् १९२९ ई० को प्राप्त हुई थी । इस संशोधित एक्टके अनुसार दिखलिया करार दिया जाने का हुक्म होनेके पश्चात् एक सालके अन्दर पहिला हिस्सा रसदी घोषित किया जावेगा जब तक कि अदालतकी कोई पर्याप्त कारण इस अवधिके बढ़ानेके लिये न दिखाया जावे तबसे पहिले पूरा एक्टके अनुसार पहिला हिस्सा रसदी छः मर्हनेके अन्दर बांटा जानेका नियम था । हिस्सा रसदी जहाँ कर्जव्याहोंमें बांटा जावेगा जिन्होंने अपना कर्ज साबित कर दिया हो दूसरे कर्जव्याहों की नहीं चाहे उनका नाम कर्जव्याहों की फेहरिस्तमें दिखलाया गया हो ।

विवालिया करार दिया जाने का हुक्म होनेके पश्चात् पहिले हिस्सा रसदी का ऐलान छः मर्हनेके अन्दर किया जाना आवश्यक है यदि इसके विरुद्ध अदालतकी कोई आज्ञा न छे ली गई हो तबसे आफिशल एसायनी पर्याप्त कारण दिखलाकर

अदालतसे समय बढा सक्ता है । इसके बाद बाहे हिस्सा रसदी भी छ छ महीनेके अवकाशमे बाटे जाय चाहिय इसमे अधिक अवकाश उनक बटे जानये न पटना चाहिये जब तब कि इसके विपक्ष कोई अज्ञा अदालत द्वारा न दी गई हो ।

उपदफा (४) में आदिशक्त एसायनीके लिये यह वचन आवश्यक है कि वह हिस्सा रसदीके ऐलानकी सूचना निर्धारित रूपसे प्रकाशन कर देवे तथा ऐसे कर्जदारों को भी उचित रूपसे सूचना दे देवे जिनका नाम कर्जखानाहोकर फिहरिमें आया हो परंतु नि होने अन्ता कर्ज साबित न किया हो ।

उपदफा (५) के अनुसार आदिशक्त एसायनी का यह कर्तव्य होगा कि वह हिस्सा रसदी का ऐलान करने पर इन कर्जखानों को जिनहोंने अपना कर्ज साबित कर दिया हो इस बातकी सूचना देवे कि उनकी किन्ता हिस्सा रसदी मिलेगा तथा वह वचन व किस प्रकार दिया जावेगा इसी उपदफामे यह भी बतलाया गया है कि यदि कोई कर्जखाना यदि तो वह अधिकशक्त एसायनीसे दिवालयके जायदादकी तफ्तील माग सकता है और उसके मागने पर निर्धारित रूपमें वह तफ्तील उसको मिल जावेगी ।

दफा ७० संयुक्त तथा अलगकी जायदाद

यदि किसी कर्म का एक शरीकदार दिवालय कसम दिया जावे तो वह कर्जखाना जिसका कर्ज दिवालियेको फर्मके सब शरीकदारों अथवा उनमेंसे किसी शरीकदारके साथ चुकाना हो, उस वक्त तक दिवालियेकी अलहदाकी जायदादसे अपना कर्जसूल करनेका हक्कदार नहीं होगा जबतक कि दिवालियेकी अलहदाकी जायदादसे उसके जुदागाना का पूर्णरूपसे न मुकायम हो ।

व्याख्या—

इस दफाके अन्तर्गत हा अर्थात् जुदागाना कर्ज पहिले उसकी जुदागाना जायदादसे चुकाये जावेगे तब उसकी जायदाद बेचने पर उसके मयूक्त कर्ज चुकाये जा सकेंगे । इस प्रकार फर्मका कर्जखाना उस वक्त तक फर्म एक शरीकदार का जुदागाना जायदादम फर्मका कर्ज बसूत नहीं कर सकता जब तक कि उसके जुदागाना कर्ज पूर्ण रूपसे न चुकाये जा सकेंगे । अग्रेजी एन्टर्मी इस दफा में (Shall) शब्द का प्रयोग किया जाता है जिससे यह अर्थ है कि इसके नियमोंकी पालनी आवश्यक है ।

दफा ७१ हिस्सा रसदीका अन्दाजा लगाया जाना

(१) हिस्सा रसदी लगाने व उनको बाँटनेसे पहिले आदिशक्त एसायनी निम्नलिखित कामोंके लिये पर्याप्त धन अपने हाथमें रोक लेवेगा:—

(ए) उन कर्जोंके लिये जो दिवालियेकी कार्रवाईके सम्बन्धमें साबित किये जासकते हैं तथा जिनके लिये दिवालियेके बयानों अथवा अन्य प्रकारसे यह साबित होय कि वह ऐसे लोगोंके हैं जो इतनी दृढ़की जगह पर रहते हैं कि मामूली सौर पर खबर भेजे जाने पर उनको पर्याप्त अवसर अपना कर्ज साबित करनेके लिये न मिल सका हो ।

(बी) यह कर्ज जो दिवालियेकी कार्रवाईके सम्बन्धमें साबित किये जासकते हैं तथा जिनका दावेका मसला तब नहीं हुआ है ।

(सी) यह सुझत व दावे जिनका विरोध किया गया हो ।

(डी) जायदादके प्रवचन तथा दूसरे मामलोंके खर्चके लिये जो आवश्यक सूच्य होवे ।

(२) उपदफा (१) के नियमोंका ध्यान रखते हुए वह सब रुपया जो हाथमें होगा बतौर हिस्सा रसदीके बांटा जावेगा ।

व्याख्या—

उपदफा (१) में बतलाया गया है कि हिस्सा रसदी बांटेसे पहिले आफिशल एसायनी क्राउ (ए), (बी) (सी) व (डी) में बतलाये हुए कामोंके लिये रुकवा रोक कर हिस्सा रसदी बांटेगा । अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है कि आफिशल एसायनीको सब क्राजोंमें बतलाये हुए कामोंके लिये पर्याप्त धन रोक लेना आवश्यक है ।

फलाज (ए) के अनुसार यदि किसी कर्जखवाहको अपना कर्ज साबित करनेके लिये पूर्ण अवकाश न मिला हो तो ऐसे कर्जखवाहके कर्जके अन्दाजेसे कगवा रोक लेना चाहिये ।

फलाज (बी) व (सी) के अनुसार झगड़के कर्जोंके सम्बन्धमें भी रोक लेना चाहिये । जायदादका इतनाम करनेमें जो खर्च आवश्यक पड़े उसके लिये भी रुपया रोका जासकता है ।

उपदफा (२) के अनुसार ऊपर बतलाये हुए कामोंके लिये रुपया रोक लेनेके पश्चात् बाकी जो रुपया बचे वह सब हिस्सा रसदीके तीर पर कर्जखवाहोंमें बांट दिया जाना आवश्यक है अर्थात् वसूले और कुछ नहीं रोका जासकता है ।

दफा ७२ उस कर्जखवाहका हक जिसमें हिस्सा रसदीके ऐलानसे पहिले, अपना कर्ज साबित न किया हो

यदि किसी कर्जखवाहने किसी हिस्सा रसदीके ऐलानसे पहिले अपना कर्ज साबित न किया हो तो वह उस बाकी बचे हुए रुपयेसे हिस्सा पावे या जो उस समय आफिशल एसायनीके हाथ में होवे तथा जिससे भविष्यमें हिस्सा रसदी बांटा जानेको होवे तथा जो पहिले उसको नहीं मिल सकता था परन्तु उसका कर्ज साबित किये जानेसे पहिले जो रुपया बांटा जा चुका हो उसमें किसी तरहकी गड़बड़ी उसके कारण नहीं पड़ सकेगी ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार उन कर्जखवाहों की भी हिस्सा रसदी मिल सकती है जो बादमें अपना कर्ज साबित करें परन्तु इस सम्बन्धमें यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि ऐसे कर्जखवाह का कर्ज साबित होनेसे पहिले जो हिस्सा रसदी बांटा जा चुका हो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं की जासकता है किन्तु उसका कर्ज साबित होनेके बाद जो रुपया बांटा जावेगा उसमें उसकी हिस्सा रसदी मिलसकेगी । इस दफा का तात्पर्य यह स्पष्ट करना चाहिये कि यदि कोई रुपया बांटा जानेसे पहिले किसी कर्जखवाहने अपना कर्ज साबित कर दिया हो तो वह उस रुपयेमें हिस्सा रसदा पाने का हकदार होगा । इस दफाकी योजना भी आवश्यक है ।

दफा ७३ अन्तिम हिस्सा रसदी

(१) जब कि आफिशल एसायनीने दिवालियेकी सब जायदाद वसूल करली हो या उसका उसना हिस्सा वसूल कर लिया हो जितना उसकी रायमें, बिला फिजूलकी बेर कार्रवाईमें किये हुए, वसूल किया जा सकता है तो वह अदालतकी आज्ञा लेने पर अन्तिम हिस्सा रसदीका ऐलान करेगा परन्तु ऐसा करनेसे पहिले वह निर्धारित ढंग पर उन लोगोंको नोटिस देवेगा जिनके कर्जखवाह होनेकी सूचना उनको दी जा चुकी है लेकिन उन्होंने अपना कर्ज साबित नहीं किया है कि

यदि वह अदालतके सम्मुख संतोष जनक रूपमें अपना कर्ज नोटिसमें दी हुई मियादके अन्दर साबित न कर दंगे तो उनके दावेका बिला लिहाज किये हुए अन्तिम हिस्सा रसदी बांट दिया जावेगा।

(२) इस प्रकारकी दी हुई मियादके समाप्त होने पर अथवा यदि किसी दावेदारकी दरखास्त पर उसको अवकाश दे दिया गया हो तो उस अवकाशकी समाप्त होने पर दिवालीयकी जायदाद उन कर्जखानोंके दायियां बांट दी जावेगी जिन्होंने अपना कर्ज साबित कर दिया हो और अन्य लोगोंके दावोंका उस समय कोई भी ख्याल न रखना जावेगा।

व्याख्या—

हाल दफाके अनुसार अन्तिम हिस्सा रसदी बांटे जानेसे पहले उन कर्जखानों को जिन्होंने अपना कर्ज साबित नहीं किया हो एक मौका मिलेगा अपना कर्ज साबित करनेके लिये दिवालीय और यदि उससे भी वह छीप लाभ न उठाया जाये अपितु नोटिसमें दी हुई मियादके अन्दर कर्ज साबित न करें तो वह किसी हिस्सा रसदीके पानेके हकदार नहीं होंगे। अंग्रेजी पुरटरी इस दफामें प्रयोग लिये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है कि इस दफाके नियमों की अवहेलना नहीं की जानी चाहिये।

उपदफा (१) से यह भी प्रकट है कि नोटिसमें दी हुई मियादके अन्तिम यदि कोई व्यक्ति मोहूत किया जाये तो उसे अत्यन्त मोहूत दे सकती है परन्तु मियाद या मोहूतके अन्दर यदि कोई कर्ज साबित न किया जावे तो बिल्कुल उसका लिहाज लिये हुए अन्तिम हिस्सा रसदी उन कर्जखानोंके दायियां बांट दिया जावेगा जिन्होंने अपना कर्ज साबित कर दिया हो। इस दफाके अनुसार लिये हुए नोटिसमें यह दिखाना देना चाहिये कि इस मियादके अन्दर तुमको कर्ज साबित कर देना चाहिये वरना बिना लिहाज तुम्हारे कर्जके अन्तिम हिस्सा रसदी बांट दिया जावेगा।

उपदफा (२) में यह साफ का दिया गया है कि मियादके या बढ़ाये हुए समयके अन्दर कर्ज साबित न किया जाने पर अन्तिम हिस्सा रसदी बांट दिया जावेगा।

दफा ७४ हिस्सा रसदीके लिये कोई दावा नहीं हो सकता

आफिशियल एसायनीके विरुद्ध हिस्सा रसदीके लिये कोई दावा नहीं किया जावेगा परन्तु यदि आफिशियल एसायनी किसी हिस्सा रसदीके चुकानेसे इनकार कर दंगे तो उस कर्जखानेके दरखास्त देने पर जिसे इस इनकारसे हानि पहुँचती हो अदालत आफिशियल एसायनीको उसके कर्ज करनेके लिये हुक्म दे सकती है और उससे रोक हुए समयके लिये विधायित की हुई दरसे खुद तथा दरखास्तके सम्बन्धमें किया हुआ खर्च दिलाया जावेगा।

व्याख्या—

आफिशियल एसायनीके विरुद्ध हिस्सा रसदीके लिये कोई उदात्ताना दावा नहीं किया जा सकता है किन्तु अदालतने दरखास्त इस बातकी सूचना देती है कि उसने हिस्सा रसदी नहीं दिया है ऐसी दरखास्तके आगे पर अत्यन्त आफिशियल एसायनीसे वह बचता दिया जा सकता है तथा ऐसे हुए सबबोंसे खुद व दरखास्तका खर्च भी इल्का करती है। अदालत इस प्रकार का हुक्म देतेके लिये तथ्य नहीं है जैसा कि अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग लिये हुए (May) शब्दसे प्रकट है किसी प्रकारका हुक्म देना न देना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है।

दफा ७५ दिवालिये द्वारा जायदादका इन्तज़ाम कराया जाना तथा उसे उसके एवज़में श्रम फल मिलना

(१) निर्धारितकी हुई शर्तोंका ध्यान रखते हुए आकिशल एसायनी स्वयं दिवालियेको उसकी जायदाद या उसके किसी हिस्सेका प्रबन्ध करनेके लिये नियुक्त कर सकता है या उसके द्वारा उसका व्यापार कर्जद्वारा करनेके लाभार्थ कर सकता है या उससे उसकी जायदाद के प्रबन्धमें और तरहसे सहायता अपनी वतलाई हुई शर्तोंके अनुसार ले सकता है ।

(२) ऊपर लिखी हुई शर्तोंका ध्यान रखते हुए अदालत समय समय पर उस जायदादसे जैसा उसे नुनासिय समझ पड़े दिवालियेको गुज़ारा उसके तथा उसके परिवारकी परधरिशके लिये या उसके कामके मुचायजिके तौर पर दिला सकती है यदि उससे उसकी जायदादके समेटनेमें सहायता ली जावे परन्तु इसक्रिस्मका गुज़ारा किसी समय भी बढ़ाया घटाया या बन्द किया जासकता है ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार दिवालियेसे स्वयं आवश्यकता पड़ने पर उसकी जायदाद या रोजगारके प्रबन्धमें सहायता ली जासकती है अदालत उसकी इस कामके एवज़में बतौर गुज़ारा उसकी जायदादसे कुछ रुपया दिला सकती है परन्तु इसका दिल नान दिखाना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है तथा वह जब चाहे उसे बन्द कर सकती है अथवा घटा बढ़ा सकता है दिवालियेको नाम दिया जावेगा वह उसके कर्जद्वाराके लाभार्थ श्रम आकरगा वह स्वयं केवल अदालत द्वारा दिलावाग हुए खर्चों की के पाने का हकदार होगा । आकिशल एसायनी की इच्छा पर दिवालियेसे बात ऐना न छना निर्भर है जैसा कि अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है ।

दफा ७६ बचे हुए हिस्सेके पानेका हकदार दिवालिया है

यदि कर्जद्वाराहोंका सब रुपया मय सूदके जैसा कि इस एक्टमें बतलाया गया है चुका दिया जावे तथा इसके अनुसारकी हुई कार्यवाहियोंका खर्च चुका दिया जावे तो दिवालिया बचा हुआ रुपया पानेका हकदार होगा ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार यदि सब कर्जद्वाराहोंका रुपया मय सूदके अदा हो चुके तथा दिवालियेके सम्बन्धमें की हुई कार्यवाहियोंका खर्च भी चुकाया जाचुके आर इसके बाद भी दिवालियेकी जायदादमें कुछ बचे तो वह बचा हुआ हिस्सा दिवालिये की मिलेगा अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है कि इस दफाके नियमों पारन्दी आवश्यक है तथा उसकी अवहेलना नहीं की जावेगी ।

चौथा प्रकरण



आफिशल एसायनी

दफा ७७ दिवालियेकी जायदादके लिये आफिशल एसायनीकी नियुक्ति तथा उसका हटाया जाना

(१) फोर्ट विलियम (कलकत्ता), बम्बई व मद्रास हाईकोर्टके चीफ जस्टिस तथा लोअर वर्माके चीफ कोर्टके चीफ जजको अधिकार है कि वह अपनी अपनी अदालतके लिये मुस्तकिल तौरसे अध्यापक या काम मुकाम तौरसे दिवालियेकी जायदादके लिये उपयुक्त व्यक्तिको आफिशल एसायनी नियुक्त कर दें और यदि कोई पर्याप्त कारण मालूम हो तो और जजोंके सहमतके साथ किसी व्यक्तिको जो उस अगह काम करता हो अलग हटा कर दें।

(२) प्रत्येक आफिशल एसायनी निर्धारितकी हुई जमानत देवेगा तथा उसको उन नियमों की पाबन्दी करना पड़ेगी व वह काम करना पढ़ेगा जो उसके लिये निर्धारित किये गये हों।

(३) यदि इन्डियन इन्साल्वेन्सी एक्ट १८५८ के अनुसार कलकत्ता बम्बई और मद्रासमें कोई व्यक्ति कर्जदारोंके हुदकारे के लिये मुस्तकिल तौरसे या कायम मुकाम तौर पर आफिशल एसायनीकी जगह पर काम करता हो या लोअर वर्माके चीफ कोर्टमें सन् १९०० ई० के लोअर वर्मा कोर्टल एक्टके अनुसार उस प्रकारसे काम करता हो तो वह व्यक्ति बिना दुधारा नियुक्तिके मुस्तकिल या कायम मुकाम आफिशल एसायनी जैसा कि मामला हो इस एक्टके अनुसार कलकत्ता बम्बई व मद्रास हाई कोर्टों तथा लोअर वर्माके चीफ कोर्टके लिये हो जावेगा और उस बहू उपदफा (१) से कोई छकावट न पड़ेगी।

ट्यारया—

कलकत्ता, बम्बई व मद्रास हाईकोर्टके चीफ जस्टिस तथा लोअर वर्माके चीफ कोर्टके चीफ जजके इस दफाके अनुसार आफिशल एसायनी की नियुक्ति सम्बन्धमें अधिकार प्राप्त है। पातु इस दफाके अनुसार कार्य करनेके लिये यह हीन बाध्य नहीं है किन उसका करना न करना उनकी इच्छा पर निर्भर है जैसा कि अप्रती एम्बवा उपदफा (१) में प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है। इस उपदफाके अनुसार आफिशल एसायनी की नियुक्ति मुस्तकिल तौरसे की जा सकती है अथवा वह कायम मुकाम तौर पर ही नियुक्त किया जा सकता है इस उपदफाके अनुसार नियुक्त किया हुआ आफिशल एसायनी अलग हटा भी किया जा सकता है परन्तु इस सम्बन्धमें यह बात बर्दाद ध्यानमें रखने की है कि चीफ जस्टिस या चीफ जज अपने ही उस अपने आप अलग हटा नहीं करेगा किन्तु वह अपनी अदालतोंके और जजों का मत लेवगा और उनके बहुमतसे सदैम होकर आफिशल एसायनी को अलग हटा कर सकता है किसी पर्याप्त कालक उपरिगत होने पर ही नियुक्त किये हुए आफिशल एसायनीका हटाया जाना चाहिये।

उपदफा (२) में बताया गया है कि आफिशल एसायनी का कर्तव्य होगा कि यदि उसमें जमानत मांगी जावे तो वह मांगा हुई जमानत दायित्व की इसी प्रकार उस निर्धारित किये हुए नियमोंकी पाबन्दी करना पड़ेगी तथा निर्धारित

किये हुए काम करना पड़ेगा। इस दफ्ते के नियमों की अवहेलना नहीं की जाना चाहिये जैसा कि अमेजी एक्ट की इस उपदफ्ते में प्रयोग किये हुए (Shall) शब्द से प्रकट है।

उपदफा (३) के अनुसार पेशरसे कानूनन नियुक्त किया हुआ आफिशल एसायनी अपनी जगह पर बसतुर काम करता रहेगा अर्थात् उसके द्वारा नियुक्त किये जाने की आवश्यकता नहीं है। इस दफ्ते में प्रयोग किये हुए (Shall) शब्द से प्रकट है कि इस उपदफ्ते के नियमों की भी अवहेलना नहीं की जाना चाहिये।

दफा ७८ हलफ देनेके अधिकार

आफिशल एसायनीको अधिकार है कि यह हलफनामोंके लिये व सुवृत पिटीशन तथा इस एक्टकी अन्य कार्यवाहियोंके सम्बन्धमें ठस्दीक इवारतके लिये हलफ दे सकता है।

व्याख्या—

इस दफ्ते के अनुसार आफिशल एसायनी को हलफ देनेके अधिकार प्राप्त है। अमेजी एक्ट की इस दफ्ते में प्रयोग किये हुए (May) शब्द से प्रकट है कि उसका देना न देना उसकी इच्छा पर निर्भर है तथा हलफ अदालत व अन्य अधिकार प्राप्त व्यक्तियों द्वारा भी दी जा सकती है।

दफा ७९ दिवालियेके व्यवहारके सम्बन्धमें कर्त्तव्य

(१) आफिशल एसायनीके कर्त्तव्य दिवालियेके व्यवहारके सम्बन्धमें तथा उसकी जायदादके प्रबंधके सम्बन्धमें होंगे।

(२) आफिशल एसायनीके कर्त्तव्य विशेष कर निम्न लिखित होंगे :—

(ए) यह कि दिवालियेके व्यवहारके सम्बन्धमें तहकीकात कर और बहाल किये जानेकी दरखास्त आनेपर रिपोर्ट दाखिल करे जिससे मालूम होसके कि आया दिवालियेने इस एक्टके अनुसार अथवा ताजीरात हिन्दीकी दफा ४२१ से लगाकर ४२४ तकका कोई जुर्म तो दिवालियेकी कार्यवाईके सम्बन्धमें नहीं किया है या कोई ऐसा काम तो नहीं किया है कि जिसकी वजहसे अदालत बहाल किये जानेका हुक्म देनेसे इनकार कर देवे, रोक देवे, या उसके साथ कोई शर्तें लगा देवे।

(बी) दिवालियेके व्यवहारके सम्बन्धमें उन बातोंकी रिपोर्ट दाखिल करे जो अदालत मांगे या जो निर्धारितकी गई हों।

(सी) घोखा देने वाले दिवालियेके चालानके सम्बन्धमें भाग लेवे तथा यह काम करे जिसके करनेके लिये अदालत हुक्म देवे या जो निर्धारित किये गये हों।

व्याख्या—

इस दफ्ते के अनुसार आफिशल एसायनी का कर्त्तव्य केवल दिवालिये की जायदादके प्रति नहीं है किन्तु उसका कर्त्तव्य दिवालियेके व्यवहार पर भी ध्यान रखने का है तथा दोनोंके लिये रॉरिवार्द करने का है। अमेजी एक्ट की इस दफ्ते में प्रयोग किये हुए (Shall) शब्द से प्रकट है कि इस दफ्ते के नियमों की अवहेलना नहीं की जाना चाहिये।

उपदफा (२) में आकिशल एसायनी द्वारा ज्ञात काम विशेष रूपसे निर्दिष्ट जाना चाहिये उनका वर्णन प्रान्त (ए), (बी) व (सी) में किया गया है ।

क़लाज़ (ए) व अनमल आकिशल एसायनी को चाहिये कि वह विशालियके व्यवहारका तदनुसार करे और जब उसका बहाल किया जानका दूरवाकान आने तक वह उसके व्यवहारक नाममें अपना निपट अंगुलीमें दाखल करे जिससे बाहिर हो कि उसने कोई काम या नहीं किया हुआ यदि ऐसा काम तो नहीं किया है जिसके कारण वह बहाल न किया जावे या उसका बहाल किया जाना सुनवी कर दिया जान अवका यदि शर्तें नहानक हुक्मके साथ लगा दा जावें ।

क़लाज़ (बी) के अनुसार यदि अंगलत चाह तो आकिशल एसायनीमें दिवालिघके व्यवहारके सम्बन्धमें और बातोंक बारेमें रिपोर्ट माग सकता है ।

क़लाज़ (सी) में बतलाया गया है कि यदि दिवालिघा घोषाद्वारासे काम करने का दोष हो और उसक विच्छा काई कोईबाई कीजाव ता आकशाय एसायनी वा उसम भाग लना चाहिये तथा अंगुलीमें निक्ष प्रसारका सहायता इस सम्बन्धमें उससे चाही ल सकती है ।

दफा ८० कर्ज़रवाहोंकी फिहरिस्त दाखिल करनेका कर्त्तव्य

यदि कोई कर्ज़रवाह बन्दे तथा वह निर्यातिलकी हुई फीस दाखिल करे तो आकिशल एसायनी उस कर्ज़रवाहको कर्ज़रवाहोंकी फिहरिस्त देगा तथा उसे बजसिये डाक रखाना करेगा और उस फिहरिस्तमें वह कर्ज़री दिखलाये जायेंगे जो प्रत्येक कर्ज़रवाहको मिलना चाहिये ।

व्याख्या—

अंग्रेजी एक्ट में इस दफा (Shall) शब्दका प्रयोग किया गया है जिससे यह सन्नि है कि आकिशल एसायनी का किसी कर्ज़रवाहका दूरवाकान जान पर तथा बदिन फीस दाखिल कर देने पर कर्ज़रवाहोंका फिहरिस्त अवश्य दाा चाहिये तथा इस दफाके निषेधकी अवहत्या न हो जाना चाहिये । जिसमें कर्ज़रवाहोंके कर्ज़री भी तफ़्फ़ील दी जाना चाहिये ।

दफा ८१ श्रमफल (मेहनतकी फीस)

(१) आकिशल एसायनी उस श्रमफल (Remuneration) को पावगा जो इसके लिये निश्चित किया गया हो ।

(२) आकिशल एसायनी उपदफा (१) में दिखलाये हुए श्रमफलके अतिरिक्त और कोई श्रमफल इस रूपमें नहीं पावगा ।

व्याख्या—

इस दफाक नियमोंका भी अंग लगा नहीं हो जाना चाहिये जसा कि अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किए हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है । आकिशल एसायनीका श्रमफल प्रकृत उसक लिय प्रत्येक अंगुलीमें अपनी अंगुलीमें दाखिल करे दफा ११० क अनुसार अनुमति बनाये । आकिशल एसायनीके श्रमफलके लिये नियम दफा ११२ की उपदफा (२) के प्राव (बी) क अनुसार बनाये जावग ।

दफा ८२ आकिशल एसायनीकी बेरनवानी

यदि आकिशल एसायनीने दियायमें या दूसरे प्रकारसे उसकी बखनवानी लापरवाही या

किसी काम का न करना मालूम हो तो अदालत उसके समझानेके वारेमें कहेंगी और यदि उसकी घंउनवानी लापरवाही या काम न करने की वजहसे दिवालिये की जायदाद को कोई नुकसान पहुँचा हो तो उससे उस नुकसान को पूरा करा सकती है ।

व्याख्या—

अदालतका कर्तव्य है कि वह आफिशल एसायनीमें उसकी गळनीके बोममें पूछे जैसा कि इन सम्बन्धमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दमें प्रकट है तथा अदालत यदि चाहे तो आफिशल एसायनीसे उसके द्वारा किये हुए नुकसान की पूर्ति करा सकती है अर्थात् दफाके इस हिस्सेके अनुसार कार्रवाई करनेके लिये असमन्त बाध्य नहीं है किन्तु उसके अनुसार करना न करना उसकी इच्छा पर निर्भर है जैसा कि अंग्रेज एक्टमें मयाग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है ।

दफा ८३ किस नामसे दावा दायर किये जाना चाहिये या दावा उसपर होना चाहिये

‘दिवालिये की जायदाद का आफिशल एसायनी’ (The Official Assignee of the property of an insolvent.) इस नामसे आफिशल एसायनी को दावा दायर करना चाहिये तथा इसी नामसे उसके विरुद्ध दावे किये जाना चाहिये और उसमें दिवालियेका नाम दिखला देना चाहिये । और इसी नामसे हर प्रकार की जायदाद पर कब्जा रखा जा सकता है, सुबाहिद किये जा सकते हैं, अपने ऊपर तथा अपने उत्तराधिकारियोंके ऊपर ज़िम्मेदारी लेने वाले वादे किये जा सकते हैं तथा अपने ओहदेके कामों को पूरा करनेके लिये, जिन कामोंका किया जाना आवश्यक तथा अनिवार्य प्रतीत हो उनको किया जा सकता है ।

व्याख्या—

आफिशल एसायनी अपने नामसे कोई कार्रवाई नहीं करेगा किन्तु वह ‘दिवालियेकी जायदाद का आफिशल एसायनी’ इस नाममें घुनहमें दायर कर सकेगा तथा इस नामसे उसके विरुद्ध भी दावे किये जाना चाहिये जिस दिवालियेकी जायदादके सम्बन्धमें कार्रवाई हो रही हो उसका नाम दे देना चाहिये । आफिशल एसायनी इसी नाममें जायदाद पर कब्जा रख सकता है तथा इसी नामसे सुबाहिदे या भय कर्षण गो आवश्यक प्रतीत हो कर सकता है और इसी नाममें किये हुए कार्योंत वह स्वयं तथा उसके उत्तराधिकारी जा उसके आहूद पर काम करें भविष्यमें पावद किये जा सकते हैं । अमेठी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है कि ऊपर बतलाये हुए नाममें कार्रवाई करनेके लिये कोई व्यक्ति बाध्य नहीं है किन्तु कार्रवाई आर भी नामसे की जा सकती है अर्थात् ऐसे नाममें की जा सकती है जिससे इसी प्रकारका अर्थ निश्चलता हो तथा जिससे भासत हो जावे कि कार्रवाई किसी दिवालियेके आफिशल एसायनी की ओरसे बनौर आफिशल एसायनीके की जा रही है या उसके विरुद्ध की जा रही है ।

दफा ८४ दिवालिया होने पर आफिशल एसायनी अपनी जगहसे हट जावेगा

यदि आफिशल एसायनीके विरुद्ध दिवालिया करार दिये जानेका हुकम हो जावे तो ऐसे हुकमके होनेसे वह आफिशल एसायनीके पदसे हट जावेगा ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार दिवालिया आफिशल एसायनी नहीं रह सकता है अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है । इस दफाके नियमोंमें अवदेना नहीं भी जावेगी किन्तु आफिशल एसायनीके खुद दिवालिया करार दिये गतेही वह अपने पदसे च्युत हो जावेगा ।

दफा ८५ मीटिंग आदि करनेके कर्तव्य तथा उसकी पाबन्दी

(१) इस एक्टके नियमोंका ध्यान रखते हुए तथा अदालत द्वारा दी हुई आज्ञाओं को मानते हुए आफिशल एसायनी दिवालिये की आयदादके प्रबन्ध तथा उसके कर्जस्वाहोंमें घाटे जानेके सम्बन्धमें कर्जस्वाहों द्वारा किसी मीटिंगमें पास किये हुए प्रस्ताव पर ध्यान रखेगा ।

(२) आफिशल एसायनी को अधिकार है कि वह समय समय पर कर्जस्वाहों की संज्ञा जाननेके लिये उनकी मीटिंग करे तथा उसका कर्तव्य होगा कि वह कर्जस्वाहों द्वारा किसी मीटिंगमें पास किये हुए समय पर या अदालत की आज्ञा दिये हुए समय पर या कर्जा साबित किये हुए कर्जस्वाहोंके चौथाई कर्जा वाले कर्जस्वाहोंके लिख कर कहने पर मीटिंग अवश्य करे ।

(३) दिवालिये की कारवाईके सम्बन्धमें पैदा हुए किसी मामलेके लिये आफिशल एसायनी अदालतसे सलाह भोग सकता है ।

(४) इस एक्टके नियमों का ध्यान रखते हुए आफिशल एसायनी आयदादके प्रबन्ध तथा उसके कर्जस्वाहोंमें तकलीफ किये जानेके सम्बन्धमें अपनी रायका प्रयोग करेगा ।

उपदफा—

उपदफा (१) में बतलाया गया है कि यदि कर्जस्वाहों की मीटिंगमें कोई प्रस्ताव दिवालिये की आयदादके प्रबन्ध अपना उसका बाद आनेके सम्बन्धमें पास किया गया हो और प्रस्ताव इस एक्टके किसी नियमके विरुद्ध अथवा अदालतकी आज्ञाके विरुद्ध न पड़ता हो तो आफिशल एसायनी का कर्तव्य होगा कि वह उसे प्रस्तावको कार्य कर्म परीक्षित करनेकी शक्ति पर तथा उसे पूरे प्रस्तावकी अवदलना नहीं करना चाहिये जैसा कि अग्रेजी एक्टकी इस उपदफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्द प्रकट है ।

उपदफा (२) में आफिशल एसायनीके लिये बतलाया गया है कि वह समय २ पर कर्जस्वाहोंकी मीटिंग किया करे परन्तु ऐसा करनेके लिये वह बाध्य नहीं है जैसा कि अग्रेजी एक्टकी इस उपदफामें प्रयोग किये हुए (May) शब्दमें प्रकट है परन्तु यदि कर्जस्वाहोंने अपना किता मीटिंगमें किसी कार्यके निर्णयके लिये मीटिंग करना पास किया हो अपना अदालत मीटिंग करनेके लिये कर्जस्वाहों साबित किये हुए कर्ज वाले कर्जस्वाहोंमें से चौथाई कर्ज वाले कर्जस्वाहों लिख कर देने ता आफिशल एसायनी का कर्तव्य होगा कि वह मीटिंग अवश्य करे जैसा कि अग्रेजी एक्टमें इस सम्बन्धमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दमें प्रकट है ।

उपदफा (३) में बतलाया गया है कि आफिशल एसायनी यदि चाहे तो वह अदालतमें दिवालियेके किसी मामलेके सम्बन्धमें राय ले सकता है इसके लिये वह बाध्य नहीं है जैसा कि अग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (May) शब्दमें प्रकट है ।

उपदफा (४) के अनुसार आफिशल एसायनी को पूर्ण स्वतन्त्रता आयदादके प्रबन्ध करने तथा उसके बादमें प्राप्त है केवल उसका इस एक्टमें बतलाये हुए किसी नियमकी अवदलना ऐसा करनेमें नहीं करना चाहिये ।

दफा ८६ अदालतमें अपील

यदि आफिशल एसायनीके किसी काम या फैसलेसे किसी कर्जस्वाह, दिवालिया या अन्य किसी व्यक्तिको हानि पहुंचती हो तो वह अदालतमें अपील कर सकता है । और अदालत शिकायत किये हुए काम या फैसले को मजूर कर सकती है, पलट सकती है अथवा संशोधित कर सकती है जैसा कि उसे उचित प्रतीत होवे ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार आफिशल एसायनीके किसी कार्य या पैगलेके विरुद्ध अपील अदालतमें की जासकती है अदालत को अधिकार है कि वह अपील होने पर आफिशल एसायनीके कार्य या पैगलेको जैसे का तैसा बना रहने दे अथवा उसे रद्द कर देवे या उसमें उचित संशोधन कर देवे । यदि अपीलमें जन लोग एक दूसरे की रायसे सहमत न हों तो दिवालिएकी बारिवाईके सम्बन्धमें लेटर्स पेटेंट अपील (Letters patent appeal) दाखिलकी जासकती है, देखो—34 Mad. 121.

दफा ८७ अदालतका द्वाब

(१) यदि कोई आफिशल एसायनीका दफादारीके साथ अपने कर्तव्य का पालन न करे और वह कानून, कूल या अन्य प्रकारसे अपने लिये धतलाये हुए नियमोंका जो उनके कर्तव्यके पालनके लिये बनाये गये हों ध्यान न रखे या उसके बारेमें किसी कर्मरवाह द्वारा शिकायत कीगई हो तो अदालत उस मामलेमें तहकीकात करेगी तथा उसके लिये आवश्यक कार्रवाई करेगी ।

(२) यदि अदालत आफिशल एसायनीसे किसी समय उस दिवालिएकी कार्रवाईके सम्बन्धमें कुछ दुर्याप्त किया चाहे जिसमें वह आफिशल एसायनी होवे तो वह पूछ सकती है तथा दिवालिएकी कार्रवाईके सम्बन्धमें उसके अथवा अन्य किसी व्यक्तिके हलफत बयान ले सकती है ।

(३) अदालत आफिशल एसायनीकी किताबों व पत्रों (Vouchers) की जाँचके लिये हुकम दे सकती है ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार अदालतका कर्तव्य होगा कि वह ऐसे आफिशल एसायनीके मामलोंकी तहकीकात करे जो अपना कर्तव्य पालन न करता हो या जो किसी कानूनकी अवहेलना करता हो जिसकी पाबंदी उसके लिये आवश्यक होवे । केवल तहकीकात ही की आवश्यकता नहीं है किन्तु यथोचित कार्रवाई भी उसके विरुद्ध की जाना चाहिये । कर्मरवाहकी शिकायत पर भी ऊपर बतलाई हुई कार्रवाई आफिशल एसायनीके विरुद्ध की जावेगी ।

उपदफा (२) के अनुसार अदालत आफिशल एसायनीसे दिवालिएकी बारिवाईके सम्बन्धमें कोई भी बात दर्शाव कर सकती है तथा उसका या अन्य किसी व्यक्ति का बयान हलफने ले सकता है ।

उपदफा (३) के अनुसार आफिशल एसायनीकी किताबों व पत्रोंके सम्बन्धमें भी जांच कराई जासकती है । अदालतकी इच्छा पर ऐसा करना न करना निर्धार है जैसा कि अमेरिकी एक्टकी इस उपदफामें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है ।

पांचवां प्रकरण

जांच कमेटी

दफा ८८ जांच कमेटी

अदालतको अधिकार है कि मुनासिब समझने पर वह उन कर्जतवाहों को जो अपने कर्ज साबित कर चुके हैं इस बातका अधिकार दे देवे कि वह कर्जतवाहोंमें से या उनके प्रोक्सी (Proxies) अथवा उनके मुकतारआममें से एक जांच कमेटी आफिशल एसायनी द्वारा दिवालियाकी जायदादके प्रबन्ध का निरीक्षण करनेके लिये नियुक्त कर सके। परन्तु शर्त यह है कि जो कर्जतवाह जांच कमेटी का मेम्बर बनाया गया हो वह उस वक्त तक उसमें कार्य करने योग्य नहीं होगा जब तक कि वह अपना कर्ज साबित न कर देवे।

व्याख्या—

जैमेनी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (May) शब्दमें प्रकट है कि अदालत इस दफाके अनुसार कार्यवाही करनेके लिये शाय नहीं है किन्तु इसके अनुसार हुकम देना न देना उसकी इच्छा पर निर्भर है इस दफाके अनुसार अन्य कमेटी बनानेके अधिकार केवल उन्हीं कर्जतवाहोंको प्राप्त हो सकते हैं जो अपना कर्ज साबित कर चुके हों परन्तु कमेटीके मेम्बर वाई भी कर्जतवाह बनये जासकेंगे चाहे उन्होंने मेम्बर बनाये जाते समय तक अपना कर्ज साबित किया हो या न किया हो कर्जतवाहोंके अतिरिक्त उन्हीं ओग्रेटे बोट देनेवाले अधिकार वाले हुए व्यक्ति तथा उनके मुस्तार आस भी कमेटीके मेम्बर बनाये जासकेंगे हैं यह बात ध्यानमें रहना चाहिये कि कर्ज न साबित किया हुआ कर्जतवाह कमेटीका मेम्बर तो बनाया जासकेगा परन्तु कमेटीमें काम करना अधिकारी उन्ही समय होगा जब कि वह अपना कर्ज साबित कर देवे। इस वष नियमकी अवहेलना नहीं की जाना चाहिये जिसके अंतर्गत एक्टमें इन सम्बन्धमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दमें प्रकट है।

दफा ८९ जांच कमेटीके आफिशल एसायनीकी जांचके सम्बन्धमें अधिकार

आफिशल एसायनी की कार्यवाहियों पर जांच कमेटीको नियन्त्रणके बड़ी अधिकार प्राप्त होंगे जो इस सम्बन्धमें निर्धारित किये जावें।

व्याख्या—

जांच कमेटी निर्धारित किये हुए जांचके नियमोंकी पाबंद होगी अर्थात् उनके विपरीत नहीं कर सकेंगी जिस कि जैमेनी एक्टमें किये हुए (Shall) शब्दका तात्पर्य है।

दफा ९२ एकके स्थानमें दूसरे कर्जस्वाह द्वारा कार्रवाईका किया जाना

यदि दरखास्त देने वाला व्यक्ति उचित मेहनतके साथ दरखास्तकी परखी न करता हो तो अदालतको अधिकार है कि वह किसी दूसरे कर्जस्वाहको उसकी जगह पर दरखास्त देने वाला मानले परन्तु इस दूसरे कर्जस्वाहके कर्जेकी तादाद वही होना चाहिये जो दरखास्त देने वाले कर्जस्वाहके लिये इस एक्टमें बतलाई गई है।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार अदालत किसी मामलेकी पैरवीमें न्यूनता देखकर उसकी उचित पैरवीके लिये अपनी दरखास्त देने वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरे कर्जस्वाहको मान सकती है परन्तु ऐसा करनेके लिये अदालत बाध्य नहीं है जैसा कि अमेरिकी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है। इस दफाके अनुसार कार्रवाई करते समय इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि दूसरा शामिल किया जाने वाला कर्जस्वाह भी कर्जदारसे कमसे कम (५००) रुपयेका कर्ज पतिता हकदार होवे।

दफा ९३ कर्जदारके मरजाने पर भी कार्रवाईका चालू रहना

यदि कोई कर्जदार जिसके विरुद्ध दिवालियेकी दरखास्त दी गई होवे अथवा जिसने दरखास्त दी होवे मर जावे तो उसके मामलेकी कार्रवाई जारी रखी जावेगी जब तक कि अदालत इसके विरुद्ध कोई हुक्म न देवे।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार कर्जदारके मर जाने पर भी दिवालियेकी कार्रवाई बाद रस्ता जावेगी व इस नियमकी अवहेलना नहीं की जा सकती है जैसा कि अमेरिकी एक्टमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे भासता है। परन्तु अनुमनकी अधिकार है कि इस नियमके विरुद्ध भी वह आज्ञा दे सकती है यदि कोई आज्ञा उक्त नियमके विरुद्ध न दी गई हो तो इस नियम की पाबंदी अवश्य की जावेगी।

दफा ९४ कार्रवाईको रोकनेके अधिकार

अदालत किसी समय भी उचित कारणके उपस्थित होने पर दिवालियेकी दरखास्तके सम्बन्धमें होने वाली किसी कार्रवाईके स्थान पर कुछ समयके लिये किन्हीं शर्तोंके साथ बंद स्थगित कर सकती है।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार कार्रवाई करना न करना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है जैसा कि अमेरिकी एक्टमें प्रयोग किये हुए (May) शब्दसे प्रकट है। इस दफाके अनुसार अदालत दिवालियेकी कार्रवाईका किसी नियत समयके लिये अथवा सर्वदिके लिये रोक सकती है जैसा कि उसे उचित प्रतीत होवे। जैसा कि दिवालियेके मामले पर या दिवालियेके विरुद्ध किन्हीं दूसरी अदालतमें कार्रवाई होने पर अपना अन्य किसी ऐसे ही अवसरके उपस्थित होने पर अदालत मुत्तरी का हुक्म दे सकती है।

दफा ९५ किसी शरीकदारके विरुद्ध दिवालियेकी दरखास्तका दिया जाना

यदि किसी कर्जस्वाहका कर्ज किसी मामलेके विरुद्ध दिवालियेकी दरखास्त देनेके लिये फाँसी होवे तो उस कर्जस्वाहको अधिकार है कि वह उस मामलेके किसी एक या अधिक हिस्से-

द्वारेके विरुद्ध दरखास्त उस कर्जेके आधार पर दे सके अर्थात् यिला सब कर्जद्वाराओंको उस दरखास्तमें शामिल किये हुए वह दरखास्त दे सकता है।

व्याख्या—

यदि किसी हिन्दू मेषकी नाबालिगीमें आनदाना वसोएके लिये कोई कर्ज लिया गया हो तो बालिग होने पर वह व्यक्ति ऐसे कर्जेके आधार पर दिवालिया कार नहीं दिया जासकता है देखो—41 Mad 821. इस दफाके अनुसार सयुक्त कर्जोंके लिये सयुक्त कर्जेके जिम्मेदार बालिगोंके लिये एक साथ या अलगहटा अलगहटा दरखास्त दिवालिया दी जासकती है व अलगहटा दरखास्त दिये जाने पर वह व्यक्ति पूरे लयुक्त कर्जेके लिये कर्जदार समझा जावेगा अर्थात् हिस्सा रसदके दिवाबदे उस पर उस कर्जेकी जिम्मेदारी नहीं संपादी जावेगी।

दफा ९६ कुछ रिस्पान्डेन्ट्सके विरुद्ध दरखास्तका खारिज किया जाना

यदि किसी दिवालियेकी दरखास्तमें एकसे अधिक रिस्पान्डेंट्स होवें तो अदालत उनमेंसे किसी एक या अधिक रिस्पान्डेंटके विरुद्ध दरखास्तको खारिज कर सकती है और इस प्रकार खारिज किये जानेका कोई प्रभाव बाकी बचे हुए रिस्पान्डेंट या रिस्पान्डेन्ट्सके विरुद्ध दिये हुए पिटीशन पर नहीं पड़ेगा।

व्याख्या—

इस दफाके नियमोंका प्रयोग अदालतकी इच्छा पर निर्भर है जैसे कि अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए (May) शब्दमें प्रकट है। इस दफाका प्रयोग उसी समय हो सवेगा जब एक्से अधिक व्यक्तियोंके विरुद्ध कोई दरखास्त दी जावे। यदि ऐसी दाय्वाला पर अदायत किसी एक या एक्से अधिक व्यक्तियोंका संग कर दवे तो बारी बच हुए व्यक्तियों पर भी बारी किये जानेका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उनके विरुद्ध वह दरखास्त बदलाव बना रहेगा।

दफा ९७ शरीकदारोंके विरुद्ध जुदागाना पिटीशनोका दिया जाना

जब कि फर्मके किसी शरीकदारके विरुद्ध या उसके द्वारा दी हुई दरखास्त पर दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म हो जावे तो उसी फर्मके किसी दूसरे शरीकदार या शरीकदारोंके विरुद्ध या उनके द्वारा दी हुई दिवालियेकी दरखास्त उसी अदालतमें दी जावेगी या उसी अदालतमें भेज दी जावेगी जहां कि पहिले बतलाई हुई दरखास्तकी सुनवाई हो रही हो। और वह अदालत उन दरखास्तोंको शामिल कर दिये जानेके लिये वह हुक्म देसकती है जो उसे उचित प्रतीत होयें।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार यदि एक ही मामलेमें सबबदलते वाले एक्से अधिक मामले होवें तो उनको एक ही अदालत द्वारा सुना जाना उचित बतलाया गया है जिसमें उचित प्रतीत होने पर वह एक साथ शामिल कर दिये जायेंगे। जेम्मे कि यदि फर्मका एक शरीकदार किसी अदालत द्वारा दिखसतिया करार दिया गयाहो तो उसी फर्मके अन्य शरीकदारोंके विरुद्धकी अन्य दिवालियेकी बाराई उसी अदालतमें ही जाना चाहिये और यदि किसी दूसरे अदालतमें दरखास्त दी गई हो तो वह भी उसी अदालतमें भेज दी जाना चाहिये।

दफा ९८ आफिशल एसायनी तथा दिवालियेके शराकदार द्वारा चलाये जाने वाले मुकदमों

(१) यदि फर्मका कोई शरीकदार दिवालिया करार दिया गया हो तो अदालत आफिशल एसायनीको उस दिवालियेके नामसे तथा उस दिवालियेके शरीकदारके नामसे कारवायोंके जारी रखने या शुरू करने व उसकी पैरवी करनेका अधिकार दे सकती है। और जिस मामलेके सम्बन्धमें कारव है चल रही हो यदि उस सम्बन्धमें कोई शरीकदार कुछ छोड़ देंतो ऐसा छोड़ा जाना रह होगा।

(२) यदि उपदफा (४) के अनुसार मुकदमा जारी रखने या शुरू करनेकी आज्ञा देने के लिये दरखास्त दी जाये तो उसकी सूचना दूसरे शरीकदारको दी जावेगी जिसमें कि वह उसका विरोध कर सके और उसकी दरखास्त पर अदालत यह हुक्म दे सकती है कि उसे उस मामलेसे उसका मुनासिब भाग मिल सके और यदि वह उससे कोई लाभ न उठाया चाहें तो उसको उस सम्बन्धमें दिलाये जाने वाले उस खर्चका मुआविजा मिलेगा जिसके लिये अदालत हुक्म देवे।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार फर्मके किसी एक शरीकदारके दिवालिया करार दिये जाने पर आफिशल एसायनीकी उस शरीकदारके नामसे तथा उसके दूसरे शरीकदारके नामसे मामले जारी रखने या नया मामला दायर करनेका अधिकार दिया जा सकता है। अदालत ऐसा करनेके लिये बाध नहीं है कि नु इसका करना न करना अदालतकी आज्ञा पर निर्भर है नैमा कि जैसी एक्टमें प्रयोग किये हुए (May) शब्दमें प्रकट है। यदि उपदफा (१) के अनुसार किसी बन्ने या मांगके सम्बन्धमें कोई मामला चल रहा हो और फर्मका कोई शरीकदार उस बन्ने आदिमें झेंड देवे तो इस प्रकारका जोराना अविविद् हागा तथा वह रह समयानुसार।

उपदफा (२) में बतलायागया है कि फर्मके दूसरे शरीकदार इनानकी दाय्यालका विरोध कर सकते हैं तथा अदालत द्वारा उनकी उनका किसी मामलेकी कामगामी पर दिनाया जासकता है और यदि वह शरीकदार मामलेसे कुछ सम्बन्ध न रखताछाहे तो ऐसा ही वह उस मामलेके खर्चों भी नहीं लाया जावेगा। जो अदालतकी मुनासिब हुक्म देना अधिकार इस प्रकारके मामलोंमें है कि नु फिर भी विरोध करनेका अवसर तथा खर्च आदिमें बचानेकी आज्ञा अदालतकी अवश्य देना चाहिये जैसा कि जैसी एक्टकी १७ उपदफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दमें प्रकट है।

दफा ९९ साझेके नामसे मामलेका चलाया जाना

(१) यदि दो या दो से अधिक साझीदार हों, अथवा कोई व्यक्ति साझेके नामसे कारोबार करता हो, तो वह लोग इस एक्टके अनुसार फर्मके नामसे कारवायों कर सकते हैं परन्तु शर्त यह है कि ऐसे मामलोंमें किसी सम्बन्धित व्यक्तिके दरखास्त देने पर फर्मके शरीकदारोंका नाम अथवा उस व्यक्तिका नाम जो फर्मके नामसे काम करता हो जाहिर करनेका हुक्म अदालत दे सकती है और यह उस प्रकार चललाये जावेगा तथा हलफसे उनकी तस्दीक उस प्रकारकी जावेगी जिस प्रकार अदालत हुक्म देवे।

(२) यदि किसी फार्मा कोई शरीकदार नावालिग होवे सो दिवालिया करार दिये जानेका हुक्म उस नावालिग शरीकदारके अतिरिक्त फार्मे विरुद्ध दिया जासकता है।

व्याख्या—

जिस नामसे बारोबार होता हो उस नामसे दिवालियेके सम्बन्धमें फार्माही जासकती है चाहे उस नामसे बारोबार कोई व्यक्ति अकेले ही किया हो अथवा उसमें कई शरीकदार हों। परन्तु यदि कोई सम्बन्धित व्यक्ति यह जानना चाहे कि उस फार्मे नाममें क्या वृत्ति कायदाई कर रहा है अथवा फार्मे से शरीकदारोंके क्या नाम हैं तो अद्वारत उन लोगों नाम बतलाये जानना हुक्म देसकता है और जब समय आदानीमें आयेके अनुसार उन लोगों नाम बतलाये जायेंगे तथा उसकी तस्दीक हुक्म की जायेगी।

उपदफा (२) के अनुसार किसी फार्मा नावालिग शरीकदार दिवालिया करार नहीं दिया जावेगा परन्तु वह फार्मे अथवा उसके दिवालिया करार दिया जासकता है इस दफाके अनुसार फार्मे बानके लिप बोई व्यक्ति बाध्य नहीं है जहाँ कि अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग दिये हुए (May) शब्दसे प्रष्ट है नावालिग सल्लेख दफा ९ में किया जासकता है।

दफा १०० अदालत दिवालियाके वारण्ट

(१) अदालत दिवालिया द्वारा जारी किये हुए वारण्टों की तामीन उसी प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार सन् १८६८ ई० के क़ायदा फौजदारीके अनुसार जारी किये हुए वारण्टोंकी जाती है।

(२) दिवालियेकी आयदादके किसी हिस्से पर क़ब्जा लेनेके लिये दिया हुआ वारण्ट जो दफा ४६ की उपदफा (१) के अनुसार दिया गया हो निर्धारित फार्ममें होगा और ऊपर बतलाये हुए एक्ट की दफाओं ७७ (२), ७६, ८२, ८३, ८४ तथा १०२ जहाँ तक होगा ऐसे वारण्ट की तामीनके सम्बन्धमें लागू होंगी।

(३) यदि दफा ४६ (२) के अनुसार तलाशीका वारण्ट जारी दिया गया हो तो उसकी तामीन उसी प्रकार होगी जहाँ वही शर्तें लागू होंगी जो ऊपर बतलाये हुए एक्टके अनुसार जोरी की आयदादके लिये जारी किये हुए तलाशीके कारण वारण्टमें लागू होती है।

व्याख्या—

इस दफाके वारण्ट की तामीनके नियम बतलाये गये हैं। बोई नये नियम इन एक्ट के लिये इस सम्बन्धमें नहीं बनाये गये हैं। उपदफा (१) में यह बतला दिया गया है कि सन् १८९८ ई० के समय क़ायदा फौजदारीका नियम वारण्टों की तामीनके लिये दिये हुए हैं जहाँ प्रयोग इस एक्टके अनुसार नाम दिये हुए वारण्टोंके सम्बन्धमें किया जावेगा। उक्त समय अथवा फौजदारीके अन्तर्गत क़ायदोंमें यह नियम दिये हुए हैं और वह दफा ७५ से लेकर दफा ९१ तक मिलेगा तथा इसके बाद दफा ९६ से दफा १०३ तक भी सार्वत्रिक प्रकरणमें कुछ नियम वारण्ट तलाशी आदिके सम्बन्धमें दिये हुए हैं।

उपदफा (२) में बतलाया गया है कि दिवालियेकी आयदाद पर क़ब्जा लेने वाले वारण्टोंके तामीनमें वह नियम लागू होंगे जो समय क़ायदा फौजदारी की दफाओं ७७ (२) ७९, ८१, ८३, ८४ और १०२ में दिये हुए हैं।

क़ायदा फौजदारीकी दफा ७७ (२) के अनुसार यदि बाण्ट एक्टसे अधिक पुलिस अधिकारों या दूसरोंके नाम जारी किया गया हो तो उसकी तामीन सब लोग भिन्नकर या उनमेंसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है।

ज्ञापता फौजदारीकी दफा ७६ के अनुसार यदि वारण्ट किसी पुलिस अफसरके नाम जारी किया हो तो उसकी तामील कोई दूसरा पुलिस अफसर भी कर सकता है जिसका नाम पहिले पुलिस अफसरने वारण्ट पर लिख दिया हो ।

ज्ञापता फौजदारीकी दफा ८२ के अनुसार गिरफ्तारी का वारण्ट ब्रिटिश भारतके किसी भी हिस्सेमें तामील किया जासकता है ।

ज्ञापता फौजदारीकी दफा ८३ के अनुसार यदि वारण्ट जारी करने वाली अदालतके अधिकार सीमासे बाहर तामील किया जानको होवे तो अदालत ऐसे वारण्टको बजाय किसी पुलिस आफीसरकी देनेके उस डिस्ट्रिक्ट मागिस्ट्रेट सप्ली-पेंटेंट पुलिस या पुलिस कमिश्नरके पास भेज सकती है जिसके अधिकार सीमामें उस वारण्टकी तामील दरकार होवे और इस प्रकार वारण्टके भेजे जाने पर पावे वाला हाकिम अपने दस्तखत करके जहा तक हो सकेगा उसकी तामील करवेगा ।

ज्ञापता फौजदारीकी दफा ८४ के अनुसार यदि किसी पुलिस आफिसरको कोई ऐसा वारण्ट तामीलके लिये दिया जावे जिसकी तामील जारी करने वाली अदालतके अधिकार सीमामें बाहर की जाने की होवे तो वह उस वारण्ट पर उस मजिस्ट्रेट या थानेदार या उससे ऊंचे किसी पुलिस आफिसरके दस्तखत करवेगा जिसके हल्केमें उस वारण्टकी तामीलकी जाने की होवे और ऐसे अफसरके दस्तखत होने पर तामील करने वाले पुलिस आफिसरको उसके तामील करने का अधिकार प्राप्त हो जावेगा तथा वह भी छोड़ल पुलिस भी आवश्यकता पड़ने पर उसे मदद देगी यदि दस्तखत आदि करनेमें देर होनेकी सम्भावना हो जिसके कारण फिर वारण्टकी तामीलही नामुमकिन हो जाती हो तो पुलिस आफिसर बिना दस्तखत करायेही तामील कर सकता है ।

ज्ञापता फौजदारीकी दफा १०२ के अनुसार यदि किसी बन्द जगह की तलाशी ली जाने की होवे तो उस जगह का मालिक या कब्जा उस जगहकी तलाशी वारण्ट दिखाने जाने पर देने देवेगा, यदि वह उसकी तलाशी नहीं छेन देवे तो जबरन उसकी तलाशी ली जावेगी और यदि कोई आदमी किसी चीजको अपने निस्पमें छिपाये हुए होवे तो उसके निस्पमें भी तलाशी ली जासकती है ।

उपदफा (३) के अनुसार तलाशके वारण्ट भी समूह जावना कानूनधर्ममें बतलाये हुए चोरोंके मालकी तलाशी वाले नियमोंके अनुसार तामील किये जावेंगे तलाशीके वारण्टका जिक्र दफा ९६ से लेकर दफा १०३ तक किया गया है दफा ९८ में चोरों की जायदाद वाले मकानकी तलाशी । जिक्र है अर्थात् हर प्रकारके वारण्टकी तामील जावता कानूनधर्ममें बतलाये हुए नियमोंके अनुसार की जासकती है ।

सातवां प्रकरण

मियाद

दफा १०१ अदालतके लिये मियाद

आफिशल एसायनीके किसी काम या फैसलेकी अपील अथवा अदालतके किसी अफसर के हुक्मकी अपील जिसे दफा ६ के अनुसार अधिकार दिया गया हो उस कामसे अथवा हुक्म या फैसलेसे जैसा कि मामला होव वीस दिनके अन्दर की जावेगी।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार आफिशल एसायनीके किसी काम या फैसलेकी अपील उस काम या फैसलेके होनेके बाद २० दिनोंके अन्दर की जासकती है। उस अफसरके नाम अथवा फसलेकी अपील भी इसी मियादके अन्दर की जासकती है जो इस एक्टकी दफा ६ में बतलाये हुए नियमके अनुसार नियुक्त किया गया हो—देखो पिछली दफा ६ व उसकी व्याख्या यदि दिवा-लिया का काम करने वाले जनके हुक्मकी अपील की गई हो तो अदालत अपीलकी अपेक्षा है कि वह खर्चों अमानत लिये जनके सम्बन्धमें दो हुई दरवाजोंके ले सके तथा उस पर विचार कर सके देखो—43 Cal 243 इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि अदालतकी दफा १० (५) के अनुसार मियाद बढ़ाने का अधिकार शासक है अर्थात् अदालत मियाद समाप्त होनेके बाद अथवा उसमें पहिले यदि वह उचित समझे तो गिन गणोंके साथ चाहे उस एक्ट अथवा कानूनके अनुसार नियमकी हुई मियादसे बढ़ा सकता है—देखो पिछली दफा १० (५) इस दफामें बरतार्ह हुई २० दिनोंकी मियाद काम या फैसला होनेके समयमें सुधार की जावेगी इस प्रकार यदि आफिशल एसायनाने किसी सुवृत्तरी न माना हो तो इसके अपीलकी मियाद उस दनके समझी जावेगी जबकि आफिशल एसायनीके वसूह लिखकर सुवृत्तकी नामावली किया हो जैसा कि उसे दूसरी सूचीके पचासवें कलके अनुसार करना आवश्यक है।

आठवां प्रकरण

दण्ड

दफा १०२ विला बहाल हुआ दिवालिया यदि कर्ज लेवे

यदि विला बहाल हुआ दिवालिया किसी व्यक्तिसे विला उसको यह बतलाये हुए कि वह विला बहाल किया हुआ दिवालिया है पचास रुपये या इनसे अधिकका कर्ज लेवे तो मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी निर्धारित किये जाने पर उसको छः महीने तकके कारावासका दण्ड या जुर्मानाका दंड अथवा दोनों प्रकारके दंड साथ साथ दिये जासकेंगे।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार कोई दिवालिया गण तक कि वह बहाल न कर दिया जाने पचास रुपये या इससे अधिकका कर्ज

नहीं हो सकता है यदि वह ऐसा करेगा तो दण्ड का भागी होगा परन्तु इस बात का ध्यान रहना चाहिये कि जिस व्यक्ति को दण्ड दिया गया हो उसको नष्ट हो जाने का हाल न बनलया गया हो अर्थात् यदि बर्ज किये समय दिवालिया में बर्ज देने की वृत्ति से यह बतला दिया हो कि वह बिना बहाल हुआ दिवालिया है तो ऐसी दशा में किसी रूप से उधार दिया जाना उचित नहीं समझा जावेगा मनिस्ट्रेट इस दफा के अनुसार दिवालियों को निर्धारित कर सकता है और दण्ड निर्धारित किये जाने पर वह मन्त्रिने तब के कारावास का दण्ड या जमाने का दण्ड अथवा दोनों प्रकार के दण्ड साथ साथ दिये जावेंगे। कारावास के दण्ड के सम्बन्ध में इस दफा में यह नहीं बतलाया गया है कि वह कटोरे वास्तविकता दण्ड होगा अथवा साधारण परन्तु इसका मतलब यह समझना चाहिये कि दोनों प्रकार के कारावास का दण्ड मनिस्ट्रेट की आज्ञानुसार दिया जा सकता है। अंग्रेजी पदार्थ प्रयोग किये हुए (Shall) शब्द से प्रत्येक कि इस दफा के नियमों की अवहेलना नहीं की जाना चाहिये अर्थात् दण्ड निर्धारित किये जाने पर वह किसी न किसी दण्ड से अवश्य पावेगा जैसा कि कृपा निर्धारित करने वाली अदालत तब के विषय उचित समझे।

दफा १०३ कुछ जुर्मानों के लिये दिवालिये को दण्ड दिया जाना

यदि कोई व्यक्ति जो दिवालिया क्रार दिया जा चुका हो नीचे दिये हुए जुर्मानों से कोई जुर्मा करे तो वह दोषी निर्धारित किये जाने के कारावास का दण्ड पा सकता है : -

(ए) यह कि उसने अपने मामलों की हालत छिपाने की भ्रंश से अथवा इस एक्ट के अनुसार होने वाले कार्य को न होने की भ्रंश से या धोखा दे ही से -

(i) किसी किताब, कागज़ या तहरीर को जिसका सम्बन्ध उसके उन मामलों से होवे जो इस एक्ट के अनुसार जेर तजवीज हैं बरबाद कर दिया हो अथवा किसी दूसरे प्रकार से जानते हुए रोका हो या जानबूझ कर उसको पेय न होने दिया हो, या

(ii) झूठी किताबें रखी हों या रखवाई होयें या

(iii) किसी किताब, कागज़ या तहरीर को जिसका सम्बन्ध उसके उन मामलों से होवे जो इस एक्ट के अनुसार जेर तजवीज हैं गलत इन्टरज किया हो या उसमें कोई इन्टरज न किया हो अथवा जान बूझ कर उसे तब्दील किया हो या गलत किया हो, या

(बी) यह कि उसने धोखा दे ही से तथा इस नीयत से कि उसके कर्जदारों में बाँटे जाने वाला रुपया कम हो जावे या उसके किसी एक कर्जदार को और कर्जदारों के मुकाबले बेजा तर्जिह दी जा सके : -

(i) उससे लेने या देने वाले कर्ज को चुका दिया हो या छिपाया हो, या

(ii) अपनी किसी प्रकार की जायदाद को लेकर भाग गया हो या उस पर भार पैदा कर दिया हो या उसे रेहन कर दिया हो अथवा छिपा दिया हो।

व्याख्या—

इस दफा में वह जुर्मा बतलाये गये हैं जिनसे स्पष्ट होते पर दिवालियों को दण्ड दिया जा सकता है।

उपदफा (५) में दिशावर्षा विताओं तथा अन्य तद्वर्गी बाधनाओंका उल्लेख है वह उपदफा तीन प्राणोंमें विभक्त का नहीं है । (१) पहिले प्राणके अनुसार किताबी आदिना न पक्ष किया जाना जब कि उनका पक्ष किया जाना आवश्यकता इस प्रकारके अनुसार होने दण्डनीय बनलाया गया है (११) दूसरे प्राणके अनुसार यदि छुटी हिमावर्षा विताओंमें ग्वती गई हो तो वह दण्डनीय है (१११) तसारे प्राणके अनुसार यदि नुटे इन्दान किया गये हों या बाई इन्दान किया हो न गये हों तो ऐसे काम भी दण्डनीय मतलब गये हैं ।

उपदफा (बी) में किसी कर्मन्वादीको बेजा तर्जिह देनेके लिए अपना कर्मन्वादीमें माथी नाने योग्य आपदाको कम करनेकी मशारे यदि कोई कर्म लिखाया गया है या घुसा दिया गया हो अपना कोई आपदा लिखाई गई हो या उस पर बार पड़ा गया हो तो ऐसा काम ऊर्ध्व समझा जायेगा यह उपदफा भी दो प्राणोंमें विभक्त है पहिले प्राणके अनुसार कोई या वक्त मशारे लिखाया जाना या घुसाया जाना ऊर्ध्व है दूसरे प्राणके अनुसार आपदाका इशारा देना उसे रोकना कर देना या उस पर बार पड़ा कर देना ऊर्ध्व है । ॥ दफाके अनुसार ऊर्ध्व साबित होने पर दो साल तककी सजा दी जावेगी इस दफामें यह नहीं बतलाया गया है कि सजा सारी कैद होगी या सरल कैद इसलिये यह समझना चाहिये कि सारी व सरल दोनों प्रकारकी सजाएँ दी जासकेंगी । यदि किसी रेलवे प्राविडेंट कण्डस दिवालयका कुछ कथना मिलने वाला होवे और वह उस रुपयेको उठा लेवे तो वह ऊर्ध्व नहीं समझा जावेगा क्योंकि प्राविडेंट कण्डस कथना बलीक है और उसका उठालना प्राजेकी कार्रवाई नहीं है वर्यो कि वर्यो वाधानका बस पर एक नहीं होता है देखो—45 Bom 694 मशारे बाईकेरने यह तथ किया था कि दफा १०३ के अनुसार १५ रुपये ऊर्ध्वमें सुमानका बाई अधिवार प्रसीडेंसी पनिरट्टको नहीं है यह ऊर्ध्व एकदमे अनुसार ऊर्ध्व मतलब गये हैं और बनवा फसला करनेका अधिवार कनक अदालत दिशालयको है जो कि ऐसे मामलोंकी सुननेके लिये एक विश्व अदालत है व उसका कार्यक्रम भी भिन्न है देखो—लकी बनाप नरसिंहाणी 25 Mad L. I 577 ॥ दफाके अनुसार दोषी निर्धारित करनेके लिये सुदरईका बतल्य होगा कि वह दिवालयकी नियतको साबित करे । और जब तक कि किये हुए मामले स्वाभाविक पीणाम यहा न निकलना हो तब तक नीयत नहीं मानी जावेगी देखो—अनुपराधीन बनाम आफिशल एमायना 27 I. C 753, किसी कर्मन्वादी दिवालयिया दरखास्त दी इसका बाद उसके किसी कर्मन्वादीने प्रेसी-डेसी मेनिरट्टके यहा घोलादहा (Cheating) का मामला दायर किया तो यह तथ हुआ कि दिवालयकी दरखास्त दे दिये जाने ही से प्रेसीडेंसी मेनिरट्टके अधिवार कर्मन्वादीके विरुद्ध मामला सुननेके नहीं जाते रहते हैं दफा १० में जो सदी कानुनी कार्रवाईका सिद्ध है वे दावाना कार्रवाईका समझना चाहिये 25 Bom 63 परन्तु इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि ऐसे मामलोंमें जब कि बाधक अदालत दिवालयियोंमें दाखिल किये गये हों आर उसके सम्बन्धमें कोई कार्रवाई की जायेगी होवे तो अदालत दिवालयियोंकी आज्ञा होना उचित मनीत होता है देखो—37 Mad. 107. इस दफामें सुमाना किया जाने का कोई उल्लेख नहीं है और इसलिये यदि ॥ दफाके अनुसार ऊर्ध्व किया जाने पर सुनने का वह दिया जाय तो वह साफ तौरसे गलत है, देखो—मोत्याल विश्वास बनाम सरकार बहादुर 32 O W N. 1140.

यदि दफा १०३ (बा) (११) क अनुसार कोई कर्मन्वादी खारिज हो गई हो तो वह ससे ताज्जाद हिन्दकी दफा ४२२ व ४२४ के अनुसार कार्रवाई किये जानेमें रुकावट नहीं पडगी, देखो 61 Rang 664 वह व्यक्ति जो दिवालयी करार दिया जायगा हो तथा जिसकी आपदाद आफिशल एमायनाकी सुदरईमें आर्य हो तो वह ऐसी रिकोके हवायमें जेल नहीं भना जाना चाहिये जिसमें कि वह पहिल ही शागो की जमानत दे चुका हो चाहे उसने अपनी रिताओं पेश न की हों या रक्षाका हुक्म (Protection Order) उमका न मिला हो । रिताओं न पेश करने पर उसके विरुद्ध कानून दिवालयियोंके अनुसार कार्रवाई की जासकती है, देखो—नगरपाल मोदी बनाम लक्ष्मीनारायण गुप्ता A. I. R. 1929. Cal 1144.

दफा १०४ दफा १०३ के जुर्मोंके लिये कार्य क्रम

(१) जब कि आफिशल एमायनी अदालतमें इस बातकी रिपोर्ट करे कि दिवालयियेने

दफा १०३ के अनुसार कोई जुर्म किया है या न कि अदालतको किसी क्रॉन्प्राइड के कहने पर यह विश्वास हो जावे कि दिवालियेने कोई ऐसा जुर्म किया है तो अदालत इस बातका हुकम दे सकती है कि दिवालियेके पास नोटिस निर्धारित किये हुए डंग का भेजना चाहिये कि जिसमें वह बजह जाहिर करे कि उसके विरुद्ध जुर्म क्यों न लगाया जावे ।

(१) नोटिसमें जुर्म की असलियत दिखलाई जावेगी और एक ही नोटिसमें अनेकों जुर्म दिखलाये जासकते हैं ।

(३) ऐसे नोटिसके सुने जानेमें तथा इस नोटिसके अनुसार अदालत द्वारा लगाये हुए जुर्मके सुने जानेमें जहां तक मुमकिन होगा वही तरीका अमलमें लाया जावेगा जो सन् १८६८ ई० के जायदा फौजदारीके इक्कीसवें चैप्टरमें मजिस्ट्रेटों द्वारा चारण्ड कसेज करनेके लिये बतलाया गया है और उस कोर्टके तेईसवें चैप्टरमें बतलाया हुआ हार्दकोर्ट तथा सेशन्स कोर्टमें होने वाले मामलों का तरीका ऐसे मामलोंमें लागू नहीं होगा ।

(४) इस दफाके साथ अनेकों जुर्म एक साथ लगाये जासकते हैं ।

व्याख्या—

इस दफामें दफा १०३ के अन्तर्गत किये हुए छपीसी बरिवाइ विषे जार्जके नियम बतलये गये हैं बरिवाइ उही वक्त बाद की जासकेगी जब कि आफिशल एसायनी इस बातकी रिपोर्ट करे कि दिवालियेने दफा १०३ में बतलाये हुए किसी छपीके दिया है अथवा किसी कर्नैल्वाइके दरखास्त देने पर अदालतको विश्वास हो जावे कि दिवालियेने दफा १०३ में बतलाये हुए जुर्मकी किया है इस प्रकार आफिशल एसायनी की रिपोर्ट तथा किसी कर्नैल्वाइके दरखास्त देने पर यानी दोनों शर्तोंमें अदालत मामला चारू कर सकती है ।

उपदफा (१) के अनुसार अदालत निर्धारित ढंगमें एक नोटिस दिवालियेको इस बातका दे सकती है कि वह ननह जाहिर करे कि उसके विरुद्ध जुर्म क्यों न लगाया जावे ।

उपदफा (२) में बताया गया है कि ऐसे नोटिसमें जुर्म लगाये जातेका कारण दिखलाया जावेगा तथा एक ही नोटिसमें बहुतसे जुर्म एक साथ दिखलाये जासकते हैं अर्थात् अनेक जुर्मके लिये अलग-अलग आवश्यक्ता नहीं है ।

उपदफा (३) में बताया गया है समझ जायता फौजदारीके इक्कीसवें चैप्टरके अनुसार बरिवाइ की जावेगी परन्तु यह दफा सन् १९२६ ई० के संशोधित एक्टके अनुसार बदल गई है और अब अदालत दिवसखिया बजाय इसके कि वह स्वयं मामलोंको सुने प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेटोंके पास भेज सकती है परन्तु ऐसा वह उसी समय करेगी जब कि उसको प्रायः रूपमें यह मान्य हो कि दिवालियेने दफा १०३ के अनुसार किसी जुर्म की टिप्पणी है व उसके विरुद्ध बरिवाइ की जाना चाहिये । अदालत दिवालीया यदि उचित समझे व जिस प्रकार उक्तन समझे मामला भेजेगा पहले प्राथमिक जाच भी कर सकती है । यह संशोधन इसलिये किया गया था कि जिसमें हार्दकोर्टके जनों का मुख्यतः समय छोटे छोटे मामलोंकी तहकीकात व सुनवाईमें बुरा नष्ट न होवे व बरिवाइ फौजदारीक अन्य मामलों की भांति नियम पूर्वक सुननेके बाद की जासके अर्थात् जुर्म साबित होने पर अदालत फौजदारी दिवालिये की दण्ड दे सके । सन् १९२६ ई० के संशोधन एक्टके जारी होनेसे पहले दिवालिपर्वी बरिवाइ चारू हो चुकी थी परन्तु इसके जारी होनेके पश्चात् नजने इत्तायासा मजिस्ट्रेटोंके पास भेजा तो यह तय हुआ कि तद-कीकत संशोधन एक्टके अनुसार होना चाहिये इसी मामलेमें यह भी तय हुआ था कि दफा २७ के अनुसार दिये हुए दिवालि-येके बयानों पर विचार किया जासकता है । देखो—मोतीअल विश्वास बनाम सरकार नं० 32, C W. N. 1140 (The Yearly Digest 1928 P. 1141.)

दफा १०५ बहाल होनेके बाद या तस्फीहा होनेके बाद भी जिम्मेदारी

जब कि दिवालिया दफा १०२ या दफा १०३ में बतलाये हुए किसी जुर्माना दोषी निर्धारित किया गया हो और वह बहाल हो चुका हो अथवा उसका तस्फीहा या स्कीम स्वीकार करती गई हो तो इन कारणोंसे उसके विरुद्ध कार्रवाई रोकी नहीं जावेगी अर्थात् बहाल होने पर या तस्फीहा हो जाने पर भी उसके विरुद्ध फौजदारीकी कार्रवाई चालूकी जावेगी ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार यदि किसी व्यक्तिके बहाल हो जानेके बाद अथवा उसके द्वारा पेशकों हुई रकम या तस्फीहाके स्वीकार किये जानेके बाद-उसके विरुद्ध कोई जुर्माना जिसका उल्लेख दफा १०२ व १०३ में किया गया है मादित होवे तो उसके विरुद्ध उस जुर्माने कार्रवाई जरूरीकी जावेगी अर्थात् मामला चला दिया जावेगा और वह हमसे बरी नहीं समझा जावेगा । यद्यपि हुए दिवालियोंके अथवा उस दिवालियोंके निमेषा तस्फीहा स्वीकार कर लिया गया हो अपनेको बरी नहीं समझना चाहिये अर्थात् उन जुर्माने सम्बन्धमें उनकी जिम्मेदारी उस समय भी बनी रहेगी ।

नवां प्रकरण

दिवालियेकी छोटी कार्रवाइयां

दफा १०६ छोटे मामलोंमें सरसरी की कार्रवाइयां

(१) जब कि अदालतको हजरतनामेले अथवा अन्य किसी प्रकारसे यकीन हो आवे या आफिशल एसायनी अदालतमें रिपोर्ट दे देवे कि दिवालियेकी जायदादकी कीमत तीन हजार रुपयेसे या इससे कम निमतकी हुई तादादसे अधिक न होगी तो अदालत दिवालियेकी जायदाद का प्रत्यक्ष सरसरी तीरसे करनेका हुक्म दे सकती है और तब इस पदकके नियमोंमें निम्नलिखित संशोधन होगा :—

- (अ) अदालतके किसी हुक्मके विरुद्ध बिला उसकी आहवा लिये हुए कोई अपील नहीं की जावेगी ।
- (बी) बिला आफिशल एसायनीके अथवा किसी कर्जदारके दरखास्त दिये हुए दिवालियेका ध्यान नहीं लिया जावेगा ।
- (सी) जब कि मुमकिन होगा जायदाद एक ही हिस्सा रसदीमें बांट दी जावेगी ।
- (डी) उर्ख कम करने तथा कार्य क्रमको सुगम बनानेके लिये जो दूसरे संशोधन निर्धारित किये जावें परन्तु शर्त यह है कि इस दफा की किसी बातसे दिवालियेके बहाल होनेके सम्बन्धमें दिये हुए नियम संशोधित नहीं किये जावेंगे ।

(२) अदालत किसी समय भी यदि उसे उचित प्रतीत हो दिवालिये की जायदादके सम्बन्धमें सरसरीके इन्तज़ाम का हुक्म दे सकती है ।

न्याय्या—

इस दफ़ा में दिवालियेके छोटे मोटे मामलोंमें अधिक समय न लगाने तथा फ़िजूल खर्चों की बचतकी नीयतसे उनकी कार्रवाई को सरसरी तौर पर करनेके नियम बताये गये हैं सरसरीकी कार्रवाई उसी समय की जासकेगी जब कि आफ़िशल एसायनीने रिपोर्टकी हो कि दिवालियेकी जायदाद तीन हज़ारसे अथवा अथर्विंशति निश्चितकी हुई रकमसे अधिककी नहीं होगी अथवा अदालतको हलफ़नामासे अन्य किसी प्रकारसे विश्वास हो जावे कि जायदाद उक्त क्रमसे अधिककी नहीं है । अदालत सरसरीकी कार्रवाई करनेके लिये बाध्य नहीं है । इसका करना न करना अदालतकी इच्छा पर निर्भर है तथा उपदफ़ा (५) से यह भी प्रस्ट है कि अदालत जब चाहे तो सरसरीकी कार्रवाई किये जानेके हुक्मभी मसूख भी कर सकता है और उस वर्क मामूली कार्रवाई अमलमें लाई जावेगी । सरसरीकी कार्रवाई किये जाने का हुक्म होने पर मामूली कार्रवाई जो उस एक्टमें बतलाई जा चुकी है किसी हद तक सशोधित होकर सरसरी वाले मामलोंमें लायी होगी । सशोधनों का उल्लेख उपदफ़ा (१) के क्लॉज (ए), (बी), (सी) व (डी) में किया गया है ।

क्लॉज (ए) के अनुसार बिना अदालतकी आज्ञा लिये हुए अदालतके किसी हुक्मकी अपील नहीं की जावेगी जो एक्टके अनुसार अपील बिना आज्ञाके की जासकती है ।

क्लॉज (बी) के अनुसार दिवालियेके बचतकी आवश्यकता नहीं है परन्तु आफ़िशल एसायनी या कर्जदारके दरख़ास्त देने पर अदालत सरसरीके मामलोंमें भी दिवालियेके बचान ले सकती है ।

क्लॉज (सी) के अनुसार दिवालियेकी जायदाद एक ही बार हिसा रसदीमें बाँटी जासकेगी यह आवश्यक नहीं होगा कि कोई हिसा रसदी होवे व अन्तिम हिसा रसदीके लिये बतलाई हुई नोटिस आदि की कार्रवाई अमलमें लाई जावे, देखो—दफ़ा ७२ खर्च कम करने तथा कार्रवाई को सादा बनानेके लिये ।

क्लॉज (डी) के अनुसार और भी सशोधन जो इस सम्बन्धमें बताये गये हैं प्रवीण किये जावेंगे ।

उपदफ़ा (१) के अन्तर्गत् यह भी बतला दिया गया है कि ऊपरके सशोधनका कोई प्रभाव बढ़ाहट होने की कार्रवाई पर नहीं पड़ेगा अर्थात् बढ़ाहट होनेके सम्बन्धमें वह सब नियम उसी प्रकार प्रयोग किये जावेंगे जितना प्रकार इस एक्टमें मामूली कार्रवायोंके लिये बतलाये गये हैं अर्थात् दफ़ा ३८ से लेकर ४५ तकमें बतलाये हुए नियम बरस्तूर लागू समझना चाहिये ।

दसवां प्रकरण



विशेष नियम

दफा १०७ कारपोरेशन आदिका दिवालियेकी कार्रवाईसे बरी होना

दिवालियेकी दख्खास्त किसी प्रचलित एक्टके अनुसार रजिस्ट्री की हुई किसी कम्पनी, सम्प्रदाय (Association) या कारपोरेशन (Corporation) के विरुद्ध नहीं दी जावेगी ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार रजिस्ट्री हुआ कम्पनी व सम्प्रदाय (Association) दिवालियेकी कार्रवाईसे बचाये गये हैं इसी प्रकार कारपोरेशन (Corporation) भी बचाये गये हैं चूंकि उनकी एगस्टमें (Against) एक्ट कारपोरेशन के लिये एक मर्तवा तथा बादमें एगोभियेशन व कम्पनीके लिये एक साथ दूसरी मर्तवा इस्तेमाल किया गया है व (Registered) राज्यवा प्रयोग कम्पनी व एगोभियेशन ही के सम्बन्धमें किया हुआ मान्य होता है इससे यह प्रस्ट है कि कारपोरेशनके रजिस्ट्री होनेका कोई शिक नहीं है किन्तु कम्पनी व एगोभियेशनका किसी प्रचलित कानूनके अनुसार रजिस्ट्री होना आवश्यक है तब वह बरी हो सकते हैं अर्थात् उस समय उनके विरुद्ध दिवालियेकी दख्खास्त नहीं दी जा सकेगी । रजिस्ट्री हुआ ऐसी कम्पनी आदिके लिये कम्पनी एक्टके अनुसार डिक्लेरेशन (Liquidation) की कार्रवाई असंभवमें अवैध ।

दफा १०८ दिवालियेकी हालतमें मरनेवाले कर्जदारकी जायदादका दिवालिये की कार्रवाईके सम्बन्धमें प्रबन्ध

(१) यदि किसी मरे हुए कर्जदारके कर्जदख्खाहका इतना कर्ज होवे कि जिसके आधार पर वह कर्जदारकी हिन्दगीमें उसके विरुद्ध दिवालियेकी दख्खास्त दे सकता हो तो वह उस अदालतमें जिसकी अधिकार सीमामें कर्जदार मरनेसे छ माह पहिले अधिकतर रहा हो, या व्यापार करता रहा हो निर्धारित किये हुए ढंग पर एक दख्खास्त इस बातका हुक्म होनेके लिये दे सकता है कि उस मृतक कर्जदारकी जायदादका प्रबन्ध इस एक्टके अनुसार किया जावे ।

(२) मरे हुए कर्जदारके कानूनी वारिसको निर्धारित नोटिस दिये जानेके बाद पिटीशनरके कर्ज साधित होने पर अदालत मृतक कर्जदारकी जायदाद का प्रबन्ध दिवालियेके सिलसिलेमें करनेका हुक्म दे सकती है अथवा बजह ज़ाहिर किये जाने पर पिटीशनको मय खर्चके या बिना खर्चके खारिज कर सकती है परन्तु यदि अदालतको इस बातका विश्वास हो जाय कि मृतक कर्जदारके कर्जोंके उसकी जायदाद द्वारा चुका दिये जानेकी अवैध सम्भावना है तो वह उसकी जायदादका प्रबन्ध दिवालियेके सिलसिलेमें किये जानेका हुक्म नहीं दे सकती है ।

(३) इस दफाके अनुसार जायदादके प्रबन्धकी दख्खास्त अदालतमें उस समय नहीं दी जावेगी जब कि किसी दूसरी अदालतमें मृतक कर्जदारकी जायदादके प्रबन्धके लिये कार्रवाई चालू की जा चुकी हो, परन्तु यह दूसरी अदालत ऐसे मामलोंमें इस बातका सुवृत्त होने पर कि

मृतक कर्जदारकी जायदाद उसके कर्जोंको चुकानेके लिये अर्पयार्त है उस दरखास्तकी कार्रवाई को उस अदालतके पास भेज सकाया है जिसे इस एक्टके अनुसार दिवाणियेकी कार्रवाई करनेके अधिकार प्राप्त हैं और तब अन्तमें बतलाई हुई अदालत (अदालत दिवाणिया) मृतक कर्जदारकी जायदादके प्रबन्धका हुक्म दे सकती है और यही नतीजा उस समय होगा जो किसी कर्जद्वारा द्वारा दी हुई दरखास्त पर प्रबन्धका हुक्म होने पर होता है।

व्याख्या—

इस दफ्तेके अनुसार मो हुए कर्जदारकी जायदादके विरुद्ध दिवाणियेकी कार्रवाई बर्नासम्ती है। वह कर्जद्वारा ऐसी दरखास्त दे सकता है जो कर्जदारकी ज़िन्दगीमें अपने कर्जके आधार पर दिवाणियेकी दरखास्त दे सकना ही ऐसी दरखास्त के जाने पर मो हुए कर्जदारके कानूनी उत्तराधिकारियोंको नोटिस दिया जावेगा तथा उनका विशेष सुननेवाला इस बातमें विश्वास होने पर कि मृतक कर्जदारके सब कर्ज उसकी जायदादसे नहीं चुकाये जा सकते हैं अदालत दिवाणियेकी कार्रवाई निये जानेका हुक्म दे सकती है। अदालतको यदि यह यकीन होजावेगा कि मृतक कर्जदारके सब कर्ज उसकी जायदादसे उठाये जासकते हैं अथवा कर्जदारके वारिसोंकी उत्तरदायी किसी अन्य कारणसे कभी समझ पड़े तो अदालत दरखास्तकी जातिन कर सकती है अर्थात् वैसी दशामें अदालत मृतक कर्जदारकी जायदादका प्रबन्ध दिवाणियेकी कार्रवाईके सम्बन्धमें नहीं होने देवेगी। यदि किसी दूसरी अदालतमें मृतक कर्जदारकी जायदादके प्रबन्धके सम्बन्धमें कार्रवाई चाहनी आ रही हो तो अदालत दिवाणियामें इस दफ्तेके अनुसार प्रबन्ध निये जानेकी दरखास्त नहीं दी जावेगी अर्थात् ऐसी दरखास्त दिये जाने पर वह रर्जिज बाह्य नहीं होगी।

उपदफा (३) में यह भी बतला दिया गया है कि यदि अदालत दिवाणियेकी अतिरिक्त अन्य किसी अदालतमें ऊपर बतलाये अनुसार प्रबन्धकी कार्रवाईकी जा रही हो आर उस दूसरी अदालतकी यह शायद पड़े कि मृतक कर्जदारकी जायदाद उसका कर्ज चुकानेके लिये पर्याप्त नहीं है तो वह दूसरी अदालत अपने यहाँ की कार्रवाईके सम्बन्धन दिवाणियामें भेज सकती है। इस प्रकार भेजे जाने पर अदालत दिवाणिया अपने अधिकारोंके अनुसार उस जायदादके प्रबन्धको कार्रवाई करेगी य इस एक्टके नियम लागू होंगे। यदि मृतक कर्जदारका लड़ना उमरके बच्चोंके रूप में होवे तो लेटर ऑफ़ अडमिनिस्ट्रेशन (Letters of administration) मिल सकते हैं वरों कि वेसी हालतमें केवल इन्हीं दफ्तेके अनुसार कार्रवाई असम्भवे नहीं छाई जाना चाहिये अर्थात् कर्जद्वारा या अन्य व्यक्ति दूसरे कानूनोंके अनुसार जा लागू होते हैं कि कार्रवाई कर सकते हैं देखो—15 Cal. W. N 350

दफा १०९ जायदादका मिलना तथा उसके प्रबन्धका तरीका

(१) दफा १०८ के अनुसार मृतक कर्जदारकी जायदादके प्रबन्धका हुक्म होने पर जायदाद अदालतके आफिशल एसायनरीके प्रबन्धमें आजावेगी और यह इस पर इस एक्टके नियमोंके अनुसार जायदादको वसूल करेगा या बांटेगा।

(२) आगे दिये हुए संशोधनोंके साथ तीसरे भागके सब नियम जिनका सम्बन्ध दिवाणियेकी जायदादके प्रबन्धसे है उस हद् तक लागू होंगे जहाँ तक वह लागू होसकते हैं तथा इस प्रकारका हुक्म उसी प्रकार माना जावेगा जैसा कि इस एक्टके अनुसार दिया हुआ दिवाणिया क्रार दिया जानेका हुक्म।

(३) आफिशल एसायनरी, प्रबन्धका हुक्म होने पर मृतक कर्जदारकी जायदादका प्रबन्ध करते समय मृतकके कानूनी वारिसके उस दिवाणिया ध्यान रखेगा जो वह उचित मृतक संस्कार

कार्तिक सम्बन्धमें तथा मृतक कर्जदारकी जायदादकेलिये कानूनी खर्च करनेके सम्बन्धमें करेगा। और यह दावे इस हुक्मके अनुसार तर्जोह वाले कर्जे समझे जायेंगे और दूसरे कर्जोंके मुकाबिले सबसे पहिले पूर्ण रूपसे चुकाये जावेंगे।

(४) यदि मृतक कर्जदारकी जायदादका प्रबन्ध करने पर उसके सब कर्जों पूर्ण रूपसे चुकाये जानेके पश्चात् आफिशल एसायनीके पास कुछ रकम फाजिल बचे तथा प्रबन्धना खर्च या दिवालियेके सम्बन्धमें इस एन्टमें बतलाया हुआ खर्च भी अदा कर दिया गया हो तो बचत मृतक कर्जदारकी जायदादके कानूनी वारिसको दो जायगी अथवा अन्य किसी निर्धारित ढंग पर उसका प्रयोग किया जावेगा।

व्याख्या—

दफा १०६ के अनुसार दाखलानेके मजूर किये जाने पर अर्थात् मृतक कर्जदारकी जायदादका प्रबन्ध दिवालियेकी वारिसाईके अनुसार किये जानेका हुक्म होने पर मृतक कर्जदारकी जायदाद आफिशल एसायनीके प्रबन्धमें आजावेगी और वह सब जायदादको मितनी एन्ट हो सकेगा बसूत रहेगा तथा बाद बसूनी कानूनके अनुसार उसी कर्जकारोंमें बांट देगा।

उपदफा (२) के अनुसार इस एन्टके तालीम भरणमें बतलाये हुए नियम जहां तक कि उनका तात्त्विक समझा जायेगा इस दफाके अनुसार वारिसाई किये जानेमें लागू होंगे।

उपदफा (३) में यह बतलाया गया है कि यदि मृतक कर्जदारके किसी वारिसने मृतक संस्कारमें अथवा मृतक कर्जदारकी जायदादके सम्बन्धमें कोई कानूनी खर्च किया हो तो आफिशल एसायनीका कर्तव्य होगा कि वह ऐसे खर्चोंकी सभ से पहिलेका कर्ज माने तथा उसकी पूर्ण रूपसे मृतककी जायदादसे सबसे पहिले चुका देवे। इस प्रकार इस उप दफाके अनुसार इन वारिसोंके खर्चोंकी रक्षाई गई है जो वारिस होनेके कारण उनकी मृतक कर्जदारके सम्बन्धमें करना पड़े हों।

उपदफा (४) में बतलाया गया है कि यदि मृतककी जायदादसे उसके सब कर्जों पूर्ण रूपसे चुकाये जा चुके तथा मृतक जैसा कि इस एन्टमें बतलाया गया है चुकाया जा चुका हो और प्रबन्धके लिये किये हुए खर्च भी अदा किये जा चुके हों और इसके बाद कोई जायदाद या रूपया बचे तो वह मृतक व्यक्ति के कानूनी वारिसोंको दिया जावेगा या किसी अन्य निर्धारित किये हुए ढंग पर लगाया जावेगा। जायदादका प्रबन्ध आफिशल एसायनी इस दफाके अनुसार वही प्रकार कर सकेगा जिस प्रकार कि किसी व्यक्ति के दिवालिया करार किये जाने पर उसकी जायदादका प्रबन्ध वह इस एन्टके अनुसार कर सकेगा।

दफा ११० कानूनी वारिस द्वारा रुपयेकी अदायगी या जायदादका अलहदा किया जाना

(१) दफा १०८ के अनुसार दी हुई दखलास्तके दिये जानेकी सूचना होनेके पश्चात् कानूनी वारिसने यदि कोई अदायगीकी हो या उसने कोई इन्तकाल जायदाद किया हो तो उससे यह कोई छुटकारा नहीं पावेगा जहां तक उसका वह आफिशल एसायनीका एक दूसरेसे सम्बन्ध है।

(२) ऊपर बतलाई हुई बातको छोड़ कर दफा १०८ दफा १०६ या इस दफाकी कोई बात कानूनी वारिस द्वारा नेकनीयतासे किया हुआ कोई काम कोई बात अथवा कोई अदायगी रह नहीं करेगी यदि यह काम प्रबन्धका हुक्म होने से पहिले किया गया हो इसी प्रकार यदि डिस्ट्रिक्ट जज ने दि एडमिनिस्ट्रेटर जनरल एन्टकी दफा ६४ के अनुसार दिये हुए अधिकारोंका प्रयोग करते हुए कोई अदायगी का काम या बातकी हो तो वह भी रह नहीं होगी।

व्याख्या—

उपदफा (१) के अनुसार यदि मृतक कर्जदारकी जायदादके प्रबंधके लिये दफा १०८ के मुअज्जिफ दख्खास्त दीगइ हो और ऐसी दख्खास्तकी सूचना हो जानेके पश्चात् उस कर्जदारका कानूनी वारिस कोई अदायगी करे या कोई इन्तज्जुअ जायदाद करे तो उससे वह आकिसल एसायनीके विरुद्ध लाम नहीं उठा सकता है अर्थात् ऐसी अदायगीमें उसे हटकरा नहीं मिलेगा ।

उपदफा (२) में बतलाया गया है कि प्रबन्धका हुक्म होनेमें पहिले यदि जेन्नीयतमें मृतक कर्जदारके वारिस ने कोई अदायगीकी हो या अन्य कोई काम किया हो तो वह अदायगी या काम ठीक समझा जावेगा और इस दफाके अन्सार अर्थात् दफा १०८ व १०९ के अनुसार वह रद्द नहीं हो सकेगा । इस दफामें यह भी बतलाया गया है कि यदि डिस्ट्रिक्ट जजने अपने कानूनी अधिकारोंको बतते हुए कोई अन्त्ययगीकी हो या काम किया हो तो वह भी रद्द नहीं समझा जावेगा किन्तु वह ठीक माना जावेगा । अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए 'Shall' शब्दसे प्रकट है कि इस दफाके नियमोंकी अवहेलना नहींकी जावेगी किन्तु उसको पाबन्दी आवश्यक है । एडमिनिस्ट्रेटर जनरल एक्ट १८७४ जिसका थिक उपदफा (२) में है रद्द किया जा चुका है और उससे स्थान पर एडमिनिस्ट्रेटर जनरल एक्ट ३ सन् १९१३ चाड़ है ।

दफा १११ एडमिनिस्ट्रेटर जनरलके अधिकारोंकी रक्षा

यदि एडमिनिस्ट्रेटर जनरलको किसी मृतक कर्जदारकी जायदादके प्रबन्धके लिये किसी मामलेमें प्रोबेट या लैटर्स आफ एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया हो तो उस मामलेमें दफा १०८, १०९ व ११० के नियम लागू नहीं होंगे ।

व्याख्या—

इस दफाके अन्सार मृतककी जायदादका प्रबंध एडमिनिस्ट्रेटर जनरलके हाथ आने पर उस जायदादका प्रबंध दिया-लियेकी कार्रवाईके अनुसार नहीं किया जावेगा बल्कि इस बातका ध्यान रहना चाहिये कि एडमिनिस्ट्रेटर जनरलने उस जायदादका प्रबंध प्रोबेट (Probate) अथवा लैटर्स आफ एडमिनिस्ट्रेशन (Letters of Administration) के सिन्डिलेमें मिला हो । इस दफासे यह भी प्रकट है कि जब जायदादका प्रबंध प्रोबेट या लैटर्स आफ एडमिनिस्ट्रेशनके आधार पर एडमिनिस्ट्रेटर जनरल द्वारा किया जा रहा हो तो दफा १०८, १०९ व ११० के कोई नियम लागू नहीं होंगे अर्थात् कानूनी वारिस द्वारा की हुई अदायगी या इन्तज्जुअ आदिवा रद्द होना या उनका ठीक माना जाना इस दफाओंमें बतलाये हुए नियमोंके अनुसार नहीं समझा जावेगा अंग्रेजी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है कि इस दफाके नियमोंकी पाबन्दी आवश्यक है ।

ग्याह्व्रां प्रकरण

नियम (रुख)

वर्षा ११२ रुख

(१) इस एक्टके उद्देशों को धार्यग्यमें परिगणित करनेके लिये यह अशासनने निम्नलिखित अनुसार अधिकाय प्राप्त हैं समय समय पर नियम (रुख) बनायेगा ।

(२) इन नियमोंमें ग्रामका तथा उपर वर्णनामें हुए अधिकारोंमें विषय कक्षाएँ टालि हुए निम्नलिखित बातोंकी व्याख्या तथा उनका नियन्त्रण किया जायकता है :-

(ए) यह कि इस एक्टके अनुसार कयाकी, या कयाकी, या कयाकी लिये जाना चाहिये और किस प्रकार यह इच्छाकी जायेगी, य उम्मा हिमाय दिया जायेगा और किस हिमायमें यह अक्षाकी जाना चाहिये ।

(बी) यह कि ऐसे हिमाय उम्माकी जान लिये गया हो अलहदा अलहदा या इच्छाकी काममें लगाना या दिननिर्देश जायदतीका बचा हुआ रुपया य उम्मा सम्बन्ध रखने वाला और रुपया चाहि दिवालिवा इस एक्टके अनुसार लक्ष्य पिटने किसी कानूनके अनुसार दिवालिवा कया दिया गया हो कैसे लगाना चाहिये ।

(सी) यह कि दिवालिवाके कर्तव्योंकी जायदाद पर अतिशय धन घनी दाग किस प्रकार कया जाना चाहिये तथा उन्हे किस प्रकार बण्ट करना चाहिये ।

(डी) यह कि अतिशय धनघनीका क्या धनघन (रूम) होना चाहिये ।

(ई) यह कि अतिशय धनघनीका दाग की जाने य ली गयी, अदायगी तथा हिमाय किस प्रकार हो ।

(एफ) अतिशय धनघनीके हिमायकी जांच (Audit) किया जाना ।

(जी) अतिशय धनघनीके धनघनका अदा किया जाना, लुचें धनघनका अदा किया जाना, अतिशय धनघनीके धनघनका लुचें तथा उम्माके हिमायकी जांचका लुचें इन लुचेंका उम्माके लक्ष्य लक्ष्य हुए लुचेंकी अदायगीमें अदा किया जाना ।

(एच) ऊपर वर्णनाई हुई धनघनीमें अशासनकी आशानुसार अतिशय धनघनीका दाग योग्यलिने वाले, दिवालिवाके विरुद्ध पैगवा करने तथा अदायगी वांछितमें लुचें करना

(आई) अदायगीके लुचें अथवा आदेशके अन्तर्गत कार्यवाई करने वाले अतिशय धनघनीका दाग पैगवा की हुई किसी दीवानकी आशानुसार अदा किया जाना ।

(जे) दिवालिवाके कर्तव्यों तथा कर्तव्योंकी दागियाल लक्ष्य या लक्ष्यके प्रदायकों सम्बन्धमें कार्यवाई किया जाय ।

(के) दिवालय तथा उनकी जायदादके सम्बन्धमें दी हुई दरखास्तों तथा उनके मामलों क सुने जानेमें आफिशल पसायनी द्वारा हस्तक्षेप किया जाना ।

(पल) बिला बहाल हुए दिवालियेके हिसाबकी किताबों व कामगजातकी आफिशल पसायना द्वारा जांच की जाना ।

(एम) इस एक्टके अनुसार होने वाली कार्रवाईयोंमें नोटिसकी तामील

(एन) जांच कमेटीकी नियुक्ति उनकी मीटिंग तथा उनके कार्य करनेका तरीका

(थो) इस एक्टके अनुसार किसी फर्मके मामले कार्रवाईका किया जाना

(पी) इस एक्टके अनुसारकी जाने वाली कार्रवाईयोंमें जो फार्म प्रयोग किया जाना चाहिये ।

(फ्यू) जो जायदाद सरसरी तौर पर देखी जाना चाहिये उनके प्रबन्धमें किस प्रकार कार्रवाई करना चाहिये ।

(आर) भरे हुए कर्जदारों की जायदादका प्रबन्ध जो इस एक्टके अनुसार किया जावेगा किस प्रकार किया जाना चाहिये ।

व्याख्या—

उपदफा (१) के अनुसार इस एक्टके मामलोंके कार्यरूपमें परिणत करनेके लिये अदालतें समय समय पर नियम (रूल) बना सकती हैं ।

उपदफा (२) में उपदफा (१) के अनुसार बनाये जाने योग्य रूलसका वर्णन किया गया है । इस उपदफामें यह नहीं बताया गया है कि कौन २ से रूलस होंगे किन्तु यह बतलाया गया है कि किन किन मामलोंके सम्बन्धमें ऐसे रूलस बनाये जाना चाहिये यह उपदफा १८ डायमें विभक्त है तथा उन सब बातोंका उल्लेख इन डायमें कर दिया गया है गिनके सम्बन्धमें कुछ नियमोंके बनाए जानेकी आवश्यकता है जैसे कि कर्जदारोंकी मीटिंग किस प्रकार होना चाहिये, नोटिस किस प्रकार जाना चाहिये, उसकी जांच किस प्रकार होना चाहिये, आफिशल पसायनी को क्या अधिकार मिलना चाहिये इत्यादि के बारे में ।

दफा ११३ रूलसके लिये स्वीकृति मिलना

इस भागके नियमोंके अनुसार बनाये हुए रूलसके लिये स्वीकृति, कलकत्ता हाईकोर्टके लिये सपरिषद् गवर्नर जनरल हिन्दुसे हासिलकी जाना चाहिये तथा अन्य अदालतोंके लिये उनकी प्रान्तिक सरकारसे हासिल की जावेगी ।

व्याख्या—

कमेडी एक्टकी इस दफामें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दमें प्रकट है कि इस दफाके नियमों की अवहेलना नहीं की जाना चाहिये । सिवाय कलकत्ता हाईकोर्टके अन्य अदालतों द्वारा बनाये हुए रूलसके अन्य स्वीकृति प्रान्तिक सरकारों द्वारा ली जावेगी । कलकत्ता हाईकोर्टके रूलसके लिये स्वीकृति सपरिषद् गवर्नर जनरल हिन्दु द्वारा दी जाना चाहिये । ऐसी स्वीकृति मिलनेके पश्चात् वह रूलस कार्यरूपमें धीमेधिये लागू किये जासकेंगे अन्यथा वह अपूर्ण समझे जावेंगे ।

दफा ११४ रूलसका प्रकाशित किया जाना

इस प्रकार बनाये हुए तथा स्वीकृति प्राप्त किये रूलस गज़ट आफ़ इण्डिया या प्रान्तिक

सरकारी गजटमें प्रकाशित किये जावेंगे जैसा कि मामला होवे और इससे बाद उस अदालतमें जिसने द्वारा वह बनाये गये हैं इस एक्टकी कार्रवाईके लिये वही असर रखेंगे जैसे कि मानो वह इस एक्टके साथ बनाये गये हों ।

व्याख्या—

अपेक्षी एक्टकी इस दफामें भी (Shall) शब्दका प्रयोग है निम्नो यह एक्ट है कि कम्पक सरकारी एक्टमें प्रकाशित किया जाना आवश्यक है । कलन्तार हाइकोर्टके कम्प गजट भाग इतिहासमें प्रकाशित किए जावेंगे तथा अन्य अदालतोंके कलन्तार प्रान्तिक सरकारी गजटमें प्रकाशित किये जावेंगे और प्रकाशित होनेके पक्षपर यह कम्प कितने अदालतों द्वारा बनाये गये होंगे उसके लिये वही प्रसार प्रयोग किये जायेंगे निम्न प्रकार इस एक्टके नियम कर्षण करना एक प्रकारसे इस एक्टके साथ बनाया हुआ कानून मान लिया जावेगा ।

वारहवां प्रकरण



दफा ११५ इस एक्टके अनुसार किये हुए इन्तकाल आदिका स्टाम्प या करसे वरी होना

(१) अदालतके सामने तथा अदालतके हुक्मके अनुसार किये हुए हर एक इन्तकाल जायदाद, रेंटन मामा, जायदादका किसीके नाम किया जाना मुस्ताफानामा, सादीका कागज (Proxy Paper), सर्टीफिकेट, हलफनामा दस्तावेज या दूसरी कार्रवाई दस्तावेज या दख्खीर या इनकी कोई नकलमें स्टाम्प या दूसरे किसी प्रकारका कर नहीं लगगा ।

(२) इस एक्टके अनुसार आधिकार एसायनी द्वारा ही हुई दरख्वास्तमें कोई स्टाम्प ड्यूटी या दूसरी कीस नहीं ली जावेगी या अदालत द्वारा ऐसी दरखास्त पर दिये हुए कि " आदिक किये जाने या जारी करने पर भी स्टाम्प, ड्यूटी या कोई फीस नहीं ली जावेगी ।

व्याख्या—

आधिकार एसायनी की तरफसे काय बनवाने दायीगी भी बड़ी सुविधा प्राप्त होगी या आधिकार एसायनी दायीगीमें इस दफाके अनुसार प्राप्त है । इस कारण यह जगह विधिकी अधिकारोंके प्रयोग किये हुए किसी आदिक होना उसकी नकलमें किये कोई स्टाम्प नहीं देना पड़ेगा, दफा ११५ Mad १४७.

उपदफा (१) के अनुसार विधिकी कार्रवाईके समयमें अदालतके हुक्म द्वारा किये हुए इन्तकाल जायदाद आदि दस्तावेजों पर स्टाम्प नहीं लगवा जावेगा । इसी प्रकार इन दस्तावेजोंकी नकलमें भी कोई स्टाम्प लागू नहीं होगा ।

उपदफा (२) के अनुसार आधिकार एसायनी द्वारा ही हुई दरख्वास्तों तथा उनके अनुसार दिये गये किये हुए दस्तावेजों पर भी स्टाम्प नहीं लगवा जावेगा ।

दफा ११६ गज़ट, शहादत होगा

(१) वह सरकारी गज़ट जिसमें इस एक्टके अनुसार दिया जाने वाला नोटिस प्रकाशित हुआ हो नोटिसमें दिखलाई हुई बातोंका शहादत होगा ।

(२) वह सरकारी गज़ट जिसमें दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मका प्रकाशन किया गया हो दिवालिया करार दिये जाने वाले हुक्मके लिये तथा उसकी तारीखके लिये पूरी शहादत माना जावेगा ।

व्याख्या—

अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किया हुआ (Shall) शब्दसे प्रारंभ है कि इस दफाके नियमोंकी अवहेलना नहीं की जाना चाहिये तथा उनकी पाबंदी की जावेगी । यदि नोटिसमें दिखलाई हुई बातोंका सुन्दर देना हो तो उपदफा (१) के अनुसार वह सरकारी गज़ट जिसमें नोटिस प्रकाशित किया गया हो काफी शहादत माना जावेगा ।

उपदफा (२) के अनुसार दिवालिया करार देनेका हुक्म देने में बाने तथा उसके दिये जानेकी तारीख उस सरकारी गज़टके अनुसार मानी जावेगा जिसमें दिवालिया करार दिया जानका हुक्म प्रकाशित किया गया हो । इस प्रकार इस दफामें अदालतकी अगली दृष्टिके पेश करने अथवा किसी नोटिसमें दी हुई बातोंके सामने कम्बरे लिए मिसिल ब लिखने वाले को तत्त्व करानेकी आवश्यकता नहीं है किंतु सरकारी गज़ट सुन्नेमें पेश किया जायकता है ।

दफा ११७ हलफनामेकी तस्दीक

निम्न प्रकारसे तस्दीक किये हुये हलफनामे इस एक्टके अनुसार अधिकारोंको धर्तने वाली अदालतोंमें प्रयोग किये जासकते हैं :—

(ए) ब्रिटिश इण्डियामें

(१) किसी भी अदालत या मजिस्ट्रेट, या

(११) जायता दीवानी सन् १६०८ ई० के अनुसार हलफ देनेका अधिकार पाया हुआ कोई अफसर या दूसरा व्यक्ति द्वारा तस्दीक किये हुए ।

(बी) इंग्लैंडमें किसी भी ऐसे व्यक्तिके सामने जिस शाहंशाहके हाईकोर्टमें हलफ देनेका अधिकार प्राप्त हो, या लॉकास्टर की काउण्टी पैलेटाइनके चान्सेरी अदालतमें, या किसी बैरफ्फी अदालतके सामने, या बक्रफ्सी कोर्टके किसी अधिकार प्राप्त अफसरके सामने जिसे लिखकर उस अदालतके किसी जजने इसके लिये अधिष्ठा दिया हो या किसी ऐसे काउण्टी अथवा जगहके जस्टिस अफ दि पीसके सामने जहां कि वह हलफनामा तस्दीक किया गया हो ।

(सी) स्काटलैण्ड व आयरलैण्डमें किसी आरटिंगरी जज मजिस्ट्रेट या जस्टिस आफ दि पीसके सामने, और

(डी) किसी दूसरी जगहमें किसी मजिस्ट्रेट जस्टिस आफ दि पीस या अन्य किसी ऐसे व्यक्तिके सामने जिस उक्त स्थानमें हलफ देनेका अधिकार प्राप्त हो (ऐसे व्यक्ति

लिये किसी ब्रिटिश मिनिस्टर या ब्रिटिश कौन्सल या ब्रिटिश पोलिटिकल एजेण्ट या नोटरी पब्लिकको इस बातका सर्टीफिकेट देना चाहिये कि वह मजिस्ट्रेट, जस्टिस आफ दी पीस या उक्त प्रकारसे अधिकार प्राप्त व्यक्ति है ।

व्याख्या—

इस दफामें इल्फनामोंके तस्दीक किये जानेकी व्यवस्था नती गई है । हर जगह इस दफामें बतलाये हुए नियमोंकी पाबंदी कले हुए इल्फनामोंके तस्दीक किये जासकते हैं । ब्रिटिश भात इन्डियन, स्टाट्यूट्स न अपारलैण्डके लिये अदालत या अन्य व्यक्तिके नाम बतला दिये गये हैं जो इल्फनामा तस्दीक कर सकते हों । इनके अतिरिक्त अन्य स्थानोंमें भी अधिकार प्राप्त व्यक्ति या अदालतें इल्फनामा तस्दीक कर सकती हैं पन्तु ऐसे व्यक्ति या अदालतोंकी तस्दीक ऊपर उपद्रका (४) के अन्तमें बतलाये हुए ब्रिटिश आकितों द्वारा ही जाना चाहिये ।

दफा ११८ व्यवहारिक गलतीके कारण कार्रवाईयां रह नहीं होनी चाहिये

(१) दिवालियेके सम्बन्धमेंकी हुई कोई कार्रवाई किसी व्यवहारिक गलती या वेतर्तीवीके कारण उस वक्त तक रह नहीं होगी जब तक कि वह अदालत जिसके सामने किसी कार्यवाईके लिये एतराज किया गया हो यह राय न कायम करे कि उस व्यवहारिक गलती या वेतर्तीवीके कारण बड़ी बेइन्साफी हो गई है और वह बेइन्साफी अदालतके किसी हुक्म द्वारा नहीं सुधारा जासकती है

(२) आफिशल एसायनी या जांच कमेटीके किसी मेम्बरकी नियुक्तिमें यदि कोई गलती या वेतर्तीवी हुई हो तो किसी ऐसी गलतीसे उसके द्वारा नेक्नीयसीसे किया हुआ कोई काम रह नहीं होगा ।

व्याख्या—

यदि कोई व्यवहारिक गलती या वेतर्तीवी हो जावे जेमे कि लिखने आदिमें कुछ रह जावे परंतु उसमें कोई बिशेष बेइन्साफी न होती हो अथवा जो बेइ साफी होती हो वह अदालत अपने हुक्म द्वारा ठीक कर सकती हो तो ऐसी गलती या वेतर्तीवीके कारण अदालतकी कार्रवाई उपद्रका (१) के अनुसार रह नहीं होगी । ऐसा कार्रवाई उसी समय रह होगी जब कि एतराज सुनने वाली अदालतकी रायमें उक्त गलती या वेतर्तीवीसे बड़ी बेइ साफी हुई हो या वह बेइ साफी किसी दूसरे हुक्म से न सुधारा जासकती हो ।

उपद्रका (२) के अनुसार यदि आफिशल एसायनीकी नियुक्ति या जांच कमेटीके किसी मेम्बरकी नियुक्तिमें कोई गलती या वेतर्तीवी हुई हो और इस प्रकार नियुक्ति किये हुए व्यक्तने नेक्नीयसीसे कोई काम किये हों तो उसके द्वारा किये हुए काम रह नहीं होंगे अर्थात् ठीक समेत जावेंगे । अमेनी एक्टमें प्रयोग किये हुए (Shall) शब्दमें प्रकट है कि इस दफा के नियमकी पाबंदीकी जावेगी तथा उसकी अवहेलना नहीं की जाना चाहिये ।

दफा ११९ ट्रस्टीके दिवालिया होने पर दूसरे एक्टका लागू होना

यदि इण्डियन ट्रस्टीज एक्ट १८८६ के अनुसार कोई ट्रस्टी होवे और वह दिवालिया कारार दिया जावे तो उस एक्टकी दफा ३५ लागू होगी जिससे आवश्यकता प्रतीत होने पर उस दिवालिये के स्थान पर नया ट्रस्टी नियुक्त किये जानेका अधिकार दिया जासकता है (चाहे वह दिवालिया स्वयं इस्तीफा देवे या न देवे) और उस एक्टके तथा उस एक्टसे सम्बन्ध रखने वाले दूसरे एक्ट के सब नियम इसके पश्चात् लागू होंगे ।

व्याख्या—

इस दफ्तरे इण्डियन ट्रस्टीज एक्ट १८६६ के अनुसार ट्रस्टी होने वाला यदि कोई व्यक्ति दिवालिया कारा दिया जावे तो ट्रस्टीज एक्ट की दफा ३५ का लागू होना मतलब गंगा है अर्थात् उसका स्थान पर दूसरे ट्रस्टीकी नियुक्त होना चाहे ट्रस्टीज एक्ट (Trustees Act 1866) की दफा ३५ इस प्रकार है :—

“ उन सब मामलोंमें जिनमें नये ट्रस्टी या ट्रस्टियोंमें नियुक्त किया जाना आवश्यक हो और ऐसा करना निम्न हाई-कोर्टकी मददके उचित न मान्य होता हो अथवा कठिन हो या किया ही न जा सकता हो तो अदालत कानूनन नये ट्रस्टी या ट्रस्टियोंको नियुक्त कर सकती है चाहे ऐसा हुक्म दिये जाने समय कोई ट्रस्टी होवे या न होवे और यदि कोई ट्रस्टी होवे तो नये ट्रस्टी उनके स्थान पर अथवा उनके अतिरिक्त बनाने जा सकते हैं। ऐसे हुक्मके अनुसार होने वाले ट्रस्टी या ट्रस्टियोंकी वही अधिकार प्राप्त होंगे जो उनको रिक्त बाकायदे दायर किये हुए मामलोंमें डिकी होने पर प्राप्त हो सकते थे” । इस दफ्तरे यह प्रष्ट है कि किसी ट्रस्टीके दिवालिया कारा दिये जाने पर उसके स्थानमें दूसरा व्यक्ति कानूनन नियुक्त किया जा सकता है ।

दफा १२० सरकारको पाबंद करने वाले कुछ नियम

केवल उन बातोंको छोड़ कर जो बतलाई गई हैं इस एक्टके नियम जो किसी दिवालियेकी जायदादके विरुद्ध कार्रवाईके सम्बन्धमें होंगे, कर्जोंका एक दूसरेसे पहिले अदा किया जाना, तरफिया या तय होनेकी स्वीमका प्रभाव और बहाल होनेका प्रभाव इन सब बातोंकी पाबन्दी सरकार पर होगी ।

व्याख्या—

अंग्रेजी एक्टमें प्रयोग किये हुए शब्द (Shall) का अर्थ प्रष्ट है कि इस एक्टके नियमोंकी अवहेलना नहीं की जायेगी तथा बहाल होनेका प्रभाव आदि अन्य दिसलाई हुई बातोंकी पाबन्दी सरकार पर भी होगी ।

दफा १२१ मुलाकातके अधिकारोंकी बचत

इस एक्टकी कोई बात या इसके अनुसार किये हुए अधिकार परिवर्तनके होने पर कोई बात किसी व्यक्तिके मुलाकातके अधिकारोंको जो उसे इस एक्टके प्रारम्भ होनेसे पहिले प्राप्त हों नहीं लागू होगी या यदि दिवालिये कर्जदारोंके हुक्मारेके लिये दिवालियेकी कार्रवाईके सम्बन्धमें इस प्रकार का अधिकार प्राप्त न रहा हो तो वह अधिकार वहीं दिया जावेगा ।

दफा १२२ उन हिस्सा रसदीका, जिनका कोई दावेदार न होवे सरकारको मिलना

यदि आफिशल प्रमायनीके हाथमें कोई ऐसा हिस्सा रखदी होवे जो प्लानसे १५ साल तक या इससे कम नियत किये हुए किसी समय तक न लिया गया हो तो वह उस स्थानकी गवर्नमेंट आफ़ प्रोपर्टीके हिस्सावमें उसके नाम जमा कर देवेगा अगर इसके विरुद्ध अदालत कोई दूसरा हुक्म न देवे ।

व्याख्या—

हिस्सा रसदीका मर्यादा ऐलानके बाद १५ सालके अंदर अथवा अन्य निर्धारितमें हुई मर्यादके अन्दर न लिया जाने पर इस दफ्तरे अनुसार सरकारी हो जावेगा परन्तु अदालतकी अधिमता है कि वह इसके विरुद्ध भी कोई आज्ञा दे देवे व ऐसे हुक्मके होने पर वह स्थान मर्यादा सरकारी हो जावेगा जानेके उस हुक्मके अनुसार लपटा जावेगा ।

दफा १२३ दफा १२२ के अनुसार सरकारमें दिये हुए रुपये पर दावे

यदि दफा १२२ के अनुसार कोई रुपया भारत सरकारके हिसाबमें दे दिया गया हो और कोई व्यक्ति उस रुपये पानका अधिकारी अपनेको बतलावे तो वह उस रुपयेके मिलनेके लिये अदालतमें दरखास्त दे सकता है और अदालत जब कि उसे विश्वास हो जाये कि दावा करने वालेका हक उन रुपये पर पहुँचता है उस रुपयेके दिये जानेका हुक्म देवेगी परन्तु शर्त यह है कि भारत सरकारमें आम किये हुए रुपयेके दिये जानेका हुक्म देने से पहिले अदालत गवर्नर जनरल हिन्दु द्वारा इसी लिये नियुक्त किये अफसर पर इस बातका नोटिस तामील करेगी कि वह अफसर एक महीनेके अन्दर बजह जाहिर करे कि रुपयेके दिये जानेका क्यों न हुक्म दिया जाये ।

व्याख्या—

यदि कोई दफा न लिये जानेके कारण भारत सरकारसे दफा १२२ के अन्सार पर मिल गये हों और इसके बाद उन रुपयोंका दावीदार खान हो तो वह अदालतमें दरखास्त देकर तथा अदालतसे जाने हुक्मों यहाँन दिलाकर उस रुपयेके वापिस पानेका हुक्म अदालतसे ले सकता है परन्तु अदालत कत्तय होगी कि वह ऐसा अज्ञानसे पाविल भात सरकार द्वारा नियत किये हुए अफसरको रुपये पानेकी दरखास्तके विरोध करनेवा अवसर देवे तथा नागितकी तामील पर १ माहका मोका दिय जानेक बाद रुपये वापिसका हुक्म देवेगी रुपये वापिसका हुक्म देनेके लिये अदालत हर हालतमें बाध्य नहीं है किन्तु हुक्म यहाँन होने पर रुपये वापिसका वह हुक्म देवेगी ।

दफा १२४ दिवालियेकी किताबोंका मुआयना व क़ब्ज़ा

(१) आफिशल एसायनीके विरुद्ध किसी व्यक्तिको दिवालियेकी किताबोंको रोकनेका अधिकार नहीं होगा और न उन पर उनका कोई वार ही होगा ।

(२) दिवालियेका कोई भी कर्जदार अदालतकी आज्ञाके अनुसार तथा इस सम्बन्धमें निर्धारितकी हुई फीसके अक्षर करने पर स्वयं या अपने एजएटक जरिये उचित समयों पर आफिशल एसायनीके कर्जमें होने वाली ऐसी किताबोंका मुआयना कर सकता है ।

व्याख्या—

इस दफासे यह प्रकट है कि दिवालियेके हिमायती किताब पर सबसे पहिले आफिशल एसायनीका हक होगा और वही दूसरी पक्षापर उन किताब पर कब्ज़ा पानका हुक्मदार होगा । अपनी एक्थम (Shall) शब्दके प्रयोग से पाने से यह समझना चाहिये कि इस अदफाक नियमना ज़रूरतना नहीं की गयी ।

उपदफा (२) के अनुसार बख्शानेको दिवालिये दिवालिये किताबना जो आफिशल एसायनाक कर्जमें होने फीस देने पर मुआयना करनेवा अधिकार प्राप्त है परन्तु अदालत इस सम्बन्धमें इसका कर सकता है ।

दफा १२५ फीस व..... फी सैकड़ा

वह फीस व..... फी सैकड़ा इन एक्टके अनुसारकी जाने वाली कार्रवाइयोंके सम्बन्धमें लिया जावगा जो निर्धारित किया गया हो ।

दफा १२६ अदालतें एक दूसरेकी सहायक होंगी

इस एक्टके अनुसार अधिकार रखने वाली सब अदालतें ऐसे हुकम देंगी व ऐसे काम करेंगी जिससे बैंकपसी एक्ट १८८३ (विक्टोरिया चैप्टर ४६ व ४७) की दफा ११८ तथा प्रांतिन कानून दिवालिया १६०७ (एक्ट ३ सन् १६०७ ई०) की दफा ५० कार्य रूपमें परिणित की जा सकें ।

व्याख्या—

सन् १९०७ ई० का प्रांतिन कानून दिवालिया (एक्ट ३ सन् १९०७ ई०) बदल गया है अब उसके स्थानमें सन् १९२० ई० का प्रांतिन कानून दिवालिया (एक्ट ५ सन् १९२० ई०) प्रचलित है । पिछले एक्टकी दफा ५० जिसका हवाला इस दफामें है उसे एक्टकी दफा ७७ के रूपमें बदल दिया गई है व वह इस प्रकार है—“ वह सब जदालतें जिन्हें दिवालियेक मामले सुननेका अधिकार है तथा उनके हाजिर्त एक दूसरेकी दिवालिने मामलोंमें मदद देने और अगर कोई जदालत दूसरी अदालतकी मदद चाहनेके लिये कोई हुकम देगी तो उस दूसरी अदालतों उस मदद चाहने वाले मागलिने लिये जिसका शिक हुकममें होगा वही अधिकार प्राप्त होंगे जो इस एक्टके अनुसार ऐसे मामलोंमें उन अदालतोंकी हो सकते हैं । ” बैंकपसी एक्टकी दफा ११८ जिसका शिक इस दफामें है वह भी इसी आधार की है अब पुनः बैंकपसी इस एक्टके स्थानमें बैंकपसी एक्ट १९१४ (Bankruptcy Act 1914) प्रचलित है और नये एक्टकी दफा १०९ में वह बतें दी गई हैं जो पिछले एक्टकी दफा ११८ में थी । इस दफाके पांच दायी भी आवश्यकता है जिसका कि अमेजी एक्टमें प्रयोग लिये हुए (Shall) शब्दसे प्रकट है ।

दफा १२७ कानूनोंकी मंजूरी

(१) तीसरे सिद्ध्युक्तमें दिखलाये हुए कानून उस हद तक मंजूर किये जाते हैं जिस हद तक उसके चौथे कालममें दिखलाये गये हैं ।

(२) इस एक्टके अनुसार की हुई मंजूरीके होते हुए भी दिवालियेकी उन दण्डधान्तों की कार्यवाहियां जो इण्डियन इन्साल्वेंसी एक्ट १८८८ (विक्टोरिया चैप्टर २१ के ११ व १२) के अनुसार इस एक्टके प्रारम्भ होते समय चल रही हों जारी रहेंगी अगर इस एक्टका कोई नियम साफ तौर पर चालू कार्यवाहियोंके लिये न दिया गया हो । और उस हुकमके सब नियम ऊपर बतलाई हुई बातोंकी छोड़कर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि यह पास हो न हुआ हो ।

व्याख्या—

उपदफा (१) में बतलाया गया है कि तीसरे सिद्ध्युक्तमें दिखलाये हुए एक्ट मंजूर किये गये हैं तथा उनकी मंजूरी उस हद तक समझना चाहिये जिस हद तक कि उस तीसरे सिद्ध्युक्तके चौथे कायम (खाने) में दिखलाया गया है ।

उपदफा (२) के अनुसार पिछले कानून दिवालियाके अनुसार होने वाली कार्यवाहियां बदलती नहीं रहेंगी परन्तु यदि इस एक्टमें खास तौरसे दे दिया हो कि किसी विशेषकी कार्यवाही मंजूर हमसी जायगी वा वह दूसरे दण्डसे की जायगी तो इस प्रकार बतलाये हुए नियमकी पालनीकी जायगी । अर्थात् यदि कोई खास नाम इस एक्टमें न हो तब तो पिछले एक्टके अनुसार होने वाली कार्यवाही उसी प्रकार होती रहेंगी तथा उसी एक्टके नियम भी लागू होंगे इस एक्टमें उस कार्यवाहीमें कोई रूकावट नहीं पड़ेगी ।

पहिली सूची

(The First Schedule.)

कर्मचारीकी मीटिंग

१ कर्मचारीकी मीटिंग

आफिसल एसायनी जब चाहे कर्मचारीकी मीटिंग कर सकता है और वह कर्मचारीकी मीटिंग उस वक्त तहर करेगा जब कि ऐसा करनेके लिये अदालत कहे या कर्मचारीगाने ऐसा करनेके लिये किसी मीटिंगमें प्रस्ताव पास किया हो या जब कि कर्त्ता साबित कर चुकने बाद कर्मचारीमेंसे इतने कर्मचारी मिल कर मीटिंग करनेके लिये कहें जिनके कुल कुर्से एक चौथाई कमतके बराबर होने होवें ।

व्याख्या—

तीन दशाओंमें आफिशल एसायनी कर्मचारीकी मीटिंग करनेके लिये बाध्य है— (१) यह कि जब अदालत मीटिंग करनेका हुक्म देवे, (२) यह कि जब किसी मीटिंगमें कर्मचारीगाने मीटिंग किये जानेके लिये दोर्ब प्रस्ताव पास किया हो (३) यह कि जब एक चौथाई कमत वाले कर्मचारी जिनके कुर्से साबित हुये हों मिल कर किसी मीटिंगके करनेकी प्रार्थना करें । इसके अलावा आफिशल एसायनी जब चाहे कर्मचारीकी मीटिंग आवश्यकता समझने पर कर सकता है ।

२ मीटिंगका बुलाया जा ना

मीटिंग किये जानेके समय तथा स्थायकी सुचना सब कर्मचारीके पास भेजी जावेगी, कर्त्ता साबित कर चुकने बाद कर्मचारीकी पास यह सूचना उस पतेसे भेजी जावेगी जो उन्होंने कर्त्ता साबित करनेमें बतलाया हो दूसरे कर्मचारीको उस पतेसे भेजी जावेगी जो दिखलायेने कर्मचारीकी सूचीमें दिखलाया हो या किसी दूसरे पतेसे जो आफिशल एसायनीको मालूम हो ।

व्याख्या—

मीटिंगकी सूचना सब कर्मचारीके पास भेजी जावेगी चाहे उन्होंने बर्जे साबित किया हो या न साबित किया हो । सूचनामें मीटिंगकी जगह तथा उसके किये जानेका समय बतलाया जावेगा । सूचना उस पतेसे दी जावेगी जो कर्त्ता साबित करने में कर्मचारीगाने अपना २ पता बतलाया हो परन्तु जिन्होंने कर्त्ता साबित हा न किया हो उसको उसी पतेसे भेजा जावेगा जो दिखलायेने अपनी किहरियमें दिखलाया हो अथवा जो आफिशल एसायनीको अन्य किसी प्रकारसे मालूम हो सके ।

३ मीटिंगके नोटिस

मीटिंगके लिये नियत किये हुए दिनों, कमसे कम सात दिन पहिले नोटिस भेजे जावेंगे और वह या तो स्वयं कर्मचारी दिये जा सकत है या स्टाम्न लगाने हुए खर्चसे भेजे जा सकत है जैसेमें सुचीता होवे । आफिशल एसायनीको यदि शकित प्रतीत होवे तो वह स्थानीय अखबार अथवा प्रतिष्ठित आफिशल मजदूरों मीटिंगके समय व स्थानकी सूचना प्रकाशित कर सकता है ।

व्याख्या—

मीटिंगके होनेसे कमसे कम सात दिन पहिले नोटिस जारी करनेकी आवश्यकता है नोटिस जारी तौर पर दिये जा

सन्ने हैं अथवा टिकट लगाकर खलके द्वार पर भेजे जासकते हैं अर्थात् वेग नहीं भेज जाना चाहिये। आनिश्ल एसायनी इन्ज पर निर्भर है कि वह यदि सुनासिव समझ तो मीटिंगके समय व स्थानकी सूचना स्थानाय अजबार्मे अथवा प्रातिक सरकारी गजटम प्रकाशित कर देवे। ऐसा उसी समय आवश्यक हो सकता है जब कि बहुतसे कर्मचारी हर्ने या आधुनिक कर्मचारी एवही स्थानो होवें अथवा एक ही स्थानके होवें अथवा अधिकतर एसायनीको अन्य किसी पर्याप्त कारणसे ऐसा करना उचित प्रदान हो।

४ यदि आवश्यकता हो तो दिवालियेके हाजिर होनेका कर्तव्य

यदि आफिशल एसायनी किसी मीटिंगमें हाजिर होनेकी सूचना दिवालियेको देवे तो उसका कर्तव्य होगा कि वह इन मीटिंगमें अथवा यदि वह किसी कारीखके लिये बका बर्गई हो तो उस बर्गई हुई तारीख पर हाजिर होवे। इस प्रकारका नोटिस या तो स्वयं उसे ही दिया जावेगा या मीटिंगसे कमसे कम तीन दिन पहिले डाकके जरिये उसके पतेसे भेजा जावेगा।

व्याख्या—

दिवालियेको मीटिंगमें हाजिर होनेका नोटिस जारी होने का तारीखसे कमसे कम तीन दिन पहिले दिया जाना चाहिये। नोटिसकी जारी तारीख कीमतसक्ती है अथवा वह डारुने जरिये उसके पतेसे भेजा जासकता है पुछाय जाने पर मीटिंगमें इन दिन तथा बर्गई हुई तारीख पर हाजिर होना दिवालियेका कर्तव्य है।

५ नोटिस न पहुंचने पर मीटिंगकी कार्रवाईका रद्द न होना

यदि किसी कर्मचारीका भेजा हुआ नोटिस उसको न भी मिला हो तो किसी मीटिंगमकी हुई कार्रवाईका व उसमें पास किये हुए प्रस्ताव ठीक माने जावगे जब तक कि अदालत इसके विरुद्ध कोई हुक्म न देवे।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार यदि किसी कर्मचारीको नोटिस भेजा गया हो परन्तु उसे न मिला हो और मीटिंग होकर कोई प्रस्ताव आदि पास किय गये हों तो नोटिसकी तारीखी हुए बिना मीटिंगकी कार्रवाईका किया जाना रद्द नहीं समझा जावेगा परन्तु यदि अदालत चाहे तो ऐसे मीटिंगकी कार्रवाई या उसमें पास किये हुए प्रस्तावका रद्द कर सकता है।

६ नोटिसके जारी होनेका सुबूत

यदि आफिशल एसायनी इस बातका सर्टीफिकेट दे देवे कि किसी मीटिंगका नोटिस बाकायदा दिया गया है तो यह काफ़ी शहादत इस बातकी होगी कि नोटिस जिसके पतेसे भेजा गया है उसका ठीक तौर से भेजा गया है।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार आफिशल एसायनी जिस पतेसे नोटिस भेजा होगा उस पतेसे उसका भेजा जाना पर्याप्त माना जावेगा अर्थात् नोटिसके बाकायदा भेजे जानका बात आफिशल एसायनीके तस्दीक करने पर ठीक माना जावेगी और वह नतीर शहादत इस्तेमाल वा जासकेगी।

७ मीटिंगका खर्च

जब कि कर्मचारीकी प्रार्थना पर आफिशल एसायनी कोई मीटिंग करे तो सदस्यी प्रार्थनाके साथ हर चीस कर्मचारीको हिसाबसे पांच रुपये मीटिंग किये जानेके खर्चेके तौर पर जमा किये जावंग जिसमें सब खर्चे शामिल समझना चाहिये, परन्तु शत यह भी है कि आफिशल एसायनी मीटिंगके खर्चेके लिये जो उसकी रायमें सुनासिव मालूम पड़े और भी अधिक रुपया जमा करा लगा।

व्याख्या—

कर्जेंवाह जस गांगि वराना चाहे तो उनको पाव रुपया की बीस कर्जेंवाहके हिमावते बतोर खर्चके दरखास्त के साथ जमा करना चाहिये । आफिसर एसायनी को गुनामिष मालूम पडनेपर और भा अधिक रुपया बतोर खर्चके जमा कथया जासकता है ।

८ खयरमैन

भाषिशाल मुसायनी हर मीटिंगका खयरमैन (सभापति) होगा ।

९ घोट देनेके अधिकार

कोई कर्जेंवाह जब तक कि वह अपना कर्ज जो दिवालियाकी कारवाहीके सम्बन्धमें आवेष्ट किया जा सकता हो आकायदा संचित न कर देवे मीटिंगस पाठ देनेका अधिकारी न होगा और कनका सुबुत मीटिंग होनेके लिये नियत किए हुए समयसे ठीक एक दिन पहिले हो चुकना चाहिये ।

व्याख्या—

बर्ता संचित कर चुकने वाले कर्जेंवाह ही घोट दे सकेगें । इस बातका भी ज्ञान रहना चाहिये कि मीटिंगके लिये नियत शिथे हुए समयसे ठीक एक दिन पहिले कर्जे संचित हो जाना चाहिये अर्थात् जहाँ कर्जेंवाह मीटिंगके १२० वरते संचित किया चाहे वह घोट देनका अधिकारी नहीं होगा । जिन कर्जेंवाहोंका कर्जो संचित नहीं किया गया है वह घोट नहीं देसकेंगे ।

१० कुल कर्जोंके सम्बन्धमें घोट नहीं दिय जासकेगे

किसी मीटिंगका कोई एसा कर्जेंवाह जो नहीं है सकया जिसका कज निश्चित भनराशिके रूपस न होव या जिसका कर्ज किसी बातके होन पर निर्भर होवे अथवा कोई एसा कर्ज होव जिसकी कीमत तय न हुई हो ।

११ महफूज कर्जेंवाह

यदि किसी महफूज कर्जेंवाहने अपनी जमानत न छोड़ दी होवे और वह घोट देना चाहे ता वह अपने सुबुतमें अपनी जमानतकी तफसील बतलायगा वह सारीज जस कि जमानतकी राह है और इसकी अदागा लगाई हुई कीमत और वह अदागा लगाई हुई कीमत कर्जेंके घटानक बाद जा कतें बचगा उपाक शिथ पाठ दे सकगा । यदि वह अपने पूरे कर्जोंके सम्बन्धमें घोट देवे तो यह मान लिया जावगा कि उसका जमानत छोड़ दी है जस तक कि अदालतको इसके दरखवास्त देने पर यह पकीन न हो जावे कि वह गलती स अपने जमानतकी कीमत नहीं दिला सका है ।

व्याख्या—

महफूज कर्जेंवाह अपने पूरे कर्जोंके सम्बन्धमें जमानत छोड़ देने पर घोट दे सकत है तथा वह जमानतका कामदे बतला कर्जोंसे एगकर बाकी कर्जोंके लिये वोग दे सकता है ।

१२ उन दस्तावेजोंका सुबुत जो कायिल वय थे तवादलेके होवें

यदि कोई कर्जेंवाह किसी बिल आक एक्सचेंज (Bill of Exchange) प्रोमिसरी नोट (Promissory Note) या अन्य किसी एसी दस्तावेजको जो बयनामा, हवालगी या किसी इश्आरते बन्नी जा सकती हो (Negotiable Instrument) या किसी जमानतका जिसके लिये दिवालिया पाबन्द हो संचित किया चाह तो वह बिल आक एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट, निगाशियोरबल इन्स्ट्रुमेंट या जमानत आफिसरल दस्तावेजोंके सामन एसा ही जाना चाहिये पाइल इसके कि उसका सुबुत घाटक लिये माना जावे परन्तु अशालत इसके विरुद्ध कोई विशेष हुकम भी दे सकता है ।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार जिन दस्तावेजोंका कर्ज बतलाया जाता हो वह आफिशल एसायनीके सामने पेश की जाना चाहिये और उसके पेश होनेके बाद कर्जेका सुधूत बोट देनेके लिये पर्याप्त माना जावेगा। अदालतकी अधिकार हैं कि वह इसके विरुद्ध कोई विशेष आज्ञा दे देवे और ऐसा होने पर अदालतकी आज्ञाके अनुसार किया जावेगा।

१३ कर्जस्वाहसे जमानत छोड़ देनेके लिये कहनेका अधिकार

यदि किसी महफूज कर्जस्वाहने अपनी जमानतकी कीमतका अर्द्धांश देनेके बाद किसी मीटिंगमें बोट देने के अधिकारका प्रयोग किया हो तो आफिशल एसायनीकी अधिकार होगा कि वह उस सुधूतमें २४ अर्द्धांश दिनेके अन्दर उस महफूज कर्जस्वाहसे अर्द्धांश लगाई हुई कीमत लेकर सब कर्जस्वाहोंके लामार्थ जमानत छोड़ देनेको कहे।

व्याख्या—

इस दफाके अनुसार आफिशल एसायनी महफूज कर्जस्वाह द्वारा जमानता लगाई हुई कीमतको अर्द्ध करने पर उसके उसकी जमानतकी अप सब कर्जस्वाहोंके लामार्थ ले सकता है परन्तु ऐसा २४ दिनेके अन्दर ही किया जाना चाहिये। इस दफाका तात्पर्य यह है कि यदि कोई महफूज कर्जस्वाह अपनी जमानतकी कीमत कम लगाकर बेना फायदा उठाया चाहे यानी अपने बर्किया कर्जेकी ओर कर्जस्वाहोंके साथ मसूल किया चाहे तो उसके उसके अर्द्धांश लगाई हुई कीमत पर उसकी जमानत आफिशल एसायनी द्वारा ली जा सकती है। इस प्रकार जमानत कम कीमतमें ले लिये जानेके बरत कोई महफूज कर्जस्वाह कम कीमत लगाकर बेना फायदा उठानेकी हिम्मत नहीं कर सकेगा।

१४ शरीकदारका सुधूत

यदि किसी फर्मका एक शरीकदार दिवालिया करार दिया गया हो तो उस शरीकदारका कोई कर्जस्वाह जिसका कर्ज उस फर्मके अन्य शरीकदार या शरीकदारोंके साथमें दिवालिये से लेना होवे अपना कर्ज मीटिंगमें बोट देनेके लिये साबित कर सकता है और ऐसा करने पर वह बोट देनेका अधिकारी होगा।

व्याख्या—

फर्मका कर्जस्वाह या एक से अधिक शरीकदारोंका समुक्त कर्जस्वाह अपने कर्जेको उन शरीकदारोंमें से किसी एक के दिवालिया करार दिये जाने पर अपना कर्ज उसके विरुद्ध साबित कर सकता है तथा उसके आधार पर कर्जस्वाहोंकी मीटिंगमें बोट दे सकता है।

१५ आफिशल एसायनीके कर्जा साबित मानने या न माननेके सम्बन्धमें अधिकार

आफिशल एसायनीको बोट देनेके सम्बन्धमें दिये हुए सुधूतको मानने या न माननेका अधिकार हासिल होगा परन्तु उसके फैसलकी अपील अदालतमें की जा सकेगी। यदि आफिशल एसायनीको इस बातका शक होवे कि आया सुधूत माना जाना चाहिये या खारिज कर देना चाहिये तो वह उस सुधूतमें यह लिख देवेगा कि सुधूतमें पुराना है और कर्जस्वाहको बोट देनेका अधिकार प्राप्त हो जावेगा परन्तु तब यह रहेगी कि अगर पुराना कायम बना रहेगा तो उसका बोट ग़ुलब करार दिया जा सकेगा।

व्याख्या—

बोट देनेके सम्बन्धमें सुधूतका मानना या खारिज कर देना आफिशल एसायनी पर निर्भर होगा परन्तु उसके फैसलकी अपील अदालतमें की जा सकेगी। शक वाले मामलोंमें बोट देनेका अधिकार कर्जस्वाहको इस बात पर प्राप्त रहेगा कि उसके विरुद्ध दिये हुए पुरानेके ठीक साबित होने पर उसका बोट रद्द माना जावेगा।

१६ प्रोक्सी

कर्जवाह स्वयं वोट दे सकता है तथा वह किसी कायम मुकाम (प्रोक्सी) के जरिये भी वोट दे सकता है ।

व्याख्या—

प्रोक्सी तो तत्पर्य उस व्यक्ति से समझना चाहिये जिसे किसीने अपनी तरफ से वोट देने का अधिकार दिया हो ।

१७ प्रोक्सी की दस्तावेज

अपनी तरफ से वोट देने का अधिकार (प्रोक्सी) देने वाली दस्तावेज निर्धारित क्रिये हुए ढंग (फॉर्म) पर होगी और आफिशल एसायनी द्वारा जारी की जावेगी ।

१८ प्रोक्सी का आम अधिकार (General Proxy)

कर्जवाह को अधिकार है कि वह अपने सुत्तारको, मैनेजरको, क्लर्कको अपना अपनी वाक्यापवाद मौकामें रखे हुए किसी मुनीम या अन्य व्यक्ति को आम अधिकार वोट देने का (General Proxy) दे देवे । ऐसे मामलों में प्रोक्सी की दस्तावेजमें यह लिखलाना आवश्यक होगा कि वोट देने वाले व्यक्ति का कर्जवाह से क्या सम्बन्ध है ।

व्याख्या—

हम इसके अन्वय कर्जवाह अपने किसी आदमी की आम इज्जियार वोट देने का दे सकता है परन्तु ऐसी हालतमें प्रोक्सी के फॉर्ममें यह लिखलाना चाहिये कि वोट देने वाले का असली कर्जवाह से क्या सम्बन्ध है ।

१९ मीटिंग की तारीख से एक दिन पहिले प्रोक्सी का दाखिल किया जाना

यदि हम मीटिंग होने से जितने कि प्राक्सी इस्तेमाल की जाने को होवे कम से कम एक दिन पहिले प्रोक्सी का फॉर्म आफिशल एसायनी को न दे दिया जावे तो वह प्रोक्सी इस्तेमाल नहीं की जा सकेगी ।

व्याख्या—

मीटिंग होने से कम से कम एक दिन पहिले वोट देने का अधिकार देने वाला कायम आफिशल एसायनी को दे दिया जाना चाहिये वरना वोट देने का अधिकार उस कायम के लिये प्राप्त नहीं माना जावेगा ।

२० आफिशल एसायनी का स्वयं प्रोक्सी होना

के हू भी कर्जवाह आफिशल एसायनी को अपनी ओर से वोट (Proxy) देने के अधिकार को दे सकता है ।

२१ मीटिंग का वड़ा दिया जाना

आफिशल एसायनी को अधिकार है कि वह किसी मीटिंग को एक समय में दूसरे समय के लिये तथा एक स्थान से दूसरे स्थान में किये जाने के लिये हटा सके और ऐसे बढ़ाये जाने का नोटिस दिये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

व्याख्या—

मीटिंग ही में समय या स्थान के बढ़ाये जाने की सूचना हो जाने के लिये उस के लिये नोटिस की आवश्यकता हम दफ्तर के अनुसार नहीं रखी गई है ।

२२ कार्रवाई का विवरण

आफिशल एसायनी मीटिंग में कार्रवाई का विवरण तैयार करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा ।

दूसरी सूची

(The Second Schedule)

कजोंके सुवृत



मामूली मामलोंमें सुवृत

१ सुवृत दाखिल करनेका समय

दिवालिया करार दिया जानेका हुक्म होनेके पश्चात् त्रितनों तबद हो सकेंगा हर एक कर्जस्वाह अपना अपना सुवृत दाखिल करेगा ।

२ सुवृत दाखिल करनेकी तरीका

कर्जकी तस्दीक करने वाला हलफनामा आफिशल एसायनीकी देनेसे या उसके पास बगरिये रजिस्ट्री क्व के डाक द्वारा रवाना करनेसे सुवृत दाखिल किया जा सकता है ।

ध्याख्या—

इस दफ्तेके अनुसार कजोंकी तस्दीकमें लिखा हुआ हलफनामा आफिशल एसायनीके पास पहुंचनेसे कर्जेश सुवृत करना माना जावेगा । यह हलफनामा हाथमें भी दिया जा सकता है व रजिस्ट्री बज द्वारा भी भेजा जा सकता है ।

३ हलफनामा दाखिल करनेका अधिकार

कर्जस्वाह स्वयं या अपनी ओरसे इस कामके लिये अधिकार दिये हुए किसी व्यक्ति द्वारा हलफनामा दाखिल कर सकता है यदि वह प्रकारसे अधिकार दिये हुए व्यक्ति द्वारा हलफनामा दाखिल किया गया हो तो उसमें यह बतलाया जावेगा कि वह किस अधिकारसे हलफनामा पेश कर रहा है तथा उसे मामलेका इहम किस प्रकार हुआ है ।

ध्याख्या—

यह आवश्यक नहीं है कि स्वयं कर्जस्वाह ही हलफनामा पेश करे उसकी ओरसे अन्य व्यक्ति भी हलफनामा दाखिल कर सकता है परन्तु उस व्यक्तिकी चाहिये कि वह अपने अधिकारको बतलावे तथा यह भी दिखलावे कि उसे मामलेका हाल कैसे मादूम हुआ है जैसे कि मुनीम या मुस्तारजाम अधशा दफतरमें काम करने वाला व्यक्ति निजके सामने कर्ज दिया गया हो या जिसने कामजातमें इदराज किया हो हलफनामा दाखिल कर सकता है ।

४ हलफनामामें क्या बात दिखलाई जाना चाहिये

हलफनामामें कर्जकी तफसील जाहिर करनेके लिये हिसाब या हिसाबका हवाला दिया जावेगा और उसमें उन कामजातका हवाला होगा निजके जरिये उस हिसाबकी पुष्टिकी जा सकती है । आफिशल एसायनी किसी समय भी उन कामजातको पेश करा सकता है ।

ध्याख्या—

हलफनामामें एक तो हिसाब दिखाना जाना चाहिये या उसका हवाला दिया जाना चाहिये जिससे कि कर्जकी

तत्कालीन मादम हो सके दूसरे यदि कोई कायनात उस हिमावर्ती पुष्टिमें कर्जस्वाहके पास होने तो उनका भी हवाला उस हकनामें दे दिया जाना चाहिये । साथ ही साथ आफिशल एग्जायनीमे अधिनष्ट प्राप्त है कि जब वह चाहे वन कायनात को गिनना हवाला हकनामें दे दिया गया हो पेश करा लेवे ।

५ हलफनामेंमें जमानतकर जिक्र होना चाहिये

हलफनामेंमें यह भी दिखलाया जावेगा कि आया कर्जस्वाह महफूज कर्जस्वाह है या नहीं ।

न्याय—

सादा बपयेकी डिक्ता रेहननामेंके तौर पर लिखी जा सकती है । और इससे यह तत्पर्य निश्चलता है कि सुर्तीहिनकी महफूज कर्जस्वाह समझना चाहिये । 38 Bom. 359.

६ कर्ज साबित करनेका सूच्य

कर्ज साबित करनेका सूच्य स्वयं कर्जस्वाह बर्तास्त करेगा जब तक कि अवास्त इसके बिल्व कोई क्षम हुसम न देवे ।

७ सुवृत देखने व उसका सुधायना करनेका अधिकार

वह कर्जस्वाह जो अपना सुवृत दाखिल कर चुका है दूसरे कर्जस्वाहों द्वारा दाखिल किये हुए सुवृतको हमेशा उचित समय पर देख सकता है ।

८ सुवृतसे घट्टका घटाया जाना

कर्जस्वाह अपना सुवृत दाखिल करते समय अपने कर्जेमेंसे तिजाराती बट्टेको घटा देवेगा पान्तु वह अपने खास कर्जेके पांच रुपये सेकडे तकका घटा घटानेके लिये उस समय मसबूर नहीं होगा जब कि वह मसबूर दाममें वसे घटानेके लिये तैयार रहा हो ।

न्याय—

५ रुपये सेकडे तकका घटा वह अपने कर्जेमें बना रहने दे सकता है जब कि मसबूर दाममें बट्टा दिया जाता हो ।

महफूज कर्जस्वाहोंका सुवृत

६ जब कि जमानत बसूलकी जाचुकी हो तबका सुवृत

यदि कोई महफूज कर्जस्वाह अपनी जमानत बसूल कर चुका हो तो वह बसूल किये हुए रुपयेको घटाने के बाद जा कर्ज टकका बचे उसे साबित कर सकता है ।

न्याय—

इस दफ्तर अनुसार वह महफूज कर्जस्वाह भी अपना कर्ज साबित कर सकते हैं जो अपनी जमानत बसूल कर चुके हो पान्तु ऐसा वह उही समय कर सर्वेमे जब कि वापानदम कुछ राया बसूल न हुआ हो और जमानत बसूल किये जानेके बाद भी उसका कर्ज कुछ नारी बच रहे । इस सम्बन्धमें इस बातका भा प्यान रहना चाहिये कि ऐसे कर्जस्वाह स्वतः बचे हुए कर्जे के सम्बन्ध ही में साबित कर सकते हैं अपन पूरे कर्जेके लिये नहीं । जमानत रेहननामेंमें शरलमें अथवा अथ किता वारकी शान्दमें हो सकती है ।

१० जब कि जमानत छोड़ दी गई हो उस समय सुदृढ

जब कि आफिशल एसायनी के हकमें किसी मद्रुज कर्जस्वाहने अपनी जमानत सब कर्जस्वाहको लामें छोड़ दी हो तो वह अपने पूरे कर्जों के लिये साबित कर सकता है ।

व्याख्या—

जमानत छोड़ देने के बाद मद्रुज कर्जस्वाह भी अन्य कर्जस्वाहों की भाँति अपने पूरे कर्जों के लिये साबित कर सकता है ।

११ दूसरे मामलों में सुदृढ

यदि कोई कर्जस्वाह न तो अपनी जमानत छोड़ और न उसमें अपनी जमानत को बसूल ही किया हो तो वह हिस्सा रसदी पाने में पहिले सुदृढ में अपनी जमानत छोड़ाई हुई जमानत की कीमत तथा जमानत की तर्फी और इसके किये जाने की तारीख बतलायेगा और अन्तर्गत छोड़ाई हुई कीमत घटाने के बाद जो कर्ज बचेगा उन्हीं के लिये वह हिस्सा रसदी पास करेगा ।

व्याख्या—

जमानत वाले कर्जस्वाह जमानत की कीमत घटाकर अपने बाकी कर्जों के सम्बन्ध में हिस्सा रसदी ले सकते हैं ।

१२ जमानत की कीमत का लगाया जाना

(१) जब कि जमानत की कीमत का अन्तर्गत उक्त प्रकार से लगाया गया हो तो आफिशल एसायनी के अधिकार होगा कि वह अन्तर्गत छोड़ाई हुई कीमत कर्जस्वाह को अर्पण करने के बाद उस जमानत को छोड़ लेवे ।

(२) यदि किसी जमानत की अन्तर्गत छोड़ाई हुई कीमत से आफिशल एसायनी सन्तुष्ट न होवे तो वह जमानत की जमानत को उन शर्तों व नियमों के साथ तथा इस समयों पर नीलाम पर चढ़ा सकता है जो उसके और कर्जस्वाह के दमियान तथा होवें या ऐसा कोई समझौता न होने पर जैसा अन्तर्गत हुक्म देवे । यदि जमानत नालाम नाम में बेची जाने को होवे तो कर्जस्वाह या आफिशल एसायनी दिवालिये की जमानत की तरफ से बीछी बोल सकता है व जमानत को खरीद सकता है । परन्तु शर्त यह है कि कर्जस्वाह किसी समय भी आफिशल एसायनी को लिखकर नोटिस दे सकता है कि वह जमानत को छुटाना चाहता है या नहीं अथवा उसको बसूल कराना चाहता है या नहीं और यदि ऐसा होवे तो अन्तर्गत आफिशल एसायनी लिखकर कर्जस्वाह को अपने इस प्रकार के अधिकार के प्रयोग किये जाने की सूचना न देवे तो वह । पर इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता । और एक हुक्म का या अन्य कोई एक जो आफिशल एसायनी का पहुँचता होगा कर्जस्वाह को प्रप्त हो जावेगा और उसके कर्जों की तादाद में जमानत की अन्तर्गत छोड़ाई हुई कीमत कम कर दी जावेगी ।

व्याख्या—

उपदृष्ट (१) के अनुसार आफिशल एसायनी कर्जस्वाह से उन्हीं जमानत की जमानत अन्तर्गत छोड़ाई हुई कीमत पर ले सकता है तथा उपदृष्ट (२) के अनुसार वह कीमत से असहमत होने पर जमानत बसूल करने के लिये कर्जस्वाह को मजबूर कर सकता है । इस प्रकार जमानत बसूल करने में नीलाम आग किये जाने पर कर्जस्वाह व आफिशल एसायनी दोनों ही जमानत को खरीद कर सकते हैं । दफ्तर में जो शर्त छोड़ाई गई है उसके अनुसार व महान के अन्तर्गत कर्जस्वाह आफिशल एसायनी के निश्चय को मान्य कर सकता है । जवाब न मिलने पर आफिशल एसायनी के हक कर्जस्वाह की प्राप्त हो सकते हैं तथा उसकी अन्तर्गत छोड़ाई हुई कीमत मान कर बाकी कर्जों के लिये वह हिस्सा रसदी ले सकता है ।

१३ कीमतमें संशोधन

यदि कर्जस्वाहने अपनी जमानतकी कीमत ऊपर बनाये हुए दण पर लगाई हो तो वह उसकी कीमत तथा अपने सुदुनका संशोधन किसी समय भी कर सकता है जब कि वह आफिशल एसायनी या अदालतकी हम बात का विश्वास दिला देवे कि कीमत व सुदुन गलतीसे कीमत का अन्दाजा लगाये जानेके कारण नुक़्तीयतीसे गलत हो गये हैं । या कीमतके अन्दाजा लगाये जानेके बाद जायदादकी कीमत बढ़ या घट गई है । परन्तु इस प्रकारका संशोधन कर्जस्वाहके खर्च पर होगा तथा इन बातोंके अनुसार होगा जो अदालत अपने हुक्मके अनुसार क़ानून से इस समय इसकी बात हो जायेगी जब कि आफिशल एसायनीने बिना अदालतमें दरखास्त दिये हुए संशोधनकी आज्ञा दे दी हो ।

व्याख्या—

१३ दफ़ेके अनुसार कीमत का अदालत तथा आफिशल एसायनी दोनों ही पक्षों का पक्ष बनलिये जाति पर का सकते हैं । जब कि आफिशल एसायनी बिना अदालतम दरखास्त दिये हुए संशोधन की आज्ञा दे देवेगा तो कर्जस्वाहकी खर्च वह जायेगा तथा अदालत द्वारा लगाई हुई शर्तों की पाबन्दी बसने परना पड़ेगा तथा शर्तों भी उनमें बदलाव करना पड़ेगा । संशोधन की आज्ञा जायदादकी कीमत घटाने या बढ़ाने पर दा जासतत है इसी प्रकार यदि किसी पक्षीसे जायदादकी कीमतका गलत अन्दाजा लगाया गया हो तो फ़ीमाका संशोधन हो सकता है ।

१४ क़ानून क़ानून वसूल हो जाने पर उसका लौटाया जाना

जब कि ऊपर वक्तव्यमें हुए नियमके अनुसार कोई कीमत तुक्कम की गई हो तो कर्जस्वाह उस अधिक वसूल किये हुए हिस्सा रसदी को लौटा देगा जो कि उसको सहायित कीमतके हिस्सेसे न मिलना चाहिये था अथवा वह हिस्सा रसदीके किये जाने हुए रूपमेंसे अधिक हिस्सा रसदी बाँटे जानेसे पहिले उस रूपमेंसे पाने का अधिकारी होगा जो उसे ठीक की हुई कीमतके अनुसार हिस्सा रसदीमें उपादा मिलना चाहिये और जिसे वह गलत कीमतकी वजहसे न प्राप्त हो । परन्तु संशोधनसे पहिले बाँटे हुए हिस्सा रसदीमें वह किसी प्रकारकी ग़ल्ती नहीं कर सकेगा ।

व्याख्या—

संशोधनसे पहिले यदि कोई हिस्सा रसदी बाँटे चुका हो तो उसमें कोई रसदीदल नहीं दिया जायेगा परन्तु संशोधनके समय यदि कोई क़ानून हिस्सा रसदीके किये जाने हो तो उसमेंसे अग्रगण्य का हिस्सा रसदी बढानेसे पहिले उस कर्जस्वाहकी क़ानून दिया जायेगा जो संशोधनके अनुसार कुछ अधिक मिलना चाहिये । वह भी आनमें रसदी चाहिये कि यदि संशोधनसे पहिले कोई कर्जस्वाह अपने हिस्सेसे अधिक क़ानून बतौर हिस्सा रसदीके वसूल कर चुका हो तो उसे बाद संशोधन वह क़ानून बाँटने पड़ेगा और उस प्रकार लौटाया हुआ क़ानून सब कर्जस्वाहोंको हिस्सा रसदीके तौर पर मिल सकेगा ।

१५ जब कि जमानत बादमें वसूल की गई हो तब संशोधन

यदि जमानतकी कीमत का अन्दाजा लगाये जानेके पश्चात् कोई कर्जस्वाह अपनी जमानत वसूल कर लेवे अथवा वह रुक १२ के अनुसार वसूल की गई हो तो वसूल किया हुआ क़ानून अन्दाजा लगाई हुई कीमतके स्थान पर सनडा जायेगा और वह दा प्रकारसे कर्जस्वाह द्वारा सहायित किया हुआ मुख्य समझा जायेगा ।

व्याख्या—

कीमत का अन्दाजा लगाये जानेके बाद कोई कर्जस्वाह स्वयं जमानतकी वसूल कर लेवे अथवा वह रुक १२ के

अनुसार वसूल की जावे वसूलवा हुई कीमत ही असली कीमत माना जावेगा और उसको अदाशा लगाई हुई कीमत की जगह पर समझना चाहिये ।

१६ हिस्सा रसदीसे वंचित रहना

यदि कोई मजदूर कर्जस्वाह पिछके रुस्त (नियमों) की पाबन्दी न करे तो वह हिस्सा रसदीसे हर प्रकार वंचित रहा जावेगा ।

१७ पानेकी हद

रूल १२ के नियमोंका ध्यान रखते हुए कोई भी कर्जस्वाह रुपयेमें १६ भागसे अधिक तथा इस पृष्ठमें यतकथे हुए सूदको छोट कर और कुछ नहीं पावेगा ।

व्याख्या—

इस रूलके अनुसार कोई भी कर्जस्वाह अपने कर्जसे अधिक नहीं पासकेगा । हा वह इस पृष्ठमें बनलाये हुए नियमों के अनुसार सूद अलवता मासकता है यदि रूल १२ के अनुसार कोई कर्जस्वाह स्वयं जायदादको सस्तेमें खरीद लेवे या उसकी कम अदाशा लगाई हुई कीमत मान ली जावे तो ऐसी बातोंसे वह फायदा उठा सकता है ।

रेहनकी हुई जायदादका हिसाब लिया जाना तथा उसका बेचा जाना

१८ रेहननामे आदिकी तहकीकात

अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनेको दिवालियेकी किसी खास जायदाद या ठेके पर ली हुई जायदादका मुतहिन बतलाता हो और चाहे वह मुतहिन किसी दस्तावेजके जरिये होवे अथवा किसी और प्रकारसे होवे और चाहे वह कानूनी हो या कानूनीके तौर पर (Equitable) होवे अदालतमें दरखास्त देवे या आफिशल एमाथनो एक प्रकारसे मुतहिन जाहिर करने वाले व्यक्तिकी रजामन्दारी दरखास्त देवे या अदालत इस बातकी तहकीकात करेगी कि आया वह व्यक्ति उस प्रकारका मुतहिन है या नहीं और किस मुआविलेके एवजमें तथा किस हालतमें है और अगर यह मालूम पड़े कि वह व्यक्ति उस प्रकारका मुतहिन है तथा उस रेहननामेके अनुसार बतलाई रकम के लिये उसके हक्के विरुद्ध कोई क़ाफी बजह न मालूम हो तो अदालत उस रेहननामेके असली रुपये सूद व खर्चें का हिसाब लेगे या तहकीकात करनेका हुक्म जो उसे मुनासिब समझ पड़े देवेगी तथा किराये, मुनाफे, हिस्सा रसदी, सूद या दूसरी आमदनी जो उस व्यक्तिको या उसके हुक्मसे अथवा उसके लिये किसी दूसरे व्यक्तिकी हुई हो जब कि रेहनकी हुई कुल जायदाद या वसला कोई हिस्सा उसके कब्जेमें रहा हो तो वसला भी हिसाब व तहकीकात करनेका मुनासिब हुक्म देगी । और यदि अदालतको यकीन हो जावे कि जायदाद बेची जाना चाहिये तो इस बातकी सूचना उन अखबारोंमें निकालनेका हुक्म देगी जो उसे मुनासिब मालूम पड़े कि कब कहा किस व्यक्ति द्वारा किस प्रकारसे रेहनकी हुई किस इलाक़े या जायदाद अथवा उसके किसी हक़को बेचा जावेगा और फिर उसी प्रकार वह जायदाद बेची जावेगी और आफिशल एमाथनो अगर इसके विरुद्ध कोई हुक्म न दिया गया हो उस नीलामकी कारायेगा परन्तु उस मुतहिनके लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह ऐसी दरखास्त अवश्य देवे । ऐसे नीलाममें मुतहिन भी बोल सकता है तथा जायदादको खरीद सकता है ।

व्याख्या—

इस दफ़्तेके अनुसार मुतहिन दरखास्त देनेके लिये बाध्य नहीं है उसका देना न देना उसकी इच्छा पर निर्भर है ।

यदि कोई मुर्तद्दिन दिवालियेको किसी जायदादका हकदार उस हस्तियतसे अपनेकी समझता हो तो वह अदायतमें दरखास्त दे सकता है या आफिशान एसायनी द्वारा ऐसी दरखास्त दिया सकता है। दरखास्तके पहुँचने पर अदालतका कर्तव्य होगा कि वह उसके दफ्तर की तद्विज्ञान को कि वही तक व सिध प्रमाण हक उसका दिवालिये की किस जायदादके सम्बन्धमें पहुँचना है और यदि अदालतको उसके हकका यकीन हो जाने तो वह जिसान लिये जाने तथा तद्विज्ञान किये जानेका हुक्म देवेगा कि जिससे मादग हो सके कि असल व सूद गिनना है तथा खर्चक तौर पर गिनना मिलना चाहिये। इस दफ्तरमें यह भी बनना दिया गया है कि यदि उस प्रकारका मुर्तद्दिन रहनेवाला हुई जायदाद या उसके किसी हिस्से पर काबिज रहा हो अथवा उसको ओरसे अथ कोई व्यक्ति काबिज रहा हो तो उस क जेस जिस कदर कायदा मुर्तद्दिनने या उसकी आरसे किसी अन्य ब्याप्तने उदाया हो वह उसकी मुआविलेसे मुजरे लिया जावेगा। जायदाद उचित प्रजात होने पर नीलाम भी कराई जा सकेगी मुर्तद्दिन स्वयं भी गोली बोल सकता है तथा नीलामकी घुसहरी अजबसेमें कर्तई जा सकती है व नीलामका मार व निगमना आफिशान एसायनीकी होगी। इस दफ्तरमें अनुसार होने वाली कर्तवाई एक प्रकारसे दरखतीकी कर्तवाई समझना चाहिये क्योंकि इसमें कोई किसी इस्तदारे बनने आदिनी व्यवस्था नहीं है और न उसमें कोई फ़क रहने कबजे जानेका हो जिस है केवल दोष दिये हुए रूल १२ के अनुसार आफिशान एसायनी जायदादको छुड़ा सकता है दरखास्त पहुँचने पर तद्विज्ञान करना अशुद्धता कर्तव्य है परन्तु और बाँके एफ प्रकारसे उसकी इच्छा पर निर्भर है क्योंकि उसका धरना यकीन हो जाने पर निर्भर है।

११. दस्तावेज इतकाल

खुशियारके हकमें लिखी जाने वाली दस्तावेजमें वह सब फरीकन शामिल होंगे जिनकेलिये अदालत हुक्म देवे।

२०. बिक्रीका रुपया

इस प्रकार बचे जाने पर जो रुपया आवेगा वह पहिले उस खर्चकी अन्वयगीमें लगाया जावेगा जो कि अदालतमें दरखास्त देनेके सम्बन्धमें हुआ हो पा किया गया हो तथा जो नीलामके सम्बन्धमें हुआ हो और इससे आफिशान एसायनीका कमीशन भी यदि उसे कुछ मिलना चाहिये पहिले ही दिलाया जावेगा। और इसके बाद मुर्तद्दिनका वह रुपया जहाँ तक हो सकेगा दिलाया जावेगा जो उसे असल सूद व खर्चमें दिलाया जाना बरामद हो और यदि इसके बाद बिक्रीका कोई रुपया बचे हो वह आफिशान एसायनीको मिलेगा। परन्तु यदि बिक्रीके रुपयेसे मुर्तद्दिन के निकलने वाले रुपयेकी पूरी अदायगी नहीं हो सकेगी तो वह अपने बचीया रुपयेके किये बतौर कर्जेक और कर्जद्वाराही भाति समित कर सकेगा तथा उसके साथ हिस्सा रसदी पालेका अधिकारी होगा परन्तु उसका पहिले बाटे हुए हिस्सा रसदीमें किसी प्रकारकी गदबडी नहीं कर सकेगा।

ग्याख्या—

रूल १८ में जायदादके बचे जानेका उल्लेख है उसी सम्बन्धम इस रूलमें बननाया गया है कि बिक्रीके रुपयेसे पहिले हीन प्रकारके खर्च चुगये जावेंगे (१) एक तो वह खर्च जो अदालतमें दरखास्त देनेके सम्बन्धमें किये गये हो (२) दूसरे वह खर्च जो जायदादके बचे जानेमें किये गये हों (३) तीसरे वह कमीशन जो आफिशान एसायनीको इस सम्बन्धमें मिलना चाहिये। इसके बाद मुर्तद्दिनका रुपया अदा किया जावेगा अगर मुर्तद्दिनका पूरा कर्त उससे न पूरे तो वह बाकी कर्जे को और कर्जद्वाराही भाति समित कर सकता है तथा हिस्सा रसदी ले सकता है परन्तु हिस्सा रसदी जा बट चुका है उसमें कोई गदबडी उसके इस बचीया कर्जेकी बजहसे नहीं पड़ेगी आर्वात व्यापदा यदि जाने वाले रुपयेमें ही वह हिस्सा रसदी पासकेगा। नीलामका रुपया मुर्तद्दिनका कर्जा चुगये जानेके बाद बचने पर आफिशान एसायनीको हिस्सा रसदीके तौर पर बाटे जानेके लिये मिलेगा।

२१ तहसीलात पर फारिवाई

हस प्रकारकी तहसीलात अगळे ठगसे किये जानेके लिये तथा हिसाबके अगळे ठंग पर लिखे जानेके लिये और खरीदारको हक पट्ट्यानेके लिये सब फरीकैनाक बयान मवालात दाखिले करके या अन्य प्रकारसे जैसा अदालत खचित समझे लिया जासकता है और सब फरीकैना अदालतके हुक्मके अनुसार दिवालिएकी जायदादस सम्बन्ध रखने वाली सब दस्तावेजों, कागजात, किताबों या अन्य तहसीलाको हलफिया पेश करेंगे ।

व्याख्या—

अदालत इस रूलके अनुसार फरीकैनाके बयान जिस प्रकार चाहे ल सकती है तथा उनमें जायदाद सम्बन्धी सब कागजात दाखिल कर सकती है जिससे कि तहसीलात ठग प्रचारत हो सके और खरीदारमें जायदादक खरादने पर हक पट्टा ल सके ।

२२ समय समय पर रुपयेकी अदायगी

यदि कोई किराया या दूसरी अदायगी किसी नियतकी हुई मुहत्त पर होना चाहिये और दिवालिएा करार दिया जानेका हुक्म उस मुहत्तके अलावा किसी और समय पर किया गया हो तो वह व्यक्ति जिसे किराया या वह अदायगी मिलना चाहिये उस हुक्मके होनेकी तारीख तकके इस्तेमालसे साबित कर सकता है जैसे कि वह किराया या अदायगी रोजानाके हिसाबसे मिलनेको चाहे ।

व्याख्या—

किसी मियादके समाप्त होनेसे पहिले दिवालिएा करार दिया जानेका हुक्म होने पर हुक्म होनेकी तारीख तकका हिसाब लगाया जासकता है जैसे कि यदि जमाही जमादानी किराया किया जानेका होवे और केवल दो ही महीने बचने पर दिवालिएा करार दिया जावेक हुक्म हो गया हो तो दो महानाका किराया और कर्जोंकी भांति बसूल किया जासकता है या जायदाद छ महीने समाप्त होने पर किराया वानिजुल अदा होगा । इसी प्रकार दूसरी शिर्कोंके बागमें समझना चाहिये ।

सूद

२३ सूद

(१) यदि किसी निश्चित कर्ज या धनके लिये सूद न रखा गया हो या तब न हुआ हो और जो दिवालिएा करार दिया जाने का हुक्म होनेसे पहिले वानिजुल अदा हो चुका हो तथा वह कर्ज या धन इस दफ्तरेके अनुसार साबित किया जासकता हो तो कर्जदारके विभिन्न प्रकारसे छे रुपया सैकड़ा सालाना तकके हिसाबसे सूद साबित कर सकता है—

(ए) यदि वह कर्ज अथवा धन किसी तहसीली दस्तावेजके आधार पर किसी निश्चित समयमें अदा किया जाने को होवे तो उस अदायगी की तारीखसे दिवालिएा करार दिया जाने का हुक्म होने तकका सूद लगाया जावेगा ।

(बी) और यदि कर्ज किसी अन्य प्रकारसे निकलना हो तो उस तारीखसे जबसे कि तहसीली तौर पर रुपया भगा गया हो और कर्जदारको इस बातका नोटिस दिया गया हो कि उससे उस तारीखके बादसे अदायगी तकका सूद लिया जावेगा । यह सूद भी दिवालिएा करार दिया जाने का हुक्म होने वाली तारीख तक मिलेगा ।

२ यदि दिवालियाकी कारवाहीके सम्बन्धमें साबित किये हुए किसी कर्जमें सूद या सूबके स्थानमें और कोई रूपया लगाया गया हो तो वह सूद या रूपया हिस्सा रसद्रीक लिये केवल छ रूपया सेरज साखाना ही क तौर पर जोड़ा जावेगा परन्तु साबित किये हुए सब कर्जोंक अदा हो जानेके बाद यदि कोई रूपया बचे तो उक्त उस कर्जवाहका बड़ीया तथा शुदा सूद या सुगारा दिलाया जावेगा ।

व्याख्या—

इस कलके अनुसार बिना तय हुए सूदके स्थानमें छ रूपया सेरज साखाना तथा सूद दिलाया जाहकता है उक्त लिये वा सूतें बनलाई गई हैं एक ता उस वक्त जब कि रूपया किसी दलालके आधार पर वाणिज्य अदा हो और दूसर बिना दस्तावेजी कर्जों पर उक्त समयसे सूट मिलेगा जब कि रूपया वाणिज्य अदा हो और बिना दस्तावेजा कर्जों पर उक्त समयसे सूट मिलेगा जब कि इसके लिय कर्जदारको नेटिव दिया गया हो दोनों हाथोंमें सूद उस तत्प्राप्त तत्का मिल सकगा जब कि दिवालिया करार । दया जानका हुका हुआ हो ।

उपरुल (२) में यह बताया गया है कि दिला रसदी कल छ रूपया सेरज साखाना हिस्से लिये हुए सूद पर हो मिल मरेगा चाहे इसके अधिक सूद या मनाफा क्यों न तब हुआ हो परन्तु माप ही साथ यह भा दिया हुआ है कि अगर साबित नियो हुए सब कल पूर्ण रूपसे चुकाया जायके व कुछ कालिज बच तो उसमें तय शुदा बकाया सूद अदा किया जावेगा ।

वह कर्ज जो भविष्यमें अदा किये जाना चाहिये

२४ भविष्यमें चुकाये जाने वाले कर्ज

कलकवाह सम्बन्धके लिये भी जो दिवालिया करार दिये जाते समय अदा किया जानेको न होने इती प्रकार साबित कर सकना है जैसे कि वह कर्ज अभी समय अदा किया जान का होवे केवल उसमेंसे छ रूपया सेरज साखाना दिलावये सूद हिस्सा रसदी बाद जनेके समयसे रूपयको वाणिज्य अदा होने वाले समय तक लिये वन शर्तकि हिस्सासे घणया जावेगा जिनके अनुसार कर्ज लिया गया हो ।

व्याख्या—

इस कलके अनुसार यदि कोई कर्ज दिवालिया करार दिये जाने वागी तालिजके बाद किया समय अदा किया जानकी होने ही भी वह साबित किया जाहकता है उक्तमें हिस्सा रसदा वाचक समयसे कर्ज वाणिज्य अदा होने वाली तालिज तत्का सूद छ रूपया सेरज साखाना हिस्सा वग दिया जावेगा ।

सुदूतका मान लिया जाना या उसका खारिज होना

२५ सुदूतका मान लिया जाना या उसका खारिज होना

आफिदाल एसायमी हर एक सुदन तथा कलके बतुहातको समझेगा और लिखकर पूरे कल या उमर किमी हिस्से का मजूर या कामचूर करेगा या उमर ताईदमें और अधिक सुदन मागगा । यदि वह किसी सुदूत खारिज पर तो वह उसक खारिजकी जागी बतुह कर्जवाहका लिखकर बतलावेगा ।

व्याख्या—

इस कानून के अनुसार किसी सुवृत्त के खारिज निये जान की वजह कर्जस्वाह को दिसपर बताई जाना चाहिये । सुवृत्त नावाको मादूम पडने पर अधिक सुवृत्त भी मागा जासकता है । पूरा कर्ज अथवा उसका कोई हिस्सा साबित माना जासकता है । सुवृत्त की मानना न मानना अधिकश एसायनी के हाथ है वही सुवृत्त को सुनगा व मज्दुरी अथवा खारिज करनेका हुक्म दगा भी अदालतमें इसकी आज्ञा इस प्रकार बताए हुए नियमोंके अनुसार की जासकती है ।

२६ बंकायदा लिखे हुए सुवृत्तको अदालत खारिज कर सकती है

यदि अधिकश एसायनीको मालूम पड़े कि कोई सुवृत्त बंकायदे ले लिया गया हो तो अदालत अधिकश एसायनीके दरखास्त देने पर कर्जस्वाह को नोटिस देनेके बाद उस सुवृत्तको निकाल सकती है अथवा उसकी तादाद कम कर सकती है ।

व्याख्या—

इस कानून के अनुसार यदि गन्तावे कोई सुवृत्त मान लिया गया हो तो अदालत उसे बादमें रद्द कर सकती है । यदि दूसरे कर्ज का सुवृत्त घात हो तो पूरा कर्ज रद्द कर दिया जावेगा अथवा यदि कर्जके किसी हिस्से का सुवृत्त ठीक न हो तो वह हिस्सा कर्जसे निकाल दिया जावेगा । अदालत इस कानून के अनुसार कर्जवाई करनेमें पहिले उस कर्जस्वाहको निसक कर्ज रद्द किया जाने की हानि सूचना देवेगा । यदि कोई मुर्तद्दिन दिवालिया करार दिया जानेका हुक्म होनेसे दो सालके अन्दरवा गिला हुआ रेशननामा पेश करे तो इस बातका बार सुवृत्त मुर्तद्दिन पर होगा कि वह रेशननामा काफ़ी मुआविके लिये नेक नापनाके साथ दिया गया था और यदि अधिकश एसायनीने एक बार इस कर्ज की मान भी लिया हो तो उससे बार सुवृत्त बदल नहीं जावेगा तथा अधिकश एसायनी अदालतमें उस कर्ज की रद्द कर देनेकी दाखला देसकता है । देखो अधिकश एसायनी मद्रास बचान सम्बन्ध मुद्दालियर 43 Mad 739

२७ किसी सुवृत्तको रद्द कर देने या उसे घटा देनेके लिये अदालतके अधिकार

यदि अधिकश एसायनी किसी मामलेमें दस्तन्दारी करनेसे इन्कार कर देवे तो अदालत किसी कर्जस्वाह के दरखास्त देने पर किसी सुवृत्तको रद्द कर सकती है या कम कर सकती है अथवा तक्षणीया या स्वीतके मामलेमें दिवालियेके दरखास्त देने पर किसी सुवृत्तको निकाल सकती है या कम कर सकती है ।

व्याख्या—

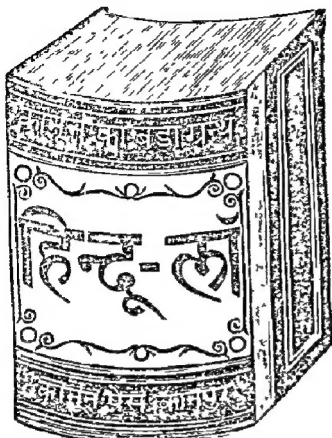
अधिकश एसायनीके अनिश्चित किसी कर्जस्वाह या दिवालियेके दरखास्त देने पर भी अदालत किसी सुवृत्तको खारिज कर सकती है या एतित शब्द कर्जकी तादादको कम कर सकती है । कर्जस्वाह उसी समय इस नियमके अनुसार कर्जवाई करनेकी दाखला दे सकता है जब कि अधिकश एसायनी दस्त दाखी करनेसे इन्कार कर देवे । दिवालिया तरकीब या स्वीम वाले मामलेमें दरखास्त देसकता है अर्थात् यदि कोई कर्ज कर्जा उसके विरुद्ध साबित किया गया हो तो उसने रद्द निये जानेका दाखला या कर्ज गट्टो हुए कर्ज को कम निये जानेकी दाखला दे सकता है ।

तीसरी सूची

(The Thired Schedule.)

मंसूख किये हुए एक्ट

साल	नम्बर	नाम	मंसूख किये जानेकी दिना
१८७८	११, १२ विधेय रिषा चैप्टर २१	I स्टैट्यूट दी इण्डियन इन्साल्वेन्सी एक्ट १८७८	वतना जो कि मंसूख न किया जा चुका हो
१८७९	२६	II. सपरिषद गवर्नर जनरल द्विन्द द्वारा बनाये हुए एक्ट दी इन्साल्वेन्सी इस्टेड (एनलैन्ड डिबिटिड) एक्ट, १८७९	वतना जो मंसूख न किया जा चुका हो
१८९८	१७	दी इण्डियन इन्साल्वेन्सी इन्स एक्ट, १८९८	दफाये २ व ३
१९००	३	दी लोभर वर्मा कोर्ट्स एक्ट	दफा ८ के उपदफा (१) का ड्राज (डी) और उपदफा (२), तथा दफा १७ के उपदफा (२) में मन्त्र शब्द "Official assignee" और उप- दफा (२) व (४) में यह शब्द "Official assignee"
१९०८	५	१९०८ का संशोधन अधिनियम	दफा १२० की उपदफा (२)



हिन्दू-लॉ

दूसरी बार छपा हुआ

पहलेसे चौगुना बड़ा

हिन्दीमें वानूतना सबसे बड़ा ग्रन्थ



आज तक कानूनका ऐसा सर्वोत्तम पूर्ण ग्रन्थ हिन्दीमें नहीं छपा। पढ़तेही चित्त सुखा होगा और विना प्रशंसा किये जान न होंगे। पहिलेसे चौगुना बड़ा, चौगुनी गतीरे व सत्र नये कानून, सग चौगुना पाबदेमंद हैं, तिम पर भी मुख्य नहीं बढ़ाया गया। अझालतमें होने वाले न्याय को घरहीमें समझ लेनेक लिय यह पुस्तक छपा गया है। १० संस्कृत ग्रन्थों, १०२

दूसरे कानूनों, हजारों गजीरों, बड़ाइरणों व सैकड़ों नक़्शोंसे परिपूर्ण है। यानी शामिलशरीक या बंटे हुए परिवारमें मर्दों, छियों, लडकों, गर्भमें बच्चोंका, जायदादमें कितना हक है, किसके सरने पर कौन वारिस कब होगा, विवाह कैसे कर-कन्याके साथ किम उमरमें, कब जायज है, कैसे विवाहके लडके वारिस होंगे, पति, पत्नीको कैसे, कब, किस तरह अपने पास रख सकते हैं, नावाजिगका चली कौन होगा, चलीक हक, पाबान्दिया, व जिसेदागिया, कौन हैं, कैसे चली निकाला जायगा, उस पर छिन्नी होगी, मोदका पूरा कानून बया ह, ३२७ वारिसों को जिसके बाद किसे व किस हंगसेकब हक मिलता है, अये, व अन्न भन्न वारिसों का नया कानून बया है; रहियों व वश्याओं की जायदादका कानून बया है, उनके वारिस कौन, कब व जिस तरह होत हैं, भिठलाई औरताहा हक क्या है, कौन धन छी धन है, उसके वारिस कौन, कब जिस तरह होत हैं, छियोंके हकका पूरा कानून बया है, फकी रहन, वय चाली जायदादक झगड़ोंका कानून बया है, दान व दयायत कैसे कब किम जायदादकी होगी कैसे हक देकर छिल्वी जायगी कैसे नाजायज हागी, मन्दिर, पाठशाला, धर्मशाला आदिमें जायदाद कैसे लगाई जाय, ट्रस्ट कैसे सुत्तर हो, जराभी गलतीसे कैसे मसूप होगा, साधु सन्यासी महन्त, गद्दीघरोंक हक बया है, बेरा, पुजारी, शिष्यायतक हक, अधिकार कब, किस तरह, किस जायदादमें कैसे होत हैं, दवस्थानका पूरा कानून बया है, भावी वारिसोंक हक कब कमे होंगे, इत्यादि हजारों बानाका आपरा पूर्ण ज्ञान होगा। रु० १९२५ ई० तकके सब नये कानून हजारों गजीरों व न्याय्या माहित दिय गय हैं। आप कानूनके पणेत हा सकय। मूल्य १२) टा० १॥)

मिलनेका पता:—कानून प्रेस, कानपुर